वार्षिक रिपोर्ट

2008 - 2009

विदेश मंत्रालय

भारत सरकार

आवरण चित्र:
जनपथ, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के
निर्माणाधीन मुख्यालय, जवाहर लाल नेहरु भवन का मॉडल

द्वारा प्रकाशित:
नीति नियोजन और अनुसंधान विभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.mea.gov.in

रूपरेखा एवं मुद्रण:
साइबरआर्ट इनफारमेशंस प्रा. लि.
1517 हेमकुन्ट चैम्बरस, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110 019
ईमेल: cyberart.mail@gmail.com
वैबसाइट: www.cyberart.co.in / 0120-4231676

विषय सूची

प्रस्तावना और सारांश i-xvi

1. भारत के पड़ोसी देश 1
2. दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत 17
3. पूर्व एशिया 30
4. यूरेशिया 34
5. खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका 41
6. अफ्रीका (सहारा से दक्षिण) 54
7. यूरोप 79
8. अमरीका 93
9. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 108
10. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध 125
11. तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास में भागीदारी 132
12. निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन 135
13. नीति आयोजना और अनुसंधान 136
14. प्रोतोकोल 139
15. कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं 145
16. प्रशासन और स्थापना 149
17. समन्वय 153
18. विदेश प्रचार 155
19. लोक राजनय प्रभाग 157
20. विदेश सेवा संस्थान 161
21. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 163
22. भारतीय विश्व कार्य परिषद 168
23. विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली 170
24. पुस्तकालय 175

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय बजट से प्रदान किए गए पद और बाह्य-संवर्ग पद इत्यादि शामिल हैं)।	179
परिशिष्ट II	विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2008 से नवम्बर 2008 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े ।	180
परिशिष्ट III	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भा.वि.से. के अधिकारियों की संख्या	181
परिशिष्ट IV	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2008 तक प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों और तत्काल योजना सहित जारी किए गए पासपोर्टों, विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाएं एवं राजस्व (तत्काल योजना के तहत राजस्व सहित) और पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय संबंधी आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण	182
परिशिष्ट V	वर्ष 2008-2009 में विदेश मंत्रालय का वित्त	183
परिशिष्ट VI	वर्ष 2008-09 बजट (संशोधित प्राक्कलन) में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (राजस्व और पूंजी)	184
परिशिष्ट VII	भारत के सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य	185
परिशिष्ट VIII	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विदेश मंत्रालय संबंधी रिपोर्ट से उद्घृत अंश	186
परिशिष्ट IX	वर्ष 2008 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार	187
परिशिष्ट X	1 जनवरी 2008 से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज	198
परिशिष्ट XI	1 जनवरी 2008 से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	200
परिशिष्ट XII	जनवरी, 2008 तक नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रुप से वित्त पोषित की गई संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं	202
परिशिष्ट XII	आई टी ई सी/एस सी ए ए पी भागीदार देशों की सूची	204
परिशिष्ट XIV	भारत में आई.टी.ई.सी. प्रशिक्षण संस्थानों की सूची	206
परिशिष्ट ꣳ	आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित व्याख्यान/संगोष्ठियां/सम्मेलन/बैठकें/ द्विपक्षीय वार्ताएं/पुस्तक विमोचन समारोह	207
परिशिष्ट XVI	आरआईएस द्वारा आयोजित संगोष्ठिया	209
	संक्षिप्तियाँ	211

प्रस्तावना और सारांश

भारत की विदेश नीति का लक्ष्य देश के सर्वोच्च हितों की सुरक्षा करना है। इसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य एक शांतिपूर्ण व स्थिर बाह्य परिवेश तैयार करना व संवर्धित करना, जिसमें समावेशी आर्थिक विकास व गरीबी उपशमन के घरेलू कार्यकलापों में तीव्र व अबाध प्रगति हो सके। भारत सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास को दी गयी उच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर अनुकूल बाह्य परिवेश तैयार करने में भारत का महत्वपूर्ण हित निहित है। इस प्रकार भारत एक शांतिपूर्ण माहौल चाहता है तथा अपने विस्तारित पड़ोस में अच्छे पड़ोसियों के संबंध कायम करने के लिए कार्यरत है। भारत की विदेश नीति में यह भी स्वीकार किया गया है कि भारत में परिवर्तन के लिए निर्णायक जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे विश्वव्यापी हैं तथा इनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

वर्ष 2008-09 में कई सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुईं तथा भारत की विदेश नीति के सामने कई चुनौतियां उभर कर आयीं।

भारत भारतीय उपमहाद्वीप में सभी देशों के साथ नजदीकी संबंध कायम करने के लिए तथा उनके साथ संप्रभु समानता तथा पारस्परिक सम्मान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए वचनबद्ध है। भारत और इसके पड़ोसी देशों की नियतियां साझी हैं। भूटान में लोकतंत्र लागू होने तथा महामहिम के राज्याभिषेक के वर्ष में भूटान के साथ संबंधों में और सुधार हुआ है। भारत, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन तथा बांग्लादेश में लोकतंत्र के पुनर्स्थापन का सशक्त रूप से समर्थन करता है, जो कि इन दोनों देशों में हाल ही की उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं से प्रदर्शित होता है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण व विकास में योगदान दिया है। भारत ने अपने निकटवर्ती देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध कायम करने के अलावा सार्क को एक परिणामोन्मुखी संगठन के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया है, जो कि क्षेत्रीय एकीकरण को प्रभावशाली ढंग से संवर्धित करता है।

जनवरी में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की विशेष चीन यात्रा तथा जून, 2008 में श्री प्रणब मुखर्जी की यात्रा से 2008 के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय संबध और मजबूत हुए हैं। भारत-चीन सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण रही, जबकि विशेष प्रतिनिधि सीमा मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते रहे। सीमांतर नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के कार्य क्षेत्र में विस्तार होता रहा। दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग से पारस्परिक विश्वास में वृद्धि करने में सहायता मिली है। चीन ने कोलकाता में एक नया कोंसलावास खोला है तथा इससे पहले जून में भारत ने ग्वांगझु में एक नया कोंसलावास खोला था।

प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत की सहभागिता और गहन व सशक्त हुई है, क्योंकि हमने अमरीका, रूस, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, आईबीसीए तथा कई अन्य देशों, जिनके साथ भारत ने सार्थक व सक्रिय वार्ता शुरू की है, सहित विभिन्न देशों, समूहों तथा क्षेत्रों के साथ आर्थिक व सामरिक संपर्क के क्षेत्र तथा गहनता में विस्तार किया है।

अक्तूबर, 2008 में भारत-यूएस असैनिक परमाणु करार पर हस्ताक्षर के साथ-साथ 6 सितंबर, 2008 को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा अपने सदस्यों को भारत के साथ असैनिक परमाणु व्यापार व सहयोग में शामिल होने की अनुमति देना एक मुख्य घटनाक्रम रहा। इस करार से परमाणु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से इंकार की 30 वर्षों की अवधि समाप्त हो गयी है। इस द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर होने के बाद फ्रांस, रूस व कजाखस्तान के साथ असैनिक परमाणु सहयोग से संबंधित करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सितंबर, 2008 में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ द्विपक्षीय बैठक तथा नवंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की वाशिंगटन यात्रा से भारत-यूएस रणनीतिक सहभागिता और मजबूत हुई। यूएस भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा प्रौद्योगिकी का स्रोत रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में संबंधों में विस्तार हुआ है।

इस अवधि के दौरान रूस के साथ भारत के पारंपरिक, मैत्रीपूर्ण व रणनीतिक संपर्क मजबूत हुए। रूस के राष्ट्रपति श्री दिमित्री मेदवेदेव ने वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन के लिए दिसंबर, 2008 में भारत की शासकीय यात्रा की। वर्ष 2008 भारत में "रूस वर्ष" के रूप में मनाया गया, जिसके दौरान पूरे भारत में लगभग 140 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2009 रूस में "भारत वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। हम मध्य एशियाई देशों के साथ सशक्त ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तथा इस क्षेत्र में और सतर्कतापूर्वक कार्य करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध सारवान तथा विविधतापूर्वक बने।

भारत ने रक्षा व सुरक्षा, परमाणु व अंतरिक्ष, व्यापार व निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में अपने रणनीतिक सहयोगी यूरोपीय संघ के साथ-साथ यूरोप के अलग-अगल देशों के साथ अपने संपर्क बनाए रखे तथा उन्हें

और मजबूत बनाया है। यूरोपीय संघ आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा हमारे निवेश का एक मुख्य स्रोत है।

भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण व सहयोगी संबंधों को महत्व देना जारी रखा है। अप्रैल, 2008 में सर्वप्रथम भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन में सहयोग के लिए दिल्ली घोषणा तथा भारत-अफ्रीका सहयोग संरचना पारित की गयी थी जो कि एक मुख्य कार्यक्रम था। दोनों दस्तावेजों में एक साथ भारत व अफ्रीकी देशों के मध्य सहयोग के लिए एक भावी खाका परिभाषित किया गया था। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 26 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत-सरकार की प्रतिष्ठित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन किया था।

हाल ही के वर्षों में लैटिन अमरीकी व कैरीबियाई क्षेत्र के देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय वार्ता तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए संस्थागत प्रक्रिया के ढांचे सहित अधिक से अधिक सशक्त संबंध स्थापित करने के लिए भारत के प्रयासों के प्रभावशाली परिणाम निकले हैं। भारत इस क्षेत्र के साथ निकट राजनीतिक संबंधों तथा और अधिक तीव्र संपर्कों के लिए कार्य करेगा। इस क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारिक व आर्थिक संबंधों में पर्याप्त सुधार हुआ है, परंतु अभी भी ऐसे कई अवसर हैं, जिनका पता लगाकर इनका लाभ उठाया जाना है।

आज पश्चिम एशिया व खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ हमारा सहयोग समकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा इसमें भारतीय प्रक्षेपण यान के प्रयोग सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 5 मिलियन प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, जिन्होंने भारत व खाड़ी क्षेत्र, दोनों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत-आसियान तथा एशिया प्रशांत के देशों के साथ सहयोग को भारत की पूर्वोन्मुख नीति में दर्शाए गए 21वीं शताब्दी के राजनय के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखता है।

वर्ष के दौरान भारत ने अपने आर्थिक व तकनीकी सहयोग के नेटवर्क में पर्याप्त विस्तार किया है। भारत आईआरसी (भारत-रूस-चीन), बीआरआईसी (ब्राजील-रूस-भारत-चीन) तथा आईबीएसए (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) जैसे हाल ही में स्थापित मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत आसियान, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक, मैकांग-गंगा सहयोग, जी-15 व जी-8 जैसे आर्थिक संगठनों के साथ लगातार संबंध स्थापित किए हुए है।

भारत ने बहुपक्षवाद के लिए अपनी सशक्त वचनबद्धता के साथ संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने का कार्य किया है। भारत ने यूएनएससी के सुधार तथा यूएनजीए को सक्रिय बनाने के प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत यह देखना चाहेगा कि विश्वस्तरीय संस्थाएं विकासशील देशों तथा उभरती शक्तियों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वव्यवस्था की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करें।

इन सकारात्मक घटनाओं के साथ-साथ 2008-09 में भारत की विदेश नीति के सामने कई बड़ी चुनौतियां आयी थीं, जिनमें भारत के निकटवर्ती देशों में सुरक्षा की अस्थिर स्थिति तथा सीमा पर आतंकवाद शामिल है। भारत की सुरक्षा के लिए कई नई चुनौतियां भी उभर कर सामने आयी हैं।

वर्ष 2008-09 में पाकिस्तान के साथ हमारी समग्र वार्ता प्रक्रिया 5वें दौर में प्रवेश कर गयी। यह वार्ता पाकिस्तान द्वारा व्यक्त इस वचनबद्धता पर आधारित थी कि वह किसी भी तरीके से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन देने के लिए अपने नियंत्रणाधीन किसी भी भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। वर्ष के दौरान सीमा पार व्यापार शुरू करने व यात्रा व्यवस्था को उदार बनाने तथा संवेदनशील और विवादित द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के संबंध में इस वार्ता में कुछ प्रगति हुई थी। तथापि, पाकिस्तान अपनी वचनबद्धता को लागू करने में असमर्थ रहा, जिसका साक्ष्य जुलाई, 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास तथा नवंबर, 2008 में मुंबई में पाकिस्तान की ओर से किए गए आतंकवादी हमले हैं, जिससे वार्ता प्रक्रिया स्थगित हो गयी।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुट होकर मुंबई हमले की निंदा की थी। इन हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों के शामिल होने के बारे में पाकिस्तान व विश्व को ठोस सबूत पेश किए गए। तत्पश्चात पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने इन हमलों का षड्यंत्र रचा व कार्यान्वित किया। तथापि, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा की गयी कार्रवाई ढुलमुल व अस्पष्ट रही तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई अथवा पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना अभी बाकी है।

वर्ष 2008 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर चलाए गए सैन्य अभियान से लिट्टे की पारंपरिक सैन्य क्षमता नष्ट कर दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों तथा नागरिकों को राहत आपूर्ति व चिकित्सा सहायता भेजकर इस मानवीय संकट पर तत्काल कार्रवाई की थी। संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से घायल नागरिकों के उपचार के लिए पुल्लूमदायी में 62 सदस्यीय फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया। भारत इस जातीय समस्या का वार्ता आधारित व राजनीतिक समाधान के लिए भी श्रीलंका के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। चूंकि श्रीलंका में स्थिति एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए भारत अखंड श्रीलंका के ढांचे के भीतर सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कार्य करेगा, जो विशेष रूप से तमिलों सहित सभी समुदायों को स्वीकार्य हो।

वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख चुनौती बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति थी। चूंकि मुख्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं व बाजारों में मंदी व आर्थिक संकट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट बन गया था, इसलिए भारत के विकास के लिए सहायक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में तेजी से परिवर्तन हुए। इसके बावजूद 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.7% की दर से विकास हुआ तथा यह विश्व अर्थव्यवस्था में विकास व स्थिरता का एक कारक रहा। तथापि, कुछ और समय के लिए इस कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बने रहने की संभावना है। भारत ने इस संकट से

निपटने के लिए जी-20 शिखर बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि यह देखा जा सके कि विकासशील देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। इन प्रयासों में हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकासशील देशों में धनराशि का प्रवाह बहाल किया जाए, आर्थिक उत्प्रेरकों के लाभों का व्यापक प्रसार हो तथा यह कि इस संकट से निपटने के उपाय संरक्षणवादी न हो, जिससे वस्तुओं, सेवाओं व व्यक्तियों का मुक्त प्रवाह प्रतिबंधित होता हो। भारत ने यह भी सुनिश्चित करना चाहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की शक्ति लोकतांत्रिक हो, ताकि वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाया जा सके।

वर्ष के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी आर्थिक संकट, आंतरिक आतंकवाद, सामान्य व परमाणु निरस्त्रीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व सतत् विकास जैसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का सहयोगी विश्वस्तरीय समाधान अपेक्षित है। इनके समाधान के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत एक उत्तरदायी शक्ति के रूप में सक्रिय भागीदारी करेगा और उन्हें सफल बनाने में अपना योगदान देगा।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तानः सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति, जिसकी प्रत्यक्ष परिणति जुलाई, 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हमले के रूप में हुई, के बावजूद हम अफगानिस्तान में स्थिर लोकतांत्रिक और बहुवादी समाज का निर्माण करने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी बने रहे। अफगानिस्तान को समुद्र क्षेत्र से जोड़ने वाली जरांज-डेलाराम सड़क का औपचारिक उद्घाटन 22 जनवरी, 2009 को विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति करजई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हमारी वचनबद्धताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अवसंरचना, मानवीय सहायता तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित हो रहा है। अफगान राष्ट्रिकों के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजना तथा आईटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और समुदाय आधारित कृषि, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे लघु विकास कार्यक्रमों में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है और सामान्य स्तर पर ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को परिलक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास को अपना अंशदान देना जारी रखा और इसने यूएनवीपी चुनाव कोष में 1 मिलियन अमरीकी डालर देने की वचनबद्धता व्यक्त की। हमने जारी और भावी परियोजनाओं की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर (पूर्व की 750 मिलियन अमरीकी डालर से आगे) की अतिरिक्त राशि देने की भी वचनबद्धता व्यक्त की है। राष्ट्रपति करज़ई ने अगस्त, 2008 और फिर जनवरी, 2009 में भारत का दौरा किया।

बांग्लादेशः वर्ष के दौरान भारत ने द्विपक्षीय मुद्दों के व्यापक परिदृश्य पर बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संपर्क बनाए रखे। दिसंबर, 2008 में आवामी लीग के नेतृत्व में महागठबंधन को जबरदस्त बहुमत प्राप्त होने तथा शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने फरवरी, 2009 में बांग्लादेश की यात्रा की। अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में 24 फरवरी- 1 मार्च, 2008 को बांग्लादेश के थल सेनाध्यक्ष जनरल मोईन की यात्रा, वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश की ढाका यात्रा तथा थल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर की यात्रा शामिल है।

भारत ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए जिनमें से अनेक एकपक्षीय थे। इन कदमों में 43 वर्ष बाद कोलकाता और ढाका के बीच "मैत्री एक्सप्रेस" रेलगाड़ी पुनः प्रारंभ हुई। भारत ने चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बांग्लादेश को पर्याप्त सहायता दी। भारत ने 1 जनवरी, 2008 से बांग्लादेश सहित सार्क के अन्य अल्प विकसित देशों के निर्यात को शुल्कमुक्त बाजार उपलब्ध कराना आरंभ किया (भारत की संवेदनशील सूची में शामिल कुछ मदों को छोड़कर)। भारत ने ढाका विश्वविद्यालय के नाटक व संगीत विभाग के लिए कलाभवन का निर्माण करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। बांग्लादेश की भूमि पर भारतीय आतंकवादी समूह की गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्य समूह को पुनर्जीवित किया।

भूटानः भारत तथा भूटान के मध्य मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे, जो कि वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय संपर्कों के माध्यम से और मजबूत हुए। इसी वर्ष भूटान के 5वें नरेश का राज्याभिषेक भी हुआ। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 16-17 मई, 2008 को भूटान की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित संसद के पहले सत्र को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार ने 2020 तक भारत को निर्यात करने के लिए भूटान में पनबिजली उत्पादन का दोगुना करके इसे 10,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार भारत व भूटान के मध्य पहले रेल संपर्क के निर्माण तथा भूटानी विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति प्रारंभ करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

भूटान के प्रधान मंत्री लियोनचिन जिग्मे वाई थिनले ने 14-17 जुलाई, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की तथा 12-14 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिर से भारत की यात्रा की। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील के साथ विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 5-8 नवंबर, 2008 को भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के औपचारिक राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि के रूप में भूटान की यात्रा की।

वर्ष 2008 को भूटान सरकार ने वर्ष 1958 में पं. जवाहरलाल नेहरू के भूटान यात्रा की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया। फरवरी, 2009 के दौरान भूटान के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की तथा भारत में अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की। हम भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए भूटान को पूरा समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है।

चीनः भारत-चीन संबंधों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 13-15 जनवरी, 2008 को जनवादी

गणराज्य चीन की सरकारी यात्रा की थी। भारत तथा चीन के नेताओं ने दोनों देशों के मध्य शांति व समृद्धि के लिए सामरिक एवं सहकारी भागीदारी का विकास करने की संकल्प लिया। उन्होंने शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सभी बकाया मतभेदों का समाधान करने की ठोस वचनबद्धता सुनिश्चित करते हुए दोहराया कि ऐसे मतभेदों से द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। दोनों प्रधान मंत्रियों ने "21वीं शताब्दी के लिए एक साझा दृष्टिपत्र" पर भी हस्ताक्षर किए, जो आपसी हित के क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय कार्यों में एक-दूसरे को सहयोग देने की दोनों देशों की इच्छा प्रदर्शित करता है।

भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों ने क्रमशः जून, 2008 तथा सितंबर, 2008 में यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान ग्वानझु व कोलकाता में नए प्रधान कोंसलावासों का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कैलेंडर वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार 51.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जो कि दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा 2010 तक निर्धारित 60 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के निकट है। दिसंबर, 2008 में भारत में आयोजित दूसरे संयुक्त सैन्याभ्यास तथा दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता से रक्षा संबंधों के क्षेत्र में सहयोग व आदान-प्रदान निरंतर होते रहे। आर्थिक व्यापार मुद्दों, नागरिक उड्डयन, युवा कार्य व अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में भी वृद्धि होती रही। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विचार-विमर्श के 12वें दौर के लिए सितंबर, 2008 में मुलाकात की। मई, 2009 में चीन के सिचुवान प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने चीन को 5 मिलियन अमरीकी डालर की मानवीय सहायता प्रदान की। दोनों देशों ने अंतराष्ट्रीय वित्तीय संकट व जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दों पर एक-दूसरे से विचार-विमर्श किया।

ईरानः वर्ष 2008-09 में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान तथा साथ ही उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से भारत-ईरान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में तेजी बनी रही। उच्चस्तरीय विचार-विमर्श गति के कारण ऊर्जा, व्यापार व वाणिज्य, निवेश, संस्कृति तथा पारगमन से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में सहयोग से द्विपक्षीय सहयोग में बहुत योगदान मिला है। दोनों सरकारों की ओर से क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए कार्य करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की साझा वचनबद्धता को उच्च स्तर पर दोहराया गया। ईरान के राष्ट्रपति डॉ. महमूद अहमदीनेजाद ने 29 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 28-30 जुलाई, 2008 को गुट निरपेक्ष आंदोलन के 15वें मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लेने के लिए तथा उसके बाद 31 अक्तूबर- 2 नवंबर, 2008 को भारत-ईरान के 15वें संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए तेहरान की यात्रा की। विदेश सचिव स्तर का छठा वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श 17-18 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मालदीवः भारत तथा मालदीव के मध्य घनिष्ठ व मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बने रहे। उच्चस्तरीय आदान-प्रदान तथा कई विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दोनों देश अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने में लगे रहे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद नाशीद ने 23-25 दिसंबर, 2008 को भारत की सरकारी यात्रा की, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच मालदीव को 100 मिलियन अमरीकी डालर की आकस्मिक ऋण सुविधा के लिए करार तथा हवाई सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने 29-31 जनवरी, 2008 को मालदीव की यात्रा की। जनवरी व फरवरी, 2009 में मालदीव के रक्षा मंत्री व स्वास्थ्य व परिवार मंत्री ने क्रमशः सुरक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की।

म्यांमाः इस अवधि के दौरान म्यांमा के साथ संबंधों में और विकास होता रहा तथा वे बहुआयामी हो गए। भारत उन देशों में से एक है, जिन्होंने सर्वप्रथम मई, 2008 में नर्गिस चक्रवात के बाद म्यांमा को तत्काल आपात सहायता भेजी। म्यांमा के प्रधान मंत्री थीन सीन ने नवंबर, 2008 में बिम्सटेक सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा की तथा भारत के उप राष्ट्रपति डॉ. एम. हमीद अंसारी ने 5-8 फरवरी, 2009 को म्यांमा की यात्रा की।

उप प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान एचएमआईटी (आई) द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तथा अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए। आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में संबंधों में काफी मजबूती आयी। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। म्यांमा के साथ नागालैंड की सीमा पर एक नया व्यापार मार्ग खोलने पर भी सहमति हुई। म्यांमा में भारतीय उग्रवादी गुटों की गतिविधियों को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकासित किया गया। भारत म्यांमा के भीतर अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए भी वचनबद्ध रहा है, जिसमें कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना तथा तेल व प्राकृतिक गैस के गवेषण, विद्युत क्षेत्र तथा विनिर्माण इत्यादि में सहयोग को मजबूत करना भी शामिल है।

नेपालः भारत ने, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए नेपाल की सरकार तथा जनता को हर संभव समर्थन दिया है। भारत नेपाल को लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण व समृद्ध राज्य के रूप में परिवर्तित होने में पूर्ण सहायता देने के लिए तैयार है। वर्ष के दौरान कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं हुईं। प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहाल "प्रचंड" ने 14-18 सितंबर, 2008 को भारत की प्रथम विदेश यात्रा ने भारत के साथ 21वीं शताब्दी के संबंध स्थापित करने में व्यापक राजनीतिक दिशा प्रदान की। यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री "प्रचंड" से बातचीत की तथा नेपाल के लोकतांत्रिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायता देने के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। एक नया संविधान तैयार करना तथा शांति-प्रक्रिया को पूरा करना नेपाल सरकार की प्राथमिकताएं हैं। हमने इन कार्यों में नेपाल सरकार की सहायता करने के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति के अनुसार कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रियाओं को भी पुनः सक्रिय किया गया।

निवेशक अनुकूल व्यापार परिवेश में संवर्धन से पारस्परिक लाभ के

लिए नेपाल में पनबिजली, कृषि, पर्यटन व अवसंरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों में भारतीय निवेश को बढ़ाने संबंधी उसकी क्षमताओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नवंबर, 2008 में नेपाल की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने प्रधान मंत्री "प्रचंड" की भारत यात्रा तथा विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान हुई सहमति पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए 17-18 फरवरी, 2009 को नेपाल की यात्रा की थी।

पाकिस्तानः वर्ष 2008-09 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्ता प्रक्रिया अपने 5वें दौर में पहुंच गयी है। वर्ष 2004 में बहाल यह वार्ता पाकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 2004 को दी गयी इस वचनबद्धता पर जारी रखी गयी थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह आतंकवाद का समर्थन करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। वर्ष के दौरान संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त की गयी उपलब्धियों के बावजूद आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 2004 की वचनबद्धता को कार्यान्वित न किए जाने के कारण, वार्ता प्रक्रिया का मूल आधार समाप्त हो गया। भारत में आतंकवादी हमले व जुलाई, 2008 में काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास पर हमले, युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि तथा नियंत्रण रेखा के पार लगातार घुसपैठ का भारत-पाकिस्तान संबंधों तथा विशेष रूप से वार्ता प्रक्रिया पर प्रतिकूल पड़ा। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले तथा इस हमले में पाकिस्तानी तत्वों के शामिल होने के ठोस सबूतों के परिणामस्वरूप वार्ता प्रक्रिया में रूकावट आयी।

मुंबई हमले के बाद मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए, ताकि पाकिस्तान में बसे आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी गतिविधियां फिर से न हों। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की अलकायदा व तालिबान प्रतिबंध समिति ने सुरक्षा परिषद संकल्प, 1267 के अंतर्गत लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं सहित पाकिस्तान आधारित अलग-अलग संगठनों को सूचीबद्ध किया। जमात-उद-दावा को भी लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों को मुंबई के आतंकवादी हमले से जोड़ने के संबंध में पाकिस्तान को 5 जनवरी को उपलब्ध कराए गए डोजियर पर पाकिस्तान के जवाब के बारे में 12 फरवरी, 2009 को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। अपने जवाब में पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान में बसे तत्व मुंबई के आतंकी हमले में शामिल थे। पाकिस्तान ने इससे जुड़ी अतिरिक्त सूचना एवं सामग्री की मांग की थी। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में इसे एक सकारात्मक घटनाक्रम बताया था। भारत सरकार ने 13 मार्च, 2009 को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को पाकिस्तान द्वारा उठाए गए सभी 30 प्रश्नों के विस्तृत जवाब और सूचनाएं सामग्री प्रदान की थीं, जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्राप्त किया।

मुंबई हमले के संबंध में सहयोग का आश्वासन देने से संबंधित पाकिस्तान के उच्चस्तरीय वक्तव्यों तथा उपरोक्त घटनाक्रम के बावजूद वास्तविक कार्रवाई की दृष्टि से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध काफी खराब हो गए।

अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के लिए अमरीका की नयी रणनीति की घोषणा के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 30 मार्च, 2009 को इस "स्पष्ट अभिव्यक्ति" का स्वागत किया कि "अफगानिस्तान में उग्रवाद तथा पाकिस्तान में इसकी जड़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा जाएगा" तथा "सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने में एक जिम्मेदार देश के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने" के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की।

श्रीलंकाः श्रीलंका के उत्तरी प्रान्त में 2008 के दौरान सैनिक संघर्ष बढ़ा जिससे एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया था और अन्ततः लिट्टे को सेना ने पराजित किया। उत्तरी प्रान्त की स्थिति और संघर्ष से विस्थापित तथा प्रभावित हुए तमिल नागरिकों की दुर्दशा भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। विदेश मंत्री ने 27 जनवरी, 2009 को कोलम्बो की यात्रा की और राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे से मिले। इसके पहले 16-17 जनवरी, 2009 को विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने श्रीलंका की यात्रा की।

श्रीलंका में उभरते मानवीय संकट को देखते हुए भारत ने भारी मात्रा में आपात राहत सहायता भेजी जिसके अंतर्गत आंतरिक रूप से विस्थापितों के लिए घरेलू सामान, दवाएं एवं उत्तरी श्रीलंका में एक 62 सदस्यों वाले आपातकालिक क्षेत्र अस्पताल की स्थापना भी शामिल थी। अखंड श्रीलंका के अंतर्गत शांतिपूर्ण वार्ता से राजनैतिक समाधान के समर्थन में भारत ने श्रीलंका के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय आदान-प्रदान मजबूत होते रहे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी 2-3 अगस्त, 2008 को आयोजित 15वीं सार्क शिखर बैठक में भाग लेने श्रीलंका गये। व्यापार और निवेश सम्पर्कों में और भी दृढ़ता आई। भारत 2008 में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा और द्विपक्षीय व्यापार 3.27 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत 2008 में श्रीलंका में दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में भी उभरा।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)ः अप्रैल, 2007 से अगस्त, 2008 तक भारत को मिली सार्क की अध्यक्षता अवधि सार्क के इतिहास में सर्वाधिक उत्पादक रही, जब इसके स्वरूप ने घोषणाकारी से कार्यान्वयनकारी चरण में प्रवेश किया। दिल्ली में आयोजित 14वीं शिखर बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा की गयी प्रत्येक घोषणा कार्यान्वित की जा चुकी है और भारत अपनी जिम्मेदारी को अनन्य (असममित) ढंग से निभा रहा है। कोलम्बो में (2-3 अगस्त, 2008 को) आयोजित 15वीं सार्क शिखर बैठक में श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता संभाली जो कि काफी सफल रही और इस शिखर बैठक में 4 महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सार्क विकास कोष चार्टर भी शामिल था। दक्षिण

एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है।

बाह्य क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए सार्क वाणिज्य मंत्रियों की तीसरी बैठक (3 मार्च 2008) में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि साफ्टा के पूर्ण कार्यान्वयन की अनुसूची को बनाए रखा जाएगा और यह भी निर्णय लिया गया कि मौजूदा संवेदी सूची की शीघ्र ही समीक्षा की जाएगी। इस संदर्भ में, भारत ने लक्ष्य तिथि से एक वर्ष पहले 1 जनवरी, 2008 से अल्प विकसित देशों (एल डी सी) को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है और एल डी सी एवं गैर एल डी सी के लिए अपनी निषिद्ध सूची को एकतरफा 744 से घटाकर लगभग 500 कर दिया।

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत

भारत ने वर्ष के दौरान अपनी "पूर्वोन्मुख नीति" में यथा परिकल्पित दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। क्षेत्र के कुछ देशों के साथ हमने अपने संबंध सामरिक स्तर तक बढ़ाए जबकि अन्य देशों के साथ संबंधों को विविध और सुदृढ़ बनाया गया। द्विपक्षीय स्तर पर उच्च स्तरीय दौरों के नियमित आदान-प्रदान और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर वार्ताओं से क्षेत्र के नेताओं के बीच उच्च स्तरीय सम्पर्क बढ़ाने में योगदान मिला और उससे इन देशों के साथ भारत के संबंधों में नवीन गतिशीलता विकसित करने में मदद मिली। पिछले पाँच वर्षों में क्षेत्र के कई देशों के प्रधान मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। हमारे नेताओं ने भी क्षेत्र के विभिन्न देशों की यात्रा की। इन दौरों और कई ढाँचागत करारों पर हस्ताक्षर होने से इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते संबंधों को महत्वपूर्ण योगदान मिला।

भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई जो 2007-08 में लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा छू गया। वस्तुओं के भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर सफलतापूर्वक वार्ता हुई और वह हस्ताक्षर किए जाने हेतु तैयार है। भारत-आसियान एफ टी ए के कार्यान्वयन से आसियान देशों के साथ व्यापार 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य पार कर लेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के कई देशों के साथ द्विपक्षीय एफ टी ए पर वार्ताएं चल रही हैं जिनके सम्पन्न होने पर द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी। आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार भी 10 बिलियन अमरीकी डालर पार कर गया।

इस क्षेत्र के देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत अनुदान, लघु ऋण और ऋणपत्रों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में आई टी ई सी स्कीम के तहत कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपीन्स को सहायता प्रदान करता रहा। प्रशांत द्वीपसमूह मंच(पी आई एफ) देशों के वार्ता भागीदार के रूप में भारत ने क्षमता निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों तथा दीर्घकालिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहायता प्रदान करके प्रशान्त द्वीप के देशों के साथ अपना सम्पर्क बनाए रखा। इसके उत्तर में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी, राष्ट्रमण्डल, असैनिक नाभिकीय सहयोग आदि जैसे भारत के हित के मुद्दों पर क्षेत्र के अधिकांश देशों का समर्थन हासिल करने में सफलता मिली।

भारत की विकासशील रूपरेखा ने दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को आसियान, ई ए एस, बिमस्टेक, एम जी सी और ए आर एफ जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए आकृष्ट किया है।

पूर्व एशिया

जापानः भारत-जापान संबंधों में, जिसमें हाल के वर्षों में विस्तार और व्यापकता आई है, महत्वपूर्ण और गुणात्मक परिवर्तन होते रहे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 22-23 अक्तूबर, 2008 को वार्षिक भारत-जापान शिखर बैठक के लिए जापान की राजकीय यात्रा की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की उन्नति संबंधी एक संयुक्त वक्तव्य और सुरक्षा सहयोग संबंधी एक संयुक्त करार पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रियों के बीच दूसरी सामरिक वार्ता अगस्त 2008 में आयोजित की गई जब जापान के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। आर्थिक और व्यापार संबंधी मामलों और ऊर्जा पर मंत्रिस्तरीय वार्ताएं भी आयोजित की गईं।

भारत वित्त वर्ष 2008-09 में जापान की सरकारी विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (236.047 बिलियन येन या लगभग 11,802.4 करोड़ रूपए) था। दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी से प्रगति हुई। जापानी पक्ष वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के चरण-I के लिए ऋण के रूप में लगभग 450 बिलियन येन की वित्तीय सहायता प्रदान करने को राजी हुआ है और उन्होंने समूचे वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए सहायता को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के लिए भारत के साथ काम करने की बचनबद्धता जाहिर की है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर पहल के संबंध में दोनों पक्षों ने परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त कार्य बल की बैठकें की है। रक्षा आदान-प्रदान से संबंधित हमारा एक वार्षिक कैलेण्डर है। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर विचार विमर्श जारी रखा जिसका उद्देश्य परस्पर लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले करार का सम्पन्न करना है। दोनों पक्षों ने हैदराबाद में एक नए आई आई टी के लिए जापानी सहायता पर भी विचार-विमर्श किया है। रक्षा और कार्यात्मक आदान-प्रदान भी द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

कोरिया गणराज्यः कोरिया गणराज्य के साथ हमारे संबंध सहज रूप से बढ़े हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कोरिया गणराज्य के नए राष्ट्रपति ली म्यूंग बैक के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जुलाई 2008 में जापान में आयोजित जी-8 शिखर बैठक के दौरान नए राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के संबंध में वार्ता हो रही है, आशा है कि यह वार्ता वित्त वर्ष 2009-10 में सम्पन्न हो जाएगी। वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सहयोग हुए।

मंगोलियाः प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर 2008 में बीजिंग में आयोजित 7वीं एसेम शिखर बैठक के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मंगोलिया के रक्षा मंत्री फरवरी 2009 में भारत आए थे। आर्थिक और व्यापार संबंधी मामलों; रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत मंगोलियाई नागरिकों के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान द्विपक्षीय सहयोग बढ़ता रहा। भारत ने मंगोलिया के साथ हमारे बेहद दोस्ताना रिश्तों को देखते हुए मानवीय सहायता के रूप में 5000-5000 मीट्रिक टन चावल और चीनी मंगोलिया को दिया।

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्यः भारत और डी पी आर के के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और मानवीय सहायता तथा संस्कृति, खेलकूद और शिक्षा के क्षेत्रों में आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान दिया गया।

यूरेशिया

भारत ने दौरों, द्विपक्षीय करारों आवधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं, सहयोग कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से वर्ष के दौरान रूस, उक्रेन, बेलारूस, मध्य एशिया और काकेसियन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय क्रियाकलाप थे- दिसम्बर 2008 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दिमित्रि ए. मेदवेदेव की भारत की राजकीय यात्रा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव की गणतंत्र दिवस समारोह 2009 के मुख्य अतिथि के रूप में की गई भारत की यात्रा और अप्रैल 2008 में भारत के उपराष्ट्रपति की कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान की यात्रा।

भारत और रूस ने अपनी सामरिक भागीदारी को और सुदृढ़ बनाना जारी रखा। रक्षा, अंतरिक्ष और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग सघन किए गए हैं। वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठकों के लिए 4-5 दिसम्बर, 2008 को राष्ट्रपति मेदवेदेव की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा के अतिरिक्त 9 महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन करारों में कुदांकुलम में एक और नाभिकीय विद्युत संयंत्र के निर्माण में सहयोग पर एक अंतर्सरकारी करार और नए स्थानों पर रूस द्वारा प्रारूपित नाभिकीय विद्युत संयत्र के निर्माण में सहयोग संबंधी करार शामिल थे और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रमों पर इसरो और रूसी फेडरल स्पेस एजेन्सी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी शामिल है। रूसी पक्ष से रक्षा मंत्री अनातोली सेरड्यूकोव ने 28-30 सितम्बर, 2008 को भारत की यात्रा की, विदेश मंत्री श्री सेरगे लवरोव ने 20 अक्तूबर को भारत की यात्रा की और रूस के उप प्रधान मंत्री एलैक्जैण्डर झुकोव ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस आई जी सी के 14वें सत्र की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत की यात्रा की। वर्ष 2008 भारत में "रूस वर्ष" के रूप में मनाया गया जिसमें भारत के विभिन्न नगरों में लगभग 140 कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसी तरह वर्ष 2009 को रूस में "भारत वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है।

तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री राशिद मेरेदोव 20-22 जनवरी 2008 को एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल की अगुवाई में भारत आए। श्री मेरेदोव ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु भारत-तुर्कमेनिस्तान अंतर्सरकारी आयोग के दूसरे सत्र की विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के साथ सह अध्यक्षता की। अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री मेरेदोव ने उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी मिले। उप राष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी ने 4-6 अप्रैल 2008 को तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा की। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी वह पहली विदेश यात्रा थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने नवम्बर 2008 में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। बेलारूस के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल लियोनिड माल्टसेव नई दिल्ली में आयोजित डिफएक्सपो इण्डिया 2008 में शामिल होने के लिए 16-18 फरवरी को भारत आए। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए 16 फरवरी को रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने 12-15 मार्च 2008 को बेलारूस की यात्रा की और बेलारूस के रक्षा मंत्री, राज्य सैनिक और औद्योगिक समिति के अध्यक्ष और सेना प्रमुख से मुलाकात की। जनरल कपूर बेलारूस सैनिक अकादमी और अनेक रक्षा उत्पाद उपक्रमों को देखने गये। बेलारूस के उद्योग मंत्री श्री एनातोली रूसेट्स्की ने 17-18 नवम्बर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक,प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस आई जी सी के चौथे सत्र में हिस्सा लिया। सैनिक तकनीकी सहयोग पर भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग का पहला सत्र 27-30 मई, 2008 को मिन्स्क में आयोजित किया गया। किर्गीज गणराज्य के विदेश मंत्री श्री एदनान काराबेव ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 4-6 फरवरी 2008 को भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से मुलाकात की।

2008 में उप राष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी की 6-10 अप्रैल 2008 को कजाकिस्तान की यात्रा से भारत-कजाकिस्तान संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी। अपनी यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मिले और सीनेट को संबोधित किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव ने 23-26 जनवरी, 2009 को भारत की राजकीय यात्रा की और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे- यह पहला अवसर था जब एक मध्य एशियाई देश के नेता को यह सम्मान दिया गया। 1 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के आयोजन और सितम्बर 2008 में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-उजबेकिस्तान अंतर्सरकारी आयोग के 8वें सत्र के आयोजन के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण मध्य एशियाई देश उजबेकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों में प्रगति हुई। उजबेकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री बी.खोदजीव ने आई जी सी के 8वें सत्र के लिए 16-17 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की थी।

खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

भारत ने खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और परंपरागत सौहार्दपूर्ण रिश्तों और सहयोग को बनाए रखा। खाड़ी देशों से हमारी

कुल कच्चे तेल की जरूरत का 70% प्राप्त होता है और लगभग 4.5 मिलियन भारतीय इस क्षेत्र में रहते और काम करते है जो एक वर्ष में 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक धन यहाँ भेजते हैं। वर्ष के दौरान कई उच्च-स्तरीय दौरे हुए जो इस क्षेत्र के साथ हमारे रिश्तों के महत्व को रेखांकित करता है। सबसे महत्वपूर्ण नवम्बर 2008 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की कतर और ओमान की यात्रा थी जिससे द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्र खुले। कतर में प्रधान मंत्री ने रक्षा सहयोग और सुरक्षा के साथ-साथ विधि के प्रवर्तन मामलों से संबंधित दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये। ओमान में मानव शक्ति पर एक समझौता ज्ञापन तथा भारत ओमान संयुक्त निवेश निधि की स्थापना पर एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद और सचिव(पूर्व) के साथ विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 13-14 जनवरी, 2008 को मस्कट की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने मंत्रिपरिषद के उप प्रधान मंत्री और ओमान के विदेश मामलों के मंत्री श्री यूसूफ बिन अलवाई बिन अब्दुल्ला से मुलाकात की।

बहरीन के श्रम मंत्री श्री मजीद मोहसिन अल आलवी ने 25 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा की और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री के साथ श्रम और जनशक्ति विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श किया। बहरीन के सामाजिक विकास मंत्री डॉ. फातिमा बिन्ट अल बलूशी ने 17-21 अगस्त 2008 को भारत की यात्रा की और अन्यों के साथ-साथ कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री से चर्चा की।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद ने 29-31 जनवरी, 2008 को कुवैत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने कुवैत के प्रधान मंत्री से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री की कुवैत के उप-प्रधान मंत्री/विदेश मंत्री और श्रम में सामाजिक मामलों के मंत्री के साथ हुई बैठकों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें कुवैती नियोक्ता एवं भारतीय कामगारों के बीच हस्ताक्षर होने वाले श्रम अनुबंध के संशोधित प्रारूप पर हुई चर्चा शामिल है।

वर्ष के दौरान अनेक उच्च-स्तरीय दौरों के साथ सउदी अरब से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई। सउदी विदेश मंत्री प्रिन्स सउद अल फैजल ने 2008 में दो बार भारत की यात्रा की, पहली बार वह फरवरी में आए जब उन्होंने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उसके बाद 26 दिसम्बर को आए और तब उन्होंने उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 19-20 अप्रैल, 2008 को सउदी अरब की 2 दिन की यात्रा की और सउदी शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और रियाद के गवर्नर प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद ने 17 अप्रैल 2008 को सउदी अरब की यात्रा की और सउदी हज मंत्री डा. फौउआद अल-फारसी के साथ हज करार पर हस्ताक्षर किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ वित्त मंत्री सउदी शाह अब्दुल्ला के अनुरोध पर 22 जून, 2008 को जेद्दा में आयोजित तेल शिखर बैठक में शामिल हुए।

वर्ष 2008 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में मजबूती का भी था। विदेश व्यापार मंत्री शेख लुब्ना अल कासिमी ने 25 अप्रैल को भारत की यात्रा की और फिक्की द्वारा उन्हें "वुमेन अचीवर ऑफ दि इयर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितम्बर 2008 में आबू धाबी में पहली बार भारत-यूएई संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। विदेश मंत्री ने मई, 2008 में यू ए ई की यात्रा की और विदेश मंत्री एवं युवराज दोनों से मुलाकात की।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों को अनेक उच्च स्तरीय दौरों द्वारा मजबूत बनाए गए जिनमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद, मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी मुबारक और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भारत की राजकीए यात्राएं शामिल थीं। विदेश मंत्री की जुलाई 2008 में मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान मिस्र के साथ भारत की वार्ता में भी प्रगति हुई। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी हितों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन को रेखांकित किया गया और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रपति अब्बास ने नई दिल्ली में फिलिस्तीनी राजदूतावास के भवन का शिलान्यास किया जो भारत सरकार और भारत के नागरिकों की ओर से एक उपहार है और उसका निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को बजटीय सहयोग के रूप में प्रधान मंत्री की 10 मिलियन डालर की पेशकश को भी वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया।

भारत ने दिसम्बर 2008 में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में अचानक किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। अरब लीग के महासचिव महामहिम श्री आमरे मूसा की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान दिसम्बर, 2008 में अरब लीग राष्ट्रों के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद अरब जगत के साथ भारत के विविधतापूर्ण संबंधों को संस्थागत स्वरूप मिला।

भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के तहत इराक को 100 स्लॉट प्रदान करके वहाँ के मानव संसाधन विकास में योगदान दिया जिसके तहत वहाँ के अधिकारियों को पूरे भारत में स्थित विभिन्न प्रशिक्षण और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारतीय तेल निगम ने 228 इराकी तेल अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया। 26 फरवरी, 2009 को इराक के राष्ट्रपति जलाल तालाबानी ने भारत की अपनी पारगमन यात्रा के दौरान हमें इराक के पुनर्निर्माण और विकास, खासतौर पर वहाँ विद्युत क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। सचिव(पूर्व) के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने इराक में भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहित करने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की और उन्हें पूरा सहयोग देने का निजी तौर पर आश्वासन भी दिया।

अफ्रीका

नई दिल्ली में 8-9 अप्रैल, 2008 को आयोजित भारत-अफ्रीका मंच की पहली शिखर बैठक दोनों के बीच विद्यमान ऐतिहासिक संबंधों की नींव से जुड़ी थी और इससे आने वाले वर्षों में एक ढाँचागत तालमेल,

प्रगाढ़ता और सहयोग की रूपरेखा तैयार हुई। शिखर बैठक में अफ्रीका के प्रति भारत की वचनबद्धता को फिर से ताजा किया गया। शिखर बैठक के अन्त में दो ऐतिहासिक दस्तावेजों- दिल्ली घोषणा और भारत अफ्रीका सहयोग की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। दिल्ली घोषणा एक राजनैतिक दस्तावेज है जिसमें में भारत और अफ्रीका के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों के मुद्दे शामिल किये गए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुधारों, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आदि पर हमारी साझी स्थिति भी शामिल है। भारत-अफ्रीका सहयोग के सहमत की रूपरेखा में सहयोग की सहमति वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रधान मंत्री ने अफ्रीका को दिए गए मौजूदा ऋण-पत्र में अत्याधिक वृद्धि करके उसे अगले पाँच वर्षों के लिए 5.4 बिलियन अमरीकी डालर किए जाने और क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के एक पृथक अनुदान की घोषणा की।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में शामिल होने वाले अफ्रीका के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जकाया म्रिशो किक्वेटे, अफ्रीकी संघ आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अल्फा उमर कोनारे, कांगो के राष्ट्रपति श्री जोसेफ कबिला कबांजे, घाना के राष्ट्रपति श्री जॉन एजीकुम कुफुर, सेनेगल के राष्ट्रपति श्री अब्दुलाए वाडे, दक्षिण अफीका के राष्ट्रपति श्री थाबो म्बेकी, उगांडा के राष्ट्रपति श्री योवेरी कागुता मुसेवेनी, बुर्कीना फासो के प्रधान मंत्री श्री तर्तियस जोंगो और ईथोपिया के प्रधान मंत्री श्री मेलेस जेनावी शामिल थे।

अफ्रीका से भारत के कई उच्च-स्तरीय दौरे हुए जिनमें ईथोपिया के प्रधान मंत्री मेलेस जेनावी, रवाण्डा के राष्ट्रपति श्री पॉल कागामे और बेनिन गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. बोनी यायी के दौरे शामिल थे। मंत्रियों और आधिकारियों के स्तर पर नियमित आदान-प्रदान चलते रहे।

भारत ने विशिष्ट बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी देशों को अनेक ऋण-श्रृखलाएं प्रदान की। टीम-9 और इकोवास दोनों ने कृषि, स्वास्थ्य,ग्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन और विद्युत जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण पत्रों का पूरा उपयोग किया, ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अफ्रीकी संघ आयोग के साथ हमारे मौजूदा राजनैतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होते रहे और कोमेसा, एसएडीसी, ईसीसीएएस और ईएसी जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ हमारे संस्थागत सहयोग भी मजबूत होते रहे। मंत्रालय के अफ्रीका को सहायता बजट का उपयोग दूसरे सहयोग कार्यक्रमों के लिए किया गया।

भारत में अफ्रीकी देशों के लिए आई टी ई सी स्लॉट को 279 से बढ़ाकर 575 कर दिया गया जबकि विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने छात्रवृत्तियों की संख्या को 21 से बढ़ाकर 66 कर दिया।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के समर्थन से सी आई आई द्वारा दो भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी कान्क्लेवों का सफलतापूर्वक अयोजन किया गया, पहला दास-ए-सलाम में 28 अगस्त, 2008 को और दूसरा नई दिल्ली में 22-24 मार्च, 2009 को। फिक्की ने भी 19-20 जनवरी को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका व्यापार भागीदारी शिखर बैठक आयोजित किया। इन सभी अवसरों पर भारत और अफ्रीका के उच्च-स्तर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया।

इन तमाम पहलों से उप-सहारा अफ्रीका के देशों के साथ भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई और अफ्रीका में निजी क्षेत्र के कार्यकलाप बढ़ाने के अवसर उत्पन्न हुए। दोनों ओर का व्यापार 2001-02 के 5.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2008-09 में लगभग 36 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जो इन वर्षों में लगभग सात गुना की वृद्धि दर्शाता है। द्विपक्षीय निवेश लगभग 17 बिलियन अमरीकी डालर है।

भारत ने माली और नाइजर में आवासीय मिशन खोले जाने की घोषणा की। गाम्बिया, गैबोन और मेडागास्कर ने अपने मिशन नई दिल्ली में खोले हैं और माली ने शीघ्र ही उसे खोले अपना मिशन खोलने की मंशा प्रकट की है।

भारत सरकार की प्रतिष्ठित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 26 फरवरी, 2009 को विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया जिसमें 35 में से ग्यारह देशों को रखा गया है, जिन्होंने परियोजना में शामिल होने के करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

यूरोप

यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री गोर्डन ब्राउन ने 20-21 जनवरी, 2008 तक नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-यूके शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लंदन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में 1 अप्रैल, 2009 को पुनः श्री गोर्डन ब्राउन के साथ मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी ने एक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय एवं व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 25-26 जनवरी, 2008 तक भारत का दौरा किया और वे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत-फ्रांस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 सितंबर, 2008 को पेरिस का दौरा किया। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने भारत और फ्रांस के बीच सामरिक भागीदारी की पुष्टि की तथा नाभिकीय ऊर्जा सहयोग, अंतरिक्ष एवं रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने की वचनबद्धता व्यक्त की। जर्मनी, यूरोपीय संघ के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा। जर्मन संघीय चांसलर और विदेश मंत्री डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ने 19-21 नवंबर, 2008 तक भारत का दौरा किया। हाल में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग भारत-जर्मनी क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभरा है। इस अवधि के दौरान मंत्रियों के स्तर पर भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय यात्राएं जारी रहीं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भारतीय वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पैट्रोलियम एवं गैस मंत्री की स्पेन यात्रा थीं। भारत ने विभिन्न स्तरों पर इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करना जारी रखा। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 24 अक्तूबर, 2008 को बीजिंग में आयोजित एएसईएम शिखर सम्मेलन के दौरान

अतिरिक्त समय में प्रधान मंत्री श्री सिल्विओ बलुस्कोनी से मुलाकात की।

भारत तथा नोर्दिक और मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देशों के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को विविधतापूर्ण तथा गहन बनाने का प्रयास जारी रहा। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन, पेट्रोलियम, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग और गहरे समुद्र मात्स्यिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नयी संभावनाओं का पता चला। इन देशों के साथ मंत्रिस्तरीय एवं अधिकारी स्तरीय तालमेल जारी रहे। हेलेनिक गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री कोस्तास करामानलिस ने 10-13 जनवरी, 2008 तक भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता से मुलाकात की। हंगरी के प्रधान मंत्री श्री फेरेन ग्यूरसानी ने 16-19 जनवरी, 2008 तक भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, संप्रग अध्यक्षा, लोक सभा में विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, पेट्रोलियम एवं गैस तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ मुलाकात की। स्वीडन से व्यापार मंत्री, लोक स्वास्थ्य मंत्री, अप्रवासन एवं आश्रय नीति मंत्री तथा युवराज ने इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा की। स्वीडिश संसद की विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने जनवरी, 2009 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। चेक गणराज्य और भारत के बीच द्विपक्षीय यात्राओं में विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ का चेक गणराज्य का दौरा तथा चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार मंत्री तथा चेक गणराज्य के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ का भारत का दौरा शामिल है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने फिनलैंड में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए अप्रैल, 2008 में फिनलैंड का दौरा किया तथा फिनलैंड की राष्ट्रपति श्रीमती तारजा हैलोनेन ने दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 5-7 फरवरी, 2009 तक भारत का दौरा किया। पोलैंड के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित यात्राएं होती रहीं। सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने मार्च, 2008 में पोलैंड का सद्भावना दौरा किया। 4-8 फरवरी, 2008 तक डेनमार्क के प्रधान मंत्री एंडर्स फोघ रासमुसेन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और संवर्धित हुए। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत और तुर्की के बीच संवर्धित क्रियाकलाप हुए। तुर्की के प्रधान मंत्री रेसेप तय्यिप इरदोगान ने 21-24 नवंबर, 2008 तक भारत का सरकारी दौरा किया।

यूरोपीय संघः भारत और यूरोपीय संघ उदीयमान बहु-ध्रुवीय विश्व में अपरिहार्य ध्रुव हैं। भारत और यूरोप के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान बनाए रखा गया और शिखर बैठक स्तरीय क्रियाकलाप हुए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रतिरक्षा एवं रक्षा, नाभिकीय एवं अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में क्रियाकलाप जारी रहे। अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग हेतु एनएसजी में छूट प्राप्त करने के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु यूरोपीय संघ के सभी देशों में विशेष दूत भेजे गए। मुंबई हमलों के पश्चात यूरोपीय संघ के नेता और सदस्य राज्यों ने इन हमलों की भर्त्सना करते हुए संदेश भेजे और टेलीफोन किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नौवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 29 सितंबर, 2008 को मार्सिले, फ्रांस की यात्रा की। प्रधान मंत्री ने यूरोपीय संघ/फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैनुअल बारोसो के साथ चर्चा की। शिखर सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्ययोजना 2005 की समीक्षा की गयी और सामरिक भागीदारी को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने की एक संशोधित योजना जारी की गई। इसके दौरान ऊर्जा, स्वच्छ विकास तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के लिए संयुक्त कार्य-योजना भी जारी की गयी। प्रधान मंत्री ने "भागीदारी के लिए नई समानताएं" विषय पर 30 सितंबर को पेरिस में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। 19वीं भारत-यूरोपीय संघ त्रोयका विदेश मंत्रियों की बैठक 30 मई, 2008 को और भारत-यूरोपीय संघ सामरिक वार्ता का आयोजन 5 दिसंबर को नई दिल्ली में किया गया। इसके अतिरिक्त भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल बैठक के चौथे दौर तथा कोंसली मामलों पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यकारी दल की 11वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में क्रमशः 08 सितंबर और 23 मई, 2008 को किया गया।

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2007 में द्विपक्षीय व्यापार 55 बिलियन यूरो पार कर गया और 5 वर्षों में इसे 100 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत और यूरोप के बीच अत्यंत गतिशील निवेश संबंध रहे हैं।

अमेरिका

वर्ष 2008 के दौरान भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय क्रियाकलाप गहन हुए। 10 अक्तूबर, 2008 को वाशिंगटन में भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर हस्ताक्षर किया जाना जुलाई, 2005 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा के दौरान घोषित असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल की परिणति थी। 1 अगस्त, 2008 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सफलतापूर्वक भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय करार संपन्न किया, जिससे अमरीका द्वारा 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के साथ संपर्क करके एनएसजी दिशा-निर्देशों में परिवर्तन लाते हुए इसके सदस्यों और भारत के बीच असैनिक नाभिकीय सहयोग तथा व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विदेश मंत्री और उनकी अमरीकी समकक्ष विदेश मंत्री डॉ. कोंडोलिजा राइस ने 10 अक्तूबर, 2008 को वाशिंगटन में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए। यह करार द्विपक्षीय वार्ता के परिवर्तित स्वरूप का एक प्रतीक है और इसने हमारे संबंधों में सामरिक आयाम जोड़ा है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के लिए व्यापक अवसर भी उत्पन्न हुए हैं।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के

बीच संपर्क तो द्विपक्षीय कार्यसूची में प्राथमिकता के क्षेत्र थे ही साझे हित के वैश्विक मुद्दों पर भारत-अमरीका परामर्श, कार्य योजनाओं तथा ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय पहलकदमियों से भारत-अमरीका संबंध और संवर्धित हुए।

इस अवधि के दौरान अनेक उच्च-स्तरीय यात्राएं हुईं। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सितंबर, 2008 में वाशिंगटन का दौरा किया। राष्ट्रपति बुश के साथ अपनी बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और प्रधान मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान जारी जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में तथा राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान मार्च, 2006 में जारी संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित द्विपक्षीय कार्यसूची में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

अमरीकी विदेश मंत्री डॉ. कोंडोलिजा राइस ने अक्तूबर, 2008 में नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के साथ चर्चा की। श्री प्रणब मुखर्जी ने 24-25 मार्च, 2008 तक वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। उन्होंने अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की और राष्ट्रपति जार्ज बुश से भी मिले। उन्होंने वाशिंगटन स्थित एक विचार मंच कार्नेगी प्रतिष्ठान में चुनिंदा विद्वानों के एक समूह के साथ विचार-विमर्श किया। प्रधान मंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नवंबर, 2008 में वाशिंगटन का दौरा किया।

ओबामा प्रशासन ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए अमरीकी नागरिक अधिकारों के नेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15-24 फरवरी, 2009 तक अपना पहला प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. किंग के सबसे बड़े पुत्र डॉ. मार्टिन लूथर किंग।।। भी शामिल थे। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के लिए विशेष अमरीकी प्रतिनिधि राजदूत रिचर्ड हॉलब्रुक ने 15-16 फरवरी तक भारत का दौरा किया। उन्होंने 16 फरवरी को विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा विदेश सचिव के साथ मुलाकात की और उनके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा की।

कनाडा के प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर के नेतृत्व वाली कनाडा सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान भारत के साथ संबंधों में पर्याप्त सक्रियता आई और भारत के साथ संबंधों को विदेश नीतिगत प्राथमिकता प्रदान किया जाना जारी रहा। कनाडा के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम बर्नियर ने 10-12 जनवरी, 2008 तक भारत का दौरा किया। कनाडा के नागरिकता एवं आप्रवासन उप मंत्री श्री रिचर्ड बी फादेन ने 12-18 जनवरी, 2008 तक भारत का दौरा किया। कनाडा द्वारा आईएईए के साथ भारतीय सुरक्षोपाय करार का समर्थन किए जाने से भारत-कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय खुला और कनाडा ने भारत के साथ नाभिकीय व्यापार करने की अनुमति देने के संबंध में एनएसजी द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय का साथ दिया।

लैटिन अमरीका और कैरीबिया (एलएसी)

द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों तथा पारस्परिक आर्थिक हितों के संबंध में विद्यमान समानताओं के आलोक में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लैटिन अमरीकी और कैरीबियाई देशों के साथ हमारे संबंध और भी गहन हुए। राजनैतिक तथा सरकारी स्तर पर नियमित वार्ता के जरिए तथा दोनों पक्षों से व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, विशेषज्ञों एवं व्यावसायिकों के आदान-प्रदान के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में संपर्कों को सुविधाजनक बनाया गया। संयुक्त आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठकों तथा विदेश कार्यालय परामर्शों के जरिए संस्थागत स्तर पर संपर्क बनाए रखे गए। इस अवधि के दौरान 21 करार और समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए। भारतीय कंपनियों ने तेल एवं हाइड्रोकार्बन, आईसीटी, खनन, भेषज, कृषि, ऑटो उद्योग, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की। हमारी विकास भागीदारी तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग पहल के भाग के रूप में एलएसी देशों के लिए 160 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण श्रृंखला की सहायता की घोषणा की गयी और 2.125 मिलियन अमरीकी डालर की आपदा राहत सहायता वितरित की गयी। तीन एलएसी देशों में आईटी केंद्रों की स्थापना की गयी और कुल 382 आइटेक छात्रवृत्तियों की घोषणा की गयी और एलएसी उम्मीदवारों द्वारा इनका उपयोग किया गया। पूर्वी वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबॉल तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन एवं विकास गतिविधियों के लिए वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी और ओएनजासी विदेश के बीच संयुक्त उपक्रम करार पर हस्ताक्षर किया जाना, बी पी आर एल-वीडियोकोन संयुक्त उपक्रम द्वारा ब्राजील के 10 विदेशी ऑफशोर ब्लाक्स में कनाडा इनकाना कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी का अधिग्रहण, क्यूबा के 128 करोड़ रू0 के व्यावसायिक ऋण और ब्याज की माफी और इक्वाडोर को एचएएल द्वारा निर्मित 7 अत्याधुनिक हल्के (ध्रुव) हेलीकाप्टरों की बिक्री लैटिन अमरीकी देशों के साथ आर्थिक/व्यावसायिक संबंधों के महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे।

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रातिनिधिक स्वरूप और इसकी विश्वसनीयता एवं प्रभाविता में संवर्धन करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार की जारी प्रक्रिया पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। अन्य सदस्य राज्यों के सहयोग से भारत ने सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार लाने तथा महासभा को पुनः सक्रिय बनाने के लिए अन्य सदस्य राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनेक उच्च-स्तरीय यात्राएं हुईं। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सितंबर, 2008 में महासभा के 63वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 27 सितम्बर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यसूची के महत्वपूर्ण तत्वों की प्रगति पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न संकट तथा वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समन्वित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस तथ्य के संदर्भ में कि वर्ष 2008 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय की आधी अवधि बीत चुकी है, प्रधानमंत्री ने वैश्विक समृद्धि तथा हित-कल्याण के व्यापक स्वरूप पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का उल्लेख करते हुए इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करने के लिए पूरी दुनिया का आहवान किया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर

व्यापक अभिसमय (सी सी आई टी) को शीघ्र संपन्न किये जाने की आवश्यकता को पुष्टि की।

विदेश मंत्री ने 28 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2008 तक न्यूयार्क का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में भाग लिया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 25 सितम्बर, 2008 को आयोजित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की मध्यावधिक समीक्षा पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, श्री बान की मून ने 30-31 अक्तूबर, 2008 तक भारत का दौरा किया और 31 अक्तूबर, 2008 को राजीव गांधी स्मारक व्याख्यान दिया। उन्होंने दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4-6 फरवरी, 2009 को पुनः भारत का दौरा किया।

भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया कि वैश्विक वित्तीय मंदी और खाद्य एवं सुरक्षा बाजारों में आयी उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में विकास महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे। इस संबंध में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को संवर्धित सहायता, बाजार पहुंच, ऋण राहत प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने व्यापार, वित्त एवं आर्थिक निकायों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में और अधिक विकास पर बल दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों के समानुपातिक सरोकार और भागीदारी पर बल दिया।

भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा राष्ट्रमण्डल के साथ भी अपना सक्रिय क्रियाकलाप जारी रखा। विदेश मंत्री ने 27-30 जुलाई, 2008 तक तेहरान में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री कमलेश शर्मा, जिन्हें नवम्बर, 2007 में राष्ट्रमण्डल महासचिव चुना गया, ने 1 अप्रैल, 2008 को कार्यभार संभाला और वे 16-22 अक्तूबर, 2008 और 4-11 फरवरी, 2009 तक भारत का दौरा किया।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

इस अवधि के दौरान बहुपक्षीय मंचों की कार्यसूचियाँ मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल, खाद्य पदार्थों की उंची कीमतों तथा ऊर्जा संसाधनों की घटती-बढ़ती कीमतों से प्रभावित रही। भारत ने ए एस ई एम (एशिया-यूरोप बैठक); बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन मई, 2008) जी-8-05, जी-20, आई बी एस ए (भारत,ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका), आई ओ आर-ए आर सी (हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ), ए सी डी (एशिया सहयोग वार्ता) इत्यादि के साथ अपना सक्रिय क्रियाकलाप जारी रखा जिनमें इसने वित्तीय संकट तथा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में अपने विचार रखे। मार्च, 2007 में तेहरान में आयोजित आई ओ आर- ए आर सी मंत्रियों की सातवीं परिषद में घोषित भारतीय पहल के भाग के रूप में प्रथम आई ओ आर-ए आर सी फिल्म महोत्सव का आयोजन फरवरी-मार्च, 2008 तक नई दिल्ली में किया गया।

सचिव (आर्थिक संबंध) ने 10-11 मार्च, 2008 तक रियो डी जेनारियो में आयोजित ब्रिक उप विदेश मंत्रियों की तैयारी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। इस बैठक का उद्देश्य मई 2008 में रूस में आयोजित होने वाली ब्रिक विदेश मंत्रियों की प्रथम औपचारिक बैठक का रोडमैप तैयार करना था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत ने नई दिल्ली में दूसरे बिम्सटेक (13/11/2008) और तीसरे आई बी एस ए शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया। बीजिंग में आयोजित ए एस ई एम शिखर सम्मेलन, वाशिंगटन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन (15/11/2008) और ब्रिक देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के बीच होने वाले औपचारिक क्रियाकलापों में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीका) के अंतर्गत "सामनों के व्यापार" से संबद्ध करार पर वार्ता की समाप्ति को भारत की "पूर्वान्मुख" नीति में एक मील का पत्थर माना गया।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आइटेक) और विकास भागीदारी (डीपी)

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) कार्यक्रम भारत के तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रयासों का एक अग्रणी कार्यक्रम है। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और इसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा भागीदार देशों को प्रदान की जा रही तकनीकी और विकास सहायता को बढ़ाने और विस्तारित करने का प्रयास किया गया जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा अनुभवों के आदान-प्रदान पर बल दिया गया। इसमें एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमरिका में आइटेक के अंतर्गत 139 देश और स्कैप (विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत 19 देशों सहित 158 विकासशील देश शामिल है। 158 विकासशील देशों के सरकारी और निजी क्षेत्रों के लगभग 5000 व्यवसायिकों ने भारत के सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित 200 से अधिक असैनिक एवं रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। अफ्रीका, आई ओ आर-ए आर सी, सी आई एस, अफगानिस्तान, लाओ पी डी आर, यमन के लिए प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन संबंधी विषयों, श्रम लेखा-परीक्षा इत्यादि के संबंध में विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा-परीक्षा, कानूनी विशेषज्ञता, फार्माकोलोजी, सांख्यिकी एवं जनसंख्या विज्ञान, लोक प्रशासन, वस्त्र एवं कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया गया। इस वर्ष विश्व के विभिन्न भागों में सूचना प्रौद्योगिकी, लघु एवं मझोले उपक्रमों, सिविल विनिर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं चलाई गईं। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान की गई।

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन (आई टी पी)

एक-दूसरे के प्रति बढ़ती निर्भरता और एक-दूसरे से जुडे विश्व में विशेष स्थान क्षेत्र प्राप्त करते हुए, आर्थिक राजनय का भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। आई टी पी प्रभाग के जरिए मंत्रालय विदेशी निवेश एवं व्यापार को संवर्धित और सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से लगा रहा। इसने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की नीतिगत बैठकों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार तथा उदारीकरण तथा निवेश प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर आयोजित अन्य नीतिगत बैठकों में भाग लिया। आईटीपी प्रभाग ने निवेशक समुदाय के साथ संपर्क करके तथा निजी क्षेत्र, सर्वोच्च व्यावसायिक परिसंघों एवं विदेश स्थित हमारे मिशनों के सहयोग से संवर्धक कार्यक्रमों के आयोजन एवं वित्तपोषण के जरिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढावा देने के सरकार के प्रयासों को बढावा दिया। "भारत-गतिशील व्यावसायिक भागीदारः निवेशक हितैषी गंतव्य" जैसे विशेष प्रकाशनों इत्यादि तथा आई टी पी प्रभाग की वेबसाइटः www:indiabusiness.nic.in के जरिए एक निवेशक हितैषी देश के रूप में भारत की छवि को प्रस्तुत करते हुए विदेशी निवेश की प्रक्रिया को बढावा दिया गया।

लैटिन अमरीका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों को अनुदान एवं ऋण श्रृंखलाओं सहित अन्य प्रकार की विकास सहायता प्रदान करना हमारे आर्थिक राजनय का एक महत्वपूर्ण घटक रहा। इन विकासशील देशों में ठेके तथा सामानों की आपूर्ति के आदेश दिलवाने में भारतीय कंपनियों की सहायता करने के अतिरिक्त ऋण श्रृंखलाओं से इन क्षेत्रों के अवसंरचना विकास सहायता मिली है और इससे भारत के लिए सद्भावना का भी विकास हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान 16 विकासशील देशों के लिए 744 मि. अमरीकी डालर की 17 ऋण श्रृंखलाओं का अनुमोदन किया गया।

भारत के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को देखते हुए मार्च 2009 में अलग से एक ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा से जुडे मंत्रालयों और विदेश स्थित मिशनों के साथ समन्वय करना है। इस प्रभाग ने नवम्बर 2008 में हाइड्रोकार्बन पर भारत - सी आई एस गोलमेज बैठक तथा पेट्रोटेक 2009 का आयोजन किये जाने के लिए पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया, भारत के ऊर्जा विकल्पों पर सेमिनारों की मेजबानी/सह-मेजबानी की तथा ऊर्जा के अधिक्य वाले देशों तथा क्षेत्रों पर अध्ययन करवाया, अन्य मंत्रालयों तथा वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित सेमिनारों/सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और विदेशों में ऊर्जा सहयोग तथा अवसरों के लिए कार्य करने वाली कंपनियों को सहायता प्रदान की। इसने तेल एवं अवसंरचना क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऊर्जा पर एक कार्यकारी दल की स्थापना करने की भी पहल की।

नीति नियाजन एवं अनुसंधान

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग ने नीति अनुसंधान और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ क्रियाकलाप बनाये रखा और हमारी विदेश नीति की आयोजना, निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए बहुमूल्य सूचना सामग्रियाँ प्राप्त करने हेतु भारत के विदेश संबंधों तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सम्मेलनों, सेमिनारों, का आयोजन करने, शोध पत्र तैयार करने तथा विद्वानों का आदान-प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/विचार मंचों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग ने मंत्रिमण्डल के लिए मासिक सारांश निकालने का कार्य जारी रखा। प्रभाग ने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का संपादन और प्रकाशन करना भी जारी रखा। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विविध पहलुओं पर सरकार के विचारों सहित राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शेष विश्व के साथ भारत के क्रियाकलापों के संकलन का कार्य करता है।

इस प्रभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले स्थिति कक्ष का उपयोग मुम्बई संकट के दौरान 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2008 तक चौबीसों घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष के रूप में किया गया।

क्षेत्रीय प्रभागों को सीमा से जुड़े मामलों पर मानचित्रण संबंधी सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सीमा सैल की स्थापना की गई है। इसने भारतीय सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके भारत की विदेशी सीमाओं का चित्रण करने वाले नक्शों की जांच से संबंधित कार्य किया। इसने भारत की विदेशी सीमाओं को कवर करने वाले सीमा पट्टी नक्शों के लिए डेटा बेस बनाने का कार्य आरंभ किया है।

प्रोतोकोल

पूरे विश्व के साथ भारत के सक्रिय तालमेल को दर्शाते हुए राज्याध्यक्ष, उप-राष्ट्रपति, शासन प्रमुख और विदेश मंत्री स्तर पर वर्ष 2008 के दौरान भारत के 62 दौरे हुए और वर्ष के दौरान इन्हीं स्तरों पर विदेशों के 27 दौरे हुए। दिल्ली में तीन शिखर सम्मेलन आयोजित हुए- अप्रैल, 2008 में भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन; अक्तूबर, 2008 में तीसरा भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच शिखर सम्मेलन; और नवंबर, 2008 में बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन।

कोंसुली, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं

वर्ष के दौरान अमृतसर, देहरादून और कोयम्बटूर में 3 नए पासपोर्ट कार्यालय खोले गए। सभी 37 पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया और वे मशीनों द्वारा मुद्रित और मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।

वर्ष 2008-09 में कुल 53.15 लाख पासपोर्ट जारी किए गए जो कि वर्ष 2007-08 की समान अवधि के दौरान जारी पासपोर्टों की तुलना में लगभग 6.5% अधिक रही। सभी पासपोर्ट कार्यालयों से प्राप्त कुल राजस्व भी बढ़कर 606 करोड़ रू. हो गया, जो वर्ष 2007-08 में प्राप्त कुल राजस्व से लगभग 5.5% अधिक है।

मंत्रालय ने जनता की सुविधा के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया

को सरल एवं तेज बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने और सत्यापन की प्रक्रिया को प्रभावकारी रूप से बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर जिला पासपोर्ट सैल (डीपीसी) खोले गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की शुरूआत की गई है। वर्ष 2008 के दौरान आवेदकों के सहायतार्थ और साथ ही उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सुविधा काउंटर और हैल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

आशा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पासपोर्ट सेवा परियोजना के परिणामस्वरूप पुलिस सत्यापन के पश्चात तीन दिनों के भीतर नए पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सभी अन्य औपचारिकताएं एक दिन में पूरी हो सकेगी। पायलट परियोजना जुलाई-अगस्त, 2009 तक चंडीगढ़ और बेंगलूर में शुरू होने की आशा है। पूरे देश में 2010 तक यह पूर्णतः कार्यान्वित हो जाएगी।

मंत्रालय ने विदेश स्थित 140 भारतीय मिशनों/केन्द्रों के संबंध में सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली में मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों की केन्द्रीकृत मुद्रण परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में सभी राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट अब ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किया जा रहे हैं। प्रस्ताव है कि इस पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्ष 2009 के अंत तक सामान्य वर्ग में ई-पासपोर्ट जारी होने शुरू हो जाएंगे। वर्ष 2008 के दौरान मिस्र, अल-सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, दक्षिण अफ्रीका और टर्की के साथ वीजा से छूट संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्राजील, आस्ट्रेलिया, ईरान और मिस्र के साथ प्रत्यार्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय के चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहटी स्थित शाखा सचिवालय कार्यालयों में 15 जून, 2008 से साक्ष्यांकन और टिप्पणी कार्य भी प्रारंभ हो गया। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 1,70,000 निजी एवं शैक्षिक दस्तावेजों और 1,71,000 वाणिज्यिक दस्तावेजों का साक्ष्यांकन किया गया। इसके अलावा विदेशों में सदस्य देशों में उपयोग किए जाने के लिए 80,000 दस्तावेजों की टिप्पणी तैयार की गई।

प्रशासन

विदेशों में अभी 171 आवासीय भारतीय मिशन एवं केंद्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान आइसलैंड में एक आवासी भारतीय मिशन खोला गया जबकि नाइजर, माली और ग्वाटेमाला में निकट भविष्य में तीन नए मिशन खोले जाने हैं। भारत में बढ़ती राजनीतिक जिम्मेदारियों को नजर में रखते हुए कार्मिकों की अत्यधिक कमी के समाधान के उद्देश्य से मंत्रालय में 514 अतिरिक्त पदों को चरणबद्ध विधि से शामिल करने के लिए एक 10 वर्षीय योजना तैयार की गई है।

मंत्रालय में नियमों, विनियमनों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आतंरिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। विदेश मंत्रालय का भावी मुख्यालय अर्थात जवाहरलाल नेहरू भवन और कैनिंग लेन, नई दिल्ली स्थित पारगमन आवास का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी रहा। मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक आवासीय परिसर, एफ्रो-एशियाई विधि परामर्शदात्री समिति का मुख्यालय भवन और चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में इसके महासचिव का आवास और कोलकाता में आई.सी.सी.आर. के क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य पूरा हो गया। विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए संपत्तियों की खरीद और निर्माण के कार्य में और तेजी लायी गई ताकि किराए पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके। विदेशों में निर्माणाधीन परियोजनाओं में शामिल हैं- काबुल, बीजिंग, टोक्यो, काठमांडु, लंदन और सिंगापुर में चांसरी/आवासीय परियोजनाएं।

समन्वय

समन्वय प्रभाग ने राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों, न्यायिक सेवा के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरे के लिए 21% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 2539 राजनीतिक अनुमोदन जारी किया। प्रभाग ने गैर-अधिसूचित विदेश उड़ानों के लिए अप्रैल-नवंबर, 2008 के दौरान 13% की वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए 971 अनापत्तियां भी जारी कीं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2008 में विदेश मे डेफेक्सपो इंडिया-2008 और फरवरी, 2009 में बंगलौर में आयोजित एयरो इंडिया-2009 प्रदर्शनी के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के साथ तालमेल स्थापित करने में मंत्रालय के समन्वय प्रभाग ने रक्षा मंत्रालय की सहायता की।

विदेश प्रचार

प्रभाग के अधिकतर कार्यकलाप भारत के उसके निकटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के प्रमुख देशों के साथ संबंधों से जुड़ी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित थे। प्रभाग ने मुख्यालय में सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिए मीडिया मानीटरिंग परियोजना के पहले चरण की शुरूआत की। इसका उद्देश्य मंत्रालय के लिए मीडिया संसाधनों की मानीटरिंग को सुव्यवस्थित करना था। यह परियोजना प्रिंट, वेब और इंटरनेट आधारित मीडिया पर सुप्रणालीबद्ध ढंग से नजर रखती है और वास्तविक काल आधार पर उपयोगकर्त्ताओं को 5 दैनिक उत्पाद प्रदान करता है।

प्रभाग ने ईरान के राष्ट्रपति श्री अहमदनिजाद, सीरिया के राष्ट्रपति डा. बशर अल-असद; मिस्र के राष्ट्रपति श्री हुस्नी मुबारक; नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहाल "प्रचंड" भूटान के प्रधानमंत्री श्री लियोनचेन जिग्मी वाई. थिनले और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री अनातोली मेदवेदेव की यात्राओं से मिले अवसरों का उपयोग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए किया। प्रभाग ने इन यात्राओं के दौरान दौरे पर आए गणमान्य अतिथियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी आयोजित की। भारत की चिंता वाले महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष ब्रीफिंग कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए गए।

राष्ट्रपति की ब्राजील, मैक्सिको, चिली, वियतनाम और इंडोनेशिया यात्रा; प्रधानमंत्री की भूटान, जापान (जी-8 शिखर बैठक), श्रीलंका (15 वें सार्क शिखर सम्मेलन), अमरीका और फ्रांस (संयुक्त राष्ट्र महासभा और असैनिक नाभिकीय सहयोग करार), चीन, ओमान और कतर (द्विपक्षीय) यात्रा; उप-राष्ट्रपति की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा और विदेश मंत्री की सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस, आस्ट्रेलिया, मिस्र और अमरीका की यात्रा पर मीडिया के प्रतिनिधिमंडल को एक्सपी प्रभाग द्वारा सुविधाएं प्रदान की गईं। विदेश मंत्री, विदेश सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया के लिए विशेष ब्रीफिंग का कार्यक्रम भी आयोजित किए। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टी.वी. संगठनों के साथ प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री, विदेश राज्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए।

लोक राजनय

लोक राजनय प्रभाग, भारत के बाहर और भारत में आउटरीच कार्यकलापों के अपने अधिदेश को पूरा करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारत की विदेश नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से परिलक्षित करने के लिए मुद्रित प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से भारत में और अन्य देशों में शोधकर्त्ताओं, बुद्धिजीवियों, सभ्य समाज, मीडिया और उद्योग जगत के सहयोग से कार्य करता है।

प्रभाग ने भारत की विदेश नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से परिलक्षित करने और अन्य देशों के साथ ट्रैक-II तालमेल बिठाने में सहायता देने के लिए कई संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया। प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भारतीय एवं विदेशी शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्त्ता, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत और मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेपाल, अफगानिस्तान, कजाखस्तान, पाकिस्तान और इथियोपिया के साथ हमारे संबंधों पर सम्मेलन आयोजित करना प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप थे। प्रभाग ने शीत युद्ध के परिणाम, पूर्वोत्तर विकास, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे भिन्न-भिन्न विषयों पर भी सम्मेलन आयोजित किए। आधुनिक भारत और हमारी चिंताओं से अन्य देशों के नीति एवं मत निर्माताओं को परिचित कराने के उद्देश्य से प्रभाग ने यू.के., मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, तजाकिस्तान और ताइवान के साथ-साथ 16 देशों से आए भारतीय मूल के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं की मेजबानी की।

प्रभाग ने भारतीय संस्कृति एवं विरासत के साथ-साथ हमारी रूचियों को प्रदर्शित करने वाले वृत्तचित्रों का भी निर्माण कराया। प्रभाग द्वारा निर्मित कुछ वृत्तचित्रों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में प्रदर्शित किया गया और उन्हें विशेष पुरस्कार/विशेष उल्लेख से नवाजा गया। प्रभाग की प्रमुख पत्रिका "इंडिया पर्सपेक्टिव" जिनमें भिन्न-भिन्न विषयों के लेख छपते हैं, ने अपने 20 वर्ष पूरे किए; एक वर्षगांठ अंक और दो विशेषांक भारतीय प्रकाशन और भारतीय सिनेमा पर प्रकाशित किए गए।

विदेश सेवा संस्थान (एफ.एस.आई.)

विदेश सेवा संस्थान ने भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों, राजनयिक संवाददाताओं, पुलिस अधिकारियों, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय/विभागों के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। दक्षिणी सूडान के अधिकारियों, आसियान राजनयिकों और नार्वे के राजनयिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ विदेशी राजनयिकों के लिए विशेष व्यावसयिक पाठ्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 48वें पाठ्यक्रम में भाग ले रहे विदेश से आए अधिकारियों ने एफ.एस.आई. का दौरा किया और उनके लिए एक व्याख्यान आयोजित किया गया।

एफ.एस.आई. और उक्रैन के उनके समकक्ष संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बंग्लादेश, रोमानिया और चीन के प्रतिनिधिमंडलों ने एफ.एस.आई. का दौरा किया। इब्सा (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) के राजनयिक संस्थानों के डीन की दूसरी बैठक एफ.एस.आई. में सितम्बर, 2008 में आयोजित की गई। इस अवसर पर "भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका सहयोगः चुनौतियां एवं अवसर" विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई।

सांस्कृतिक संबंध

परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ स्थापित और पुनर्जीवित करना तथा उसे मजबूत बनाना है। परिषद की प्रमुख परियोजना, रबीन्द्रनाथ टैगोर केंद्र का उद्घाटन पूर्व विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा एक जून, 2008 को किया गया। भा.सां.सं.परि. ने अपनी "छः-सूत्रीय विस्तार योजना" का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है जिसके लिए उसे 75 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं।

परिषद ने भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इब्सा शिखर सम्मेलन, अरब लीग की बैठक इत्यादि जैसे बड़े सम्मेलनों के दौरान भारतीय और विदेशी मंडलियों के साथ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसने दक्षिण एशिया सांस्कृतिक उत्सव का भी समन्वय किया और अति महत्वपूर्ण विशिष्ट आगंतुकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। कई उत्सव आयोजित किए गए जैसे कि श्रीनगर में सूफी संगीत उत्सव, मल्हार उत्सव और भारत में रह रहे विदेशी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव। "भारत में रूस वर्ष" का आयोजन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें कई उच्च स्तरीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। इसके अलावा, परिषद ने भिन्न-भिन्न देशों की 50 सांस्कृतिक मंडलियों की मेजबानी की जिनके कार्यक्रम दिल्ली और अन्य शहरों में आयोजित किए गए। परिषद ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। परिषद ने विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत भिन्न-भिन्न देशों से आए 19 सुविख्यात अतिथियों की मेजबानी की।

विदेश स्थित 21 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों ने भारत की "साफ्ट पावर" को बढ़ावा देने में पूरी मेहनत लगा दी। बीजिंग स्थित भारतीय राजदूतावास का विस्तारित सांस्कृतिक विंग वर्ष के दौरान प्रकार्यात्मक हो गया और बैंकाक, क्वालालम्पुर, टोक्यो और ढाका में नए सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की तैयारी की गई है।

परिषद ने सीरिया, मिस्र, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और हंगरी इत्यादि देशों में विविध एवं भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाले कई सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन किया। "रूस में भारत वर्ष" का उद्‌घाटन 31 मार्च, 2009 को मास्को में अध्यक्ष, भा.सां.सं.परि. द्वारा किया गया। परिषद ने 93 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित किया जिन्होंने 73 देशों की यात्रा की, साथ ही कई उत्कृष्ट कलाकारों की विदेश यात्राएं भी प्रायोजित की और उन्हें यात्रा अनुदान दिया। विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में परिषद के 21 दीर्घकालिक एवं 12 अल्पकालिक भारतीय अध्ययन पीठ निरंतर चले रहे।

भा.सां.सं.परि. का प्रमुख ध्यान विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने को सुविधाजनक बना रहा है। वर्ष 2008-09 में, भा.सां.सं.परि. ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 3200 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसमें अफगानी छात्रों के लिए 500 छात्रवृत्तियां सहित 1778 नई छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

परिषद ने भारत के पूर्वी भाग और पूर्वोत्तर में अपना संपर्क बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कटक और शिलांग में दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। परिषद ने भारतीय और विदेशी कला एवं मूर्तिकला को प्रदर्शित करते हुए बड़ी प्रदर्शनियां भी लगाईं; भिन्न-भिन्न 5 भाषाओं में 6 पत्रिकाओं का प्रचार-प्रसार किया और साथ ही भारत में 24 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं की भी सहायता की।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने 18 नवंबर, 2008 को अरब मिस्र गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हुस्नी मुबारक को अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए वर्ष 1995 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया। "एक नई अहिंसक क्रांति" विषय पर श्री मार्टिन लूथर किंग-III द्वारा मौलाना अबुल कलाम स्मारक व्याख्यान, 2009 दिया गया।

भारतीय विश्व-कार्य परिषद (आई.सी.डब्ल्यू.ए.)

भारतीय विश्व-कार्य परिषद ने भारत के विदेश मामलों पर चर्चा करने के लिए एक विचार-मंच और महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकास करना जारी रखा। आई.सी.डब्ल्यू.ए. ने द्विपक्षीय सहयोग के 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, नामतः अफगानिस्तान के विदेश कार्य मंत्रालय के सामरिक अध्ययन केन्द्र के साथ, न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वेलिंगटन, आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मेलबर्न, दी एमीरात्स सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च, आबू धाबी, एशिया सेंटर; बंगलौर, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र, चंडीगढ़। "राजनीतिक आधुनिकीकरण की समकालीन प्रक्रियाः मध्य एशियाई राज्यों और भारत के अनुभव" पर भारत-मध्य एशिया प्रतिष्ठान (आई.सी.ए.एफ.), आईसीडब्ल्यूए और अल्माटी, कजाकिस्तान के अल-फराबी कजाख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के बीच परिषद ने एक संयुक्त अध्ययन प्रायोजित किया। परिषद ने 7 व्याख्यान, 9 संगोष्ठी/सम्मेलन, 6 द्विपक्षीय वार्ताएं एवं 14 बैकग्राउड ब्रीफिंग, पुस्तक लोकार्पण/पैनल चर्चा आयोजित की। बड़ी संख्या मं विद्वानों एवं छात्रों द्वारा आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय का उपयोग करना जारी रहा।

ई-जी एवं सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, मास्को, दोहा, वाशिंगटन, सान फ्रांसिस्को, शिकागो और ह्यूस्टन में पासपोर्ट एवं वीजा सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य पूर्ण हो गया। जद्दा में पासपोर्ट सेवाओं के आउटसोर्सिंग का कार्य पूरा हो गया। वर्ष के दौरान लंदन, मास्को, दुबई, आबूधाबी, जद्दा, रियाद, कुवैत, क्वालालम्पुर और सिंगापुर में पासपोर्ट/वीजा सेवाओं को आउटसोर्स पर देने का कार्य पूरा हो गया।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर.आई.एस.)

एक स्वायत्तशासी नीति विचार-मंच के रूप में आर.आई.एस. ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीति अनुसंधान किया और अन्यों के साथ-साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इब्सा शिखर सम्मेलन, सार्क और बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन संबंधी वार्ता, सीईपीईए के ट्रैक-II अध्ययन दल जैसी प्रमुख शिखर बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण वार्ताओं की तैयारी में विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। इसने एशिया के शीर्ष नीति विचार-मंचों के साथ सहयोग कर एशियाई आर्थिक समुदाय के लिए सार्थकता और आगे के दिशा-निर्देशों पर नीति वार्ता आयोजित करना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों एवं विकास सहयोग पर नीतिगत सांमजस्य और क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों के नीति संबंधी विचार-मंचों को नेटवर्क से जोड़ा।

■■

भारत के पड़ोसी देश

1

अफगानिस्तान

द्विपक्षीय संबंध

अफगानिस्तान सरकार के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे गए। अफगानिस्तान में हमारे विकास और पुनर्निर्माण सहायता कार्यक्रम को अफगानी जनता के सभी वर्गों ने व्यापक तौर पर सराहना की है। सुरक्षा स्थितियों में गंभीर गिरावट देखी जाने के बावजूद भारत अफगानिस्तान सरकार और वहां की जनता को एक स्थायी, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज के निर्माण में सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी बना रहा। अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थितियों की गिरावट का 7 जुलाई, 2008 को भारत के राजदूतावास पर हुए हमले के बाद भारत पर सीधा प्रभाव पड़ा।

अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम हामिद करजई ने 3 से 5 अगस्त, 2008 को भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति करजई का दौरा 7 जुलाई, 2008 को काबुल में भारतीय राजदूतावास पर आतंकी हमले के कुछ समय बाद ही हुआ था। भारत और अफगानिस्तान ने एकजुट होकर और अपनी पूरी शक्ति से आतंकवाद से लड़ने का अपना दृढ़निश्चय जाहिर किया। प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान के प्रति भारत की सारी बचनवद्धताएं पूरी की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने पहले से चल रही और भावी परियोजनाओं की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त सहयोग देने का वचन दिया(जो पहले घोषित 750 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त है)।

राष्ट्रपति करजई ने 11 से 12 जनवरी, 2009 को पुनः भारत का कार्यकारी दौरा किया और मुम्बई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और भारत की जनता के प्रति अफगानिस्तान की एकजुटता व्यक्त की। दौरे के अंत में जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति श्री करजई और प्रधानमंत्री ने अपने नियंत्रण के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए राष्ट्रों की द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पूर्ण अनुपालन किये जाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की जनता को मौजूदा खाद्य संकट से उबरने में मदद के लिए 250000 मीट्रिक टन गेहूं उपहारस्वरूप देगा। भारत में अध्ययन करने/ पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने के लिए अफगान राष्ट्रिकों को दी जा रही शिक्षा और तकनीकी छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने संबंधी अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति करजई ने प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह को अफगानिस्तान का राजकीय दौरा करने के लिए भी न्यौता दिया।

पंचायती राज मंत्री ने मई, 2008 में अफगानिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान स्थानीय शासन के एक समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किये गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एन.गोपालास्वामी ने अप्रैल, 2008 में अफगानिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों निर्वाचन आयोगों के बीच सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

राजदूतावास पर आतंकी हमला

7 जुलाई, 2008 को सुबह काबुल स्थित हमारे राजदूतावास पर एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें राजदूतावास के 5 कर्मचारी मारे गए। लगभग 60 अफगानी राष्ट्रिकों की भी इस हमले में मौत हो गई। भारतीय राजदूतावास पर हमला अफगानिस्तान में हुए भीषणतम आतंकी हमलों में एक था। अफगानिस्तान सरकार द्वारा की गई छानबीन और हमारे साक्ष्यों से भी यह साबित हो गया कि यह हमला सुनियोजित था और इसे पाकिस्तान में बसे तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया, यह तथ्य इसे एक खतरनाक और अस्वीकार्य स्थिति बनाता है।

अफगानिस्तान को भारत की सहायता

भारत अफगानिस्तान सरकार जनता को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में, और एक स्थिर, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राजव्यवस्था स्थापित करने में, सहायता के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी रहा है। विदेश राज्य मंत्री ने जून, 2008 में पेरिस में आयोजित अफगानिस्तान की सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारत अफगानिस्तान को विकास सहायता का समन्वयन करने संबंधी विभिन्न बहुपक्षीय बैठकों में सक्रिय भागीदारी करता रहा जिनमें अन्यों के साथ-साथ संयुक्त समन्वयन और प्रबोधन बोर्ड की बैठकें शामिल थी। भारत ने पेरिस में दिसंबर, 2008 में आयोजित अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

7 जुलाई, 2008 को भारतीय राजदूतावास पर हुए आतंकी हमले और राजदूतावास, कोंसलावास, परियोजनाओं और कार्मिकों को मिल रही सुरक्षा संबंधी धमकियों के बावजूद अफगनिस्तान

के पुनर्निर्माण और विकास पर भारत की वचनबद्धता अप्रभावित रही। प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2008 में राष्ट्रपति करजई के भारत दौरे के दौरान 450 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की जिससे भारत के व्यापक विकास सहायता कार्यक्रम के लिए भारत की ओर से अफगानिस्तान को दी गई कुल सहायता राशि बढ़कर 1.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। नवंबर, 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी अफगानिस्तान के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी जो बहुलतावाद और लोकतंत्र के प्रति दोनों देशों की साझी वचनबद्धता का प्रतीक है। यह परियोजना शुरू हो चुकी है।

पूर्ण की गई परियोजनाएं

निरुत्साही संभारतंत्रीय और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बावजूद जारंज से डेलाराम तक 218 किमी लंबी सड़क के निर्माण हेतु एक बड़ी बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजना, सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। सड़क का लोकार्पण 22 जनवरी 2009 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

एक अन्य बड़ी बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजना पुल-ए-खुमरी से काबुल तक की 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन और साथ ही चिम्टाला में एक उप-स्टेशन के कार्य निष्पादन में जो काबुल को उजबेकिस्तान से विद्युत की आपूर्ति करेगा- में उल्लेखनीय प्रगति हुई है (जिसके अप्रैल, 2009 में पूर्ण हो जाने की आशा है)।

नई योजनाएं

राष्ट्रपति करजई के जनवरी 2009 में भारत दौरे के दौरान भारत ने 250,000 मीट्रिक टन गेहूं देने की घोषणा की थी ताकि अफगानिस्तान की जनता को मौजूदा खाद्य संकट से उबरने में मदद मिल सके।

मई, 2008 में दोनों देशों के बीच स्थानीय शासन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

22 अप्रैल, 2008 को दोनों देशों के निर्वाचन आयोगों के बीच सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अफगानिस्तान में चुनाव के लिए भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र न्यास कोष में 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि सहायता स्वरूप दी है।

क्रियान्वयन अधीन प्रमुख परियोजनाएं

हेरात प्रांत में सलमा बांध विद्युत परियोजना (42 मेगावाट) के निर्माण का कार्य चलता रहा।

मानवीय सहायताः मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को एक मिलियन टन गेहूं प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता के हिस्से के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रोटीनयुक्त बिस्कुट बांटने का पहले से चल रहा स्कूल आहार कार्यक्रम चलता रहा। अब स्कूल के कार्य दिवसों पर लगभग 2 मिलियन स्कूली बच्चों को भारतीय बिस्कुट दिये जाते हैं और इसके दायरे में अफगानिस्तान के 34 में से 32 प्रांत शामिल हैं। भारत ने अप्रैल, 2008 में जन स्वास्थ्य मंत्रालय को 10 एम्बुलेंस दान दी। जलालाबाद प्रांत स्थित स्कूलों को 30,000 डेस्क-सह-बेंच की आपूर्ति नवंबर, 2008 में शुरू की गई।

काबुल, कंधार, जलालाबाद, मजार-ए-शरीफ और हेरात स्थित 5 भारतीय चिकित्सा मिशनों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं और दवाएं प्रदान की जाती रहीं और काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का पुनर्निर्माण विभिन्न चरणों में चलता रहा।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

आईसीसीआर द्वारा संचालित भारतीय छात्रवृत्ति योजना और आईटीईसी के अधीन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों ही प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाते रहे। चालू वर्ष में अफगानिस्तान के लिए प्रस्तावित 500 आईसीसीआर छात्रवृत्तियों में से 493 छात्रवृत्तियों का लाभ भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अफगानी उम्मीदवारों द्वारा उठाया गया। आईटीईसी के अधीन अफगानिस्तान को 500 वार्षिक अंशकालिक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत अफगानी पेशेवर लोगों के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, मानव संसाधन योजना भू-सूचना एवं मानव संसाधन योजना और विकास, कपड़ा मिल प्रबंधन, विकास पत्रकारिता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सूक्ष्म उद्यमों का संवर्धन आदि जैसे क्षेत्र शामिल थे।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईए) की कौशल विकास परियोजना के तहत 1000 अफगानों का निर्माण कार्यों से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण देने और स्वनियोजित महिला संघ (सेवा) द्वारा काबुल में बाग-ए-जनाना में एक महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके 1000 अफगानी महिलाओं को कपड़ा बनाने, फल प्रसंस्करण और बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना जून, 2008 में लोकार्पित की गई। 2002 से लगभग 3150 अफगानियों ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया/ अध्ययन किया।

लघु विकास परियोजनाएं

कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में समुदाय आधारित लघु विकास परियोजना स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से चलता रहा। चरण- I (2006-2008) के अंतर्गत ऐसे 50 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और उनका निष्पादन किया जा रहा है।

चरण- II (2008-2010) के अंतर्गत 50 से अधिक अन्य परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत, अफगान पुनर्निर्माण ट्रस्ट निधि के लिए 200,000 अमरीकी डालर का वार्षिक योगदान करता रहा है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई 4 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात करते हुए।

भूटान के प्रधानमंत्री लियोंनछेन जिग्मी 16 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में
केंद्रीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए।

भारतीय संस्कृति केंद्र

भारतीय राजदूतावास पर आतंकी हमले के बावजूद भारत संस्कृति केंद्र (आईसीसी) के कार्यकलाप और भारतीय शिक्षकों द्वारा शास्त्रीय संगीत और योग की कक्षाएं चलती रहीं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहे।

बांग्लादेश

भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र को पूरी तरह बहाल किए जाने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव की अपनी आशा को दोहराते हुए बांग्लादेश की कामचलाऊ सरकार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को व्यापक दायरे में सार्थक ढंग से उठाता रहा। एक यादगार अवसर पर दोनों देशों ने 43 वर्षों बाद कोलकाता और ढाका के बीच 14 अप्रैल, 2008 को यात्री रेल सेवा "मैत्री" की पुनः शुरुआत की।

बांग्लादेश के विदेश सचिव ने 17 जुलाई, 2008 को वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श के लिए भारत की यात्रा की जिसमें सुरक्षा, व्यापार, पारगमन और सम्पर्क बहाल करने से जुड़े मसलों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई।

भारत खास तौर पर भारतीय उपद्रवी ग्रुपों द्वारा तथा दूसरे राष्ट्रों के आतंकियों द्वारा बांग्लादेशी भूक्षेत्र के प्रयोग किए जाने संबंधी अपनी सुरक्षा चिंताओं को बांग्लादेश के साथ जोरदार ढंग से उठाता रहा। दोनों पक्षों ने सुरक्षा से जुड़े कार्यात्मक मसलों पर चर्चा के लिए संयुक्त कार्य दल को पुनर्जीवित किया और नई दिल्ली में 29-30 मई, 2008 को इसकी एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद 29 से 31 अगस्त, 2008 को ढाका में गृह सचिव स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की गई।

दोनों देशों ने अपने-अपने सीमा सुरक्षा बलों के द्विवार्षिक डी.जी.-स्तरीय सीमा समन्वयन सम्मेलनों के माध्यम से सीमा प्रबंधन से जुड़े कार्यात्मक मसलों पर चर्चा को जारी रखा। ये सम्मेलन क्रमशः नई दिल्ली में 11-12 अप्रैल, 2008 और ढाका में 20-25 अगस्त, 2008 को आयोजित किये गए। सीमा/व्यापार अवसंरचना पर द्विपक्षीय उपसमूह की पहली बैठक ढाका में 6-7 अगस्त, 2008 को आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान, दोनों पक्षों के बीच 15-27 सितंबर, 2008 को 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद समुद्री सीमा संबंधी तकनीकी स्तर की बैठक भी आयोजित की गई।

सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने 28 जुलाई से 1 अगस्त, 2008 तक बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

नई दिल्ली में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप भारत ने 1 जनवरी, 2008 से बांग्लादेश सहित सार्क क्षेत्र में न्यूनतम विकसित देशों से भारत में होने वाले निर्यात पर से शुल्क हटा लिया जिसमें भारत की संवेदी सूची में शामिल कुछ मदों को नहीं रखा गया है। बांग्लादेश के साथ हुआ 2007 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन जिसके अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष के दौरान बांग्लादेश से भारत को 8 मिलियन तक सजावटी सामानों के आयात को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया था, भी अप्रैल, 2008 से प्रभावी हो गया।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने ढाका चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए 31 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2008 तक ढाका की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समकक्षों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने 11-13 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वायु सेवा करार की समीक्षा की और दोनों देशों के नियत कैरियरों द्वारा चुनिंदा गंतव्यों की उड़ानों की संख्या को बढ़ाकर सप्ताह में 61 किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सार्क क्षेत्र में संपर्क को बढ़ावा देने की भारत की नीति की तर्ज पर भारत दोनों देशों के बीच परिवहन और व्यापार संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के प्रस्तावों की वकालत करता रहा। अंतःदेशीय जल परिवहन और व्यापार पर द्विपक्षीय प्रोतोकाल के अंतर्गत स्थायी समिति की 10वीं बैठक ढाका में 26-27 मई, 2008 को आयोजित की गई।

बांग्लादेश के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबरने में मदद के लिए द्विपक्षीय सहायता और सहयोग प्रदान किया। भारत की सहायता में 1000 मीट्रिक टन स्किमयुक्त दूध का पाउडर और 40000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति शामिल था। भारत ने बांग्लादेश में 11 चक्रवात प्रभावित गांवों के पुनर्वास हेतु 2800 रिहायशी मकानों, प्रसाधन और 22 ट्यूबवेलों के निर्माण की परियोजना भी शुरू की है और साथ ही ढाका विश्वविद्यालय के रंगमंच और संगीत विभाग के लिए एक कला भवन के निर्माण की परियोजना भी शुरू की गई है।

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 फरवरी, 2009 को ढाका का दौरा किया। बांग्लादेश में 29 दिसम्बर, 2008 को हुए आम चुनावों के बाद महामहिम शेख हसीना के अधीन बनी नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह भारत की ओर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री नव निर्वाचित सरकार के कई नेताओं से मिले जिनमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री शामिल

थे और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें सुरक्षा कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश और आम जनों के बीच सम्पर्क जैसे मुद्दे शामिल थे। दो करारों अर्थात् (i) व्यापार करार और (ii) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार(बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री ने भारत द्वारा चक्रवात "सिद्र" से प्रभावित 11 बांग्लादेशी गांवों में बनाए जाने वाले 2800 कोर रिहायशी मकानों के मॉडल का अनावरण किया और ढाका विश्वविद्यालय में कला भवन के निर्माण हेतु एक फलक का भी अनावरण किया।

लोकसभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी ने 21-23 फरवरी, 2009 को ढाका की यात्रा की। लोकसभा अध्यक्ष ने "नवीं जातीय संसद हेतु संसदीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम" के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश संसद के सदस्यों को संबोधित किया और बांग्लादेश ने कई नेताओं से मुलाकात की।

भूटान

रिपोर्ट अवधि के दौरान भारत और भूटान ने नजदीकी परामर्शों, परिपक्वता, पूर्ण विश्वास और परस्पर समझादारी के साथ अपने विलक्षण निकट और सौहार्द्रपूर्ण रिश्ते को बनाए रखा। वर्ष के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू की 1958 में भूटान यात्रा की स्वर्ण जयंती और भूटान के पांचवें नरेश के राज्याभिषेक और वांगचुक राजवंश की 100वीं वर्षगांठ के अवसरों पर ये रिश्ते और भी प्रगाढ़ हुए। दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर नियमित दौरों और विचारों के आदान-प्रदान की परम्परा को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय दौरे किये गए जिससे हमारे आर्थिक और राजनैतिक संबंधों में मजबूती आई।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने विदेश मंत्री और यूपीए की अध्यक्षा के साथ भूटान की शाही सरकार के आमंत्रण पर 5-8 नवंबर, 2008 को भूटान का दौरा किया और भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के औपचारिक राज्याभिषेक में हिस्सा लिया। भारत सरकार ने भूटान नरेश के राज्याभिषेक के आयोजनों के हिस्से के रूप में कई संगीत कार्यक्रम, फुटबाल मैच आदि का सीधा प्रसारण प्रायोजित किए।

अप्रैल, 2008 में भूटान के लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने 16-17 मई, 2008 को पहले विदेशी प्रतिनिधि के रूप में भूटान की यात्रा की और भूटान नरेश और भूतपूर्व नरेश से मिले और साथ ही खास तौर पर पनबिजली क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सघन करने के संबंध में सकारात्मक चर्चा की। ताला पनबिजली परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करने और पुनात्सांगछु पनबिजली परियोजना का शिलान्यास करने के अलावा प्रधानमंत्री ने भूटान से भारत को 5000 मेगावाट (2006 के समझौते के अनुसार) के पनबिजली निर्यात के लक्ष्य को बढ़ाकर 2020 तक 10,000 मेगावाट किए जाने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा भी की, कि भारत सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी जिसका उपयोग भूटान की 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की सहायता और पनबिजली एवं अवसंरचना की बड़ी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत और भूटान के बीच पहले रेल मार्ग के निर्माण के लिए भारत सरकार की सहायता की भी वचनबद्धता व्यक्त की- जो भारत हाशीमारा से भूटान में फूण्टशोलिंग को जोड़ने वाली स्वर्ण जयंती रेल लाइन होगी और साथ ही भारत स्थित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले मेधावी भूटानी छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिष्ठित नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति की और थिम्पू में मेडिकल कालेज की स्थापना की भी वचनबद्धता व्यक्त की।

विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे भूटान में पनबिजली परियोजनाओं में लगे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में 4-7 दिसंबर, 2008 को भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री के आमंत्रण पर थिम्पू गए। उसके बाद विदेश सचिव 14-15 फरवरी, 2009 को भूटान गए और द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जिनमें खास तौर पर विकास सहायता और दोनों देशों के बीच पनबिजली सहयोग के मुद्दे शामिल थे।

भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन जिग्मी वाई.थिनली ने लोकतांत्रिक विधि से चुने गए भूटान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने चयन के बाद 14-17 जुलाई, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री थिनली ने नई दिल्ली में आयोजित दूसरे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 12-14 नवंबर, 2008 को फिर से भारत की यात्रा की। भूटान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष ल्योन्पो जिग्में सुल्टिम की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त से 5 सितंबर, 2008 को भी भारत की यात्रा की जबकि भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ल्योन्पो जांग्ले दुक्पा ने 11-18 सितंबर, 2008 को भारत की यात्रा की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाया। उसके बाद 15-21 दिसंबर, 2008 को भूटान के अटार्नी जनरल अध्ययन दौरे पर भारत आए।

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना रहा। भूटान की नवीं योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को भारत की सहायता से क्रियान्वित किया जाना था उनमें संतोषपूर्ण प्रगति रही। सेम्टोखा जोंग, थिम्पू और मोंगार क्षेत्रीय रेफरल अस्पताल, युवा केंद्र, रिन्यू केंद्र और राष्ट्रीय म्यूजियम के लिए प्रदर्शनी हाल ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं जिन्हें पूर्ण किया गया। दोनों सरकारों के बीच भूटान की दसवीं योजना के लिए भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं चलाए जाने के लिए भी सहमति हुई। भारत सरकार नवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना के दौरान भूटान को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि को दो गुणा करके 3400 करोड़ रु. करने के लिए राजी हो गई। भारत सरकार ने भूटान की शाही सरकार के साथ मार्च, 2008 में एक समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर भी किया जिसके अंतर्गत भूटान की शाही सरकार को स्टेंडबाई क्रेडिट सुविधा के रूप में 300 करोड़ रु. दिए जाएंगे ताकि भूटान की शाही सरकार अपने रुपए के भंडार की कमी को पूरा कर सके। असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और भूटान की शाही सरकार के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में सहयोग बना रहा। भारत भूटान के लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र बनने के दौरान परिवर्तन की स्थितियों में सहायता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध बना रहा।

भूटान में पनबिजली विकास पर अधिकार प्राप्त संयुक्त दल की पहली बैठक 17 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और उसमें भूटान में 10,000 मेगावाट पनबिजली के विकास से संबधित मुद्दों पर चर्चा की गई जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा मई, 2008 की अपनी भूटान यात्रा के दौरान 2020 तक भारत को निर्यात किए जाने हेतु की गई थी। भारत सरकार की इस वचनबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए भारत और भूटान के बीच पनबिजली सहयोग पर 2006 के समझौते के प्रोतोकोल पर दोनों पक्षों द्वारा नई दिल्ली में 16 मार्च, 2009 को हस्ताक्षर किए गए।

चीन

यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने 13-15 जनवरी, 2008 को चीन की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ राजकीय चर्चा की और चीनी राष्ट्रपति हु जिन्ताओं एवं चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष वु बंगुवो से मुलाकात की। दोनों पक्षों की ओर से भारत और चीन के बीच 21वीं सदी के लिए एक साझी दृष्टि जारी की गई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को शामिल करते हुए दस अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान सैपोरो में 8 जुलाई, 2008 को और एसेम शिखर सम्मेलन के दौरान बीजिंग में 25 अक्तूबर, 2008 को पुनः मुलाकत की। प्रधानमंत्री यूएनजीए सत्र के दौरान न्यूयार्क में 24 सितंबर, 2008 को भी चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओं से मिले।

प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह की यात्रा के पश्चात् उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान का संवेग बनाए रखा गया। विदेश मंत्री ने 4-7 जून, 2008 को चीन की यात्रा की। उन्होंने चीनी उप-राष्ट्रपति जी जिन्पिंग से मुलाकात की ओर विदेश मंत्री यांग जीची से वार्ता की। बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी की जल स्तर संबंधी सूचना चीन द्वारा भारत को प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विदेश मंत्री ने गुआंगझू में भारत के नए महा कोंसलावास का उद्घाटन भी किया। चीनी विदेश मंत्री श्री यांग जीची ने 7-9 सितंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। उन्होंने कोलकाता में नए चीनी प्रधान कोंसलावास का उद्घाटन किया और विदेश मंत्री से चर्चा की एवं प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

फरवरी, 2008 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2007 में द्विपक्षीय व्यापार 38.96 बिलियन अमरीकी डालर था। चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार 51.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जबकि भारत का व्यापार घाटा 11.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा। चीन के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री दोनों द्वारा अपनी चीनी यात्राओं के दौरान उठाया गया था। चीनी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से कहा था कि उन्होंने इस चिंता को नोट कर लिया है और इसे हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी उप वाणिज्य मंत्री की अगुवाई में एक कारपोरेट खरीद मिशन 9-12 अक्तूबर, 2008 को भारत आया था और उन्होंने व्यापार पर 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जिनके अंतर्गत एक वर्ष के भीतर भारतीय निर्यात को बढ़ाकर 390 मिलियन अमरीकी डालर करने की इच्छा व्यक्त की गई है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने वाणिज्य मंत्रियों से यह भी कहा कि संयुक्त आर्थिक दल की 8वीं बैठक में क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) के लाभों पर व्यवहार्यता अध्ययन की जांच की जाए और इस संबंध में तथा परस्पर चिंता के अन्य मसलों पर सिफारिशें की गईं। तीसरी भारत-चीन वित्तीय वार्ता 16 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

रक्षा सहयोग से परस्पर विश्वास और सहयोग को बढाने में योगदान मिला है। दोनों पक्षों ने 4-14 दिसंबर, 2008 को भारत (बेलगांव) में दूसरा संयुक्त सैनिक अभ्यास किया और 15 दिसम्बर, 2008 को भारत में उच्च स्तरीय (सचिव/डीसीजीएस) द्वितीय वार्षिक रक्षा वार्ता भी आयोजित की गई। पीएलए नेवी प्रमुख ने 1-5 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने नवंबर, 2008 को हवाई प्रदर्शन और द्विपक्षीय बैठक के लिए झुहाई की यात्रा की।

26-28 नवंबर, 2008 को मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और विदेश मंत्री यांग जीची ने शोक संदेश भेजा। 25 दिसम्बर, 2008 को विदेश मंत्री के साथ टेलिफोन पर हुई वार्ता में चीनी विदेश मंत्री यांग जीची ने कहा कि चीन ऐसे हमले की घोर भर्त्सना करता है और हर तरह के आतंकवाद के प्रति अपने देश के दृढ़ विरोध को दोहराया।

सीमा संबंधी प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 12वां दौर 18-19 सितंबर, 2008 को बीजिंग में सम्पन्न हुआ। अगले दौर की वार्ता दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

सरकार ने मई, 2008 में सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के लिए राहत सहायता के रूप में 5 मिलियन अमरीकी डालर दिए जाने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना के 9 विमानों द्वारा 18 मई से 8 जून, 2008 तक टेंट, स्लीपिंग बैग, कम्बल और दवाएं तथा अन्य राहत सामग्रियां मुहैय्या कराई गईं।

बीजिंग, चीन के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में 24 अक्तूबर, 2008 को आयोजित सातवें एसेम शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा अन्य राज्याध्यक्ष।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद 24 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए।

भारत और चीन के बीच कांसुलर स्तर की वार्ता का पहला दौर नई दिल्ली में 3 मार्च, 2008 को आयोजित किया गया। भारत और चीन के बीच हवाई सेवा मामलों पर एक समझौता ज्ञापन पर 20 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा यह सहमति हुई कि भारत की कुछ चुनिंदा वायु सेवाएं पूरे पंचम स्वतंत्रता अधिकारों के साथ चीन से आगे सैन फ्रांसिस्को तक आपरेट कर सकेंगी। आतंकवाद के विरोध पर भारत-चीन संयुक्त मार्च दल की तीसरी बैठक 9-10 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कृषि सहयोग पर भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक और ग्रामीण विकास पर कार्यशाला नई दिल्ली में 14-18 अक्तूबर, 2008 को आयोजित की गईं।

सीमापार नदियों संबंधी भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 10-12 अप्रैल, 2008 को आयोजित की गई। दो पक्षों द्वारा विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के कार्य विनियमन पर हस्ताक्षर किए गए और चीन द्वारा भारत को बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर की सूचना प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान पर दोनों जल संसाधन मंत्रियों के बीच मसौदा समझौता ज्ञापन पर आद्यक्षर किए गए; और चीन द्वारा भारत को सतलुज नदी की जलस्तर संबंधी जानकारी प्रदान करने संबंधी कार्यान्वयन योजना पर तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के हाइड्रोलोजी और जल संसाधन ब्यूरो और केन्द्रीय जल आयोग के बीच हस्ताक्षर किए गए। चीन द्वारा भारत को दी जाने वाली बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर से संबंधित सूचना के प्रावधान संबंधी समझौता ज्ञापन पर दोनों ही जल संसाधन मंत्रालयों के बीच विदेश मंत्री की 4-7 जून, 2008 को चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान नाथुला, लिपुलेख पास और शिप्किला के रास्ते सीमा पार व्यापार प्रभावित हुआ क्योंकि बीजिंग ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक के कारण चीनी प्राधिकारियों द्वारा अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लागए गए थे। 2008 में कैलाश-मानसरोवर यात्रा के तीन जत्थों की यात्रा चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रद्द करनी पड़ी थी।

दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। दोनों पक्ष विश्व व्यापार, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण परिवर्तन संबंधी चिंताओं, विश्वव्यापी वित्तीय संकट आदि जैसे मुद्दों पर अपने हितों को जोड़कर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों के अवसर पर उच्च स्तरीय बैठकें इन संबंधों की मुख्य विशेषताएं थीं। दोनों पक्ष पूर्व एशिया शिखर वार्ता, एसेम, एससीओ, सार्क जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों पर प्रेक्षकों और सदस्यों के रूप में भी परस्पर मेल मिलाप रखते हैं।

वर्ष के दौरान अन्य उल्लेखनीय कार्यात्मक आदान-प्रदान निम्नलिखित थेः

- केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुश्री अम्बिका सोनी ने 6-8 अप्रैल, 2008 को चीन की यात्रा की; वित्त राज्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल मई में चीन वित्त और बैंकिंग परिषद् भारतीय बैंक संघ, और आईसीईसी परिषद् द्वारा आयोजित द्वितीय उच्च स्तरीय भारत-चीन वित्तीय सम्मेलन में भाग लेने चीन गए; दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने मई में चीन की यात्रा की; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ने 29 जुलाई, 2008 में बीजिंग की यात्रा की; युवा मामले और खेल मंत्री डा.एम.एस.गिल ने अगस्त, 2008 में बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया; शहरी विकास मंत्री श्री एस जयपाल रेड्डी ने सितंबर में द्विपक्षीय दौरा किया; और आवास एवं निर्धनता उन्मूलन की प्रभारी राज्य मंत्री सुश्री कुमारी सैलजा ने 2-10 नवंबर, 2008 को चीन की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व शहरी मंच की बैठक में हिस्सा लिया और अपने चीन समकक्षियों के साथ द्विपक्षीय महत्व के मसलों पर चर्चा भी की।

- विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग के बीच 2004 में संस्थापित विनिमय कार्यक्रम(विदेश मंत्रालय-आईएलडी कार्यक्रम) के तहत असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने मई, 2008 के तीसरे सप्ताह में चीन की यात्रा की, जबकि शंघाई के पार्टी सचिव और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री यू झेंगशेंग ने 16-22 अक्तूबर, 2008 को भारत की यात्रा की। असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने अगस्त, 2008 में बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया।

- सचिव (युवा मामले) श्री एस.के.अरोड़ा की अगुवाई में तृतीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने 29 जून से 8 जुलाई, 2008 तक चीन की यात्रा की। अखिल चीन युवा परिसंघ के उपाध्यक्ष श्री वैंग हांगयान की अगुवाई में तृतीय चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने 10-19 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की।

- युन्नान प्रांत के गवर्नर श्री किन गुंगरोंग ने 7-15 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। हीलांगजियांग प्रांत के गवर्नर श्री ली झांशू ने 20-24 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। चीन के राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की उप सभापति महामहिम फेंग शुपिंग की अगुवाई में एक 6 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने 18-22 अक्तूबर, 2008 को भारत की यात्रा की।

- चीन के उप विदेश मंत्री श्री हे याफेई ने 5 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की।

आर्थिक सर्वेक्षण 2008 के अनुसार चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2007 में द्विपक्षीय व्यापार 38.96

बिलियन अमरीकी डालर था। चीनी सुत्रों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा 8.32 बिलियन अमरीकी डालर है। यह मुद्दा चिंता का विषय रहा है और प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री दोनों द्वारा अपने-अपने दौरों के दौरान इसे उठाया गया है।

रक्षा सहयोग से परस्पर विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में योगदान मिला है और पीएलए नेवी के प्रमुख ने 1-5 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की और भारतीय वायु सेना प्रमुख ने वायु प्रदर्शन के लिए झूहाई की यात्रा की।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण बने रहे। दोनों देश उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और परस्पर पहचान किए गए क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा इस संबंध को और मजबूत बनाने में लगे रहे। विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने मालदीवी प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए 27-29 जनवरी, 2008 को मालदीव की यात्रा की। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वह मालदीव सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वहां के विदेश मंत्री से भी मिले।

वाणिज्य राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश 29-31 जनवरी, 2008 को एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में मालदीव गये। वाणिज्य मंत्री ने मालदीव के प्राधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा भारत और मालदीव के बीच आर्थिक सहयोग के उपायों पर चर्चा की।

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति मोयून अब्दुल गायूम ने 6-12 फरवरी, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गायूम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के एक समझौते पर 11 फरवरी, 2008 को हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, माले और भारत-मालदीव फाउंडेशन की स्थापना पर एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए भी सहमत हुए। मालदीव के राष्ट्रपति ने 7 फरवरी, 2008 को टीईआरआई द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप पुरस्कार भी प्राप्त किया।

मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम अब्दुल्ला शाहिद ने 19-20 सितंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। दो समझौता ज्ञापनों-एक इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, माले की जनशक्ति संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित और दूसरा भारत-मालदीव फाउंडेशन की स्थापना से संबंधित-पर 19 सितंबर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए।

मालदीव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम 7 अगस्त 2008 को उठाया गया जब वहां के नए संविधान का अनुसमर्थन किया गया और इससे मालदीव में बहुदलीय राष्ट्रपति निर्वाचन कराने का मार्ग खुला। मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री मोहम्मद नशीद ने 54.21% मत प्राप्त करके चुनाव में विजय हासिल की जबकि मौजूदा राष्ट्रपति मउमून अब्दुल गायूम को 45.79% मत मिले। उपराष्ट्रपति ने 11 नवंबर, 2008 को उनके शपथग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम डा.अहमद शहीद ने 30 नवंबर से 2 दिसंबर, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की। मालदीव में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद यह मालदीव से भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। डा.शहीद ने 2 दिसंबर, 2008 को विदेश मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की।

भारत सिविल और रक्षा दोनों से जुड़े क्षेत्रों में मालदीव के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता रहा।

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नशीद ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 23-25 दिसंबर, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नशीद ने 24 दिसंबर, 2008 को भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत के उप-राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, यूपीए की अध्यक्षा और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता से भी राष्ट्रपति नशीद ने मुलाकात की।

24 दिसंबर, 2008 को दोनों देशों के बीच दो समझौतों-मालदीव को 100 मिलियन अमरीकी डालर की सर्मथन ऋण सुविधा पर समझौते और एक वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

मालदीव गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद नसीम ने 8-10 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की।

मालदीव के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री अमीन फैजल ने 1-5 फरवरी, 2009 को रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए भारत की यात्रा की।

मालदीव गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार मंत्री डा.अमिनथ जमील ने 22-26 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान डा.जमील ने 26 फरवरी, 2009 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की और लोक स्वास्थ्य देखरेख सहित पारस्परिक हित के मसलों पर चर्चा की। उन्होंने महिला और बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से भी मुलाकात की।

मालदीव गणराज्य के शिक्षा मंत्री डा.मुस्तफा लुटफी ने 24-28 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली की यात्रा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 25-26 फरवरी, 2009 को आयोजित उच्च शिक्षा पर विश्व सम्मेलन के लिए एशिया-प्रशांत उप-क्षेत्रीय तैयारी सम्मेलन में हिस्सा लिया।

म्यांमार

भारत-म्यांमार के संबंधों की जड़े सामाजिक, संस्कृति, धार्मिक और ऐतिहासिक जुड़ाव से जुड़ी है। दोनों देशों की लगभग 1650 किमी लंबी साझी भू सीमा है। चार उत्तर पूर्वी राज्य-अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। म्यांमार में भारतीय मूल के लगभग 2.5 मिलियन नागरिक भी रहते हैं। भू-सामरिक कारकों से भारत और म्यांमार के लिए घनिष्ठ संबंध रखना महत्वपूर्ण है।

भारत म्यांमार संबंधों को दोनों देशों की अपनी सीमाओं पर शांति और सौहार्द्रता को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, आम नागरिकों के बीच आपसी मेल-मिलाप और उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने की साझी इच्छा के रूप में देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे आदान-प्रदान में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई जिनके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय जुड़ाव में घनिष्ठता और व्यापकता आई।

गृह सचिव/उपगृह मंत्री के स्तर पर 14वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक 7-10 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अपनी यात्रा के दौरान यू न्यान विन ने 2 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने 2 जनवरी, 2008 को विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

म्यांमार के विदेश मंत्री यू न्यान विन ने 31 दिसंबर से 4 जनवरी, 2008 को भारत की यात्रा की। उप विदेश मंत्री महामहिम यू क्या थू ने प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में 23-26 जनवरी, 2007 को भारत का दौरा किया। उपवरिष्ठ जनरल मौंग अए ने 2-6 अप्रैल, 2008 को भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री थीन सेन और वित्त मंत्री यू न्यान विन ने नवंबर, 2008 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने अप्रैल, जून और अक्तूबर, 2008 में म्यांमार की यात्रा की।

विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन ने उप विदेश मंत्री महामहिम यू क्या थू के आमंत्रण पर म्यांमार की यात्रा की। यात्रा के दौरान हुई चर्चा में द्विपक्षीय महत्व के अनेक मुद्दों को शामिल किया गया जिनमें सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दे, व्यापार और आर्थिक सहयोग और सीमापार विकास परियोजनाओं में सहयोग सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, विद्युत और शिक्षा तथा प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन ने नवंबर, 2008 में म्यांमार की पुनः यात्रा की।

भारत म्यांमार में आईआईजी की गतिविधियों को रोकने के लिए म्यांमार का निरंतर आधार पर सहयोग पाने का इच्छुक है। इस प्रयोजन के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किए गए हैं। इनमें वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श (एन एलएम); क्षेत्र स्तरीय बैठकें (एसएलएम) और अर्धवार्षिक सेना सीमा सम्पर्क बैठकें शामिल हैं। म्यांमार ने भारत सहित अपने पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी संगठन को अपने भूक्षेत्र का उपयोग करने अनुमति न देने की सर्वोच्च स्तर पर प्रतिज्ञा ली है।

म्यांमार के उप गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल फोन स्वे के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7-10 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच 14वें एनएलएम में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की। बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, मादक दवाओं की तस्करी, सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों, सीमापार व्यापार और सीमा पार परियोजनाओं पर चर्चा की गई। भारत और म्यांमार के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों (एफओसी) का नवां दौर यांगों में 22-23 नवंबर, 2008 को आयोजित किया गया।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान जारी रहा। भारत सरकार ने म्यांमार के महाद्वीपीय जलमग्न क्षेत्र के परिसीमन के लिए म्यांमार के विशेषज्ञों को तकनीकी आंकड़ों के संग्रह और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की है।

भारत म्यांमार के भीतर अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध रहा है। दोनों पक्षों के बीच अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें कालादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, तामू-कलेम्यू सड़क का रखरखाव और पुनःसमतलीकरण और रिटिडिम और रि-फलम सड़कों का दर्जा बढ़ाया जाना शामिल है।

कालादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना पर ढांचा करार, पारगमन परिवहन को सुगम बनाने संबंधी एक प्रोतोकोल और रखरखाव तथा प्रशासन पर एक प्रोतोकोल एवं दोहरा कराधान निवारण करार पर भारत और म्यांमार के बीच अप्रैल, 2008 में एसपीडीसी के उपाध्यक्ष उप वरिष्ठ जनरल मौंग अए के दौर के दौरान हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य और विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश की 22-25 जून, 2008 को म्यांमार दौरे के दौरान द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षा करार (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

जहां तक द्विपक्षीय व्यापार का संबंध है, 2007-08 के दौरान भारत को म्यांमार का निर्यात 984.48 मिलियन अमरीकी डालर था जबकि इसी अवधि के दौरान म्यांमार को भारत का निर्यात 189.95 मिलियन अमरीकी डालर था। संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की तीसरी बैठक म्यांमार में 13-15 अक्तूबर, 2008 को आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच यह सहमति हुईं कि मोरेह-तामू और जोखातार-रि सीमा बिन्दुओं पर सीमा व्यापार का दर्जा बढ़ाकर उसे सामान्य व्यापार का दर्जा दिया जाएगा; भारत में नागालैंड राज्य में अवांगखुग पर और म्यांमार में रोबर्मी में एक नया सीमा व्यापार बिन्दु खोला जाएगा और भारत-म्यांमार सीमा व्यापार करार के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में विस्तार करके उनकी संख्या को 22 से बढ़ाकर 40 किया

जाएगा। म्यांमार के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 11-14 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली का दौरा किया और बिमस्टेक व्यापार बैठक में हिस्सा लिया। म्यांमार से दलों के त्वरित निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए एक सरकार से सरकार के करार पर नवंबर, 2008 में हस्ताक्षर किए गए।

भारत और म्यांमार ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजली के क्षेत्र में भी भागीदारों के रूप में उभर रहे हैं। सितम्बर, 2008 में म्यांमार में चिन्दविन नदी में तमांती जल-विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए एनएचपीपी (भारत)ले. और म्यांमार के विद्युत मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सी-डैक ने आईटी कौशल के विकास हेतु एक भारत म्यांमार केंद्र (आईएमसीईआईटीएस) की स्थापना की है जिसका उद्घाटन 16 अक्तूबर, 2008 को म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल थीन सेन द्वारा किया गया।

मई 2008 को चक्रवात नरगिस के बाद म्यांमार को आपातिक राहत सहायता पहुंचाने वाले सबसे पहले पहुंचें देशों में भारत एक था। दो भारतीय नौसैनिक पोतों और आई भारतीय वायु सेना विमानों द्वारा तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई जिसमें म्यांमार को खाद्य सामग्रियों और दवाओं की आपूर्ति शामिल थी। दो स्वतःपूर्ण चिकित्सा दल दो सप्ताह से अधिक प्रभावित क्षेत्र में डटे रहे। पुनर्वास चरण मे छत बनाने के लिए नालीदार स्टील की चादर की आपूर्ति, 16 नष्ट हुए ट्रांसफार्मरों को बदलना, 500 सौर मशालों और लालटेनों की आपूर्ति, 20 बायोमास गैसीफायरों को स्थापित करना और IV फ्लूड की 1.8 लाख बोतलों की आपूर्ति का कार्य भारत द्वारा किया गया। यांगों में खेडागोन पगोडा परिसर के पुनर्निर्माण के लिए 200000 अमरीकी डालर (लगभग 85 लाख रुपये) की नकद सहायता भी म्यांमार को प्रदान की गई।

भारत म्यांमार सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक भारतीय कठपुतली रंगमंच दल ने म्यांमार की यात्रा की और नवंबर में यांगों और मंडाले में कठपुतली नृत्य प्रस्तुत किया।

भारत के उपराष्ट्रपति डा.एम हमीद अंसारी ने 5-8 फरवरी, 2009 को म्यांमार की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान वह महामहिम सीनियर जनरल थान श्वे और वाइस सीनियर जनरल मौंग अये से मिले। उन्होंने नयपेईटव और यांगों तथा मंडालय की यात्रा की। उनकी वार्ताओं में सुरक्षा, सड़क, कृषि, तेल और प्राकृतिक गैस, शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास की परियोजनाएं शामिल थीं। एचएमटी (आई) द्वारा एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और एक अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए। मोरहे और मण्डालय के बीच औप्टिक फाइबर लिंक को अधिकृत किया गया। उपराष्ट्रपति ने यांगों में उद्यमिता विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया।

दसवां भारत-म्यांमार विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में 5-6 मार्च, 2009 को आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन और म्यांमार पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री यू माउंग मिंट द्वारा किया गया। चर्चा में द्विपक्षीय महत्व के अनेक मुद्दे शामिल किए गये।

नेपाल

भारत ने नेपाल सरकार और वहां की जनता को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन को मजबूत करने और उसके विकास प्रयासों में सभी संभव सहयोग प्रदान किया। सरकार नेपाल के साथ बहुआयामी संबधों को सुदृढ़ बनाने और व्यापक सहयोग के लिए नेपाल सरकार के साथ मिलकर कार्य करती रही। भारत सदैव हर संभव तरीके से मदद के लिए तैयार है ताकि नेपाल एक लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण ओर सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उभरे।

विगत वर्ष के दौरान नेपाल में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन ने कई महत्वपूर्ण सोपान प्राप्त किए हैं। संविधान सभा के चुनाव 10 अप्रैल, 2008 को सम्पन्न कराए गए जिसमें सीपीएन (माओवादी)अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। संविधान सभा द्वारा 28 मई को हुई अपनी पहली बैठक में नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अंतरिम संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का सृजन किया गया। नेपाली कांग्रेस से डा. रामबरन यादव और मधेशी जनाधिकार के श्री परमानंद झा को 23 जुलाई, 2008 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलायी गई थी। प्रधानमंत्री और सीपीएन (माओवादी) अध्यक्ष, पुष्प कमल दहाल, जिन्हें "प्रचंड" भी पुकारा जाता है, की अगुवाई में यूएनएल मधेशी जनाधिकार मंच और दूसरी छोटी राजनैतिक पार्टियों के सहयोग से एक गठबंधन सरकार अगस्त 2008 में बनाई गई।

नेपाल में एक नव निर्वाचित सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों का नियमित आदान-प्रदान चलता रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री 14-18 सितंबर, 2008 को सरकारी दौरे पर भारत आए ओर बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 11-14 नवंबर, 2008 को पुनः भारत आए। सितम्बर, 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय तंत्रों को फिर से सक्रिय बनाया गया। सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की तथा कोशी बाढ़ में नष्ट पूरब-पश्चिम राजमार्ग के हिस्से के पुनर्निर्माण की वचनबद्धता दी और नेपाल सरकार को पी आर एल आपूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपये का ऋण दिया। नेपाल के विदेश मंत्री बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अगस्त 2008 में भारत आए।

नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए जाने के बाद भारत की ओर से पहले उच्च-स्तरीय दौरे में विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने नेपाल के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर 24-26 नवंबर, 2008 को नेपाल की यात्रा की। उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति को भी शीघ्र ही परस्पर सुविधाजनक तिथि को भारत

आने का न्यौता दिया। नेपाल के वाणिज्य ओर आपूर्ति मंत्री पेट्रोटेक अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन में हिस्सा लेने जनवरी, 2009 में भारत आए और अपने समकक्षी से भी मुलाकात की।

नेपाल के साथ जल संसाधान क्षेत्र में सहयोग ने और प्रगति हुई है। बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं पर यह निर्णय लिया गया कि पंचेश्वर परियोजना के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए ओर सुन कोसी सप्त कोसी परियोजना के लिए संयुक्त परियोजना छानबीन यथाशीघ्र पूरी की जाए।

भारत नेपाल सरकार द्वारा अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण ओर सामुदायिक विकास के क्षेत्र में चलाई गई परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास प्रयासों में योगदान करता रहा। लघु विकास परियोजना स्कीम के लिए समझौता ज्ञापन का और तीन वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। भारत-नेपाल सीमा पर सीमा ढांचे को सुदृढ़ बनाना सरकार की उच्च प्राथमिकता रही। दोनों देशों के बीच एकीकृत जांच चौकियों व सड़क और रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं। मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और नेपाली संस्थाओं में क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाया गया है।

पाकिस्तान

समग्र वार्ता

आठ विषयों अर्थात् विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम)सहित शांति और सुरक्षा जम्मू कश्मीर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, दोस्ताना आदान प्रदान, तुलबुल नौपरिवहन परियोजना, सर क्रीक और सियाचीन को शामिल करके समन्वित वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ और व्यापक बनाने के लिए 2004 में फिर से शुरू की गई। इसके बाद 6 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद का किसी तरह से समर्थन करने के लिए, अपने नियंत्रण वाले भूक्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। समन्वित वार्ता के चौथे दौर की मई, 2008 में विदेश सचिवों की बैठक में समीक्षा की गई और समन्वित वार्ता का 5वां दौर 21 मई, 2008 को हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस बैठक के दौरान कांसुलीय पहुंच पर एक करार पर हस्ताक्षर भी किए गए।

वार्ता के पिछले दौरों में स्थापित किए गए परिवहन मार्गों को सफलतापूर्वक आपरेट किया जाता रहा जिससे लोगों की आवाजाही सुविधाजनक हुई और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला। श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर 21 अक्तूबर, 2008 से ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरू हुआ। नियंत्रण रेखा के पार जाने के लिए 1 अक्तूबर, 2008 से तीन प्रवेश द्वारों की अनुमति दी गई। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट बस सेवा के फेरे क्रमशः 21 अगस्त, 2008 और 25 अगस्त, 2008 से दो सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में एक बार किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच वायु सेवा करार का दर्जा बढ़ाने के लिए 15 फरवरी, 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस सेवा के फेरे 12 से बढ़ाकर 28 कर दिए गए, निर्दिष्ट वायु संचालकों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन की गई और मौजूदा चार बिंदुओं अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, कराची ओर लाहौर के अतिरिक्त इस्लामाबाद और चेन्नई को भी इनमें शामिल किया गया। जुलाई, 2008 में भारत ने पाकिस्तान की हवाई सेवाओं के लिए निर्दिष्ट एयरलाइनों की सूची में मैसर्स जेट लाइट और मैसर्स डेक्कन एविएशन लिमिटेड के नाम जोड़ दिये। बस सेवा संबंधी भारत-पाकिस्तान स्थायी समिति की पहली बैठक 21 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली-लाहौर बस सेवा के फेरे सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर तीन बार किए जाएंगे।

आतंकवाद

समन्वित वार्ता के 5वें दौर की शुरू आत के बाद शुरूआती महीनों में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद आतंकवाद का मुद्दा वार्ता प्रक्रिया में रूकावटें डालता रहा और बाद में यह प्रक्रिया रूक गई। प्रधान मंत्री गिलानी ने सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 2 अगस्त, 2008 को कोलम्बों में हुई अपनी बैठक में हमारे प्रधान मंत्री को आश्वस्त किया कि वह 7 जुलाई, 2008 को काबुल में हमारे राजदूतावास पर हुए हमले की स्वतंत्र जाँच कराएंगे। 24 सितम्बर, 2008 को न्यूयार्क में हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जरदारी के बीच हुई बैठक में आगे यह सहमति हुई थी कि संयुक्त आतंकवाद-निरोधक तंत्र (जे ए टी एम) का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और उसमें काबुल में भारतीय राजदूतावास पर हुए बम हमले सहित परस्पर हितों के मसलों पर चर्चा की जाएगी। जे ए टी एम की यह विशेष बैठक 24 अक्तूबर 2008 को आयोजित की गई थी और दूतावास पर आतंकी हमले की छानबीन में हुई प्रगति की सूचना पाकिस्तान के साथ साझा की गई थी। काबुल हमले के संदर्भ में हमारी चिन्ता और साझा की गई सूचना पर पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई।

26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई पर आतंकी हमलाः 1 दिसम्बर, 2008 को पाकिस्तान को यह सूचित किया गया कि मुम्बई पर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए तत्वों द्वारा किया गया था। गिरफ्तार आतंकी द्वारा लिखा गया एवं पाकिस्तान उच्चायोग को संबोधित पत्र 22 दिसम्बर, 2008 को सौंपा गया। 5 जनवरी, 2009 को भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयुक्त को वह सामग्री सौंपी जो 26-29 नवम्बर, 2008 के मुम्बई हमले को पाकिस्तान स्थित तत्वों से जोड़ती थी। इस सामग्री में गिरफ्तार आतंकी से हुई पूछताछ से संबंधित सामग्री, पुलिस अभिरक्षा में रखा गया पाकिस्तानी नागरिक; मुम्बई हमले के दौरान पाकिस्तान स्थित तत्वों के साथ आतंकियों से हुई वार्ता के तार; जब्त किए गए हथियार और उपकरण और अन्य सामग्रियाँ; और जब्त जी

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड 12 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए।

श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्द्र राजपक्षे 13 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए।

पी एस से प्राप्त आंकड़े और आतंकियों द्वारा प्रयुक्त सेटलाइट फोन यंत्र शामिल थे। यह साक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी प्रस्तुत किए गए। पाकिस्तान को अभी इन साक्ष्यों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी है और सहयोग के आश्वासन वाले, उच्च स्तर पर दिए गए वक्तव्यों के बावजूद, वास्तविक कार्रवाई की दृष्टि में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है।

26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई पर हुए आतंकी हमले के बाद किए गए राजनयिक प्रयासः आतंकी हमले के मद्दे नज़र प्रधान मंत्री ने लोक सभा में कहा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद का गढ़, जो पाकिस्तान में स्थित है, के साथ कठोरता और प्रभावी ढंग से पेश आने के लिए सचेत किया जाना जरूरी है। मुम्बई हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने और यह सुनिश्चित करने कि ऐसी आतंकी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसके अनुसरण में द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े राजनयिक कदम उठाए गए। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अल कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति ने सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 की सूची में पाकिस्तान में बसे इन व्यक्तियों और समूहों, जिनमें लश्कर-ए-तय्यबा के नेता भी शामिल हैं के नाम जोड़े गए। जमात-उद-दावा का नाम भी लश्कर-ए-तय्यबा के सहायक संगठन के रूप में सूची में जोड़ा गया। आतंकी हमलों के पूरे ब्यौरे और पाकिस्तान में बसे तत्वों का इन हमलों से जुड़ाव के पुख्ता सबूतों को प्रस्तुत करने को लिए भारत स्थित मिशनों के सभी स्थानिक प्रमुखों के लिए विस्तृत चर्चा विदेश मंत्रालय में आयोजित की गई। इसी तरह विदेश स्थित हमारे मिशनों के प्रमुखों ने अपनी अपनी सरकारों से चर्चा की। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री ने सभी देशों में अपने समकक्षियों को पत्र लिखे और साथ में आतंकी हमले में शामिल व्यक्तियों के जीवनवृत्त और पाकिस्तान स्थित अपराधिक तत्वों के सबूत भी भेजे।

उच्च स्तरीय बैठकें

प्रधान मंत्री की पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ बैठक

प्रधान मंत्री ने सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 2 अगस्त, 2008 को कोलम्बो में और एसेम शिखर वार्ता के दौरान 24 अक्तूबर, 2008 को बीजिंग में भी पाकिस्तानी प्रधान मंत्री श्री यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। कोलंबो में 2 अगस्त, 2008 को पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रधान मंत्री ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं, काबुल में हमारे राजदूतावास पर हमलों, युद्धविराम उल्लंघनों और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लगातार प्रयासों के बारे में हमारी चिंता से अवगत कराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह दृढ़ इच्छा प्रकट की कि दोनों देशों के लिए इन घटनाओं पर नियंत्रण करना जरूरी है और संबंध सुधार की पटरी पर फिर से जाने की जरूरत है। प्रधान मंत्री गिलानी ने यह भी आश्वासन दिया कि वे हमारे राजदूतावास पर हुए हमले की स्वतंत्र जाँच कराएंगे।

प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात

प्रधान मंत्री 24 सितम्बर, 2008 को न्यू यार्क में यू एन जी ए बैठक के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ जरदारी से मिले। इस बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दिए गए अपने आश्वासन के प्रति पाकिस्तान की वचनबद्धता दोहराई। यह सहमति हुई थी कि दोनों देश अगले तीन माह में समन्वित वार्ता के 5वें दौर की बैठक आयोजित करेंगे; युद्धविराम को स्थायी बनाया जाएगा; काबुल में भारतीय राजदूतावास पर बम फेंके जाने सहित परस्पर चिंता के विषयों के हल के लिए अक्तूबर, 2008 में संयुक्त आतंक निरोधक तंत्र की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी; आम जनता के परस्पर सम्पर्कों, व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वाघा-अटारी सड़क मार्ग और खोखरापार मुनाबाओ रेल मार्ग को व्यापार की सभी स्वीकृत मदों के लिए खोला जाएगा; 21 अक्तूबर, 2008 को श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुँछ रावलकोट मार्गों से नियंत्रण रेखा पार व्यापार शुरू किया जाएगा। यह भी सहमति हुई थी कि स्कार्दू-कारगिल मार्ग को खोले जाने के तौर-तरीकों पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी।

विदेश मंत्री द्वारा की गई वार्ताएं

विदेश मंत्री ने 20-21 मई, 2008 को पाकिस्तान का दौरा किया। यह दौरा आम चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विजय के बाद पाकिस्तान में नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किए जाने के संदर्भ में था। इस बैठक के दौरान समन्वित वार्ता का चौथा दौर सम्पन्न हुआ और 5वाँ दौर शुरू किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री शाह महमूद कुरेशी 27 जून, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। विदेश मंत्री कुरेशी 26-29 नवम्बर, 2008 को पुनः नई दिल्ली आए। इस बैठक में मंत्रियों ने गौर किया कि समन्वित वार्ता के पाँचवे दौर में पर्याप्त प्रगति पहले ही की जा चुकी है जैसे नियंत्रण रेखा पार व्यापार खोलना, वाघा-अटारी मार्ग को व्यापार की सभी स्वीकृत मदों के लिए खोले जाने के सिद्धांत रूप से सहमति, माल वाहक वाहनों में व्यापार के लिए खोखारापार-मुनाबाओ रेल मार्ग को खोला जाना, कारगिल-स्कार्दू मार्ग को खोलने के तौर तरीकों पर चर्चा आदि।

मानवीय मुद्दे

एक बड़ी संख्या में भारतीय कैदी, मछुआरे और नौकाएं पाकिस्तान की अभिरक्षा में हैं। पाकिस्तान भी भारत की जेलों में बंद अपने राष्ट्रिकों के लिए चिन्तित है। कैदियों पर भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति की पहली बैठक 26 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी। समिति ने दोनों सरकारों को अपनी सिफारिशें भेजी है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों की तत्काल रिहाई और उनकी कोंसलीय पहुँच और 31 मार्च, 2008 को एक दूसरे देश की जेलों में बन्द राष्ट्रिकों की एकीकृत सूची का अदान-प्रदान शामिल है। समिति ने जून, 2008 में पाकिस्तान की जेलों और अगस्त, 2008 में भारत की जेलों का दौरा किया और अनेक सिफारिशें कीं।

वाणिज्य और व्यापार
भारत संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ पारगमन व्यापार सहित द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को महत्व देता है। वर्ष 2007-2008 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 2.12 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास था जो 2006-2007 की तुलना में (1.67 बिलियन अमरीकी डालर) 27% अधिक था। अप्रैल से दिसम्बर, 2008 की अवधि में कुल व्यापार 1.3 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास था। तथापि, इस अवधि के दौरान भारत को पाकिस्तान का निर्यात 2007-08 के कुल निर्यात (211 मिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में 30% अधिक (293 मिलियन अमरीकी डालर) था। तीसरे देशों के रास्ते गैर अधिकृत व्यापार भी महत्वपूर्ण है जिससे पाकिस्तान में अंतिम प्रयोगकर्त्ता के लिए खरीद लागत बढ़ती है। जब कि भारत ने पाकिस्तान को एम एफ एन स्थिति प्रदान की है, पाकिस्तान ने भारत से आयात की मदों को सकारात्मक सूची तक सीमित रखा है। साफ्टा पर, पाकिस्तान ने भारत को निर्यात की जाने वाली सकारात्मक सूची के अलावा मदों को सहमत टैरिफ रियायत देने से इंकार कर दिया है जिससे साफ्टा को अक्षरशः नकारा गया क्योंकि निर्यात को सकारात्मक सूची की मदों तक ही सीमित रखा गया है।

पाकिस्तान ने 19 जुलाई, 2008 को नई व्यापार नीति की घोषणा की और सकारात्मक सूची में 139 और मदों को जोड़ दिया। सकारात्मक सूची का क्रमिक विस्तार द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार देने के साधन के तौर पर पाकिस्तान की एक अधिमान्य नीति है न कि प्रमुख रूप से एम एफ एन की स्थिति में सुधार की।

अन्य मुद्दे
भारत ने सितम्बर, 2008 में राहत सामग्रियों की आपूर्ति के लिए उत्तर पूर्व सीमान्त प्रान्त की प्रान्तीय सरकार को प्रांत में आई भीषण बाढ़ के फलस्वरूप 1.3 करोड़ रूपए की बाढ़ राहत सहायता प्रदान की।

श्रीलंका

भारत ने श्रीलंका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में विगत वर्ष के सकारात्मक संवेग को बनाए रखा। सर्वोच्च राजनैतिक स्तरों पर दौरों के आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान मिला। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2-3 अगस्त, 2008 को कोलम्बों में 15वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षे से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन से पहले सार्क मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने भी अपने श्रीलंकाई समकक्ष श्री रोहिथ बोगोलागमा से मुलाकात की। विदेश मंत्री रोहिथ बोगोलागमा ने 16 जून, 2008 को भारत की यात्रा की और कोलंबो में सार्क शिखर सम्मेलन का आमंत्रण पत्र सौंपा। दोनों विदेश मंत्री 10वीं बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 26 अगस्त,2008 को नई दिल्ली में और यू एन जी ए के दौरान 1 अक्तूबर, 2008 को न्यूयार्क में फिर से मिले।

श्री लंका में सुरक्षा संबंधी हालात, खासतौर पर उत्तरी प्रांत में संघर्ष और उससे आम नागरिकों नागरिकों के पलायन और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के मुद्दे भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहे। विदेश मंत्री ने जनवरी 2009 में अपनी यात्रा के दौरान गिरती हुई मानवीय स्थिति पर भारत की चिंता को दोहराया और युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वहां से नागरिक सुरक्षा के लिए बाहर निकल सकें। उन्होंने नागरिकों की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने, सुरक्षित क्षेत्रों का सम्मान और विस्तार करने और नागरिकों पर संघर्ष के प्रभावों को न्यूनतम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत ने इस विश्वास को दोहराया कि संघर्ष का कोई सैनिक हल नहीं है और एक अखण्ड श्रीलंका की रूपरेखा के तहत शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा सभी समुदायों को स्वीकार्य राजनीतिक समाधान ही इसका एकमात्र उपाय है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक विश्वसनीय एवं वास्तविक हस्तांतरण पैकेज और श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन का कार्यान्वयन शामिल होना चाहिए।

सद्भावना प्रदर्शित करते हुए भारत ने श्रीलंका के उत्तरी भाग में सिविलियनों और आंतरिक रूप से विस्थापितों के लिए मानवीय राहत सहायता प्रदान की है। अभी तक राहत सामग्रियों की तीन खेपें भेजी जा चुकी हैं। पहली खेप में तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा जुटाई गई राहत सामग्रियों के 80,000 फैमिली पैक श्रीलंका स्थित आईसीआरसी कार्यालय द्वारा दिसंबर, 2008 में प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किए गए। दवाओं से भरी दूसरी और तीसरी खेपें 2009 के प्रथम तीन महीनों में श्रीलंका को सौंपी गईं। इसके बाद मार्च 2009 में भारत ने संघर्ष क्षेत्र से आने वाले सिविलियनों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर पूर्वी श्रीलंका को 50 सदस्यों वाली आपातकालीन चिकित्सा यूनिट और सचल अस्पताल भेजें हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच मछली पकड़ने की व्यवस्था पर एक समझौता भी हुआ है जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष दोनों में से किसी देश से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने वाले वैध मछुआरों के लिए व्यावहारिक व्यवस्था करने के लिए राजी हुए। यह सहमति श्रीलंकाई संसद सदस्य और राष्ट्रपति के विशेष दूत बासिल राजपक्षे की 26 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा के दौरान हुई थी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंध लगातार बढ़ते रहे। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जो श्रीलंका के कुल व्यापार का 16.8% या छठा हिस्सा है। वर्ष 2008 में कुल व्यापार 3.265 बिलियन अमरीकी डालर रहा। 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के एफ डी आई

अनुमोदन के साथ ही भारत श्रीलंका में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। भारती एयरटेल, जिसे श्रीलंका में चौथे मोबाइल आपरेटर के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। भारत ने आर आई टी ई एस - आई आर सी ओ एन द्वारा कोलम्बो-मटारा रेलवे लाइन के उन्नयन के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण पत्र भी प्रदान किया है।

दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार(सीईपीए) पर बातचीत किया है जिससे हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों में और व्यापकता और गहराई आने की आशा है। अक्तूबर 2008 में नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए जिसमें संगोष्ठियों कार्यशालाओं और वैज्ञानिकों एवं शोधकर्त्ताओं की यात्राओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। एक परस्पर पहचान करार और चाय अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग संबंधी एक और करार पर सितम्बर, 2008 में भारत और श्रीलंका के चाय बोर्डों के बीच हस्ताक्षर हुए। इसके पहले मई 2008 में श्रीलंकाई सड़क विकास प्राधिकरण (आरडीए) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

श्रीलंका को विकास सहायता भारत के श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य घोषणापत्र है। इन परियोजनाओं में 20 नेनासाला (ई - शिक्षा किओस्क) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, जातीय संघर्ष से प्रभावित हुए पूर्वी प्रान्त के मछुआरों को मछली पकड़ने की नौकाएं और जाल प्रदान करना, और पूर्वी प्रान्त में नवगठित सरकार की अवसंरचना व्यवस्था को बढ़ाने के लिए 10 बसें प्रदान करना शामिल है। वर्ष के दौरान, भारत ने एक परियोजना भी कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत श्रीलंका से 41 अंग्रेजी शिक्षक प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजे गए थे। पुत्तलम में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं सृजित करने की एक अन्य परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में भारत केन्द्रीय प्रान्त में स्कूलों की शैक्षणिक अवसंरचना को उन्नत करने की पहल करता रहा है जिसके अंतर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर लैबों की स्थापना और ए स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए महात्मा गाँधी छात्रवृत्ति योजना और भारत में गांधी ग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय में चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए भारतीय मूल के तमकलों को 20 छात्रवृत्तियां शामिल हैं। भारत ने सीलोन वर्कर्स एजूकेशन ट्रस्ट को भी योगदान दिया है जो प्रत्येक वर्ष भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।

संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध फोटोग्राफर विनय बहल द्वारा मटारा में बौद्ध कला और विरासत के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। यह प्रदर्शनी अन्य शहरों में भी लगाई जाएगी।

■■

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत **2**

आस्ट्रेलिया

भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होते रहे। दोनों पक्षों की ओर से अनेक उच्च स्तरीय दौरे वर्ष के दौरान किए गए जिसकी शुरूआत प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम शरण की विदेश मंत्री श्री स्टीफेन स्मिथ साथ पर्थ में चर्चा के लिए जनवरी 2008 में आस्ट्रेलिया यात्रा के साथ हुई। आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री श्री साइमन क्रीन ने 15-19 जनवरी को भारत की यात्रा की और व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान उन्होंने 16 से 18 जनवरी को सी आई आई भागीदारी शिखरवार्ता में एक भाषण दिया और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं कृषि, वित्त, खान, वाणिज्य और उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भी मुलाकात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने नवाचार, विज्ञान और अनुसंधान मंत्री श्री किम कार के आमंत्रण पर आस्ट्रेलियाई सरकार के अतिथि के रूप में फरवरी 2008 में सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन की यात्रा की। श्री सिब्बल ने 5 विश्वविद्यालयों और 7 अनुसंधान संस्थाओं में गये और उनसे सम्पर्क किया। श्री सिब्बल की यात्रा के बाद तीन माह के भीतर संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति एवं संयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी समिति की बैठकें इन क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत बढ़ाने की दृढ़ इच्छाशक्ति का सूचक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर 30 - 31 मार्च को सिडनी में आयोजित उत्तर पूर्व भारत निवेश अवसर संगोष्ठी में हिस्सा लेने आस्ट्रेलिया यात्रा पर गये।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ और आस्ट्रेलिया के व्यापर मंत्री श्री साइमन क्रीन की सह अध्यक्षता में संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की 11वीं बैठक 20 मई को मेलबोर्न में आयोजित की गई। फिक्की और आस्ट्रेलिया-भारत व्यापर परिषद द्वारा संचालित संयुक्त व्यापार-परिषद की बैठक; एफ टी ए व्यवहार्यता अध्ययन संबंधी संयुक्त अध्ययन दल की दूसरी बैठक भी 21 मई, 2008 को मेलबोर्न में आयोजित की गई। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री प्रपुल्ल पटेल ने आस्ट्रेलियाई अवसंरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय शासन मंत्री श्री एन्थोनी अल्बानीज के बुलावे पर सिडनी, मेलबोर्न और कैनबरा की यात्रा पर गये। इस्पात राज्यमंत्री श्री जितिन प्रसाद न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी आस्ट्रेलिया की राज्य सरकारों से चर्चा के लिए जून, 2008 में सिडनी और पर्थ की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी 23 जून,2008 को द्विपक्षीय विदेश मंत्रियों की ढ़ाँचा वार्ता में हिस्सा लेने कैनबरा गये। एक प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में परस्परिक विधिक सहायता संबंधी एक संधि पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने अगस्त 2008 में सिडनी की यात्रा की।

आस्ट्रेलिया से व्यापार मंत्री साइमन क्रीन जनवरी में भारत आए। विदेश मंत्री स्टीफेन स्मिथ सितम्बर 2008 में भारत आए। पासपोर्ट, वीजा और कोंसुली मामलों पर एक संयुक्त कार्यदल (जे डब्ल्यू जी) की स्थापना इस दौरे के दौरान की गई। आस्ट्रेलिया के संसाधन, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री श्री मार्टिन फर्ग्युसन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमडल 3-6 नवम्बर, 2008 को भारत आया था। खान, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों के साथ आस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा सहयोग हेतु कार्य-योजनाओं पर हस्ताक्षर किये गये।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 10.9 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर पहुँच गया जिसमें 9.3 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का आस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात और 1.6 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का भारत से आस्ट्रलिया को निर्यात शामिल था। भारत आस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। भारत आस्ट्रलिया के लिए तीसरा सबसे बड़ा आप्रवासी स्रोत, दूसरा सबसे बड़ा कुशल श्रमिक स्रोत और दूसरा सबसे बड़ा समुद्रपार विद्यार्थी स्रोत था।

ब्रूनेई

ब्रूनेई दारूस्सलाम के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना बने रहे। पारस्पारिक व्यवहार के महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनैतिक, रक्षा और वाणिज्य रहे।

भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर सुल्तान ने 20-23 मई, 2008 को भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा की। यह यात्रा भारत की उनकी पिछली यात्रा के 15 वर्षों से अधिक समय बाद हुई थी। सुल्तान ने विभिन्न भारतीय नेताओं से मुलाकात की और प्रधान मंत्री से पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गएः (i) निवेश का पारस्परिक संवर्द्धन और संरक्षण संबंधी करार; (ii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग का समझौता ज्ञापन; (iii) संस्कृति, कला और खेल-कूद के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन; (iv) संयुक्त व्यापार समिति की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन; (v) उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलिमेट्री ट्रैकिंग और

टेलिकाम और स्टेशन के संचालन में सहयोग एवं अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन का नवीकरण।

भारतीय नोसैनिक पोत, आई एन एस घड़ियाल और आई एन एस कुलिश तीन दिन की सद्भावना यात्रा पर 18-20 अक्तूबर, 2008 को ब्रूनेई में मौरा बंदरगाह गए। भारतीय नौसेना पोतों की यात्रा सुल्तान की मई 2008 में भारत यात्रा से बढ़े हुए द्विपक्षीय संबंधों के अंतर्गत भारतीय और ब्रूनेइयन सशस्त्र बलों के बीच संलग्नता बढ़ाने के हिस्से के रूप में थी।

वाणिज्य सचिव श्री जी. के. पिल्लै ने 5-7 अगस्त, 2008 को ब्रूनेई में आयोजित एस ई ओ एम-भारत परामर्श के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया और सामाग्रियों के व्यापार संबंधी भारत-एशियान एफ टी ए संबंधी वार्ता को सम्पन्न किया।

उप संचार मंत्री डोटो मोहम्मद यूसोफ ने 15-18 अप्रैल, 2008 को कोची में राष्ट्रकुल दूरसंचार संगठन द्वारा आयोजित आई सी टी मंच में हिस्सा लिया।

प्रधान मंत्री कार्यालय में उप मंत्री डैटो यूसोफ अगाकिया की अगुवाई में ब्रूनेई दररूस्सलाम के संचार मंत्रालय का एक 9 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमण्डल 7-11 अप्रैल, 2008 को कार्यकारी दौरे पर भारत आया।

कम्बोडिया

भारत और कम्बोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना रहे।

भारत अनुदान और ऋण पत्रों के माध्यम से कम्बोडिया को द्विपक्षीय सहायता प्रदान करता रहा। पनबिजली, सिंचाई और मंदिरों के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भारत की सहायता से कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण कम्बोडिया में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए हैण्ड पम्प लगाने और सूचना प्रौद्योगिकी में सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना के लिए दूसरी बड़ी सहायताओं पर कार्रवाई की जा रही है। जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज 15-19 फरवरी को कम्बोडिया गए और जल संसाधन एवं मौसम विज्ञान मंत्री श्री लिन कीन होर से मिले।

जून, 2008 में कम्बोडिया के लिए तीन पनबिजली परियोजनाओं हेतु 15 मिलियन अमरीकी डालर का एक नया ऋण पत्र अनुमोदित किया गया जिसका उपयोग कम्बोडिया में पेलिंग और बट्टमबैंग के बीच ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाएगा।

अपने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों के अतिरिक्त भारत ने कम्बोडिया में प्रीह विहियर मन्दिर के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सहायता दी है ताकि उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सके। मन्दिर का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सफलतापूवर्क दर्ज कराया गया है।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से उन्नति हुई है। कम्बोडिया से भारत को अधिकाधिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगसत 2008 में सीमाशुल्क अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत कम्बोडिया के संबंध में सीमाशुल्क मुक्त टैरिफ प्रिफरेंस स्कीम लागू की गई है। आतंकवाद, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार, अवैध हथियारों की तस्करी और उससे जुड़े अपराधों से मुकाबला करने में कम्बोडिया एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

वर्ष के दौरान दो भारतीय नौसेना पोत कम्बोडिया भेजे गए थे। आई टी ई सी योजना के अंतर्गत भारतीय सेना 1995 से कम्बोडियाई कार्मिकों को विशिष्ट डिमाइनिंग(सुरंगी बारूद विफल करना) आपरेशन का प्रशिक्षण देता रहा है और शांति-रक्षा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाने के प्रस्ताव भी दिए गए थे। भारत ने शाही कम्बोडियाई सशत्र बल को 2-5 करोड़ रूपए के मेडिकल स्टोर जिसमें एम्बुलेंस वैन, उपकरण और जरूरी सामग्रियां और दवाएं शामिल थीं और 1.025 करोड़ रूपए के अभियांत्रिकी और तोपखाना स्टोर उपहार स्वरूप दिया।

कम्बोडिया क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय मंचों पर भारत की विभिन्न पहलों और हितों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर हमारी उम्मीदवारी भी शामिल है, का निरन्तर समर्थक रहा है। कम्बोडिया ने वर्ष 2011-12 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए हमारी उम्मीदवारी को अपना समर्थन औपचारिक तौर पर सूचित कर दिया है। हमारी "पूर्व की ओर देख" नीति और आसियान के संदर्भ में कम्बोडिया एक महत्वपूर्ण बिचौलिया और एक अच्छा भागीदार है।

फिजी

भारत अंतरिम प्रधानमंत्री कोमोडोर जोसाइया वोरेक बैनिमारमा के नेतृत्व वाली फिजी द्वीप गणराज्य की अंतरिम सरकार के सतत् सम्पर्क में रहा। भारत फिजी में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वापसी पर जोर देता रहा है और इसका मख्य ध्यान उसे सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर रहा और उसका लक्ष्य वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय के बीच दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए शांति और सौहार्द को बढावा देना रहा है।

अंतरिम वित्त, राष्ट्रीय योजना और चीनी उद्योग और सार्वजनिक उपयोगिता मंत्री श्री महेन्द्र पाल चौधरी, 25 अप्रैल से 2 मई 2008 तक भारत दौरे पर आए और इस दौरे के दौरान वे प्रधान मंत्री से मिलने गए और वित्त मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, रेल राज्य मंत्री से मिले। पुलिस आयुक्त श्री तेलेनी 24-28 जून, 2008 को भारत आए और पुलिस बल के ढाँचे, क्षमता और कार्यप्रणाली को समझने के लिए भारतीय अधिकारियों से चर्चा की। फिजी द्वीप व्यापार और निवेश ब्यूरो (एफ टी आई बी) के अध्यक्ष श्री फ्रांसिस नारायण 20 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2008 तक एक व्यापार और निवेश प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई में भारत आए जिनका मुख्य ध्यान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था।

21 मई, 2008 को नई दिल्ली में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया मुआजाद्दीन वादुल्लाह के साथ प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह।

केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान से भारतीय विशेषज्ञ 26 जुन से 23 अगस्त 2008 तक फिजी द्वीप गए और फिजी के नारियल उद्योग विकास प्राधिकरण की सहायता की और फिजी द्वीप में नारियल उद्योग के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारतीय संस्कृति केन्द्र भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग और हिन्दी भाषा की कक्षाएं चला रहा है। फिजी में तीन भाषा सूत्र के हाल के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए भारत ने हिन्दी भाषा की 19000 पुस्तकें दान की और इस प्रकार फिजी के सारे प्राइमरी और सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययन सामग्री भेजी गई। भारत ने फिजी की आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सिलाई मशीनों के रूप में भी सहायता प्रदान की है।

इण्डोनेशिया

वर्ष 2008-09 के दौरान इण्डोनेशिया के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बने रहे। दोनों देशों के बीच नियमित तौर पर उच्चस्तरीय दौरों और अन्य प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान चलता रहा। इससे भारत और इण्डोनेशिया के बीच पहले से चल रहे घनिष्ठ राजनैतिक, सुरक्षा, रक्षा, वाणिज्यक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूती मिली।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2008 तक इण्डोनेशिया का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाली और जकार्ता गयीं। बाली में बाली के गवर्नर राष्ट्रपति से मिले।। राष्ट्रपति तमन आयु मंदिर गयी और बाली में प्रतिष्ठित नागरिकों, सांस्कृतिक सक्शियतों और भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। जकार्ता में राष्ट्रपति ने इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति युधोयोनो से द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर संतोष प्रकट किया और द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर तक ले जाने का संकल्प लिया जो भारत और इण्डोनेशिया के बीच सामरिक भागीदारी के उद्देश्यों के अनुरूप होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दो समझौता ज्ञापनों-कृषि सहयोग और युवा मामले और खेलकूद में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया गया। राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सदनों के अध्यक्ष और जन परामर्श सभा के अध्यक्ष भी मिले।

दोनों पक्षों के बीच संसद स्तरीय नियमित सम्पर्क होते रहे हैं। समित- रूरू (स्वास्थ्य और श्रम) से इण्डोनेशियाई प्रतिनिधि सदन का एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल 11-17 अक्तूबर, 2008 को अध्ययन दौरे पर भारत आया था। श्री फहरी हमजा की अगुवाई में भारत के लिए संसदीय मैत्री दल का एक इण्डोनेशियाई प्रतिनिधिमण्डल 2-6 नवम्बर, 2008 को भारत आया।

इण्डोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री सिती फैडिलाह सुपरी ने 2008 में भारत की यात्रा की। इण्डोनेशिया के व्यापार मंत्री ने भी 2008 में भारत की यात्रा की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ ने एशियान-भारत आर्थिक मामलों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेने अप्रैल 2008 में इण्डोनेशिया गये थे। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री नमो नरायण मीणा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमण्डल जून 2008 में बसेल अभिसमय की सीओपी 9 बैठक के लिए बाली गया था। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री ऑस्कर फर्नाण्डीस अक्तूबर, 2008 में द्वितीय एसेम श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने बाली गये। सचिव(पूर्व) विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2008 में बाली में आयोजित आसियान भारत बैठक में भाग लेने एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

वर्ष के दौरान सभी क्षत्रों हमारे संबंधों में तेजी से विकास हुआ। दोनों देशों के बीच नियमित रक्षा आदान-प्रदान हुए जिनके अंतर्गत उच्च स्तरीय दौरों का, पोतों के दौरों, दोनों में से किसी भी देश के स्टॉफ कालेजों में अध्ययन करने वाले अधिकारियों का और मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर संयुक्त समन्वित चौकसी का आदान-प्रदान शामिल है। सेना प्रमुख ने फरवरी 2009 में इण्डोनेशिया की यात्रा की।

इण्डोनेशिया आसियान में हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार 2007 में 6.5 बिलियन अमरीकी डालर था और 2008 के पूर्वार्द्ध में यह 5.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। हमारे बीच सक्रिय सांस्कृतिक आदान - प्रदान होता रहा जिससे इण्डोनेशियाई समाज में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप देखी गई। जाकार्ता और बाली में स्थापित हमारे दो सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा पूर वर्ष कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। वर्ष के दौरान आई टी ई सी द्वारा इण्डोनेशिया को कुल 75 प्रशिक्षण स्लाटों का प्रस्ताव किया गया, जिनमें कोलम्बो योजना के अर्न्तगत 38 प्रशिक्षण स्लाट, 25 जीसी एस एस छात्रवृत्रि स्लाट और 2 हिन्दी एक वर्षीय पाठ्क्रम छात्रवृत्ति शामिल थे। मिशन ने 14 नवम्बर, 2008 को आई टी ई सी दिवस के रूप में मनाया जिसमें 200 आई टी ई सी अध्येताओं ने हिस्सा लिया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर इण्डोनेशिया की स्थिति चिन्ता के कई महत्वपूर्ण् मामलों में भारत के पक्ष में रही है। इण्डोनेशिया ने मुम्बई में हुए आतंकी हमलों की कठोर निंदा की और एक बहुलतावादी और बहुद्वीपीय राष्ट्र के रूप में आतंकवाद के लिए स्वयं की अतिसंवेदनशीलता के प्रति बेहद सजग है। इण्डोनेशिया शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से कश्मीर मुद्दे के समाधान के पक्ष में है और भारत-पाकिस्तान मसले पर व्यापक तौर पर अपना एक तटस्थ दृष्टिकोण रखता है और ओ आई सी में भारत-विरोधी संकल्पों पर अपना विरोध दर्ज कराता है। तथापि, इण्डोनेशिया के पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में पाकिस्तान से दूरी न बनाए रखने के प्रति बहुत सावधान रहा है। इण्डोनेशिया भारत की "पूर्व की ओर देखें" नीति का समर्थक रहा है और फिलहाल भारत के आसियान के साथ वार्ता भागीदारी का आसियान समन्वयक है। इण्डोनेशिया ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का भी जोरदार समर्थन किया था।

1 दिसंबर, 2008 को जर्काता, इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति सुसीलो बामबांग युधोयोनो से मुलाकात करते हुए।

27 अगस्त, 2008 को दिल्ली में लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति चौमाली सायासोने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।

पूर्व एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जाकार्ता में 3 जून, 2008 को आसियान और पूर्व एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान(ई आर आई ए) की स्थापना की गई थी। ई आर आई ए शासी बोर्ड में श्री रतन टाटा भारत के नामिती हैं। इण्डोनेशिया ने बाली लोकतंत्र मंच की पहली बैठक दिसम्बर 2008 में आयोजित की। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र और अच्छी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने की एक नई क्षेत्रीय पहल है। न्यू एशियन-अफ्रीकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप(एन ए ए एस पी) की पहल के अंतर्गत इण्डोनेशिया ने फिलीस्तीन के लिए क्षमता निर्माण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसका आयोजन जाकार्ता में 14-15 जुलाई, 2008 को किया गया। सम्मेलन में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन, मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक अनुवर्ती तंत्र स्थापित करने की सहमति हुई थी।

लाओ पी डी आर

इस वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की मुख्य बात 26-30 अगस्त, 2008 को लाओ पी डी आर के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा रही। यह 30 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किसी लाओ राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। इस दौरे के दौरान भारत ने विएनतिएन में बाढ़ राहत और चम्पसैक, लाओ पी डी आर में बौद्ध कालेज के निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की मानवीय सहायता की घोषणा की। 2009 मे लाओ रक्षा बल की 60 वीं वर्षगांठ के लिए 50 पैराशूट उपहार स्वरूप देने की घोषणा भी की गई। लाओ पी डी आर में तंत्रिका अस्पताल और वायुसेना अकादमी के निर्माण हेतु भारत की वचनबद्धता भी दोहराई गई। दोनों देशों के बीच 33 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पत्र करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उपयोग तीन जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाना है। भारत ने इस वर्ष से भारत में अध्ययन के लिए लाओ नागरिकों के लिए आई टी ई सी के मौजूदा 60 स्लॉटों को बढ़ाकर 80 और 14 छात्रवृत्तियों को भी बढ़ाकर 20 कर दिया।

लाओ उप शिक्षा मंत्री श्रीमती सेंगडुआने लैचन्याबोउन उन की अगुवाई में एक 5 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमण्डल 23-27 जून, 2008 को भारत आया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न एजेन्सियों से मुलाकात की।

पहली भारतीय व्यापार प्रदर्शनी 14-17 नवम्बर, 2008 को विएनतिएन में आयोजित की गई और इस अवसर पर एक भारतीय कठपुतली दल भी गया था। भारतीय वायु सैनिक सूर्यकिरण एरोबेटिक्स दल ने 16से17 नवम्बर तक लाओस में प्रदर्शन किया। लाओस में इस तरह का यह अब तक का पहला प्रदर्शन था।

लाओ पी डी आर विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और नाभिकीय मुद्दे के संबध में भारत का समर्थन करता है।

मलेशिया

वर्ष के दौरान भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। मलेशिया के साथ हमारे संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और भी गति मिली क्योंकि दोनों पक्षों ने चौथी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में लिये गए निर्णयों का क्रियान्वयन किया। यह आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा और कोंसुली क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों में उल्लेखनीय प्रगित के रूप में देखा जा सकता है।

भारत और मलेशिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 13 मई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की अनुमित दी गई। दोनों पक्ष सम्पर्क और सहयोग मजबूत और घनिष्ठ करने के लिए सहमत हुए और दोनों देशों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी सहमति हुई। वर्ष के दौरान दोनों पक्षों के उच्च-स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान होता रहा और मलेशिया में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक/वाणिज्यिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जनवरी-अक्तूबर, 2008 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 2007 के दौरान हुए व्यापार के अनुरूप ही था। 2008 के पहले दस महीनों (जनवरी-अक्तूबर) में दोनों ओर से किया गया व्यापार 9.1 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए व्यापार से 34% अधिक है। यह 2007 में दोनों ओर से किए गए व्यापार के 8.14 बिलियन अमरीकी डालर (भारतीय नियात 2.1 बिलियन अमरीकी डालर और आयात 6.03 बिलियन अमरीकी डालर) या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% वृद्धि के मुकाबले बेहतर था। मौजूदा वर्ष के अंत तक द्वीपक्षीय व्यापार के 10बिलियन अमरीकी डालर को छू लेने की आशा है जो लक्ष्य तिथि 2010 से पहले ही है। उल्लेखनीय है कि जनवरी-अक्तूबर, 2008 दौरान 2.7 बिलियन अमरीकी डालर का भारतीय निर्यात पिछले वर्ष इसी अवधी के दौरान किए गए निर्यात के मुकाबले 58% अधिक है।

न्र्षर्ष 2008 की एक उल्लेखनीय घटना क्रम मलेशियाई परिवहन मंत्री का 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की एक बड़ी रेलवे डबल ट्रैकिंग परियोजना को आई आर सी ओ एन को देने का निर्णय है।

संयुक्त अध्यपन दल की सिफारिशों के आधार पर भारत और मलेशिया ने फरवरी 2008 में व्यापक आर्थिक सहयोग करार(सी ई सी ए) तैयार करने की वार्ता शुरू की है जिसे 2009 में सम्पन्न किया जाना है। अभी तक व्यापार वार्ता समिति (टी एन सी) की दो बैठकें हो चुकी हैं एक फरवरी, 2008 में क्वालालम्पुर में और दूसरी जून/जुलाई 2008 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

वर्ष 2008 के पहले 10 महीनों के दौरान भारतीय निवेश 48.44 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। हैदराबाद स्थित भारतीय कम्पनी वाइवो बायो टेक लि0 ने 140 मिलियन अमरीकी डालर, मल्लाडी ग्रुप ने अगले 3-5 वर्षों में 300 मिलियन अमरीकी

डालर निवेश करने की घोषणा की है। भारत की रिलायंस कैपिटल एसेट को मलेशियाई सरकार से नवम्बर 2008 में एक इस्लामिक फण्ड मैनेजमेण्ट लाइसेंस मिला है। संचयी एफ डी आई अनुमोदन के अनुसार मलेशिया जनवरी 1991 से भारत में 21वाँ सबसे बड़ा निवेशक है जिसके पास 210 से अधिक एफ डी आई अनुमोदनों तक हो चुका हैं जिसका मूल्य 1.84 बिलियन अमरीकी डालर है। हाल के वर्षों में भारत में मलेशियाई निवेश भी बढ़ रहा है। मैक्सिस की योजना भारत में 2009-10 में 4 से 5 बिलियन अमरीकी डालर निवेश करने का है और एक अन्य कम्पनी टी एम आई 2009 में 1.8 बिलियन अमरीकी डालर निवेश करेगी। यदि हम मारिशस के रास्ते हुए निवेश को भी शामिल करें तो आज तक भारत में हुआ मलेशियाई निवेश 4.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होगा।

द्वितीय मलेशिया-भारत आर्थिक सम्मेलन (एम आई ई सी) सितम्बर, 2008 में आयोजित किया गया जिसमें मलेशिया और भारत से 600 से अधिक व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। सी आई आई और मलेशिया की एशियन सामरिक और नेतृत्व संस्थान(ए एस एल आई) के तत्वावधान में पहली मलेशिया-भारत सामरिक वार्ता सितम्बर 2008 में क्वालालम्पुर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री के विशेष दूत राजदूत सतिन्दर लाम्बा ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की। यह दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में आयोजित पहली महत्वपूर्ण ट्रैक- ख्ख् वार्ता थी जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक गहराई प्रदान करने के लिए भारत-मलेशिया प्रतिष्ठान की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। प्रथम भारत-मलेशिया सी ई ओ मंच का आयोजन भी सामरिक वार्ता की तर्ज पर किया गया।

भारत मलेशिया में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले केन्द्रीभूत देशों में एक रहा है। भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में विगत वर्षों में बहुत अधिक बृद्धि हुई है। जनवरी- नवम्बर, 2008 मे दौरान मलेशिया जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 0.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई जबकि 2007 में यह संख्या 0.28 मिलियन और 2006 में 0.18 मिलियन थी। मलेशिया से 2007 में भारत आए कुल 0.113 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ 10वाँ सबसे बड़ा स्रोत देश है जो भारत आए कुल विदेशी पर्यटकों का 2.22% है। यह संख्या 2006(0.107 मिलियन) की तुलना में 6 % अधिक है।

भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग 6-8 जनवरी, 2008 को रक्षा मंत्री ए. के. एंटोनी की मलेशिया की बेहद सफल यात्रा से और उसके बाद क्रमशः फरवरी और अगस्त 2008 थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख की यात्राओं से काफी प्रोत्साहित हुआ। सहयोग के बढ़े हुए दायरे में थल सेना और वायु सेना के लिए सेवा-विशिष्ट स्टाफ वार्ता(नौसेना से नौ सेना स्टाफ वार्ता पहले ही सक्रिय की जा चुकी है) शुरू की जानी शामिल थी। रक्षा सहयोग में सबसे बड़ी बिन्दु भारत और मलेशिया में भारतीय वायु सेना(आई ए एफ) द्वारा सु-30 एम के एम विमान के संचालन और रख रखाव के लिए शाही मलेशियाई वायु सेना (आर एम ए एफ)कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करना और उसे कार्यान्वित किया जाना था। तकनीकी प्रशिक्षण जनवरी से जून 2008 तक भारत में आयोजित किया गया। मलेशिया में "फ्लाइंग" और "ग्राउण्ड" प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों की अवधि हेतु मलेशिया में 31 सदस्यों वाला आई ए एफ प्रशिक्षण दल तैनात किया गया है,यह प्रशिक्षण कार्य फरवरी 2008 से शुरू हुआ। आर एम ए एफ ने भी सु-30 एम के एम के लिए संचार तंत्र एवं अतिरिक्त पुर्जों की सहायता का अनुरोध किया है (जिस पर एच ए एल द्वारा कार्रवाई की जा रही है) और साथ ही उसके हवा से जमीन पर मार करने वाले वाले हथियारों के लिए रेन्ज सुविधा एवं सम्बद्ध सहायता हेतु भी अनुरोध किया है (जिस पर विचार हो रहा है)।

थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर अपने समकक्ष सेना प्रमुख जनरल मुहम्मद इस्माइल के बुलावे पर 4-6 फरवरी 2008 को सरकारी यात्रा पर मलेशिया गये। उनके प्रमुख कार्यक्रमों में जनरल इस्माइल के साथ गहन परिचर्चा और उप प्रधान मंत्री एवं रक्षा मंत्री मोहम्मद नजीब से मुलाकात करना शामिल थे। वे आतंकवाद निरोधक दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय केन्द्र और आर्मी कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर(पुलादा) भी गये। यह हमारे थल सेना प्रमुख की 1999 के बाद मलेशिया की पहली यात्रा थी।

वायु सेना प्रमुख, एअर चीफ मार्शल एफ एच मेजर 17 से 21 अगस्त 2008 को सरकारी दौरे पर मलेशिया गये। यात्रा के दौरान वायु सेना प्रमुख उप प्रधान मंत्री मोहम्मद नजीब और उप रक्षा मंत्री वीरा अबू सेमन से मिलने गए और साथ ही सी डी एफ जनरल अब्दुल अजीज से भी मिले और साथ ही अपने समकक्ष रॉयल मलेशियाई वायु सेना प्रमुख जनरल अजीज़न बिन अरीफिन से भी चर्चा की। वे मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी तट कुआन्तन (मिग-29 और एफ- 18 बेस) और गोंग केडग (सु-30 एम के एम बेस) स्थित दो सामरिक एअर बेस देखने गये। गोंग केडग में वायु सेना प्रमुख आई ए एफ प्रशिक्षण दल (सु-30 एम के एम के संबंध में आर एम ए एफ कर्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए मलेशिया में नियुक्त) के सदस्यों और उनके परिजनों से मिले। वायु सेना प्रमुख एयरोस्पेस निरीक्षण, मरम्मत और ओवरहाल डिपो(ए आई आर ओ डी) और एयरोस्पेस सिस्टम टेक्नोलोजी कोर (ए एस टी सी), जो मलेशिया में एअरोस्पेस परिसम्पतियों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार दो कम्पनियाँ हैं, में भी गये।

भारतीय नौसेना और तटरक्षक पोत दक्षिण पूर्व/पूर्व एशिया में अपने समुद्र पार नियोजन के हिस्से के रूप में मलेशिया भेजे गए। जिन मलेशियाई बंदरगाहों का दौरा किया गया उनमें लूमुट(दो नौसैनिक पोतों द्वारा) और पेनांग तथा पोर्ट क्लैंग (तीन तटरक्षक पोतों द्वारा) शामिल थे। रायल मलेशियाई नौसेना (आर एम एन) प्रमुख ने 13 से 18 फरवरी , 2008 को आयोजित भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी (आई ओ एन एस)-2008 मे हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी-डिफ-एक्सपो-2008 भी देखा।

भारतीय रक्षा मंत्री ए.के एण्टोनी 6 जनवरी, 2008 को 3-दिन की यात्रा पर मलेशिया गये। उनके साथ रक्षा सचिव विजय सिंह, उप थल सेना प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल जेड.यू शाह, उप वायु सेना प्रमुख एअर मार्शल नोक ब्राउन और वाइस एडमिरल के. एन. सुशील भी गये थे।

रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद प्रायद्वीपीय मलेशिया के दक्षिणी प्रान्त में सेरेम्बैन से जेमैस तक 100 कि.मी विद्युतीकृत दोहरे ट्रैक वाले रेल पथ के 3.45 बिलियन आर एम की परियोजना भारतीय रेलवे कांस्ट्रंक्शन कम्पनी(इरकॉन) को सौंपे जाने के कार्यक्रम को देखने 14-17 मई, 2008 तक क्वालालम्पुर में थे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा 19-21 मई, 2008 को सरकारी यात्रा पर क्वालालम्पुर में थे जिसके दौरन उन्होंने 16वें विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रस (डब्ल्यू सी आई टी 2008) में मंत्रिस्तरीय मंच को संबोधित किया और साथ ही पहली साइबर-आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय भागीदारी(आई एम पी ए सी टी) की मंत्रिस्तरीय शिखर बैठक में भी हिस्सा लिया।

लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 1 से 9 अगस्त, 2008 तक क्वालालम्पुर में आयोजित 54वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (सी पी ए) में भाग लेने के लिए 6 संसद सदस्यों और 26 राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की। आवास और शहरी निर्धनता उन्मूल न राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुश्री सैलजा राष्टमण्डल महिला सांसदों (सी डब्ल्यू पी) सदस्य की हैसियत से सी पी ए में भाग लेने गई। सी पी ए की महासभा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह और असम विधान सभा अध्यक्ष श्री तंका बहादुर राय के साथ-साथ श्री सोमनाथ चटर्जी को सी पी ए की कार्यकारी समिति में भारतीय क्षेत्र से क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के रूप में चुना।

प्रधान मंत्री दातुक सेरी अब्दुल्ला अहमद बदावी के बुलावे पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 27-29 अगस्त, 2008 को खजाना वैश्विक व्याख्यान देने मलेशिया गये। व्याख्यान का शीर्षक "सामाजिक परिवर्तनों की गतिशीलता" था। उन्होंने यूनिवर्सिटी मलाया(यू एम) में व्याख्यान दिया और साथ ही "विधि और विकास" पर लिंकन इन मेमोरिलय व्याख्यान भी दिया। उनके अन्य कार्यक्रमों में कारकोसा सेरी नेगरा में कारपोरेट नेताओं और तेनागा नेशनल बरहड (टी एन बी) में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से मुलाकात की। उन्हें पेनाग में यूनिवर्सिटी सैंस मलेशिया से मानद डाक्टरेट की उपाधि भी दी गई।

अप्रवासी भारतीय मामले मंत्री श्री व्यालार रवि ने 11-13 अक्तूबर, 2008 को मलेशिया की यात्रा की और मलेशियाई मानव संसाधन मंत्री दातुक डा. एस सब्रमण्यन से मिले। दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आदान-प्रदान संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 3 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गए।

न्यूजीलैण्ड

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने 22 जनवरी को ऑकलैण्ड में सर एडमुण्ड हिलेरी की राजकीय अन्त्येष्ठि में हिस्सा लिया। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा 15 जनवरी को नई दिल्ली स्थित न्यूजीलैण्ड उच्चायोग में सर एडमण्ड हिलेरी की शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया।

गवर्नर जनरल माननीय आनन्द सत्यानन्द और उनके साथ् श्रीमती सुसान सत्यानन्द ने 8-14 सितम्बर, 2008 को भारत का राजकीय दौरा किया। इस दौरे का विशेष महत्व यह था कि यह न्यूजीलैंड के किसी गवर्नर जनरल द्वारा की गई भारत की पहली यात्रा थी और इसका यह भी खास महत्व है कि माननीय आनन्द सत्यानन्द भारतीय कुल के हैं। गवर्नर जनरल रष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक अन्य भारतीय नेताओं से मिले। उन्होंने बुम्बई और हैदाराबाद में राज्य प्राधिकारियों से भी मुलाकात की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय कमलनाथ ने 21-24 मई, 2008 तक न्यूजीलैंड की यात्रा की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अपने न्यूजीलैंड समकक्ष फिल गोफ और कृषि तथा मत्स्य पालन मंत्री जिम एण्डरसन से मुलाकात की। उनके दौरे के दौरान एक संयुक्त व्यापार समिति की बैठक और संयुक्त व्यवसाय परिषद की बैठक भी आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस, 2008 को भारत सरकार द्वारा सर एडमण्ड हिलेरी को मरणोपरान्त दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार 22 मई, 2008 को श्री कमलनाथ द्वारा सर एडमुण्ड की पत्नी श्रीमती ज्यून हिलरी को सौंपा गया।

युवा, खेलकूद और स्थानीय शासन मंत्री माननीय मणि शंकर अय्यर ने अप्रैल, 2008 में न्यूजीलैंड की यात्रा की।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 21 अगस्त, 2008 को नियू में आयोजित प्रशान्त क्षेत्र द्वीप समूह पोस्ट-फोरम वार्ता भागीदार बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की।

सचिव(पूर्वी क्षेत्र) श्री हरदीप सिंह पुरी प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 11 अगस्त, 2008 को न्यूजीलैण्ड गये और अमरीका-भारत असैनिक नाभिकीय करार तथा एन एस जी छूट के संबंध में रक्षा, निःशस्त्रीकण, शस्त्र नियंत्रण और व्यापार मंत्री श्री फिल गोफ और विदेश तथा व्यापार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की।

भारतीय विश्व कार्य परिषद और न्यूजीलैण्ड अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 7 नवम्बर, 2008 को हस्तक्षार किए गए।

पापुआ न्यू गिनी (पी एन जी)

भारत के पापुआ न्यू गिनी के साथ रिश्ते घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं। अधिकांश वैश्विक मुद्दों पर हमारे विचारों में समानता है।

पापुआ न्यू गिनी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी का समर्थ किया है। पी एन जी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थक है।

पी एन जी इग्नू के साथ संबंध बनाने का इच्छुक है और साथ ही सुदूरवर्ती/ पहुँच से परे क्षेत्रों के लिए अपना खुद का एक शैक्षिक उपग्रह बनाने और उसे प्रक्षेपित करने के लिए भारत की सहायता पर विचार कर रहा है ताकि दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा,ई-गवर्नेन्स और सामान्य दूर संचार जैसे अनुप्रयोगों को कवर किया जा सके।

एक केमेक्सिल(रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद) प्रतिनिधिमण्डल ने अप्रैल 2008 में पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की।

भारत और पी एन जी के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरन यह लगभग 290 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच चुका था।

एक भारतीय कम्पनी ने पापुआ न्यू गिनी में एक यूरिया खाद संयत्र स्थापित करने के लिए एक बड़ी तेल कम्पनी ऑयल सर्च लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय कम्पनियाँ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग हेतु पापुआ न्यू गिनी के सम्पर्क में हैं।

आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत् भारत सरकार ने भारत में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पापुआ न्यू गिनी को 20 स्लॉट प्रस्तावित किया है। इन स्लॉटों का पूरा उपयोग किया गया और संबंधित सरकारों द्वारा इनकी सराहना की गई। वित्त मंत्रालय की कोलम्बो योजना के टी सी एस के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पापुआ न्यू गिनी को अन्य 4 स्लॉट प्रस्तावित किए गये हैं।

भारत ने भारत सरकार की प्रशान्त द्वीपीय देशों के लिए क्षेत्रीय सहायता पहल के अन्तर्गत पापुआ न्यू गुनिया को 100,000 अमरीकी डालर के सहायता अनुदान का प्रस्ताव किया है।

फिलीपीन्स

हाल में दोनों ओर से किए गए कई उच्च स्तरीय दौरों से (राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम फरवरी 2006 में फिलीपीन्स गये, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जनवरी 2007 में आसियान भारत और पूर्व एशिया शिखर बैठक के लिए फिलीपीन्स गये और राष्ट्रपति ग्लोरिया मेकापेगल एरायो अक्तूबर, 2007 में भारत की राजकीय यात्रा की) भारत और फिलीपीन्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आयी है और उद्देश्य में भी वृद्धि हुई है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संस्थागत तंत्र स्थापित किये गये है। इसे दोनो देशों के बीच बढ़े व्यापार और निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है।

सचिव(पूर्व) श्री एन. रवि ने जुलाई, 2008 में विशेष दूत के रूप में मनीला की यात्रा की और विदेश सचिव श्री अल्बर्टो रोमुलो के साथ एक बैठक की। शहरी विकास मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी ने 7-10 सितम्बर, 2008 को मनीला की यात्रा की। वह एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित परिवहन मंच के बीज वक्ता थे। श्री रेड्डी परिवहन और संचार विभाग के सचिव श्री लिएर्न्डो मेण्डोजा से भी मिले और लाइट रेल परिवहन प्राधिकरण और मेट्रो मनीला विकास प्राधिकरण के साथ बैठकें की।

वर्ष के दौरान विभिन्न संयुक्त कार्य दल की बैठकें आयोजित की गई। पर्यटन विभाग से एक दो सदस्यों वाला प्रतिनिधिमण्डल 4 जुलाई, 2008 को मनीला में आयोजित पर्यटन संबंधी संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक में हिस्सा लेन फिलीपीन्स गया। कृषि संबंधी भारत- फिलीपीन्स संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक नई दिल्ली में 21 अगस्त, 2008 को आयोजित की गई थी। विभिन्न विषयों जिनमें डेयरी विकास, खजूर के तेल का उत्पादन, चावल की नस्लें, जैव-ईंधन, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रियाँ, बम्बू और शुष्क भूमि कृषि शामिल थे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। व्यापार और आर्थिक संबंधों संबंधी संयुंक्त कार्य दल की 10 वीं बैठक नई दिल्ली में 21-22 नवम्बर, 2008 को आयोजित की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से एक प्रतिनिधिमण्डल 8वें आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी सप्ताह में हिस्सा लेने 6-9 जुलाई, 2008 को मनीला गया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी 6वें आसियान-भारत संयुक्त कार्य दल में भी हिस्सा लिया और फिलीपींस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव सुश्री एस्ट्रेला अल्बास्ट्रो से द्विपक्षीय वार्ता भी की थी।

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है कुल व्यापार 206-07 में 745.34 मिलियन डालर से बढ़कर 2007-08 में 823.29 मिलियन डालर तक पहुँच गया। वर्ष 2007-08 में भारतीय निर्यात 618.65 मिलियन डालर मूल्य का था और भारतीय आयात 204.64 मिलियन डालर मूल्य का हुआ। निवेश के क्षेत्र में कई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों ने फिलीपींस में अपना कार्य शुरू कर दिया है। इसी तरह फलीपिनो कम्पनियाँ भी रियल एस्टेट, खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश कर रही हैं।

वर्ष के दौरान भारत से कई व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों ने फिलीपींस की यात्रा की। कैपेक्सिल से एक प्रतिनिधिमण्डल ने 2-5 अप्रैल 2008 को फिलीपींस की यात्रा की और एक क्रेता-विक्रेता बैठक में हिस्सा लिया। फिक्की की अगुवाई में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल 21अक्तूबर, 2008 को आयोजित संयुक्त व्यवसाय परिषद की 7वीं बैठक में हिस्सा लेने फिलीपींस गया। वाणिज्य विभाग का 5 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमण्डल आसियान - भारत व्यापार वार्ता समित की बैठक में भाग लेने अक्तूबर 2008 में फिलीपींस गया था।

भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े के समुद्रपार तैनाती के हिस्से के रूप में 17-21 अप्रैल, 2008 को 2 भारतीय नौसेनिक पोत मनीला गये। फिलीपींस से नौसेना प्रमुख रियर एडमीरल रोजेलियों कैलुन्सैग मई 2008 में सरकारी दौरे पर भारत आए और कोलकाता, विशाखापत्तनम तथा नई दिल्ली भी गये।

फिलीपींस आई टी ई सी और कोलम्बो योजना प्रशिक्षण के सबसे बड़े लाभग्राहियों में एक है जिसने हाल के वर्षों के दौरान आबंटित सीटों का 90% से अधिक का उपयोग किया। चालू वर्ष 2008-09 के दौरान आई टी ई सी के अंतगत 25 स्लॉटो में से 23 का और कोलम्बो योजना के अंतर्गत 25 स्लॉटों में से 23 का उपयोग किया गया है।

अक्तूबर 2007 में राष्ट्रपति एर्रोय की भारत यात्रा के दौरान राजनयिक और शासकीय पासपार्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओ से छूट संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष के दौरान वीजा अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया था। सभी राजनयिक और शासकीय पासपार्ट धारक एयरपोर्ट पर 30 दिन के प्रवास के लिए अब अपने वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

व्यापार ,पर्यटन और रोजगार के लिए भारत आने वाले फिलीपींस नागरिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। कलेण्डर वर्ष 2007 के दौरान 12,297 वीजा जारी किए गए 1 जनवरी से 5 नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान 11,356 वीजा जारी किए गए थे।

पेशेवर प्रबंधकों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की बड़ी संख्या से फिलीपीन्स में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में फिलीपींस में मेडिकल कालेजों और निजी पायलट प्रशिक्षण स्कूलों में भारतीय विद्यार्थियों के दाखिले से भी भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

सिंगापुर

हाल के वर्षों में भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों में हुए गुणात्मक परिवर्तनों की धुरी ठोस आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर टिकी है। अप्रैल से सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान दोनों ओर के द्विपक्षीय व्यापार 10.38 बिलियन अमरीकी डालर तक पहँच गये जबकि वित्त वर्ष 2007-08 का कुल व्यापार 17.46 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल 2000 से जुलाई 2008 के दौरान 5.8 बिलियन अमरीकी डालर के एफ डी आई आगम के साथ ही सिंगापुर एफ डी आई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होकर उभरा है। द्विपक्षीय संबंधों को और भी समन्वित करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में पहली भारत-सिंगापुर सामरिक वार्ता और संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति की पहली बैठक वर्ष के दौरान ही आयोजित की गई। निरंतर उच्च स्तरीय दौरे के अलावा सिंगापुर में "प्रवासी भारतीय दिवस" और भारत @ 60 का आयोजन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों की खास-खास बाते रहीं।

भारत-सिंगापुर संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति (जे एम सी) की पहली बैठक 22 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और सिंगापुर के विदेश मंत्री सी जार्ज इयो द्वारा बैठक की सहअध्यक्षता की गई। मंत्रिस्तरीय बैठक के पहले 21 अप्रैल, 2008 को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जे एम सी दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने वाले तंत्र के रूप में काम करेगी। भारत-सिंगापुर सामरिक वार्ता(आई एस एस डी) की पहली बैठक सिंगापुर में 5-7 मई 2008 को आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई राजदूत एस के लाम्बा द्वारा की गई थी। वार्ता द्विवपक्षीय संबंधों, साझी चिंता के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर 5 सत्रों में की गई।

सिंगापुर न्यूयार्क के बाद वह दूसरा शहर बना जो भारत सरकार और सी आई आई द्वारा संयुक्त रूप से ओयोजित भारत @60 समारोहों का साक्षी बना। यह कार्यक्रम व्यवसाय/पर्यटन और संस्कृति पर केन्दित था। इन समारोहों में सिंगापुर सरकार की कई राजनैतिक हस्तियां उपस्थित थी। एक व्यवसाय सम्मेलन का उद्‌घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ और सिंगापुर के युवा,सामुदायिक विकास और खेल मंत्री श्री विवियन बालाकृष्णन द्वारा संयुक्त रूप से 4 अप्रैल, 2008 को किया गया। संस्कृति और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों की शुरूआत संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी अपने सिंगापुर के समकक्ष सूचना, संचार और कला मंत्री श्री ली बून यांग द्वारा संयुक्त रूप से 5 अप्रैल, 2008 को "अतुल्य भारत@60" के रूप में की गई। पूर्व अंचल सांस्कृतिक केन्द्र के कलाकारों और यू एन डी पी के ग्रामीण पर्यटन पहल द्वारा समर्थित शिल्पकारों ने इस समारोह में हिस्सा लिया।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे भारतीय डायस्पोरा तक पहुँच के उद्देश्य से पी डी बी सिंगापुर नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 9-11 अक्तूबर, 2008 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। "प्रवासी भारतीय दिवस" के मॉडल पर बने इस सम्मेलन का आयोजन भारत और सिंगापुर की सरकारों के समर्थन से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, सी आई आई और सिंगापुर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (एस आई सी सी आई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। बीस देशों से आये 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और मंत्री मेण्टर ने हिस्सा लिया जो सम्मेलन के प्रति सिंगापुर के नेताओं द्वारा प्रदर्शित किए गए महत्व को दर्शाता है। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई भारतीय प्रवासी कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि द्वारा की गई।

28 अगस्त, 2008 को सम्पन्न हुए छठे आसियान आर्थिक मंत्री - भारत परामर्श में मंत्रियों ने सामग्रियों के व्यापार संबंधी आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार वार्ता के समापन की घोषणा की। भारत-सिंगापुर सी ई ओ मंच के प्रमुखों-रतन टाटा और डी बी एस बैंक के कोह बून हवी के बीच मंच की बैठक के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को बैठक हुई। सिंगापुर के नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरण ने भारत के विमान प्राधिकरण के साथ मई 2008 में नागरिक उड्‌डयन में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर ने अपने-अपने सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए 12 अगस्त, 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों के रक्षा सचिवों ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये। पाँचवी भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 7-8 अक्तूबर, 2008 को सिंगापुर में आयोजित की गई। भारत सिंगापुर रक्षा तकनीक कार्यसंचालन समिति की तीसरी बैठक सिंगापुर में 17-18 अप्रैल, 2008 को आयोजित की गई। तीनों सेवाओं में से प्रत्येक के बीच वार्षिक स्टॉफ वार्ता भी आयोजित की गई। सिंगापुर सशस्त्र बल और भारतीय सेना ने मध्य भारत में 25 मार्च से 5 मई 2008 तक एक द्विपक्षीय वख्तर अभ्यास कोड नाम बोल्ड कुरूक्षेत्र आयोजित किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन ने 6 से 9 अक्तूबर, 2008 को सिंगापुर विधि अकादमी में "वर्ष 2008 के लिए वार्षिक व्याख्यान" देने सिंगापुर गये। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम वैश्विक भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्कूल का तृतीय परिसर खोलने और नान्यांग प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय से मानद डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने 26-27 अगस्त 2008 को सिंगापुर गये। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ आसियान-भारत आर्थिक मामलों के मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने अगस्त 2008 में सिंगापुर गये। केन्द्रीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद "टर्नएराउण्ड ऑफ इण्डियन रेलवेज" पर इन्सीड में अभिभाषण देने 11-14 मई 2008 को सिंगापुर गये। सूचना और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल "पी बी डी सिंगापुर" में हिस्सा लेने अक्तूबर, 2008 में सिंगापुर गये। वह सिंगापुर ऊर्जा सम्मेलन में "चेन्जिंग आवर वे ऑफ लाइफ" विषय पर बीज व्याख्यान देने 4-6 नवम्बर 2008 को सिंगापुर भी गये थे। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने आसियान मंत्रियों की 41वीं बैठक और 15वीं ए आर एफ बैठक के लिए 22-24 जुलाई 2008 को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की। भारत से दूसरे महत्वपूर्ण दौरे थेः योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोण्टक सिंह अहलूवालिया (सितम्बर 2008); भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर, डॉं वाई. वेणुगोपाल रेड्डी (मई 2008); रक्षा राज्य मंत्री श्री एम. एम. पल्लम राजू शांगरी ला वार्ता में हिस्सा लेने (मई 2008) दिल्ली के उप राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना(अगस्त 2008); केरल के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री पी. के. श्रीमती टीचर(नवम्बर 2008); जल आपूर्ति और सफाई राज्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार श्री रंजीत काम्बले और केन्द्रीय शहरी विकास सचिव डॉं एम. रामचन्द्रन अन्यों के साथ 23-26 जून 2008 को सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह में हिस्सा लेने सिंगापुर गये थे।

सिंगापुर की ओर से व्यापार और उद्योग मंत्री श्री लिम हैंग कियांग 23-24जून, 2008 को भारत के सरकारी दौरे पर आए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ के साथ अपनी बैठक के दौरान श्री लिम ने भारत-सिंगापुर आर्थिक सहयोग के अगले चरण की कार्ययोजना का एक प्रारूप पेश किया और दोनों पक्षों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई कि 2012 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 48 बिलियन सिंगापुर डालर किया जाएगा। सिंगापुर के विदेश राज्य वरिष्ठ मंत्री डा. बालाजी सदाशिवम 17 से 23 जून, 2008 तक गुजरात, तमिलनाडु और केरल में एक व्यापार मिशन की अगुवाई की। इस व्यापार मिशन का आयोजन सिंगापुर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल और अंतरराष्ट्रीय उद्यम सिंगापुर और सिंगापुर गुजराती सोसाइटी द्वारा किया गया। गुजरात में सिंगापुर का प्रतिनिधिमण्डल गुजरात के मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं, रियल एस्टेट, बंदरगाह फार्मा, तेल और गैस ,पेट्रोकेम और अन्य उद्योगों में गहरी रूचि प्रकट की। केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सिंगापुर प्रतिनिधिमण्डल के केरल दौरे के दौरान उनके साथ परिचर्चा सत्र का आयोजन किया।

31 अक्तूबर, 2008 को स्थिति के अनुसार मिशन ने 78, 703 कोंसुली सेवाएं प्रदान की है जिनमें 44,200 वीजा सेवाएं और 14,370 पासपोर्ट सेवाएं भी शामिल हैं। मिशन सितम्बर 2007 से वीजा सेवाएं बाहरी स्रोतों से करवा रहा है और पासपोर्ट सेवाएं दिसम्बर 2008 में बाहरी स्रोत से उपलब्ध कराई गईं।

थाइलैण्ड

भारत- थाइलैण्ड संबंध बहुआयमी है और हाल के वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में इन संबंधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और आने वाले वर्षों में खासतौर पर मुक्त व्यापार के क्षेत्र में इनका और भी विस्तार होने की संभावना है।

प्रधान मंत्री सुरायुद की जून 2007 में भारत की राजकीय यात्रा से दोनों पक्षों में वृहत्तर सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा जगी है। तब से कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अनेक क्षेत्र विशिष्ट करारों के माध्यम से एक व्यापक संस्थागत ढॉचा भी तैयार किया गया है।

एच आर एच राजकुमारी महा चक्री सिरिधोर्न ने मार्च 2008 में भारत की सरकारी यात्रा की।

दोनों पक्षों की ओर से अनेक स्तरों पर उच्च स्तरीय दौरे नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी जनवरी 2008 में भारत- आसियान पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने बैंकाक गयी। उप उद्योग मंत्री महामहिम श्री पियाबत्र योल्विजर्न ने एक अन्य उच्च स्तरीय थाई प्रतिनिधिमण्डल के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के दौरे की जनवरी 2008 में अगुवाई की।

द्विपक्षीय व्यापार 5 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर चुका है। दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह में सतत् वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के माध्यम से टाटा कम्पनी ने थाइलैण्ड में अपना कारोबार शुरू किया है। अप्रैल 2000 से अगस्त 2007 के दौरान थाईलैण्ड से भारत को एफ डी आई आगत 41 मिलियन अमरीकी डालर रही। भारत में निवेश करने वाली प्रमुख थाई कम्पनियों के नाम हैं; सी. पी. एक्वाकल्वर लि., इटाल थाई डेवलपमेण्ट पी सी एल, क्रंग थाई बैंक पीसीएल, शेरोन पोकफण्ड प्राइवेट लिमिटेड, स्टैनेली इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, थाइ

सम्मिट नील ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और थाई एअरवेज इंटरनेश्नल पी सी एल। थाइलैंड में अनुमोदित भारतीय निवेश 2001से 2006 के दौरान 268.8 मिलियन अमरीकी डालर था। प्रमुख भारतीय कम्पनियाँ है; आदित्य बिरलाग्रुप, थाई बड़ोदा इंडस्ट्रीज, ऊषा श्याम स्टील इण्डस्ट्रीज, रैनबक्सी लेबोरेटरीज, लूपिन लेबोरेटरीज, इण्डो-रामा ग्रुप, इन्फोटेक सत्यम कम्प्युटर्स, एनआई आई टी, टाटा स्टील(थाइलैण्ड) और टाटा मोटर्स।

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गठित संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक बैंकाक में जनवरी 2008 में आयोजित की गई। भारत और थाइलैण्ड के बीच वायु सेवा संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर मार्च 2008 में हस्ताक्षर हुए थे। बैकाक भारत में 9 गंतकों से वायु मार्ग से जुड़ा है। दोनों देशों के बीच 106 साप्ताहिक उड़ाने हैं। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष थाइलैण्ड को 106 प्रशिक्षण स्लॉट प्रस्तावित करता है। भारतीय नागरिक थाइलैण्ड में पहुँचकर वीजा प्राप्त करने के पात्र हैं। दोनो देशों के बीच बहुत अधिक पर्यटकों का आना-जाना होता है। 2007 में 5.3 लाख भारतीयों ने थाइलैण्ड की यात्रा की और लगभग 40,000 थाई नागरिकों ने भारत की यात्रा की। लगभग 100,000 भारतीय मूल के नागरिक थाइलैण्ड में बसे हैं उनमें से बहुत से लोग उस देश में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। भारतीय समुदाय सम्पन्न है और वे वहाँ आदरपूर्वक रहते हैं।

तिमोर लेस्ते(टी एल)

तिमोर लेस्ते के राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रयासों में एक योगदान के रूप में भारत ने तिमोर लेस्ते को खासतौर पर क्षमता निर्माण के लिए सहयोग और सहायता प्रदान की है। भारत आई टी ई सी के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लॉट और जी सी एस एस छात्रवृत्तियां तिमोर लेस्ते को प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 के लिए 5 आई टी ई सी प्रशिक्षण स्लॉट और 10 जी सी एस एस छात्रवृत्तियाँ आबंटित की गई थीं किन्तु टी एल सरकार अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए छोड़ नहीं सकी जिससे इनका काफी कम उपयोग हो सका। भारत ने सतत् विकास के लिए उपकरणों और सामानों की खरीद हेतु 2008 में तिमोर लेस्टे को100 000 अमरीकी डालर का अनुदान दिया है।

तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉ. जोस रेमोस होरटा को अपना प्रत्यय प्रत्र प्रस्तुत किया।

वियतनाम

वियतनाम के उप विदेश मंत्री श्री वु डुंग ने 3-4 जनवरी 2008 को भारत की यात्रा की। उनकी सचिव (पूर्व), सचिव(वाणिज्य), सचिव(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) और ओ एन जी सी विदेश लि. के प्रबंधन निदेशक के साथ बैठकें हुईं और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री लि होंग अन्ह 20-25 मार्च, 2008 को भारत दौरे पर आए। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, वियतनामी पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा भारत के सहयोग से वियतनाम में एक साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। वह 25 मार्च 2008 को प्रधानमंत्री से मिलने गये।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 24- 28 नवम्बर 2008 को वियतनाम की राजकीय यात्रा की। दौरे के दौरान वे वियतनाम के राष्ट्रपति, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, वियतनाम के प्रधान मंत्री और अन्य वियतनामी नेताओं से मिलीं और अनेक द्विपक्षीय और परस्पर हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कीं। राष्ट्रपति हो ची मिन्ह सिटी और हनोई भी गईं। दौरे के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। वियतनामी वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा भारतीय व्यापार मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर हुए।

रक्षा आदान-प्रदान में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के रक्षा सचिव ने अक्तूबर, 2008 में सुरक्षा वार्ता के चौथे दौर के लिए वियतनाम की यात्रा की। दो भारतीय नौसेना पोतों- आई एन एस कोरा और आई एन एस किरपाण की यात्रा अप्रैल 2008 में सम्पन्न की गई।

विदेश मंत्रालय के प्रेस और सूचना विभाग के एक अधिकारी की अगुवाई में 12 वियतनामी पत्रकारों का एक दल(मुद्रण और दृश्य दोनों मीडिया के) 26 अप्रैल-2 मई 2008 को भारत यात्रा पर आया था। इस यात्रा का उद्देश्य 7 जुलाई 2008 को सामरिक भागीदारी की पहली वर्षगांठ से पहले वियतनाम में इसका प्रचार-प्रसार करना था।

भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार विगत वर्षों में तेजी से प्रगित कर रहा है। द्विपक्षीय व्यापार के 2008 में 3 बिलियन अमरीकी डालर पार कर लेने की आशा है।

वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का लगातार समर्थन करता रहा है। भारत ने वर्ष 2008-09 के लिए यू एन एस सी की अस्थायी सीट के लिए वियतनाम की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

प्रशांत द्वीपसमूह मंच

नियू में 39वीं प्रशांत द्वीपसमूह मंच(पी आई एफ) शिखर बैठक सम्पन्न होने के बाद भारत ने वहाँ 21 अगस्त 2008 को आयोजित 20 पोस्ट-मंच वार्ता (पी एफ डी) भागीदार बैठक में हिस्सा लिया।

पी एफ डी भागीदार बैठक के दौरान विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने जोर देकर कहा कि भारत का मुख्य लक्ष्य मानव संसाधन विकास, द्विपक्षीय सहायता और निवेश तथा व्यापार में वृहत्तर भागीदारी है ताकि प्रशांत द्वीप समूह देशों को उनकी जरूरतों के आधार पर क्षमता निर्माण में सहायता और परियोजना सहायता प्रदान की जा सके जिससे कि इन देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान किया जा सके।

क्षेत्र में हित से जुडे निम्नलिखित मुद्दों पर विषय-संगत चर्चा की गईः (क) मौसम के परिर्वतन (ख) ऊर्जा सुरक्षा (ग) खाद्य सुरक्षा (घ) मत्स्य पालन। वार्ता भागीदारों को इनमें से किसी भी विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। विदेश राज्य मंत्री मौसम के परिवर्तन पर बोले।

प्रशांत द्वीपसमूह मंच सदस्यों के पी एफ डी भागीदार बैठक में विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद द्वारा निम्नलिखित "क्षेत्रीय सहायता पहल" की घोषणा की गई जिसका भलीभांति स्वागत किया गया। वास्तव में यह पी एफ डी भागीदारों की ओर से केवल एक ठोस प्रस्ताव था। इस पहल के अंतर्गत आने वाले वर्षों में भारत प्रशांत द्वीपसमूह के देशों के लिए निम्नलिखित सहायता पैकेजों को कार्यान्वित करेगाः

1. 14 पात्र प्रशांत द्वीप के देशों में से प्रत्येक को 100 000 अमरीकी डालर की अनुदान सहायता, जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों और सतत विकास वाली परियोजनाओं के लिए उपकरणों और सामाग्रियों की आपूर्ति के लिए किया जाएगा।

2. सुवा मे जहाँ प्रशांत द्वीप सचिवालय स्थित है टी ई आर आई(ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली)द्वारा प्रशांत द्वीप के देशों के अधिकारियों के लिए "भारत-प्रशांत द्वीप वाले देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण पर कार्यशाला" का आयोजन;

3. विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में प्रशांत द्वीप के देशों के राजनयिकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना;

4. भारत के आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत सभी प्रशांत द्वीप वाले देशों को सतत् रूप से प्रशिक्षण अवसर प्रदान करना।

5. प्रत्येक प्रशांत द्वीप वाले देश को पूर्व स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति प्रदान करना।

राष्ट्रमण्डल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने 39वीं प्रशांत द्वीप मंच शिखर बैठक में हिस्सा लिया। विदेश राज्य मंत्री और राष्ट्रमण्डल महासचिव नियू में मिले।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी का सोलोमन द्वीप और वानुवातू ने समर्थन किया है।

सोलोमन द्वीप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है। सोलोमन द्वीप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता(2011-12) के लिए हमारी उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन की भी पुष्टि की है। सोलोमान द्वीप ने राष्ट्रमण्डल महासचिव के पद के लिए श्री कमलेश शर्मा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था।

आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सोलोमन द्वीप समूह और वानुआतू प्रत्येक को 5-5 स्लॉट प्रस्तावित किया है। इन स्लॉटों का पूरा उपयोग किया गया है और संबंधित सरकारों द्वारा इनकी सरहाना की गई है।

नियूः 2007 में घोषित अनुदान सहायता के रूप में 100 000 अमरीकी डालर की धनराशि जून 2008 में भुगतान की गई जिसका उपयोग सड़को के सुधार, ग्रामोद्धार और इण्टरनेट संचार सुविधा सुधार संबंधी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

नौरूः आम चुनाव 26 अप्रैल 2008 को नौरू में आयोजित कराए गए थे। इस चुनाव में राष्ट्रपति मारकस स्टीफेन की मुकम्मल जीत हुई जिन्हें नई संसद के लिए दुबारा चुना गया।

पलाऊ गणराज्य और मारशल द्वीप गणराज्यः भारत सरकार ने पलाऊ गणराज्य और मारशल द्वीप गणराज्य को उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 000 अमरीकी डालर की राशि प्रदान की।

फिजीः फिजी सरकार को महिलाओं की आर्थिक दशा के सुधार संबंधी उनकी परियोजना के लिए 26, 900 अमरीकी डालर की धनराशि दी गई।

■■

पूर्व एशिया

3

जापान

हाल के वर्षों में भारत-जापान संबंधों में महत्वपूर्ण और गुणात्मक बदलाव आया है जिसके अंतर्गत नियमित तौर पर सफल शिखर स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं। प्रधान मंत्री कोइजुमी और प्रधान मंत्री एबे ने क्रमशः अप्रैल 2005 और अगस्त 2007 में भारत की यात्रा की था। वर्ष 2006 में प्रधान मंत्री के दौरे के दौरन हस्ताक्षर किए गए संयुक्त वक्तव्य के बाद भारत-जापान सामरिक और वैश्विक भागीदारी की स्थापना हुई। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दिसम्बर 2006 में और 22-23 अक्तूबर, 2008 को जापान की यात्रा की। प्रधान मंत्री ने जापानी प्रधान मंत्री एसो से बातचीत की। उन्होंने सम्राट, जापानी विदेश मंत्री, अर्थव्ययवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री तथा नई कोमीटो पार्टी और जापान की डिमोक्रैटिक पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधान मंत्री ने जापान के एक शीर्ष संघ केइडान्रेन द्वारा आयोजित एक व्यापारिक भोज को संबोधित किया जिसमें प्रमुख जापानी निगमों के अग्रणी सीईओ उपस्थित थे। द्वितीय भारत-जापान व्यापार नेताओं के मंच का आयोजन किया गया और भारत-जापान आर्थिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में दोनों प्रधान मंत्रियों की सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। भारत और जापान के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी की वृद्धि पर एक संयुक्त वक्तव्य और भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर इस दौरे के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

जापान के विदेश मंत्री मैसाहिको कोउमुरा ने भी सामरिक वार्ता के दूसरे दौर में भाग लेने 4-5 अगस्त, 2008 को भारत का दौरा किया। भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोण्टेक सिंह अहलूवालिया ने जापान की यात्रा की। भारत के नौसेना प्रमुख की 19-24 अगस्त, 2008 की जापान यात्रा से रक्षा और सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। जापनी उच्च सदन(हाउस ऑफ काउंसिलर) के अध्यक्ष श्री सतसुकी ईडा ने 1-3 जुलाई 2008 को भारत की यात्रा की।

भारतीय पक्ष से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल 5-7 अक्तूबर, 2008 को जापान दौरे पर गये। योजना अयोग के उपाध्यक्ष डा.मोण्टेक सिंह अहलूवालिया 17 सितम्बर, 2008 को जापान के अर्थ व्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता के तीसरे दौर के लिए जापान गये और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ ने द्वितीय भारत जापान नीति वार्ता के लिए 21 अक्तूबर, 2008 को जापान की यात्रा की। रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने 12-16 जनवरी, 2009 को जापान की यात्रा की। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एण्टोनी का फरवरी के अंत में जापान यात्रा पर जाना निर्धारित है।

भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष और जापान अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा उद्योग मंत्री की सहअध्यक्षता में भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के तीसरे दौर की बैठक 17 सितम्बर, 2008 को टोक्यों में आयोजित की गई। इस वार्ता का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्रों में व्यापक तरीके से सहयोग को बढ़ावा देना है। बिजली उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा में भावी सहयोग के क्षेत्रों की रूपरेखा पर दोनों मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किए।

जापान-भारत नीति वार्ता की दूसरी बैठक 21 अक्तूबर, 2008 को टोक्यों में आयोजित की गई थी जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच और व्यापक और गहरे आर्थिक रिश्ते स्थापित करना है। दोनों पक्षों ने क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ और जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री निकाई तोशिहिरो की अगुवाई में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारों करार(सी ई पी ए), वैश्विक व्यापार वार्ता में सहयोग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॅरीडोर का संवर्धन, भारतीय एस एम ई के लिए सहयोग और साथ ही आसियान और पूर्व एशियाई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़ी वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की।

विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श के लिए 6 अक्तूबर, 2008 को जापान गये। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जापानी विदेश मंत्री मसाहिको कौमुरा से मुलाकात की।

सभी आर्थिक मुद्दों पर एक बहुआयमी वार्ता तंत्र विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय सामरिक आर्थिक वार्ता शुरू की गई है। वित्त सचिव और जापान के उप विदेश मंत्री की सहअध्यक्षता में इसकी दूसरी बैठक 24 जुलाई, 2008 को टोक्यो में आयोजित की गई थी।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के बढ़ने की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री एबे की यात्रा के दौरान यह सहमति हुई थी कि वर्ष 2010 तक 20 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार लक्ष्य पाने के लिए कोशिश की जाएगी। गतिरोध की अवधि के बाद हाल के व्यापार संबंधी आकड़े द्विपक्षीय संबंधों में अच्छी प्रगति का संकेत देते हैं। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के

आकड़ों के अनुसार 2007-08 में दोनों ओर का व्यापार 9.89 बिलियन अमरीकी डालर रहा (निर्यात 3.5 बिलियन अमरीकी डालर और आयात 6.3 बिलियन अमरीकी डालर) जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है।

जापान वर्तमान में भारत में आने वाले संचयी विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश के मामले में छठे स्थान पर है। जापनी कम्पनियों ने वर्ष 1991 और मार्च 2008 के बीच 3 बिलियन अमरीकी डालर का वास्तविक निवेश किया है जिसमें मौजूदा शेयरों की खरीद,भारतीय रिजर्व बैंक की एन आर आई स्कीमों, स्टॉक विनियम और जारी होने वाले शयरों के लिए प्राप्त आमद के रूप में प्राप्त एफ डी आई शामिल नहीं है। भारत में अधिकांश प्रत्यक्ष जापानी निवेश आटोमोबाइल उद्योग (39%),विद्युत उपकरण (17%), ट्रेडिंग(6), सेवा क्षेत्र (वित्तीय और गैर वित्तीय) (5%) और दूरसंचार (3%)के क्षेत्रों में हुआ है। वर्ष के दौरान जापानी कम्पनियों द्वारा दो बड़ी भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदे गए: डैची सैंक्यों ने रैन बैक्सी लेबोरेटरी के 34% स्टेक खरीदे जिनकी कीमत 215.6 बिलियन रूपए या 4.6 बिलियन अमरीकी डालर है और एन टीटी डोकोमो ने टाटा टेलिसर्विसेस के 26% स्टेक खरीदे जिनकी कीमत 13,070 करोड़ रूपए या 2.7 बिलियन अमरीकी डालर है।

विगत 5 वर्षों में भारत जापानी शासकीय विकास सहायता(ओ डी ए) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है। मार्च 2008 तक वचनबद्धता आधार पर भारत को जापानी ओडीए ऋण की संचयी बचनबद्धता 2662.56 बिलियन येन (मौजूदा विनिमय दरों पर लगभग 101497 करोड़ रु तक पहुँच गया है। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर के ओ डी ए के पहले बैच को औपचारिक रूप देने के लिए नोटों का विनमय किया गया।

दोनों पक्षों द्वारा जनवरी/फरवरी 2007 से शुरू होने वाले व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी ई पी ए) के लिए भी वार्ता शुरू कर दी गई है। इस वार्ता की अगुवाई भारत की ओर से वाणिज्य सचिव और जापान की ओर से उप विदेश मंत्री द्वारा की गई है। दोनों पक्षों के बीच दो वर्ष के समय सीमा के भीतर वार्ता पूरी करने पर सहमति हुई है।

जापान ने ओडीए/एस टी ई पी ऋण सहायता के माध्यम से समूची वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर में सहायता के लिए अपनी तत्परता से अवगत कराया है। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि पश्चिमी कोरिडोर के प्रथम चरण के लिए ओडीए की कुल मात्रा लगभग 450 बिलियन येन होगी। दोनों प्रधान मंत्रियों ने पश्चिमी कोरिडोर के लिए जापानी सहायता को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए साथ मिलकर कार्य करने की अपनी वचनब्द्धता भी जाहिर की।

प्रधान मंत्री की दिसम्बर 2006 में जापान यात्रा के दौरान दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएम आई सी) के विकास हेतु प्रस्ताव पर सहमति हुई थी। 1483 किमी. लम्बा डी एम आई सी अहमादाबाद, पालमपुरा, फुलेरा, रेवाड़ी और दादरी होकर गुजरेगा। पूरी कार्ययोजना तैयार करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डी आई पी पी) के सचिव और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय(एम ई टी आई) के उप मंत्री की सहअध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य बल (जे टी एफ) की स्थापना की गई है। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान दोनों पक्षों द्वारा यह पुष्टि की गई कि डी एम आई सी के लिए परियोजना विकास निधि की स्थापना के लिए दोनों मिलकर कार्य करेंगे। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन तथा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

उच्च प्रौद्योगिकी हेतु द्विपक्षीय परामर्शदात्री तंत्र के तीसरे दौर की बैठक 13 जून, 2008 को टाक्यो में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य दोनों ओर से उच्च प्रौद्योगिक व्यापार को सुगम बनाना और उनकी अपनी-अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मसलों को हल करना था। जून 2008 में जापान सरकार ने अपनी एण्ड-यूजर सूची से 7 भारतीय कम्पनियों के नाम हटा दिये जिससे सूची में भारतीय कम्पनियों की कुल संख्या घटकर 26 रह गई।

आई ए ई ए पर सर्ववम्मति प्रकट करने में जापान भी शामिल हुआ और भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय ऊर्जा करार के संदर्भ में एन एस जी दिशा-निर्देशों से भारत को छूट देने के मामले में भी जापान ने एन एस जी में हमारा पक्ष लिया।

रक्षा और सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आए हैं। एक संस्थागत ढांचे के अंतर्गत् आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2008 के लिए कार्यक्रमों के एक कैलेण्डर को अंतिम रूप दिया गया। सचिव स्तरीय वार्षिक रक्षा नीति वार्ता अप्रैल 2007 में आयोजित की गई थी और नवम्बर 2008 में नई दिल्ली में इसके दूसरे दौर की बैठक हुई थी। 3 जापानी समुद्री आत्म रक्षा पोतों का जत्था अगस्त 2008 में सद्भावना मिशन पर मुंबई आया था। व्यापक सुरक्षा वार्ता(सीएस डी) और सेना से सेना की बातचीत 14 फरवरी 2008 को टोक्यो में आयोजित की गई थी। भारत के नौसेना प्रमुख ने 19-24 अगस्त, 2008 को जापान की यात्रा की थी।

नवम्बर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रधान मंत्री टैरो एसो का एक शोक संदेश प्राप्त हुआ था और विदश मंत्री हिरोफूमी नाकासोन का एक वक्तव्य आया था। प्रधान मंत्री टैरो एसो ने 30 नवम्बर को प्रधान मंत्री से टेलिफोन पर बात की थी और आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ सहयोग हेतु जापान की इच्छा की पुष्टि की थी।

द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ता 17-18 जून, 2008 को टाक्यो में आयोजित की गई थी। भारत और जापान के बीच वायु यातायात के विस्तार और उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई। उड़ानों के फेरे दोगुना करके एक सप्ताह में 42 बार

कर दिए गए हैं। 2010 की गर्मियों में टोक्यो-नारिता हवाई अड्डे का काम पूरा होने के बाद भारत को उपलब्ध स्लाट मौजूदा 8 से बढ़कर 28 प्रति सप्ताह हो जाएंगे। चल रहे टोक्यो-हनेडा हवाई अड्डा विस्तार कार्य सम्पन्न होने के बाद जापान भारत को अतिरिक्त 28 स्लाट मुहैया कराएगा। 5वें स्वतंत्रता फेरे 14 से बढ़ाकर 21 प्रति सप्ताह कर दिये गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल के अंतर्गत् दोनों पक्ष नैनो प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चलाने और गहरे समुद्र में वैज्ञानिक ड्रिलिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान टोक्यों में अक्तूबर, 2008 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे जिससे हमें उच्च-ऊर्जा भोतिकी में प्रयोग के लिए सुकूबा में जापानी सुविधा के ई के से अपने खर्च पर "बीम लाइन" बनाने की अनुमित मिल जाएगी।

अगस्त, 2007 में प्रधान मंत्री एबे की यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्ष एक नए आई आई टी की स्थापना करने के लिए अध्ययन और करने संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए एक कार्य दल गठित करने की पहल करेंगे। इस कार्य दल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 1 मई, 2008 को आयोजित की गई थी। अक्तूबर, 2008 में प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान जे डब्ल्यू जी ने दोनों प्रधान मंत्री को एक रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों ने हैदराबाद में एक नए आई आई टी की स्थापना में सहयोग करने हेतु अपनी बचनबद्धता की पुष्टि की जो भारत में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए संयुक्त प्रयास का प्रतीक बनेगा जिसमें जापान का वित्तीय सहयोग भी शामिल होगा। दोनों पक्षों द्वारा इसकी स्थापना के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा रही है।

वाणिज्य मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार 2007-08 में दोनों ओर का व्यापार 9.89 बिलियन अमरीकी डालर पहुँच चुका है जो विगत वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। जापान वर्तमान में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 6ठें स्थान पर है। विगत 5 वर्षों में भारत जापानी सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है।

कोरिया गणराज्य(आर ओ के)

कोरिया गणराज्य के साथ हमारे संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल के वर्षों में इनके क्षेत्रों का और अधिक विस्तार हुआ है। हमारे राजनैतिक संबंध उत्कृष्ट हैं और क्षेत्रीय राजनैतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर हमारे विचारों में तालमेल बढ़ रही है।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम फरवरी, 2008 में कोरिया गणराज्य के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपित श्री ली म्यंग-बैक के निजी न्यौते पर भाग लेने गये।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 8 जुलाई, 2008 को सैपोरो, जापान में आयोजित जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली म्यंग-बैक से मिले। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ली ने प्रधान मंत्री को कोरिया गणराज्य आने का निजी तौर पर न्यौता दिया।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कोरिया गणराज्य के नौसेना आपरेशन प्रमुख ने 18-21 मई, 2008 को भारत की यात्रा की और हमारे नौसेना प्रमुख ने 24-28 अगस्त, 2008 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की। मध्य कमान के जी ओ सी-इन-सी ने 17-19 सितम्बर, 2008 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की। फ्लैग अफिसर कामाण्डिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने 5-10 अक्तूबर, 2008 को कोरिया गणराज्य में पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी एवं अंतरराष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। दो भारतीय नौसेना पोतों ने इस समीक्षा में हिस्सा लिया। कोरिया गणराज्य के दो नौसैनिक पोत 625 कार्मिकों के साथ 30 सितम्बर-3 अक्तूबर, 2008 तक सद्भावना दौरे पर कोचिन पत्तन पर आए।

भारतीय और कोरिया गणराज्य के तटरक्षा के बीच हुए समझौता ज्ञापन का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षा के महानिदेशक, 27-29 अगस्त, 2008 को कोरिया गणराज्य गए और कोरियाई तट रक्षक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। भारतीय तटरक्षक और कोरियाई तट रक्षा के बीच तृतीय उच्च स्तरीय बैठक 15 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कोरियाई प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई कोरियाई तट रक्षा के रक्षा ब्यूरो महानिदेशक ने की।

रक्षा उद्योग और संभार तंत्रीय सहयोग संबंधी भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 13 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों पक्षों के बीच रक्षा उद्योग और अनुसंधान तथा विकास सहित संभारतंत्रीय व्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी करार(सी ई पी ए) पर वार्ता के 12 दौर पूरे हो चूके हैं और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत और कोरिया दोनों को आशा है कि सी ई पी ए को 2009 के अंत तक सम्पन्न कर दिया जाएगा।

हाल के वर्षों में भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2007 में यह 11.22 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया जो वर्ष 2010 के लिए निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है। 2008 के पूर्वाद्ध के दौरान कोरिया गणराज्य के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक रहा है। कोरिया का विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश में 9वां स्थान हैं और वह हमारा एक प्रमुख निवेश भागीदार है।

कोरिया गणराज्य ने मई, 2008 में नई दिल्ली में एक पर्यटन संवर्द्धन कार्यालय स्थापित किया है।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया के बीच सीधे तौर पर और 2000 वर्षों से अधिक समय से बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी आपसी संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध मंगोलियाई प्रधान मंत्री श्री एन. एनखबयार की 2004 में हुई भारत यात्रा के दौरान "भागीदारी के नए स्तर" तक पहुँच गए।

प्रधान मंत्री अक्तूबर, 2008 में बीजिंग में आयोजित 7 वें एसेम शिखर सम्मेलन के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति एन एनखबयार से मिले। दोनों नेताओं ने भारत- मंगोलिया द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की और परस्पर हितों के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रही।

रक्षा के क्षेत्र में भारत-मंगोलिया सहयोग में वर्ष 2008 के दौरान खूब प्रगति हुई। मंगोलियाई सशस्त्र बल के सामान्य स्टॉफ के प्रमुख ले. जनरल स. टोगू ने फरवरी, 2008 में भारत की यात्रा की। चौथा भारत-मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास "नोमैडिक एलिफैण्ट 2008" 17-30 नवम्बर, 2008 को भारत में आयेजित किया गया। भारत ने अगस्त-सितम्बर, 2008 में मंगोलिया में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास "खान क्वेस्ट 2008" में भी हिस्सा लिया।

भारत और मंगोलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एन एस सी) के बीच वर्ष के दौरान परस्पर वार्ता नियमित तौर पर चलती रही। मंगोलिया के जनरल इण्टेलिजेंस एजेंसी के निदेशक श्री आर बोल्ड ने फरवरी, 2008 में भारत की यात्रा की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का 5 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमण्डल अध्यक्ष, जे आई सी श्री एच उपाध्याय की अगुवाई में सितम्बर, 2008 में उलानबतार गया और मंगोलिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से बातचीत की।

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) के महानिदेशक की अगुवाई में तीन-सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमण्डल परस्पर हित के विषयों पर चर्चा के लिए जुलाई, 2008 में मंगोलिया गया। मेजर जनरल बातर्टसोग्त आजाद, अध्यक्ष सीमा संरक्षण सामान्य बोर्ड, मंगोलिया 20-26 जनवरी, 2009 को भारत आए और दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने के संबंध में बीएसएफ से बातचीत की।

रक्षा सहयोग संबंधी भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्यदल (जे डब्ल्यू जी) की दूसरी बैठक 5-6 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

मंगोलिया के रक्षा मंत्री महामहिम श्री एल. बोल्ड 10-12 फरवरी, 2009 को भारत दौरे पर आने वाले हैं।

भारत-मंगोलिया संयुक्त स्कूल का उद्घाटन 2002 में सम्पन्न एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 2003 में किया गया। इस समझौता ज्ञापन का विस्तार पाँच और वर्षों 2012 तक के लिए किया गया ह। राजीव गाँधी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और अटल बिहारी वाजपेई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र जिनकी स्थापना भारतीय सहायता से क्रमशः 1992 और 2002 में की गई थी, अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

मंगोलियाई सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने मई, 2008 में मंगोलिया को आपात खाद्य सहायता के रूप में 5000 मी.ट. चावल और 5000 मी.टन चीनी प्रदान की है।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर, 2008 में बीजिंग में आयोजित 7 वें एसेम शिखर सम्मलेन के दौरान अलग से मंगोलिया के राष्ट्रपति एन. एनखबयार से मुलाकत की थी। दोनों नेताओं ने भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा की और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य (डी पी आर के)

भारत और डी पी आर के के बीच संबंध परम्परागत रूप से और मानवीय विषयों एवं मानव संसाधन विकास सहायता को केन्द्र बनाकर सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। संस्कृति, खेलकूद और शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान में लगातार प्रगति हो रही है।

विदेश मंत्रालय में सचिव श्री एन. रवि ने 27-28 मई, 2008 को डी पी आर कोरिया के उप विदेश मंत्री श्री किम योंग-II के साथ वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श के 5वें दौर के लिए प्योंगयांग गये थे।

भारतीय फिल्मों ने 17 से 26 सितम्बर, 2008 तक आयोजित 11वें प्योंगयाँग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिस्सा लिया और बंग्ला फिल्म "एक नादिर गल्पो" (एक नदी की कहानी) को इस समारोह में संगीत के लिए पुरस्कृत किया गया।

डी पी आर के में मानव संसाधन विकास के लिए हमारी सहायता का सतत् विस्तार हो रहा है। डी पी आर के को वर्ष 2008-09 के लिए आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत 18 स्लॉट आबंटित किए गए थे। हमने आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र, पंचमढ़ी में डी पी आर के को अंग्रजी भाषा पाठ्यक्रम के लिए 2 स्लॉटों का प्रस्ताव भी किया है। आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल, 2008 में डी पी आर के को पाँच किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले जौ का बीज भी भेजा गया था। भारत और डी पी आर के संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग बनाए रखे हैं।

■■

4 यूरेशिया

भारत ने दौरों, द्विपक्षीय करारों को सम्पन्न करके, आवधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं, सहयोग कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों के माध्यम से वर्ष के दौरान रूस, उक्रेन, बेलारूस, मध्य एशिया और काकेशियन देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और उन्हें आगे बढ़ाया। विभिन्न क्षत्रों में सहयोग की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अंतः सरकारी बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2008 को भारत में रूस वर्ष के रूप में मनाया गया और वर्ष 2009 को रूस में भारत वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय कार्यकलापों में दिसम्बर, 2008 में रूसी महासंघ के राष्ट्रपति श्री डीमिट्री ए. मेडवेडेव की कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नुरसुज्तान नजरबायेव की गणतंत्र दिवस 2009 के मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय यात्राएं और अप्रैल 2008 में भारत के उपराष्ट्रपति की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा शामिल थी। भारत ने मई 2008 में रूस में आयोजित भारत-रूस-चीन के साथ-साथ ब्राजील-रूस-भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की बैठकों में हिस्सा लिया तथा क्रमशः अगस्त और अक्तूबर, 2008 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में प्रेक्षक के रूप में हिस्सा लिया।

रूस

वर्ष के दौरान भारत राजनीतिक वार्ता, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में चल रहे बहु-आयामी सहयोग एवं द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी में और विविधत एवं सुदृढ़ता लाने के लिए सभी स्तरों पर रूस के साथ सक्रियता से संबद्ध है। रूसी महासंघ के राष्ट्रपति श्री डीमिट्री ए. मेडवेडेल द्विपक्षीय वार्षिक शिखर वार्ता के लिए 4-5 दिसम्बर, 2008 को भारत के राजकीय दौरे पर आये। अपने दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों से मिले। भारतीय और रूसी राष्ट्रपति भारत में "रूस वर्ष" के समापन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधान मंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मेडवेडेव द्वारा एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें द्विपक्षीय सहयोग की प्रमुख दिशाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर साझी स्थिति को इंगित किया गया है। दौरे के दौरान 9 अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें कुदनकुनम स्थान पर अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्र इकाइयों के निर्माण और भारत गणराज्य में नए स्थानों पर रूस द्वारा अभिकल्पित नाभिकीय विद्युत संयंत्र के निर्माण में सहयोग पर अंतर-सरकारी करार; मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त कार्यकलापों पर इसरो और रूसी संघीय अंतरीक्ष एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन; भारत की वित्तीय आसूचना इकाई और रूसी वित्तीय मानीटरिंग सेवा के बीच सहयोग पर करार; और भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रूसी महासंघ की फेडरल वित्तीय बाजार सेवा के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल हैं जो परस्पर सहयोग और सूचना आदान-प्रदान से संबंधित हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे किए गएः

- उद्योग और व्यापार मंत्री श्री विक्टर खिस्टेन्को ने 25-27 नवम्बर, 2008 को भारत की यात्रा की और भारत में आयोजित रूसी राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्‌घाटन किया।
- ऊर्जा मंत्री श्री सरजेई स्मात्को ने 25-26 नवम्बर, 2008 को भारत की यात्रा की और भारत- सी आई एस हाइड्रोकार्बन सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने 4-5 नवम्बर, 2008 को मास्को की यात्रा की और रूसी प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमीर पुतिन एवं रूसी ऊर्जा मंत्री श्री सरजेई श्मात्को से मुलाकात की।
- रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पट्रुशेव ने 21-24 अक्तूबर, 2008 को भारत की यात्रा की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री श्री सरजे लवरोव 20 अक्तूबर, 2008 को भारत आये और विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिले।
- रूस के रक्षा मंत्री, श्री अनातोली सरडुको ने 28-30 सितम्बर, 2008 को भारत के रक्षा मंत्री के साथ सहअध्यक्ष के रूप में सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की 8वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने 13 अगस्त, 2008 को मास्को की यात्रा की और रूसी राष्ट्रपति तथा रूसी महासंघ के सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की।

5 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी रूस के राष्ट्रपति डिमित्री ए मेदवेदेव के साथ मुलाकात करते हुए।

24 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नुरसुल्तान नजरबायेव के स्वागत समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील, केंद्रीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी।

- विदेश मंत्री ने भारत-रूस-चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक तथा ब्राजील, रूस, भारत, चीन (बीआरआईसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए 14-16 मई, 2008 को यकात्रिनबर्ग, रूस की यात्रा की तथा द्विपक्षीय मंच पर रूस तथा चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की।
- रूसी परिसंघ की ओर से दो संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने अप्रैल, 2008 में भारत की यात्रा की, जिनमें से एक का नेतृत्व संसदीय प्रक्रिया से संबंधित आयोग तथा संघीय परिषद की संसदीय गतिविधियों के संगठन (रूसी संसद का ऊपरी सदन) के अध्यक्ष श्री निकोलाई ने किया तथा दूसरे में दुमा राज्य (रूसी संसद का निचला सदन) के पांच युवा सांसद शामिल थे।
- मॉस्को शहर का एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के साथ "रूसी वर्ष" के दौरान दिल्ली में मास्को दिवस आयोजित करने पर विचार-विमर्श करने के लिए 17-21 जून, 2008 को दिल्ली आया।

इसके अलावा बहुपक्षीय प्रासंगिक घटनाओं पर निम्नलिखित बहुपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गयी।

- प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 9 जुलाई, 2008 को जी-8 सम्मेलन के अवसर पर टोक्यो, जापान में रूस के राष्ट्रपति श्री डीमित्रे मेदवेदेव से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 63वीं बैठक के अवसर पर 29 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में विदेश मंत्री श्री सरजे लावरो से मुलाकात की।
- विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र के अवसर पर 26 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में आयोजित बीआरआईसी देशों (ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग का 14वां सत्र विदेश मंत्री तथा रूस के उप प्रधान मंत्री की सहअध्यक्षता में 3 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोग ने वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग व आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसका विस्तार करने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। सहअध्यक्षों ने आयोग के विचार-विमर्श पर तैयार एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए। सिस्तेमा कंपनी समूह के अध्यक्ष श्री ब्लादीमीर इबतु सेनको तथा रिलांइस उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी की सहअध्यक्षता में द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार संबंधों पर कार्रवाई करने के लिए तथा उसका संवर्धन करने के लिए भारत-रूस व्यापार के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की परिषद भी स्थापित की गयी थी। विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन तथा रूस के प्रथम उपविदेश मंत्री श्री एंड्रेयी डेनीसोव के बीच 30 जून, 2008 को मास्को में विदेश मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के विदेश कार्यालयों ने निम्नलिखित विषयोंः भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय वार्ता (फरवरी, 2008, मास्को); यूरोपीय संघ (मार्च, 2008, मास्को); कोंसली मुद्दों (अक्तूबर, 2008); ईरान व अफगानिस्तान (नवंबर, 2008, मास्को); अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (दिसंबर, 2008) पर विचार-विमर्श किया।

भारत में वर्ष 2008 में "रूसी वर्ष" के दौरान संस्कृति, अर्थव्यवस्था व विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में 140 समारोह आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत-रूस संयुक्त कार्यसमूह की 5वीं बैठक 16-17 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। आतंकवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव, श्री विवेक काटजू तथा रूसी पक्ष का नेतृत्व रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि श्री अन्नातोली साफोनोव ने किया।

श्री एल.के.पुनापा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत तथा रूस की सुरक्षा परिषद के मध्य संयुक्त समन्वय समूह की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 3-4 फरवरी, 2009 को मास्को की यात्रा की।

रूस के उप विदेश मंत्री श्री एलेक्से ब्रोदावकिन ने 25 फरवरी, 2009 को विदेश मंत्री तथा सचिव (पूर्व) श्री एन. रवि से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सामूहिक रूप से डीएफएम ब्रोदावकिन व दक्षिण एशियाई देशों (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, बांग्लादेश, म्यांमा, श्री लंका, मालद्वीव तथा नेपाल) के राजदूतों से मुलाकात की।

अर्मेनिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के आमंत्रण पर 12-15 सितंबर, 2008 को येरेवान के मेयर श्री यरवांद जखारियन की भारत यात्रा अर्मेनिया के साथ भारत के ऐतिहासिक, निकट व मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रतीत है। भ्रमणकारी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। येरेवान के मेयर तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली व येरेवान के मध्य निकटता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा उसी दिन येरेवान के मेयर तथा दिल्ली की मेयर सुश्री आरती मेहरा ने अर्मेनिया के नाम (भारत में तीसरा) पर दिल्ली की एक सड़क का नामकरण किया। भ्रमणकारी प्रतिनिधिमंडल ने आगरा की यात्रा भी की।

भारत के साथ वाणिज्यिक संबंधों में विस्तार लाने के लिए अर्मेनिया की बढ़ती दिलचस्पी को प्रदर्शित करने हुए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के संघ (फिक्की) तथा अर्मेनिया के

दूतावास ने संयुक्त रूप से 1-2 दिसंबर, 2008 को भारत-अर्मेनिया व्यापार मंच आयोजित किया। अर्मेनिया के प्रथम उप कृषि मंत्री श्री सामवेल अवेतीसियेन तथा आर्थिक उपमंत्री श्री मुसेग तुमासिया के साथ आए 10 सदस्यों वाले व्यापार प्रतिनिधिमंडल में सूचना प्रौद्योगिकी, संसाधित खाद्य पदार्थ, कपड़ा तथा उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र से प्रतिनिधि शामिल थे। वाणिज्यिक समुदायों के साथ बातचीत तथा निर्यातोन्मुखी एककों को देखने के अलावा सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद तथा सचिव (कपड़ा) श्री ए.के.सिंह से मुलाकात की।

तीन दिवसीय भारत-अर्मेनिया मैत्री शतरंज टूर्नामेंट दिसंबर, 2008 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों की ओर से शतरंज के ग्रांड मास्टरों ने हिस्सा लिया था। भारत व अर्मेनिया के मध्य यह इस प्रकार का पहला समारोह था।

अज़रबेजान

इस अवधि के दौरान भारत तथा अजरबेजान के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। बहुपक्षीय घटनाओं के मद्देनजर अनेक कार्यकारी तथा व्यापारिक स्तर की यात्राएं हुईं, जिनमें अप्रैल, 2008 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी संघ की कार्यपालक समिति की बैठक के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा कार्मिक विभाग के विशेष सचिव की बाकू यात्रा, सितंबर, 2008 में तेल व गैस से संबंधित अजरबेजान-तुर्कमेनिस्तान के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तथा फिक्की की बाकू यात्रा, नवंबर, 2008 में बाकू तेल 2008 प्रदर्शनी के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में टेली कॉम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड की यात्रा शामिल है।

रत्न व आभूषण व्यवसाय से संबंधित एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 12-13 दिसंबर, 2008 को बाकू की यात्रा की। अक्तूबर, 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि दर्ज हुई, जो कि 323.78 मिलियन अमरिकी डालर रहा।

बेलारूस

वर्ष 2008 में उच्च तथा कार्यकारी स्तर पर बेलारूस के साथ द्विपक्षीय आदान-प्रदानों में तेजी आयी। वर्ष के दौरान सचिव (एन.रवि) ने 25 जुलाई, 2008 को बेलारूस की यात्रा की तथा बेलारूस के उप विदेश मंत्री प्रो. विक्टर ए. गायसीनोक से मुलाकात की तथा बेलारूस के राष्ट्रपति को संबोधित प्रधानमंत्री का एक पत्र उन्हें सौंपा। यात्रा के दौरान बेलारूस के उप मंत्री ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग पर बेलारूस का समर्थन जताया।

आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय व सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित भारतीय, बेलारूस अंतरसरकारी आयोग का चौथा सत्र 17-18 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बेलारूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग मंत्री श्री अन्नातोली रुजेत्सिकी ने किया, जिनके साथ 7 सदस्य वाला एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल तथा रसायन व उर्वरक, पेट्रो रसायन, टिंबर, भारी इंजीनियरी, आटो मोबाइल, पेय पदार्थ, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 18 सदस्यों वाला एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व उद्योग राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार ने किया। आगंतुक मंत्री ने विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहनदेव तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुबोध कांत सहाय से मुलाकात की। व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कृषि सहयोग के क्षेत्र में कार्यकारी स्तर की बैठकें आयोजित की गयी थीं। आईबीआईजीसी के विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। बेलारूस ने 14-27 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2008 में भी भाग लिया।

बेलारूस गणराज्य के संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पियोत्र पी. मिकलासेविक तथा बेलारूस के संवैधानिक न्यायालय के विधि एवं विशेषज्ञ विभाग के उपाध्यक्ष श्री बेसिली आई. सेलिडेबिस्की ने भारत के मुख्य न्यायधीश की के.जी.बालकृष्णा के आमंत्रण पर 13-15 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की।

सैन्य तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग का प्रथम सत्र 27-30 मई, 2008 को मिंस्क में आयोजित किया गया था। 5 सदस्यों वाले भारतीय प्रतिनधिमंडल का नेतृत्व रक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री पी.के.रस्तोगी ने किया। दोनों देशों ने रक्षा, संयुक्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

वाणिज्य विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेनेट्री एवं साइटोसेनेट्री सुरक्षापायों तथा तकनीकी विनियमों से संबंधित संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक के लिए 15-16 मई, 2008 को भारत की यात्रा की। कृषि एवं सहकारिता विभाग के मुख्य सलाहकार, एस.एम. झाड़वाल के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय के 4 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने कृषि सहयोग से संबंधित भारत-बेलारूस संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक के लिए 10-14 जून, 2008 को बेलारूस की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत करने तथा कार्ययोजना पर हस्ताक्षर करने के अलावा कई कृषि एवं कृषि औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का दौरा भी किया।

जार्जिया

वर्ष 2008-09 के दौरान जार्जिया के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। येवरान में हमारे राजदूत (जिन्हें जार्जिया का कार्यभार भी दिया गया है) ने तबलिसी में जार्जिया के विभिन्न उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया गया तथा दोनों देशों के मध्य आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम जारी रखे गए।

अगस्त, 2008 में जार्जिया तथा रूस के मध्य सैन्य संघर्ष हुआ तथा बाद में रूस ने दक्षिण आस्ट्रिया व अवखाजिया को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दे दी तथा उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

कजाखस्तान

वर्ष के दौरान कजाखस्तान के साथ भारत के संबंधों में और विकास तथा विस्तार हुआ। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने कजाखस्तान गणराज्य की संसदीय सीनेट के अध्यक्ष श्री कासिम तोकायेब के आमंत्रण पर 6-10 अप्रैल, 2008 को कजाखस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्री नूर सुल्तान नजरबायेव से मुलाकात की, प्रधान मंत्री श्री करीम मेसीमोब के साथ उपयोगी बैठक की तथा कजाख सीनेट को संबोधित किया। उन्होंने अस्ताना में कजाख लोक प्रशासन संस्थान तथा अल्माटी में अलफरेबी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी संबोधित किया। अलफरेबी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति को सम्मानार्थ डॉक्टर की उपाधि भी प्रदान की। एक भारतीय सांस्कृतिक दल ने माननीय उप राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कजाखस्तान के विभिन्न भागों का दौरा किया व कला का प्रदर्शन किया।

सचिव (पूर्व) तथा प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने 26-27 जुलाई, 2008 को कजाखस्तान की यात्रा की तथा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय असैनिक ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख श्री कैरात कैलंबीतोब, उप विदेश मंत्री श्री अन्नातोलाई बी. समीरनोव व ऊर्जा एवं खनिज संसाधन उप मंत्री श्री लियाजत के. किनोव से मुलाकात की।

अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं राजनीति के क्षेत्र में भी बैठकें आयोजित की गयीं। कजाखस्तान के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष केरात मेमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13-20 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की तथा मुख्य न्यायधीश, न्यायधीशों तथा भारत के महान्यायवादी के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। वस्त्र संबंधी संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक भी आयोजित की गयी थी, ताकि इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके।

कजाख राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव ने 23-26 जनवरी, 2009 को भारत की सरकारी यात्रा की। वे गणतंत्र दिवस की परेड में माननीय अतिथि थे। ऐसा पहली बार हुआ कि मध्य एशियाई क्षेत्र का कोई नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना। राष्ट्रपति नजरबायेव के साथ विदेश मंत्री श्री मरात ताझिन सहित एक उच्चस्तरीय सरकारी मंडल तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भी यात्रा की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्री नजरबायेव ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित की तथा भारत के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक राजकीय भोज भी दिया। कई करारों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कजाखस्तान से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, कजाखस्तान को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करना, कजाखस्तान में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा अंवेषण व उत्पादन शामिल है। एक प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

उद्योग राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार ने 4-6 मार्च, 2009 को कजाखस्तान की यात्रा की। उन्होंने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा की। उन्होंने कई व्यापारिक बैठकों के अलावा कजाख के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्री श्री साउत मिन बायेव के साथ भी बैठक की।

भारत कजाखस्तान अंतर्राष्ट्रीय आयोग का 7वां सत्र 12-13 मार्च, 2009 को अस्ताना में आयोजित किया गया था। श्री मुरली देवरा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कजाखस्तान के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री साउत मिन बायेव ने इस आयोग की सहअध्यक्षता की। आयोग के अधिकार क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक, विज्ञान व प्रौद्योगिक, कोंसुली मामलों में सहयोग शामिल है। इस सत्र की समाप्ति पर एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। श्री देवड़ा ने अस्ताना यात्रा के दौरान कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव तथा प्रधान मंत्री मेसीमोव से मुलाकात की।

किर्गीज गणराज्य

भारत व किर्गीज गणराज्य ने 2008-09 में मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। फरवरी, 2008 में किर्गीज गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अदनाम काराबायेव की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय कार्यान्वित किए गए। तथा उसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए, आर्थिक, शिक्षा, रक्षा इत्यादि के क्षेत्र में सरकारी यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए और अवसरों का पता लगाया। भारत-किर्गीज सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (भारत सरकार की अनुदान सहायता से स्थापित) ने केंद्र के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधियों के प्रमाणन के लिए वैलोर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ जोड़ किया।

तजाकिस्तान

श्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने 28 अगस्त, 2008 को दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की शीर्ष बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान उन्होंने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री इमोमाली रहमान से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। यात्रा के दौरान मंत्री ने वारजो-1 पनविद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण व समन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना का उद्घाटन किया।

भारत-तजाकिस्तान अंतरसरकारी आयोग का 5वां सत्र 19-20 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव श्री जी.के.पिल्लई तथा ताजिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त व अर्थव्यवस्था मंत्री श्री गुलाम जोन बोबोजोदा ने किया। भारत तथा तजाकिस्तान ने 20 नवंबर, 2008 को दोहरा कराधान परिवर्जन करार पर भी हस्ताक्षर किए थे।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत भारत में अक्तूबर, 2008 में ताजिक सांस्कृतिक दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर तजाकिस्तान के संस्कृति मंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए भारत की यात्रा की तथा आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉ. करन सिंह से मुलाकात की।

तुर्कमेनिस्तान

वर्ष के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार व संस्कृति के क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत के बहु-आयामी संबंधों में और विकास हुआ। उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 4-6 अप्रैल, 2008 को तुर्कमेनिस्तान की सरकारी यात्रा की। उपराष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वर्दीमुहामदेव से मुलाकात की तथा दोनों विशिष्ट व्यक्तियों ने दोनों देशों के मध्य प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की अध्यक्षता की। उप राष्ट्रपति के साथ विदेश राज्य बीच श्री ई. अहमद भी थे। उप राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान में मैरी शहर की यात्रा भी की। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तेल व गैस के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय आदान-प्रदान हुए, जिनमें सरकारी व व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने नवंबर, 2008 में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की तथा तुर्कमेनिस्तान के तेल व गैस मंत्री से मुलाकात की। तेल व गैस, अवसंरचना, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य क्षेत्रों में विभिन्न व्यापारिक स्तर के आदान-प्रदान हुए। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 3-4 फरवरी, 2009 को तुर्कमेनिस्तान का सरकारी दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर तुर्कमेन के नेताओं के साथ बातचीत की।

यूक्रेन

वर्ष के दौरान भारत तथा यूक्रेन ने विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध व गठजोड़ बनाए रखे। द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में और विकास हुआ तथा दोनों देशों ने विज्ञान व प्रौद्योगिक, रक्षा, राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में आदान-प्रदान जारी रखे। वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी व संगठनों ने संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार व संवर्धन करने के लिए यूक्रेन में कई प्रदर्शनियों व मेलों में हिस्सा लिया।

सचिव (पूर्व) तथा प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री एन. रवि व यूक्रेन के उप विदेश मंत्री श्री ओलेक सांदर गोरिन के मध्य विदेश कार्यालय वार्ता का 7वां दौर 24 जुलाई, 2008 को कीव में आयोजित किया गया। सचिव (पूर्व) ने यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया।

श्री मिकोला तोमानको, यूक्रेन संसद, वेरखोवना रादा के उपाध्यक्ष ने 7-14 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने के. रहमान खान, उपाध्यक्ष राज्यसभा व चरनजीत सिंह अटवाल, उपाध्यक्ष लोक सभा के साथ मुलाकात की तथा संसदीय व्यवहार व प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श किया तथा भारत व यूक्रेन के मध्य अधिक से अधिक संसदीय आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, श्रीमती अंबिका सोना से मुलाकात की तथा राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय), श्री आनन्द शर्मा के साथ भी विचार-विमर्श किया तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व विश्वस्तरीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की।

उज्बेकिस्तान

अंतरसरकारी संरचनाओं, विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों तथा अन्य वार्ताओं के तहत वर्ष 2008-09 में भारत उज्बेकिस्तान संबंधों में काफी प्रगति हुई। 1 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय विदेश वार्ताएं आयोजित की गयी, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व विश्वस्तरीय मुद्दों के सभी आयामों पर चर्चा की गयी। सचिव (पूर्व) श्री एन. रवि ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा उप मंत्री रुस्तम अस्कारोविच तुहाताबायेव ने उज्बेकिस्तान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित भारत-उज्बेकिस्तान अंतरसरकारी सहयोग का 8वां सत्र 16-17 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री, श्री जयराम नरेश ने किया। उज्बेक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उज्बेकिस्तान गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री वी. खोबीजेव ने किया। आयोग ने व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संबंधों में प्रगति तथा इन क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया। आयोग की बैठक की समाप्ति पर दोनों देशों ने एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 4-5 फरवरी, 2009 को उज्बेकिस्तान का सरकारी दौरा किया। उनकी सरकारी वार्ता में सभी द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गयी।

भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय वार्ता संरचना

भारत ने रूस तथा चीन के साथ तीनों विदेश मंत्री स्तर पर त्रिपक्षीय स्वरूप की अपनी नियमित वार्ता जारी रखी। विदेश

मंत्रियों की अंतिम त्रिपक्षीय बैठक यकात्रिनबर्ग (रूस) में आयोजित की गयी थी, जिसमें त्रिपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों तथा विश्वस्तरीय घटनाक्रम पर विचार-विमर्श किया गया। कृषि, आपदा प्रबंधन तथा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में त्रिपक्षीय वार्ता भी प्रारंभ की गयी थी। तीनों देशों ने त्रिपक्षीय वार्ता को व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों तक भी बढ़ा दिया।

शंघाई सहयोग संगठन

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में एक प्रेक्षक राज्य के रूप में अगस्त एवं अक्तूबर, 2008 में क्रमशः दुशांबे व अस्ताना में आयोजित राज्य के प्रमुखों तथा सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठकों में भाग लिया। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने राज्य के प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शंघाई सहयोग संगठन के राज्यों के प्रमुखों की बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन ने यह निर्णय लिया कि संगठन के प्रेक्षक राज्यों के साथ गुणवत्ता के नए स्तर पर सहयोग में वृद्धि की जाए। तत्पश्चात भारत को आर्थिक एवं परिवहन के क्षेत्र में शंघाई सहयोग संगठन की मंत्रालयी बैठकों में आमंत्रित किया गया है।

श्री एन. रवि, सचिव (पूर्व) के आमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव श्री बोलाट नूरगालिब ने 26-27 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव ने विदेश मंत्री से मुलाकात की तथा सचिव (पूर्व) के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय सरकारी विचार-विमर्श किया। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने शंघाई सहयोग संगठन- विकास, वृद्धि व भविष्य विषय पर शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव की एक वार्ता आयोजित की। उन्होंने रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित गोलमेज वार्ता में भी भाग लिया।

■■

5 खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी

भारत खाड़ी देशों के साथ अपने ऐतिहासिक तथा पारंपरिक सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग बनाए हुए है। तेल एवं गैस के बढ़ते आयात तथा व्यापार एवं निवेश के निरंतर बढ़ रहे अवसरों को देखते हुए 2008 में इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग के सतत् उपाय किए गए थे। वर्ष के दौरान हमारे संबंधों में इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाने वाली कई द्विपक्षीय उच्चस्तरीय यात्राएं हुई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 2008 में प्रधान मंत्री की कतर व ओमान यात्रा है, जिससे सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम खुले हैं।

खाड़ी क्षेत्र भारत का एक मुख्य व्यापार साझेदार है। 2006-07 के दौरान दोनों देशों के बीच 47 बिलियन अमरीकी डालर का कुल कारोबार हुआ तथा 2007-08 में यह बढ़कर 76 बिलियन डालर से अधिक हो गया। खाड़ी क्षेत्र कुल मिलाकर हमारी कच्चे तेल की कुल 70% आवश्यकता पूरी करते हैं तथा हमारी ऊर्जा सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लगभग 4.5 मिलियन भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते तथा काम करते हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य सहायक हैं तथा वे वार्षिक रूप से 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि जमा करते हैं।

बहरीन

कई महत्वपूर्ण यात्राएं प्रतीक है कि भारत तथा बहरीन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रहे। बहरीन सरकार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहरीन के कुल 1.04 मिलियन निवासियों में से भारतीय राष्ट्रिकों की कुल संख्या 3,00,776 है।

बहरीन के श्रम मंत्री डॉ. माजिद मोहसिन अल अलावी ने 25 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा की तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि के साथ श्रम व श्रमशक्ति विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श किया। डॉ. फातिमा बिंत अलवालुशी, सामाजिक विकास मंत्री, बहरीन ने 17-21 अगस्त, 2008 को भारत की यात्रा की थी तथा कपड़ा मंत्री व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के साथ बातचीत की थी। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 28-29 सितंबर, 2008 को बहरीन की यात्रा की। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि ने 29-31 अगस्त, 2008 के दौरान बहरीन की यात्रा की तथा बहरीन में भारतीय समुदाय से मिले।

ईरान

द्विपक्षीय संबंध

भारत तथा ईरान के बीच संबंध बने रहे तथा उच्चस्तरीय यात्राओं तथा द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की नियमित बैठकों, विदेश कार्यालय परामर्शों और दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच परामर्शों के माध्यम से ये संबंध और मजबूत हुए। इससे उपार्जित गतिशीलता से ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य पारगमन निवेश, संस्कृति के साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि हुई।

उच्चस्तरीय द्विपक्षीय आदान प्रदान

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 15वें गुटनिरपेक्ष मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-30 जुलाई, 2008 को तेहरान की यात्रा की। उन्होंने 31 अक्तूबर - 2 नवंबर, 2008 को भारत-ईरान संयुक्त आयोग के 15वें सत्र के लिए फिर से ईरान की यात्रा की। पिछले दो वर्षों में यह विदेश मंत्री की तीसरी ईरान यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक तथा भारत-ईरान संबंधों पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गयी थी। एक प्रत्यर्पण संधि तथा आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा कृषि, समरूप बंदरगाह प्रबंधों तथा व्यापार प्रदर्शनियां आयोजित करने संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश राज्य मंत्री, श्री ई. अहमद ने 4-5 मई, 2008 को तेहरान में क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ की मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लिया। आवास, शहरी विकास उन्मूलन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कुमारी शेलजा ने 10-15 मई, 2008 को तेहरान में आयोजित आवास व शहरी विकास के संबंध में दूसरी एशियाई प्रशांत मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया तथा सम्मेलन की अध्यक्षता ईरान को सौंप दी।

श्री एम. के नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने ईरानी समकक्ष के आमंत्रण पर 30 जून- 2 जुलाई, 2008 को तेहरान की यात्रा की।

ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. महमूद अहमदी नेजाद ने 29 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। ईरानी राष्ट्रपति के साथ यात्रा पर आए उप राष्ट्रपति, श्री इसफदियार रहीम मासाये ने 30 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली व मुंबई में "ईरानी सांस्कृतिक दिवस" उत्सव का उद्घाटन किया। आवास

व शहरी विकास मंत्री श्री मोहम्मद सईदि किया ने 12-14 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रालयी सम्मेलन की कार्यालयीन बैठक में हिस्सा लिया।

विदेश कार्यालय परामर्श

भारत की ओर से विदेश सचिव तथा ईरान की ओर से उप विदेश मंत्री स्तर पर छठीं वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श, 17-18 दिसंबर, 2008 को भारत में आयोजित की गयी। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग, हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र में सहयोग, अफगानिस्तान में स्थिति तथा अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गयी।

संयुक्त आयोग की बैठक

भारत-ईरान संयुक्त आयोग में 7 उपसमितियां हैं जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, व्यापार, परिवहन व संचार, उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कोंसली मामलों से संबंधित कार्य देखते हैं। भारत-ईरान संयुक्त आयोग जुलाई, 1983 में स्थापित किया गया था तथा अब तक संयुक्त आयोग की 15 बैठकें आयोजित की गयी। संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक 31 अक्तूबर-2 नवंबर, 2008 को तेहरान में आयोजित की गयी। इसकी सहध्यक्षता विदेश मंत्री के साथ-साथ इस्लामिक गणराज्य ईरान के आर्थिक कार्य व वित्त मंत्री डॉ. सईद शामसेद्दीन हुसेनी ने की।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच परामर्श

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के मध्य वार्ता का 6ठा दौर जुलाई, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तेहरान यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था। सचिव, एसएनएससी ईरान के डिप्टी ने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ परामर्श के लिए 10-14 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की थी। वर्ष 2006-07 में ईरान व भारत के मध्य व्यापार में 9.5 बिलियन अमरीकी डालर (भारत से निर्यात- 1.5 बिलियन अमरीकी डालर तथा भारत द्वारा आयात 8 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर 2007-08 में 13 बिलियन अमरीकी डालर (भारत से निर्यात- 2 बिलियन अमरीकी डालर तथा भारत द्वारा आयात 11 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया, जो लगभग 40% की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 की अवधि के दौरान भारत तथा ईरान के मध्य कुल व्यापार 12.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। ईरान को निर्यात की जा रही महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं हैं- प्राथमिक एवं अल्प-निर्मित लोहा व इस्पात, धातु की वस्तुएं, मशीनरी व उपस्कर, औषध व भेषज, संसाधित खनिज, अकार्बनिक/कृषि रसायन, चाय, धागा व फैब्रिक इत्यादि। भारत ईरान को काफी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करता है। ईरान से भारत को निर्यातित सामग्री में कच्चा तेल, फल व मेवे, दालें, अलौह धातु, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन, रद्दी धातु रसायन, लौह व इस्पात, कार्बनिक रसायन व चमड़ा शामिल है।

कई भारतीय कंपनियाँ या तो ईरानी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से अथवा निवेश के माध्यम से नौवहन, खनन, रेलवे, इस्पात, आईसीटी, आटोमोटिव, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में ईरान में सक्रिय है।

द्विपक्षीय निवेश संवर्धन व सुरक्षा करार (बीआईपीपीए) तथा दोहरे कराधान से बचने के लिए करार (डीटीएए) को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

इन दो करारों को अंतिम रूप देने तथा उन्हें लागू करने से दोनों देशों के मध्य भावी आर्थिक व निवेश सहयोग के लिए ठोस आधार मिलेगा।

व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान

आर्थिक एवं वाणिज्यिक आदान-प्रदान जारी रहे। भारत की ओर से ईरान जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में रेल प्रतिनिधिमंडल, रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, अखिल भारतीय उद्योग संघ, भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, नाल्को, ऑटोमोटिव उपस्कर विनिर्माण संघ, नई दिल्ली और भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ शामिल थे।

भारतीय वाणिज्य व उद्योग चैंबर परिसंघ ने 15वीं संयुक्त आयोग बैठक, नई दिल्ली के साथ-साथ 9वीं संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक आयोजित की।

ईरान की ओर से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों में ईरान राष्ट्रीय गलीचा केंद्र, तेहरान आभूषण सिंडीकेट, चावल अनुसंधान संस्थान ईरान, सीआईआई द्वारा आयोजित खनन एवं एसएमई प्रदर्शनी के लिए आर्थिक कार्य व ईरान चैंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग व खनन मंत्री, तेहरान शेयर बाजार, तथा ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हित में तथा क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि के एक साधन के रूप में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को अत्यधिक महत्व देता है। भारत ऊर्जा का एक प्रमुख उपभोक्ता तथा ईरान हाइड्रो-कार्बन का एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार ईरान से कच्चे तेल का आयात, भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात, गैस क्षेत्र के गवेषण तथा विकास सहयोग के विभिन्न आयामों तक पहुंच गया है। ईरान से एलएनजी के आयात तथा पाकिस्तान के माध्यम से ईरान से भारत तक गैस अंतरित करने के लिए पाइपलाइन का निर्माण करने की योजना भी विचाराधीन है।

पारगमन

मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान को भारतीय सामग्री के पारगमन के लिए ईरान का विशेष महत्व है। अफगानिस्तान के लिए भारत का व्यापक सहायता कार्यक्रम भी पारगमन के लिए ईरान पर

29 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डा.महमूद अहमदीनिजाद के साथ प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह।

3 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में कुवैत के वित्त मंत्री मुस्तफा जासिम अल शमाली
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकत करते हुए।

निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते ऐसी पारगमन सुविधा नहीं मिली है। भारतीय कंपनियों का एक परिसंघ चाबाहार बंदरगाह के विकास की परियोजना पर बात कर रहा है, जिसे मजबूत बनाने से मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच में सुधार होगा। ईरान से होकर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कारीडोर को भी हम महत्व देते हैं।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। उच्चस्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान इन संबंधों का प्रतीक है। राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 29-31 जनवरी, 2008 के दौरान कुवैत की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान राज्य मंत्री ने कुवैती प्रधान मंत्री से मुलाकात की। उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री तथा श्रम में सामाजिक कार्य मंत्री के साथ बैठकों में कुवैती नियोक्ता तथा भारतीय कर्मचारियों के मध्य हस्ताक्षरित किए जाने वाले श्रमिक अनुबंध के लिए संशोधित प्रपत्र सहित व्यापक किस्म के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। कुवैत राज्य की सरकार के सरकारी आंकडों के अनुसार फरवरी, 2008 में कुवैत में 579,409 भारतीय राष्ट्रिक थे। श्री ई. अहमद, राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) ने 13 मई, 2008 को फादर अमीर शेख साद अब्दुल्ला अल सवाह की मृत्यु पर कुवैत के लोगों तथा शाही परिवार को अपनी संवेदना प्रेषित करने के लिए कुवैत की यात्रा की।

दूसरे भारत-कुवैत संयुक्त मंत्रालयी आयोग की बैठक 1-3 जुलाई, 2008 को दिल्ली में आयोजित की गयी थी, जिसकी अध्यक्षता भारत की ओर से श्री ई. अहमद, राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) तथा कुवैत की ओर से वित्त मंत्री श्री मुस्तफा अल-शमाली ने संयुक्त रूप से की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कुवैत राज्य के लेखा परीक्षण ब्यूरो के बीच सहयोग के लिए 15 जुलाई, 2008 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कुवैत कक्ष

प्रतिपूर्ति वितरण का अंतिम चरण यूएनसीसी द्वारा 8615 गुमशुदा दावेदारों को एसकेसी भेजने के साथ ही शुरू हुआ। इन व्यक्तियों का पता लगाने तथा उन्हें भुगतान करने के लिए यूएनसीसी द्वारा हमें दिया गया यह अंतिम अवसर है। अवितरित राशि यूएनसीसी को वापस की जानी थी तथा यूएनसीसी में यह अव्यपगत हो जाएगी, जिससे कि राशि को फिर से प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं होगा। अक्तूबर, 2005 में दावेदारों की सूची भेजने के साथ ही दावेदारों का पता लगाने का कार्य शुरू हो गया था, जिन्होंने यूएनसीसी के द्वारा दी गयी सूची के अनुसार विज्ञापनों का उत्तर दिया था। यह कार्य अक्तूबर, 2006 में समाप्त हो गया था, क्योंकि यूएनसीसी ने अन्य सूचियों को प्राप्त करने से इंकार कर दिया था। यूएनसीसी ने जनवरी, 2007 तथा जुलाई, 2007 के मध्य राशि भेज दी थी, जो कि 6 महीनों के भीतर वितरित की जानी थी तथा अवितरित राशि यूएनसीसी द्वारा भारत को राशि अंतरित किए जाने के 6 माह के भीतर यूएनसीसी को वापस की जानी थी। अवितरित राशि की अंतिम किश्त जनवरी, 2008 में वापिस कर दी गयी। यूएनसीसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वापस की गयी राशि को भेजने के लिए सरकार के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए दावेदार अथवा उनकी सरकार कोई भी औचित्य व तर्क प्रस्तुत करे।

प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति के दावेदारों से पूछताछ के संबंध में अप्रैल- दिसंबर, 2008 तक सूचना अधिनियम के अंतर्गत 12 मामलों के जवाब दिए हैं।

ओमान

श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री के साथ राज्य मंत्री श्री ई. अहमद तथा सचिव (पूर्व) ने 13-14 जनवरी, 2008 को मस्कट की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने मंत्रिपरिषद के उप प्रधान मंत्री तथा विदेशी कार्यों के लिए उत्तरदायी मंत्री श्री युसूफ बिन अलवाई बिन अब्दुल्ला ओमान से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भारतीय दूतावास तथा आवासीय परिसर का उद्घाटन किया तथा खाड़ी व मध्य एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों में भारतीय मिशन प्रमुखों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। 8-9 नवंबर, 2008 को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ओमान यात्रा के साथ ही भारत तथा ओमान के मध्य हमारे वर्तमान सौहार्दपूर्ण संबंधों में और मजबूती आयी। जनशक्ति पर समझौता ज्ञापन तथा 100 मिलियन अमरीकी डालर की मूल पूंजी से प्रारंभ है, भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोश, जो 1.5 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गयी है, स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन इस यात्रा की मुख्य-मुख्य बातें हैं।

विदेश राज्य मंत्री ने सितंबर, 2008 को ओमान की यात्रा की थी। उन्होंने डॉ. उमर बिन अब्दुल मुनिम अलजवावी, विदेशी संपर्क के लिए माननीय सुल्तान के विशेष सलाहकार तथा श्री यूसुफ बिन अलाबी बिन अब्दुल्ला, विदेशी कार्यों के लिए उत्तरदायी मंत्री के साथ पारस्परिक चिंताओं के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए बातचीत की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री शंकर सिंह बघेला ने 29-31 अगस्त, 2008 को ओमान की यात्रा की थी। उन्होंने सल्तनत के वाणिज्य मंत्री मकबूल अली सुल्तान के साथ बैठक की। विधि कार्य मंत्री श्री मोहम्मद बिन अली बिन नासिर अल अलावी ने अफ्रीकी विधि परामर्श समिति की 47वीं बैठक में भाग लेने के लिए जून में नई दिल्ली की यात्रा की।

विदेश कार्य मंत्री श्री युसूफ बिन अलावी ने 16 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। भारत-ओमान सामरिक परामर्शदायी समूह की छठीं बैठक 7 मई, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी तथा सातवीं बैठक 18-19 जनवरी, 2009 में मस्कट में आयोजित की गयी थी।

28 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में सउदी अरब अधिराज्य के विदेश मंत्री शाहजादा सौद अल फैज़ल केंद्रीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए।

आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों में और मजबूती आयी। द्विपक्षीय व्यापार (गैर-तेल) में सतत् वृद्धि हुई है तथा यह 2008 तक 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होगा, जबकि 2007 में यह 1.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

कतर

वर्ष 2008 में कतर के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हुए।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 9 नवंबर, 2008 को कतर की यात्रा की। यात्रा के दौरान कतर तथा भारत में रक्षा सहयोग एवं सुरक्षा के साथ-साथ विधि प्रवर्तन मामलों पर दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के उपायों तथा कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने 10 नवंबर, 2008 को अपने कतारी समकक्ष उप प्रधान मंत्री तथा ऊर्जा व उद्योग मंत्री श्री अब्दुल्ला बिन हामाद अल अतियाह से मुलाकात की। वर्तमान में भारत, कतर के साथ एक दीर्घावधिक समझौते के अंतर्गत रास गैस से 7.5 मिलियन टन एलएनजी खरीद रहा है।

सऊदी अरब

इस वर्ष कई उच्चस्तरीय यात्राएं हुई हैं, जिनमें भारत तथा सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ है। सऊदी विदेश मंत्री शहजादा सौद अल फैजल ने 28-29 फरवरी, 2008 को भारत की यात्रा की तथा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने 26 दिसंबर को फिर से भारत की यात्रा की तथा उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 19-20 अप्रैल, 2008 को सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा की तथा सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सौद तथा रियाद के गवर्नर सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद से मुलाकात की। उन्होंने सऊदी विदेश मंत्री शहजादा सौद अल फैजल से भी विचार-विमर्श किया। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 17 अप्रैल, 2008 को सऊदी अरब की यात्रा की तथा सऊदी हज मंत्री डॉ. फॉउद अल-फारसी के साथ हज करार पर हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्री, पी. चिदंबरम के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने 22 जून, 2008 को सऊदी शाह अब्दुल्ला के आदेश पर जद्दा में आयोजित मुख्य तेल उत्पादक व उपभोक्ता देशों के तेल सम्मेलन में भाग लिया।

वर्ष के दौरान आर्थिक संबंधों में और मजबूती आयी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोटेक सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2008 में रियाद की यात्रा की तथा सऊदी अर्थव्यवस्था व नियोजन तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रियों से मुलाकात की।

भारत तथा सऊदी अरब ने जनवरी, 2008 में नए द्विपक्षीय वायुसेवा करार पर हस्ताक्षर किए। सचिव (उर्वरक) के नेतृत्व में उर्वरक मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय से एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उर्वरक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए 25-27 अक्तूबर, 2008 को रियाद की यात्रा की थी। आधुनिक परिगणना केंद्र (सी-डेक) से एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर, 2008 में रियाद की यात्रा की।

भारतीय उप थल सेनाध्यक्ष ने मई, 2008 में सऊदी अरब की यात्रा की तथा सऊदी रक्षा सहायक मंत्री शहजादा खालिद बिन सुल्तान से मुलाकात की। जुलाई, 2008 में दो सऊदी नौसेना जहाजी बेड़े अल दमन तथा अल यामदू ने जुलाई, 2008 में मुंबई की प्रथम सौहार्दपूर्ण यात्रा की।

हज

दिसंबर, 2008 में हज यात्रा करने वाले भारतीय की कुल संख्या 175000 थी। 122213 भारतीय यात्रियों ने भारत की हज समिति के माध्यम से सऊदी अरब की यात्रा की तथा शेष यात्रियों ने गैर-सरकारी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा की। झारखंड के राज्यपाल श्री सईद सिबते रजी के नेतृत्व में एक भारतीय हज सौहार्द प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब की यात्रा की। उन्होंने 9 दिसंबर, 2008 को सऊदी अरब के शासक माननीय अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की मेजबानी में आयोजित एक भोज में हिस्सा लिया।

संयुक्त अरब अमीरात

वर्ष 2008 भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का वर्ष था। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने मई, 2008 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री, शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद अल नाह्यान तथा अबु दाबी के शासन शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान से मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने अप्रैल में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम तथा दुबई के शासक, अर्थव्यवस्था मंत्री तथा उच्चतर शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री से मुलाकात की। भारतीय प्रवासी कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि ने नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की तथा संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री सकर घाबाश सईद घाबाश के साथ हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यूएई की ओर से विदेश व्यापार मंत्री माननीय शेख लुबना अल कासिमी ने 25 अप्रैल को भारत की यात्रा की। फिक्की ने उन्हें वर्ष की सफल महिला के खिताब से नवाज़ा। प्रथम भारत यूएई वायुसेना अभ्यास सितंबर, 2008 को आबु दाबी में हुआ।

यमन

भारत व यमन द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। वर्ष के दौरान दोनों देशों के मध्य यात्राओं के आदान-प्रदान से इन संबंधों में और मजबूती आयी। सचिव (पूर्व) ने मार्च, 2008 में विदेश कार्यालय विचार-विमर्श के लिए यमन में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड तथा एनटीपीसी अन्य ऐसे प्रतिनिधिमंडल हैं, जिन्होंने यमन की यात्रा की। यमन की ओर से यमन तेल प्रतिनिधिमंडल, यमन तेल व गैस प्रतिनिधिमंडल, यमन सैन्य (शिक्षा व प्रशिक्षण) प्रतिनिधिमंडल इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों ने भारत यात्रा की।

इराक

भारत तथा इराक के बीच सहनशील, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध हैं, जो 8 अप्रैल, 2003 को भारतीय संसद में पारित संकल्प द्वारा निर्देशित है, जिसके द्वारा भारत इराकी जनता की प्रभुसत्ता को शीघ्र पुनःस्थापित करने तथा इराकी जनता के लिए उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने तथा राजनीतिक भविष्य निर्धारित करने के अधिकार के पक्ष में है। भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, बहुवादी, संघीय व एकीकृत इराक का समर्थन करता है तथा इसने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के एक भाग के रूप में तथा प्रत्यक्ष रूप से इराकी सरकार तथा इसकी जनता को सहायता दी थी।

वर्ष 2008-09 में भारत ने इराक के मानव संसाधन के विकास में योगदान दिया था। भारत ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत इराक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित एवं व्यावसायिक संस्थानों में 100 स्थान प्रदान किए। भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 228 इराकी तेल कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया है। भारत ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना (सीईपी) तथा सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस) के अंतर्गत उच्चतर अध्ययन के लिए इराक को शैक्षणिक स्थान देने का प्रस्ताव भी किया।

भारत ने नई दिल्ली में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से सीरिया में इराकी शरणार्थियों को 800 मीट्रिक टन पौष्टिक बिस्कुट प्रदान किए। बगदाद स्थित भारतीय दूतावास ने अप्रैल-अक्तूबर, 2008 के दौरान इराकी राष्ट्रिकों को औसतन प्रतिमाह लगभग 1350 वीजा जारी किए। अधिकांश इराकियों ने पर्यटन एवं चिकित्सा वीजा पर भारत की यात्रा की तथा इनमें लगभग 400 इराकी विद्यार्थी शामिल हैं।

भारत- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

भारत- जीसीसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहे तथा 2008 में इनमें और मजबूती आयी। जीसीसी वार्ता का चौथा दौर 29 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में आयोजित किया गया, जिसमें संरचना को संस्थागत रूप दिया गया। विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल तथा जीसीसी महासचिव ने जीसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, उन्होंने पारस्परिक चिंता के मुद्दों तथा भारत जीसीसी संबंधों में संवर्धन के लिए तथा उन्हें और अधिक मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

भारत- जीसीसी मुक्त व्यापार करार की वार्ताकार टीम की बैठक का दूसरा दौर ढ़ाई वर्ष की अवधि के बाद (सितंबर, 2008) रियाद में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले आगामी दौर से पहले इलेक्ट्रानिक माध्यमों से सूचना आदान-प्रदान की सतत् प्रक्रिया स्थापित करने पर सहमति हुई।

पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका

संपूर्ण क्षेत्र के साथ संबंध

भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में वाना क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के साथ संबंधों को विविध क्षेत्रों में और मजबूती प्रदान की गयी है, जिसमें उच्चस्तरीय राजनीतिक व आर्थिक वार्तालाप स्थापित द्विपक्षीय संरचना के माध्यम से परियोजना सहायता तथा इसी प्रकार अरब गणराज्य मिस्र अरब राज्य लीग तथा प्रवर्तनकारी वार्ता संरचना के माध्यम शामिल हैं। अधिकृत फिलीस्तीनी भूभाग में आम जनता के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय, जिसमें मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में कम प्रगति हुई है, के दौरान फिलीस्तीन के लक्ष्य के लिए भारत का समर्थन और अधिक महत्वपूर्ण है।

अल्जीरिया

अप्रैल, 2008 में अल्जीरियाई संसद में भारत तथा अल्जीरिया के मध्य संसदीय मैत्री समूह स्थापित किया गया था। श्री अहमद कुहाइया, अल्जीरियाई राष्ट्रपति के वैयक्तिक प्रतिनिधि ने अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका सम्मेलन मंच में अल्जीरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पश्चिम एशिया तथा मध्य पूर्व शांतिप्रक्रिया पर विशेष दूत श्री सी.आर. घारेखान ने 22 जुलाई, 2008 को अल्जीरिया की यात्रा की तथा उन्होंने अल्जीरिया के विदेश मंत्री डॉ. मोराद मेडेल्की से मुलाकात की तथा अल्जीरिया के राष्ट्रपति श्री अब्देल आजिज बुते फिल्का ने उनका स्वागत किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने जुलाई, 2008 को तेहरान में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री श्री मोराद मेडेल्की से मुलाकात की।

वर्ष के दौरान भारत-अल्जीरिया व्यापार व आर्थिक संबंधों में पर्याप्त विकास हुआ है। भारतीय फर्मों में ऑटोमोबाइल पैट्रो रसायन तथा अल्जीरिया के अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं का सक्रिय रूप से पता लगाया है।

जिबुती

जिबुती के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने शर्मेल शेख, मिस्र में आयोजित अफ्रीकी संघ सम्मेलन के अवसर पर 28 जून, 2008 को जिबुती के विदेश मंत्री श्री मोहम्मद अली यूसुफ से मुलाकात की।

आईएनएस सिंधु विजय अक्तूबर, 2008 में जिबुती तट पर पहुंचा तथा आईएनएस तबर, जिसे जलदस्युता विरोधी प्रयासों के तहत तैनात किया गया है, भी उससे अगले महीने जिबुती तट पर पहुंचा।

मिस्र

वर्ष के दौरान मिस्र के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुए हैं। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 1-3 जुलाई, 2008 को मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने शर्मेल शेख में राष्ट्रपति मोहम्मद हुसने मुबारक से मुलाकात की तथा कैरो में मिस्र के विदेश मंत्री श्री अहमद अबूल गीत से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने अरब राज्य लीग के महासचिव महामहिम श्री अमरे मुसा से भी मुलाकात की।

राष्ट्रपति हुसने मुबारक ने 16-19 नवंबर, 2008 को भारत का दौरा किया। उनके साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों में श्रीमती सुजानी मुबारक व विदेश कार्य, व्यापार, उद्योग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना मंत्री तथा साथ ही बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुबारक ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की तथा यूपीए के अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपति मुबारक से मुलाकात की। प्रधान मंत्री ने 18 नवंबर, 2008 को राष्ट्रपति मुबारक के साथ विस्तार से प्रतिनिधिमंडल स्तरीय विचार-विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थेः (i) प्रत्यर्पण संधि (ii) राजनयिक, विशेष तथा सरकारी व सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाएं समाप्त करने पर करार (iii) स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (iv) गवेषण में सहयोग तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग करने पर समझौता ज्ञापन; तथा (v) व्यापार व तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन। विदेश मंत्री तथा मिस्र के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मुबारक की राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के मध्य रणनीति व सुरक्षा नीति वार्ता स्थापित की गयी है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मुबारक को अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए वर्ष 1995 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी दिया। राष्ट्रपति मुबारक ने भारतीय व्यापारियों को भी संबोधित किया। इस यात्रा के अवसर पर कई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मिस्र के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आशय के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नैसकॉम तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास अभिकरण ने भी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के मध्य अन्य यात्राओं के आदान-प्रदान में मई, 2008 में वाणिज्य व विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश की यात्रा शामिल है। जिसके दौरान उन्होंने शर्मेल शेख में आयोजित विश्व आर्थिक मंच मध्य पूर्व में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री आनन्द शर्मा माननीय विदेश राज्य मंत्री ने भी शर्मेल शेख में अफ्रीकी संघ के 11वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून, 2008 में यात्रा की। श्री सी. आर. घारेखान पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के विशेष दूत ने अप्रैल, 2008 में काहिरा की यात्रा की। श्रीमती अंबिका सोनी माननीय केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री ने नवंबर, 2008 में काहिरा की यात्रा की। उच्चस्तरीय मिस्री आगंतुकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री सुश्री फाहिजा अबुल नागा, जिन्होंने भारत-अफ्रीका सम्मेलन मंच में मिस्री प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, व्यापार व उद्योग मंत्री ईएनजी रशीद मोहम्मद रशीद तथा कृषि व भूमि सुधार मंत्री श्री अमीन अब्जा, जिन्होंने अप्रैल, 2008 में भारत की यात्रा की, इत्यादि शामिल है।

मिस्र के साथ व्यापार व आर्थिक संबंधों में विस्तार के अनुसार कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने 16-18 नवंबर, 2008 को काहिरा में इजीटेक्स 2008 प्रदर्शनी में भाग लिया; 20 मई, 2008 को काहिरा में एक "टी टेस्टिंग कम बिजनैस मीट" आयोजित की गयी; कैपेक्सिल के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 29 नवंबर- 4 दिसंबर, 2008 को मिस्र की यात्रा की; मिस्र के निवेश व मुक्त क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल ने 12-18 अप्रैल, 2008 को निवेश संवर्धन अभियान के लिए भारत की यात्रा का; गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने 9 मार्च, 2008 को मिस्र में दो तेल व गैस गवेषण ब्लॉकों के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किए; 13 नवंबर, 2008 को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने उत्तरी रमादान कंसेशन, स्वेज की खाड़ी में तेल की दूसरी खोज कर ली है।

मिस्री सैन्य बलों के प्रचालन प्राधिकरण के उप प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद मोहसिन साद अल सेजले के नेतृत्व में एक मिस्री रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने भारत मिस्र संयुक्त रक्षा संघ की दूसरी बैठक के लिए 7-13 जून, 2008 को भारत की यात्रा की। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव श्री पी.के. रस्तोगी ने किया था।

10-17 नवंबर, 2008 को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक सप्ताह के लिए मिस्र में भारतीय सांस्कृतिक दिन, समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय संगीत व नृत्य दलों के प्रस्तुतिकरण, चित्रकला तथा फोटोग्राफ की प्रदर्शनी तथा भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन शामिल है।

18 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद होश्नी मुबारक केंद्रीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए।

7 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील से मुलाकात करते हुए।

मिस्र के उप संस्कृति मंत्री डॉ. फैजल अब्देल कादर युनिस ने भारत-अरब सहभागिता मंच तथा 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अरब समारोह में भाग लिया।

इजराइल

सचिव (कृषि व सहयोग), डॉ. पी.के मिस्रा ने अप्रैल 1-8, 2008 को इजराइल में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2008-10 के लिए द्विपक्षीय कृषि सहयोग के संबंध में एक कार्ययोजना पर भी सहमति हुई। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. टी. रामास्वामी के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री एम. के भान ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी में सहयोग पर विचार-विमर्श के लिए 8-10 नवंबर, 2008 को इजराइल की यात्रा की। रक्षा सचिव ने रक्षा सहयोग के संबंध में भारत-इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक के लिए नवंबर, 2008 में इजराइल की यात्रा की। इजराइल के विदेश कार्य मंत्रालय के महा निदेशक श्री एरन अब्राहम विच ने 7-8 जुलाई, 2008 को भारत की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने माननीय विदेश मंत्री से मुलाकात की तथा एन. रवि, सचिव (पूर्व) के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारतीय अध्ययनों में क्रमागत अध्यक्षता स्थापित करने के लिए तेल अबीब विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को शामिल करके एक दल ने 6-12 जुलाई, 2008 को इजराइल की यात्रा की थी। आईसीसीआर द्वारा प्रत्यायोजित सुश्री बेजंती काशी के नेतृत्व में एक कुचीपुड़ी नृत्य दल तथा सुश्री अनुप्रिया दियोसतावे के नेतृत्व में एक हिंदुस्तानी वायलिन दल ने 24 जुलाई, 2008 को कार्मिल नृत्य महोत्सव में प्रस्तुतिकरण किया।

जॉर्डन

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 29 सितंबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र के अवसर पर जॉर्डन के विदेश मंत्री डॉ. सिलाहेदीन वासीर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। राजदूत सी.आर. घारेखान, पश्चिमी एशिया व एमईपीपी के लिए विशेष दूत ने अप्रैल, 2008 में जॉर्डन की यात्रा की।

निर्यातोन्मुखी एककों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद ने व्यापार तथा आर्थिक मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए 4 मई, 2008 को जॉर्डन के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद तथा ईओयू तथा एसईजेड से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के तत्वाधान के अंतर्गत 40 भारतीय कंपनियों के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 5-8 मई, 2008 को ओमान में आयोजित पांचवीं इराक पुनर्निर्माण प्रदर्शनी में भाग लिया। 2-9 अगस्त, 2008 को भारत की यात्रा पर आए जॉर्डन निवेश बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई, बंगलौर व नई दिल्ली में कई उद्योग प्रमुखों तथा व्यापार निकायों से बातचीत की। जॉर्डन निवेश बोर्ड ने जॉर्डन में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को 14 लक्ष्य देशों में से एक माना है। जॉर्डन के चमड़ा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-18 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं दिल्ली चमड़ा मेले में भाग लिया।

जॉर्डन से 25 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह ने 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में भारत-अरब सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया।

मोरक्को

पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया से संबंधित राजदूत श्री सी. आर. घारेखान ने 23-26 जुलाई, 2008 को मोरक्को की यात्रा की।

"ओबराय होटल एंड रिजार्ट्स" भारतीय समूह तथा मोरक्को के रीयल एस्टेट समूह "अल अलामी होल्डिंग" ने मरीकेक में 76.3 मिलियन अमरीकी डालर के पर्यटन परिसर का निर्माण करने के लिए सितंबर, 2008 में एक संयुक्त करार पर हस्ताक्षर किए। इस परिसर में 90 लग्जरी सुइट तथा विला शामिल हैं, जो की 30 हेक्टेयर में बनाए जाएंगे।

इलेक्ट्रानिक व सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मोरक्कन बाजार में भारत के इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए 31 मार्च-3 अप्रैल, 2008 को मोरक्को की यात्रा की।

प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 अक्तूबर, 2008 को मोरक्को की यात्रा की।

एक राजस्थानी खानाबदोश संगीत दल ने 16 मई, 2008 को रबात में आयोजित 8दिवसीय मावाजेइन, राईम्स ऑफ द वर्ड संगीत महोत्सव में भाग लिया। भारत से एक शास्त्रीय गायक सुश्री मुधुप मुदगल ने 6-15 जून, 2008 को आयोजित वर्ल्ड सेक्रेड म्यूजिक फेज महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारत की ओर से सुश्री पदमावती परादिन व बीना परादिन ने 24-26 अक्तूबर, 2008 को आयोजित फैज कलनरी फेस्टिबल में भाग लिया। एक 18 सदस्यीय नावा संगीत समूह ने 2-7 दिसंबर, 2008 को भारत-अरब सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया।

एक मोरक्कन सांस्कृतिक समूह ने 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अरब सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। संस्कृति उप मंत्री श्रीमती खादिजा अलगोड ने 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अरब सहभागिता मंच तथा भारत अरब महोत्सव में भाग लिया।

श्री जावेद कादेरी को मरीकेक में भारत का अवैतनिक कोंसल नियुक्त किया गया है।

फिलीस्तीन

भारत, मातृभूमि के लिए फिलीस्तीनियों की उचित आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए अपना स्थाई समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है तथा फिलीस्तीन और इजराइल के मध्य व्यापक वार्ता का समर्थन करता है, जो कि नवंबर, 2007 में आनापोलिश शांति सम्मेलन में शुरू की गयी थी। भारत ने जुलाई, 2008 में जकार्ता में फिलीस्तीन के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित नए एशिया अफ्रीका सामरिक साझेदारी मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत ने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिलीस्तीनी लोगों के लिए 60 आईटीईसी स्थान प्रदान करने की वचनबद्धता दी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 80 कर दिया गया।

फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकारण के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अब्बास ने 6-9 अक्तूबर, 2008 को भारत की सरकारी यात्रा की। राष्ट्रपति अब्बास ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की तथा उप राष्ट्रपति एम. हमीद अंसारी ने राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात की। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व राष्ट्रपति अब्बास ने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर विचार-विमर्श किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी तथा विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात की।

इस यात्रा के दौरान आबुदिश (फिलीस्तीन) में जवाहरलाल नेहरू हाईस्कूल के विनिर्माण तथा उसे साधन संपन्न बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रपति अब्बास ने फिलीस्तीन के राजदूतावास के चांसरी एवं आवासीय परिसर की आधारशिला रखी, जो कि नई दिल्ली में सरकार तथा भारत के लोगों की ओर से उपहार स्वरूप में निर्मित किया जा रहा है। फिलीस्तीनी पक्ष ने उनके हितों के लिए भारत की पारंपरिक तथा सतत् वचनबद्धता की सराहना की।

विचार-विमर्श की प्रक्रिया के दौरान भारत ने फिलीस्तीन के आर्थिक विकास में अपनी वचनबद्धता दोहरायी। इस संबंध में फिलीस्तीन के लिए परियोजना सहायता में भारत सरकार की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की बजटगत सहायता के साथ फिलीस्तीन विकास कार्यक्रम के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालरों की अनुदान सहायता प्रदान करने की घोषणा की।

भारत सरकार ने वक्तव्यों की श्रृंखला के माध्यम से दिसंबर, 2008 में गाजा में शुरू इजराइली सैनिक कार्रवाई की भरसक निंदा की। फिलीस्तीन के उचित हितों के लिए भारत की स्थायी तथा सतत् समर्थन दोहराते हुए प्रधान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायता दें। इसके अलावा भारत सरकार ने गाजा के राहत प्रयासों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए के लिए 1 मिलियन डालर का सहयोग दिया।

लेबनान

भारत तथा लेबनान में सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे। भारत ने मई, 2008 में लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में जनरल माइकल सुलेमन के निर्वाचन का स्वागत किया।

डॉ. एम. एम. पालम राजू, रक्षा राज्य मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दल के एक भाग के रूप में दक्षिण लेबनान में तैनात भारतीय दल से मिलने के लिए 10-12 सितंबर, 2008 को लेबनान की यात्रा की।

आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित, श्री समुंदर खान लांगा के नेतृत्व में एक राजस्थानी संगीत समूह तथा पंडित दयाशंकर के नेतृत्व में एक शहनाई समूह ने 17-22 अक्तूबर, 2008 को लेबनान की यात्रा की थी।

दुबई में भारतीय पर्यटन कार्यालय ने अक्तूबर, 2008 में बेरुत मे आयोजित पर्यटन प्रदर्शनी में भाग लिया।

लीबिया

वर्ष के दौरान भारत-लीबिया द्विपक्षीय संबंधों में विकास होता रहा। श्री अब्दुल सलाम तरीकी ने लीबियन प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच मे भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। एक लीबियाई सांस्कृतिक दल ने संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण किया।

राईट्स व रेलरोड्स प्रोजेक्ट कार्यान्वयन प्रबंधन बोर्ड के बीच नवंबर, 2008 में रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, इसमें परियोजनाओं के साथ-साथ विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण का आदान-प्रदान शामिल है। मई, 2008 में दोनों पक्षों के बीच इंडियन आयेल - सोनाट्रक (अल्जीरिया) एक परिसंघ का प्रचालन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय कंपनियां तथा तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम लीबिया में तेल और तेल पाइपलाइनों, आवास, विनिर्माण व अवस्थापना, विद्युत, कंप्यूटरीकरण व प्रशिक्षण जैसे विकासात्मक कार्यकलापों में लगे रहे।

आईसीसीआर- प्रयोजित सांस्कृतिक मंडलियों ने त्रिपोली और सिरते में अगस्त, 2008 में कार्यक्रम आयोजित किए।

19 भारतीय कंपनियों ने अप्रैल, 2008 में आयोजित त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया। पिछले वर्ष पेट्रोलियम मंत्री श्री मुरली देवड़ा की लीबिया यात्रा के दौरान लीबिया को प्रस्तावित

100 स्थानों में से लीबिया के राष्ट्रीय तेल निगम के कर्मचारियों ने केवल 40 स्थानों का उपयोग किया।

सोमालिया

कीनिया में भारत के उच्चायुक्त को सोमालिया का कार्यभार भी सौंपा गया है। इस दौरान सोमाली तटों पर जल दस्युता ने भारतीय ध्वज वाहक जहाजों तथा भारतीय व्यापारी नाविकों को बार-बार अक्रांत किया। सोमाली समुद्र में जलदस्युता विरोधी अभियान में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के लिए सोमाली अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

सूडान

निवेश से संबंधित राज्य मंत्री, श्री सलमान सुलीमान अलसाफी ने 1 अप्रैल, 2008 में फिक्की- भारत-अरब निवेश परियोजना कन्कलेव-। में भाग लिया विदेश कार्य मंत्रालय के अवर सचिव महामहिम डॉ. मुतरीफ सिदीक ने जुलाई, 2008 में भारत की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद से मुलाकात की। वित्त एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री डा. अबाद अलजाज ने सूडान के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में अक्तूबर, 2008 में भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने सूडानी राष्ट्रपति की ओर से डा. मनमोहन सिंह के लिए एक पत्र उन्हें सौंपा। इस यात्रा के दौरान विशेष दूत ने वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देबड़ा से मुलाकात की।

थल सेना उपाध्यक्ष ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति दल के निरीक्षण के लिए सूडान की यात्रा की।

वर्ष के दौरान सूडान में दो भारतीय राष्ट्रिक लापता रहे।

सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी वेपकोस ने दक्षिण सूडान में विद्युत व जल आपूर्ति परियोजना की परामर्शदायता के लिए अंशदाताओं द्वारा वित्त पोषित परियोजना की निविदा प्राप्त की।

आईसीसीआर के तत्वाधान में गोवा से एक लोक संगीत व नृत्य समूह ने नवंबर, 2008 में खारतूम, कुडूगिल और मलाकाल की यात्रा की। विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में दक्षिण सूडान की सरकार के क्षेत्रीय सहयोग मंत्रालय के 15 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सूडान के संस्कृति युवा एवं खेल मंत्री श्री मोहम्मद यूसुफ अबदाला ने 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अरब सहभागिता मंच तथा भारत-अरब महोत्सव मे भाग लिया।

सीरिया

सीरिया के राष्ट्रपति डॉ. बसार अल असाद तथा श्रीमती अस्मा असाद ने 17-21 जून, 2008 को भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान सीरिया के राष्ट्रपति ने बंगलौर व आगरा का भी दौरा किया। डॉ. बसार अलअसाद के साथ विदेश कार्य मंत्री श्री वालिद अल मुआलम पर्यावास मंत्री डॉ. सुश्री भूटानिया साहवान, आर्थिक एवं व्यापार मंत्री श्री अमर हुसैन लुत्फी, दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ईमाद सवोनी भी थे। सीरिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की। भारत के उप राष्ट्रपति डा. एम. हमीद अंसारी, विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

राष्ट्रपति बसार अल असाद व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 18 जून को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत तथा सीरिया के मध्य द्विपक्षीय आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत बनाने का प्रयास, सीरियाई फास्फेटिक उर्वरक, हाइड्रोकार्बन व विद्युत क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देना, इस वार्ता की मुख्य विशेषताएं थीं। भारत ने सीरियाई फास्फोरिक क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एक परामर्शदायी अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद सचिव, उर्वरक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीरिया की यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेजों में (i) पारस्परिक निवेश सुरक्षा व संवर्धन से संवधित करार (ii) दोहरे कराधान से बचाव व राजस्व चोरी से सुरक्षा से संबंधित करार (iii) 2008-2009 हेतु कृषि व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्य योजना शामिल है।

सीरिया के संस्कृति मंत्री डॉ. रियाद नासान आगा ने 2-7 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अरब सहभागिता मंच तथा भारत-अरब महोत्सव में भाग लिया। सीरिया ने भी चित्रकला प्रदर्शनी, हस्तकला प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया।

ट्यूनीशिया

लघु व मध्यम उद्यम से संबंधित संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक 8-9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। औषध एवं भेषज संबंधित संयुक्त कार्यसमूह की चौथी बैठक 5-7 अक्तूबर, 2008 को ट्यूनिश में आयोजित की गयी। ट्यूनीशिया तथा भारत में वैक्सीन व सिरम के वाणिज्यिक उत्पादन के साथ-साथ उनके अनुसंधान के लिए पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूनीशिया तथा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा व अनुसंधान संस्थान के मध्य साझेदारी पर विचार किया गया तथा जैव प्रौद्योगिकी को सहयोग के क्षेत्र के रूप में पहचान की गयी।

भारत-ट्यूनीशिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक 8 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह ने 29 जुलाई- 7 अगस्त, 2008 को ट्यूनीशिया की यात्रा की। इस समूह ने ट्यूनीशिया के विभिन्न शहरों में 7 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

अरब राज्य लीग

जुलाई, 2008 में विदेश मंत्री की काहिरा यात्रा के दौरान आयोजित विचार-विमर्श की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अरब राज्य लीग के महासचिव महामहिम श्री अमरे मुसा ने 30 नवंबर-2 दिसंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। महासचिव व विदेश मंत्री ने 2 दिसंबर, 2008 को प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की, जिसके बाद सहयोग से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत तथा व्यापक बनाने के लिए एक औपचारिक संरचना के रूप में भारत-अरब सहयोग मंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया। विदेश मंत्री व महासचिव ने आईसीसीआर व विदेश मंत्रालय के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित एक सप्ताह के सांस्कृतिक महोत्सव "भारत-अरब मंचः संस्कृति के माध्यम से सहभागिता" का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न अरब देशों से लगभग 200 कलाकारों को 2-7 दिसंबर, 2008 के दौरान इकट्ठा किया गया। इस महोत्सव में फिल्म प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण, हस्तकला मेला, चित्रकला व फोटो प्रदर्शनी तथा आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित भारत-अरब सभ्यता संपर्क पर एक संगोष्ठि शामिल है। सूडान, सीरिया, मोरक्को, मिस्र, यमन व ओमान से संस्कृति मंत्रियों ने इस महोत्सव में भाग लिया।

■■

6 अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)

पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीका

भारत-अफ्रीका सम्मेलन मंच

8-9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इस सम्मेलन से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत व अफ्रीका के मध्य संबंधों के लिए एक नयी संरचना सृजित हुई। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप सहयोग के लिए अफ्रीका-भारत ढांचा व दिल्ली घोषणाओं से एक महत्वाकांक्षी खाका तैयार हुआ।

प्रधान मंत्री ने आगामी 5 वर्षों में अफ्रीका को दिए जाने वाले वर्तमान ऋण के स्तर को दुगुना करके 5.4 बिलियन डालर करने की घोषणा की। इस ऋण का उपयोग अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण, लघु व मध्यम उद्यमों, सिंचाई, अवस्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा व भेषज क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। अफ्रीकी सरकारें अपनी आवश्यकताएं के आधार पर इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगी।

विशेष रूप सें क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के अलग अनुदान की घोषणा भी की गयी थी। इनमें सब प्रकार के कार्यक्रम अर्थात् आईटीईसी के अंतर्गत शैक्षणिक छात्रवृत्ति को दोगुना करना, आईसीसीआर की सामान्य छात्रवृत्ति योजनाएं, जल संसाधन, स्वास्थ्य, कृषि, खनन हेतु पाठ्यक्रम आयोजित करना, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हीरे, कोयले इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में शीर्ष संस्थान स्थापित करना शामिल है। इन कार्यक्रमों से अफ्रीका आईटीईसी कार्यक्रमों से लाभांवित होने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा।

प्रधान मंत्री ने अफ्रीकी एलडीसी से उत्पाद प्राप्त करने के लिए शुल्कमुक्त, शुल्क अधिमानता (डीएफटीपी) योजना के प्रस्ताव की घोषणा भी की। विश्व के 50 एलडीसी में 34 अफ्रीका में हैं। कई अफ्रीकी राष्ट्र पहले ही इस योजना से जुड़ चुके हैं। इससे विश्व व्यापार संगठन में हमारे द्वारा पहले से दी गयी वचनबद्धता पूरी हुई है।

भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन की इस संरचना का निर्माण भारत और अफ्रीका के बीच पहले से ही मौजूद ऐतिहासिक एवं प्राचीन संबंधों के ठोस आधार पर किया गया है तथा जो उप निवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद के विरुद्ध लंबे संघर्ष के दौरान और मजबूत हुए थे, जिसमें भारत व अफ्रीका सहभागी थे।

भारत ने इस क्षेत्र से विभिन्न उच्च स्तरीय दौरों की मेजबानी की:

- 7-9 अप्रैल, 2008 के दौरान नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री थाबो मबेकी ने भारत का दौरा किया।
- जाम्बिया के तत्कालीन उप राष्ट्रपति, श्री रूपेया बेवजार्नी बान्दा ने 8 और 9 अप्रैल, 2008 को दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- यूगान्डा के राष्ट्रपति, श्री योवेरी कागुता मुसवेनी ने पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के प्रमुख के रूप में 8-9 अप्रैल, 2008 को भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वह 10 अप्रैल, 2008 को सरकारी दौरे पर आए थे।
- तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जाकया मरीशो किकवेटे ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में 8-9 अप्रैल, 2008 को भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ईथोपिया के प्रधान मंत्री श्री मेलेस जेनावी ने भारत का दौरा किया और 8-9 अप्रैल, 2008 को भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति श्री कगलेमा मोटलांथे ने विभिन्न दक्षिणी अफ्रीकी मंत्रियों के साथ 15 अक्तूबर 2008 को नई दिल्ली में तीसरे आई बी एस ए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।
- मारिशस के उप राष्ट्रपति श्री अनगीदी वीरया चेतियार ने 7-9 जनवरी, 2009 को 7वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए चैन्ने का दौरा किया।
- माननीय प्रधान मंत्री के आमंत्रण पर आरटी माननीय रेला ओडिंगा, ई जी एच, एम पी केन्या के प्रधान मंत्री ने 11-14 जनवरी, 2009 को वाइब्रेण्ट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन (वी जी जी आई एस) 2009 में भाग लेने के लिए गुजरात का दौरा किया।
- रवान्डा के राष्ट्रपति श्री पाल कागमे नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार भागीदारी शिखर सम्मेलन (19-20 जनवरी) में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने हेतु 18-23 जनवरी, 2009 को भारत का दौरा किया।
- इथोपिया के प्रधान मंत्री श्री मेलेस जेनावी ने टेरी द्वारा आयोजित दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन 2009 में भाग लेने के लिए 4-5 फरवरी, 2009 को भारत का दौरा किया।

- भारतीय पक्ष से राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने लेटिन अमेरिकी देशों की अपनी यात्रा के पश्चात भारत लौटते समय 24 अप्रैल, 2008 को केपटाउन में संक्षिप्त तकनीकी स्टाप ओवर किया।

वर्ष के दौरान भारत के अन्य महत्वपूर्ण दौरों में शामिल हैं:

- केन्या के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में केन्या के विदेश मंत्री (अप्रैल)
- अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष (जून)
- इथोपिया के हाउस आफ फेडरेशन के स्पीकर (मई)
- नामिबिया के विदेश मंत्री (जून)
- तंजानिया के प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन मंत्री (जून)
- इथोपिया के श्रम और सामाजिक कार्य राज्य मंत्री (जून)
- दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा मंत्री (जुलाई)
- दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री (जुलाई)
- दक्षिण अफ्रीका फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष और हाउस ऑफ ट्रेडीशनल लीडर्स के अध्यक्ष राजकुमार मैंगोसुथू बुथलेजी (जुलाई)
- मोजेम्बिक के इन्टीरियर (जुलाई)
- इथोपिया के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण राज्य मंत्री (जुलाई)
- दक्षिण अफ्रीका के लोक सेवा और प्रशासन मंत्री (अगस्त)
- मेडागास्कर के स्वास्थ्य मंत्री (अगस्त)
- उगान्डा के उप एटार्नी जनरल/न्याय और संवैधानिक कार्य राज्य मंत्री (अगस्त)
- तंजानिया के आधारभूत संरचना विकास मंत्री (सितम्बर)
- तंजानिया के संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (सितम्बर)
- रवान्डा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री (अक्तूबर)
- इरीट्रिया के कृषि मंत्री (अक्तूबर)
- मारीशस की नेशनल एसेम्बली के उप स्पीकर के नेतृत्व में मारीशस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल (23 सदस्य) (अक्तूबर)
- दक्षिण अफ्रीका के आवास मंत्री (अक्तूबर)
- तंजानिया के कृषि, खाद्य सुरक्षा और सहकारिता मंत्री (नवम्बर)
- रवान्डा के कृषि और पशु संसाधन मंत्री (नवम्बर)
- उगान्डा के मत्स्य पालन राज्य मंत्री (नवम्बर)
- तंजानिया के लोक सेवा प्रबंधन मंत्री (नवम्बर)
- यूथोपिया के क्षमता निर्माण राज्य मंत्री (नवम्बर)
- मालावी के कृषि और खाद्य सुरक्षा उप मंत्री (नवम्बर)
- लिसोथा के व्यापार और उद्योग, सहकारिता और विपणन सहायक मंत्री (नवम्बर)
- मारीशस के राष्ट्रपति (निजी दौरा) (दिसम्बर)
- नामीबिया के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (दिसम्बर)
- इरीट्रिया के ऊर्जा और खान मंत्री (जनवरी)
- केन्या के प्रधान मंत्री माननीय रेला ओडिंगा ने वाइक्रेन्ट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन (वी जी जी आई एस) 2009 में भाग लेने के लिए गुजरात का दौरा किया (जनवरी)
- केन्या के कृषि मंत्री तथा पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के मंत्री श्री अमासन किंगी जिफा ने भारत का दौरा किया (जनवरी)
- मारीशस के पर्यावरण तथा राष्ट्रीय विकास यूनिट मंत्री (जनवरी)
- मोजाम्बिक के ऊर्जा मंत्री (जनवरी)
- स्वाजीलैण्ड के वाणिज्य, उद्योग तथा व्यापार मंत्री (जनवरी)
- तंजानिया के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्री तथा उप विदेश मंत्री (जनवरी)
- तंजानिया के उद्योग, व्यापार और विपणन मंत्री (जनवरी)
- उगान्डा के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (आई सी टी) (जनवरी)
- उगान्डा के राष्ट्रपति का कार्यालय में आर्थिक मानिटरिंग राज्य मंत्री (जनवरी)
- जाम्बिया के स्वास्थ्य उप मंत्री (जनवरी)
- मोजाम्बिक के विदेश कार्य और सहयोग मंत्री (फरवरी)
- मोजाम्बिक के पर्यावरण कार्य समन्वय मंत्री (फरवरी)
- मारिशस के सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सुधार संस्थान मंत्री (26 जनवरी से 8 फरवरी)
- रवान्डा के स्वास्थ्य मंत्री (फरवरी)
- रवान्डा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री (फरवरी)
- केन्या के चिकित्सा सेवा मंत्री (फरवरी)
- बोत्सवाना के रक्षा, न्याय और सुरक्षा मंत्री (फरवरी)
- नामीबीया के रक्षा उप मंत्री (फरवरी)

- तंजानिया के ऊर्जा और खनिज मंत्री (मार्च)
- बोत्सवाना के व्यापार और उद्योग मंत्री (मार्च)
- मारीशस के उप-प्रधान मंत्री, वित्त और आर्थिक अधिकारिता मंत्री (मार्च)
- मोजाम्बिक के कृषि उप मंत्री (मार्च)
- स्वाजीलैण्ड साम्राज्य के प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा मंत्री और सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री (मार्च)
- उगान्डा के निवेश राज्य मंत्री, व्यापार और उद्योग मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री (मार्च)
- जिम्बावे के क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री (मार्च)

भारत से

- लोक सभा के उप अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा मारीशस और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (अप्रैल)
- विदेश मंत्री द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (मई)
- जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के विशेष दूत द्वारा मारीशस की यात्रा (मई)
- गोवा सरकार के एन आर ई मामलों के आयुक्त द्वारा केन्या की यात्रा (मई)
- गोवा सरकार के एन आर ई मामलों के आयुक्त द्वारा मोजाम्बिक की यात्रा (मई)
- विदेश राज्य मंत्री द्वारा ईथोपिया की यात्रा (जुलाई)
- विदेश राज्य मंत्री, श्री आनन्द शर्मा द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (जुलाई और सितम्बर)
- पर्यटन और संस्कृति मंत्री द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (अगस्त)
- विदेश राज्य मंत्री द्वारा तंजानिया की यात्रा (अगस्त)
- रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (सितम्बर)
- वाणिज्य और विद्युत राज्य मंत्री द्वारा ईथोपिया की यात्रा (अक्तूबर)
- केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (नवम्बर)
- गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा उगांडा और केन्या की यात्रा (नवम्बर)
- असम सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री द्वारा केन्या की यात्रा (जनवरी 2009)

बोत्सवाना

भारत तथा बोत्सवाना के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, जिन्हें बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट कहा है। दिसंबर, 2006 में भूतपूर्व राष्ट्रपति फिस्टस मोगाय की यात्रा की दौरान हस्ताक्षरित 6 करारों पर वर्ष 2006 के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई की गयी। दोनों देश अन्य कई करारों पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में सहयोग तथा कृषि व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन शामिल है। 14-17 सितंबर, 2008 को बोत्सवाना रक्षा दल के कमांडर ले. जनरल टी. एच. सी. मासीरे के आमंत्रण पर वायु सेनाध्यक्ष (सीएएस) और एयर चीफ मार्शल जे. एच. मेजर की बोत्सवाना यात्रा तथा 27-28 नवंबर, 2008 को थल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर की यात्रा से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को काफी प्रोत्साहन मिला है।

द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग में वृद्धि करने के लिए बोत्सवाना के शिक्षा मंत्रालय से एक प्रतिनिधिमंडल ने दूर शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए भारत की यात्रा की। टीसीआईएल ने फ्रैंसिसटाउन में नायनगंबावे अस्पताल में पहले ही टेलीमेडिसीन हार्डवेयर स्थापित कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क से संबंधित कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। बोत्सावाना में पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना को सराहा गया है। भारत में साइबर सिटी के समान बोत्सवाना में एक नवीन केंद्र स्थापित किया जा चुका है। बोत्सवाना के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भारत व साकू पीटीए वार्ता के तीसरे दौर में भाग लेने के लिए 25-27 नवंबर, 2008 को भारती की यात्रा की।

आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सचिव डॉ. हरजीत सिंह आनन्द के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीका में सतत आवास के लिए नवीन निर्माण सामग्री व विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकियों से संबंधित एक प्रदर्शनी व संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 11-14 अप्रैल, 2008 को बोत्सवाना की यात्रा की।

द्विपक्षीय आर्थिक व वाणिज्यिक मुद्दों के संबंध में इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय सूचना उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 सितंबर, 2008 को गैबरोन की यात्रा की तथा क्रेक्र-विक्रता-बैठक व बोत्सवाना की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ अलग-अलग बातचीत में हिस्सा लिया।

संस्कृति विभाग व युवा खेल व संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 10-15 नवंबर, 2008 को गैबरोन में भारत-बोत्सवाना सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक बालफिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की ओर से 14 बाल फिल्में प्रदर्शित की गयी थीं।

बोत्सवाना के रक्षा, न्याय व सुरक्षा मंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डिग्गागानास्टो एनडेलू सेरिटस ने 11-15 फरवरी, 2009 को

बंगलौर में आयोजित 7वें इंटरनेशनल एरोस्पेस एक्सपोजिशन के संबंध में भारत की यात्रा की।

बोत्सवाना सरकार के व्यापार व उद्योग मंत्री माननीय डेनल एन मोराका ने 22-24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता से संबंधित सीआईआई- एग्जिम बैंक के 5वें कनक्लेव में भाग लिया।

बुरुंडी

2007-08 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 9.89 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें लगभग 25% की वृद्धि हुई। भारतीय निर्यात का लगभग 8.04 मिलियन अमरीकी डालर था।

गुजरात के वाणिज्य व उद्योग चैंबर से व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 14-15 नवंबर, 2008 को बुरुंडी की यात्रा की।

कोमोरोस

कोमोरोस ने देश में एक पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क स्थापित करने के लिए टीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आवश्यक उपस्कर मरोनी पहुंच गए हैं तथा कोमोरोस सरकार द्वारा टेलीमेडिसीन, दूर शिक्षा तथा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति संपर्क के स्थानों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

आईबीएसए के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में कामोरोस को एक मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर एक परियोजना प्रस्तावित की गयी है। कोमोरोस सरकार को व्यवहार्यता अध्ययन जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि भारत सरकार परियोजना का कार्यान्वयन कर सके।

इरिट्रिया

भारत के दो नोसैनिक जहाजों, अर्थात् आईएनएस गोदावरी तथा आईएनएस आदित्य ने 3-6 सितंबर, 2008 को मासावा तट तथा 7-8 सितंबर, 2008 को आसाव तट की सद्भावना यात्रा की।

इरिट्रिया के कृषि मंत्री श्री अराफेन बरहे तथा राष्ट्रपति कार्यालय में महानिदेशक श्री यामिनी गेबरे मैसकल ने 28 सितंबर- 5 अक्तूबर, 2008 को भारत की सरकारी यात्रा की। रिट्रिया के मंत्री ने दोनों देशों के मध्य कृषि के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करने तथा विचार-विमर्श करने के लिए 29 सितंबर, 2008 को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की।

इरिट्रिया राज्य में ऊर्जा व खान मंत्री श्री टेसफाई गेबरीसिलाईसी ने भारत सरकार द्वारा समर्थित तथा फिक्की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार सहभागिता सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-23 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। मंत्री तथा प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए खान मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की।

इथोपिया

इथोपिया के प्रधान मंत्री श्री मेलिश जनावी के साथ विदेश मंत्री श्री सेयोम मेसफिन ने अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन में भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने प्रधान मंत्री के एक विशेष दूत के रूप में इथोपिया, जो कि आईएईए के साथ प्रस्तावित भारतीय सुरक्षा करार से संबंधित शासी निकाय का एक सदस्य है, का समर्थन प्राप्त करने 30-31 जुलाई, 2008 को इथोपिया की यात्रा की। इथोपिया ने वियना में भारत का पूरी तरह समर्थन किया तथा प्रधान मंत्री ने राज्य मंत्री आनन्द शर्मा से यह कहा कि विश्वस्तर पर भारत का पुनःउद्भव सामान्य रूप से अफ्रीका के लिए तथा विशेष रूप से इथोपिया के लिए काफी अच्छा था।

श्री जयराम रमेश, वाणिज्य व विद्युत राज्य मंत्री ने भारतीय कर्मचारियों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आदिस अबाबा में आयोजित भारतीय-इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए 5-7 अक्तूबर, 2008 को इथोपिया की यात्रा की।

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने यूएनजीए, न्यूयार्क के अवसर पर इथोपिया के प्रधान मंत्री मेलिश जनावी से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

संघ के सदन के अध्यक्ष ने 6-9 मई, 2008 को दिल्ली में अध्ययन यात्रा के संबंध में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जनप्रतिनिधि सदन के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक अन्य 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक निर्देशन मिशन पर 4-8 अगस्त, 2008 को बीपीएसटी, नई दिल्ली की यात्रा की। दक्षिण राष्ट्र, राष्ट्रीयता जनक्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने एक संसदीय अनुभव साझेदारी कार्यक्रम के रूप में 26-28 अगस्त, 2008 को बीपीएसटी की यात्रा की।

श्रम व सामाजिक कार्य राज्य मंत्री श्री मोहम्मद मालिन अली ने 16-21 जून, 2008 को भारत की यात्रा की। इथोपिया के राज्य मंत्री ने 17.06.2008 को श्रम व रोजगार राज्य मंत्री (आईसी) से मुलाकात की तथा पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण राज्य मंत्री श्री वोंडवोसन किफलू ने 14—17 जुलाई, 2008 तक भारत का दौरा किया। इथोपिया के मंत्री ने 17 जुलाई, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत की। इथोपिया के अलावा निर्माण राज्य मंत्री श्री फिकरु देसालेगने ने 23-28 नवंबर, 2008 को अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में बैठकें/प्रस्तुति दी। प्रतिनिधिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी की यात्रा भी की।

वर्ष, 2008, भारत तथा इथोपिया के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है।

इथोपियाई डाक सेवा ने इथोपिया तथा भारत के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के साठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तीन डाक टिकट जारी किए थे।

2 अक्तूबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था। यहां प्रधान मंत्री मेलिश जनावी ने गांधी स्मृति व्याख्यान दिया। इथोपियाई प्रधान मंत्री ने अम्हारिक में प्रकाशित प्रथम पुस्तक "भारत- एक गतिशील लोकतंत्र" का विमोचन किया। यूएनईसीए के सहयोग से राजदूतावास ने इसे आयोजित किया।

टेरी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अफ्रीकी प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन नीतिअध्ययन हेतु अफ्रीकी केंद्र स्थापित करने के लिए यूएनईसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

इथोपिया, अफ्रीका में वर्ष 2007 में शुरू की गयी पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का लाभ उठाने वाला पहला देश है, थी।

गुरु सरोजा वैद्यनाथन के नेतृत्व में एक भरतनाट्यम नृत्य मंडली ने जून, 2008 में इथोपिया की यात्रा की। गोवा की एक संगीत व नृत्य मंडली "पाइनियर ऑफ क्यूपेम" ने 27 अक्तूबर - 2 नवंबर, 2008 को इथोपिया की यात्रा की तथा चार शहरों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इथोपिया के प्रधान मंत्री श्री मेलिश जनावी ने टेरी द्वारा आयोजित दिल्ली सतत् विकास सम्मेलन, 2009 में भाग लेने के लिए 4-5 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने इथोपिया के प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह मुख्यतः भारत के पक्ष में है। इथोपिया के सीमा शुल्क प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2007 में भारत ने इथोपिया को 426.9 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात है, जबकि इथोपिया से 14 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सामग्री का आयात हुआ है। वर्ष 2008 में इथोपिया में भारतीय निवेश 3.5 बिलियन डालर से अधिक था तथा सूडान के बाद भारत इथोपिया में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है।

कीनिया

कीनिया के विदेश मंत्री श्री मोजेज वेटांगउला ने राष्ट्रपति किबाकी के प्रतिनिधि के रूप में भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6-10 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा की। गोवा सरकार के अनिवासी भारतीय मामलों के आयुक्त श्री एडुओर्डो फ्लेरो ने विशेष रूप से कीनिया में बसे गोवा के निवासियों के समुदाय के कल्याण का संवर्धन करने के लिए तथा सामान्य रूप से विदेशी भारतीय समुदाय से बातचीत करने के लिए 21-25 मई, 2008 को कीनिया की यात्रा की। श्री फेलेरो ने कीनिया के शिक्षा मंत्री प्रो. सैम ओंगेरी से भी मुलाकात की। भारत के राष्ट्रीय रक्षा महा विद्यालय से 15 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के एक दल ने अपने विदेशी अध्ययन दौरे के रूप में 11-16 मई, 2008 को कीनिया की यात्रा की। आईएनएस गोदावरी 17-21 अगस्त, 2008 को सद्भावना यात्रा पर मोमबासा पहुंचा।

राजस्व एकत्रीकरण के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर कार्यक्रम शुरू करने के लिए कीनिया के राजस्व अधिकारियों की सहायता हेतु सीमा शुल्क कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6-8 अगस्त, 2008 को कीनिया की यात्रा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एस. राजेंद्र बाबू सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्र मंडल मानवाधिकार संस्थान मंच की बैठकों तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 19-25 अक्तूबर, 2008 को कीनिया की यात्रा की।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीवंत गुजरातः विश्वस्तरीय निवेशक सम्मेलन 2009 को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोड शो के एक भाग के रूप में 18-20 नवंबर, 2008 को कीनिया की यात्रा की। उनके साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों तथा गुजरात के अग्रणी व्यापारियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भी था। मुख्य मंत्री ने कीनिया के उप राष्ट्रपति व गृह मंत्री श्री कालोंजो मुसियोका, प्रधान मंत्री श्री रेला ओडिंगा तथा उप प्रधान मंत्री व स्थानीय सरकार के मंत्री श्री मोसालिया मोदावदी से मुलाकात की।

कीनिया रेलवे के प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मैट्रो परियोजना की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने तथा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की यात्रा की थी।

भारत-कीनिया संयुक्त व्यापार समिति की 5वीं बैठक 16-17 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। कीनियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थायी सचिव डॉ. (ईएनजी) सायरस एनजिरू तथा व्यापार मंत्री ने किया था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य व विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने किया था।

असम सरकार के उद्योग व वाणिज्य मंत्री माननीय प्रद्युत वाडालोई के नेतृत्व में एक चाय प्रतिनिधिमंडल ने कीनिया के छोटे चाय कृषि क्षेत्रों में स्थापित संरचना के बारे में जानने के लिए 11-16 जनवरी, 2009 को कीनिया का एक अध्ययन दौरा किया तथा चाय विकास प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक की।

महान्यायवादी माननीय अमोस बाको ने 28 दिसंबर, 2008 - 5 जनवरी, 2009 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति व विधि बैठक में भाग लेने के लिए अहमदाबाद की यात्रा की।

प्रधान मंत्री माननीय श्री रेला ओडोलिंगा ने 11-14 जनवरी, 2009 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित "जीवंत गुजरात विश्वस्तरीय निवेशक सम्मेलन" में भाग लिया और उन्होंने भारत के शीर्ष उद्योगपतियों व व्यापारियों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह व पोरबंदर इत्यादि सहित कई औद्योगिक

9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में इथोपिया के प्रधानमंत्री मेलिश जेनेवी
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ।

26 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र के अवसर पर
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह नामीबिया के राष्ट्रपति हिफिकेपुनिये पोहांबा के साथ मुलाकात करते हुए।

प्रतिष्ठानों की यात्रा भी की। प्रधान मंत्री रेला ओडलिंगा ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी विचार-विमर्श किया, जो उन्हें उचित मूल्य की दुकानों पर ले गए, ताकि समाज के निर्धन वर्गों में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था का अध्ययन किया जा सके।

कीनिया के कृषि मंत्री श्री विलियम रुटो तथा पूर्व अफ्रीकी समुदाय मंत्री श्री इमेजन किंगी जेफा ने भारत की यात्रा की तथा 19-20 जनवरी, 2009 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार सहभागिता सम्मेलन में भाग लिया।

कीनिया के चिकित्सा सेवा मंत्री, श्री पी. ऐ. नियोंग ओ ने 1-4 फरवरी, 2009 को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल (आईएपी) की 5वीं बैठक के संबंध में भारत की यात्रा की।

पिछले 4-5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2007 में 650 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। भारत से कीनिया को निर्यात की प्रमुख मदों में औषध व भेषज रसायन व मशीनरी शामिल है। भारत द्वारा आयातित प्रमुख मदों में काजू, चमड़ा व चमड़े के उत्पाद तथा रद्दी धातु इत्यादि शामिल हैं।

भारतीय कंपनी एस्सार के साथ इकोनेट वायरलैस इंटरनेशनल ने वाईयू ब्रांड के अंतर्गत 26 नवंबर, 2008 को चौथी जीएसएम नेटवर्क मोबाइल सेवा शुरू की थी। एस्सार समूह ने इस संयुक्त उद्यम में 500 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। इसके अलावा एस्सार समूह ने एस्सार तेल के माध्यम से कीनिया पेट्रोलियम रिफाइनरी में 11 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर 50% शेयरों की खरीद की थी। अन्य मुख्य निवेशों में रिलाइंस समूह द्वारा नेरोबी में 200 मिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति की खरीद, करुंतरी समूह की एक फूलों की फर्म शेर करुंतरी द्वारा 70 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा नैरोबी में 70 मिलियन अमरीकी डालर की कुल लागत से एलपीजी संयंत्र का विनिर्माण शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान 20 नवंबर को कीनिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ओसवाल केंद्र व व्यापार बैठक में जीवंत गुजरात पर एक रोड शो आयोजित किया गया था, जिसमें कीनिया के 500 से अधिक उद्योगपतियों व व्यापारियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच लघु स्तरीय उद्योग, ढांचागत विकास, ऊर्जा, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा खनिज गवेषण आदि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श किया गया था।

लिसोथो

लिसोथो के साथ भारतीय संबंधों में लगातार विकास हुआ है। लिसोथो के प्रधान मंत्री के अनुरोध पर मासेरु में भारतीय सेना प्रशिक्षण दल की अवधि को 2011 तक बढ़ा दिया गया था। लिसोथो के नेता भारतीस सेना प्रशिक्षण दल के निष्पादन की निरंतर सराहना करते हैं।

यात्राओं के आदान-प्रदान के संबंध में लिसोथो सरकार के व्यापार व उद्योग, सहकारिता व विपणन सहायक मंत्री श्री खोटशो मातला ने भारत एवं साकू के मध्य पीटीए वार्ता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साक्षी के रूप में 26 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की थी।

भारत-लिसोथो संयुक्त आयोग का पहला सत्र 17 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में एसएमएमई, मानव संसाधन विकास, खनन, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास व जल संसाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई।

तकनीकी सहयोग के संबंध में लिसोथो आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण अवसरों का पूरा उपयोग कर रहा है। भारत मासेरु में लिरोथेली पॉलीटेक्निक में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी स्थापित कर रहा है। भारत व लिसोथो के मध्य कृषि सहयोग व स्थानीय सरकार से संबंधित ज्ञापन भी विचारणीय है।

मेडागास्कर

भारत सरकार ने मेडागास्कर में (i) चावल उत्पादकता के लिए परियोजना (10 मिलियन अमरीकी डालर) तथा (ii) उर्वरक उत्पादन परियोजना (15 मिलियन अमरीकी डालर) नामक दो परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। इस संबंध में एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया तथा मालागासी के कृषि, लाइव स्टॉक व मत्स्य पालन मंत्री श्री अरमांद पांजा रमनोलिना के बीव 4 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। मेडागास्कर के राष्ट्रपति श्री मार्क रवलोमनना ने भी 18 नवंबर, 2008 को अटानानारिवो में मेडागास्कर कार्य योजना से संबंधित संगोष्ठी के दौरान कृषि क्षेत्र में भारतीय सहायता का विशेष उल्लेख किया था।

भारत शीघ्र ही एक इंटरनेट परियोजना स्थापित करेगा, जिगमे मालागासी के राष्ट्रपति का कार्यालय, मेडागास्कर सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों से जुड़ जाएगा। 6 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 18 सितंबर, 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक अन्य प्रतिष्ठित परियोजना पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क स्थापित करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा रही है, जो कि मालागासी की जनता को स्वास्थ्य की देखरेख व शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

मेडागास्कर के स्वास्थ्य मंत्री रिलेनिइरेना पॉल रिचर्ड ने 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 17-24 अगस्त, 2008 को भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई व गोवा की यात्रा की तथा सिप्ला लिमिटेड के साथ विचार-विमर्श किया और उनके विनिर्माणकारी यूनिटों का दौर भी किया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से 15 सदस्यीय बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान अंतानानारिवो में द्विपक्षीय व्यापार व निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 28 सितंबर, 2008 एक भारत-मेडागास्कर व्यापार संगोष्ठी आयोजित की गयी थी।

भारत ने मेडागास्कर को 50 हजार टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया, ताकि इस कठिन समय में खाद्यान्न की कमी का समाधान करने में उसकी सहायता की जा सके।

अक्टूबर 2008 में नई दिल्ली में मेडासागर का आवासी दूतावास खोले जाने के साथ ही इस वर्ष द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। वर्ष 2007 के दौरान भारत से मालागासकी के लिए कुल 76.75 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सामग्री का आयात हुआ, जबकि मेडागास्कर से भारत को कुल 18.68 अमरीकी डालर का निर्यात हुआ। सितंबर, 2008 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मेडागास्कर के लिए भारत द्वारा 58.50 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया था, जबकि भारत को मेडागास्कर द्वारा 6.8 मिलियन अमरीकी डालर की सामग्री निर्यात की गयी थी।

मैसर्स एस्कोर्ट, मेडागास्कर को भारत के ऋण के तहत 10 मिलियन अमरीकी डालर के 450 ट्रैक्टर तथा संबंधित उपस्कर भेज रहा है। मेडागास्कर सरकार ने उपरोक्त ऋण के अंतर्गत मैसर्स लक्की एक्सपोर्ट को 20 उर्वरक संयंत्र व जैव उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संविदा प्रदान की थी। 3 भारतीय कंपनियों, अर्थात् गिमपैक्स, वरुण ट्रेडिग तथा सहारा इंडिया ने 2008 के दौरान मेडागास्कर में अपने कार्यालय खोल दिए हैं तथा वे खनन क्षेत्र में निवेश के लिए अवसरों का पता लगा रहे हैं। मैसर्स एस्सार पिछले दो वर्षों से मेडागास्कर में तेल व गैस के गवेषण कार्य में लगा हुआ है। टाटा, बिरला, अशोक लेलैंड, किरलोस्कर, एचसीएल, इरकोम, एंजलिक, जगुआर इत्यादि सहित कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने मेडागास्कर में निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने के लिए गवेषणात्मक यात्राएं की हैं।

मालावी

कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री फ्रैंक तुंपाला ने 10-12 नवंबर, 2008 को सतत् खाद्य सुरक्षा के लिए भारत-अफ्रीका सहयोग से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी।

14 मई, 2008 को एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया व मालावी सरकार के मध्य एक करार के माध्यम से मालावी को सिंचाई खाद्यान्न भंडारण, तंबाकू की कटाई तथा एक गांव एक परियोजना के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया था। 16 जून, 2008 को बाढ़ राहत के लिए 260,689 अमरीकी डालर (1 करोड़ रुपए) का एक चैक मालावी के राष्ट्रपति को सौंपा गया था। मालावी भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधाओं का नियमित उपयोग कर रहा है। अप्रैल, 2008 में भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के बाद 2008-09 में मालावी को आईटेक असैनिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित स्थानों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गयी थी।

ओडिसी नृत्यांगना रंजना गुहार तथा शास्त्रीय संगीत कलाकार डॉ. मुस्तफा रजा के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रत्यायोजित एक नृत्य व संगीत मंडली ने 28-31 अक्तूबर, 2008 को मालावी में कार्यक्रम किया।

मॉरीशस

वर्ष के दौरान मॉरीशस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के व्यापक संबंध जारी रहे।

लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह अटवाल के नेतृत्व में 16 सदस्यीय एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-12 अप्रैल, 2008 को केपटाउन में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 118वीं बैठक में भाग लेने के लिए जाते समय मॉरीशस की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा के माननीय अध्यक्ष श्री राजकेश्वर प्रयाग से मुलाकात की।

मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री मेरी जोजेफ नोएल एतीन्ने घिसलेन सीनाटांबु के नेतृत्व में मॉरीशस के 23 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इस मंत्रालय के लोक राजनय प्रभाग द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12-17 अक्तूबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के अलावा मुम्बई का भी दौरा किया।

मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगनोथ ने 14-21 दिसंबर, 2008 को भारत की गैर-सरकारी यात्रा की।

मॉरीशस के उप प्रधान मंत्री श्री अंगिडी विरया चेत्तियार के नेतृत्व में तथा संसद सदस्य श्री यतिन वर्मा तथा श्री कादिर सैयद हुसैन सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 7-9 जनवरी, 2009 को 7वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया। भारत के राष्ट्रपति ने सम्मेलन के दौरान श्री अंगिडी चेत्तियार को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। वे मॉरीशस के चौथे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2003 में मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगनोथ, वर्ष 2006 में मॉरीशस के भूतपूर्व उप राष्ट्रपति श्री अब्दुल रऊफ बुंधुन तथा वर्ष 2008 में मॉरीशस के प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम शामिल हैं।

मॉरीशस के पर्यावरण व राष्ट्रीय विकास एकक के मंत्री श्री लार्मस बुंधु ने अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यपालक समिति के 57वें अधिवेशन तथा अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के 16वें आम अधिवेशन में भाग लेने के लिए 4-11 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह पर्यावरण व वन मंत्री श्री नमोनारायण मीणा आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री कु. शैलेजा, जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम शरण तथा टेरी के महा निदेशक डॉ. आर.के. पचौरी से मुलाकात की।

सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय समर्थन व वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं सुधार संस्थान मंत्री श्री शीलाबाई बापू ने 26 जनवरी- 8 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। मंत्री ने महिला उन्नति केंद्र (मानसी), पुणे का दौरा किया। मंत्री ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ शिष्टाचारी मुलाकात की। प्रधान मंत्री नवीन

चंद्र रामगुलाम को डॉ. डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दी गयी थी तथा मुंबई में शीला बापू ने उनकी ओर से 4 फरवरी, 2009 को यह उपाधि स्वीकार की थी।

मॉरीशस के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मोहम्मद अशरफ अली दुलूल ने नासकोम के आईटीईएस- बीपीओ नेतृत्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रामाणीकरण प्राधिकरण के नियंत्रक तथा मॉरीशस के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के मध्य भारतीय पीकेआई मॉडल के आधार पर मॉरीशस की लोक मुख्य अवस्थापना स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के एक दल ने राष्ट्रीय कंप्यूटर आपदा प्रतिक्रिया दल (सीईआरटीएमयू) स्थापित करने में मॉरीशस के राष्ट्रीय कंप्यूटर बोर्ड की सहायता करने के लिए 27 अप्रैल- 19 मई, 2008 को मॉरीशस की यात्रा की।

मॉरीशस के उप प्रधान मंत्री, वित्त व आर्थिक सशक्तिकरण मंत्री डॉ. रामकृष्ण सिथाने ने 22-24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका परियोजना सहभागिता में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने 23 मार्च, 2009 को विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। डॉ. सिथाने ने मुंबई का दौरा भी किया।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम शरण ने मॉरीशस सरकार को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित भारत की स्थिति का ब्यौरा देने के लिए 20-25 मई, 2008 को मॉरीशस की यात्रा की।

अप्रैल, 2008 में आईएनएस इंवेस्टीगेटर को सेंट ब्रांडन क्षेत्र में जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस के समुद्र में तैनात किया गया था। भारतीय तटरक्षक के महा निदेशक ने 7-10 अप्रैल, 2008 को मॉरीशस की सरकारी यात्रा की। आईएनएस मुंबई व आईएनएस कारमुक ने भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए जाते समय मॉरीशस के यात्रा की। दोनों जहाजों ने मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षक के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी किया। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्कार्डन आईएनएस तीर, आईएनएस कृष्णा तथा सीजीएस विवेक ने 24-28 सितंबर, 2008 को मॉरीशस की यात्रा की। यात्रा के दौरान जहाजों ने मॉरीशस के तटरक्षकों के साथ अभ्यास भी किया। मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षक जहाज ओवजर्वर के कल-पुर्जे मॉरीशस अधिकारियों को सौंपे गए थे। इस यात्रा के साथ वाईस एडमिरल सुनील दामले, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिण कमान ने 23-28 सितंबर, 2008 को मॉरीशस की यात्रा की। नौसेना के उच्च कमान पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों के 33सदस्यीय दल ने 27 अप्रैल- 1 मई, 2008 को मॉरीशस की यात्रा की। एक भारतीय नोसैनिक प्रशिक्षण दल ने 19 मई - 6 जून, 2008 को मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षक के लिए मॉरीशस में जहाज गोताखोरी के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा मेराइन कमांडो पाठ्यक्रम आयोजित किया।

मॉरीशस को आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की आपूर्ति करने के लिए 27 फरवरी, 2009 को भारत-मॉरीशस अंतरसरकारी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मॉरीशस में चावल के अत्यधिक अभाव के कारण भारत सरकार ने निर्यात प्रतिबंध के बावजूद मॉरीशस को 900 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारत व मॉरीशस के कुल द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 1096.11 मिलियन अमरीकी डालर (4,41,301.74 लाख रुपए) था। भारत से मॉरीशस को किए गए निर्यातों का मूल्य 1086.04 मिलियन अमरीकी डालर (437245.95 लाख रु.) तथा मॉरीशस से भारत को किए गए आयातों का मूल्य 10.07 मिलियन अमरीकी डालर (4055.79 लाख रु.) था।

अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि के दौरान मॉरीशस, भारत में एकमात्र सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्रोत था। मॉरीशस से भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल राशि 7 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो कि इस अवधि के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का लगभग 41% है।

जल सर्वेक्षण के संबंध में भारत-मॉरीशस संयुक्त समिति की चौथी बैठक 4-6 फरवरी, 2009 को आयोजित की गयी थी। मॉरीशस पक्ष का नेतृत्व भूमि व आवास मंत्रालय के स्थायी सचिव सुश्री आशा देवी बुरेन चौबे ने किया।

दूरस्थ शिक्षा व दूरस्थ चिकित्सा के लिए 26 फरवरी, 2008 को शुरू की गयी पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का मॉरीशस में भव्य स्वागत किया गया था।

चैन्ने का शंकर नेत्रालय चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठान, मॉरीशस के न्यूसोलेक सरकारी चिकित्सालय में एक नेत्र चिकित्सालय स्थापित कर रहा है। आईटीसी-वेलकम ग्रुप, मॉरीशस में एक 5 सितारा होटल स्थापित करने की योजना बना रहा है। मॉरीशस ब्रिटिश अमरीकन निवेश समूह तथा भारतीय अपोलो समूह की एक संयुक्त परियोजना अपोलो बेम्बल चिकित्सालय वर्ष 2009 से कार्य करना शुरू कर देगा। 27 अगस्त, 2008 को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ मॉरीशस तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल (मॉरीशस) लिमिटेड (एसबीआईआईएमएल) के बीच हुए करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत एसबीआईआईएमएल, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ, मॉरीशस को मंगलौर रिफाइनरी तथा भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड (एमआरपीएल) से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए ऋण प्रदान करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मॉरीशस ने इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक का अधिग्रहण पूरा कर लिया है तथा 27 अक्तूबर, 2008 को एकल निकाय में इसका विलय कर

दिया है। मॉरीशस कृषि विपणन सहकारिता परिसंघ तथा भारत के सेरिस बीजा अनुसंधान समूह ने जुलाई, 2008 में परिसंघ के कृषि उत्पादन तथा तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए भारतीय सेरिस बीजा अनुसंधान समूह से सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड लगभग 135 मिलियन अमरीकी डालर की आय के साथ मॉरीशस की शीर्ष 100 कंपनियों में 16वें स्थान पर पहुंच गयी है। बिनानी सीमेंट ऑफ इंडिया ने 5,00,000 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए मॉरीशस सरकार से एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। फोर्टीस क्लीनिक डारने चिकित्सालय का उद्घाटन 25 मार्च 2009 को किया गया था। फोर्टीस तथा इसके सहभागी सीआईईएल समूह के पास इस अस्पताल में 58% नियंत्रणकारी शेयर है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी); डॉ. डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय तथा एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ ने मॉरीशस में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

सरकार तथा मॉरीशस की जनता ने बिहार में बाढ़ के संबंध में प्रधान मंत्री राहत कोष 1.72 करोड़ रुपए की राशि का योगदान दिया है।

भारत ने मॉरीशस को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक दल भेजना जारी रखा है।

मोजांबिक

इस अवधि के दौरान मोजांबिक के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण बने रहे। दो भारतीय नोसैनिक जहाज- आईएनएस मुंबई तथा आईएनएस कुरमुक ने मई, 2008 में मोजांबिक की यात्रा की। इसके तहत इन्होंने मापुतो बंदरगाह के आमंत्रण पर 20-23 मई, 2008 को बंदरगाह का दौरा किया। आईएनएस कुरमुक ने भारत वापसी के मार्ग में नकाला बंदरगाह का भी दौरा किया। विज्ञान व प्रोद्योगिकी मंत्री प्रो. विनेंसियो मेसिंग उन उच्चस्तरीय आगंतुकों में से एक हैं, जिन्होंने मापुतो बंदरगाह पर जहाज के रुकने की अवधि के दौरान उसका दौरा किया। मोजांबिक नौसेना के तीन कार्मिकों को मापुतो से नकाला तक यात्रा के दौरान आईएनएस कुरमुक में विदेशी प्रशिक्षण दिया गया था।

गोवा सरकार के अनिवासी भारतीय आयुक्त श्री एडवार्डो फुलेरो ने 16-21 मई, 2008 को मोजांबिक की यात्रा की। पीआईओ/एनआरआई के विभिन्न वर्गों के साथ बैठक के अलावा श्री फुलेरो ने मोजांबिक गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति जोखिम विस्सोना मुलाकात की तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. वेनेंसियो मेसिंग से मुलाकात की। श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव (उवर्रक) ने 18-19 सितंबर, 2008 को मापुतो में एक 12सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया उन्होंने मोजांबिक में एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए मोजांबिक सरकार के खनिज संसाधन मंत्री के साथ भी विचार विमर्श किया। मोजांबिक की ओर से आंतरिक मंत्री श्री जोस एंटोनियो पेकिको ने राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में 17-22 जुलाई, 2008 को भारत की यात्रा की तथा राईट्स तथा इरकॉन के मेल से बनी- भारतीय कंपनी रिकोन द्वारा कार्यान्वित की जा रही बेरा रेल परियोजना पर उच्चस्तरीय वार्ता की, और बेरा रेलवे प्रणाली (सेना लाइन) के प्रबंधन तथा पुनर्स्थापन के लिए 25 वर्ष की रियायत प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल से भी मुलाकात की।

कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग (डेयर), आईसीएआर, कृषि मंत्रालय के सचिव डॉ. मंगला राय ने 2-5 दिसंबर, 2008 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शदात्री समूह की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए मापुतो की यात्रा की।

मोजांबिक के ऊर्जा मंत्री श्री सलवाडोर नंबुरेत ने 11-19 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित पेट्रोटेक 2009 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। आगंतुक मंत्री ने माननीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा, माननीय विद्युत मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे तथा माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा से मुलाकात की तथा उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने 19-20 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापर सहभागिता सम्मेलन में भी भाग लिया।

मोजांबिक के विदेश कार्य व सहयोग मंत्री श्री ओल्डिमिरो बलोई ने 18-20 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। उन्होंने 17 फरवरी, 2009 को आयोजित वैज्ञानिक, तकनीकी व आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत-मोजांबिक संयुक्त आयोग के दूसरे सत्र की सह-अध्यक्षता की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री, श्री आनन्द शर्मा ने किया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय निवेश संवर्धन व सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। मोजांबिक के विदेश मंत्री ने भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम हमीद अंसारी तथा विदश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि के साथ उनकी बैठकें भी हुईं।

मोजांबिक के समन्वय व पर्यावरण कार्य मंत्री डॉ. अलसिंहा एंटेमियो डी आवरो ने 5-7 फरवरी, 2009 को दिल्ली सतत् विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने राज्य मंत्री (पर्यावरण) से मुलाकात की।

आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार तथा लोक कार्य व आवास मंत्रालय, मोजांबिक सरकार ने अफ्रीका में सतत् आवास के लिए मापुतो में नव प्रवर्तनकारी निर्माण सामग्री व विर्निर्माण प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रदर्शनी व सम्मेलन आयोजित किया। भारत सरकार की तकनीकी सहायता के रूप में नामपुल्ला व जाम्बेज़िया प्रांत में जल ड्रिलिंग परियोजनाओं के लिए अप्रैल, 2008 में 20 मिलियन अमेरिकी डालर का तीसरा ऋण अनुमोदित किया तथा इस संबंध में एग्जिम बैंक तथा मोजांबिक सरकार के मध्य मापुतो में मई, 2008 में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार ने मोजांबिक में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर का चौथा ऋण भी अनुमोदित कर दिया था। मोजांबिक के इनहाम्बेन, गाजा, जाम्बेनिया व नामपुला प्रांत में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर का 5वां ऋण भी अनुमोदित कर लिया गया है।

भारत सरकार ने वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप के आयोजन को ध्यान में रखते हुए खेलों (फुटबॉल) पर विशेष जोर देते हुए युवा केदं का विकास करने के लिए आईबीएस कोष के तहत मोजांबिक को 333,000 अमरिकी डालर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव किया है, मई, 2008 में भारत ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए मोजांबिक सरकार को 1 करोड़ रु. (256000 अमरिकी डालर अनुमानित) की आकस्मिक सहायता भी प्रदान की गयी है।

भारत तथा मोजांबिक के बीच व्यापारिक संबंधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। भारत मोजांबिक के 8 मुख्य व्यापारिक सहभागियों में से एक हैं। 2006 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 113.591 मिलियन अमेरिकी डालर था। 2007 में इसमें 34% वृद्धि दर्ज हुई और यह बढ़कर 159.28 मिलियन डालर हो गया। यह मुख्य रूप से भारत से मोजांबिक को किए गए निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ, जो कि 2006 में 78.946 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2007 में 135.858 मिलियन अमेरिका डालर हो गया।

कैपेक्सिल, इंडिया के तत्वावधान में एक 11सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 23-26 नवंबर, 2008 को मापुतो की यात्रा की तथा मापुतो में अपने प्रवास के दौरान एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की।

एनटीपीसी से एक प्रतनिधिमंडल ने मोजांबिक में एक कोयले की खन का अधिग्रहण करने तथा थर्मल संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए 16-20 फरवरी, 2009 को मापुतो की यात्रा की। अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा कोयला खानों के निजी स्वामियों से बातचीत की।

मोजांबिक सरकार द्वारा जारी खुली निविदा में भाग लेकर मार्च, 2009 में कोल इंडिया को मोजांबिक के मोफाटिज, टेटे प्रांत में 2 कोयला ब्लॉक मिले थे।

नामीबिया

भारत व नामीबिया के मध्य संबंध उत्कृष्ट है तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जिसकी विशेषताएं दोनों देशों के मध्य सहयोग की सशक्त परंपरा का पारस्परिक मूल्यांकन है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान ये संबंध और मजबूत हुए हैं। नामीबिया ने संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र मंडल तथा अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार समर्थन किया; कई संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया; तथा विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मुख्य रूप से समर्थन देना जारी रखा है। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 26 सितंबर, 2008 को यूएनजीए के सत्र के अवसर पर नामीबिया के राष्ट्रपति पोहावा से मुलाकात की तथा पारंपरिक हित के कई व्यापक शीर्षकों पर सार्थक विचार-विमर्श किया।

वर्ष के दौरान दोनों देशों के मध्य कई उच्चस्तरीय यात्राओं में दोनों देशों के मध्य विद्यमान मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण संबंधों पर फिर से जोर दिया गया है।

श्री जयराम रमेश, राज्य मंत्री (वाणिज्य) ने 26-28 मार्च, 2008 को नामीबिया की यात्रा की। राज्य मंत्री (वाणिज्य) ने नामीबिया के प्रधान मंत्री, श्री नाहज अंगुला व संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सैम नुयोमा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान श्री जयराम रमेश ने खान व ऊर्जा मंत्री एरकी न्हिमतिना, व्यापार व उद्योग मंत्री इमेन्यूल न्गात्यीजेको, लोक कार्य, परिवहन व संचार मंत्री, लोकल कपांदा व विदेश कार्य मंत्री मार्को होसिको से मुलाकात की। यह यात्रा काफी सार्थक थी, जिसके दौरान हीरे, व्यापार व उद्योग, रेलवे, कृषि (वापसी खरीद व्यवस्था सहित नामीबिया में दाले उगाने की योजनाएं), खनन व एसएमई सहित कई प्रकार की पहल की गयी। इस यात्रा के अवसर पर एटीसी वएलएलडी हीरा (पीटीवाई) लि. ने (नामीबिया से) आभूषणों के लिए कच्चे हीरों को संसाधित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

नामीबिया के सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जोयल कपांदा ने 3-6 दिसंबर, 2008 को हैदराबाद में इंटरनेट अभिशासन मंच की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

भारत-नामीबिया संयुक्त राज्य समिति की दूसरी बैठक 18-19 फरवरी, 2008 को वॉलविस की खाड़ी में आयोजित की गयी थी। यह बैठक बहुत ही सार्थक रही तथा इसमें व्यापार व निवेश; सीमा शुल्क सहयोग व राजस्व मामले; नामीबिया सरकार को ऋण; कृषि क्षेत्र, आइटेक/स्काप कार्यक्रम; जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, दूर संचार, खनन गवेषण व विकास; रतन व आभूषण; भंडारण व संभार तंत्र; औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग; ऊर्जा क्षेत्र; परिवहन ढांचा; स्वास्थ्य; फिल्म उद्योग व पर्यटन शामिल है। यह सहमति भी हुई थी कि दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश का संवर्धन करने तथा खनन क्षेत्र में घनिष्ठ गठबंधन विकसित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा व संवर्धन करार तथा खनन करार/ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जेटीसी बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन एक सकारात्मक घटना है, जिसका उद्देश्य नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क केंद्र के साथ भारत के व्यापार व निवेश में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 16सदस्यीय दल ने 11-16 मई, 2008 को नामीबिया की यात्रा की। यह नामीबिया में एनडीसी दल की सर्वप्रथम यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दल ने नामीबिया के राष्ट्रपति श्री के पुलिम पोहाम्बा, नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक राष्ट्रपति व नामीबिया के राष्ट्रपति डॉ. साल नजुमा, प्रधान मंत्री

नाहास अंगुला, रक्षा मंत्री, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) चार्ल्स नामालोह तथा नामीबियाई रक्षा बल के अध्यक्ष ले. जनरल मार्टिन शैली से मुलाकात की।

नामीबिया की ओर से नामीबिया के रक्षा मंत्री श्री चार्ल्स नामोलोह ने 14-19 फरवरी 2008 को 5वीं थल व नौसेना प्रणाली प्रदर्शनी-डेफ एक्सपो इंडिया-2008 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। मंत्री के साथ नामीबिया के नौसेना कमांडर भी थे तथा उन्होंने रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी से मुलाकात की। नामीबिया के लोक कार्य, परिवहन व संचार मंत्री श्री जोयल कपांदा ने 18-25 फरवरी, 2008 को भारत की यात्रा की थी तथा उन्होंने रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की।

नामीबियाई संसद की आर्थिक, प्राकृतिक संसाधन व लोक प्रशासन से संबंधित स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष माननीय पेया मुशि लेंगा की अध्यक्षता में नामीबिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 मई, 2008 को मुंबई में एसएनई वित्तपोषण, बेहतर बैंकिंग विनिमय व एसएमई एकीकरण के सम्मेलन में भाग लिया।

नामीबिया के विदेश मंत्री, मार्की हासिको ने 15-22 जून, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व निर्वाचन सहायता (I - आइडिया) परिषद संस्थान की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की तथा वे सीधे अफ्रीकी संघ में भाग लेने के लिए शर्म-ऐल-शेख चले गए, जहां राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) ने पारस्परिक हित के मामलों पर सार्थक विचार-विमर्श किया।

नामीबिया के उप रक्षा मंत्री, श्री विक्टर सिमुजा ने 11-15 फरवरी, 2009 को बैंगलौर में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस एक्सपोजिशन के संबंध में भारत की यात्रा की।

नामीबिया की प्रथम महिला, मैडम पोहाम्बा द्वारा स्थापित न्यास, मुक्वामलंग तुकोंजेनी समुदाय की कार्यपालक निदेशक सुश्री एंजेलिका, बर्गमान्न तथा फर्डी रुलेन टाईटज (नामीबिया एग्रीभाईन) ने अप्रैल, 2008 में भारत, अफ्रीका मंच सम्मेलन के विस्तारित कार्यक्रम युवा व महिला वार्ता में भाग लिया। नामीबिया के सहभागी भारत में इस अवसर पर उनके विशेष अनुभव व ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित होकर वापस आए तथा उन्होंने नामीबिया में अपने सामाजिक व आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए संदर्भगत मुद्दों के रूप में अपने भारतीय अनुभव का उपयोग करने का निश्चय किया।

द्विपक्षीय, आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि करने के लिए कई उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों ने नामीबिया की यात्रा। मार्च, 2008 में राज्य मंत्री (वाणिज्य) की नामीबिया यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसरण में डायमंड इंडिया लिमिटेड के एक 3सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नामीबिया की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने खनन व ऊर्जा मंत्री श्री एरकनी एन जीमितना, व्यापार व उद्योग मंत्री, डॉ. हेग जिंगॉव व संस्थापक राष्ट्रपति ज. सैम न्यौमा से मुलाकात की। फिर उसी यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एसटीसी/संघ समूह के एक 6सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने एसटीसी तथा एलएलडी डायमंड (प्राइवेट) लिमिटेड, नामीबिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मई, 2008 में नामीबिया की यात्रा की। राईट्स के एक दल ने नामीबिया के लोक कार्य, परिवहन व संचार मंत्री, श्री जोयल कपांडा की भारत यात्रा के अनुसरण में 16-22 अप्रैल, 2008 को नामीबिया की यात्रा की।

वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यीय दल ने 16-17 सितंबर, 2008 को नामीबिया की यात्रा की तथा भारत में नामीबियाई चीते के आयात की संभावनाओं का पता लगाया, यहां के वन्य जीवन में चीता विलुप्त हो चुका है। आईसीसीआर ने नामीबिया के राष्ट्रीय थियेटर, विंडहॉक में 4 नवंबर, 2008 को रंजना गुहार द्वारा ओडिसी नृत्य और डॉ. मुस्तफा राजा ने विचित्र वीणा वादन प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण ने जनता में काफी रुचि व सौहार्द पैदा किया।

रवांडा

रवांडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री कमांजी स्टेनीस्लास ने राज्य मंत्री (पर्यावरण व वन) श्री एस रघुपति के साथ 14—15 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में बांस व रतन के लिए कांउसिल इंटरनेशनल नेटवर्क के छठे सत्र की सह-अध्यक्षता की।

रवांडा के कृषि एवं पशु संसाधन मंत्री श्री क्रिस्टोफी बाज़ीवामो ने 10-12 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका सतत् खाद्य सुरक्षा सहयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की, जिसका आयोजन अप्रैल, 2008 में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन की घोषणाओं व सिफारिशों के अनुसरण में किया गया था।

रवांडा के राष्ट्रपति श्री पाल कगामे ने नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका व्यापार सहभागिता सम्मेलन (19-20 जनवरी) में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 18-23 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। यह सम्मेलन विदेश एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयों की सहायता से फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। इस यात्रा के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने भारत विश्व कार्य परिषद व भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में व्याख्यान भी दिया।

रवांडा के स्वस्थ्य मंत्री डॉ. रिचर्ड सेज़िवेरा ने अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल की 5वीं बैठक के संबंध में 1-4 फरवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। रवांडा के मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमश्र करने के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास से मुलाकात की।

रवांडा गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री स्टानिस्लास कमांजी ने 5-7 फरवरी, 2009 को टेरी द्वारा आयोजित दिल्ली सतत्

विकास सम्मेलन 2009 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

द्विपक्षीय व्यापार 13.58 मिलियन अमरीकी डालर हुआ, जिसमें 12.92 मिलियन अमरीकी डालर का भारतीय निर्यात था।

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वृद्धि की संभावना का पता लगाने के लिए 12-13 नवंबर, 2008 को रवांडा की यात्रा की।

सेशल्स

दो भारतीय नौसेना जहाज- आईएनएस मुंबई तथा आईएनएस कुरमुक ने 1-3 जून, 2008 को सेशल्स की सद्भावना यात्रा की।

दो भारतीय युद्धपोतों- आईएनएस गोदावरी व आईएनएस तलवार ने 2 सितंबर, 2008 को सेशल्स की चार दिवसीय सद्भावना यात्रा की।

पांच सदस्यीय टेलीकॉमिनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड ने पेन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन/स्थापना के लिए 28 सितंबर- 1 अक्तूबर, 2008 सेशल्स की यात्रा की।

श्रीमती परमिता मैत्रा के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय कथक नृत्य मंडली ने 4–6 जुलाई, 2008 तक सेशल्स की यात्रा की।

कैलेंडर वर्ष 2007 के दौरान भारत से निर्यातों का कुल मूल्य 7.63 मिलियन अमरीकी डालर था। निर्यात की कुल मदों में खाद्य व सजीव पशु, पेय पदार्थ, तंबाकू, कच्ची सामग्री, गैर-खाद्य खनिज ईंधन, स्नेहक, पशु व वनस्पति तेल व रासायन शामिल है।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी नए क्षेत्रों तक फैल चुकी है तथा उच्चस्तरीय यात्रा की श्रृंखला तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से इसे और मजबूत बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा परमाणु आपूर्तिकता समूह की बैठकों में भारत के साथ संपूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग में सहायता करने के प्रस्ताव का पूर्ण सक्रिय समर्थन किया है। दोनों देशों के मध्य बहुपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार, विश्व व्यापार संगठन का दोहा दौर तथा विश्वस्तरीय वित्तीय संकट के संबंध में सहयोग सार्थक रहा। दोनों देशों ने सीमा शुल्क सहयोग, एसएनटी राजनयिक व सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजामुक्त यात्रा तथा 2008 के दौरान संस्कृति सहयोग कार्यक्रम के संबंध में नए करारों पर हस्ताक्षर किए।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री थावो मवेकी ने विदेश मंत्री डलामिनी जुमा के साथ 7-9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। जिसके दौरान तशवाने घोषणा 2006 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गयी।

दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति श्री गालिमा मोटलांटी ने 15 अक्तूबर, 2008 को नयी दिल्ली में तीसरे आईबीएसए सम्मेलन में भाग लिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तथा प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की दक्षिण अफ्रीका के कई मंत्रियों ने राष्ट्रपति मोटलांटी के साथ यात्रा की।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने लेटिन अमरीकी देशों की अपनी यात्रा से भारत लौटते समय 24 अप्रैल, 2008 को केपटाउन में एक संक्षिप्त तकनीकी प्रवास किया।

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने सोमरसेट वेस्ट में आयोजित आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रालयीय आयोग की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए 10-11 मई, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उन्होंने 20-22 फरवरी, 2008 को प्रिटोरिया में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीकी संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। विदेश मंत्री ने इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63 वें सत्र के दौरान 29 सितम्बर, 2008 को दक्षिण अफ्रिका के विदेश मंत्री से भेंट की।

पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने 14-17 अगस्त, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की तथा दक्षिण अफ्रीका में अपने समकक्ष श्री पोलो जोर्डन से मुलाकात की। एएनसी के उपाध्यक्ष श्री गालेमा मोटलांटे के साथ उन्होंने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक बहिष्कार आंदोलन, जिसके परिणास्वरूप 1908 में विदेशी वस्तुओं का दहन किया गया था, की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जोहंसबर्ग तक शांति पद यात्रा का नेतृत्व किया। महात्मा गाँधी के शिक्षओं को पुनः अपनाने के उद्देश्य से अन्य कार्यक्रमों में शामिल है – प्रो. कादर आसमल द्वारा एक सार्वजनिक व्याएयान, विटवाटर्सरैंड विश्वविद्यालय में एक संगोष्टी, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की।

श्री आनन्द शर्मा, राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 29–30 जुलाई, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति मवेकी, मुलाकात की। राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) ने जोहंसबर्ग में विटवाटररैंड विश्वविद्याल में अफ्रीका में भारतीय अध्ययन से संबंधित केंद्र का उद्घाटन करने के लिए 15-18 सितंबर 2008 को पुनः दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसा पहला केंद्र है तथा एएनसी के अध्यक्ष श्री जेकब जुमा ने संयुक्त रूप से डरबन में क्वाजलू-नेटल विश्वविद्यालय में गांधी लूथूली चेयर ऑफ पीस स्टडी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती टीचर के नेतृत्व में केरल सरकार के 3सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 नवंबर, 2008 को केपटाउन की यात्रा की।

लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह अटवाल के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केपटाउन में अंतरसंसदीय संघ के 118वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए 13-18 अप्रैल, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की।

कई दक्षिण अफ्रीकी मंत्रियों ने भी भारत की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक विकास मंत्री डॉ. जोला सिडनी थेंवा कविया ने यूनेस्को व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5-6 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशिया के सामाजिक विकास मंत्रियों के मंच की दूसरी मंत्रालयीय बैठक में भाग लेने के लिए 2-8 मार्च, 2008 को भारत की यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका के आवास मंत्री डॉ. लिंडिवे नानसेवा सीसुलु ने शहरी विकास मंत्री के आमंत्रण पर पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 9-13 मार्च, 2008 को भारत की यात्रा की। वे स्लम ड्वेलर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अक्तूबर, 2008 में भारत लौटी। दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा मंत्री ग्रेस नलेडी मंदिसा पंडोर ने 29 जून- 3 जुलाई, 2008 को भारत की यात्रा की तथा अपने भारतीय समकक्ष के साथ मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों, विशेष रूप से तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डा. मानतोमबजाना ने 29-30 जुलाई, 2008 को भारत की यात्रा की तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. अंबुमनि रामदास के साथ विचार-विमर्श किया। दक्षिण अफ्रीका के एक स्वास्थ्य प्रतिनिधिमंडल ने फार्मासिस्टों की तैनाती पर विचार करने के लिए भारत की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका के लोकसेवा व प्रशासन मंत्री सुश्री जी.जे. फ्रेजर मोलिकेटी ने 9-17 अगस्त, 2008 को भारत की यात्रा की।

डॉ. जेकोब जुमा, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) के अध्यक्ष कई एएनसी कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ 8-12 जून, 2008 तक भारत की यात्रा की, जबकि एएनसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ. जेकोब जुमा और प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों व मंत्रालयीय यात्राओं के अलावा कई उच्चस्तरीय अधिकारियों की यात्राएं भी हुईं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका में नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी द्वारा एक एल्यूमीनियम स्मेल्टर स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए सचिव, खान 11-16 फरवरी, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, दक्षिण अफ्रीका के व्यापार व उद्योग विभाग द्वारा 31 जुलाई- 2 अगस्त, 2008 को आयोजित वार्षिक लघु व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री की यात्रा, त्रिपक्षीय आईबीएसए में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए 6-7 अगस्त, 2008 को सचिव, नागरिक उड्डयन की यात्रा के साथ-साथ तंबाकू नियंत्रण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन संरचना सम्मेलन के तीसरे दलीय सम्मेलन अभिसमय में भाग लेने के लिए नवंबर, 2008 को स्वास्थ्य, सचिव की डरबन यात्रा और केपटाउन और जोहान्सबर्ग में वस्त्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी की 19–24 मार्च, 2009 की यात्रा शामिल है।

रक्षा क्षेत्र दोनों देशों के मध्य सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। संयुक्त रक्षा समिति की छठीं बैठक 13-14 मार्च, 2008 को आयोजित की गयी थी। इस बैठक में सैनिक अभ्यास में प्रेक्षकों के आदान-प्रदान, भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दक्षिण अफ्रीका की सहभागिता, प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा, वरिष्ठ स्तरीय सैनिक पाठ्यक्रमों का आदान-प्रदान तथा खेल-कूद व साहसिक गतिविधियों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। दो भारतीय नौसैनिक जहाजों, आईएनएस- मुंबई तथा आईएनएस-कुरमुक ने साइमस टाउन में मई, 2008 में प्रारंभिक त्रिपक्षीय आईबीएसए नौसैनिक अभ्यास, आईबीएसएएमएआर- 1 में भाग लिया। जहाजों ने डरबन तक सद्भावना यात्रा भी की। रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने केपटाउन में अफ्रीका-ऐरास्पेस एंड डिफेंस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सितंबर, 2008 में भारत की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के उप रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने दक्षिण अफ्रीका के थल सेना अध्यक्ष के आमंत्रण पर 24-27 नवंबर, 2008 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत के थल सेना अध्यक्ष ने सेना के आपसी सहयोग पर विस्तृत विचार-विमर्श भी किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की।

वर्ष 2006-07 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 4.7 बिलियन अमरीकी डालर हुआ, जो कि 2007-08 में 33% बढ़कर 6.27 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। दक्षिण अफ्रीका का भारत द्वारा कुल मूल्य 2.65 बिलियन अमरीकी डालर निर्यात हुआ तथा आयात 3.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

भारत ने अपने वाणिज्यिक आदान-प्रदान में और वृद्धि करने के लिए अफ्रीका की 10वीं वार्षिक ऊर्जा व विद्युत कांग्रेस, कंप्यूटर मेला 2008, अफ्रीकी रेल सम्मेलन व प्रदर्शनी, अफ्रीका विग 7 तथा जोहंसबर्ग इंटरनेशनल मोटर शो सहित कई क्षेत्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। सीईआईआई के सहयोग से जोहंसबर्ग में 23 सितंबर, 2008 को भारतीय सम्मेलन के साथ एक मुख्य व्यापार समारोह आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य सहभागियों को भारतीय अर्थव्यवस्था के पर्यावलोकन सहित भारत के व्यापार संचालन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना था। सम्मेलन की सफलता से सीआईआई इसे एक वार्षिक समारोह बनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय स्थापित करने वाली भारतीय कंपनियों को एक मंच प्रदान करने के लिए मई, 2007 में शुरू भारतीय व्यापार मंच की सफलता से प्रेरित होकर मुंबई में एक दक्षिण अफ्रीका व्यापार मंच शुरू किया गया। इससे भारत में व्यापार स्थापित करने वाली दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों के अध्यक्षों को एक मंच पर लाया जा सकेगा। हाल ही में स्थापित कोयला व हाइड्रो-कार्बन से संबंधित भारत-दक्षिण अफ्रीका कार्यचालन

समूह ने 29-30 जुलाई, 2008 को दिल्ली में अपनी पहली बैठक की। इसके अलावा अप्रैल, 2008 में एईपीसी से कई प्रतिनिधिमंडलों ने कपड़ा उद्योग का संवर्धन करने के लिए यात्राएं की, जिनमें अगस्त, 2008 में एसोचेम, नवंबर, 2008 में विद्युत विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में आईईईएमए तथा नवंबर, 2009 में सक्षम गुजरात को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात निवेश निगम के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा शामिल है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कंपनियों द्वारा लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाएं कार्यान्वित करने के अनुमान के साथ ही द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि होती रही।

अफ्रीका में प्रथम "इंडिया फोकस" केंद्र, विटवाटस्रैंड विश्वविद्यालय में सितंबर, 2008 को अफ्रीका में भारतीय अध्ययन तथा क्वाजलू नेटल विश्वविद्यालय में लथोली चेयर ऑफ पीस स्टडी के शुरू होने के साथ ही दोनों देशों के मध्य शैक्षिक संपर्क में काफी तेजी आयी है। दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय से कई कुलपतियों ने अपने समकक्ष संस्थानों के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत की यात्रा की, इनमें प्रिटोरिया, जोहंसबर्ग, उत्तर-पश्चिम विटवाटरसैंड और स्टेनली वॉक विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल है। स्टेनली वॉक विश्वविद्यलाय ने 28 अगस्त, 2008 को भारत की एक शाम आयोजित की। पश्चिम के विश्वविद्यालय ने भी 14 नवंबर, 2008 को भारत की एक शाम की मेजबानी की जिसके दौरान महात्मा गांधी के एक प्रतिमा तथा भारत से संबंधित पुस्तकें विश्वविद्यालय को उपहार में दी गयी।

अगस्त, 2008 में पर्यटन व संस्कृति मंत्री, श्रीमती अंबिका सोनी की यात्रा के दौरान भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच कला व संस्कृति के क्षेत्र में एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रत्यायोजित कई सांस्कृतिक दलों ने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों की यात्रा की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता है- टीम वर्क प्रोडक्शन द्वारा सरकारी-गैर सरकारी सहभागिता के रूप में आयोजित साझा इतिहास कार्यक्रम जिसके द्वितीय संस्करण अगस्त-अक्तूबर, 2008 में भारतीय साहित्य, नृत्य, थियेटर, संगीत, कला, खानपान, सिनेमा तथा कपड़ा भी शामिल है। भारत ने सितंबर, 2008 में प्रिटोरिया में शवाने शहर में आयोजित कैपिटल आर्ट फेस्टिबल के प्रारंभिक सत्र में भाग लिया था।

स्वाजीलैंड

इस अवधि में स्वाजीलैंड साम्राज्य के साथ भारत के संबंधों में भी विकास हुआ है। स्वाजीलैंड में 4 हॉल-इन-द-वाल शिक्षण केंद्रों को स्थापित करने के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार पर मोजांबिक में भारत के उच्चायुक्त, जिन्हें कि स्वाजीलैंड साम्राज्य का कार्यभार भी दिया गया है तथा स्वाजीलैंड के उद्यम व रोजगार मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। हॉल-इन-द-वॉल परियोजना पूरी की जा चुकी है तथा स्वाजीलैंड के उप प्रधान मंत्री ने 2 मार्च, 2009 को इसका उद्घाटन किया था। मोजांबिक में भारत के उच्चायुक्त, जिन्हें स्वाजीलैंड का कार्यभार भी दिया गया है, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे।

वाणिज्य, उद्योग व व्यापार मंत्री सुश्री जाबुली माशवामा ने 19-20 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार सहभागिता सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वाजीलैंड के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

स्वाजीलैंड साम्राज्य के प्राकृतिक संसाधन व ऊर्जा मंत्री, शाही राजकुमारी शैंजिल डालमिनी सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय पेस्टर नेलीसीवे ने 22-24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय-अफ्रीकी परियोजना सहभागिता में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

तंजानिया

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत तथा तंजानिया के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे।

अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया म्रिसो किकवेते के चुनाव के बाद उन्हें नई दिल्ली में 8-9 अप्रैल, 2008 को आयोजित भारत-अफ्रीकी मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपित जकाया किकवेते ने इस शिखर सम्मेलन की प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ सहध्यक्षता की।

राष्ट्रपति किकवेते ने भारत और तंजानिया के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी तकनीकी सहयोग तथा मानव संसाधन विकास जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। भारत ने तंजानिया को कृषि उपस्करों की खरीद के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया।

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 27-29 अगस्त, 2008 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता के 10वें क्षेत्रीय कंक्लेव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में दार-ए-सलाम की यात्रा की। तंजानिया के उद्योग व्यापार व विपरण मंत्री श्री मेरी नागू ने इस समारोह की सह-अध्यक्षता की थी। यात्रा के दौरान श्री वर्मा ने तंजानिया के विदेश कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उप मंत्री श्री शेफ अली इदी से विचार-विमर्श भी किया। उन्होंने 28 अगस्त, 2008 को भारतीय उच्चायोग के चांसरी एवं आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी।

तंजानिया के प्राकृतिक संसाधन व पर्यटन मंत्री श्री श्याम सेलिंगिया बांगूगा के साथ तंजानिया पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन क्षेत्र के

व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने 17-24 जून, 2008 को भारत की यात्रा की थी। श्री बांगूगा ने पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी से मुलाकात की तथा तंजानिया में श्रम शक्ति प्रशिक्षण तथा आतिथ्य क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत की सहायता की मांग की।

तंजानिया के अवस्थापना विकास मंत्री श्री शुकरु कवांवा ने रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के आमंत्रण पर सितंबर, 2008 में भारत की यात्रा की। बैठक के दौरान उन्होंने तंजानियाई रेलवे लिमिटेड के लिए भारत सरकार से ऋण का अनुरोध किया, जिसमें राईट्स की अधिसंख्या शेयर धारिता है। रेलवे मंत्री ने तंजानिया के मंत्री को यह आश्वासन दिया कि अनुरोध पर विचार किया जाएगा तथा तंजानिया में रेलवे प्रचालन व प्रबंधन में सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख किया।

तंजानिया के लोक सेवा प्रबंध राज्य मंत्री श्रीमती हावा ए. घसिया ने 6सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा सामान्य व रोजगार प्रबंधन में भारत सरकार के निष्पादन का अध्ययन व शिक्षण करने के लिए भारत का अध्ययन दौरा किया।

आईसीटी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सी-डेक से 6 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने 11-24 दिसंबर, 2008 को तंजानिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इस दल ने दार-ए-सलाम में एक आईसीटी केंद्र तथा पूरे तंजानिया में 10 अन्य केंद्रों की पहचान पूरी कर ली थी। भारत में सी-डेक द्वारा तंजानिया के 10 विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी।

तंजानिया के कृषि खाद्य सुरक्षा तथा सहकारिता मंत्री श्री स्टीफन मस्तु वासिरा ने अप्रैल, 2008 में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन की सिफारिशों तथा घोषणाओं के अनुसार 10-12 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका सतत् खाद्य सुरक्षा सहयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

भारत-तंजानिया आर्थिक तकनीकी व वैज्ञानिक सहयोग से संबंधित संयुक्त आयोग का 7वां सत्र 13-14 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव श्री नलिन सूरी तथा तंजानिया पक्ष का नेतृत्व स्वास्थ्य व समाज कल्याण मंत्री प्रो. डेविड एच. वाक्यूसा, संसद सदस्य द्वारा किया गया था। विदेश कार्य व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उप मंत्री श्री शेफ अली इदी भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। बैठक के बाद हुई सहमति के अनुसार कार्यवृत्त में कृषि, लघु व मध्यम उद्योग, व्यापार व उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गयी। लघु व दीर्घावधिक तकनीकी प्रशिक्षण व स्नातक पाठ्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

तंजानिया के ऊर्जा व खनिज मंत्री श्री विलयम म्गांगा गेलीज़ा ने एस्टनोफिल्ड नवीकरणीय संसाधान लिमिटेड के आमंत्रण पर नवीकरणीय ऊर्जा (सौर शक्ति) की बैठक में भाग लेने के लिए 6-8 मार्च, 2009 को भारत की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान तंजानिया के मंत्री ने खान मंत्री श्री शीशराम ओला से शिष्टाचार मुलाकात की तथा द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

आईसीसीआर के प्रयोजन से सुश्री रंजना गोहार, ओडिसी तथा मुस्तफा रजा, विचित्र वीणा के संयुक्त समूह ने 18-24 अक्तूबर, 2008 को तंजानिया की यात्रा की तथा दार-ए-सलाम में चार कार्यक्रम तथा जंजीबार में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

जून-अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरा भारत तथा तंजानिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 852 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें भारत के द्वारा निर्यात- 709 अमरीकी डालर का निर्यात तथा तंजानिया से भारत का- 143 मिलियन अमरीकी डालर का आयात हुआ था (स्रोतः तंजानिया राजस्व प्राधिकरण)। भारत के निर्यात की मुख्य मदें थीं- भेषज, परिवहन उपस्कर, विद्युत मशीनरी, विनिर्माण सामग्री/मशीनरी, कपड़ा व वस्त्र, आईसीटी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर इत्यादि।

बैंक ऑफ इंडिया ने जून, 2008 में तंजानिया में पुनः अपने प्रचालन शुरू किए। एयर इंडिया दार-ए-सलाम तथा मुंबई के मध्य सप्ताह में तीन बार उड़ानें संचालित करता है। कीनीडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में तंज-इंडिया एश्योरेंश कंपनी के मुख्य प्रवर्तन भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंशोरेंश कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंशोरेंश कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंश कंपनी लिमिटेड हैं। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी दार-ए-सलाम में है। टाटा ने उत्तर-पश्चिम तंजानिया में लेक नेटरन सोडा ऐश निष्कर्षण की सुविधा स्थापित करने के लिए नेशनल डैवलेंपमेंट कार्पोरेशन ऑफ तंजानिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास उत्तर केंद्र तंजानिया में जेगा, इबुंगू में भावी रियायत प्राप्त है। तंजानिया रेलवे को लोकोमोटिव पट्टे पर देने के लिए राईट्स का एक लघु परियोजना कार्यालय ताबोरा में है। मार्च, 2006 में राईट्स को 25 वर्षों के लिए तंजानियाई रेलवे निगम का संचालन करने के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की रियायत प्रदान की गयी थी। रिलाइंस उद्योग लिमिटेड ने गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कार्पोरेशन के अधिसंख्य शेयर तथा प्रबंध नियंत्रण प्राप्त किया है, जिसका मुख्यालय मॉरीशस में है तथा अधोगामी पेट्रोलियम क्षेत्र में पूर्व अफ्रीका में इसका महत्वपूर्ण अस्तित्व है।

उगांडा

भारत के उगांडा के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबध रहे। अप्रैल, 2008 में राष्ट्रपति योबेरी कगूता मुसवेनी ने भारत

की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने पूर्व अफ्रीकी समुदाय के अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद 10 अप्रैल, 2008 को उन्होंने राजकीय यात्रा की। उनके साथ विदेश मंत्री श्री सामकुटेसा तथा वित्त नियोजन व आर्थिक विकास (निवेश) राज्य मंत्री, श्री समाकुला किवानुका भी थे।

राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मूसेविनी ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल से मुलाकात की, जिन्होंने राष्ट्रपति मूसेविनी के सम्मान में एक भोज आयोजित किया। राष्ट्रपति मूसेविनी ने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी बातचीत की। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति मूसेविनी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया, जिसमें कृषि प्रसंस्करण, रेलवे, ऊर्जा, खनन, लघु व मध्यम उद्यम तथा रक्षा शामिल हैं। उन्होंने एक द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा एवं संवर्धन करार पर हस्ताक्षर करने के संबंध में बातचीत की। अपने भोज अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मूसेविनी ने उगांडा की अर्थव्यवस्था में भारत के प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधान मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने उगांडा के आर्थिक विकास में भारत की अधिक से अधिक भूमिका की मांग की। जिस पर भारतीय पक्ष की ओर से सकारात्मक जवाब दिया गया। निवेश क्षमता निर्माण व बाजार तक पहुंच के रूप में कई क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें भारतीय पक्ष उगांडा की सहायता करने के लिए सहमत है। इस यात्रा में आगामी कुछ वर्षों के दौरान दोनों देशों के मध्य सहयोग का एक खाका प्रस्तुत किया गया तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता की गयी।

न्याय व संवैधानिक कार्य राज्य मंत्री, उप महान्यायवादी श्री फ्रैडरिक रुहिंडी ने एक अध्ययन दौरे के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत की यात्रा की। उगांडा के न्याय एवं संवैधानिक कार्य राज्य मंत्री ने उद्योग राज्य मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार, वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश तथा विधि व न्याय राज्य मंत्री श्री के. वेंकटपति से मुलाकात की तथा पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

उगांडा के मत्स्य पालन मंत्री श्री फ्रैड मुकिसा ने अप्रैल, 2008 में आयोजित भारत अफ्रीका सम्मेलन की सिफारिशों तथा घोषणाओं के अनुसार 10-12 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित सतत् खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत-अफ्रीका सहयोग के संबध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

वर्ष 2008-08 के दौरान 168.76 मिलियन अमरीकी डालर द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें 50% वृद्धि हुई। भारत से उगांडा को किए गए निर्यात की राशि 153.64 अमरीकी डालर थी तथा उगांडा से किए गए आयात की राशि 15.12 मिलियन अमरीकी डालर थी।

एसोचेम से एक 12सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27-31 मई, 2008 को उगांडा की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने उगांडा के नियोजन व निवेश राज्य मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, आर्थिक परिवीक्षण मंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक प्रशासन राज्य मंत्री तथा उगांडा के व्यापार समुदाय के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17-18 नवंबर, 2008 को उगांडा की यात्रा की, उनके साथ एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें कई भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक शामिल थे। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उगांडा की कई कंपनियों से बातचीत की।

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8-11 नवंबर, 2008 को उगांडा की यात्रा की।

उगांडा के उप राष्ट्रपति प्रो. गिलवर्ट वी. बुकेनिया ने 12-20 जनवरी, 2009 को गुजरात की गैर-सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 11-14 जनवरी, 2009 को सक्षम गुजरात विश्वस्तरीय निवेशक सम्मेलन 2009 में भी भाग लिया। उगांडा के प्रतिनिधिमंडल में वित्त नियोजन व आर्थिक विकास राज्य मंत्री प्रो. सेमाकुला कीबानुका, उद्योग व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्रो. इफरान कामंतु तथा स्थानीय सकरार के राज्य मंत्री श्री होप विजागे शामिल थे।

उगांडा के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हेम मुलिरा ने 19-20 जनवरी, 2009 तक फिक्की द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका व्यावसायिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

उगांडा के राष्ट्रपति कार्यालय के आर्थिक अनुवीक्षण राज्य मंत्री मॉरिस पी. कागीमु किवानुका अध्ययन दौरे पर 18-20 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होनें केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कांतिलाला भूरिया और भारत के योजना आयोग के सदस्य श्री अनवर उल होदा से मुलाकात की। उन्होंने फिक्की के एक कार्यक्रम में भी शिरकत की।

उगांडा के निवेश राज्य मंत्री श्री एस्टन कजारा, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री गगावाला वम्बुजी और वहां की वित्त राज्य मंत्री सुश्री रूथ ननकाबिखा ने भारत की यात्रा की और नई दिल्ली में 22-24 मार्च, 2009 तक आयोजित भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी, 2009 में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान इन तीनों मंत्रियो ने विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा से भेंट की और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

जाम्बिया

भारत और जिम्बाव्बे की बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर प्रगाढ़ होते रहे। जांबिया के वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री फेलिक्स सी.

7 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया किकवेते के साथ मुलाकात करते हुए।

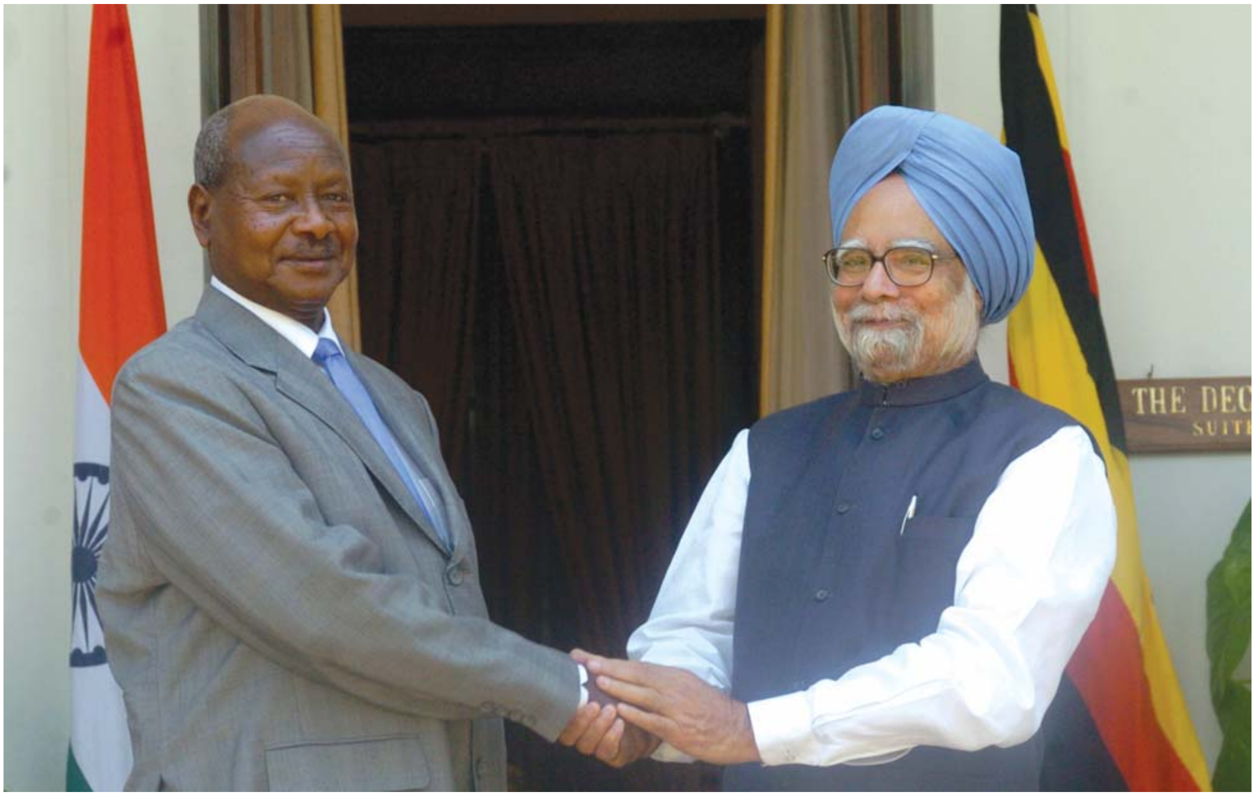

10 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुता मुसेविनी के साथ मुलाकात करते हुए।

मुटाटी ने नई दिल्ली में 19-21 मार्च, 2008 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका कान्क्लेव में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। वहां के विदेश मंत्री श्री कबिंगा जे. पांडे, स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रिआन चितुवो, शिक्षा मंत्री श्री जियोफ्रे लुंग्वांग्वा के साथ वहां के तत्कालीन उप राष्ट्रपति श्री रूपियाह बेजानी बांदा और अन्य सरकारी अधिकारियों ने दिल्ली में 8-9 अप्रैल, 2008 तक आयोजित भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

भारत द्वारा जाम्बिया के उप-राष्ट्रपति श्री रूपियाह बेजानी बांदा को बाढ़ सहायता के लिए 250,689 अमरीकी डालर (1करोड़ रू) का एक चेक 14 मई, 2008 को सौंपा गया। जाम्बिया द्वारा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्णतः उपभोग किया जा रहा है। अप्रैल, 2008 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के पश्चात जांबिया को आबंटित आइटेक असैनिक प्रशिक्षण स्लाटों की संख्या को वर्ष 2008-09 में बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। भारत ने इटेझी-तेझी पनबिजली परियोजना के लिए जाम्बिया को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र की पेशकश की है।

ओडिसी नृत्यांगना रंजना गौहर तथा शास्त्रीय संगीत के कलाकार डा. मुस्तफा रज़ा के नेतृत्व में एक ग्यारह सदस्यीय नृत्य एवं संगीत मंडली ने लुसाका में 2 नवंबर, 2008 को प्रदर्शन किया जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई।

भारत सरकार के वित्त पोषण से लुसाका के दो स्कूलों प्रत्येक में एक-एक कम्प्यूटर शिक्षण कियोस्क के साथ 12 दिसम्बर, 2008 को दो होल-इन-दी-वॉल परियोजना का उद्घाटन किया गया।

नई दिल्ली में 19-20 जनवरी, 2009 तक आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाम्बिया के स्वास्थ्य उपमंत्री महामहिम श्री मेंडोई अकाकंडेलवा एमपी ने भारत की यात्रा की।

जिम्बाब्वे

भारत-जिम्बाब्वे लघु एवं मध्यम श्रेणी की उद्यम परियोजनाओं की शुरूआत 4 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति मुगाबे द्वारा किया गया जिसका कि भारत सरकार के 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान द्वारा वित्तपोषण किया गया। इस परियोजना से जिम्बाब्वे के लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के विकास में सहायता मिलेगी और जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को बदलने में उनके प्रयासों में काफी सहायता मिलेगी।

वर्ष 2008-09 के लिए जिम्बाब्वे को आवंटित आइटेक स्लॉटों को 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया। स्लाटों की उपयोगिता के आधार पर हाल ही में स्लाटों की संख्या को और बढ़ाकर 65 कर दिया गया है।

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान 27 मार्च-8 अप्रैल, 2008 तक महिला एवं युवाओं के आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिम्बाब्वे के तीन प्रतिनिधियों ने भारत की यात्रा की।

जिम्बाब्वे के गृहमंत्री श्री के.सी.डी मोहादी के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मेसर्स ईगल प्रैस प्रा.लि. के संयंत्र एवं उत्पादन की सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए 29 दिसम्बर, 2008 से 3 जनवरी, 2009 तक चेन्नई की यात्रा की।

जानुपीएफ के विदेश सचिव और जिम्बाब्वे के संसद के भूतपूर्व उपाध्यक्ष (स्पीकर) श्री के.एम. कांगाई के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि वहां के उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ओ.एस. मोफु भी शामिल थे, ने जिम्बाब्वे में हीरे के पालिशिंग प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सूरत, भारत की 2-5 जनवरी, 2009 तक यात्रा की।

जिम्बाब्वे गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्रीमती प्रिससिला मिसीहैराब्वी - मुशोंडा ने "भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी कान्क्लेव पर 5वें सीआईआई एक्जिम बैंक कान्क्लेवः 22-24 मार्च, 2009" में भाग लेने के लिए 23-25 मार्च, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों सहित विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा के साथ विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की।

भा.सां.सं.परि. द्वारा प्रायोजित एक 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य मंडली "पनघट" ने 22-31 अक्तूबर, 2008 तक जिम्बाब्वे की यात्रा की। इस मंडली की हरारे, क्वेक्वे और बुलावायो में हुए प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में दर्शक आए और अपने प्रदर्शन के लिए इन्हें काफी सराहना मिली। भारत ने हरारे में 5-14 सितम्बर, 2008 तक आयोजित जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 11वें सत्र में भाग लिया। भारत ने "इनटीचिंग वुमैन" विषय पर 21-29 नवम्बर 2008 तक हरारे में महिलाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इमेजेस फिल्म महोत्सव में भी भाग लिया जिसमें महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए एक भारतीय प्रविष्टि "दातु" (कन्नड़) को पुरस्कार मिला।

अफ्रीका क्षमता निर्माण प्रतिष्ठान (ए.सी.बी.एफ.)

भारत ने हरारे स्थित अफ्रीका क्षमता निर्माण प्रतिष्ठान की बैठकों में भाग लेना जारी रखा। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि अफ्रीका के सतत विकास और गरीबी उन्मूलन की एक प्रमुख संस्था एसीबीएफ का एक पूर्ण सदस्य बना।

अफ्रीकी संघ

भारत-अफ्रीका मंच के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) श्री आनंद शर्मा ने जून 2008 में शरम-अल-शेख, मिस्र में आयोजित ए.यू. शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और

ए.यू.सी. के अध्यक्ष और सदस्य राज्यों के विभिन्न मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। ए.यू.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27-28 नवंबर, 2008 को आदिस अबाबा में विचार विमर्श किया गया जिसमें भारत अफ्रीका कार्य योजना के तहत प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क की संचालन समिति की 5वीं बैठक 1-2 दिसंबर, 2008 को आदिस-अबाबा में संपन्न हुई। टीसीआईएल के साथ अभी तक 32 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और 31 मार्च, 2009 तक परियोजना 12 देशों में प्रकार्यात्मक हो जाएगी। नेटवर्क का केन्द्र बिन्दु जो कि डकर में है पहले से ही प्रकार्यात्मक है और इथियोपिया में प्रायोगिक परियोजना पहले से ही कार्य कर रहा है।

पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (सी.ओ.एम.ई.एस.ए.)

कोमेसा के एक उच्च शक्तिप्राप्त प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 2008 में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच के शिखर बैठक में भाग लिया। कोमेसा के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की अक्तूबर, 2006 में हुई नई दिल्ली की यात्रा के दौरान जारी विज्ञप्ति पर इस अवधि के दौरान प्रगति दिखी। भारत के एक ऊर्जा विशेषज्ञ ने प्रतिनियुक्ति पर 1 जुलाई, 2008 कोक कोमेसा सचिवालय, लुसाका में कार्यभार ग्रहण किया।

पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ई.ए.सी.)

ई.ए.सी. के महासचिव राजदूत जुमा वी. म्वापाचु ने विदेश मंत्रालय क आमंत्रण पर अप्रैल, 2008 में भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लिया। इसके पश्चात समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ई.ए.सी. सचिवालय में जुलाई, 2008 में आरूषा में एक बैठक आयोजित की गई। राजइत म्वापाचु ने नई दिल्ली में 22–24 मार्च, 2009 तक आयोतिज पांचवें भारत–अफ्रिका परियोजना सहभागिता पर सीआई आई – एक्जिम बैंक कान्क्लेव में भी भाग लिया।

एस.ए.सी.यू.

भारत और दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन (एस.ए.सी.यू.) के बीच अधिमानतः व्यापार करार (पी.टी.ए.) के लिए बातचीत में इस अवधि के दौरान प्रगति हुई। भारत-एसएसीयू पीटीए बातचीत का दूसरा दौर वाल्वीस बे में 21-22 फरवरी, 2008 को संपन्न हुआ। बातचीत सफल रही और भारत-एसएसीयूपीटीए संपन्न होने की दिशा में काफी प्रगति हुई।

भारत और एसएसीयू के बीच पीटीए के लिए वार्ता का तीसरा दौर 25-27 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पीटीए पर समझौता ज्ञापन जिसे कि वार्ता के दूसरे दौर के दौरान दोनों पक्षों द्वारा सहमति के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था पर कि वाणिज्य सचिव श्री जे.के. पिल्लै और लिसोथो सरकार के व्यापार एवं उद्योग, सहकारी एवं विपणन सहायक मंत्री श्री खोतसो मातला की उपस्थिति में 26 नवंबर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए। लिसोथो वर्तमान में एसएसीयू का अध्यक्ष है।

दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एस.ए.डी.सी.)- भारत मंच

भारत-एसएडीसी मंच की अप्रैल, 2006 में विंडहोक में हुए बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक चार सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने एसएडीसी सचिवालय का दौरा किया। कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित 11 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं का चयन किया गया।

पश्चिम अफ्रीका

वर्ष के दौरान अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित अब तक का पहला भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक की मेजबानी और शिखर बैठक में नेताओं द्वारा घोषित पहलों के कारण 25 पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों में काफी प्रगति हुई। यह क्षेत्र खनिज एवं धातु तथा हाइड्रोकार्बन से भरा पूरा है। इनके उत्खनन में भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग और समग्र विकास की नीति के भाग के रूप में इस क्षेत्र में भारत सरकार ने शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्र में मानवशक्ति दक्षता को समुन्नत बनाने का प्रयास किया है। संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के प्रति भारत द्वारा दी जा रही महत्ता माली और नाइजर में आवासी मिशनों को खोलने से प्रदर्शित होता है। गाबोन ने नई दिल्ली में अपना आवासी मिशन खोला है और गांबिया ने भी अपना आवासी मिशन खोलने की इच्छा जाहिर की है। भारत सरकार ने इन देशों के लिए आइटेक स्लाटों की संख्या 279 से बढ़ाकर 575 कर दी है जबकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से छात्रवृत्तियों की संख्या 21 से बढ़ाकर 66 कर दी है।

अंगोला

भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में अंगोला का प्रतिनिधित्व वहां के उद्योग उपमंत्री ने किया। वाणिज्य विदेश राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने मार्च, 2008 में अंगोला का दौरा किया और भूगर्भशास्त्र, खनन एवं पैट्रोलियम तथा विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2007-08 में दुगना होकर लगभग 1200 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। आइटेक स्लाटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है।

बेनिन

बेनिन गणराज्य के राष्ट्रपति डा. बोनी यायी 34 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में 3-7 मार्च, 2009 तक पांच दिवसीय यात्रा पर भारत आए जो कि बेनिन के राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी।

भारतीय पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा

बेनिन पक्ष की ओर से राष्ट्रपति डा. बोनी यायी के नेतृत्व में पूर्ण चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूचि के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मसलों पर पूरे विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने 2 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के अलावा 15 मिलियन अमरीकी डालर तक की रियायती ऋण-पत्र देने की पेशकश की।

यात्रा के दौरान 5 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जो कि संयुक्त आयोग का गठन, विदेश कार्यालय परामर्शों और बेनिन में उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा क्षमता-निर्माण और एसएसआई सेक्टर में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से संबंधित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रति भारत की दावेदारी तथा वर्ष 2011-12 में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन देने के बेनिन ने बात दोहराई। बेनिन ने मुम्बई पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की भी दृढ़ता से निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की महाविपत्ति का मुकाबला करने में भारत के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतीज्ञा की।

बुर्किना फासो

प्रधानमंत्री टर्सियस जोंगो ने नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए वर्ष 2008 में भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय रूचि के मामलों पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ विचार-विमर्श किया। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए भारत सरकार ने 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र की पेशकश की। जून, 2008 में भारत सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 80,000 अमरीकी डालर मूल्य की दवाइयों का एक खेप भेजा।

कैमरून

विदेश कार्यालय परामर्श सितम्बर, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोनों पक्ष एक संयुक्त आयोग स्थापित करने पर सहमत हुए। भारत कैमरून में सूचना प्रौद्योगिकी का एक उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हुआ। भारत सरकार ने कृषि-प्रसंस्करण उत्पादों के लिए 38 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र देने की पेशकश की है। आइटेक स्लाटों को बढ़ाकर 15 कर दिया गया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

अगस्त, 2008 में भारत सरकार ने - (क) एक आधुनिक ड्राई प्रोसेस सीमेंट संयंत्र 400 टीपीडी क्षमता वाला (24 मिलियन अमरीकी डालर) और (ख) आंतरिक परिवहन के लिए 100 बसों की खरीद के लिए (5.5 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए 29.5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण-पत्र प्रदान करने की मंजूरी दी। भारतीय एक्जिम बैंक, डकर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सरकार के बीच अक्तूबर, 2008 में उपर्युक्त राशि के संवितरण के एक करार पर बांगुई में हस्ताक्षर किए गए।

चाड

भारत सरकार ने टीम- 9 पहल के अंतर्गत 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र प्रदान की तथा साइकिल संयंत्र स्थापित करने की परियोजना, कृषि उपकरण संयंत्र, लौह बिलेट संयंत्र तथा रोलिंग मिल संयंत्र, सूती धागा संयंत्र कार्यान्वयानाधीन है।

कोट-डी-आइवरी

(i) महात्मा गांधी आई टी एवं बीटी पार्क (20 मिलियन डालर) (ii) मत्स्य पालन प्रसंस्करण संयंत्र (4 मिलियन अमरीकी डालर) और (iii) नारियल रेशा प्रसंस्करण संयंत्र (1.5 मिलियन अमरीकी डालर) की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु कोट-डी-आइवरी की सरकार को 25.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र प्रदान करने से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में और प्रगति देखने को मिली। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं संवर्धन केन्द्र (सीडीटी) स्थापित करने की एक परियोजना पूरी हो गई है और इसका उद्घाटन जनवरी, 2009 में होना निश्चित है। आइवरी के उद्योग एवं निजी क्षेत्र संवर्धन मंत्री ने दिल्ली में 18-21 मार्च, 2008 तक आयोजित सीआईआई-एक्जिम बैंक भारत अफ्रीका परियोजना सहभागिता कानक्लेव में भाग लिया। कोट-डी-आइवरी के लिए आइटेक स्लाटों की संख्या को बढ़ाकर 45 कर दिया गया है।

कांगो जनवादी गणराज्य

प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति जोसेफ कबीला अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भी भाग लिया। भारत ने 1 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य की दवाइयां दानस्वरूप कांगो भेजी और प्राथमिकता वाली एक परियोजना के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर की तत्काल ऋण-श्रृंखला देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों वाला एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में जून, 2008 में किन्हासा गया। कांगों की सरकार के मंत्रियों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर वाणिज्य सचिव ने अपने ऋण-श्रृंखला के तहत भारत सरकार के विचारार्थ कई परियोजनाओं की सिफारिश की। इस यात्रा के दौरान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा फेडरेशन ऑफ कांगोलीज इंटरप्राइजेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। व्यापार एवं व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 2008 में डी.आर.सी. का दौरा किया।

4 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर समारोह में बेनिन गणराज्य के राष्ट्रपति डा.बोनी याई के साथ प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह

गाम्बिया

भारत सरकार ने नेशनल एसेम्बली भवन परिसर के निर्माण का वित्तपोषण करने के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की एक्जिम बैंक की ऋण-श्रृंखला की मंजूरी प्रदान की। विदेश मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डा. उमर ए. तुरे ने मई, 2008 में भारत की यात्रा की और विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) के साथ हुई अपनी बैठक के दौरान नई दिल्ली में अपने सरकार द्वारा एक आवासी मिशन खोलने के लिए लिए गए निर्णय की सूचना दी।

घाना

दोनों देशों से हुए उच्च स्तरीय दौरों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाया। राष्ट्रपति जे.ए. कुफुओर ने भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने अप्रैल, 2008 में अकरा के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति जे.ए. कुफुओर से भेंट की और आपसी रूचि के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश राज्यमंत्री (ए.एस.) ने एक भारतीय कंपनी (शप्पोरजी पल्लोनजी एंड कं.) द्वारा निर्मित 'सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसीडेंसीयल कांप्लेक्स' का उद्घाटन करने के लिए वर्ष 2008 में घाना की यात्रा की। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला प्रदानकी थी। घाना के राष्ट्रपति द्वारा विदेश राज्यमंत्री (ए.एस.) को 'दि कंपेनियन ऑफ दी आर्डर ऑफ दी वोल्टा' पुरस्कार से नवाजा गया। इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) ने विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान की नींव भी रखी। इस संस्थान के एक सभागृह का नामकरण पं. जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया जाएगा। भारत के एस्काट्‌र्स लिमिटेड ने टेमा में एक ट्रैक्टर पुनःसंयोजन संयंत्र स्थापित किया जबकि महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने एक अन्य ट्रैक्टर पुनःसंयोजन संयंत्र कुमासी में लगाया है। भारत सरकार ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रेल कारीडोर और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला प्रदान की है।

गीनिया

परिवहन मंत्री और ऊर्जा एवं हाइड्रोलिक मंत्री तथा एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में 19-21 मार्च, 2008 तक आयोजित भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी 2008 पर सी.आई.आई.-एक्जिम कान्क्लेव में भाग लिया। शहरी परिवहन प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए गीनिया की सरकार को इकोवास निवेश एवं विकास बैंक (ई.बी.आई.डी.) के माध्यम से 8.51 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला मंजूर की गई। इसके अलावा ई.बी.आई.डी. के ही माध्यम से गीनिया में विद्युत नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्वास के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी ऋण-श्रृंखला देने की भी घोषणा की गई। गीनिया के लिए आइटेक स्लाटों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया है।

माली

माली के आर्थिक उद्योग एवं व्यापार मंत्री तथा वाणिज्य एवं करारों के राष्ट्रीय निदेशक ने 26-30 मई, 2008 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। भारत सरकार ने बमाको में अपना एक आवासी मिशन खोलने के निर्णय की घोषणा की।

नाइजर

भारत सरकार ने नियामे में एक आवासी मिशन खोलने के अपने निर्णय की घोषणा की। विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतिकरण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र की मंजूरी दी गई।

नाइजीरिया

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अक्तूबर, 2007 में हुई यात्रा के दौरान नाइजीरिया के साथ स्थापित द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी के अनुसरण में आगे सहयोग का एक रोड मैप निश्चित किया गया। उप-राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में अब तक की आयोजित पहली भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में नाइजीरिया का प्रतिनिधित्व किया। विदेश राज्यमंत्री श्री आनंद शर्मा ने जुलाई, 2008 में नाइजीरिया की यात्रा की और अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उमारू मुसा यार-आदुआ के साथ मुलाकात की जिन्होंने असैनिक नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने की भारत की तलाश का समर्थन किया। विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री चीफ ओजो माड्यूक्वे के साथ सितम्बर में न्यूयार्क में द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। भारत के उच्चायोग ने भारत और नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत नाइजीरिया संबंधों पर लागोस में एक फोटोग्राफ की प्रदर्शनी आयोजित की। कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन भी आयोजित किए गए। वर्ष 2007-08 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक रही और भारतीय निर्यात 1 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर 20% की वृद्धि दर्ज की। नाइजीरिया हाइड्रोकार्बन का हमारा एकल सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। वर्ष 2008-09 के लिए नाइजीरिया को आंवटित आइटेक स्पाटों की संख्या को बढ़ाकर 85 कर दिया गया।

सेनेगल

सेनेगल के राष्ट्रपति अब्दुलाये वाडे ने भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लिया। एक्जिम बैंक ने डकर में अपना कार्यालय खोला। विदेश राज्यमंत्री (ए.एस.) ने जुलाई, 2008 में सेनेगल की यात्रा की। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के एक उत्कृष्ट केन्द्र का उद्घाटन किया जो भारत द्वारा अनुमोदित की गई 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। विदेश राज्यमंत्री (ए.एस.) ने सेनेगल

9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति जोजेफ कबीला कबांगी से मुलाकात करते हुए।

8 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह सेनेगल के राष्ट्रपति अब्दुल्ले बाडे के साथ मुलाकात करते हुए।

के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और वहां के विदेश मंत्री डा. चेख टिडियाने गाडियों और खनन एवं उद्योग मंत्री कुसमाने नोम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत द्वारा प्रदत्त विकास सहायता के लिए डा. गाडियों ने सेनेगल के सरकार की ओर से आभार प्रकट किया। इस यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतिकरण एवं मत्स्यपालन उद्योग विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए एक्जिम बैंक के माध्यम से 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र मंजूर की। भारत सरकार ने सेनेगल को 15,000 टन चावल निर्यात किया।

सियेरा लियोन

विदेश राज्यमंत्री (ए.एस.) के आमंत्रण पर सियेरा लियोन के विदेश मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्रीमती जैनब हाबा बांगुरा ने 6-11 अक्तूबर, 2008 तक भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय विचार-विमर्श की। दोनों देशों ने कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, परिवहन एवं उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान की। सियेरा लियोन के सरकार के अनुरोध पर भारत ने 40,000 टन गैर-बासमती चावल निर्यात किया। वाणिज्यिक कृषि के विकास का वित्तपोषण करने के लिए भारत सरकार ने 15 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र सियेरा लियोन के लिए मंजूर की। दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्वास के लिए इकोवास निवेश एवं विकास बैंक के माध्यम से 29.45 मिलियन अमरीकी डालर की एक अन्य ऋण-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। सियेरा लियोन के लिए आइटेक स्लाटों की संख्या को बढ़ा कर 25 किया गया।

टोगो

भारत सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 225,000 अमरीकी डालर के मूल्य की दवाइयों का एक खेप टोगो भेजा। भारत सरकार द्वारा 20 मिलियन अमरीकी डालर की प्रदत्त ऋण-पत्र के अंतर्गत हॉस्पीटलों का पुनर्वास कार्य शुरू किया गया।

पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के लिए आर्थिक आयोग (इकोवास)

राष्ट्रपति इब्न मोहम्मद चम्बास ने भारत-अफ्रीका मंच की शिखर बैठक में भाग लिया। इकोवास देशों ने इकोवास औद्योगिक बैंक को मंजूर 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया।

पान अफ्रीकी ई-नेटवर्क

अफ्रीकी संघ के सभी 53 देशों के बीच प्रभावी संचार एवं संपर्क प्रदान कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की सितम्बर, 2004 में उद्घोषित भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना में, मंत्रालय और टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल.) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर होने के साथ ही आगे प्रगति हुई। 53 देशों में से 32 देशों ने कंट्री करारों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रीय समन्वयकर्त्ताओं, कंसाइनी और स्थलों की पहचान कर ली है। अधिष्ठापन एवं शुरूआती कार्यकलाप शुरू हो गए हैं। डकर, सेनेगल में हब स्टेशन और सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन अगस्त में प्रकार्यात्मक हो गए हैं। उपकरणों का अधिष्ठापन और परीक्षण का कार्य 12 देशों में पूरे कर लिए गए हैं। भारत के विनिर्दिष्ट अस्पतालों और विश्वविद्यालयों के साथ सेनेगल और अदीस अबाबा में टेली-मेडिसीन का लाइव प्रदर्शन और वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

■■

यूरोप

7

यूरोपीय संघ के साथ-साथ यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों के साथ भारत के कार्यकलाप गहन हुए हैं और प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा, नाभिकीय एवं अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, खाद्यान्न सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में फैले हैं।

भारत और यूरोप के बीच उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान होता रहा। ईयू, फ्रांस, बेल्जियम और यूके के साथ शिखर बैठक स्तरीय क्रियाकलाप हुए। इसके अलावा बहुपक्षीय कार्यक्रमों से यूके, जर्मनी और इटली के साथ प्रधानमंत्री स्तरीय तालमेल कायम करने का अवसर मिला। नेताओं के बीच नियमित रूप से टेलिफोन पर बातचीत होने से भारत और यूरोप आपसी रूचि के मसलों पर चर्चा करते हुए एक दूसरे के निरंतर संपर्क में रहे। संसद सदस्यों और सिविल समाज के बीच वार्ताओं के बढ़ते आदान-प्रदान के अलावा मंत्रिस्तरीय और अधिकारी स्तरीय पर व्यापक तालमेल जारी रहे।

भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए एन.एस.जी. में रियायत प्राप्त करने के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु यूरोपीय संघ के सभी देशों में विशेष दूत भेजे गए। बेल्जियम के महाराज की नवंबर, 08 में हुई यात्रा के दौरान बेल्जियम ने सार्वजनिक रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। मुम्बई में हुए आतंकी हमले के पश्चात यूरोपीय संघ के नेताओं और सदस्य राज्यों ने हमलों की निंदा करते हुए, पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में एकजुटता की पुष्टि करते हुए संदेश भेजा और टेलीफोन पर वार्ता की।

मध्य यूरोप

प्रस्तावना

भारत का नोर्दिक के देशों के साथ-साथ मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देशों के साथ पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। इन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और विविधतापूर्ण और गहन बनाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तारित यूरोपीय संघ से नई चुनौतियां और अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

यूरोप की तुलना में भारत की आर्थिक प्रगति की अपेक्षाकृत उच्च दर, भारत में अत्यंत प्रतियोगी दरों पर दक्ष तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता, विस्तृत भारतीय बाजार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं दवाइयों सहित उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण क्षेत्र और विदेशों में निवेश करने की भारतीय कंपनियों की बढ़ती क्षमता, बढ़ते उम्र वाली जनसंख्या का भविष्य और सिकुड़ती शैक्षिक एवं श्रमिक बल को एक साथ लेकर चलने-इन सबों के कारण नोर्दिक, मध्य और पूर्वी यूरोपियाई देशों की भारत के प्रति रूचि फिर से बढ़ी है। इनमें से अधिकांश देशों के साथ व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही इसका रुझान पारंपरिक पण्यों से अलग हट कर इंजीनियरी सामानों और मूल्य संवर्धित सामानों की ओर हुआ है। भारत से इनमें निवेश भी बढ़ रहा है। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन की संभावना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ पैट्रोलियम, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी में सहयोग एक साथ जुड़ने के नए अवसर प्रदान करते हैं। नार्डिक देश भी अपने विशाल निवेश करने योग्य कोष के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट और वित्तीय दस्तावेजों को सुरक्षित एवं लाभकारी निवेश के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। भारत और यूरोप के इन भागों के बीच परस्पर लाभ के लिए पूर्ववर्ती पूर्वी यूरोप की अपेक्षाकृत उच्च विकास दर के साथ-साथ गतिशील और आर्थिक रूप से सक्षम भारत से उत्पन्न होने वाली नई संभावना आर्थिक क्रियाकलापों को और मजबूत बना रही है।

अल्बानिया

अल्बानिया के विदेश मंत्री श्री लुलजिम बाशा ने 17-20 दिसंबंर, 2008 तक भारत की यात्रा की। यह दोनों में से किसी ओर से किसी भी विदेश मंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा थी। विदेश मंत्री के साथ हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताओं के अलावा, विदेश मंत्री बाशा का रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आई.डी.एस.ए.) में एक अंतर-क्रियात्मक सत्र भी हुआ। इस यात्रा के दौरान अल्बानिया के विदेश मंत्री द्वारा अल्बानिया के राजदूतावास का 18 दिसंबर, 2008 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। वे कोलकाता भी गए जहां कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। वे मदर टेरेसा मैमोरियल हाउस भी गए। विदेश मंत्री और उनके साथ-साथ आए व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कोलकाता में भारतीय व्यापार परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार मंडल के साथ एक बैठक भी हुई। भारत के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के प्रति समर्थन जुटाने के लिए सचिव (ई.आर.) ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 28 जुलाई को अल्बानिया की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री साली बेरिशा और विदेश मंत्री लुलजिम बाशा से मुलाकात की। अल्बानिया ने आई.ए.ई.ए. में

भारत का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। अल्बानिया के कार्य प्रभारी अपना आवासी मिशन खोलने के लिए नई दिल्ली आए।

बेल्जियम

बेल्जियम के महाराज महामहिम अल्बर्ट-II 3-12 नवंबर, 2008 तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ महारानी पाओला, विदेश मंत्री कारेल डी गुच और एक विशाल शैक्षणिक एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया। दिल्ली के अलावा वे आगरा, मुम्बई, हैदराबाद, मम्मलापुरम और चेन्नै भी गए। विदेश मंत्री कारेल डी गुच ने उद्योग से जुड़े लोगों के साथ अपने बातचीत के दौरान सार्वजनिक रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारतीय उम्मीदवारी के प्रति बेल्जियम द्वारा समर्थन दिए जाने की घोषणा की। बैकिंग, बंदरगाह ठहराव स्थल, कृषि आधुनिकीकरण में नाभिकीय/रेडियोलॉजी तकनीकों का अनुप्रयोग करना, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के फर्मों के साथ कई समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शैक्षणिक सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों के स्तर को अच्छे से वैश्विक स्तर तक ऊंचाई पर ले जाने और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। सचिव (पश्चिम) ने विदेश कार्यालय परामर्श के प्रथम दौर के लिए 29 जुलाई, 2008 को बेल्जियम का दौरा किया।

वालुन की क्षेत्रीय सरकार के आर्थिक एवं वाणिज्य मंत्री जीन-कलाउडे मारकोर्ट ने 20-27 सितम्बर, 2008 तक भारत की यात्रा की।

आई.सी.सी.आर. के प्रायोजन के अंतर्गत सुश्री उमा शर्मा ने अपनी मंडली के साथ जून, 2008 में ब्रुसेल्स और लियुवेन में कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। राजस्थान की एक सांस्कृतिक मंडली ने सितम्बर, 2008 में घेंट व्यापार मेले, जिसमें कि भारत अतिथि देश था, में प्रदर्शन किया।

बुल्गारिया

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बीजिंग में आयोजित सातवें ए.एस.ई.एम. शिखर बैठक के दौरान बुल्गारिया के राष्ट्रपति जार्जी पुखानोव के साथ 24 अक्तूबर, 2008 को मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 16-20 जून, 2008 तक एक 13 सदस्यों वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का बुल्गारिया में नेतृत्व किया। सोफिया में 8-12 जून, 2008 तक आयोजित आई.टी. के लिए छठे जनरल एसेम्बली ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन एसोशिएशन में श्री एस.एस. अहलुवालिया, संसद सदस्य (आर.एस.) के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारत के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के प्रति समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में तथा विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में सचिव (पश्चिम) ने 20-22 जुलाई, 2008 तक सोफिया की यात्रा की। बुल्गारिया ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत विशिष्ट रियायत के लिए अपना समर्थन दिया। भारत-बुल्गारिया संयुक्त रक्षा समिति का 13वां सत्र 8-9 मई, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बुल्गारिया के आंतरिक उपमंत्री के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9-13 जून, 2008 तक भारत की यात्रा की। भारत सरकार ने बुर्गास में एक मानद कोंसल की नियुक्ति की है। आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी संधि तथा सजायाफ्ता लोगों के अंतरण पर संधि से संबंधित अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान संबंधी प्रोतोकोल पर सोफिया में 9 सितम्बर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए। बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 27 फरवरी-4मार्च, 2009 तक भारत की शासकीय यात्रा पर आए। सरकारी कार्य दिवस 3 मार्च, 2009 था।

क्रोएशिया

श्री नलिन सुरी, सचिव (पश्चिम) ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 30-31 जुलाई, 2008 को जगरेब की यात्रा की और भारत के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रोएशिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डन जान्द्रोकोविक के साथ मुलाकात की। क्रोएशिया ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत विशेष छूट के लिए अपना समर्थन दिया। द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2006 की तुलना में 40% की वृद्धि दर्ज की गई। भा.सां.सं.प. द्वारा प्रायोजित 5 सदस्यीय मोहिनीअट्टम नृत्य मंडली ने जगरेब, जाबोक, सिसाक और साकोवेक में अप्रैल, 2008 में प्रस्तुति दी। क्रोएशियाई नेशनल थियेटर में राजस्थान के तैतालीस सदस्यीय मंगनीयार सूफी संगीतकारों के एक दल ने जुलाई, 2008 में प्रस्तुति दी।

साइप्रस

साइप्रस ने 6 सितंबर, 2008 को विएना में आयोजित एन.एस.जी. बैठक के दौरान भारत को अपना बहुमूल्य समर्थन दिया। इस संबंध में सी.आर. गरेखां, प्रधानमंत्री के विशेषदूत ने 30 जुलाई-1 अगस्त, 2008 तक साइप्रस का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति डिमेट्रिस क्रिस्टोफिआस और विदेश मंत्री मार्कोस किप्रिआनु से भेंट की। साइप्रस-भारत व्यवसाय संघ ने निकोसिया में अक्तूबर, 2008 में एक व्यवसायिक संगोष्ठी आयोजित किया। साइप्रस के वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री ने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को उन्नत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आंतरिक रूप से देश में साइप्रस गणराज्य के छठें राष्ट्रपति के रूप में डिमेट्रिल क्रिस्टोफियास के चुनाव से साइप्रस मसले के समाधान की आशा बनी थी। साइप्रस के साथ विदेश कार्यालय परामर्श 3 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में होनी है।

चेक गणराज्य

सचिव (ई.आर.) ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई,

2008 में प्राग की यात्रा की और भारत के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के लिए चेक गणराज्य का समर्थन मांगा। एन.एस.जी. की सितंबर, 2008 में हुई बैठक में चेक गणराज्य ने भारत का समर्थन किया और भारत के पक्ष में मतदान किया। इस अवधि के दौरान दोनों देशों से नियमित उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) श्री आनन्द शर्मा द्वारा 7-9 सितंबर, 2008 और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ द्वारा 10-12 सितंबर, 2008 तक भारतीय पक्ष की ओर से की गई यात्राओं में शामिल थे। चेक पक्ष की ओर से उद्योग एवं व्यापार मंत्री मार्टिन रीमान ने नवंबर, 2008 में भारत की यात्रा की जबकि चेक सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ प्रमुख ले.ज. ब्लास्टिमिल पीसेक की भारत यात्रा अप्रैल, 2008 में संपन्न हुई। चेक गणराज्य के साथ व्यापार एवं आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डालर पार कर जाने की आशा है। भारत और चेक गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर वार्ता पूरी हो चुकी है और करार पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर होने की आशा है।

डेनमार्क

डेनमार्क के प्रधानमंत्री की फरवरी, 2008 में हुई भारत यात्रा के पश्चात द्विपक्षीय तालमेल और सुदृढ़ हुए हैं। नई एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री विलास बी. मुत्तेमवार ने नई एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत- डेनमार्क संयुक्त समिति की पहली बैठक में भाग लेने के लिए अप्रैल, 2008 में डेनमार्क की यात्रा की। व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एक 3 सदस्यीय डेनिश ऊर्जा एजेंसी प्रतिनिधिमंडल ने द्वितीय संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 24-28 नवंबर, 2008 तक भारत का दौरा किया और विंड इंडिया 2008 संगोष्ठी में भाग लिया। स्वास्थ्य संबंधी डेनमार्क की एक 12 सदस्यीय संसदीय ने समिति अध्ययन दौरे पर 10-17 सितंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य संबंधी भारतीय संसदीय समिति, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने सामाजिक सुरक्षा करार और डेनमार्क के साथ लेबर मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन को शीघ्र संपन्न कराने हेतु 29-30 सितंबर, 2008 को कोपनहेगन की यात्रा की। डेनमार्क विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अक्तूबर, 2008 में नई दिल्ली स्थित डेनिस राजदूतावास में "वर्क-इन-डेनमार्क केंद्र" की शुरुआत की। भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 27 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007-08 में डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1074.6 मिलियन अमरीकी डालर थी। प्रधानमंत्री के विशेषदूत के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने डेनमार्क के विदेश मंत्री से भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय ऊर्जा करार पर उनका समर्थन पाने के लिए 25 जुलाई, 2008 को बातचीत की। एन.एस.जी. की सितंबर, 2008 में हुई बैठक में भारत विशेष छूट के लिए डेनमार्क ने समर्थन किया और भारत के पक्ष में मतदान किया।

एस्टोनिया

एस्टोनिया के साथ हमारा संबंध तेजी से मूर्त रूप ले रहा है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री श्री उर्मास पेट ने 23-25 नवंबर 2008 तक भारत की यात्रा की और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल के साथ बैठक की और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के साथ वार्ता की। वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श भी 8-9 अक्तूबर, 2008 को तालीन्न में आयोजित किए गए। इससे पूर्व भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग करार पर एस्टोनिया के प्राधिकारियों को जानकारी देने के लिए विशेष सचिव (ए.डी.) ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई, 2008 में एस्टोनिया की यात्रा की। एस्टोनिया ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत को विशेष छूट दिए जाने के लिए बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दिया था। एस्टोनिया ने आईटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाना जारी रखा और वर्ष 2008-09 के लिए उसे आवंटित स्लाटों की संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 45 मिलियन यूरो रहने की आशा है जो संतोषजनक है तथा इसके और बढ़ने की आशा है।

फिनलैंड

वर्ष 2008 के दौरान फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंध आकार और मात्रा दोनों में बढ़े हैं। विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने जून, 2008 में वहां की यात्रा की और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और वहां के विदेश मंत्री और संसद की विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष और विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव से भी मुलाकात की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भूगर्भ-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग करार पर फिनलैंड की सरकार को जानकारी देने के लिए जुलाई, 2008 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में हेलसिंकी की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य सचिव के अलावा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे मंत्री से भेंट की। फिनलैंड ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत को विशिष्ट छूट देने के लिए बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दिया। उन्होंने इससे पूर्व हेलसिंकी की मार्च, 2008 में यात्रा की थी और फिनलैंड के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए थे। उद्योग राज्यमंत्री डा. अश्विनी कुमार ने द्वितीय ग्लोबल इनोवेशन शिखर बैठक, जिसमें बड़ी संख्या में भारत और फिनलैंड की शीर्ष कंपनियों ने भाग लिया था, का उद्घाटन करने के लिए 25-29 मई, 2008 को फिनलैंड की यात्रा की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत सम्मेलन सहित सित्रा के लिए मुख्य अतिथि के रूप में 14-16 अप्रैल, 2008 तक फिनलैंड की यात्रा की। वर्ष 2007 में फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार 31.54% बढ़ा और यह 645 मिलियन यूरो रहा। व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 15 वां संयुक्त आर्थिक आयोग की दिल्ली में अप्रैल, 2008 में बैठक हुई। फिनलैंड के साथ विदेश कार्यालय परामर्श मार्च, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुई। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट

(टी.ई.आर.आई.) द्वारा आयोजित दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए फिनलैंड की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती टार्जा हैलोनेन ने 5-7 फरवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ विदेश व्यापार एवं विकास मंत्री श्री पावो वेरीनेन और एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया।

फ्रांस

राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 25-26 जनवरी, 2008 को राजकीय यात्रा पर भारत आए। वे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। उनके साथ फ्रांस के पांच उच्च स्तरीय मंत्री और एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। विस्तृत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मसलों पर चर्चाएं हुई। असैनिक नाभिकीय सहयोग, ऊर्जा, व्यापार एवं सहयोग के उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। यात्रा की समाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य के अलावा ग्लोबल वार्मिंग क विरूद्ध लड़ाई पर एक संयुक्त घोषणा जारी की गई। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए करारों में- रक्षा के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना की परस्पर सुरक्षा पर करार, सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण पर करार, जुलेस होरोविज (जे.एच.) रिएक्टर का निर्माण एवं प्रचालन हेतु कमिशरीयात एल एनर्जी एटोमिक (सी.ई.ए.) फ्रांस और डी.ए.ई., भारत के बीच करार, ए.एफ.डी. के माध्यम से भारत-फ्रांस विकास सहयोग पर करार और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एशोसिएटेड लेबोरेटरी पर एक समझौता-ज्ञापन शामिल थे।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भारत-फ्रांस द्विपक्षीय शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 30 सितंबर, 2008 को पेरिस की यात्रा की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी दोनों ने भारत और फ्रांस के बीच सामरिक भागीदारी और असैनिक नाभिकीय सहयोग, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकी एवं शैक्षिक क्षेत्रों में और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग को और बढ़ाने पर बल दिया गया। शिखर बैठक के दौरान हस्ताक्षरित करारों में - असैनिक नाभिकीय सहयोग के क्षेत्र, बाहरी अंतरिक्ष में सहयोग, उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए पी.एस.एल.वी. का उपयोग और सामाजिक सुरक्षा-शामिल थे।

फ्रांस के विदेश एवं मानवाधिकार राज्य मंत्री सुश्री रमा याडे की 30 मई, 2008 को आयोजित 19वीं भारत-ई.यू. त्रोयका मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए हुई यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने पेरिस में अफगानिस्तान के समर्थन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-प्रथम 11-14 जून, 2008 तक और पुनः 14 दिसंबर, 2008 को- में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सिनेटर श्री पियरे फाउचोन के नेतृत्व में भारत-फ्रांस संसदीय मैत्री दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14-22 सितंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। एन.एस.ए. और राष्ट्रपति सरकोजी के राजनयिक सलाहकार जीन डेविड लेविट के बीच भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता का 19वां दौर 11 अगस्त, 2008 को पेरिस में और 20वां दौर 17 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत-फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श 6 फरवरी, 2009 को पेरिस में संपन्न हुआ। विदेश सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पेरिस में 25-26 नवंबर को हुई रक्षा पर उच्च स्तरीय समिति की 11वीं बैठक में अदेन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा और एंटी-पाइरेसी अभियान को बढाने और समन्वय को और उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त अभ्यास, सशस्त्र बलों के स्तर पर स्टाफ-वार्ता और मध्य सेवा स्तर पर अन्य व्यवसायिक आदान-प्रदान भली-भांति कार्य कर रहा है। वरूण नौसेना अभ्यास मई, 2008 में आयोजित की गई और द्वितीय प्रचालनात्मक समन्वित समुद्री गश्त हार्न ऑफ अफ्रीका से शुरू हुई।

परमाणु ऊर्जा पर छठा भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की बैठक 2-3 दिसंबर, 2008 को कलपक्कम में संपन्न हुई। 300 टन यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए फ्रांस के न्यूक्लियर ग्रुप आरेवा और परमाणु ऊर्जा विभाग ने 17 दिसंबर, 2008 को एक करार पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष के दौरान भारत-फ्रांस व्यापार तालमेल बढ़ाने के प्रयास जारी रहे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने तीन बार; पहली बार 3-5 जुलाई, 2008 को फ्रांस में अपने समकक्ष के साथ चर्चा करने के लिए; दूसरी बार सितंबर, 2008 में भारत-ई.यू. और भारत-फ्रांस शिखर बैठक के संबंध में और तीसरी बार 8-9 जनवरी, 2009 में राष्ट्रपति सरकोजी के सुझाव पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की सह-अध्यक्षता में आयोजित "न्यू वर्ल्ड, न्यू कैपिटलिज्म" नामक एक आर्थिक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए फ्रांस की यात्रा की। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर सी.आई.एम. स्तरीय भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की वार्षिक बैठक 16-17 सितंबर, 2008 तक नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश व्यापार के उप-मंत्री सुश्री एन्न मारी इद्राक ने सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए जनवरी, 2009 में भारत की यात्रा की।

फ्रांस और भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों पर, एक दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। भारतीय उपग्रहों के लिए एरियानेस्पेश ने प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करना जारी रखा है। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2008 में फ्रांस की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित करार में इस क्षेत्र में सहयोग के कानूनी ढ़ाचे की व्यवस्था है। दिसंबर, 2008 में कौउरु, फ्रेंच गुयाना में एरियान स्पेस द्वारा डब्ल्यू टू एम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया जिसे कि संयुक्त रूप से एंट्रिक्स/इसरो और ई.ए.डी.एस. - एस्ट्रियम फॉर यूटेलसैट द्वारा निर्मित किया गया था।

भारत-फ्रांस उच्चतर अनुसंधान संवर्धन केंद्र (सीईएफआईपीआरए) के शासी मंडल की बैठक 14 जनवरी, 2009 को पेरिस में संपन्न हुई।

30 सितंबर, 2008 को एलिसी पैलेस, पेरिस में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के साथ।

20 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश कार्य मंत्री एवं वाइस चांसलर डा. फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर केंद्रीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत-फ्रांस विश्वविद्यालय कंसोर्टियम एक बैठक शिलांग में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की वार्षिक बैठक के साथ 16-18 नवंबर, 2008 को संपन्न हुई।

फ्रांस में जनवरी, 2008 से भारतीय सांस्कृतिक कैलेण्डर में - 31 नृत्य प्रदर्शन; 28 संगीत सभा; 9 सांस्कृतिक महोत्सवों; 24 छायाचित्र प्रदर्शनी; वर्ष 2008 में सेंट एटियने में डिजायन की, द्विवार्षिकी में भारतीय भागीदारी सहित 20 कला प्रदर्शनी; और भारतीय भागीदारी से 14 फिल्म महोत्सव शामिल हैं। सिनेमा, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, साहित्य, फैशन इत्यादि सहित विविध क्षेत्रों को शामिल करने वाले लगभग एक दर्जन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत "कंट्री ऑफ ऑनर" था। जून, 2008 में आयोजित एन्नेसी एनिमेशन फिल्म महोत्सव और पेरिस के पोयट्री मार्केट सहित वर्ष 2008 के पूर्वाद्ध के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा प्राप्त था।

जर्मनी

जर्मनी ई.यू. के अंदर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, वैश्विक प्रौद्योगिकी सहयोजन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और एक महत्वपूर्ण निवेशक रहा है। यह वर्ष द्विपक्षीय दौरों का निरंतर आदान-प्रदान, व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहभागिता के समुचित विस्तार का साक्षी रहा।

जर्मन फेडरल वाइस चांसलर डा. फ्रेंक वाल्टर स्टीनमायर और विदेश मंत्री 19-21 नवंबर, 2008 तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ सांसदगण एवं बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। इसके अलावा डा. स्टीनमायर ने बंगलौर का भी दौरा किया जहां उन्होंने जर्मन कोंसलावास का उद्घाटन किया।

आतंकवाद से मुकाबला करने संबंधी भारत-जर्मनी संयुक्त कार्य दल की पांचवी बैठक 16-17 अक्तूबर, 2008 को बर्लिन में संपन्न हुई।

रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली। बर्लिन हवाई शो, आई.एल.ए. 2008 जो कि मई, 2008 में आयोजित की गई थी का भारत एक सहभागी देश था और जिसमें कि भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन संयुक्त रूप से रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी और चांसलर एंजेला मार्केल द्वारा किया गया था। जर्मनी के एयरोस्पेस उद्योग के 20 सी.ई.ओ. के एक दल ने रक्षा राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ सी.ई.ओ. गोलमेज में भाग लिया था जबकि व्यापार से जुड़े लगभग 200 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम के दौरान भारत पर व्यापार सम्मेलन में भाग लिया था। रक्षा सचिव स्तरीय उच्च रक्षा समिति की अप्रैल, 2008 में और पुनः मार्च, 2009 में बैठक हुई जबकि इसकी तीन उप समूहों की अप्रैल, 2008 और जनवरी, 2009 में बैठक हुई।

व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान और संवर्धनात्मक कार्यकलापों का आयोजन समान गति से जारी रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में एस.एम.ई. वाले एक नब्बे सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल 8-9 सितंबर, 2008 को जर्मनी की यात्रा पर गया। द्विपक्षीय नागर विमानन संबंधी वार्ता 10-11 अप्रैल, 2008 को बर्लिन में हुई जिसमें दोनों पक्ष प्रति सप्ताह और 26 उड़ान शामिल करने पर सहमत हुए जिससे कि प्रत्येक देश से उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह बढ़कर कुल 69 हो जाएगी। तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के मसले पर विचार-विमर्श करने हेतु सचिव, श्रम एवं रोजगार ने 6-10 अक्तूबर, 2008 तक जर्मनी की यात्रा की। कृषि पर संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 12 नवंबर, 2008 को हैनोवर में संपन्न हुई। जर्मन फेडरल पर्यावरण मंत्री श्री सिगमार गैब्रियल के नेतृत्व में जर्मनी के व्यवसायियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 17-18 नवंबर, 2008 को भारत आया जबकि उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सेवुगन रघुपति के साथ प्रथम भारत-जर्मनी पर्यावरण मंच का साथ-साथ उद्घाटन किया। 9-16 नवंबर, 2008 में हैम्वर्ग में आयोजित दूसरे भारतीय सप्ताह के दौरान "डुइंग बिजनेस विथ इंडिया" "एविएशन एंड हाई-टेक लाजिस्टिक्स" री-न्यूएबल इनर्जी, पर्यटन एवं रसायन एवं दवाओं पर व्यापार सम्मेलन आयोजित किए गए। मेसर्स वोफ्सबर्ग ए.जी. द्वारा वोफ्सबर्ग में 29-31 अक्तूबर, 2008 तक आयोजित "5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता मेले आई जेड.बी." में भारत एक भागीदार देश था। जर्मनी के एस.एम.ई. के कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए जर्मनी के दो बैंकों अर्थात बावारियन लैंडेसबैंक (बीएलबी) और लैंडेसबैंक बाडेन वर्टेनवर्ग (एलबीबी डब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से गुड़गांव में स्थापित एक जर्मनी केंद्र वर्ष 2008 के दौरान कार्य करने लगा। लोअर सैक्सोनी के मिनिस्टर प्रेसीडेंट श्री क्रिस्टीयन वुल्फ 3-7 अक्तूबर, 2008 तक भारत के दौर पर आए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-जर्मन तालमेल के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं भूगर्भ-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल ड्रेस्डेन, जर्मनी में 27 जून, 2008 को आयोजित मैक्स प्लांक सोसायटी के फेस्टिव एसेंबली में भाग लेने के लिए 26-30 जून, 2008 तक जर्मनी का दौरा किया। वे और फेडरल चांसलर एजेंला मार्केल ने संयुक्त रूप से फेस्टिव एसेंबली को संबोधित किया। श्री सिब्बल ने नोबल पुरस्कार विजेताओं की एक सभा को भी लिण्डाह में संबोधित किया। डा. एनेट्टे शावन ने इसके पश्चात आईआईटी-मद्रास के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 8-10 सितबंर, 2008 तक भारत की यात्रा की। सतत विकास अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित करने पर डीएएडी और आईआईटी, मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने आईआईटी,मद्रास से जर्मनी जाने वाले अध्येताओं के लिए स्टार छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। इस दौरान मैक्स प्लांक सोसायटी द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी वाले साइंस एक्सप्रैस ने भारत के 55 शहरों की यात्रा करने के पश्चात अपनी यात्रा पूरी की। इसे 2 मिलियन से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा।

सुश्री हाइडेमारी विकजोटेक जिउल, जर्मन फेडरल के आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री ने भारत जर्मनी विकास सहयोग में भागीदारी का 50 वां वर्ष मनाने के लिए 20-24 अक्तूबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। भारत-जर्मनी विकास सहयोग के आगे की नीतिगत रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।

आईजीसीजी (भारत-जर्मनी परामर्शदात्री दल) की 17वीं बैठक 11-14 सितम्बर, 2008 तक म्यूनिख में संपन्न हुई।

ग्रीस

भारत के असैनिक नाभिकीय करार के लिए एन.एस.जी. की बैठक में ग्रीस का समर्थन पाने के लिए विदेश मंत्रालय में सचिव श्री नलिन सूरी ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई, 2008 में एथेंस का दौरा किया। भारत द्वारा विशेष छूट पाने का एनएसजी की बैठक में ग्रीस ने समर्थन किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) नई दिल्ली के एक 16 सदस्यीय दल ने मई 2008 में ग्रीस की यात्रा की। थेस्सालोनिकी, ग्रीस में 6-14 सितंबर, 2008 तक आयोजित थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत ने भाग लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अप्रैल, 2007 में की गई ग्रीस की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-ग्रीस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार के अनुसमर्थन के दस्तावेज का 30 सितबंर, 2008 को आदान-प्रदान किया गया।

होली सी

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज,श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 अक्तूबर 2008 को सिस्टर एलफोंसा कैनोनाइजेशन समारोह में भाग लेने के लिए 10-13 अक्तूबर 2008 तक वेटिकन की यात्रा की।

हंगरी

भारत के हंगरी के साथ घने, मैत्रीपूर्ण और बहुपक्षीय संबंध रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री की जनवरी, 2008 में हुई भारत की शासकीय यात्रा के अलावा संबंधों का और विस्तार करने और ठोस बनाने से विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक गतिशीलता देखने को मिली है और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक सहयोग प्राप्त हुआ है। इस यात्रा के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और तेल उत्खनन के क्षेत्रों में 7 करारों पर हस्ताक्षर किए गए। हंगरी से भारत की हुई एक अन्य महत्वपूर्ण यात्रा हंगरी के रक्षा मंत्री इमरे सीकेरस की फरवरी, 2008 में की गई यात्रा थी। भारत की ओर से हंगरी की यात्राओं में - श्री आनन्द शर्मा, विदेश राज्य मंत्री की यात्रा श्री कमलनाथ , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की सितंबर, 2008 में की गई यात्रा और डा. एम.एस. गिल, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की नवंबर, 2008 में की गई यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में सचिव (ई.आर.) ने हंगरी का समर्थन प्राप्त करने के लिए हंगरी की जुलाई 2008 में यात्रा की। हंगरी ने भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय ऊर्जा करार का समर्थन किया और सितंबर, 2008 में हुई एनएसजी की बैठक में भारत के पक्ष में मत दिया। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काफी सहयोग बढ़े। भारत पहला देश था जिसे कि सितंबर, 2008 में बुडापेस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मानद अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत और हंगरी के बीच टोटलाइजेशन/सामाजिक सुरक्षा करार जिस पर कि वर्ष 2009 में हस्ताक्षर होने की आशा है को अंतिम रूप देने में हुई प्रगति एक अन्य महत्वपूर्ण रहा। हंगरी के साथ विदेश कार्यालय परामर्श 15 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (पश्चिमी) ने किया।

आइसलैंड

भारत के राष्ट्रपति की मई, 2005 में की गई आइसलैंड की यात्रा और आइसलैंड के राष्ट्रपति की वर्ष 2000, 2007 और 2008 में हुई भारत की यात्रा के पश्चात आइसलैंड के साथ अपने संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाने की इच्छा से भारत ने अपना आवासी मिशन अगस्त, 2008 में खोला। अपर सचिव (प्रशासन) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल ने आइसलैंड की यात्रा की और आइसलैंड में आवासी मिशन खोलने का प्रस्ताव रखने के साथ-साथ आइसलैंड के विदेश मंत्री और रेइकजाविक के मेयर से भी मुलाकात की। भू-उष्णता और नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य, नई एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिकों और सीआईआई, फिक्की और एयर इंडिया के प्रतिनिधियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने आइसलैंड की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों आइसलैंड की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और सीईओ से मुलाकात की। भारत और आइसलैंड के बीच जून, 2007 में हस्ताक्षिरत द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार को प्रवृत्त होने के लिए अनुसमर्थन के दस्तावेजों का 16 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आदान प्रदान किया गया।

आयरलैंड

नेशनल डिफेंस कालेज के एक 16 सदस्यीय दल ने अध्ययन दौरे के लिए मई 2008 में आयरलैंड की यात्रा की।

आयरलैंड के उच्च शैक्षिक संस्थानों में भारतीय छात्रों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए श्री बिली केलहर, टीडी, श्रम मंत्री के नेतृत्व में एक शिक्षा मिशन ने अप्रैल 2008 में भारत की यात्रा की।

न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू, अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयरलैंड का दौरा किया और अपने समकक्षों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।

इटली

इटली में 13-14 अप्रैल, 2008 को हुए आम चुनावों में श्री सिलवियो बर्लस्कोनी के नेतृत्व में केन्द्रीय वाम गठबंधन सत्ता में आयी। श्री बर्लुसकोनी को 8 मई, 2008 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बीजिंग में आयोजित शिखर बैठक के दौरान 24 अक्तूबर, 2008 को प्रधानमंत्री बर्लस्कोनी से मुलाकात की।

चौथे संयुक्त कार्यदल की बैठक और सैन्य सहयोग दल की मार्च, 2008 में रोम में हुई चौथी बैठक के साथ-साथ भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की 7वीं बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2008-09 के लिए एक द्विपक्षीय सहयोग योजना तैयार की गई जिस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। भारत से इटली की की गई यात्राओं में वायु सेना प्रमुख की 16-19 जनवरी, 2008 तक की यात्रा और अक्तूबर, 2008 में हुई उप-नौसेना प्रमुख की यात्रा शामिल है।

भारत से हुई अन्य यात्राओं में कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री; श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री; पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, रक्षा सचिव और सचिव (शहरी विकास) की की गई यात्रा शामिल है।

द्विपक्षीय स्टाफ वार्ता के लिए एम.सी.जी. की 5वीं बैठक 25-26 फरवरी, 2009 में नई दिल्ली में संपन्न हुई।

नौसेना स्टाफ प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता ने 15-20 मार्च, 2009 तक इटली की यात्रा की जबकि इटली के रक्षा के अवर सचिव गाइडो ग्रोसेटो बंगलौर में 10-14 फरवरी, 2009 तक आयोजित एयरो इंडिया 2009 शो में शामिल हुए।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डा. आर. चिदम्बरम ने पेरूगिया विश्वविद्यालय की संस्थापना के 700वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए 11-18 मार्च, 2009 तक इटली की यात्रा की।

लाटविया

भारत और लाटविया के बीच संबंध गर्मजोशी से भरा और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। वर्ष के दौरान की गई यात्राओं में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में श्री शरत सभरवाल, विशेष सचिव (प्रशा.) की 30 जुलाई को रीगा की यात्रा शामिल है जहां उन्होंने विदेश मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटी श्री नोर्मन्स पेन्के से और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से मुलाकात की और भारत-अमरीका नाभिकीय सौदे के लिए एन.एस.जी. में उनसे सक्रिय सहयोग मांगा। लाटविया ने एन.एस.जी. में भारत को अपना स्पष्ट समर्थन दिया। लाटविया के विदेश मंत्रालय के साथ विदेश कार्यालय परामर्श 5 मई, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यद्यपि द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से कम रहा किंतु लाटविया को भारतीय निर्यात वर्ष 2007 में बढ़कर 34.8 मिलियन अमरीकी डालर हो गया और द्विपक्षीय व्यापार में 30ऽ की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए आयात 13.1 मिलियन अमरीकी डालर रहा। लाटविया के राजनयिक एफ.एस.आई द्वारा दिल्ली में संचालित विदेशी राजनयिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं।

लिथुआनिया

श्री एंड्रिअस कुबिलीयस के नेतृत्व में नई सरकार 9 दिसंबर, 2008 को बनी। कुबिलीयस होमलैंड यूनियन-लिथुआनियन क्रिस्टियन डेमोक्रेट्स (कंजर्वेटिव्स) के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1998 में 21 मिलियन यूरो के व्यापार आंकड़े से वर्ष 2007 में कुल व्यापार 32.23 मिलियन यूरो हो गया। वर्ष 2008 के पहले छह माह में द्विपक्षीय व्यापार 100 मिलियन यूरो पहुंच गया। नई दिल्ली में जुलाई, 2008 में पूर्णरूपेण लिथुआनियन राजदूतावास खोला जाना द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति थी जिसका वर्तमान में एक कार्य प्रभारी द्वारा कार्य देखा जाता है। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में विशेष सचिव (प्रशा. एवं सीपीवी) ने जुलाई, 2008 में लिथुआनिया की यात्रा की और एन.एस.जी. से छूट प्राप्त करने के लिए लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेट्री ऑफ स्टेट से मुलाकात की। लिथुआनिया ने एन.एस.जी. बैठक में भारत विशेष छूट को बिना किसी शर्त समर्थन दिया था। भारत और लिथुआनिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों का चौथा दौर 10 अक्तूबर, 2008 को विलनीअस में संपन्न हुआ। दोहरे कराधान परिहार करार पर सरकार स्तरीय वार्ता 10-12 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। सांस्कृतिक प्रदर्शनों के क्रम में सुविख्यात कत्थक नृत्यांगना उमा शर्मा और उनकी 8 सदस्यीय मंडली ने 2 जून, 2008 को विलनीअस में प्रदर्शन किया जिसे काफी लोगों ने देखा।

लक्जमबर्ग

नाभिकीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में सचिव (पश्चिम) श्री नलिन सूरी ने 28 जुलाई, 2008 को लक्जमबर्ग की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लक्जमबर्ग के प्राधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

भारत और लक्जमबर्ग ने बातचीत के दो दौर के पश्चात दोहरे कराधान परिहार करार पर जून, 2008 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया।

एल एंड टी- पॉल वुर्थ कंसोर्टियम ने भारत के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। इस कंसोर्टियम को भूषण स्टील लिमिटेड से उनके मेरामंडली, उड़ीसा स्थित संयंत्र के लिए एक 2.5 मिलियन टीपीए ब्लास्ट फर्नेस के महत्वपूर्ण निर्माण के लिए 1205 करोड़ का आदेश भी प्राप्त हुआ।

मेसीडोनिया

मेसीडोनिया की सरकार ने नई दिल्ली में अपना राजदूतावास खोलने का निर्णय लिया और भारत सरकार ने मेसिडोनिया में एक मानद कोंसल की नियुक्ति की। भारत और मेसीडोनिया के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार, जिस पर कि 17 मार्च 2008 को हस्ताक्षर हुए थे, 17 अक्तूबर, 2008 को प्रवृत्त हुआ। मेसिडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री ने 20-24 जनवरी, 2009 को भारत की यात्रा की। सरकारी कार्य दिवस 20 जनवरी, 2009 को था।

माल्टा

माल्टा यूरोपीय संघ का वर्ष 2004 से सदस्य रहा है और वर्ष 2008 में यूरो जोन में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में श्री सी.आर. गरेखां ने जुलाई, 2008 में माल्टा की यात्रा की और माल्टा के राष्ट्रपति और उप मंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ बैठकें की और उन्हें भारत-अमरीका नाभिकीय सहयोग करार पर भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया। माल्टा ने भारत के विशेष छूट के लिए एन.एस.जी. बैठक में भारत का समर्थन किया। यूरोपीय संघ आयात-निर्यात व्यवस्था शुरू हो जाने के कारण द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2007-08 के दौरान कमी देखने को मिली। कार्य के मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा एवं नौवहन शामिल हैं। भा.सां.सं.परि. द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक मंडलियों का माल्टा में लोगों से भरी प्रेक्षागृह में जुलाई-अगस्त में प्रदर्शन हुआ।

नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड के बीच नियमित रूप से मंत्रियों के उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण द्विपक्षीय करार संपन्न हुए।

खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने 22-23 मई 2008 को नीदरलैंडस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड (एन.आई.सी.सी.टी.) द्वारा आयोजित निवेश संबंधी एक सेमिनार में भाग लेने के लिए नीदरलैंड की यात्रा की।

कानून एवं न्याय मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज ने 17-20 सितंबर, 2008 को नीदरलैंड की यात्रा की और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन की 115वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान मंत्री श्री भारद्वाज ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय स्थायी विवाचन न्यायालय (पी.सी.ए.) की सुविधा स्थापित करने के लिए पी.सी.ए. के साथ मेजबान देश करार पर हस्ताक्षर किया।

सूरीनाम हिन्दुस्तानी समुदाय के भारत से सूरीनाम के उत्प्रवासन के 135वें वर्ष पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि ने 4-6 जून, 2008 तक नीदरलैंड की यात्रा की।

नीदरलैंड के एम्सटर्डम में एक बड़े सांस्कृतिक एवं आर्थिक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में नवंबर, 2008 में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन शाही राजकुमार विल्लेम एलेक्जेंडर की पत्नी राजकुमारी मैक्सिमा; आई.सी.सी.आर. के अध्यक्ष डा. कर्ण सिंह और छह डच मंत्रियों की उपस्थिति में 12 नवंबर, 2008 को एम्सटर्डम में किया गया। इस उद्घाटन समारोह में लगभग 2000 अतिथिगण उपस्थित थे। इस महोत्सव में 127 कार्यक्रम/प्रदर्शन-शीर्ष भारतीय कलाकारों, संगीतकारों, संगीत आयोजकों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, कई अपनी तरह के अनोखे एवं अकेले कलाकारों की व्यक्तिगत प्रस्तुति, उच्च स्तरीय भारतीय समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी की भागीदारी, शीर्ष फैशन डिजाइनर और शीर्ष फिल्म निर्देशकों द्वारा बनायी फिल्मों की स्क्रिनिंग की गई। भारत महोत्सव से न केवल भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत झलकती है अपितु यह एक बड़ा द्विपक्षीय आर्थिक घटनाक्रम भी होता है जिसमें वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की यात्रा के दौरान नीदरलैंड भारत व्यापार बैठक (एनआईबीएम) और 20-21 नवंबर, 2008 को हुई सी.ई.ओ. गोलमेज बैठक शामिल है। वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम के साथ 30 एस.एम.ई वाले एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी गया था। 300 डच कंपनियों ने इस व्यापार कार्यक्रम में भाग लिया।

नार्वे

सरकारी एवं मंत्री स्तरों पर व्यापक तालमेल हुए। नार्वे के स्टेट सेक्रट्री ऑफ डिफेंस ने मई, 2008 में भारत की यात्रा की और यहां उन्होंने रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की। विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने ओस्लो मे आयोजित भारत-नार्वे संयुक्त आयोग की बैठक के तीसरे सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए जून, 2008 में ओस्लो की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नार्वे के संसद के अध्यक्ष से मुलाकात की और विदेश मंत्री, पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग मंत्री, अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा मंत्री और स्टेट सेक्रेट्री, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय और स्टेट सेक्रेट्री, रक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा की। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री के. सिब्बल जून, 2008 में नार्वे की राजकीय यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान पोलर एंड ग्लेशियल रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने नाई एलसंड में भारतीय रिसर्च केन्द्र 'हिमाद्री ' का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. अंबुमणि रामदौस ने नवंबर, 2008 में नार्वे की यात्रा की। नार्वे-भारत सहभागी पहल (एन.आई.पी.आई.) की संयुक्त संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने अगस्त, 2008 में नार्वे की यात्रा की। भारत-नार्वे जे.डब्ल्यू. जी. की हाइड्रोकार्बन पर चौथी बैठक 11 मार्च 2008 को ओस्लो में संपन्न हुई। विशेष सुरक्षा करार के समझौता ज्ञापन के प्रारूप पर वार्ता के लिए नार्वे के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2008 में भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने नार्वे के विदेश मंत्री से स्विट्जरलैंड में मुलाकात की और एन.एस.जी. में भारत विशेष छूट के लिए नार्वे के समर्थन की मांग की।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच दोनों ओर से विभिन्न स्तरों पर नियमित दौरे हुए हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने मार्च, 2008 में पोलैंड की सद्भावना यात्रा की। रक्षा सहयोग के लिए भारत पोलैंड संयुक्त कार्य दल की बैठक अक्तूबर, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुई। पोलैंड के रक्षा मंत्री की भारत की यात्रा नवंबर, 2008 के प्रथम सप्ताह में हुई।

पोलैंड के उप-आर्थिक कार्य मंत्री श्री एडम जेनफेल्ड ने पुनर्गठित भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक के पहले सत्र में भाग लेने के लिए सरकारी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए मई, 2008 में भारत की यात्रा की। विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर जून, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एन.एस.जी. से छूट प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत ने जुलाई, 2008 में पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत को विशेष छूट प्रदान करने के लिए बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दिया। कोयला राज्य मंत्री माननीय संतोष बागरोडिया ने कराको में 21वें वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस और सोसनोविक, पोलैंड में 9-12 सितंबर, 2008 को आयोजित 'एक्सो-माइनिंग 2008' में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर, 2008 में वारसा में पर्यावरण मंत्रियों की आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया।

भारत की राष्ट्रपति 23-26 अप्रैल, 2009 तक पोलैंड की सफल शासकीय यात्रा पर गए। पोलैंड की गतिमान अर्थव्यवस्था और ई.यू. की सक्रिय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा महत्वपूर्ण रही। माननीया राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान पर्यटन सहयोग एवं स्वास्थ्य और दवाइयों संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

पुर्तगाल

पुर्तगाल के विदेश मंत्री डा. लुइस अमाडो 7-9 जुलाई, 2008 तक भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा फिक्की में भारत-पुर्तगाल व्यापार बैठक के शुरुआती सत्र कोसंबोंधित किया।

भारतीय उद्योग परिसंघ से एक 10 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पुर्तगाल और भारत के बीच मुख्यतः ऑटोमोबाइल सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में व्यापार एवं निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 2-5 जुलाई, 2008 तक लिस्बन की यात्रा की।

रोमानिया

30 नवंबर, 2008 को हुए आम चुनावों के पश्चात 15 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा श्री एमिल बॉक का रोमानिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मनोनयन किया गया। श्री बॉक के नेतृत्व में X सरकार ने संसद में 22 दिसंबर, 2008 को विश्वासमत हासिल किया। इससे पूर्व श्री थियोडोर टोलोजॉन को 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था किंतु उन्होंने 15 दिसंबर को अपना नाम वापस ले लिया जिसके परिणामस्वरूप श्री बॉक को मनोनीत किया गया। आर्थिक एवं वित्त मंत्री श्री वारूजन वोस्गानियन ने 3-4 मार्च, 2008 तक भारत की यात्रा की। सचिव (पश्चिम) श्री नलिन सूरी ने 23 जुलाई, 2008 को रोमानिया की यात्रा की और अपने प्रधानमंत्री का रोमानया के प्रधानमंत्री को लिखा पत्र उन्हें सौंपा जिसमें उन्होंने भारत की असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के लिए समर्थन मांगा था। रोमानिया ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत विशेष छूट के लिए अपना समर्थन दिया था। सचिव (पश्चिम) ने राष्ट्रपति की सलाहकार श्रीमती अन्का इलियाना और प्रधानमंत्री के सलाहकार स्टेजारेल ओलारू के साथ भी बैठकें की। यात्रा के दौरान रोमानिया के साथ विदेश कार्यालय परामर्श भी संपन्न हुआ।

सर्बिया

सर्बिया में मई, 2008 में हुए चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मिर्को स्वेतकोमी के नेतृत्व में नई सरकार ने इस बात को दोहराया कि सर्बिया भारत के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधो को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सर्बिया के विदेश मंत्री वुक जेरेमी ने सितंबर, 2008 में भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विदेश मंत्री के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। बातचीत के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि दोनो देशों के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध वाणिज्यिक संपर्कों में नहीं झलकते हैं और यह अपनी क्षमता से काफी कम हैं। सर्बिया से हुई अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में सर्बिया के मंत्री डा. एना पेसीकॉन द्वारा फरवरी, 2008 में भारत की की गई यात्रा शामिल है। आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत सर्बिया एक सहभागी देश है। सचिव (कृषि) की 1-5 मार्च, 2009 तक की यात्रा के दौरान भारत और सर्बिया के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के एक करार पर बेलग्रेड में हस्ताक्षर किए गए। सर्बिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

स्लोवाकिया

सचिव (ई.आर.) ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई, 2008 में ब्रातिस्लावा की यात्रा और भारत की असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के लिए स्लोवाक गणराज्य का समर्थन मांगा। एन.एस.जी. की सितंबर, 2008 में हुई बैठक में स्लोवाक गणराज्य ने भारत का समर्थन किया और भारत के पक्ष में मतदान किया। वर्ष 2008 के दौरान भारत में स्लोवाक से दो महत्वपूर्ण यात्राएं हुई। स्लोवाकिया संसद के अध्यक्ष पावोल पास्का ने मार्च, 2008 में भारत की यात्रा की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के अलावा उन्होंने राज्यसभा के सभापति श्री हामिद अंसारी और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। स्लोवाक के विदेश मंत्री जान कुबीस ने अप्रैल, 2008 में भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। वार्ता में आपसी रूचि के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का अपने समर्थन को दोहराया।

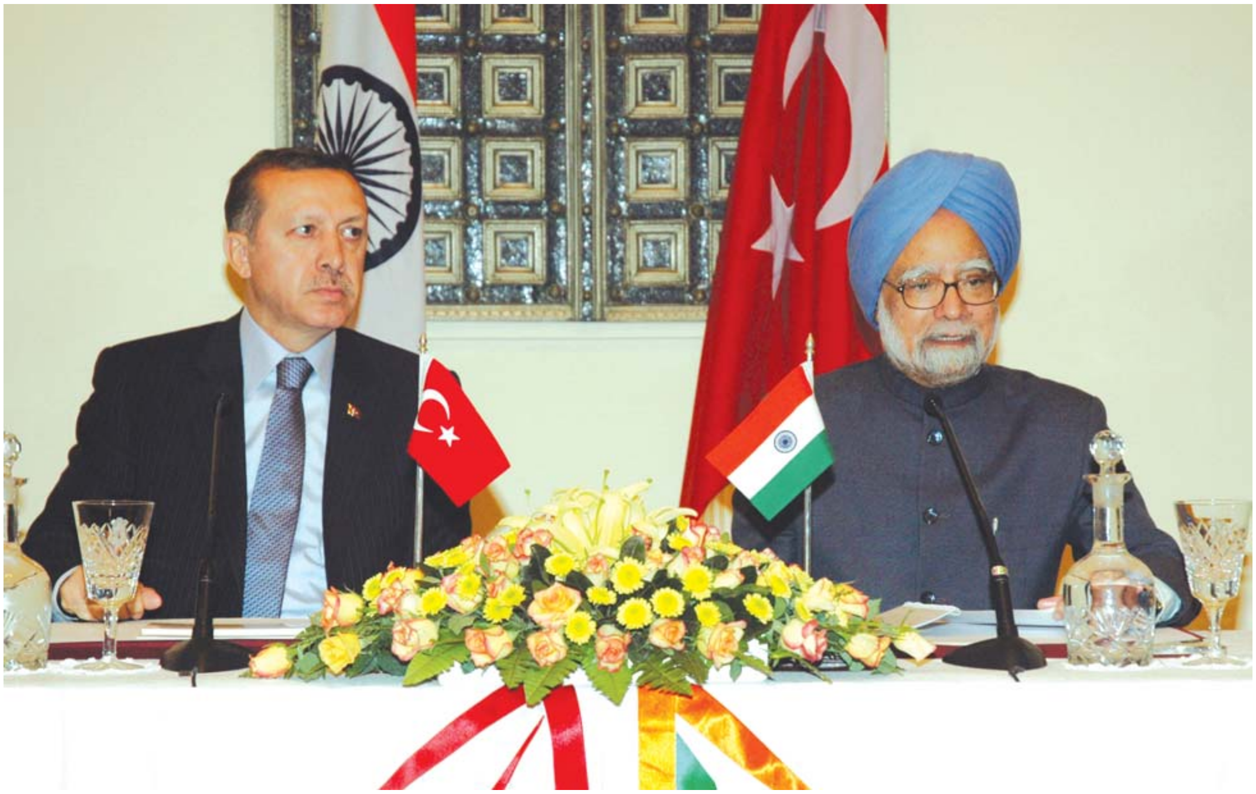

21 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और तुर्की गणराज्य के प्रधानमंत्री रिसीप ताइप इरडोगन।

26 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह
युनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री गार्डन ब्राउन के साथ।

स्लोवेनिया

विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) श्री आनन्द शर्मा ने 30 मार्च-1अप्रैल, 2008 तक जुबलाना की यात्रा की और स्लोवेनिया में हमारे आवासी मिशन के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री ने वहां अपने समकक्षी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। सचिव (ई.आर.) श्री एच.एस. पुरी ने भारत के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग बहाल करने के लिए स्लोवेनिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में स्लोवेनिया की यात्रा की। स्लोवेनिया ने भारत को विशेष छूट दिए जाने के लिए एन.एस.जी. की बैठक में अपना समर्थन दिया। जलवायु परिवर्तन एवं नाभिकीय मसलों पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन ने ब्लेड (स्लोवेनिया) में 31 अगस्त-1 सितंबर, 2008 को आयोजित ब्लेड सामरिक मंच की बैठक में पैनल के सदस्य के रूप में भाग लिया। स्लोवेनिया ने वर्ष 2008 के पूर्वार्द्ध के दौरान छह-छह माह की परिभ्रामी व्यवस्था के तहत ई.यू. की अध्यक्षता ग्रहण की। स्लोवेनिया के विदेश मंत्री डा. डी. रूपेल ने नई दिल्ली में 30 मई, 2008 को आयोजित भारत-ई.यू. मंत्री स्तरीय ट्रोइका बैठक में भाग लिया और साथ ही विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श भी किया।

स्पेन

9 मार्च, 2008 को हुए आम चुनावों में सोसालिस्ट पार्टी पीएसओई ने कांग्रेस ऑफ डिपुटीज में 350 में से 169 सीट जीती। पदस्थ प्रधानमंत्री श्री जोस लुइस रोड्रिगेज जापातेरो को 11 अप्रैल, 2008 को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया।

उप प्रधानमंत्री सुश्री मारिया टेरेसा फर्नान्डीज डी ला वेगा ने 3-9 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित स्पेन से की गई अन्य यात्राओं में शामिल हैः पापुलर पार्टी के नेता और स्पेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जोस मारिया अजनार लोपेज की 16-20 सितंबर, 2008 की यात्रा; मैड्रिड क्षेत्रीय सरकार की अध्यक्ष सुश्री एस्पेटेंजा अगाइर की 23-26 नवंबर, 2008 की यात्रा; स्पेन के उद्योग, पर्यटन एवं व्यापार मंत्री श्री मेगाइल सेबेस्टियन की 10-12 दिसंबर, 2008 को की गई यात्रा।

भारत के वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रियों ने बहुपक्षीय कार्यक्रमों/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए स्पेन की यात्रा की जिसमें उन्होंने इन अवसरों का उपयोग द्विपक्षीय कार्यों के लिए भी किया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने विश्व पर्यटन संगठन के कार्यकारी परिषद की वार्षिक बैठक, वर्तमान में जिसकीअध्यक्षता भारत कर रहा है, में शामिल होने के लिए 13-15 अक्तूबर, 2008 तक मैड्रिड की यात्रा की। संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री जवाहर सरकार ने 28वें अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला मेला (ए.आर.सी.ओ.) के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

स्पेन के विदेश मंत्रालय के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट श्री एंजेल लोस्साडा ने भारत-स्पेन ट्रिब्यून बैठक में भाग लेने के लिए 16-17 अक्तूबर, 2008 तक भारत की यात्रा की।

स्वीडेन

स्वीडेन से कई मंत्रीस्तरीय दौरे भारत के हुए, जिनमें व्यापार मंत्री सुश्री एवा बोर्लिंग (अप्रैल 2008), लोक स्वास्थ्य मंत्री, सुश्री मारिया लार्सन (मई 2008), माइग्रेशन एवं एसाइलम पॉलिसी मंत्री, श्री टोबियास विलस्ट्राम (नवंबर, 2008) और युवरानी विक्टोरिया (अक्तूबर, 2008) शामिल थे। इनमें से कुछ दौरों में महत्वपूर्ण उद्योगों के उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी साथ में थे। व्यापार और निवेश भारत-स्वीडेन ताल-मेल के मुख्य कारक बन रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2001 से लगभग 450% तक बढ़ गया है और वर्ष 2007 में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर गया है। भारत 19 वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार के रूप में उभरा है और एशिया में चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने भारत अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग करार के लिए स्वीडेन का समर्थन प्राप्त करने के लिए जुलाई, 2008 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में स्टॉकहोम की यात्रा की। स्वीडेन ने भारत-अमरीका नाभिकीय करार का एन.एस.जी. में अपना स्पष्ट समर्थन दिया।

स्वीडेन के संसद की विदेश मामलों से संबद्ध स्थायी समिति 11-16 जनवरी, 2009 तक राजकीय यात्रा पर भारत आई। उन्होंने 12 जनवरी, 2009 को भारतीय संसद की विदेश मामलों से संबद्ध स्थायी समिति के सदस्यों से मुलाकात की। दिल्ली के अलावा स्वडेन के सांसदों ने मुम्बई की भी यात्रा की।

स्विट्जरलैंड

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-24 सितंबर, 2008 तक स्विट्जरलैंड की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर (I) कॉटन स्पिनिंग मशीनरी के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड के रायटर ग्रुप के साथ और (II) महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुओनी ट्रैवल (इंडिया) प्रा. लि. के साथ - हस्ताक्षर किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां और प्रदर्शनियों का आयोजन कर वर्ष 2008 में भारत-स्विस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर का 60 वां वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री और स्विस फेडरल काउंसलर मिशेलिन काल्मी रे द्वारा हस्ताक्षरित संदेशों का भी आदान-प्रदान किया गया। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2007 में 2.8 बिलियन डालर पार कर गया। एन.एस.जी. में भारत के लिए विशेष छूट प्राप्त करने के लिए विशेष दूत के रूप में विदेश सचिव ने जुलाई, 2008 में स्विट्जरलैंड की यात्रा की।

टर्की

भारत और टर्की के बीच वर्ष 2008-09 में तालमेल बढ़े हैं। भारत और टर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2007 में 2.65 बिलियन अमरीकी डालर था। टर्की के प्रधानमंत्री रेसीय तय्यीप एरडोआन, तीन वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों और लगभग 120 व्यवसायियों के साथ 21-24 नवंबर, 2008 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री एरडोआन ने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय चर्चा/प्रतिनिधिस्तरीय वार्ताएं हुई। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और विपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी ने भी उनसे मुलाकात की। इससे पूर्व टर्की के विदेश मंत्री अली बाबाकन ने 5-10 फरवरी, 2008 तक भारत की यात्रा की और इस दौरान राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से पारस्परिक उन्मुक्ति पर एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। टर्की के विदेश व्यापार मंत्री कुरोड तुजमेन ने मार्च, 2008 में भारत की यात्रा की। तर्की के साथ विदेश कार्यालय परामर्श मई, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत के असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल के लिए टर्की का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जुलाई, 2008 में अंकारा की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल्लाह गुल, विदेश मंत्री अली बाबाकन से मुलाकात की और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव और प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की। टर्की ने एन.एस.जी. की बैठक में भारत को विशेष छूट दिए जाने के लिए अपना समर्थन दिया था। वायु सेना प्रमुख मार्शल फाली होमी मेजर ने मार्च, 2008 में टर्की की यात्रा की और टर्की के लैंड फोर्सेस कमांडर जनरल इडोआन बालाउलु ने मई, 2008 में भारत की यात्रा की।

यूनाइटेड किंगडम

प्रधानमंत्री ने जी-20 शिखर बैठक के दौरान 1 अप्रैल, 2009 को लंदन में यू.के. के प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्री नियमित रूप से टेलीफोन पर संपर्क में रहे।

यू.के. के विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड 13-15 जनवरी, 2009 को भारत आए। भारत-यू.के. विदेश कार्यालय परामर्श 6 फरवरी, 2009 को लंदन में संपन्न हुआ।

आतंकवाद से मुकाबला करने संबंधी भारत-यू.के. संयुक्त कार्यदल की बैठक 2 दिसंबर, 2008 को और सामरिक वार्ता 3 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में हुई। रक्षा सचिव स्तरीय रक्षा परामर्शदात्री दल की बैठक 20 मई, 2008 को हुई। इससे पूर्व 19 मई, 2008 को रक्षा उपकरण उप-दल की बैठक हुई।

संसदीय संपर्क नियमित दौरों के माध्यम से मजबूत हुए हैं। भारत सरकार के निमंत्रण पर तीनों भारत मित्र समूहों- लेबर (10-17 फरवरी, 2008), लिबरल डेमोक्रेटिक (1-6 सितंबर, 2008) और कंजर्वेटिव (27 नवंबर- 2 दिसंबर, 2008) पार्टियों ने भारत की यात्रा की। मंत्रीस्तरीय दौरों का आदान-प्रदान हुआ जिनमें भारत निवेशक शिखर बैठक (19-21 मई, 2008) के लिए उद्योग राज्य मंत्री डा. अश्विनी कुमार की यात्रा; पहला भारत-स्कॉटलैंड व्यापार मंच (13 जून, 2008) के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल की यात्रा, खेल कूद राज्य मंत्री डा. एम.एस. गिल, (2-4 जुलाई, 2008); राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की बैठक (7-10 जुलाई, 2008) में भाग लेने के लिए कानून मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज की यात्रा; भारत-यू.के. आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की दूसरी बैठक और पी.पी.पी.(सार्वजनिक निजी साझेदारी) के विकास में श्रेष्ठ रीतियों को बांटने को प्रोत्साहन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित रहने के लिए (11 अगस्त, 2008 को) श्री पी. चिदम्बरम की यात्रा; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ (11-14 सितम्बर, 2008) और लंदन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक (19 दिसंबर, 2009) में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा की यात्रा शामिल है। यू.के. से भारत आने वाले मंत्रियों में न्याय मंत्री श्री जैक स्ट्रा (13-15 सितंबर, 2008); समुदाय एवं स्थानीय सरकार मंत्री हाजेल ब्लियर्स (30-31 जुलाई, 2008); डी.एफ.आई.डी. मंत्री डगलस एलेक्जेंडर (17-19 नवंबर, 2008); और व्यापार उद्यम और विनियामक सुधार सेक्रेट्री पीटर मैनडेलसन (संभावित 19-23 जनवरी, 2009)। प्रधानमंत्री श्री ब्राउन कार्य दौरे पर 13 दिसंबर, 2008 को भारत आए।

यू.के. भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और यू.के. द्वारा अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2008 तक संचित निवेश 5058 मिलियन अमरीकी डालर था। भारत यू.के. में तीसरे सबसे बड़े विदेशी निवेशक और अधिग्रहण/निवेश की संख्या के आधार पर लंदन और उत्तरी आयरलैंड में दूसरे सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में उभरा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 9 बिलियन पौंड की संयुक्त बाजार कैप के साथ 52 भारतीय कंपनियां दर्ज हैं। भारतीय फर्मों ने एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो कुल 3 बिलियन पौंड की राशि खड़ी की है। मार्च, 2008 में टाटा ने 2.3 बिलियन पौंड में जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया है।

यू.के. भारत शिक्षा मंच की पहली बैठक 26 सितंबर, 2008 को लंदन में संपन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सहयोगी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक सरकार स्तरीय संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाएगा।

11वां भारत-यू.के. गोलमेज भारत के शिमला में 2-5 मई, 2008 को संपन्न हुआ।

यूरोपीय संघ

भारत और यूरोपीय संघ उभरते बहु-ध्रुवीय व्यवस्था में अपरिहार्य ध्रुव हैं। अभी भी यूरोपीय संघ लिस्बन संधि पर आयरिश "नहीं" प्रस्ताव को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा लिस्बन संधि के अनुसमर्थन संबंधी कार्यवाही चल रही है और उनमें से अधिकांश द्वारा यह कार्यवाही कर ली गयी है, किंतु इस पर हस्ताक्षर के लिए आयरलैंड में एक और

जनमत के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, जो संभवतः 2009 में होगा। लिस्बन संधि का लक्ष्य यूरोपीय संघ संस्थागत संरचनाओं में सुधार करना है, ताकि यूरोपीय संघ का तेजी से विस्तार दवाब का सामना किया जा सके और इसकी नीतियों के बेहतर समंजन के लिए आंतरिक समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने और उसकी बाह्य नीतियों को और प्रभावी स्वरूप दिया जा सके।

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2007 में 55 बिलियन यूरो पार कर गया और अगले 5 वर्षों में 100 बिलियन यूरो तक पहुंचने का इसका लक्ष्य है। भारत और यूरोप काफी गतिशील निवेश संबंधों का साक्षी रहे हैं। यूरोप से भारत के लिए मुख्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के स्रोत देशों में है - यू.के. (5.06 बिलियन अमरीकी डालर) नीदरलैंड (3.41 बिलियन अमरीकी डालर), जर्मनी (2.07 बिलियन अमरीकी डालर), साइप्रस (1.5 बिलियन अमरीकी डालर), फ्रांस (1.05 बिलियन अमरीकी डालर) और स्विट्जरलैंड (0.74 बिलियन अमरीकी डालर); कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2000 से सितंबर, 2008 तक की अवधि के संचित एफडीआई आगम को दर्शाते हैं। भारत से बाहरी निवेश विशेष रूप से यू.के. (अधिग्रहण के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा) जर्मनी और इटली में निरंतर बढ़ रहा है।

व्यावसायिकों के लिए कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाने के लिए भारत और यूरोप के उसके सहभागी देश सामाजिक सुरक्षा करार पर बातचीत कर रहे हैं। भारत के साथ ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने वाला बेल्जियम पहला देश था, इसके पश्चात फ्रांस ने 30 सितंबर, 2008 को, नीदरलैंड ने इस संबंध में बातचीत पूरी कर ली है और जर्मनी ने 8 अक्तूबर, 2008 को सामाजिक बीमा पर एक करार पर हस्ताक्षर करने के बाद एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा करार पर बातचीत शुरू की है। सांस्कृतिक महोत्सवों, वैज्ञानिक एवं छात्रों के आदान-प्रदान पर नियमित रूप से ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी छोटे-छोटे सुधारों के बावजूद यूरोपीय संघ में भारत से लोगों का आवाजाही पर बाधाएं चिंता का विषय रही है और इसका भी संतोषजनक हल ढूंढ़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 29 सितंबर, 2008 को 9वीं भारत-ई.यू. शिखर बैठक के लिए मार्शिले, फ्रांस की यात्रा की। शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी की ई.यू./फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैनुएल बारोसो से चर्चा हुई। इस शिखर बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2005 की भारत-ई.यू. संयुक्त कार्य योजना की समीक्षा की गई और नए क्षेत्रों में सामरिक सहभागिता का विस्तार करने के लिए एक संशोधित योजना जारी की गई; 28 सितंबर, 2008 को हस्ताक्षरित भारत-ई.यू. क्षैतिज नागर विमानन करार के हस्ताक्षर पर ध्यान दिया; ऊर्जा, स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य कार्यक्रम जारी किया गया; वर्ष 2009 के दौरान बी.टी.आई.ए. (व्यापक व्यापार एवं निवेश करार) को संपन्न करने की सहमति हुई; और अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के लिए 100 बिलियन यूरो के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। संयुक्त कार्य कार्यक्रम में अन्य चीजों के साथ-साथ साफ कोयला प्रौद्योगिकी, ऊर्जा प्रभाविता, फ्यूजन इनर्जी रिसर्च और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ यूराटोप और भारत के बीच फ्यूजन इनर्जी रिसर्च सहयोग करार को संपन्न करने में सहयोग की की बात कही गयी है। इस शिखर बैठक में एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति अंगीकार की गई। प्रधानमंत्री 30 सितंबर, 2008 को पेरिस में आयोजित "न्यू सिनर्जीस फॉर पार्टनरशिप" नामक भारत-ई.यू. व्यापार शिखर बैठक में भी सम्मिलित हुए।

भारत-ई.यू. ट्रोइका विदेश मंत्री स्तरीय 19 वीं बैठक 30 मई, 2008 को नई दिल्ली में हुई। यूरोपीय संसद के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए जून, 2008 में भारतीय संसद ने एक 22 सदस्यों वाले भारतीय संसदीय मैत्री दल का गठन किया; श्री वी.किशोर चन्द्र एस. देव (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) इस दल के अध्यक्ष हैं जबकि डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (भाजपा) और श्री सुरेश कुरूप (सीपीआई-एम) इस दल के उपाध्यक्ष हैं। भारत-ई.यू. सामरिक वार्ता 5 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

भारत-ई.यू. सुरक्षा वार्ता 5 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

भारत-ई.यू. ऊर्जा पैनल की बैठक का चौथा दौर 8 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसमें दोनों पक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ सोलर फोटोवोल्टैइक्स पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का पता लगाने; ऊर्जा प्रभाविता/स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने और उसे सुदृढ़ करने; और फ्यूजन इनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में यूराटोम और भारत के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय करार पर बातचीत की गति तेज करने; असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

कोंसली मुद्दों पर भारत-ई.यू. संयुक्त कार्य दल की 11वीं बैठक 23 मई, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में कोंसली मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें वीजा और कार्य परमिट को सुविधाजनक बनाने और उन्हें शीघ्रता से जारी किए जाने के मुद्दे भी शामिल थे। भारत-ई.यू. सिविल सोसायटी गोलमेज की 12वीं बैठक 15-16 जुलाई, 2008 को पेरिस में हुई। मानवाधिकार पर भारत-ई.यू. तदर्थ वार्ता की पांचवीं बैठक 27 फरवरी, 2009 को संपन्न हुई।

अमरीका

8

संयुक्त राज्य अमरीका

वर्ष 2008 में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय कार्यकलाप और संवर्धित हुए। भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर 10 अक्तूबर, 2008 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया जाना प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की जुलाई, 2005 में अमरीका की यात्रा के दौरान घोषित असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल की निष्पत्ति थी। यह द्विपक्षीय वार्ता के रूपांतरित स्वरूप का प्रतीक है और इसने विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को सामरिक आयाम दिया है। इसने द्विपक्षीय आर्थिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी तालमेल के लिए विशाल अवसर का द्वार खोला है। आर्थिक एवं वाणिज्यिक संपर्क, रक्षा सहयोग और लोगों का लोगों से संपर्क द्विपक्षीय कार्यसूची के प्राथमिकता वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, आम चिंता के वैश्विक मुद्दों पर भारत-यू.एस परामर्श और अन्यों के साथ-साथ ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय पहल के लिए वार्ताएं, कार्य योजना भारत-यू.एस. संपर्कों को न केवल मजबूत बनाया बल्कि उसमें नए अर्थ जोड़ना जारी रखा।

उच्च स्तरीय दौरे

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 24-25 मार्च को वाशिंगटन डी.सी. की यात्रा की। उन्होंने अपने समकक्ष डा. कोंडोलीजा राइस से मुलाकात की और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से भी मुलाकात की। उन्होंने वाशिंगटन स्थित विचार-मंच क्रेनेजी प्रतिष्ठान में विद्वानों के एक चुने हुए दल के साथ बातचीत भी की।

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 25 सितंबर,2008 को वाशिंगटन की यात्रा की और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से भेंट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की और प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान 18 जुलाई, 2005 और राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान जारी 2 मार्च, 2006 के संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित द्विपक्षीय कार्यसूची की उपलब्धियों और उन पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने नवाचार एवं ज्ञान, स्वास्थ्य, उच्च प्रौद्योगिकी के व्यापार, अंतरिक्ष, कृषि, जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा और पर्यावरण, रक्षा, आतंकवाद का सामना करने इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और साथ ही दोनों देशों द्वारा अपनी-अपनी सामरिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश ने सराहना करते हुए आशा की कि भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन भविष्य में संबंधों को निरंतर मजबूत बनाने के लिए आधार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा भारत के लिए अपने दिशानिर्देशों में छूट दिलवाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदत्त सहायता के लिए राष्ट्रपति बुश के प्रति अपना आभार प्रकट किया। दोनों नेताओं ने दोहा चक्र, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सहित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार का भी आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने 26 सितंबर, 2008 को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया जिसमें सं.रा.अमरीका के अटलांटा और सिएटल में दो अतिरिक्त भारतीय कोंसलावासों को खोलने की घोषणा की।

यू.एस. की सेक्रेट्री ऑफ स्टेट डा. कोंडोलीजा राइस ने 4-5 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और सेक्रेट्री राइस ने उच्च प्रौद्योगिकी वाले सहयोग, शिक्षा और लोगों का लोगों के साथ संपर्क और रक्षा संबंधों जैसे आपसी रूचि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग करार को निष्कर्ष तक लाने और भारत-अमरीका संबंधों को रूपांतरित करने में यू.एस. सरकार द्वारा समर्थन देने के लिए भारत के आभार से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने महसूस किया कि अंतिम कुछ वर्षों के दौरान भारत-अमरीका संबंध मजबूत हुए और काफी बढ़े हैं। दोनों नेताओं ने यह आशा व्यक्त की कि भारत और अमरीका में उत्तरवर्ती सरकारें इस ठोस नींव पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति पर और आतंकवाद का मुकाबला करने, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जैसे विश्व चिंता के मुद्दों पर भी चर्चा की। सेक्रेट्री सुश्री राइस ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलीं।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जी-20 शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 14-15 नवंबर, 2008 को वाशिंगटन, यू.एस.ए. की यात्रा की। शिखर बैठक में जी-20 देशों के नेताओं ने वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने के लिए उपाय करने की प्रतिज्ञा की और विश्व की प्रगति बहाल करने और विश्व की वित्तीय प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाने के लिए मिल कर कार्य करने और सहयोग को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त

की। वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर बैठक का एक घोषणा-पत्र इस अवसर पर जारी किया गया।

मुम्बई आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए संवेदना प्रकट करने और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए डा. कोंडोलीजा राइस, यू.एस. सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ने पुनः 3-4 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम और विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारतीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने मुम्बई हमले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में भारत के प्रयासों में अमरीका की सरकार के समर्थन की पेशकश की। सेक्रेट्री राइस ने आतंकवाद की त्रासदी से लड़ने में भारत को अपनी सरकार द्वारा निरंतर समर्थन देने को दोहराया।

विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन ने 2 दिसंबर, 2008 को वाशिंगटन की यात्रा की और अपने अमरीकी समकक्ष श्री विलियम बर्न्स, राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेट्री, यू.एस.स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात की और भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

असैनिक नाभिकीय सहयोग

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ 1 अगस्त, 2008 को भारत विशेष सुरक्षोपाय करार सफलतापूर्वक संपन्न किया जिससे कि अमरीका के लिए एन.एस.जी. दिशानिर्देशों के समंजन के लिए 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह से संपर्क साधने का मार्ग खुल गया जिससे कि उसके सदस्यगण भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग और व्यापार करने में समर्थ हो सके। 6 सितंबर, 2008 को एन.एस.जी. सर्वसम्मति द्वारा एसे समायोजन करने पर सहमत हो गया जिससे कि भारत पर अपने द्वारा लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की मनाही और अलग-थलग करने की 34 वर्षों का युग समाप्त हो गया। इस कदम के पूरा होते ही जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के भारत-अमरीका सहमति के अनुसार अमरीका की सरकार तब भारत-अमरीका असैनिक-नाभिकीय करार को अनुमोदनार्थ अमरीकी कांग्रेस के पास ले गई। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने 28 सितंबर, 2008 को करार पर संबंधित बिल को मंजूरी दे दी और अमरीकी सीनेट ने इसे 1 अक्तूबर, 2008 को पारित कर दिया। 8 अक्तूबर, 2008 को अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमरीकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर विधायक हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। करार पर विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और उनके अमरीकी समकक्ष सेक्रेट्री ऑफ स्टेट डा. कोंडोलीजा राइस के औपचारिक हस्ताक्षर 10 अक्तूबर, 2008 को वाशिंगटन मे हुए।

डा.डेविड ई. क्लीन,अमरीकी विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने 17-21 नवंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने मुम्बई में "टोपिकल इस्यूज इन न्यूक्लियर इंस्टालेशन सेफ्टी" पर आईएईए सम्मेलन में भाग लिया और नाभिकीय सुरक्षा और विनियामक मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग के आगे बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की।

ऊर्जा वार्ता

भारत-अमरीका ऊर्जा वार्ता की स्थायी समिति की तीसरी बैठक 4 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। (i) तेल एवं प्राकृतिक गैस, (ii) कोयला, (iii) विद्युत एवं ऊर्जा प्रभावकारिता और (iv) नई प्रौद्योगिकी और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित होते हुए कार्यदल की 31 मार्च-3 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों पक्ष सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा प्रभावकारिता और ऊर्जा सुरक्षा के साझे उद्देश्य की दिशा में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग प्रदान करने में अनेक समयबद्ध कार्यों को करने के लिए सहमत हैं।

व्यापार एवं अर्थव्यवस्था

अमरीका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बना हुआ है। भूतपूर्व सेक्रेट्री ऑफ स्टेट श्री स्ट्रॉब तालबट्ट के नेतृत्व में ब्रूकिंग्स संस्थान, वाशिंगटन डीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 15-29 जनवरी 2008 तक भारत की यात्रा की। कार्यकारी सहायक व्यापार प्रतिनिधि श्री क्लाउरियो लिलियेनफील्ड के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ 12-13 फरवरी, 2008 को द्विपक्षीय निवेश संधि पर शुरूआती बातचीत की।

अमरीकी अंडर सेक्रेट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी डेविड मैककार्मिक ने 22-24 अप्रैल, 2008 को भारत की यात्रा की और वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। डान सुल्लीवन अमरीकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और व्यापार मामलों के लिए सहायक स्टेट सेक्रेट्री ने 21-23 मई, 2008 तक भारत की यात्रा की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने 11-12 जून, 2008 को वाशिंगटन की यात्रा की। श्री कमलनाथ ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सुसन सी. स्वाब से 12 जून, 2008 को मुलाकात की और कैसे दोहा विकास कार्यसूची को आगे बढ़ायी जाए, इस पर चर्चा की। श्री कमलनाथ ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर श्री एड शाफर, अमरीकी कॉमर्स सेक्रेट्री श्री कार्लोस गुटयरेज, राजदूत रॉब पोर्टमैन, भूतपूर्व यूएसटीआर, कांग्रेसमैन गैरी एकरमैन, मध्यपूर्व और दक्षिणी एशिया पर सदन की उपसमिति के अध्यक्ष और कांग्रेसमैन जिम मैकडर्मट, भारत और भारतीय अमरीकियों पर कांग्रेसी काकस के अध्यक्ष से भी मुलाकात की।

भारत-अमरीका वित्तीय एवं आर्थिक मंच की तकनीकी स्तर की बैठक जून, 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुई। फिक्की द्वारा एक भारत-अमरीका बायोफार्मा शिखर बैठक 12-14 जून, 2008 को बोस्टन में आयोजित की गई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री

मोंटेक सिंह अहलुवालिया भारत-अमरीका आर्थिक वार्ता के भारतीय सह-अध्यक्ष ने 8-10 अप्रैल, 2008 को वाशिंगटन की यात्रा की और अपने समकक्ष श्री डान प्राइस, राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के लिए अमरीकी राष्ट्रपति के सहायक के साथ चर्चा की।

प्रस्तावित भारत-अमरीका द्विपक्षीय निवेश संधि पर प्रारंभिक वार्ता का दूसरा दौर 11-13 जून, 2008 को वाशिंगटन में संपन्न हुआ।

अमरीका सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और भारत के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के बीच टोटलाइजेशन करार पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्ग बनाने हेतु भारत-अमरीका सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर अनौपचारिक चर्चा का दूसरा दौर 24-26 जून, 2008 को वाशिंगटन में संपन्न हुआ।

छठा भारत-अमरीका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य दल की बैठक 30 जून-2 जुलाई, 2008 को वाशिंगटन में हुई। बैठक में आई.टी., आई.टी.ई.एस., ई-कॉमर्स और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

वाणिज्य विभाग के सहायक सचिव श्री डेविड बोहीगन के नेतृत्व में अमरीका से पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 7-12 सितंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की।

अमरीका प्रथम द्विवार्षिक नागर विमानन प्रदर्शनी-भारत विमानन, 2008 जो कि 15-18 अक्तूबर, 2008 तक हैदराबाद में आयोजित की गई थी, में सहभागी देश था। 20 अमरीकी विमानन कंपनियों सहित एक बड़ा अमरीकी प्रतिनिधिमंडल विमानन उद्योग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्पाद और सेवाओं को प्रर्दशित करते हुए प्रदर्शनी में भाग लिया। भारत-अमरीका विमानन संचालन समिति की दूसरी बैठक हैदराबाद में 14 अक्तूबर को संपन्न हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीका ने भारत सरकार, नई दिल्ली के नागर विमानन महानिदेशालय के साथ 5-6 नवंबर, 2008 को द्विपक्षीय चर्चा की। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन से जुड़े सुरक्षा के मसलों पर भी विचार किया।

अमरीका के सहायक ट्रेड प्रतिनिधि श्री मिशाएल डेलाने ने 4-5 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने वाणिज्य, वित्त एवं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

भारत-अमरीका सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्य दल की 7वीं बैठक 10 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने, नम्य, ठोस सूचना प्रौद्योगिकी करार का क्रियान्वयन और कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर करों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा केंद्रित थी।

भारत में असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों का पता लगाने के लिए अमरीका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) और नाभिकीय ऊर्जा संस्थान, वाशिंगटन के नेतृत्व में एक असैनिक नाभिकीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 11-17 जनवरी, 2009 तक नई दिल्ली, मुम्बई और हैदराबाद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) श्री पृथ्वीराज चव्हाण और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग डा. अनिल काकोदकर से मुलाकात की। असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पर सीआईआई-यूएसआईबीडीसी संयुक्त कार्यदल की बैठक में इस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और ऊर्जा क्षेत्र में लगी कई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठकें की।

रक्षा संबंध

अमरीका से रक्षा प्रापण से संबंधित विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए भारत-अमरीका रक्षा प्रापण एवं उत्पादन दल की 7-11 अगस्त, 2008 को नई दिल्ली में बैठक हुई।

अमरीकी रक्षा सेक्रेट्री राबर्ट गेट्स की फरवरी, 2008 में हुई भारत की यात्रा के प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी ने 8-11 सितंबर, 2008 तक अमरीका की यात्रा की। उन्होंने चल रही द्विपक्षीय वार्ता की समीक्षा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए अमरीकी डिफेंस सेक्रेट्री, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हवाई दुर्घटना में मारे गए अमरीकी वायु सैनिकों के अवशेष को प्राप्त करने के लिए भारत और अमरीका ने 15 अक्तूबर-21 नवंबर, 2008 तक अमरीकी संयुक्त पेसीफिक एक्शन कमांड (जे.पी.ऐ.सी.) की सहभागिता से भारत और अमरीका ने अरूणाचल प्रदेश में एक संयुक्त खोजी अभियान चलाया। अमरीका के सेनाध्यक्ष जनरल जार्ज डब्ल्यू कैसी ने अपने भारतीय समकक्ष के निमंत्रण पर 16-18 अक्तूबर, 2008 को दिल्ली और आगरा की यात्रा की और सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव के साथ बातचीत की। उन्होंने उत्तरी मुख्यालय में 14 वें कार्प्स का दौरा किया। उनकी इस यात्रा से अमरीका के साथ चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा करने का अवसर मिला।

भारत और अमरीका ने द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास नामतः युद्ध अभ्यास (सेना, हवाई, अमरीका अक्तूबर-नवंबर 2008), बज्र प्रहार (सेना, वैरनगेट, भारत और गुआम, अमरीका, अगस्त, 2008) मालाबार (नौसेना, ऑफ गोवा, अक्तूबर, 2008) और हबुनाग (विशाखापटनम, सितंबर, 2008) में भाग लिया। भारत ने नेलीस वायुसेना बेस, अमरीका में अगस्त, 2008 में आयोजित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग में भी भाग लिया।

अमरीका के संयुक्त सेना प्रमुख समिति के अध्यक्ष एडमिरल मिशाएल मुल्लेन ने 3-4 दिसंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की और रक्षा मंत्री, नौसेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।

वैश्विक मुद्दों पर बातचीत

भारत-अमरीका वैश्विक मुद्दा मंच की छठी बैठक 24 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। आम रूचि के वैश्विक मुद्दों जैसे कि लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना, एवियन फ्लू को नियंत्रित करना और भविष्य में महामारी का शमन करना; पोलियो को समाप्त करने के अभियान की गति तीव्र करना; जलवायु परिवर्तन का हल ढूढ़ना, खाद्यान्न सुरक्षा, आपदा प्रबंधन में सहयोग, खतरे में पड़े जंगली जीव-जंतु की सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने पर सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।

व्हाइट हाउस, अमरीका के पर्यावरणात्मक गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष श्री जेम्स कनॉटन ने भारत के नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 15-18 जून, 2008 तक नई दिल्ली और कोलकाता की यात्रा की। उन्होंने पर्यावरण राज्य मंत्री और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन से मुलाकात की।

शांतिरक्षा पर भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल की 8वीं बैठक 12-13 मई, 2008 को वाशिंगटन में संपन्न हुई। आतंकवाद पर भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल की 10वीं बैठक 25 अगस्त, 2008 को दिल्ली में संपन्न हुई।

अमरीकी स्टेट विभाग के पुनर्निर्माण एवं स्थिरीकरण कार्यालय के समन्वयकर्ता राजदूत जॉन हर्बस्ट 6-7 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली आए। उन्होंने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की जिसमें उन्होंने अमरीकी सरकार द्वारा युद्ध के उपरांत तथा युद्ध से पीड़ित समाज जैसे कि इराक और अफगानिस्तान में चलाए जा रहे पुनर्निर्माण एवं स्थिरीकरण के प्रयासों की जानकारी दी।

अमरीकी उप स्टेट सेक्रेट्री श्री जॉन डी. निग्रोपोन्टे ने भारत-अमरीका सामरिक साझेदार को आगे बढ़ाने और आतंकवाद का सामना करने में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए 12 दिसंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और विदेश सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।

श्री मिशाएल मैककोनेल, अमरीकी राष्ट्रीय आसूचना निदेशालय के निदेशक ने 22-23 दिसंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। उन्होंने गृहमंत्री से मुलाकात की और भारत-अमरीका सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद का मुकाबला करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विचार-विमर्श किया।

उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग

भारत-अमरीका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल की छठी बैठक 28-29 फरवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत की ओर से इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश सचिव और अमरीका की ओर से वाणिज्य विभाग के अंडर सेक्रेट्री ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री श्री मारियो मानसुसो ने की।

अमरीका के सान डियागो में 18 जून, 2008 को आयोजित बीआईओ 2008 सम्मेलन के दौरान भारत-अमरीका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग लघुदल की एक बैठक हुई। इस बैठक में रसायन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन स्थित अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की।

अमरीकी वाणिज्य विभाग ने उप सहायक सचिव श्रीमती होली वाइनयार्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिक्ल्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए 23-27 अगस्त, 2008 तक भारत की यात्रा की। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग और भारत-अमरीका व्यापार परिषद द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण पर एक गोलमेज का आयोजन किया गया।

शिक्षा सहयोग

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत सरकार के बीच कतिपय शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के वित्त पोषण करने संबंधी करार पर 4 जुलाई, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार वर्ष 1963 में संशोधित फुलब्राइट करार का स्थान लिया (पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन भारत के अमरीकी राजदूत श्री लोए हेंडरसन के बीच 1950 में पहली बार हस्ताक्षर होने के पश्चात)। नए करार में (i) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय अंशदान; (ii) भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठान के शासी मंडल की भारत सरकार द्वारा सह-अध्यक्षता; (iii) भारत-अमरीका कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय और अमरीकी विद्वानों के आदान-प्रदान पर नीति एवं निर्णय लेने में समान रूप से भाग लेना। इस प्रतिष्ठान को अब अमरीका भारत शैक्षणिक प्रतिष्ठान कहा जाएगा जो 'फुलब्राइट - जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति एवं अनुदान' पुरस्कार देगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल की 13 जून, 2008 को मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी), अमरीका की यात्रा के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एमआईटी के बीच सहयोग की संभावना पर विचार किया गया। एमआईटी ने एमआईटी ऊर्जा पहल नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है। दोनों पक्षों ने इस पहल के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक दल बनाने का प्रस्ताव किया है। जिसमें दोनों ओर से तीन-तीन सदस्य होंगे। डी.एस.टी. के पूर्व सचिव डा. आर. रामचंद्रन से भारतीय पक्ष का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया है। वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक भारत-अमरीका अक्षय कोष सृजित करने संबंधी एक करार दोनों पक्षों के विचाराधीनहै। डी.एस.टी. और ओहायो राज्य विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन विचाराधीन है और उस पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार, भारत-अमरीका

4 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश मंत्री डा. कोंडोलिजा राइस प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात करते हुए।

10 नवंबर, 2008 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत में कनाडा के उच्चायुक्त जोजफ कैरोन राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करते हुए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच और डी.एस.टी. और राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, अमरीका के बीच सहभागिता जैसे प्रयोजनों के लिए स्थापित विभिन्न द्विपक्षीय रूपरेखाओं के अंतर्गत भारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग जारी रहा।

फोटोभारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच के बोर्ड की 10वीं बैठक 8 दिसंबर, 2008 को आईआईटी कानपुर में हुई। बोर्ड में द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने और भावी सहयोग की कार्यसूची तय करने में मंच की उपलब्धियों पर चर्चा की गई।

कांग्रेसजनों/संसद सदस्यों के दौरे

भारत सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करने और दक्षिणी एशिया पर भारतीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से 20 फरवरी को अमरीकी कांग्रेस के सीनेटरों ने भारत का दौरा किया।

अमरीकी स्पीकर सुश्री नैन्सी पेलोसी 19-25 मार्च तक भारत की यात्रा पर आयीं। उनके साथ एक दस सदस्यीय कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत श्री श्याम सरन से मुलाकात की। वे धर्मशाला गयीं और परम माननीय दलाईलामा से मिली।

तीन अमरीकी कांग्रेसजनों के प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2008 के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया। सीनेटर बेंजामिन नेलसन के नेतृत्व में कांग्रेसजनो के एक प्रतिनिधि मंडल ने 25-26 मई, 2008 तक भारत का दौरा किया। उनके साथ तीन कांग्रेस जन भी भारत आए। सीनेटर राबर्ट केसी और सीनेटर रसेल फिनगोल्ड ने 28-30 मई, 2008 तक भारत की यात्रा की। कांग्रेस के इन प्रतिनिधिमंडलों ने क्षेत्र के बारे में हमारी समझ जानने के लिए शीर्ष नेताओं के साथ जिनमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं, बातचीत की।

प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय मामलों के मंत्री श्री व्यालार रवि के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 13-23 सितंबर, 2008 तक सद्भावना दौरे पर न्यूयार्क, वाशिंगटन और लास एंजेल्स की यात्रा की।

अमरीकी सीनेट विदेशी संबंध समिति केअध्यक्ष सीनेटर जॉन केरी ने 13-15 दिसंबर, 2008 तक भारत का दौरा किया और आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत-अमरीका संबंधों के भविष्य पर भारतीय राजनीति के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

सीनेट सशस्त्र सेवा समिति में उच्च दर्जा प्राप्त रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन मैक्केन, सीनेटर जोसेफ लाइबरमैन (सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य, सीनेट होमलैंड सिक्योरिटी एडं गवर्नमेंट अफेयर्स समिति के अध्यक्ष) और सीनेटर लिंडसे ग्राहम (सीनेट सशस्त्र सेवा समिति और सीनेट सेलेक्ट इंटेलीजेंस समिति के सदस्य) ने 2 दिसंबर, 2008 को भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ भेंट की और भारत-अमरीका संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

कृषि सहयोग

भारत-अमरीका कृषि ज्ञान पहल के बोर्ड की छठी बैठक 15-16 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बोर्ड में मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता निर्माण, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन; जल प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।

कनाडा

कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर के नेतृत्व में कनाडा की सरकार द्वारा भारत के साथ कनाडा के संबंधों को विदेश नीति की प्राथमिकता के स्तर पर रखना जारी रखने के साथ वर्ष के दौरान कनाडा के साथ भारत के संबंध पुनः काफी ऊर्जावान हुए।

शासनप्रमुखों की वार्ता

जुलाई, 2008 में होक्काइडो (जापान) में आयोजित जी-8 शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूचि के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, साझे हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और भारत-कनाडा द्विपक्षीय कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने वैश्विक वित्तीय संकट पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को 3 नवंबर, 2008 को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेता जी-20 की वाशिंगटन में हुई बैठक के दौरान 15 नवंबर, 2008 को मिले।

दौरे

कनाडा के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम बर्नीयर ने 10-12 जनवरी तक भारत की यात्रा की। कनाडा के नागरिकता एवं उत्प्रवासन उप मंत्री श्री रिचर्ड बी फैडेन ने 12-18 जनवरी तक भारत का दौरा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और अटलांटिक कनाडा अपार्टुनिटीज एजेंसी मंत्री श्री पीटर मैके ने 18-22 फरवरी तक भारत की यात्रा की।

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट (विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) सुश्री हेलेना गुर्जीस ने 15-16 अप्रैल, 2008 तक भारत की यात्रा की। नई दिल्ली में सुश्री गुर्जीस ने विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री एम.एस. गिल और उद्योग राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार से मिलीं। उनकी यात्रा के दौरान आपसी रूचि के मुद्दों पर चर्चा की गई।

श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशेष सुरक्षा करार के लिए और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह से जिसका कि कनाडा भी

सदस्य है, छूट प्राप्त करने के लिए कनाडा का समर्थन प्राप्त करने के लिए 28-29 जुलाई, 2008 को कनाडा की यात्रा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर से भेंट करने के अलावा कनाडा के रक्षा मंत्री श्री पीटर मैके जन सुरक्षा मंत्री श्री स्टॉकवेल डे और विदेश मंत्री श्री डेविड एमर्सन से मुलाकात की। आईएईए में भारत विशेष सुरक्षा करार पर कनाडा द्वारा समर्थन देने और कनाडा द्वारा भारत के साथ नाभिकीय व्यापार करने की अनुमति देने के निर्णय में एनएसजी की सर्वसम्मति में उसके जुड़ने से भारत और कनाडा के संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

कनाडियन स्कूल ऑफ पब्लिक सर्विसेज एडवांस्ड लीडरशिप कार्यक्रम के तत्वाधान में लोक सेवा के 27 कार्यपालकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-22 नवंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की।

विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत कनाडा के म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन के अनुसंधान एवं संग्रह महानिदेशक डा. स्टीफेन इंग्लीस ने 24 सितंबर-7 अक्तूबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, बनारस हिंदु विश्वविद्यालय और इतिहास विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय में वक्तव्य दिया और विरासत एवं संस्कृति में भारत-कनाडा संपर्को को बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने 'कनाडा और भारत में स्वदेशीय कला एवं आर्थिक विकास 'पर खजुराहो में आयोजित एक सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत में अपने प्रवास के दौरान डा. इंग्लीश के साथ एक सप्ताह के लिए कनाडा के म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. विक्टर राबिनोविच उनके साथ जुड़े।

कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) ने वर्ष 2008 में भारत व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जिसमें श्री एम.जे. अकबर (आर्टस ऑफ टर्बुलेंस पर) श्री प्रताप भानु मेहता (इंडियाज ग्रेट ट्रांसफोर्मेशन पर), सुश्री अलका आचार्या (भारत-चीन संबंधों पर) और श्री राजीव भार्गव (धर्म निरपेक्षता पर बहु-अवधारणा पर) शामिल हैं।

कनाडा सरकार के नागरिकता, उत्प्रवासन एवं बहुसंस्कृतिवाद मंत्री श्री जेसोन केने ने 11-18 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की।

कनाडा सरकार के कृषि मंत्री श्री रेजीनाल्ड रिज ने 10-14 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कृषि एवं अनुषांगिक सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और कनाडा सरकार के कृषि एवं कृषि खाद्य विभाग के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। श्री रिज ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की।

अल्बर्टा सरकार के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर-सरकारी संबंध मंत्री और उप-प्रीमियर श्री रोज स्टीवेंस पैट्रो-टेक 2009 में भाग लेने के लिए 7-16 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और सचिव (पश्चिम) से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कनाडा सरकार श्री स्टॉकवेल डे ने 16-23 जनवरी, 2009 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

विदेश कार्यालय परामर्श

भारत-कनाडा विदेश कार्यालय परामर्श ओटावा, कनाडा में 12 दिसंबर, 2008 को संपन्न हुई। भारतीय पक्ष की ओर से इसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) श्री नलिन सूरी द्वारा और कनाडा की ओर से विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के उपमंत्री श्री लियोनार्ड एडवर्डस ने किया। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई।

व्यापार एवं अर्थ व्यवस्था

कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उप मंत्री मारी-लुसी मोरिन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ वार्षिक व्यापार नीति परामर्श् में भाग लेने के लिए 6-12 सितंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। भारत-कनाडा व्यापार नीति परामर्श के 5 वें दौर की सह अध्यक्षता वाणिज्य सचिव एवं मारी-लुसी मोरिन ने 12 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में की। व्यापार नीति परामर्शो के दौरान गैर-टैरिफ बाधाओं और हीरे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नई एवं अक्षय ऊर्जा, रेशे, निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के प्रमाणपत्रों का प्रमाणन, तकनीकी अर्हताओं को परस्पर स्वीकार करना; उदारीकृत व्यापार वीजा व्यवस्था इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने में और व्यापार में अन्य बाधाओं को समाप्त करने की इच्छा पर चर्चा की गई। व्यापार मेले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोजन, अटलांटिक द्वार बंदरगाहों का उपयोग, भारतीय एसईजेड में निवेश, कृषि, अवसंरचना, नागर विमानन क्षेत्र इत्यादि में भाग ले वाणिज्यिक अवसरों का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया। कनाडा पक्षों ने भारत में अन्य व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की।

मंत्री श्री मोरिन के साथ आए विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, कनाडा के सहायक उप मंत्री श्री केन सनकुइस्ट ने विदेश मंत्रालय में अधिकारियों के साथ हुई अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

जी-8 सदस्य और संसाधन समृद्ध व्यापार अर्थव्यवस्था, कनाडा, जिसकी भारत की उदीयमान अर्थव्यवस्था के साथ स्पष्ट सम्पूरकताएं हैं के साथ क्रियाकलापों की छिपी संभावनाओं के प्रत्युत्तरस्वरूप भारत-कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन ने दोनों सरकारों से एक व्यापक मुक्त व्यापार करार पर बातचीत आरंभ करने की अनुशंसा की। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट को व्यापार नीति परामर्शों के 5वें दौर जो कि 12 सितंबर, 2008 को दिल्ली में हुई थी, के दौरान रखी गई।

श्री वैरी टोड और सुश्री डोरिस जिंजेरा-ब्यूयेमिम मनीटोबा के कृषि, खाद्य एवं ग्रामीण पहल के क्रमशः उप मंत्री और सहायक उप मंत्री के नेतृत्व में कनाडा के मनीटोबा प्रांत का एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल 27 नवंबर-1 दिसंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में खाद्य प्रसंस्करण के लिए खाद्य विकास केन्द्र परियोजनाओं पर स्थापित करने में मनीटोबा प्रांत के हित पर चर्चा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और पंजाब और हरियाणा की सरकारों के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।

दोनों देशों की बीच आर्थिक सम्पूरकताओं को देखते हुए, दोनों देशों के बीच 5 वर्षों में 20 बिलियन कनाडियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि कनाडा एक संसाधन संपन्न देश है और पोटास, तिलहन, तेल एवं गैस, यूरेनियम इत्यादि के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और उसके पास जीव-विज्ञान, खनन, विमानन एवं ऊर्जा क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी है, भारत के पास काफी बड़ा बाजार है और उसकी अर्थव्यवस्था उच्च प्रगति के पथ पर है। वर्ष 2008 क पहले 9 माह के दौरान (जनवरी-सितंबर) भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.07 बिलियन कनाडियाई डालर रहा जिसमें कनाडा को भारतीय निर्यात 1.59 बिलियन कनाडियाई डालर का था और आयात 1.48 बिलियन कनाडियाई डालर रहा। भारत से कनाडा को निर्यात की प्रमुख सामग्रियों में वस्त्र, दवाएं, औषधियां, अच्छे रसायन, मशीनरी और यंत्र, कपड़े, जवाहारात एवं जेवर और चावल शामिल है। कनाडा से भारत को आयात होने वाले मुख्य सामानों में दलहन, गेहूं, उर्वरक, इलौक्ट्रोनिक सामग्री, अयस्क, धातु के स्क्रैप, परिवहन उपकरण और न्यूजप्रिंट शामिल हैं। भारत में अवसंरचना के क्षेत्र में बड़े निवेशक के रूप में कनाडा की इकाइयां - एसएनसी लवलीन और बम्बार्डियर उभरे। दोनों देशों ने भारत और कनाडा के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाए। कनाडा ने भारत में अपने नए व्यापार कार्यालय खोले।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने जून, 2008 में कनाडा की यात्रा की और कनाडा के वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ बातचीत करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रहे सहयोग की समीक्षा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 17 मिलियन डालर मूल्य के 10 नए संयुक्त पहलों को शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत कृषि, पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, आई टी, ऊर्जा, वैमानिकी और जलसंभरक प्रबंधन के क्षेत्र में आठ परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है और दो भागीदारी विकास कार्यकलापों से संबंधित है। बाद वाले दोनों परियोजनाएं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सहयोग से टोरंटो विश्वविद्यालय पारस्परिक लाभ की परियोजनाएं प्रारंभ करेगा। कनाडा के जैव-रसायनविद् और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक डा. जोसेफ हुलसे ने भारत के राष्ट्रपति से 8 मई, 2008 को पद्मश्री 2008 पुरस्कार ग्रहण किया।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देते हुए 5 दिसंबर, 2008 को आयोजित इंडियाज टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस में कनाडा एक साझीदार देश था।

शिक्षा

फिक्की द्वारा उच्चतर शिक्षा पर 24-26 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित शिखर बैठक में एक सहभागी देश था। डा. आर.पी. अग्रवाल, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 11-18 जून, 2008 तक कनाडा की यात्रा की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली ने टोरंटो विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।

प्रवासी भारतीय सम्मान 2009

कनाडा के संसद सदस्य श्री दीपक ओबराय, प्रवासी भारतीय दिवस 2009 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2009 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लैटिन अमरीका और कैरेबियाई देश (एल.ए.सी.)

वर्ष के दौरान 39 देशों और लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई देशों के आश्रित भू-भागों के साथ हमारी बातचीत जारी रही। विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र-पार वार्ता सुविधाजनक बनायी गई और कुल 14 करार और समझौता-ज्ञापन पर इन देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007-08 के दौरान भारत और एलएसी देशों के बीच 11.69 बिलियन अमरीकी डालर तक के द्विपक्षीय व्यापार किए गए। वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी (पीडीवीसीए) और ओएनजीसी विदेश के बीच पूर्वी वेजेजुएला के सान, क्रिस्टोबाल तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन एवं विकास कार्यकलाप, बीपीआरएल-विडियोकॉन जे भी द्वारा ब्राजील के 10 ऑफशोर ब्लॉकों में इंकाना कॉरपोरेशन ऑफ कनाडा के अधिकारों का अधिग्रहण, भारत द्वारा क्यूबा को देय 128 करोड़ रू. तक के वाणिज्यिक ऋण और ब्याज में रियायत और एचएएल द्वारा एक्वाडोर को 7 अत्याधुनिक हल्के हेलिकॉप्टर (ध्रुव) की बिक्री के लिए एक जेभी करार पर हस्ताक्षर एलएसी देशों के साथ हमारे आर्थिक/ वाणिज्यिक संबंधों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। 160 मिलियन अमरीकी डालर तक की ऋण-पत्र सहायता की घोषणा की गई और 2.125 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि आपदा राहत के लिए वितरित की गई। हमारे विकास सहभागिता पहल के भाग के रूप में तीन लाटीन अमरीकी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए गए थे। कुल 382 आइटेक छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई और इन देशों से आए उम्मीदवारों द्वारा उसका

उपयोग किया गया। भारत के राष्ट्रपति की अप्रैल, 2008 में हुई ब्राजील, मैक्सिको और चिली की यात्रा के दौरान और एसआईसीए विदेश मंत्रियों/उपमंत्रियों की जून, 2008 की भारत की यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय वार्ता को सुविधाजनक बनाया गया। इक्वाडोर के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए नवंबर, 2008 में दिल्ली की यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2008 में जापान में आयोजित जी-8 -05 की बैठक के दौरान मैक्सिको के राष्ट्रपति से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्ष 2008 में न्यूयार्क में हुई बैठक के दौरान विदेश मंत्री जी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो के विदेश मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की।

एंटीगा एवं बरबुडा

एंटीगा एवं बरबुडा के वित्त एवं आर्थिक कार्य मंत्री डा. लियोन एरूल कोर्ट मणिपाल विश्वविद्यालय में अक्तूबर, 2008 में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए। वे विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा से मिले और विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। राजकोष, वित्त एवं कर मामलों से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाले 6 भारतीय परामर्शदाताओं ने वर्ष 2008 में एंटिगा और बरबुडा की यात्रा की। भारत द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य भी पूरा हो गया। इक्विटी अधिग्रहण के द्वारा मणिपाल शिक्षा न्यास ने दिसंबर, 2008 में एंटीगा में अमरीकी विश्वविद्यालय के ऊपर प्रबंधन नियंत्रण स्थापित किया।

अर्जेंटीना

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 7-12 फरवरी तक अर्जेंटीना की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री और विदेश उप मंत्री के साथ वार्ता की। यात्रा के दौरान अर्जेंटीना में भारतीय मिशन के एक नए चांसरी का विदेश राज्य मंत्री और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

वस्त्र मंत्री श्री शंकर सिंह बघेला ने 6-9 अप्रैल, 2008 तक अर्जेंटीना में भारत सरकार के हस्तशिल्प से जुड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 8 अप्रैल, 2008 को अर्जेंटीना के आर्थिक कार्य मंत्री श्री मार्टिन लुस्ट्यू के साथ चर्चा की।

वाणिज्य सचिव ने 9-10 जून, 2008 तक ब्यूनर्स आयर्स की यात्रा की। द्विपक्षीय विचार-विमर्श के अलावा "भारत के साथ व्यापार" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई और भारत-अर्जेंटीना वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की इस अवसर पर नींव रखी गई।

वरिष्ठ एवं कनिष्ठ भारतीय महिला हॉकी टीमों की अर्जेंटीना की यात्रा और मैत्रीपूर्ण मैच खेलने से भारत और अर्जेंटीना के बीच खेल संपर्कों को काफी बल मिला है। भारतीय सेना की पोलो टीम ने 26 नवंबर-6 दिसंबर, 2008 तक अर्जेंटीना का दौरा किया। भारतीय फुटबॉल अकादमी द्वारा डियेगो माराडोना के नाम पर रखे गए एक खेल परिसर का उद्घाटन करने के लिए उसके निमंत्रण पर डियेगो माराडोना ने दिसंबर, 2008 में कोलकाता की यात्रा की।

वर्ष 2008 में भारतीय निर्यात ने 28% की वृद्धि दर्ज करते हुए और आयात वर्ष 2007 के व्यापार की तुलना में 5% की कमी दर्ज करते हुए द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच वर्ष 2008 में 1.4 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

बोलिविया

बोलिविया के साथ भारत के संबंध सौहार्द्रपूर्ण बने रहे। जिंदल स्टील एंड पावर लि., जिसे कि बोलिविया में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर के म्यूटुन लौह अयस्क परियोजना आबंटित की गई है, ने प्रारंभिक खोजी, लाइसेंसिंग और अवसंरचना निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। भारत सरकार ने "ला नीना" नामक जलवायु में आयी गड़बड़ी के कारण आए बाढ़ के परिणामस्वरूप आपदा राहत सहायता के रूप में बोलिविया की सरकार को 1,00,000 अमरीकी डालर की नगद सहायता प्रदान की।

ब्राजील

विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 16-18 फरवरी तक ब्राजील की यात्रा की और द्विपक्षीय संबंधी और चल रहे सहयोग कार्यक्रम की स्थिति पर ब्राजील के विदेश मंत्री श्री सेलसो एमोरिन के साथ विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति श्री लुईज इनासियो लुला डा. सिल्वा और ब्राजील के संसद के लोअर हाउस के अध्यक्ष श्री अरलिंडो चिनागालिया के साथ मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान अवसंरचना, भूख और गरीबी का सामना करने के क्षेत्र में सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के साथ नवीकरणीय ऊर्जा राजय मंत्री श्री विलास मुत्तेमवार और तीन संसद सदस्य ने 13-16 अप्रैल, 2008 तक ब्राजील की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लुला डा सिल्वा से मिली। 4 करारों नामतः एक प्रत्यर्पण संधि, तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन, सिविल प्रतिरक्षा और मानवीय सहायता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री श्री जोस टेम्पोराव ने 28 जुलाई - 1 अगस्त, 2008 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अंबुमणि रामदौस के साथ वार्ता की।

दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को तीसरी इब्सा शिखर बैठक के अवसर पर अक्तूबर, 2008 में राष्ट्रपति लुला की भारत यात्रा से और बल मिला। उनके साथ ब्राजील के विदेश मंत्री श्री सेल्सो एमोरिम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सर्जियो मकाडो टेजेन्डे, विकास, उद्योग एवं विदेश व्यापार मंत्री श्री मीगेल जॉर्ज

और महिला नीति सचिवालय मंत्री सुश्री निलसिया फ्रेरे भी भारत आयी।

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री ने जी-4, बीआरआईसी और वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की जी-20 बैठक में भाग लेने के लिए 6-10 नवंबर, 2008 तक साओ पाअलो की यात्रा की।

भारत और ब्राजील के बीच व्यापार अनुवीक्षण तंत्र की पहली बैठक 3 फरवरी, 2009 को संपन्न हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव और ब्राजील के विकास, उद्योग एवं विदेश व्यापार मंत्रालय के कार्यपालक सचिव ने की। व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई और हो रहे द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने के भविष्य पर चर्चा की गई।

भारत और ब्राजील के बीच व्यापार जो कि जनवरी-दिसंबर, 2007 के दौरान 3.1 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था, वर्ष 2008 में और बढ़कर 4.66 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

चिली

भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 20-23 अप्रैल, 2008 तक राजकीय यात्रा पर चिली गई। वहां राष्ट्रपति ने प्लाजा डा ला इंडिया मोनुमेंट जहां कि 3 भारतीय नेताओं की प्रतिमा लगाई गई थी, की देखरेख के कार्य के लिए 65,000/- अमरीकी डालर की एक मुश्त देय दान की घोषणा की। यात्रा के दौरान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्कूल, सेटियागो के विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 19,500 अमरीकी डालर की राशि भेंट स्वरूप दी। चिली की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा के अलावा राष्ट्रपति ने सेंटियागो शहर के मेयर ने हमारे राष्ट्रपति को शहर की कुंजी भेंट की। राष्ट्रपति ने चिली सीनेट और चैम्बर ऑफ डिपुटीज के अध्यक्षों से भी मिली। राष्ट्रपति को चिली विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की गई। यात्रा के दौरान दो करारों (वायु सेवा करार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर करार) दो समझौता-ज्ञापन (खेल-कूद और अंटार्कटिका में संयुक्त अनुसंधान में सहयोग) पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर चिली के राष्ट्रपति डा. मिशेल बैचलेट 16-20 मार्च 2009 को भारत की यात्रा पर आयी। उनके साथ चिली के कृषि मंत्री, दो उप मंत्री, दस सांसद और 25 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। राष्ट्रपति बैचलेट की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत के उप-राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा ने उनसे मुलाकात की। यात्रा के दौरान 4 करार/समझौता ज्ञापन नामतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आदान-प्रदान कार्यक्रम; शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोगिता में सहयोग पर करार; और भू-विज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के पश्चात एक संयुक्त प्रैस वक्तव्य जारी किया गया। चिली के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली, मुम्बई और चेन्नै में हुई व्यापार संगोष्ठियों के दौरान भारतीय व्यापार जगत के साथ गहन विचार-विमर्श किया। राष्ट्रपति बैचेलेट को मद्रास विश्वविद्यालय ने मानार्थ डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की।

कोलंबिया

कोलंबिया के वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री लुइज गिलेर्मो प्लाटा व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 26-30 अप्रैल, 2008 तक भारत की यात्रा पर आए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और निवेशों के संरक्षण एवं संवर्धन पर संधियों को अंतिम रूप देने और दोहरे कराधान परिहार से संबंधित मसलों पर चर्चा की गई।

सितंबर, 2008 में बोगोटा में प्रथम कोलंबिया-भारत वाणिज्य परिसंघ की शुरूआत की गई।

कोलंबिया के ऊर्जा एवं खान मंत्री श्री हरनान मार्टिनेज ने 3-7 सितंबर, 2008 तक भारत की यात्रा की और हमारे पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ मुलाकात की और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने राज्यमंत्री (खान) एवं भारतीय व्यवसायियों से भी भेंट की। कोलंबिया सरकार द्वारा शुरू की गई बोली की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के ओवीएल ने कैरोबियन में गैस फील्ड ऑफशोर और दो ऑनशोर तेल के क्षेत्र का पता लगाने के लिए तीन रियायतें प्राप्त की।

भारत ने कोलंबिया के साथ 4 फरवरी, 2009 को रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कोलंबिया की वायु सेना के उप प्रमुख ने 11-15 फरवरी, 2009 तक बेंगलूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेश एक्सपोजिशन-एइरो 2009 में भाग लिया।

कोस्टा रीका

कोस्टा रीका के विदेश मंत्री ब्रूनो स्टागनों उगार्ते ने एकआईसीए के विदेश मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में 10 जून 2008 को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ चर्चा की और द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

क्यूबा

दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बहाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्यूबा के बकाए वाणिज्यिक ऋण और ब्याज (128 करोड़ रु तक की राशि) क्यूबा द्वारा भारत के ऋण को

17 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में चिली गणराज्य के राष्ट्रपति डा. मिशेल बैसेलेट
के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह।

17 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में इक्वेडोर के विदेश कार्य मंत्री मारिया इसाबिल सल्वाडोर
केंद्रीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए।

माफ कर दिया। यह ऋण माफी क्यूबा के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को एक्जिम बैंक और एक्सपोर्ट क्रेडिट गांरटी कॉरपोरेशन द्वारा ऋण सुविधा और बीमा कवर को सुविधाजनक बनाएगा। क्यूबा के विदेश व्यापार मंत्रालय के उप मंत्री श्री एडुआर्डो एस्कांडेल अमाडोर के नेतृत्व में एक 19 सदस्यीय क्यूबियाई व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 15 मई- 1 जून, 2008 तक भारत की यात्रा की। एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 नवंबर, 2008 तक 26 वे हवाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया।

तेल एवं गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-क्यूबा हाइड्रोकार्बन करार को अंतिम रूप देने के साथ ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। इसे पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा और उनके क्यूबियाई समकक्ष सुश्री यादिरा गार्सिया वेरा, बेसिक इंडस्ट्री मंत्री के बीच मैड्रिड, स्पेन में 19 वें विश्व पैट्रोलियम कांग्रेस के अवसर पर 30 जून 2008 को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। ओएनपीसी विदेश लि. (ओवीएल) का पहले से ही क्यूबा के आठ खनन ब्लॉकों में हिस्सेदारी है।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रहे सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग से एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-23 दिसंबर, 2008 तक क्यूबा की यात्रा की।

भारत सरकार ने फरवरी, 2010 तक भारत-क्यूबा ज्ञान केंद्र परियोजना के विस्तार की मंजूरी दे दी जिसमें कि क्यूबा के 800 लोगों को आईटी दक्षता में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इक्वाडोर

इक्वाडोर के विदेश मामलों के उप-मंत्री श्री जोस वैलेन्सिया ने सचिव (पश्चिमी) के साथ 18 जुलाई, 2008 को दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लिया और व्यापक द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री (ई.ए.) और खान राज्य मंत्री से भी भेंट की।

इक्वाडोर की विदेश मंत्री सुश्री मारिया इसाबेल सल्वाडोर ने 16-17 नवंबर, 2008 को भारत की यात्रा की और विदेश मंकत्री के साथ चर्चा की। यात्रा के दौरान वर्ष 2009-11 के लिए कृषि के क्षेत्र में सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मंत्री सल्वाडोर ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की।

इक्वाडोर ने इक्वाडोर की वायु सेना को 7 अत्याधुनिक हल्के (ध्रुव) हेलिकॉप्टर की आपूर्ति करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकस लि. के साथ एक करार की।

इक्वाडोर की वायु सेना के प्रमुख जनरल रोडरिगो बोहोरक्वेज ने 11-15 फरवरी, 2009 तक बेंगलुरू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेश एक्सपोजिशन एयरो-2009 में भाग लिया।

अल साल्वडोर

एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र सान सल्वाडोर में मई, 2008 में स्थापित की गई। अल सल्वाडोर के प्रथम राजदूत के रूप में सुश्री पैट्रिशिया फिगेरोआ ने मई, 2008 में माननीया राष्ट्रपति महोदया को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत की।

ग्रेनाडा

सेंट जॉर्ज में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए ग्रेनाडा की सरकार के साथ 21 अक्तूबर, 2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

गुयाना

भारत-गुयाना संयुक्त आयोग की चौथी बैठक 14 मई, 2008 को जॉर्जटाउन, गुयाना में संपन्न हुई। खनन, ऊर्जा, तेल एवं हाइड्रोकार्बन, अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी, आईसीटी और कृषि जैसे प्राथमिकता के नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण-पत्र मंजूर की गई। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने गुयाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जिसमें आपसी रूचि के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। गुयाना पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री डा. हेनरी बी. जेफरी ने किया।

हैती

हैती में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेने के लिए हैती में यूनाइटेड नेशन स्टेबिलाइजेशन मिशन में भारत से 140 सदस्यीय गठित पुलिस इकाई गए।

इब्सा त्रिपक्षीय पहल के अंतर्गत हैती में 14 दिसंबर, 2008 को एक ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया गया। इब्सा के दिशानिर्देश के अनुसरण में हैती के लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की यह परियोजना एक अच्छी संभावना प्रस्तुत करता है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की भारत के उद्देश्यों का समर्थन करता है।

होंडुरास

रक्षा मंत्री आटिस्टीडेज मेजिया ने बी ई एल, बीईएमएल,अशोक लीलैंड जैसी भारतीय कंपनियों और होंडुरास को भारत सरकार द्वारा पेशकश की गई 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र को निष्पादित करने में शामिल भारतीय एक्जिम बैंक के साथ चर्चा करने के लिए 20-25 अप्रैल, 2008 तक भारत की यात्रा की। भारत सरकार द्वारा तेगुसीगल्पा में मई, 2008 में एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।

17 अप्रैल, 2008 को लॉस पीनोस, मेक्सिको में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने मेक्सिको के राष्ट्रपति फिलिप काल्ड्रोन हिनोजोसा से भेंट की।

जमैका

किंगस्टन में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय सहायता से स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस केंद्र को वर्ष 2009 के प्रथम तिमाही में प्रकार्यात्मक हो जाने की आशा है। सौर ऊर्जा क्षेत्र, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के क्षेत्र में सहयोग की संभावना अभी विचाराधीन है।

मेक्सिको

भारत की राष्ट्रपति ने 16-20 अप्रैल, 2008 तक मेक्सिको की यात्रा की। राष्ट्रपति की यात्रा के साथ एक सीआई आई व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी मेक्सिको गया। वायु सेवा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित दो करारों पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

श्री दिनेश राय, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री राकेश वैद्, अध्यक्ष, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और श्री के. विजयमणि, कार्यपालक निदेशक, सिथेंटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपने-अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में तालमेल को सुदृढ़ करने के लिए मैक्सिको की यात्रा की। एयर वाइस मार्शल शंकर मीणा के नेतृत्व में भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक प्रतिनिधिमंडल ने मैक्सिको में अपने समकक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मैक्सिको की यात्रा की।

एड्स सम्मेलन, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय शक्ति और महिला अधिकार, योजना लेखा एवं वित्त प्रबंधन प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री अंबुमणि रामदौस, केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर, पंचायती राज एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, श्री वी.एन. कैला, लेखा-महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, श्री रवि ढींगरा, सचिव, अंतर-राज्य-परिषद, गृह मंत्रालय ने मेक्सिको की यात्रा की।

निकारागुआ

भारत सरकार द्वारा मानागुआ में जून, 2008 में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया। इस केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन 16 जून, 2008 को भारत के राजदूत और निकारागुआ के विदेश मंत्री द्वारा किया गया।

पनामा

भारत सरकार द्वारा पनामा सिटी में वर्ष 2005 में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र को अगस्त, 2008 में पनामा के स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप दिया गया। दो वर्षों की कालावधि के दौरान, 3 भारत स्थित टीसीएस अनुदेशकों ने बेसिक, इंटरमीडिएट और उच्चतर कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में 1300 से अधिक पनामा के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षित किया।

सूरीनाम

भारत-सूरीनाम जेसीएम की चौथी बैठक मई, 2008 में पारामारिबो में संपन्न हुई। विदेश राज्य मंत्री (ए.एस.) और सूरीनाम के विदेश मंत्री लाइजिया क्राग- केटेलडीक ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। खनन, अवसंरचना विकास, फार्मास्यूटिक्ल्स एवं जेनेरिक दवाओं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, उपग्रह लिंकिंग, कृषि अनुसंधान जैसे प्राथमिकता के नए क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण-पत्र की घोषणा की गई।

सूरीनाम में लघु एवं मध्यम उद्यमी संघ का एक तथ्यान्वेषी व्यापार मिशन और सूरीनाम-भारत निवेश एवं व्यापार संवर्धन संगठन ने नवंबर/दिसंबर, 2008 में भारत का दौरा किया। "सूरीनाम में व्यापार अवसरों" पर एक संगोष्ठी आयोजित करने के अलावा इसने पीएचडी चैम्बर और एफआईएसएम ई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

सूरीनाम गणराज्य के उप राष्ट्रपति श्री रामदीन सर्दजो ने 7-9 जनवरी, 2009 तक चेन्नै में आयोजित 7वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की।

सूरीनाम गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री इवान क्रिस्टीयन फर्नाल्ड ने 11-15 फरवरी, 2009 में बेंगलुरू में आयोजित एयरो इंडिया-2009 में भाग लिया।

त्रिनिदाद एवं टोबैगो

संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्ष 2008 में हुई बैठक के दौरान विदेश मंत्री की 29 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के अलावा दोनों नेताओं ने आपसी रूचि के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो उच्चायोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक भारतीय व्यापार मिशन ने जून, 2008 में त्रिनिदाद एवं टोबैगो का दौरा किया।

ओएनजीसी विदेश (ओवीएल) और मित्तल इनर्जी द्वारा गठित जेवी, ओ एमईएल ने अनुमानित 2 ट्रिलियन घन फीट गैस रिजर्व का त्रिनिदाद एवं टोबैगो के दक्षिणी पूर्व में 2 गैस ब्लॉकों का खनन करने का अधिकार जीता।

ओएनजीसी मित्तल इनर्जी लि. (ओएमईएल), पैट्रोटिन (राज्य स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी) और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के ऊर्जा एवं ऊर्जा उद्योग मंत्रालय के बीच उत्पादन के बांटने संबंधी करार जो कि ब्लॉक एनसीएमए2 में तेल एवं गैस के ऑफशोर खनन के लिए है, पर 30 दिसंबर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए।

उरूग्वे

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 7-12 फरवरी तक उरूग्वे की यात्रा की। उरूग्वे के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ

उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और उरूग्वे के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। पैट्रोलियम उत्पाद एवं पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में लगी उरूग्वे की राज्य स्वामित्व वाली एक कंपनी एनएनसी एपीके एक प्रतिनिधिमंडल ने उरूग्वे में तेल खनन के लिए सहयोग एवं संयुक्त उपक्रम के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए वर्ष 2008 में भारत की यात्रा की।

वेनेजुएला

सान क्रिस्टोबाल तेल क्षेत्र पर ओवीएल और पीडीवीसीए के बीच एक संयुक्त उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 7-10 अप्रैल, 2008 तक वेनेजुएला की यात्रा की। वेनेजुएला में मंत्री श्री देवड़ा ने अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज, ऊर्जा एवं पैट्रोलियम मंत्री राफेल रमीरेज और विदेश मंत्री, निकोलस माडुरो के साथ भी बैठकें कीं।

श्री आनंद शर्मा, विदेश राज्य मंत्री ने 18-20 मई, 2008 तक वेनेजुएला की यात्रा की। उनकी राष्ट्रपति चावेज के साथ 20 मई, 2008 को विस्तृत चर्चा हुई। वेनेजुएला के विदेश मंत्री, संस्कृति, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री और पर्यटन एवं छोटे उद्योग एवं वाणिज्य उप मंत्रियों के साथ बैठक की।

भारत-सीका विदेश मंत्रियों की बैठक

भारत-सीका (मध्य अमरीकी एकजुटता प्रणाली) विदेश मंत्रियों की बैठक 10 जून, 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री द्वारा इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई। बैठक में पनामा, निकारागुआ और कोस्टारका के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ होंडुरास, डोमिनिकन गणराज्य और अल सल्वाडोर के उप विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। अल सल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ के साथ राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट के लिए तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। होंडुरास के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए भारत-सीका संयुक्त तकनीकी समिति और भारत-सीका व्यापार मंच स्थापित करने पर सहमति हुई। सीका देशों के लिए आइटेक स्लाटों की संख्या 68 से बढ़ाकर 100 कर दी गई।

भारत, भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से प्रत्येक सीका देश के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-पत्र सुविधा और सीएबीएआई (मध्य अमरीकी आर्थिक एकीकरण बैंक) को 10 मिलियन अमरीकी डालर की वाणिज्यिक ऋण-पत्र देने की घोषणा की।

मर्कोसुर (दक्षिण का साझा बाजार)

मार्च, 2009 में 4 मर्कोसुर सदस्य देश के संसदों और सरकारों द्वारा भारत-मर्कोसुर पीटीए का अनुसमर्थन किया गया और अनुसमर्थन का दस्तावेज मर्कोसुर सचिवालय को सौंप दिया गया। अनुसमर्थन प्रक्रिया पूर्ण होने के बारे में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को अधिसूचित करने के 30 दिनों के बाद यह पीटीए प्रवृत्त होगा।

■■

9 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रतिनिधित्व और विश्वसनीयता और परिणामस्वरूप इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत उसमें सुधार लाने की चल रही प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। अन्य सदस्य राज्यों के सहयोग से भारत, सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार कर और उसकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाकर; महासभा को पुनः सक्रिय बना कर और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसोक) में सुधार लाकर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर निरंतर बल देता रहा। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दों में नेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना भारत की रूचि का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहा।

इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुधार के अन्य तत्वों, जिसे कि पहले ही स्थापित किया जा चुका है, के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया। इनमें शामिल हैं- शांति निर्माण आयोग के जरिए संघर्ष के उपरांत समाज को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया, नए स्थापित मानवाधिकार परिषद के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण में अधिक कारगर और परिणामोन्मुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा जनित आपातावस्था में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की जाए।

आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में लोगों के निरंतर मारे जाने को ध्यान में रखते हुए, भारत, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंक-रोधी रणनीति का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर चल रही वार्ता संपन्न करने की आवश्यकता के प्रति दृढ़ संकल्प रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कैलेण्डर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में 2 अक्तूबर को स्थापित करते हुए 2 अक्तूबर, 2008 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंहिसा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अनौपचारिक पूर्ण सत्र आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और महासभा के अध्यक्ष द्वारा की गई। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री सम्मानित अतिथि थे।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री बान-की मून ने अपनी पत्नी श्रीमती यू सून-टाक, संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के महासचिव श्री बी.लिन्न पास्को और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 30-31 अक्तूबर, 2008 को भारत का दौरा किया। उन्होंने दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए पुनः 4-6 फरवरी, 2009 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 63 वां सत्र

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 23-27 सितंबर, 2008 तक की अपनी न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63 वें सत्र की आम बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27 सितंबर, 2008 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार संबंधी कार्यसूची के महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रगति करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विश्व की वित्त व्यवस्था में आए संकट और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समन्वित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनौतियां वर्षों से कई देशों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के लाभों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2008 को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के मध्य बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया है, प्रधानमंत्री के वक्तव्य में वैश्विक समृद्धि एवं कल्याण के अविभाजनकारी स्वरूप पर बल दिया गया।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मसले के लिए एक सहकारी और सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सामूहिक विनाश के हथियारों के भंडारण से उत्पन्न चुनौतियों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने पहली बार दो दशक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा रखे गए वैश्विक, पक्षपातपूर्णरहित और सर्वव्यापी नाभिकीय निरस्त्रीकरण प्रणाली के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के द्वार खोलना शस्त्रों के अप्रसार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन है। उन्होंने आतंकवाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए विश्व का आह्वान करते हुए आतंकवाद के वैश्विक दुष्परिणाम का भी जिक्र किया और सीसीआईटी को शीघ्र निष्पादित करने की आवश्यकता की भी पुष्टि की।

न्यूयार्क की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की मध्यकालिक समीक्षा पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम के पूर्ण खंड में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान

प्रधानमंत्री चीन जनवादी गणराज्य के राज्य परिषद के प्रीमियर श्री वेन जियाबाओ पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी, ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के प्रधानमंत्री श्री गॉर्डन ब्राउन, नामीबिया के राष्ट्रपति श्री हिफीकेपुन्ये पोहाम्बा और विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट जोलिक से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री की जमैका के प्रधानमंत्री श्री ब्रुस गोल्डिंग और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री जान पीटर बाल्केनेन्डे से भी संक्षिप्त बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री की यात्रा के पश्चात विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 28 सितंबर-2 अक्तूबर, 2008 तक न्यूयार्क की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63 वें सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए 2 अक्तूबर 2008 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनौपचारिक पूर्ण सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के विदेश मंत्रियों की वार्षिक कार्यकारी बैठक, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच चतुर्थ राजनीतिक वार्ता, भारत-ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) दल की मंत्रिस्तरीय बैठक और भू-आबद्ध विकासशील देशों के लिए अल्माटी कार्य के कार्यक्रम की मध्यावधिक समीक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। विदेश मंत्री ने चेक गणराज्य, जार्डन, नेपाल, नाइजीरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के अपने समकक्षों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63 वें सत्र के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी मुलाकात की।

श्री पी. चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री (वर्तमान गृह मंत्री) ने प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में 25 सितंबर, 2008 को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की मध्यावधिक समीक्षा पर आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा की। प्रधानमंत्री के साथ एमडीजी मध्यावधिक समीक्षा की पूर्ण बैठक में भाग लेने के अलावा वित्त मंत्री ने गरीबी एवं भुखमरी गोलमेज बैठक में गरीबी उन्मूलन पर विचार प्रकट किये। महासभा के सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने युगांडा के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की विशेष बैठक और साथ ही प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली नियमित राष्ट्रमंडल की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

श्री आनन्द शर्मा, विदेश राज्य मंत्री ने 22-28 सितंबर, 2008 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का दौरा किया और अफ्रीका विकास आवश्यकता संबंधी एक उच्च स्तरीय पूर्ण कार्यक्रम, ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक और जी-77 की एक मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री ई.अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 3 से 10 दिसंबर, 2008 तक संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया तथा सउदी अरब के महामहिम शाह द्वारा आहूत 'शांति की संस्कृति ' पर एक उच्च स्तरीय विशेष कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्री जी ने केंद्रीय आपातकालीन अनुक्रिया कोष (सीईआरएफ) से संबंधित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लिया जिसमें उन्होंने भारत की ओर से 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का बहु- वर्षीय अंशदान का वायदा किया।

इसके अतिरिक्त भारत के गैर-आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के रूप में महासभा के 63 वें सत्र में 18 सांसदों सहित 21 भारतीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और कई मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण संबंधी वक्तव्य दिया।

महासभा में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र और उसकी समितियों में महासभा के पुनर्जीवन, शांतिरक्षण, शांतिनिर्माण, आप्रवासन एवं विकास, मानव सुरक्षा, सुरक्षा परिषद का सुधार, न्याय का प्रशासन के मुद्दों, गरीबी उन्मूलन सहित मैक्रो-आर्थिक नीतिगत प्रश्नों, आत्मनिश्चय के प्रश्न और संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति और संगठन के कार्यों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट पर वक्तव्य दिया। मानवाधिकार जैसे सामाजिक मुद्दे और अफगानिस्तान में स्थिति जैसे राजनीतिक मुद्दे और मध्य पूर्व में स्थिति पर हस्तक्षेप भी किए गए।

मध्य पूर्वः भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा (चतुर्थ समिति और पूर्ण सभा दोनों में) में मध्य पूर्व मुद्दे का संयुक्त राष्ट्र में चर्चा कराने में भारत लगा रहा। भारत नवंबर, 2007 में अन्नापोलिस सम्मेलन द्वारा शुरू किए गए द्विपक्षीय इजरायल-फिलिस्तीन वार्ता प्रक्रिया में हुई प्रगति की आवश्यकता के अपने विश्वास पर बल दिया। 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 के बीच गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के पश्चात जनवरी, 2009 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1860 के अनुसार इजरायल द्वारा तत्काल युद्धविराम हेतु दबाव डालने के लिए जनवरी, 2009 के तीसरे सप्ताह में दिसंबर, 2006 से आस्थगित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10वें आपातकालीन सत्र को पुनः शुरू करने की मांग की। आतंक एवं हिंसा के सभी कृत्यों का विरोध करने के अपने दृढ़संकल्प को दोहराते हुए, मध्य पूर्व की व्यापक स्थिति पर और गाजा में संघर्ष के तत्काल संदर्भ में मानवीय हितों की प्रमुखता पर भारत के वक्तव्यों में फिलिस्तीनी लोगों के अहस्तांतरणीय अधिकारों के लिए सभी अवसरों पर भारत की चिरकालिक, ऐतिहासिक और निरंतर पुष्टि करने की भारत सरकार की संतुलित स्थिति निरंतर परिलक्षित होती रही। आतंक के कृत्यों पर इजरायल के असंतुलित प्रत्युत्तरों से भारत की चिंता को भी व्यक्त किया गया। भारत ने हिंसा एवं प्रति-हिंसा के चक्र का शीघ्र समाप्ति की आवश्यकता पर भी बल दिया है। भारत ने अधिकृत फिलिस्तीनी भूभागों में अपने राहत कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को धनराशि उपलबध कराना जारी रखा।

द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवसः द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए 2 अक्तूबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अनौपचारिक पूर्ण सत्र आयोजित किया गया।

इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष श्री मीगुएल डी एस्कोटो ब्रोकमैन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान-की-मून, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री सुश्री न्कोसाजाना डामिनी जुमा और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने वक्तव्य दिए। वक्ताओं ने महात्मा गांधी को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की और सदस्य-राज्यों से उनके शिक्षण को अपनाने का अनुरोध किया। पूर्ण सभा के अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने गरीबी, असमानता, हिंसा, शस्त्रों की होड़ और आंतकवाद की समस्याओं से परेशान वर्तमान जगत में महात्मा गांधी और उनके संदेश की निरंतर सार्थकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदस्य-राज्यों से विश्व शांति और सौहार्द्र बनाये रखने के लिए महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

भारत ने हित के विशिष्ट मुद्दों और परिषद की प्रक्रिया नियामावली के तहत अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा में हस्तक्षेप किया। जिन प्रमुख मुद्दों पर भारत ने हस्तक्षेप किया उनमें अफगानिस्तान की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त करने का नेपाल का अनुरोध, आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उत्पन्न खतरे, शांतिरक्षा, सुरक्षा परिषद के कार्य करने के तरीके में सुधार और सोमालिया की स्थिति शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार और कार्य करने के तरीके में सुधार सहित अन्य व्यापक सुधार पर जोर देता रहा। समान प्रतिनिधित्व के प्रश्न तथा सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि और अन्य मामलों पर महासभा के बहुद्देशीय कार्यदल (ओ ई डब्ल्यू जी) की वर्ष 2008 के दौरान अनेक बैठकें हुईं। तथापि, इस विषय पर अंतरसरकारी वार्ता आरंभ किये जाने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। सितम्बर, 2008 में अन्य जी-4 देशों (ब्राजील, जर्मनी, जापान) तथा समान विचार वाले अन्य अफ्रीकी, एशियाई, कैरीबियाई और प्रशांत द्वीप के राज्यों के समर्थन से महासभा के अनौपचारिक पूर्ण सत्र में अंतर-सरकारी वार्ताएं तत्काल आरंभ किये जाने की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णयों को शीघ्रातीशीघ्र क्रियान्वित करने के जी-4 देशों के प्रयासों के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने 19 फरवरी, 2009 से अंतर-सरकारी वार्ता आरंभ करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार से संबंधित पांच महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता का पहला दौर मार्च 2009 में आरंभ हुआ और मार्च-अप्रैल, 2009 के दौरान आयोजित अनेक बैठकों में ऐसी वार्ताएं हुईं जिसके बाद दूसरे दौर की बातचीत हुई।

आतंकवादः आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रभावी अंतराष्ट्रीय सहयोग का निर्माण करना संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

इस संदर्भ में भारत अंतराष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध व्यापक अभिसमय को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने तथा उसे स्वीकार करने के लिए निरंतर जोर डालता रहा। हालांकि प्रारूप अभिसमय के मूल प्रावधानों पर पहले ही सहमति हो चुकी है परंतु आतंकवाद की परिभाषा और इस अभिसमय के क्षेत्र के आधार पर कुछ देशों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण अभिसमय पर और प्रगति नहीं हो पाई।

भारत ने वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के क्रियान्वयन का पूर्ण समर्थन करना जारी रखा। महासभा ने अगस्त 2008 में इस नीति की समीक्षा की जिससे सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय अनुभवों का खुलासा करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।

26-30 नवम्बर, 2008तक मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों के उपरांत भारत ने अन्यों के साथ-साथ जमात-उद-दावा और इसके संस्थापक हफीज मोहम्मद सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 के तहत प्रतिबंधित करने के लिए अल-कायदा और तालिबान से जुड़े लोगों और इकाइयों की समेकित सूची में शामिल किए जाने हेतु सफलतापूर्वक दबाव डाला।

विदेश राज्यमंत्री श्री ई.अहमद ने 9 दिसम्बर, 2008 को सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवाद पर आयोजित तत्संबंधी बहस को संबोधित किया। अपने संबोधन में विदेश राज्य मंत्री ने बल दिया कि मुम्बई हमलों के दोषी चाहे जहां कहीं भी हो, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भविष्य में होने सकने वाले हमलों से बचने के लिए संकल्प लेकर आतंकवादी संगठनों का सफाया करना होगा। उन्होंने दोहराया कि भारत द्वारा1996 में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय को तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे कि आतंकवाद के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक रूपरेखा उपलब्ध हो सके।

शांतिरक्षाः भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्रवाइयों में योगदान करने वाला सबसे पुराना, बड़ा और निरन्तर अंशदाता रहा है। वर्ष 2008 में भारत तीसरा सबसे बड़ा सैनिक अंशदाता था और 10 विभिन्न शांतिरक्षा मिशनों में इसके लगभग 8,500 सैनिक शामिल थे। भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी उपस्थिति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र मिशन (4,696) में थी और उसके बाद सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन (2,704) में थी। भारत को पूर्णतः प्रथम महिला पुलिस इकाई के लिए काफी सराहना मिली जो लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन की सहायता कर रही है। भारत ने 10 मार्च - 4 अप्रैल तथा 3 जुलाई, 2008 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित शांतिरक्षा कार्रवाइयों से संबद्ध विशेष समिति के 2008 के सत्र में सक्रिय भागीदारी की। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सचिवालय में सैनिकों

का अंशदान करने वाले देशों के साथ सहयोग संवर्धित करने के अतिरिक्त पुनर्गठन, सुरक्षा और संरक्षा, व्यवहार एवं अनुशासन से जुडे कार्यों में अग्रणी रहा।

संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष

वर्ष 2005 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष (यू एन डी ई एफ) को 35 देशों से 86.8 मिलियन अमरीकी डालर का स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त हुआ है। भारत 15 मिलियन अमरीकी डालर के साथ यू एन डी ई एफ में दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है। यू एन डी ई एफ ने 205 परियोजनाओं के लिए लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता व्यक्त की है जिनमें से 15 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समर्थन करना है। 15 सितम्बर, 2008 को यू एन डी ई एफ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया गया।

यू एन डी ई एफ के सर्वोच्च शासी निकाय अर्थात् सलाहकार बोर्ड की दो बैठकें मार्च 2008 और अक्टूबर, 2008 में हुईं। अनुशंसा की गई कि यू एन डी ई एफ नई परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के तीसरे दौर की शुरूआत करे । इस निकाय की स्थापना के बाद से ही इसका एक संस्थापक सदस्य होने के अलावा भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोष के भीतर भारत ने निधियों के प्रभावी उपयोग की मानिटरिंग और वितरण पर विशेष बल दिया है और इसने यू एन डी ई एफ की आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के तौर-तरीकों के विकास का भी समर्थन किया है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन

हवाना में वर्ष 2006 में आयोजित XIV शिखर बैठक में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों द्वारा किये गये अधिदेश के अनुसार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंत्रियों की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 27-30 जुलाई तक तेहरान में हुई। मंत्रियों ने बैठक की समाप्ति पर एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर इस आंदोलन का दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। मंत्रिस्तरीय बैठक में फिलीस्तीन, इरान के नाभिकीय मसले तथा जिम्बाबवे की स्थिति पर घोषणा भी जारी की गई।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में विषेश रूप से विकासशील देशों के समक्ष विद्यमान अंतराष्ट्रीय चुनोतियों के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जारी प्रासंगिकता पर भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। उन्होंने नोट किया कि इस आंदोलन को खाद्य, ईंधन और वित्त संकट के प्रभावों से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों और हमारी राजनैतिक तथा सुरक्षा प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न खतरों से पार उबरने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उत्पन्न इन चुनौतियों और अन्य चुनौतियां आज इस बात को पहले से अधिक अनिवार्य बना देती है कि आंदोलन सामूहिक रूप से उन मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो हमें एकजुट करते हों।”

राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डल के 53 सदस्य राज्यों में सबसे बड़ा भारत इसके बजट में चौथा सबसे बड़ा अंशदाता है। वर्ष 2005-06 में 8,00,000 ब्रिटिश पाउंड से भारत ने राष्ट्रमण्डल तकनीकी सहयोग कोष (सी एफ डी सी) में अपना अंशदान प्रति वर्ष 50 000 जी बी पी बढ़ाते हुए 2008-09 में 950,000 ब्रिटिश पाउंड कर दिया। भारत विकासशील राष्ट्रमण्डल देशों को सहायता प्रदान करने के लिए सी एफ टी सी के तहत यू.के.के पश्चात सबसे बड़ी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है। भारत राष्ट्रमण्डल देशों के बीच डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए माल्टा में चोगम द्वारा 2005 में सृजित कॉमनवेल्थ कनेक्टस स्पेशल वोल्यूटरी फंड में (1मिलियन यूरो की वचनबद्धता के साथ) सबसे बड़ा अंशदाता है। यह आइटेक और स्कैप के अंतर्गत चुनिंदा पाठयक्रमों में 50-75 तथा कॉमनवेल्थ कनेक्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत 6 माह की अवधि के लिए अधिकतम पांच आई सी टी विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है। यह कॉमनवेल्थ कनेक्ट्स कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित संचालन समिति का एक सदस्य भी है। भारत ने चंडीगढ़ में सी वाई पी एशिया केन्द्र और श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की भौतिक अवसंरचना के उन्नयन की जिम्मेदारी लेने का भी प्रस्ताव किया है जिनपर 2 मिलियन पाउंड की कुल परियोजना लागत में से लगभग 1 मिलियन पाउंड व्यय होने का अनुमान है। भारत ने दक्षिण एशिया में स्थानीय लोकतंत्र और सुशासन का समर्थन किया है और उसके लिए कोंसलर प्रशिक्षण से संबद्ध उसकी परियोजना के लिए राष्ट्रमण्डल स्थानीय सरकार मंच के सलाहकार बोर्ड के जरिए यू एन डी ई एफ द्वारा 260,000 अमरीकी डालर की राशि की मंजूरी अनुमोदित कराई है। भारत न्यूयार्क में राष्ट्रमण्डल संयुक्त कार्यालय के सैद्धांतिक समर्थकों और योगदानकत्ताओं में से एक है और इसने जेनेवा में लघु राज्य स्थायी मिशन की स्थापना का सिद्धांत रूप में समर्थन किया है।

भारत ने 12-18 अक्टूबर, 2008 तक पुणे में तीसरे राष्ट्रमण्डल युवा खेलों की सफल मेजबानी की। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 27-30 अप्रैल, 2008 तक कोलंबों में आयोजित सातवें राष्ट्रमण्डल युवा मामलों के मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। 54 वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (सी पी ए) सम्मेलन का आयोजन 1-10 अगस्त, 2008 तक कुआलालंपुर

में किया गया जिसमें लोक सभाध्यक्ष ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। कानून एवं न्याय मंत्री ने 7-10 जुलाई, 2008 तक एडिनबर्ग, स्काटलैंड में आयोजित राष्ट्रमण्डल कानून मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त श्री कमलेश शर्मा, जो नवम्बर, 2007 में राष्ट्रमण्डल के महासचिव चुने गये थे, ने 1 अप्रैल, 2008 को अपना पदभार संभाल लिया। 16-22 अक्टूबर, 2008 को वे भारत की सरकारी यात्रा पर आये थे।

आर्थिक मुद्दे

भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्य किया कि विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट और खाद्य एवं ऊर्जा संकट की पृष्ठभूमि में विकास संयुक्त राष्ट्र कार्यसूची के केन्द्र में हो। इस संब्रध में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को सहायता, बेहतर बाजार सुविधा, ऋण राहत उपलब्ध कराने तथा प्रौद्योगिकी अंतरित करने की वचनबद्धता को पूरा करने की आवश्यकता है जिससे कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों सहित अंतराष्ट्रीय स्तर पर सहमत अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत ने व्यापार,वित्त और आर्थिक निकायों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में विकास पर और बल देना सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संवर्धित भूमिका और विकासशील देशों की भागीदारी पर भी बल दिया।

भारत ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 25 सितम्बर, 2008 को किया गया। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने उद्घाटन पूर्ण सत्र में भाग लिया जबकि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने "गरीबी और भुखमरा" पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने संयुक्त राष्ट्र के आमंत्रण पर "पर्यावरण निरंतरता" पर गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का नेतृत्व किया।

भारत ने "उपलब्धियों की पहचान, चुनौतियों का समाधान तथा 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पटरी पर वापसी" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर हुई बहस में भाग लिया जिसका आयोजन 1-4 अप्रैल, 2008 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

भारत ने "वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट" पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक में भाग लिया जिसका आयोजन 18 जुलाई, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

भारत ने 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2008 तक दोहा में आयोजित मोंटेरी सर्वसम्मति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विकास हेतु वित्त-पोषण पर अनुवर्ती अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने भारतीय प्रतिनिधमण्डल का नेतृत्व किया। भारत दोहा घोषणा के लिए वार्त्ताओं के दौरान समूह 77 के दृष्टिकोण का समन्वय करने में भी सक्रिय भागीदारी की।

भारत ने 10-13 जून, 2008 तक यामोसुकरो, कोट डी आयवर में आयोजित समूह 77 में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर अंतर-सरकारी अनुवर्ती और समन्वय समिति (आई एफ सी सी- XII) के बारहवें सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (तकनीकी सहयोग) ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसोस)

वर्ष 2007 के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का वास्तविक सत्र न्यूयार्क में जुलाई, 2008 में आयोजित किया गया। विकास सहयोग मंच मे प्रथम सत्र का आयोजन इसकी प्रमुख बात थी जो 2006 में इकोसोस को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिदेशित नया कार्यक्रम है। ब्रेटन वूडस संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के साथ इकोसोस की उच्च-स्तरीय बैठक 14 अप्रैल,2008 को न्यूयार्क में हुई। आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 20-22 मई, 2008 तक न्यूयार्क में वैश्विक खाद्य संकट पर आयोजित इकोसोस की विशेष बैठक में भाग लिया।

सतत् विकास आयोग (सी एस डी)

भारत ने सतत् विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय आयोग, सतत् विकास आयोग के कार्यों में सक्रिय भागीदारी की जिसे कार्यसूची 21 और जोहान्सबर्ग क्रियान्वयन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा और संवर्धन करने की भूमिका दी गई है। आयोग का 16वां सत्र, जो द्विवर्षीय क्रियान्वयन चक्र का एक समीक्षा सत्र था, का आयोजन 5-16 मई, 2007 तक न्यूयार्क में किया गया। इस सत्र में कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि, सूखा, मरूस्थलीय तथा अफ्रीका जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। पर्यावरण एवं वन सचिव ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यू एन ई एस सी ए पी)

यू एन ई एस सी ए पी के 64वें वार्षिक सत्र का आयोजन 24-30 अप्रैल, 2008 तक बैंकाक, थाइलैंड में किया गया। इस सत्र की विषय-वस्तु थी "एशिया और प्रशांत में ऊर्जा सुरक्षा तथा स्थायी विकास"। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने किया।

अप्रैल- नवम्बर, 2008 के दौरान सामाजिक विकास,परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध समितियों के प्रथम सत्र का आयोजन बैंकाक में किया गया जिसमें भारत का

प्रतिनिधित्व दूतावास अधिकारियों के अतिरिक्त संबंधित विभागों/मंत्रालयों के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने की।

मानवीय मुद्दें

भारत ने मानवीय मामलों के समन्वय से संबद्ध कार्यालय (ओ सी एच ए) और केन्द्रीय आपातकाल अनुक्रिया कोष (सी ई आर एफ) के कार्यकरण से संबंधित अनदेखी प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की। भारत ने समूह 77 की ओर से "प्राकृतिक आपदाओं के लिए मानवीय सहायता में अंतराष्ट्रीय सहयोग, राहत से विकास" शीर्षक से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

केन्द्रीय आपातकाल अनुक्रिया कोष

माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 4 दिसम्बर, 2008 को न्यूयार्क में केन्द्रीय आपातकाल अनुक्रिया कोष के उच्च-स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने इस कोष के लिए 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता व्यक्त की जिसे 3 वर्षो में दिया जाएगा।

विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रचालनात्मक क्रियाकलाप

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विकास कार्यो में सुधार लाने के लिए जारी प्रयासों का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य उन्हें विकासशील देशों की आवश्यकताओं के और अनुकूल बनाना है। हमने संयुक्त राष्ट्र में सिस्टम वाइड कोहरेंस पर जारी बहस में भी सक्रिय भागीदारी की।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यू एन एच सी आर)

दिसम्बर, 2006 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त श्री एंतोनियो गुटेरेस की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने नियमित व्यापक द्विपक्षीय परामर्श आरंभ करने पर सहमति व्यक्त की थी। पहले औपचारिक द्विपक्षीय परामर्श का आयोजन 31 जनवरी को जेनेवा में यू एन एच सी आर मुख्यालय में किया गया जिसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व अपर सचिव (पोल एण्ड आई ओ) तथा यू एन एच सी आर का नेतृत्व उच्चायुक्त श्री एंतोनियो गुटेरेस ने किया।

आपदा जोखिम प्रशमन

भारत ने आपदा जोखिम प्रशमन के क्षेत्र में जनेवा स्थित दो प्रमुख संगठनों - मानवीय मामलों के समन्वय हेतु कार्यलय (ओ सी एच ए) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपादा प्रशमन रणनीति (यू एन/आई एस डी आर) के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाये रखा। ।माननीय गृह राज्यमंत्री श्रीमती वी राधिका सेल्वी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने 25-29 अगस्त, 2008 तक दावोस, स्विटजरलैंड में 2008 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपदा एवं जोखिम सम्मेलन में भाग लिया ।

मानवाधिकार परिषद

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मोटे तौर पर अपने संस्था-निर्माण अधिदेय को पूरा किया और विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विशष चिंता के मुद्दों का समाधान किया । परिषद का तीन नियमित और दो विशेष् सत्र आयोजित किया गया (अधिकृत फिलीस्तीनी क्षेत्र और विश्व खाद्य संकट पर)। मानवाधिकारों और मूल्यों के प्रति अपनी पारंपरिक वचनबद्धता के अनुसरण में भारत ने परिषद की संस्था निर्माण प्रक्रिया और मानवाधिकार से जुड़े ठोस मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी की।

परिषद ने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा तंत्र को प्रभावी किया। इस तंत्र के अंतर्गत 10 अप्रैल, 2008 को भारत की समीक्षा की गई। चर्चाओं में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के हमारे प्रयासों की सकारात्मक पहचान की गई और आगे के उपायों पर कुछ ठोस सुझाव दिये गये।

मानवाधिकार परिषद ने नस्लवाद पर डरबन समीक्षा सम्मेलन, जिसका आयोजन अप्रैल 2009 में किया जाना है, के लिए तैयारी प्रक्रिया आरंभ की। भारत ने तैयारी समिति ब्यूरो के सदस्य के रूप में अन्य बातों का साथ-साथ इस सम्मेलन की तैयारी में सक्रिय भागीदारी की।

भारत मानवाधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय निगमों व अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के मुद्दे पर यू एन एस जी के विशेष प्रतिनिधियों के अधिदेश को नवीकृत करने के प्रस्ताव के प्रमुख सह-प्रायोजकों में से एक था जिसे बिना मतदान के पारित कर दिया गया और जिसे 50 राज्यों ने सह-प्रायोजित किया था।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक (ई एस सी) अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत भारत की समेकित दूसरी और पांचवी आवधिक रिपोर्टों पर आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा 7-8 मई, 2008 तक जेनेवा में आयोजित इसके 40वें सत्र में विचार किया गया। भारत से गये अंतर-मंत्रालयी शिष्टमण्डल का नेतृत्व हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने किया और भारत के महान्यायवादी एक सदस्य के रूप में शामिल थे।

भारत ने अक्टूबर, 2008 में एक वर्ष की अवधि के लिए मानवाधिकार मुद्दों पर एशियाई समूह के समन्वयक का कार्यभार संभाल लिया।

अनेक प्रसिद्ध भारतीयों ने महत्वपर्ण संधि मानिटरिंग निकायों और मानवाधिकार तंत्र के सदस्य के रूप में विशेष सेवा प्रदान करना जारी रखा। इनमें शामिल थे श्री पी.एन. भगवती(मानवाधिकार समिति के सदस्य), श्री चंद्रशेखर दासगुप्ता(सदस्य, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध समिति), श्री दिलीप लाहिरी(नस्लभेद उन्मूलन से संबद्ध समिति के सदस्य) और श्री अर्जुन सेनगुप्ता(अध्यक्ष, विकास के अधिकार से संबद्ध अंतस-सरकारी कार्यकारी दल)। सुश्री इन्दिरा जयसिंह को महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति का हमारा नया सदस्य चुना गया। श्री आनंद ग्रोवर को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोत्तम मानकों का उपभोग करने के अधिकार पर विशेष रैपोर्टियर नियुक्त किया गया।

किम्बर्ली प्रक्रिया स्पष्टीकरण योजना (के पी सी एस)

वर्ष 2008 के लिए भारत के पी सी एस का अध्यक्ष था। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मित से एक संकल्प के प्रारूप को स्वीकार किया जिसमें किम्बर्ली प्रक्रिया के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त भारत ने 3-6 नवम्बर, 2008 तक नई दिल्ली में किम्बर्ली प्रक्रिया की पूर्ण बैठक की मेजबानी की।

चुनाव

भारत को संयुक्त राष्ट्र के चुनावों में सफलता मिलनी जारी रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित चुनाव सफलतापूर्वक लड़े गयेः

- इकोसोकः 22 अक्टूबर, 2008 को भारत को 3 वर्षों (2009-2011) की अवधि के लिए सुयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इकोसोक के लिए चुन लिया गया।
- समुद्री कानून से संबद्ध अभिसमय के राज्य पक्षकारों की 18वीं बैठक के दौरान आयोजित चुनावों में 13 जून, 2008 को डा0 पी. चंद्रशेखर राव को समुद्री कानून से संबद्ध अंतराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए चुन लिया गया।
- जुलाई 2008 को आयोजित महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन से संबद्ध अभिसमय के राज्य पक्षकारों की 15वीं बैठक के दौरान आयोजित चुनावों में सुश्री इन्दिरा जयसिंह को महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के उन्मूलन से संबद्ध समिति(सी ई डी ए डब्ल्यू) के लिए चुन लिया गया।
- 11 अक्टूबर, 23008 को बार्सिलोना में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कांग्रेस के दौरान श्री अशोक खोसला को आई यू सी एन का अध्यक्ष चुना गया।

जलवायु परिवर्तन वार्ताएं और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की रूपरेखा (यू एन एफ सी सी सी)

जलवायु परिवर्तन से संबद्ध अंतर-सरकारी पैनल के 29 वें सत्र का आयोजन 27 अगस्त - 4 सितम्बर, 2008 तक जेनेवा में किया गया। श्री राजेन्द्र पचौरी को पुनः आई पी सी सी का अध्यक्ष चुन लिया गया।

दीर्घावधिक सहयोग कार्य योजना पर तदर्थ कार्यकारी दल और क्वेटो प्रोतोकोल के अंतर्गत अनिबंध । के पत्रकारों की अगली वचनबद्धताओं से संबद्ध तदर्थ कार्यकारी दल सहित यू एन एफ सी सी सी बाली कार्य योजना के तहत वार्ताएं बैंकाक(31 मार्च - 4 अप्रैल, 2008), बोन (4-13 जून, 2008) और पोजनान (1-12 दिसम्बर, 2008) तक आयोजित की गईं। भारत ने इन बैठकों में सक्रिय भागीदारी की और अनुकूलन, प्रशमन, प्रौद्योगिकी अंतरण, वत्तिपोषण, एम आर वी (परिमेय, प्रतिवेद्य, सत्यापनीय) और आर ई डी डी (मरूस्थलीकरण और वन क्षरण से उत्सर्जन प्रशमन) पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं।

पर्यावरण एवं वन सचिव न 1-12 दिसम्बर, 2008 तक पोजनान, पोलैंड में जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय(यू एफ सी सी सी) के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन और क्वेटो प्रोटोकोल के पक्षकारों की चौथी बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। शिष्टमण्डल में मंत्रालय के अधिकारीगण शामिल थे।

प्रधान मंत्री ने 9 जुलाई, 2008 को होक्काइदो टोयाको, जापान में जी-8 शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक के शीर्षक के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठक में भाग लिया। प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ओजस्वी हस्तक्षेप वक्तव्य दिया। शिखर सम्मेलन के पश्चात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बैठक (एम ई एम) घोषणा जारी की गई।

स्वच्छ विकास और जलवयायु के लिए एशिया प्रशांत भागीदारी की कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक वर्ष में दो बार 19-20 मई, 2008 तक शिएटल, अमरीका और 29-30 अक्टूबर, 2008 तक वैकूंवर,कनाडा में हुई जिसका उद्देश्य इसके कार्यों को आगे बढ़ाना है। ए पी पी में आठवें कार्य बल में विभिन्न परियोजनाओं पर पर्याप्त कार्य किया गया है और अनेक परियोजनाएं समय से पूरी हुई हैं।

प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई ओ एम)

इस अवधि के दौरान प्रवासन मुद्दे पर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संबंधित क्रियाकलाप किये। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि भारत जून, 2008 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का सदस्य बन गया। पूर्ण सदस्यता से हम प्रवासन मुद्दे से संबंधित प्रमुख संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर सकेंगे।

वैश्विक प्रवासन और विकास मंच (जी एफ एम डी)

विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव(पी पी एण्ड आर) के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी शिष्टमण्डल ने 29-30 अक्तूबर, 2008 तक मनीला में आयोजित प्रवास और विकास से संबद्ध वैश्विक मंच की द्वितीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सार्वभौमिक डाक संघ (यू पी यू)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने जेनेवा (23 जुलाई - 12 अगस्त, 2008) तक आयोजित यू पी यू के 24वें सम्मेलन में भाग लिया। भारत को सार्वभौमिक डाक संघ (यू पी यू) के संघ प्रशासन परिषद (सी ए) और डाक कार्य परिषद (पी ओ सी) के लिए चुन लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय दूर-संचार संगठन(आई टी ओ)

सचिव, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 12-21 नवम्बर, 2008 तक जेनेवा में आयोजित आई टी यू परिषद के वर्ष 2008 के सत्र में भाग लिया। उन्होंने "जलवायु परिवर्तन अनुकूलनः आपातकालीन दूरसंचार की भूमिका" विषय पर 13 नवम्बर, 2008 को आयोजित सत्र के दौरान पैनल के सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय बठैक में भाग लिया।

इन्टरनेट अभिशासन मंच(आई जी एफ)

भारत ने 3-6 दिसम्बर, 2008 तक हैदराबाद में तीसरे इंटरनेट अभिशासन मंच (आई जी एफ) की मेजबानी की। सरकारें, सभ्य समाज और निजी क्षेत्र तथा इंटरनेट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 94 देशों के लगभग 1300 सहभागियों ने इस बैठक में भाग लिया। हैदराबाद आई जी एफ की विषय-वस्तु थी "सभी के लिए इंटरनेट"।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम(यू एन हैबिटेट)

भारत यू एन हैबिटेट का एक संस्थापक सदस्य है और यह 1978 में इसकी स्थापना के बाद से ही इसका सक्रिय भागीदार रहा है। इस संगठन के साथ भारत के दीर्घावधिक सहयोग के भाग के रूप में इसने 3-6 नवम्बर, 2008 तक नानजिंग, चीन में यू एन-हैबिटेट द्वारा आयोजित विश्व शहरी मंच के चौथे सत्र में भाग लिया। इस बैठक की विषय-वस्तु थी "सामंजस्यपूर्ण शहरीकरणः संतुलित क्षेत्रीय विकास की चुनौतियाँ"। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) कुमारी शैलजा ने किया जो फिलहाल यू एन हैबिटेट की शासी परिषद की अध्यक्ष हैं। कुमारी शैलजा ने विश्व शहरी मंच के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में पैनल सदस्य के रूप में भी भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान(आई डी ई ए)

भारत, जो स्टाकहोम में अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का एक संस्थापक सदस्य है, ने इस वर्ष इस संगठन के भीतर महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाना जारी रखा। भारत जून 2007 से 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए की शासी परिषद का अध्यक्ष रहा। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए ने स्पष्ट आकार प्राप्त कर लिया और इसके कार्यक्रमों में मुख्यतः विकास में लोकतंत्र, विविधता में लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के योगदान की पहचान करने जैसे मुद्दों का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 17-18 जून, 2008 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए की शासी परिषद की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। "लोकतंत्र और विकास" पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन परिषद की बैठक के दौरान किया गया जिसका उद्घाटन माननीय वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने किया। इस वर्ष के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए के बीच भी सहयोग जारी रहा जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय आई डी ई ए के ज्ञान आधार में बढ़ोत्तरी करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया।

अंतर संसदीय संघ (आई पी यू)

आई पी यू की 119वीं सभा 10-12 अक्तूबर, 2008 तक जेनेवा में आयोजित की गयी। लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री सी. एस. अटवाल के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने विचार-विमर्शों में भाग लिया।

कार्यसूची की महत्वपूर्ण मदों में शामिल थीः (1) मौजूदा वैश्विक वित्तीय स्थिति संबंधित आपातकालीन मदों पर बहस; और (2) नाभिकीय अप्रसार और निः शस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने और व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिषेध संधि को प्रभावित किए जाने को सुनिश्चित किए जाने, सांसदों की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार; तथा जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास मॉडल और नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर पैनल चर्चा। संसदीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

लोकसभा सांसद श्री रूपचंद्र पाल की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय शिष्टमण्डल ने विश्व व्यापार संगठन से संबद्ध संसदीय सम्मेलन के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए जेनेवा का दौर किया।

संसद सदस्य श्रीमती रंजीता रंजन ने 6-8 दिसम्बर, 2008 तक महिला-पुरूष समानता से संबद्ध महिलाओं की स्थिति पर संसदीय समितियों के सदस्यों और अन्य समितियों के तीसरे सम्मेलन में भाग लिया।

निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा

वैश्विक नाभिकीय निः शस्त्रीकरण सहित सामान्य और पूर्ण निः शस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की वचनबद्धता सभी नीतिगत वक्तव्यों और राजनयिक गतिविधियों में परिलक्षित होती रही। निः शस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ क्रियाकलाप करने की उसकी परंपरा पर आधारित था।

वर्ष 2008 प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा महासभा में निः शस्त्रीकरण से संबद्ध तृतीय विशेष सत्र में प्रस्तावित "नाभिकीय शस्त्र मुक्त और अहिंसक विश्वव्यवस्था की शुरूआत के लिए कार्य योजना" की बीसवीं वर्षगांठ थी। सार्वभौमिक, निष्पक्ष नाभिकीय निः शस्त्रीकरण, जिसके आधार पर नाभिकीय शस्त्रों का उन्मूलन

हो सकेगा, के प्रति भारत की वचनबद्धता "नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व की ओर" पर 9 जून, 2008 को आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा भी दोहरायी गई जिसका आयोजन नई दिल्ली में राजीव गांधी कार्ययोजना की प्रथम वर्षगांठ पर ट्रैक -II पहल के रूप में की गई थी।

भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और एशिया में क्रियाकलाप और विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध सम्मेलन (सी आई सी ए) की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की। विभिन्न मुद्दों पर भारत के विचारों का प्रसार करने के लिए निः शस्त्रीकरण के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाये रखे गये। भारत के निर्यात नियंत्रण कानूनों और सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर भारतीय उद्योग जगत और अन्य भागीदारों के साथ जन-संपर्क गतिविधियाँ भी चलाई गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

23 सितम्बर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गये वक्तव्य में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वैश्विक, सार्वभौमिक और निष्पक्ष स्वरूप के नाभिकीय निः शस्त्रीकरण के प्रति भारत की दीर्घकालिक वचनबद्धता का स्मरण किया। प्रधान मंत्री ने 20 वर्ष पूर्व महासभा में प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना का भी स्मरण किया। प्रधान मंत्री ने नाभिकीय शस्त्र अभिसमय के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया जिसके अंतर्गत नाभिकीय हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके पूर्ण उन्मूलन का प्रावधान किया जा सके।

महासभा की पहली समिति में हुई आम बहस के दौरान निः शस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने नाभिकीय निः शस्त्रीकरण के प्रति भारत की वचनबद्धता को रेखांकित किया और बहस को बढ़ावा देने तथा आगे के कार्यों पर सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के लिए कुछ व्यावहारिक उपायों का सुझाव दिया। पहले ही इन उपायों को महासभा तथा निः शस्त्रीकरण सम्मेलन मे रखा गया है और इनमें शामिल हैः

- नाभिकीय शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्यों की वचनबद्धता की पुष्टि;
- सुरक्षा सिद्धांतों में नाभिकीय शस्त्रों की प्रमुखता में कमी;
- नाभिकीय हथियार की वैश्विक पहुंच और खतरे को ध्यान में रखते हुए अचानक होने वाले नाभिकीय युद्ध सहित नाभिकीय खतरों में कमी लाने के लिए नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्यों द्वारा कदमों का स्वीकरण, अनिच्छा से और अचानक होने वाले नाभिकीय हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए नाभिकीय शस्त्रों को चौकसी की स्थिति से हटाना।
- नाभिकीय शस्त्रों के "प्रथम उपयोग नहीं" पर नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्यों के बीच वैश्विक सहमति पर बातचीत।
- परमाणु अस्त्रों से वंचित राज्यों के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग न करने से संबधित कानूनी रुप से वार्त्ता;
- नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित अभिसमय पर वार्ता;
- नाभिकीय शस्त्र अभिसमय पर वार्ता जिसके तहत नाभिकीय शस्त्रों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके, और निधारित समय-सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों का वैश्विक, भेदभाव रहित और सत्यापनीय उन्मूलन किया जा सके।

पहली समिति में "आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने से रोकने से संबंधित उपाय" पर भारत का संकल्प, जिसे पहली बार 2002 में पेश किया गया, को पुनः सर्वसम्मिति से पारित किया गया जिसमें इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मति को रेखांकित किया गया था। संकल्प में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से ऐसे उपाय करने का अनुरोध किया गया जिसका उद्देश्य आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने से रोकना था और इस बात पर बल दिया गया कि इस खतरे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया समावेशी, बहुपक्षीय तथा वैश्विक होनी चाहिए। इस वर्ष इस संकल्प को 64 राज्यों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया जिससे इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिये गये महत्व का पता चलता है।

भारत ने "नाभिकीय हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसमय" को पुनः पेश किया। संकल्प के प्रचालनात्मक भाग में निः शस्त्रीकरण सम्मेलन से ऐसी वार्ता करने का आह्वान किया गया जिससे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का मार्ग प्रशस्त हो जिसके तहत किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग और प्रयोग की धमकी पर रोक लगायी जा सके।

"नाभिकीय हथियारों के प्रशमन" पर भारत के संकल्प में नाभिकीय हथियारों के अचानक प्रयोग की संभावना को कम करने के लिए उन्हें चौकसी की स्थिति से हटाने और अन्य उपायों के महत्व को रेखांकित किया गया। संकल्प के प्रचालनात्मक भाग में नाभिकीय सिद्धांतों की समीक्षा करने और नाभिकीय हथियारों को चौकसी की स्थिति से हटाने तथा लक्ष्य से हटाने सहित उनके अचानक उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया और साथ ही नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्यों से अनुशंसित उपायों को क्रियान्वित करने हेतु उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम समिति द्वारा दो संकल्प पारित किये गये जिसमें अधिकांश सदस्य राज्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। आम सभा में 118 देशों ने "नाभिकीय हथियारों के प्रशमन" संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि 121 देशों ने "नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसमय" प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

प्रथम समिति और महासभा ने "अंतराष्ट्रीय सुरक्षा और निः शस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका" विषय पर भारत द्वारा प्रस्तावित निर्णय के प्रारूप को बिना मतदान के पारित कर दिया।

निः शस्त्रीकरण सम्मेलन

निः शस्त्रीकरण सम्मेलन(सी डी) "एकमात्र बहुपक्षीय निः शस्त्रीकरण संधि वार्ता निकाय" है जिसमें 65 राज्य हैं। वर्ष 2008 के सत्र में इसकी बैठक जेनेवा में 21 जनवरी - 28 मार्च, 13 मई - 27 जून और 28 जुलाई - 12 सितम्बर तक हुई। 2008 के सत्र में निः शस्त्रीकरण सम्मेलन की कार्ययोजना पर सर्वसम्मित नहीं बनी क्योंकि वार्ता की प्राथमिकताओं पर राज्यों के बीच मतभेद बने रहे। भारतीय शिष्टमण्डल ने कार्ययोजना पर सर्वसम्मित बनाने के लिए साझे लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने के लिए अन्य शिष्टमण्डलों के साथ मिलकर कार्य किया जिससे कि निः शस्त्रीकरण सम्मेलन में प्रगति हो सके। भारत का दृष्टिकोण मौलिक सिद्धांतों पर साझी समझ बनाने और अधिदेशों के संबंध में स्पष्टता पर पहुंचने पर आधारित था जिससे कि वार्ताएं सुचारू रूप से हो सकें और प्रक्रिया नियमावली का सम्मान किया जा सके। भारत का दृष्टिकोण एफ एम सी टी पर वार्ता सहित कार्य योजना के आधार पर ठोस कार्यों की शुरूआत किये जाने के पक्ष में था।

संयुक्त राष्ट्र निः शस्त्रीकरण आयोग

2008 में संयुक्त राष्ट्र निः शस्त्रीकरण आयोग का तीन सप्ताह का सत्र 7-24 अप्रैल तक न्यूयार्क में आयोजित किया गया। यू एन डी सी का 2008 का सत्र तीन वर्षों की अवधि में तीसरा था जिसमें दो कार्यसूची मदों, नामतः "नाभिकीय निः शस्त्रीकरण और नाभिकीय हथियारों के अप्रसार लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुशंसाएं" तथा "पारंपरिक हथियारों" के क्षेत्र में व्यावहारिक विश्वासोत्पादक उपाय पर बल दिया गया । यू एन डी सी में इन दोनों कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

जैविक हथियार अभिसमय (बी डब्ल्यू सी)

वर्ष 2006 में जेनेवा में आयोजित बी डब्ल्यू सी के राज्य पक्षकारों की छठी समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक और निर्धारित विषयों पर वर्ष 2011 में निर्धारित अगली समीक्षा सम्मेलन तक राज्य पक्षकारों की वार्षिक बैठक आयोजित करने के निर्णय के अनुसरण में विशेषज्ञों की बैठक(18-22 अगस्त) और राज्य पक्षकारों की बैठक(1-5 दिसम्बर) जेनेवा में अयोजित की गई। बैठकों में निम्नलिखित पर चर्चा की गई और साझी समझ-बूझ तथा प्रभावी कार्यवाई को बढ़ावा दिया गयाः (I) प्रयोगशाला सुरक्षा तथा पैथोजेन्स एवं टाक्सिन्स की प्रयोगशाला सुरक्षा सहित जैव सुरक्षा तथा जैव संरक्षा में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय। (II) अभिसमय द्वारा निषिद्ध उद्देश्यों हेतु उपयोग की क्षमता के साथ जैव-विज्ञान तथा जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में हुई प्रगति के संदर्भ में दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आचरण नियामावली की ओवरसाइट, शिक्षा, जागरूकता, निर्माण तथा अंगीकरण और/ अथवा विकास।

भारत ने विशषज्ञों की बैठक और राज्य पक्षकारों की बैठक में हुए विचार-विमर्शों में सक्रिय भागीदारी की। विशेषज्ञों की बैठक में भारत उन देशों में था जिनके शिष्टमण्डल में उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। भारत ने विशेषज्ञों की बैठक में दो प्रस्तुतियाँ दी, पहली भारत की "जैव-उद्योग समीक्षा" तथा दूसरी "शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और आचरण नियमावली"। राज्य पक्षकारों की बैठक में भारत ने चर्चाओं में पर्याप्त योगदान दिया तथा अध्यक्ष की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में रचनात्मक भूमिका निभाई।

कतिपय पारंपारिक हथियारों से संबद्ध अभिसमय (सी सी डब्ल्यू)

भारत कतिपय पारंपारिक हथियारों, जिन्हें अत्यंत खतरनाक माना जा सकता है और जिनका अंधाधुंध प्रभाव हो सकता है, के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध लगाने से संबद्ध अभिसमय का एक उच्च संविदाकारी पक्षकार है और इसने इसके सभी पांचों प्रोटोकोलों का अनुसमर्थन किया है जिनमें बारूदी सुरंगों, छद्म बम और अन्य हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध पर संशोधित प्रोतोकोल-स्र्ह तथा युद्ध के विस्फोटक अवशेषों पर प्रोतोकोल ज्र्ह भी शामिल हैं। भारत ने अभिसमय के अनुच्छेद 1 में संशोधन का भी समर्थन किया है।

सी सी डब्ल्यू से संबद्ध अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकारों की वार्षिक बैठक का आयोजन 13-14 नवम्बर, 2008 तक जेनेवा में किया गया। 2007 में राज्य पक्षकारों की बैठक में सरकारी विशेषज्ञों के समूह से एक ऐसे प्रस्ताव पर बातचीत करने का अनुरोध किया गया था जिससे कि सैन्य और मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एकत्रित विस्फोटकों के मानवीय प्रभाव की समस्या पर तत्काल ध्यान दिया जा सके और उसकी रिपोर्ट 2008 की बैठक से पहले प्रस्तुत की जाए। 2008 में जी जी ई की बैठक पांच बार और कुल सात हफ्तों के लिए हुई। इसने रिपोर्ट किया कि वह अपनी वार्ताएं सम्पन्न करने में असमर्थ रही। वर्षिक बैठक में निर्णय लिया गया कि जी जी ई अपनी वार्ताएं जारी रखेगा और इसे यथासंभव शीघ्र संपन्न करने के प्रयास करेगा और उच्च संविदाकारी पक्षकारों की अगली बैठक (2009) को रिपोर्ट करेगा। जी जी ई को इस प्रयोजनार्थ 2009 में दो सप्ताह तक बैठक करने का अधिदेश दिया गया। एक भारतीय शिष्टमण्डल, जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, ने एकत्रित विस्फोटकों पर 16-20 फरवरी, 2009 तक आयोजित जी जी ई बैठक में भाग लिया।

युद्ध के विस्फोटक अवशेषों पर सी सी डब्ल्यू के प्रोटोकोल V, जो नवम्बर 2008 में प्रवृत हुआ, की दूसरी वार्षिक बैठक जेनेवा

मे 10 नवम्बर, 2008 में आयोजित की गई। अध्यक्ष के रूप में लिथुआनियां ने बैठक की अध्यक्षता की जबकि भारत और आस्ट्रेलिया ने उपाध्यक्षों के रूप में कार्य किया। भारत ने 2008 मे आयोजित होने वाली एम एस पी के विषयों में से एक का समन्वय किया। भारत को 2009 में प्रोतोकोल वी एम एस पी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

बारूदी सुरंगों, छद्म बमों और अन्य विस्फोटकों के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध पर सी सी डब्ल्यू अभिसमय के संशोधित प्रोटोकोल II के राज्य पक्षकारों की वार्षिक बैठक 12 नवम्बर, 2008 तक जेनेवा में आयोजित की गई। भारत ने संशोधित प्रोटोकोल II के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए उठाये गये कदमों और बारूदी सुरंगों से मुक्त विश्व के विजन के प्रति अपनी वचनबद्धता के बारे में बैठक को सूचित किया।

भारत "बारूदी सुरंगों के उपयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा स्थानांतरण पर प्रतिबंध और उन्हें नष्ट किये जाने से संबद्ध अभिसमय" अथवा ओटावा अभिसमय का राज्य पक्षकार नहीं है क्योंकि वह राज्यों द्वारा इसके जिम्मेदारी से उपयोग किये जाने को प्रतिरक्षा का एक वैध उपकरण मानता है। फिर भी भारत बारूदी सुरंग मुक्त विश्व के संयुक्त राष्ट्र के विजन को स्वीकार करता हैं और बारूदी सुरंगों के स्थान पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ लाने के लिए तैयार है। इसी भावना में भारत दिसम्बर, 2004 में नैरोबी में आयोजित अभिसमय के प्रथम समीक्षा सम्मेलन के बाद से ही पर्यवेक्षक के रूप में अभिसमय की बैठकों में भाग लेता रहा है। भारत ने 24-28 नवम्बर तक ओटावा अभिसमय के राज्य पक्षकारों की नौवीं वार्षिक बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इसी प्रकार भारत ने 2-6 जून, 2008 तक जेनेवा में आयोजित इस अभिसमय की स्थायी समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

लघु शस्त्र एवं हल्के हथियार

जुलाई 2001 में पारित सभी प्रकार के लघु और हल्के हथियारों पर रोक लगाने, मुकाबला करने तथा उन्मूलन करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम(यू एन पी ओ ए) में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक उपायों का प्रावधान किया गया है। भारत ने बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया है। 2008 में भारत ने 14-18 जुलाई, 2008 तक न्यूयार्क में आयोजित राज्यों की द्विवार्षिक बैठक में भाग लिया जिसमें यू एन पी ओ ए तथा अंतराष्ट्रीय ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को अंगीकार किया गया।

आई ए ई ए

अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (आई ए ई ए) के शासी मण्डल के सदस्य के रूप में भारत ने आई ए ई ए के विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लिया और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत एजेंसी की ओर से चलाये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों के जरिए ऐजेंसी के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में पर्याप्त सहयोग दिया और नाभिकीय ऊर्जा के खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्य संबंधी अनुप्रयोगों, नाभिकीय सुरक्षा, एजेंसी के सुरक्षोपाय प्रणाली आदि के संवर्धन पर आई ए ई ए की वार्षिक आम सभा में संकल्प पारित किये गये।

1 अगस्त, 2008 को आयोजित विशेष सत्र में आई ए ई ए के शासी मण्डल ने भारत और एजेंसी के बीच भारत विशिष्ठ सुरक्षोपाय करार को सर्वसम्मित से अनुमोदित कर दिया। 2 फरवरी, 2009 को भारत और आई ए ई ए ने वियना में असैनिक नाभिकीय संयत्रों के सुरक्षापायों के अनुप्रयोग पर करार (आई एस एस ए) संपन्न किया। 3 मार्च, 2009 को आई ए ई ए के शासी मण्डल ने भारत और आई ए ई ए के बीच वार्ता पर आधारित एक अतिरिक्त प्रोटोकोल के पाठ का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

भारत विशेष सुरक्षा उपाय करार अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आईएनएफसीआईआरसी 66 प्रावधानों पर आधारित है तथा इसमे भारत पृथक्करण योजना के अर्न्तगत भारत द्वारा प्रस्तावित वे परमाणु संयंत्र परमाणु सुविधाएं तथा भविष्य में निर्माण किए जाने वाले वे संयंत्र भी शामिल है, जिनके लिए विदेशों से सामग्री / प्रौद्योगिकी / उपस्कर प्राप्त किए जाने है। भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम भारत व अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच वार्तासम्मत् सुरक्षा करारों व अतिरिक्त प्रोतोकाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। भारत की पृथक्करण योजना के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित संयंत्रों की पहचान कर ली गई है तथा भारत द्वारा इन संयंत्रों को अधिसूचित किए जाने के बाद इन सुरक्षा उपायों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरु कर दिया जाएगा। भारत विशेष सुरक्षा उपाय करार से संबद्ध एकपक्षीय व बहूपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग व्यवस्था लागू करने में सहायता मिलेगी।

29 सितम्बर-4 अक्टूबर, 2008 तक आयोजित आई ए ई ए की 52वीं महासभा में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व डा0 अनिल काकोदकर ने किया। डी ए ई के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव ने पूर्ण सत्र में राष्ट्रीय वक्तव्य देने के अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा संसाधन के रूप में थोरियम के उपयोग पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। महासभा के दौरान भारत की प्रदर्शनी में विश्व में स्वच्छ, सुरक्षित, सतत् तथा तीव्र ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती का समाधान करने के लिए थोरियम की क्षमताओं पर विशेष बल दिया गया।

नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह

6 सितम्बर, 2008 को एन एस जी ने असैनिक नाभिकीय

सहयोग पर एक वक्तव्य जारी किया जिसके जरिए भारत के साथ पूर्ण नाभिकीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत ने एन एस जी के निर्णय को प्रगतिशील और महत्वपूर्ण करार दिया क्योंकि इसके फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अन्य देशों के साथ सहयोग किये जाने तथा भारत की ऊर्जा एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में नया अध्याय खुल सकेगा। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक होगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 30 वर्षों से परमाणु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से इनकार करने कि नीति समाप्त करने से सम्बंधित एनएसजी का निर्णय भारत को एक विकसित परमाणु प्रौद्योगिकी वाले तथा परमाणु अप्रसार के सम्बंध में जिम्मेवार रिकार्ड वाले देश के रुप में स्वीकार करता है।

रासायनिक हथियार अभिसमय (सी डब्ल्यू सी)

भारत ने इस वर्ष के दौरान ही दि हेग में रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध से संबद्ध संगठन में सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। भारत ने दि हेग में 7-18 अप्रैल, 2008 तक आयोजित सी डब्ल्यू सी के दूसरे समीक्षा सम्मेलन और 2-5 दिसम्बर, 2008 तक आयोजित सी डब्ल्यू सी के राज्य पक्षकारों के तेरहवें सम्मेलन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपनी वचनबद्धताओं के अनुरूप अभिसमय के अधीन अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा।

एशिया में क्रियाकलाप और विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन(सी आई सी ए)

सी आई सी ए विशेष कार्यकारी दल/विरिष्ठ अधिकारी समिति की बैठक का आयोजन 18-20 फरवरी, 2009 तक नई दिल्ली, भारत में किया गया। इससे पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 25 अगस्त, 2008 को अल्माती में तीसरे सीका मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने विश्वास व्यक्त किया कि सीका आपसी समझ, विश्वास और संप्रभु समानता के आधार पर एशिया में सहकारी और बहुवादी सुरक्षा व्यवस्था में योगदान करने में सहायता कर सकता है।

आसियान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ)

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 23-24 जुलाई, 2008 तक सिंगापुर में आयोजित ए आर एफ की 15वीं बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। भारत और इंडोनेशिया ने 21-22 फरवरी, 2008 तक सेमारंग(इंडोनेशिया) में आतंकवाद निरोध तथा परा-राष्ट्रीय अपराध पर छठी अंतर-सत्रीय बैठक की सह-मेजबानी की। भारतीय तट रक्षक बल ने ए आर एफ सदस्यों के लिए समुद्री सुरक्षा पर चैन्नै में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम 24-29 मार्च, 2008 को आयोजित किया गया। पहले कार्यक्रम की सफलता के आधार पर 17-22 नवम्बर, 2008 तक एक उच्च प्रशिक्षण माड्यूल का आयोजन किया गया। इस माड्यूल में जल-दस्युता प्रतिरोध, खोज एवं बचाव, ऑफशोर तथा बंदरगाह सुरक्षा, तस्करी-रोधी तथा स्वापक नियंत्रण एवं अनाधिकार प्रवेश-रोधी कार्रवाइयाँ शामिल थी। भारत ने आपदा राहत और इंटरनेट का उपयोग आतंकवादियों द्वारा किये जाने सहित ए आर एफ की अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया।

सामरिक निर्यात नियंत्रण

भारत उन सामानों एवं प्रौद्यौगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण लगाता रहा है जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलिवरी प्रणाली के लिए किया जा सकता है। जैसा कि 2005 में अधिनियमित सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलिवरी प्रणाली अधनियम में परिकल्पना की गई है, औद्योगिक संघों के सहयोग से उद्योग जगत के साथ आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामरिक निर्यात नियंत्रण से जुड़े कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु मंत्रालय में एक प्रौद्योगिक एकक की स्थापना की गई है।

विधि एवं संधि प्रभाग

इस वर्ष विधि एवं संधि प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित रहीः

बिम्सटेक जे डब्ल्यू जी- सी टी टी सी द्वारा अभिसमय के प्रारूप पर करारः

विधि एवं संधि प्रभाग ने आतंकवाद प्रतिरोध और परा-राष्ट्रीय अपराध पर बिम्सटेक संयुक्त कार्यकारी दल(जे डब्ल्यू जी- सी टी टी सी) की चौथी बैठक का आयोजन 22-23 अक्टूबर, 2008 तक नई दिल्ली में किया। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) श्री नरिन्दर सिंह ने की। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परा-राष्ट्रीय संगठित अपराध और स्वापकों के गैर कानूनी व्यापार की रोकथाम करने से संबद्ध बिम्सटेक अभिसमय के प्रारूप पर विचार किया। इसके साथ ही (i) आम सूचना आदान-प्रदान; (ii) आतंकवाद के वित्त-पोषण की रोकथाम (iii) स्वापक औषधों; मनः प्रभावी पदार्थो और इनके कच्चे रसायनों के गैर-कानूनी व्यापार की रोकथाम; तथा (iv) विधि एवं कानून प्रवर्त्तन मुद्दों से संबंधित उप-समूहों के कार्यों की प्रगति पर लीड शैफर्ड की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया।

जे डब्ल्यू सी- सी टी टी सी ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परा-राष्ट्रीय संगठित अपराध और स्वापकों के गैर-कानूनी व्यापार की रोकथाम करने पर बिम्सटेक अभिसमय के प्रारूप पर भी सहमति व्यक्त की और इसे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में पारित किये जाने के लिए अनुशंसित किया।

यह अभिसमय बिम्सटेक सदस्य राज्यों की एजेंसियों के बीच सहयोग का एक सुदृढ़ प्रवर्तन कानूनी आधार उपलब्ध करायेगा। यह बिम्सटेक सदस्य राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आवश्यक प्रेरणाश्रोत का कार्य करेगा जिससे कि वे आसूचना के आदान-

प्रदान तथा क्षमता निर्माण क्षत्रों में प्रभावी सहयोग कर सकेगा तथा बिम्सटेक सदस्य राज्यों के बीच आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापकों के गैर-कानूनी व्यापार का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास कर सकेगा। अतः यह अभिसमय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समर्थकारी तंत्र उपलब्ध करायेगा जिससे कि वे अन्य देशों से कार्य करने वाले और इन अपराधों में शामिल लोगों/संपर्कों/नेटवर्कों का प्रभावी तरीके से पता लगा सकेगे। पारित हो जाने के उपरांत सदस्य राज्य एक-दूसरे को इन अपराधों की रोकथाम, जांच, अभियोजन तथा दमन में यथासंभव व्यापक पारस्परिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। इससे आतंकवादियों और संगठित अपराधियों को भी संकेत जाएगा कि बिम्सटेक क्षेत्र के किसी भी देश का उपयोग सुरक्षित आश्रय के रूप में नहीं किया जा सकता।

महासागर तथा समुद्री कानून

विधि एवं संधि प्रभाग ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों की कार्यसूची में समुद्री कानून से संबंधित मुद्दों की जांच की। 63वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कार्यसूची मद "महासागर एवं समुद्री कानून" तथा स्ट्रेडलिग फिश स्टॉक्स एवं उच्च प्रवासी फिश स्टॉक्स तथा संबद्ध उपकरणों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित 10 दिसम्बर, 1982 के समुद्री कानून से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 1995 के करार सहित अन्य के जरिए "उत्तरजीवी मात्स्यिकी" पर दो संकल्प 63/111 और 63/112 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में पारित किया।

समुद्री कानून से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसमें महासागर और समुद्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए कानूनी रूपरेखा निर्धारित की गई है, के सार्वभौमिक स्वरूप पर बल देते हुए महासभा ने इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय विधान का सामंजस्य अभिसमय के साथ बैठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने दाता एजेंसियों और अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सभी राज्यों, विशेष रूप से विकासशील राज्यों के लिए इस अभिसमय के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक, कानूनी, नौवहन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कौशल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। महासभा ने राज्यों से विकासशील देशों को सभी प्रकार के तकनीकी सहयोग देने का भी आह्वान किया ताकि वे महाद्वीपीय मग्नतट आयोग(सी एल सी एस) के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकें।इसने अभिसमय के राज्य पक्षकारों की बैठक के निर्णय को वहीं तक स्वीकार किया जहां तक महासचिव की प्रारम्भिक जानकारी प्रस्तुत किए जाने का संबंध है जो कि 200 समुद्री मील से इसे महाद्वीपीय मग्नतट की बाहरी सीमाओं एवं तैयारी की स्थिति का विवरण देकर दावे प्रस्तुत करने की वांछित तारीख का सूचक है। सोमालिया तट पर समुद्री लूट और सशस्त्र डकैती की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए महासभा ने राज्यों से समुद्री लूट का मुकाबला करने के लिए आई एम ओ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित विधिक उपायों को पूर्णतः क्रियान्वित करने का आह्वान किया है।

मात्स्यिकी से जुड़े मसलों पर महासभा ने राज्यों से लाभकारी स्वामियों और गैर कानूनी, असूचित तथा अनियमित मछली पकड़ने की घटनाओं में शामिल होने से रोकने के लिए जहाजों पर ध्वज लगाने सहित राज्यों से अपने राष्ट्रिकों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का अनुरोध किया। महासभा ने राज्यों से सतर्कता और पारिस्थितिकी अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया जिससे कि फिश स्टॉक करार के अनुसरण में स्ट्रेडलिंग फिश स्टॉक्स का संरक्षण और प्रबंधन तथा दोहन किया जा सके और करार के प्रावधानों के साथ उनके राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य बैठाया जा सके।

समुद्र से सामानों के पूर्ण अथवा आंशिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए संविदाओं पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

महासभा ने अपने 63वें सत्र में संकल्प 63/122 के द्वारा समुद से सामानों के पूर्ण अथवा आंशिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए संविदाओं संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को पारित कर दिया। महासभा ने सितम्बर 2009 में रोटरडम, नीदरलैंड में हस्ताक्षर समारोह के आयोजन को अधिकृत किया। इस अभिसमय को "रोटरडम नियमावली" के रूप में जाना जाएगा।

इस अभिसमय का उद्देश्य सामानों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए एक सुसंगत और समान कानूनी व्यवस्था का सृजन करना है। अभिसमय का क्षेत्र सिर्फ बंदरगाह से बंदरगाह तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें द्वार से द्वार तक परिवहन को शामिल किया गया है जो समुद्री परिवहन से पूर्व के जमीनी परिवहन पर भी लागू होगा। इस अभिसमय के अन्तर्गत परिवहन संविदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पड़ाव एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनेक नई विशेषताएं भी हैं जिन्हें परिवहन के संविदाकारी पक्षों के लाभार्थ शामिल किया गया है जिनसे उनके हितों में संतुलन आयेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो सकेगा। इन विशेषताओं में शामिल हैं इलेक्ट्रानिक परिवहन रेकार्डों, निष्पादक पक्ष, नियंत्रक पक्ष, अधिकारों का हस्तांतरण तथा अन्य तकनीकी विशेषताएं जिनसे वर्तमान परिवहन व्यवस्थाओं की कमियों को दूर किया जा सके।

अभिसमय के जरिए पोत और मालवाहक के स्वामी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसके द्वारा वार्ता आधारित व्यवस्था का सृजन किया गया है और परिवहन संविदा का कोई भी पक्ष एकपक्षीय तौर पर दूसरे पक्ष पर अपना विचार नहीं थोप सकता है।

अभिसमय के अंतर्गत इस सौहार्दपूर्ण और आधुनिक कानूनी व्यवस्था से समग्र कारोबारी लागत में कमी आयेगी और समस्याओं की स्थिति में संबंधित पूर्वानुमेयता बढ़ेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के दौरान बेहतर व्यावसायिक विश्वास को बढ़ावा मिल सकेगा।

इससे सामानों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इसमें सामान के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून की उभरती प्रक्रिया का प्रगतिशील विकास परिलक्षित होता है जो विश्व के अधिकांश भागों में 1920 के दशक से अथवा इसके पूर्व से विद्यमान है।

विधि एवं संधि प्रभाग ने अभिसमय की वार्ता में 2002 में इसके आरंभ से वर्ष 2008 में इसकी समाप्ति तक की वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत विश्व की प्रमुख समुद्री ताकतों में से एक है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के द्वारा किया जाता है। पोत और मालवाहक के बीच स्थापित नाजुक संतुलन, प्रवर्तन के व्यापक क्षेत्र, संविदा के अधिकार तथा सामानों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किये जाने के लिए नई एवं तकनीकी विचारधाराएं लाये जाने से पोत-परिवहन उद्योग को लाभ होगा।

प्रत्यर्पण एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता

विधि एवं संधि प्रभाग ने अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां तथा आपराधिक एवं सिविल मामलों में आपसी कानूनी सहायता से संबद्ध करार संपन्न करने के लिए होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया। बेलारूस, मॉरीशस और उक्रेन के साथ हुई सफल वार्ताओं के उपरांत उनके प्रवर्तन और लागू किए जाने से संबंधित प्रक्रियाएं वर्ष 2008 में पूरी की गयीं। मिस्र और ईरान के साथ संधियों पर भी बातचीत हुई और इन पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें अभी लागू किया जाना है। मलेशिया और इजराइल के साथ प्रत्यर्पण संधि के संबंध में वार्ताएं भी हुईं।

विधि एवं संधि प्रभाग ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता से संबद्ध सार्क अभिसमय का प्रारूप तैयार किया। सफल बातचीत के उपरांत, सार्क अभिसमय को स्वीकार किया गया और इस पर कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 15वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 3 अगस्त, 2008 को हस्ताक्षर किए गए। सार्क के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात यह प्रवृत्त हो जाएगा। इस क्षेत्र में मिस्र के साथ द्विपक्षीय संधि पर बातचीत की गयी और इस पर हस्ताक्षर किए गए। बोस्निया हरजेगोविना के साथ संधि के पाठ पर वार्ता करके इसे अंतिम रूप दिया गया। मलेशिया, ओमान और इजराइल के साथ भी इस क्षेत्र में बातचीत की गयी।

विधि एवं संधि प्रभाग ने घरेलू और विदेशी क्षेत्राधिकार से प्राप्त प्रत्यर्पण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्य अनुरोधों की जांच की तथा उन्हें विधिक परामर्श दिए।

अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान (यूनिडरॉइट)

यूनिडरॉइट एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय रोम में है। इसका उद्देश्य राज्यों तथा राज्यों के समूहों के निजी कानूनों में तालमेल बैठाने और उनका समन्वय करने के तौर-तरीकों की जांच करना तथा इन्हें समान निजी कानून वाले विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसका वही कार्य है जो सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में यूनीसिट्राल का है।

यूनिडरॉइट की शासी परिषद का चुनाव 11 दिसंबर, 2008 को यूनिडरॉइट महासभा के 63वें सत्र के दौरान किया गया। शासी परिषद में पुनः चयन के लिए भारत ने श्री बी. सेन को मनोनीत किया था, जो सर्वाधिक मतों से चुन लिए गए।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन

मार्च, 2008 में भारत हेग सम्मेलन का सदस्य बना। फिलहाल 69 राज्य/क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन हेग सम्मेलन के सदस्य हैं।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबद्ध हेग सम्मेलन एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों अथवा भिन्न-भिन्न कानूनों के बीच उत्तरोत्तर एकीकरण के लिए कार्य करना है। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, प्रवर्तनीय कानून तथा वाणिज्यिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय सिविल प्रक्रियाएं और बाल संरक्षण, विवाह तथा निजी मुद्दों से संबंधित मामलों जैसे व्यापक क्षेत्रों में निर्णयों को स्वीकार एवं प्रवर्तित करने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत दृष्टिकोण प्राप्त करके किया जाना है।

अब तक हेग सम्मेलन में सिविल प्रक्रियाओं, पारिवारिक कानून तथा वाणिज्यिक कानून से संबंधित कुल 39 अभिसमयों/प्रोतोकोलों को पारित किया जा चुका है।

हेग सम्मेलन के तत्वावधान में किए गए कार्य भारतीय नागरिक विदेशी व्यापार गतिविधियों में शामिल होने अथवा विवाद के एक पक्षकार के विदेश में होने और विदेश में भारतीय मूल के लोगों के बीच पारिवारिक विवाद होने अथवा विशेष रूप से विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप उत्पन्न कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

हेग सम्मेलन के सदस्य राज्य के रूप में भारत अधिकार से हेग सम्मेलन की सभी बैठकों और सम्मेलनों में भाग ले सकेगा तथा सम्मेलन की कार्य योजना, विशेष रूप से वर्तमान अभिसमयों के कार्यों के संहिताकरण तथा जांच के लिए निर्धारित किए जाने वाले नए क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेने में भी इसकी भूमिका होगी।

स्थायी विवाचन न्यायालय (पीसीए)

भारत ने नई दिल्ली में पीसीए का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाने के लिए 19 सितंबर, 2008 को दी हेग में पीसीए के साथ मेजबान राष्ट्र करार संपन्न किया।

पीसीए उन विवादों के लिए विवाचन, सुलह और तथ्य निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल होता है, जिसमें विभिन्न राज्य, निजी पक्ष तथा अंतरसरकारी संगठन शामिल होते हैं। राज्य न सिर्फ बहुधा पीसीए का सहारा लेते हैं, बल्कि पीसीए के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विवाचन कार्य भी किया जाता है। हालांकि आरंभ में इसकी परिकल्पना विभिन्न राज्यों के विवादों का

समाधान करने के लिए एक निकाय के रूप में की गयी थी, परंतु पीसीए ने उन मामलों के लिए भी विवाचन नियमों को स्वीकार किया है, जिसमें सिर्फ एक पक्षकार ही राज्य है।

नई दिल्ली स्थित पीसीए क्षेत्रीय केंद्र इस क्षेत्र में दो राज्यों के बीच विवाद, एक राज्य और एक गैर-राज्य इकाई जैसे कि विदेशी कंपनियां, जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश किए हैं, और जिनमें पक्षों ने अपना विवाद निर्वाचन के जरिए निपटाने पर सहमति व्यक्त की है, के बीच विवादों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवाचनों के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विचाचन के लागत में भी कमी आएगी जिससे विवादों का समाधान करने के लिए राज्य बार-बार विवाचन का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस विवाद के पक्षकारों को अपने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु विवाचक के रूप में अपनी पसंद के ऐसे व्यक्तियों को चुनने का अधिकार होगा, जो इस क्षेत्र के जानकार हों। इससे विवाद निपटान के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति भी संवर्धित होगी। इससे अधिक से अधिक संख्या में भारत के कानून विशेषज्ञ क्षेत्रीय केंद्र के तत्वावधान में विवाचनों में भाग ले सकेंगे, जिससे उनकी विशेषज्ञता मे वृद्धि होगी तथा घरेलू विवाचनों पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

विचाचन और विवाद समाधान के अन्य वैकल्पिक तरीकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पीसीए ने लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और कोस्टारिका में क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की है।

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की विधिक उप समिति का 47वां सत्र (अनकोपुओस)

इस समिति के लिए भारतीय शिष्टमंडल ने विधिक उप समिति की सभी कार्यसूची मदों पर हुई बहस में भाग लिया। इस सत्र में वाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण दोहन और उपयोग के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय विधान पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यसूची मद के अंतर्गत राज्यों द्वारा इस संबंध में अनेक वक्तव्य दिए गए कि किसी राष्ट्रीय विधान को अंतरिक्ष गतिविधियों, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, देयता, मुआवजा प्रक्रियाओं और राज्य से प्रमोचित अंतरिक्ष वस्तुओं के लिए बीमा के विनियमन का क्षेत्राधिकार किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। इस सत्र में लिए गए एक निर्णय के अनुसार वर्तमान कार्यसूची मदों के अतिरिक्त 48वें सत्र में "अंतरिक्ष कचरा प्रशमन उपायों पर राष्ट्रीय तंत्र" से संबंधित एक नई कार्यसूची मद होगी।

कतिपय पारंपरिक हथियारों, जिन्हें अत्यंत खतरनाक माना जा सकता है अथवा जिनका अंधाधुंध प्रभाव हो सकता है, के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध से संबद्ध अभिसमय के राज्य पक्षकारों के सरकारी विशेषज्ञों (जीजीई) की समितिः वर्ष 2008 के दौरान सरकारी विशेषज्ञों की समिति ने सैन्य एवं मानवीय विचारों में संतुलन बनाते हुए एकत्रित विस्फोटकों के मानवीय प्रभाव का तत्काल समाधान करने के प्रस्तावों पर बातचीत करने के लिए जेनेवा में पांच बैठकें कीं। अनेक प्रस्तावों को पेश करते हुए भारत ने वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि चौथे सत्र के अंत तक जीजई के अध्यक्ष ने एकत्रित विस्फोटकों पर प्रोटोकोल के पाठ पर सहमति की प्रक्रिया पर विचार करने, बातचीत करने तथा पूरा करने के लिए जीजीई के अध्यक्ष ने जीजीई की पांचवीं बैठक के लिए एक पाठ तैयार किया था, परंतु जीजीई की पांचवीं बैठक के दौरान इस पर सहमति नहीं बन पाई। वर्ष 2009में भी नए अधिदेश पर यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

सार्क (दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय)

इस प्रभाग ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना करने हेतु करार का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय भागीदारी की, जिस पर अंततः 4 अप्रैल, 2007 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य राज्यों की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इस अंतरसरकारी करार के अनुसरण में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गयी। तदुपरांत 30 नवंबर, 2008 को भारत गणराज्य की सरकार और सार्क सचिवालय के बीच दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यालय करार संपन्न किया गया। अंतरसरकारी करार को क्रियान्वित करने और इस विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ करने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए इस विभाग द्वारा एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया। इस विधेयक को 23 दिसंबर, 2008 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। इस विधेयक को 11 जनवरी, 2009 को भारत की राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इसे भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।। खंड- 1, दिनांक 13 जनवरी, 2009 में प्रकाशित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

इस प्रभाग ने हेग अभिसमय, 1970 और मांट्रियल अभिसमय, 1971 के प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 19-21 फरवरी, 2008 तक मांट्रियल में आयोजित विधिक समिति की बैठक की आईसीएओ की विशेष उपसमिति में सक्रिय रूप से भाग लिया। मूलतः यह संशोधन आतंकवाद-रोधी और प्रसार-रोधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के विचार को परिलक्षित करते हैं। इसमें विभिन्न ऐसे कार्यों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें अपने-अपने घरेलू कानूनों के अंतर्गत राज्यों को दंडनीय बनाना होगा। इनमें शामिल हैंः हथियार के रूप में नागरिक विमान का उपयोग; जैविक, रासायनिक और नाभिकीय पदार्थों के गैर-कानूनी छिड़काव हेतु नागरिक विमान का उपयोग; जैविक रासायनिक और नाभिकीय पदार्थों का उपयोग करते हुए नागर विमानन के विरुद्ध किए गए हमले; इनमें से किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की धमकी; तथा इन कार्रवाइयों को बढ़ावा देने, इनमें भाग लेने, इनका आयोजन करने, निष्पादित करने इत्यादि

में योगदान देने संबंधी कार्य इस अभिसमय के अंतर्गत निषिध अपराध के रूप में दंडनीय होंगे।

इस प्रभाग ने 21 अप्रैल- 25 मई, 2008 तक मांट्रियल में आयोजित आईसीएओ की विधिक समिति की बैठक के 33वें सत्र में भाग लिया। इस समिति ने गैर-कानूनी हस्तक्षेप की स्थिति में विमानों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान हेतु मुआवजा पर अभिसमय के प्रारूप (गैर-कानूनी हस्तक्षेप अभिसमय) और तीसरे पक्षों को विमान द्वारा हुए नुकसान के मुआवजे से संबद्ध अभिसमय के प्रारूप (सामान्य जोखिम अभिसमय) पर भी चर्चा की, जिसका उद्देश्य इन दोनों अभिसमयों के अंतिम प्रारूप का अनुमोदन करना था। 33वें सत्र के दौरान अंतिम रूप दिए गए इन पाठों को वर्ष 2009 में मांट्रियाल में आयोजित होने वाले राजनयिक सम्मेलन में पारित किया जाएगा।

निवेश

इस अवधि के दौरान आइसलैंड के साथ संपन्न द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान दिल्ली में किया गया, जिससे कि यह करार लागू हो सके। ईरान के साथ वार्ताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अंतिम पाठ हस्ताक्षर के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत पूरी हो चुकी है और वार्ता अभी चल रही हैं। वुल्गारिया, रोमानिया और चैक गणराज्य के साथ संपन्न किए गए द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करारों में संशोधन किए जाने के लिए बातचीत पूरी हो गयी है, ताकि भारत के साथ इन देशों द्वारा किए गए द्विपक्षीय निवेश करारों को उनकी यूरोपीय संघ की बाध्यताओं के अनुकूल बनाया जा सके।

बैठकों में भागीदारी

इस वर्ष के दौरान हांगकांग, स्टोनिया और अजरबेजान के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करारों पर वार्ता की पहल की गयी तथा मैक्सिको के साथ चल रही बातचीत पूरी होने के बाद करार संपन्न किया गया। कनाडा के साथ अभी बातचीत चल रही है। इस प्रभाग ने जापान, कोरिया, श्री लंका, मॉरीशस, यूरोपीय संघ और आसियान के साथ मुक्त व्यापार करारों पर बातचीत में भी भाग लिया।

विधि एवं संधि प्रभाग ने अनेक रक्षा सहयोग करारों, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबद्ध करारों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करारों की जांच की।

इस वर्ष के दौरान भारत ने अनेक देशों के साथ अनेक बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर किए/अनुसमर्थन किया। अन्य के साथ-साथ इनमें शामिल हैः प्रवर्तित गुमशुदगी से सभी व्यक्तियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय; अपंग लोगों के अधिकारों पर अभिसमय; सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना से संबद्ध करार; सार्क खाद्य बैंक की स्थापना पर सार्क करार; ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क पर अंतरसरकारी करार; खेल में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा भारत-भूटान मैत्री संधि।

विधि एवं संधि प्रभाग के अधिकारियों ने भी निम्नलिखित बैठकों सहित भारत एवं विदेशों मे आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लियाः

- 31वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शी समिति बैठक (एटीसीएम), कीव, यूक्रेन, 2-7 जून, 2008।
- कार्टेजेना, कोलंबिया में आयोजित कार्टेजेना प्रोटोकोल के अनुच्छेद- 27 के संबंध में देयता एवं समाधान पर तदर्थ बहुद्देश्यीय कार्यकारी दल की 5वीं बैठक, 12-19 मार्च, 2008।
- बॉन, जर्मनी में जैव सुरक्षा से संबद्ध कार्टेजेना प्रोटोकोल के सम्मेलन के पक्षकारों (सीओपी-एमओपी 4) की चौथी बैठक तथा देयता एवं समाधान पर अध्यक्ष के मित्रों की बैठक, 7-9 मई तथा 12-16 मई, 2008।
- पर्यावरणीय कानून के विकास एवं आवधिक समीक्षा हेतु चौथे कार्यक्रम (मोंटवीडियो कार्यक्रम- रूग्) की तैयारी के लिए पर्यावरणीय कानून में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी विशेषज्ञों की बैठक, नैरोबी, 29 सितंबर- 3 अक्तूबर, 2008।
- तेहरान में भारत और ईरान के बीच प्रत्यर्पण संधि तथा आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधि तथा नागरिक एवं व्यावसायिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधि पर बातचीत, 22-24 जून, 2008।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के वैकल्पिक प्रोतोकोल को तैयार करने के लिए मानवाधिकार परिषद का अंतरसरकारी कार्यदल, 31 मार्च- 4 अप्रैल, 2008, जेनेवा।
- अंतरसरकारी वार्ता निकाय (तंबाकू नियंत्रण से संबद्ध अभिसमय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा) का प्रथम सत्र, जेनेवा, 11-16 फरवरी, 2008।
- तंबाकू उत्पादों के गैर-कानूनी व्यापार पर प्रोतोकोल पर अंतरसरकारी वार्ता निकाय का दूसरा सत्र (आईएनबी-2), जेनेवा, 20-25 अक्तूबर, 2008।
- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति की विधिक उपसमिति का 47वां सत्र (अनकोपुओस)।
- कतिपय पारंपरिक हथियार, जिन्हें अत्यंत हानिकारक माना जा सकता है अथवा जिनका अंधाधुंध प्रभाव हो सकता है, के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध से संबद्ध अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकारों के सरकारी विशेषज्ञों का समूह (जीजीई)।
- भारत-श्रीलंका सीईपीए वार्ता, कोलंबो, 2-4 जनवरी, 2008।

- भारत-आसियान व्यापार वार्ता समिति की 18वीं बैठक, भोपाल, 7-9 जनवरी, 2008।
- भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति की 16वीं बैठक, बैकांक, 31 जनवरी- 1 फरवरी, 2008।
- भारत-आसियान व्यापार वार्ता समिति की 19वीं बैठक, वियनसियेन, लाओ पीडीआर, 13-15 फरवरी, 2008।
- डीएसएम पर साफ्टा की बैठक, दिल्ली, 1-2 मार्च, 2008।
- बिम्सटेक व्यापार वार्ता समिति की बैठक, दिल्ली, 17-18 मार्च, 2008।
- भारत-जापान निवेश समूह की बैठक, दिल्ली, 25-26 मार्च, 2008।
- भारत-कोरिया निवेश समूह की बैठक, दिल्ली, 2-4 अप्रैल, 2008।
- भारत-श्रीलंका सीइपीए वार्ता, कोलंबो, 7-9 अप्रैल, 2008।
- भारत-जापान संयुक्त कार्यबल की छठीं बैठक, टोक्यो, 10-14 अप्रैल, 2008।
- भारत-मलेशिया व्यापार वार्ता समिति की द्वितीय बैठक, दिल्ली, 16-18 अप्रैल, 2008।
- भारत-जापान संयुक्त कार्यबल की 7वीं बैठक, दिल्ली, 12-15 मई, 2008।
- भारत-कोरिया संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक, सियोल, 29 मई- 2 जून, 2008।
- हिंद महासागर टुना आयोग का 12वां सत्र, मस्कट, 7-9 जून, 2009।
- भारत-अमरीका द्विपक्षीय निवेश करार बैठक, वाशिंगटन, 10-13 जून, 2008, भारत-आसियान व्यापार वार्ता समिति की 20वीं बैठक, क्वालालम्पुर, 16-18 जून, 2008।
- भारत-आसियान व्यापार वार्ता समिति की 21वीं बैठक, जकार्ता, 26-27 जून, 2008।
- भारत-श्रीलंका सीईपीए वार्ता, कोलंबो, 8-12 जुलाई, 2008।
- भारत-जापान संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक, टोक्यो, 14-17 जुलाई, 2008।
- भारत-कोरिया संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक, दिल्ली, 29-31 जुलाई, 2008।
- भारत-कोरिया संयुक्त कार्यबल की 12वीं बैठक, सियोल, 22-25 सितंबर, 2008।
- भारत-नेपाल व्यापार करार संशोधन वार्ता, दिल्ली, 16-17 अक्तूबर, 2008।
- भारत-आयियान व्यापार वार्ता समिति की विशेष बैठक, मनीला, 20-22 अक्तूबर, 2008।
- भारत-कोरिया सीईपीए विधिक जांच, प्रथम बैठक, सियोल, 23-25 अक्तूबर, 2008।
- भारत-कोरिया सीईपीए विधिक जांच, द्वितीय बैठक, दिल्ली, 5-6 नवंबर, 2008।
- भारत-एसएसीयू व्यापार वार्ताएं, दिल्ली, 26-28 नवंबर, 2008।
- भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति की 17वीं बैठक, दिल्ली, 22-23 दिसंबर, 2008।

उपर्युक्त बैठकों के अतिरिक्त इस प्रभाग ने कैदियों/सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर हांगकांग, इजराइल और कोरिया के साथ द्विपक्षीय करारों पर हुई वार्ताओं में भी भाग लिया। प्रभाग ने अजरबैजान, वियतनाम, तुर्की, माल्टा, मालद्वीव, ट्यूनीशिया और ताईबान के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा नशीली दवाओं के गैस-कानूनी व्यापार का मुकाबला करने के संबंध में होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लिया।

इस प्रभाग ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2008 को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान भी बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करायी।

विधि एवं संधि प्रभाग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनेक करारों और समझौता ज्ञापनों की जांच तथा पुनरीक्षा की। प्रभाग ने भारत तथा विदेश की अनेक परियोजनाओं की जांच अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से की। प्रभाग ने पासपोर्ट एवं कोंसुली मुद्दों सहित ऐसे अनेक मामलों में विदेश मंत्रालय को कानूनी सलाह दी, जिनमें विदेश मंत्रालय शामिल था। प्रभाग ने विदेश मंत्रालय को संबोधित विभिन्न आरटीआई आवेदनों पर जानकारी एवं सलाह दी। प्रभाग ने हेग अंतर्राष्ट्रीय कानून अकादमी, स्थायी विवाचन न्यायालय, निजी कानूनों के एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (यूनिडरॉयड) तथा एएएलसीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भारत द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक अंशदान का भुगतान किए जाने के संबंध में कार्रवाई की।

वर्ष 2008 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत संधियों/अभिसमयों/करारों, वर्ष 2008 में विधि एवं संधि प्रभाग द्वारा संपन्न पूर्ण अधिकार दस्तावेजों, वर्ष 2008 के दौरान विधि एवं संधि प्रभाग द्वारा निष्पादित अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेजों की सूची परिशिष्टों में दी गई है।

■■

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

10

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बहुपक्षीय मंचों की कार्यसूची आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों तथा ऊर्जा की बढ़ती-घटती कीमतों से प्रभावित रही। अपनी उच्च विकास दर के बावजूद आर्थिक मंदी के वैश्विक जोखिम के प्रति जागरूक रहते हुए भारत ने एएसईएम (एशिया-यूरोप बैठक), बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन), जी 8- ओ 5, जी- 20, आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका), आईओआर-एआरसी (हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ), एसीडी (एशिया सहयोग वार्ता) इत्यादि जैसे संगठनों के साथ अपना क्रियाकलाप जारी रखा, जिनमें इसने वित्तीय संकट और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत् विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे।

वर्ष 2008 के दौरान भारत ने नई दिल्ली में दूसरे बिम्सटेक और तीसरे आईबीएसए शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत की पहली सर्वोच्चस्तरीय भागीदारी भी हुई तथा प्रधान मंत्री ने बीजिंग में होने वाले एएसईएम शिखर सम्मेलन, वाशिंगटन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और साथ ही ब्रिक सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ अनौपचारिक क्रियाकलाप में शामिल हुए। भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के तहत "सामानों के व्यापार" से संबद्ध करार पर वार्ता, जो लगभग 4 वर्षों से चल रही थी, संपन्न हो गयी और यह भारत की "पूर्वोन्मुख" नीति में मील का एक पत्थर है।

प्रधान मंत्री ने 9 जुलाई को टोक्यो, जापान में जी-8 आउटरीच सत्रों में भाग लिया। भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय करार संपन्न किए जाने के उपरांत जी-8 देशों ने इस क्षेत्र में भारत के लिए कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। जी-8 शिखर सम्मेलन, जो जी-8, भारत चीन, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र को एक साथ लाने में सफल हुआ, के दौरान अतिरिक्त समय में जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक में प्रधान मंत्री ने यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत साझी, परंतु भिन्न जिम्मेदारियों और अलग-अलग क्षमताओं के प्रावधानों एवं सिद्धांतों के महत्व को दोहराया। प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता करने के लिए उन्हें नए और अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए जाएं।

15 नवंबर, 2008 को वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने वैश्विक वित्तीय संकट का मुकाबला करने के लिए व्यापक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर बल दिया।

सार्क

एक क्षेत्रीय सहकारी ढांचे का विकास करने के इस क्षेत्र सामूहिक निर्णय की अभिव्यक्ति के रूप में वर्ष 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) की स्थापना की गयी। फिलहाल सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका।

वर्ष 2007-08 में भारत सार्क का अध्यक्ष था (3-4 अप्रैल, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर 2-3 अगस्त, 2008 तक कोलंबो में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन तक)। यह अवधि सार्क के लिए अत्यंत उपयोगी थी और इसी दौरान सार्क घोषणात्मक दौर से क्रियान्वयन के दौर में आ सका। दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गयी प्रत्येक घोषणा क्रियान्वित की गयी है और इस संबंध में भारत एक पक्षीय तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता रहा है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं: सार्क खाद्य बैंक का प्रचालन; सार्क विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना; दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परियोजना कार्यालय की स्थापना; सार्क सांस्कृतिक महोत्सव को संस्थागत रूप प्रदान करना; सेवाओं को सॉफ्टा के अंतर्गत लाने पर वार्ताओं की शुरूआत; आपराधिक मामलों में आपसी सहायता से संबद्ध अभिसमय पर हस्ताक्षर। महिला सशक्तिकरण तथा प्रतिरक्षण सहित मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तदुपरांत कोलंबो (2-3 अगस्त, 2008) मे आयोजित 15वां सार्क शिखर सम्मेलन काफी सफल रहा, जिसमें श्रीलंका ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और इस शिखर सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्र की तीन खिड़कियों के साथ सार्क विकास कोष चार्टर। भारत ने सामाजिक

क्षेत्र के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर के आकलित अंशदान के अतिरिक्त 100 मिलियन अमरीकी डालर की स्वैच्छिक वचनबद्धता व्यक्त की है।

(ii) सार्क देशों में मानकों को सुसंगत बनाने के लिए बांग्लादेश में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन की स्थापना पर करार।

(iii) आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पर सार्क अभिसमय। इस अभिसमय के जरिए आतंकवाद सहित अन्य आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन तथा कार्यवाहियों में पारस्परिक विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र से संबद्ध करार में अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर प्रोतोकोल।

15वें शिखर सम्मेलन में आस्ट्रेलिया और म्यांमा को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, जिसके फलस्वरूप पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़कर 9 (चीन, कोरिया गणराज्य, जापान, अमेरिका, ईरान, मॉरीशस, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया और म्यांमा) हो गयी है। शिखर सम्मेलन में (क) पर्यवेक्षकों और (ख) अंतरसरकारी संगठनों के साथ सहयोग के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया गया और 3 वर्षों के लिए नए पर्यवेक्षकों के प्रवेश पर स्थगन लगाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि स्थायी समिति तथा मंत्रियों की परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत अंतरसरकारी संगठन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके सार्क के साथ क्रियाकलाप करेंगे।

एक पक्षीय तरीके से सार्क में अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन करने की वचनबद्धता जारी रखते हुए भारत ने सार्क देशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की पहली बैठक (15-16 सितंबर, 2008) और सार्क कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक (5 नवंबर, 2008) की मेजबानी की। दोनों बैठकों में अनेक ठोस, केंद्रित क्षेत्रीय परियोजनाओं की पहचान की गयी, जो अभी क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता करने हेतु अधिकारियों, कार्यबलों के संयोजकों तथा एकेडमिक्स, व्यावसायिक योजना, शासन तथा विधिक ढांचा और अवसंरचना के क्षेत्रों में स्वयं कार्यबलों की नियुक्ति के साथ दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का परियोजना कार्यालय पूर्णतः प्रकार्यात्मक हो गया है। नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के लिए 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भारत सरकार और सार्क सचिवालय के लिए 30 नवंबर, 2008 को मुख्यालय करार संपन्न कर लिया गया। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक दिसंबर, 2008 में संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की संस्वीकृति के उपरांत यह अधिनियम बन जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने से संबंधित मुख्यालय करार 1 दिसंबर, 2008 को भारत सरकार और सार्क सचिवालय के बीच संपन्न किया गया।

सार्क ऊर्जा मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन 28-29 जनवरी, 2009 तक कोलंबो में किया जाएगा। भारत ने सार्क ऊर्जा रिंग (21 नवंबर, 2008 नई दिल्ली) पर एक अवधारणा दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक और सार्क देशों के बीच विद्युत ग्रिड इंटरकनेक्शन के तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं पर साझी राय बनाने के लिए कार्यबल की बैठक (4 दिसंबर, 2008 नई दिल्ली) की मेजबानी की। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सार्क देशों के संसदीय मामलों के मंत्रियों की बैठक का आयोजन 10-11 फरवरी, 2009 तक कोलंबो में किया जाएगा। बैठक में संसदीय लोकतंत्र तथा इस क्षेत्र के संसदीय मामलों के मंत्रियों के बीच सहयोग के जरिए सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मंत्रियों की परिषद के 31वें सत्र का आयोजन 27-28 फरवरी, 2009 तक कोलंबो में किया जाएगा। इस बैठक से पहले स्थायी समिति के 36वें सत्र (25-26 फरवरी, 2009) और कार्यक्रम के 35वें सत्र (23-24 फरवरी, 2009) का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में 15वें सार्क शिखर सम्मेलन (कोलंबो, 2-3 अगस्त, 2008) में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय तथा सार्क विकास कोष से जुड़े मुद्दों सहित अन्य निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

सार्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प संग्रहालय के स्थायी परिसर की स्थापना पर नई दिल्ली (11-12 नवंबर, 2008) में अंतरसरकारी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि उक्त संग्रहालय दिल्ली हाट, पीतमपुरा में अवस्थित होगा। परिसर के लिए निधियां भारत द्वारा और प्रचालन लागत सदस्य राज्यों के आकलित अंशदान के जरिए उपलब्ध करायी जाएंगी। वर्ष 2008 में भारत अन्य बैंड महोत्सव और छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम का भी आयोजन करेगा।

भारत ने सार्क विकास कोष (एसडीएफ) के लिए आकलित अंशदान का 89.8 मिलियन अमरीकी डालर और 33.9 मिलियन अमरीकी डालर के स्वैच्छिक अंशदान की पहली किस्त का भुगतान कर दिया है। एसडीएफ के तहत मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा एक परामर्शदाता की भी नियुक्ति की गयी है।

सार्क के घोषणात्मक से क्रियान्वयन चरण में पहुंचने की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, हब एंड स्पोक तंत्र के जरिए भूटान में अवस्थित और भारत द्वारा वित्त पोषित सार्क दूर चिकित्सा परियोजना का सफल क्रियान्वयन। परियोजना के अन्य अवयवों का क्रियान्वयन श्रीलंका और अफगानिस्तान में किया जा रहा

13 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के राज्याध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील।

15 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) वार्ता मंच के तीसरे सम्मेलन में त्रिपक्षीय करारों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डि सिल्वा और दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति कगलिमा मोटलांटी ।

है। श्रीलंका के साथ आरंभ करते हुए सार्क दूर शिक्षा परियोजना, श्रीलंका और भूटान के साथ आरंभ करते हुए सार्क वर्षा जल संरक्षण परियोजना, श्रीलंका में अवस्थित सार्क आतंकवादी अपराध मानीटरिंग डेस्क तथा सार्क नशीली दवा अपराध मानीटरिंग डेस्क तथा सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय पुलिस प्राधिकरणों के नेटवर्किंग से संबंधित सार्क परियोजना का क्रियान्वयन हब एंड स्पोक डिजाइन का उपयोग करते हुए किया जा रहा है और इनका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक पहलुओं पर पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कार्य करने की सार्क के समक्ष भारत द्वारा की गई गतिशील प्रतिबद्धता के कारण प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले सार्क कार्यक्रमों/बैठकों की संख्या 33 से बढ़कर 75 हो गयी है। 19-20 नवंबर, 2008 तक कैंडी में आयोजित अपनी पहली बैठक में कार्यक्रम समिति के 34वें सत्र में वर्ष 2009 से 2010 तक 135 अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है, जो एक ऐसे गतिशील सार्क को परिलक्षित करता है, जिसे उत्तरोत्तर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण वाहन के रूप में देखा जा रहा है और जिससे दक्षिण एशियाई लोगों को विकास के लाभ प्राप्त हुए हैं।

बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

अगस्त, 2006 से ही भारत की अध्यक्षता में बिम्सटेक (जो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमा, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड को एकजुट करता है) की गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गयी है। 13 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में सभी बिम्सटेक भागीदार देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन ने बिम्सटेक के प्रति भारत की सतत् वचनबद्धता का संकेत दिया जो हमारी "पूर्वोन्मुख" नीति का एक अभिन्न अंग है।

प्रधान मंत्री ने बिम्सटेक कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा किए जाने तथा ईष्टतम संभावनाओं वाले प्राथमिक क्षेत्रों में भावी सहयोग की योजना तैयार किए जाने का आह्वान किया, जिससे कि वास्तविक परिणाम प्राप्त हो सके। चूंकि बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का कार्य करता है, इसलिए परिवहन और संरचना तथा संभार तंत्रों, समुद्री संसाधनों, आपदा प्रबंधन तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्कों पर विशेष बल दिया गया। प्रधान मंत्री ने बिम्सटेक देशों के लिए उपलब्ध 300 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त बिम्सटेक भागीदार देशों को 150 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने की घोषणा की।

शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा नशीली दवाओं के गैर-कानूनी व्यापर की रोकथाम से संबद्ध बिम्सटेक अभिसमय, भारत में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र से संबद्ध संगम ज्ञापन, भारत में मौसम एवं जलवायु केंद्र से संबद्ध संगम ज्ञापन, भूटान में बिम्सटेक सांस्कृतिक औद्योगिक आयोग तथा बिम्सटेक सांस्कृतिक औद्योगिक वेदशाला से संबद्ध समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने पर गौर किया गया। इस शिखर सम्मेलन से "सामानों के व्यापार" हेतु बिम्सटेक व्यापार करार शीघ्र संपन्न किए जाने की संभावना को गति मिली और महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गयी। इसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त संकट, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन पर भी विशेष बल दिया गया।

वर्ष 2008 के दौरान भारत द्वारा आयोजित अन्य बिम्सटेक कार्यक्रमों/बैठकों में शामिल थीं: कृषि सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक (24-26 अप्रैल, 2008), वरिष्ठ अधिकारी की 12वीं बैठक तथा 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (26-29 अगस्त, 2008), आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला किए जाने से संबद्ध बिम्सटेक संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक (22-23 अक्तूबर, 2008), सर्वोच्च औद्योगिक परिसंघों-सीआईआई, फिक्की और एसोचेम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बिम्सटेक व्यावसायिक शिखर सम्मेलन (12 नवंबर, 2008), जिसमें पनबिजली, परिवहन एवं संपर्क सुविधा तथा मात्स्यिकी सहित कृषि व्यवसाय और ऊर्जा से जुड़े अन्य मुद्दों पर बल दिया गया। 8 नवंबर, 2008 को भारतीय वाणिज्यिक परिसंघ द्वारा कोलकाता में दूसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की परिचय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री मुख्य अतिथि थे।

भारत-आसियान

1990 के दशक के आरंभ से ही भारत सोच-समझकर "पूर्वोन्मुख" नीति का अनुपालन करता आ रहा है। भारत-आसियान तंत्र के जरिए आसियान के साथ भारत का सहयोग और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी इस दृष्टिकोण के अभिन्न अंग हैं और ये वृहत्तर एशिया-प्रशांत समुदाय के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों को परिलक्षित करते हैं। अतः हम आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अपनी सतत् और उत्तरोत्तर बढ़ती भागीदारी को क्षेत्रीय स्तर पर संपूरक मानते हैं।

पूर्वी एशिया क्षेत्र के साथ भारत के उत्तरोत्तर बढ़ते क्रियाकलाप और एकीकरण के परिणामस्वरूप भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार 2007-08 में बढ़कर 30 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया और आशा है कि यह वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

छठें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गयी विभिन्न वचनबद्धताओं पर स्पष्ट प्रगति करते हुए भारत ने भारत-आसियान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना की है, जिसमें इसने 1 मिलियन अमरीकी डालर का आरंभिक अंशदान दिया है और साथ ही इसने आसियान सदस्य देशों से 50 छात्रों के पहले बैच की मेजबानी भी की है। आसियान राजनयिकों के लिए वार्षिक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अगस्त/सितंबर में संचालित किया गया, जिसमें 24 युवा आसियान राजनयिकों ने भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने

जुलाई में सिंगापुर में आयोजित आसियान पश्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने 30 अक्तूबर को नई दिल्ली में भारत-आसियान कार्यकारी दल की 14वीं बैठक की मेजबानी की।

भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार

वर्ष 2004 में आरंभ हुई भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीइसीए) के तहत "सामानों के व्यापार" के संबद्ध में करार पर वार्ता सिंगापुर में 28 अगस्त को आयोजित आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 7वीं बैठक तथा 7 नवंबर को पट्टाया, थाइलैंड में आयोजित वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक के उपरांत संपन्न हो गयी।

मैकांग गंगा सहयोग (एमजीसी)

मैकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) हमारी पूर्वान्मुख नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। भारत ने एमजीसी सदस्य देशों को वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा।

ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक)

वर्ष 2008 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली एकल बैठक का आयोजन मई माह में रूस के येकेतेरिनबर्ग में किया गया। ब्रिक रूपरेखा के अंतर्गत चतुष्पक्षीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2006 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन के मन में आया था। सचिव (आर्थिक संबंध) ने मई, 2008 को रूस में आयोजित होने वाली ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली औपचारिक बैठक आयोजित किए जाने के लिए योजना तैयार करने हेतु 10-11 मार्च, 2008 तक रियो दी जनारियो में आयोजित होने वाली ब्रिक उप विदेश मंत्रियों की तैयारी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रूस में आयोजित बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने किया। ब्रिक विदेश मंत्रियों की प्रथम एकल बैठक के उपरांत एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गयी। अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त विज्ञप्ति में आपसी विश्वास एवं सम्मान, साझे हित तथा वैश्विक विकास के समक्ष उत्पन्न तात्कालिक समस्याओं के संबंध में दृष्टिकोणों की समानता पर आधारित ब्रिक वार्ता की संभावना पर बल दिया गया। इसमें ब्रिक देशों के इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया कि आज की समसामयिक विश्वव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय विधिसम्मत शासन तथा बहुपक्षवाद पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका हो। इसमें संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की भी पुष्टि की गयी, जिससे कि इसे वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के संबंध में और भी प्रभावी बनाया जा सके।

ब्रिक रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग की प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम 9 जुलाई को टोक्यो, जापान में आयोजित जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ब्रिक राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की पहली अनौपचारिक बैठक थी। प्रधान मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। 7 नवंबर को साओ पोलो में आयोजित जी-20 बैठक के दौरान ब्रिक देशों के वित्त/आर्थिक मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किया गया।

जी-8 - आउटरीच सत्र

प्रधान मंत्री ने टोक्यो, जापान में 9 जुलाई को आयोजित जी-8 आउटरीच सत्रों में भाग लिया। भारत को एक आरटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। जी-8 आउटरीच सत्रों में चर्चा के विषयों में शामिल थेः हेलीगेंडम प्रक्रिया, विश्व-अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, विशेष रूप से अफ्रीका के संदर्भ में विकास तथा क्षेत्रीय मुद्दे। जी-8 आउटरीच सत्रों में भारत की भागीदारी से हमें स्पष्ट रूप से विभिन्न मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को रखने का अवसर मिला। जी-8 देशों ने असैनिक नाभिकीय सहयोग के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। 2008 में आयोजित जी-8 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के व्याख्यान के सार में इस आशय के एक पैराग्राफ को भी शामिल किया गया था।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के प्रति समर्पित विस्तारित जी-8 आउटरीच के एक विशेष सत्र (जिसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक कहा गया और जिसमें जी-8, भारत, चीन, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र एक साथ आए) में प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी विकासशील देशों के लिए सतत् एवं त्वरित आर्थिक विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए विकसित देश, वर्तमान में अपने उत्सर्जनों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का विचार नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विकासशील देशों को नए एवं अतिरिक्त संसाधन भी मुहैया कराए जाने चाहिए जिससे कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के अपने प्रयासों को बढ़ावा दे सके। बैठक के उपरांत ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक पर एक घोषणापत्र भी जारी किया गया।

ओ-5 (ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका) के नेताओं की बैठक जी-8 आउटरीच सत्रों से पूर्व 8 जुलाई को हुई, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उर्जा सुरक्षा तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गयी। बैठक के उपरांत राजनीतिक घोषणापत्र जारी किया गया।

एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने एएसईएम के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठकों में भाग लिया, जिनकी परिणति 24-25 अक्तूबर तक बीजिंग में आयोजित 7वें एएसईएम शिखर सम्मेलन

के रूप में हुई। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री ने किया। सितंबर, 2006 में हेलसिंकी में आयोजित छठें एएसईएम शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत को शामिल किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने के पश्चात शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च स्तर पर यह भारत की पहली भागीदारी थी। एएसईएम के 7वें शिखर सम्मेलन का आयोजन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में हुई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय परिदृश्य पर आयोजित पहले पूर्ण सत्र और सतत् विकास पर आयोजित तीसरे सत्र में प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप वक्तव्य दिया। शिखर सम्मेलन के उपरांत 7वें एएसईएम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष का वक्तव्य, सतत् विकास पर बीजिंग घोषणापत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य पर एक वक्तव्य जारी किया गया।

जी-20 शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन में बुलाए गए जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भावी वैश्विक आर्थिक रूपरेखा का डिजाइन इस पर तैयार किया जाना चाहिए कि यह नियामक एवं पर्यवेक्षण तंत्रों की असफलता, क्रमिक जोखिमों के प्रबंधन की अपर्याप्तता तथा वित्तीय संस्थाओं की पारदर्शिता में कमी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके, जिनके कारण मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट हुआ है। इस संबंध में उन्होंने वित्तीय स्थिरता से जुड़े विशेषीकृत मंचों जैसे कि बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबद्ध वेसल समिति और वित्तीय स्थिरता मंच में आज की तुलना में वृहत्तर प्रतिनिधित्व सहित अन्य व्यापक बहुपक्षीय दृष्टिकोणों के महत्व पर भी बल दिया। समूह- 20 (जी-20) में निम्नलिखित देश शामिल हैंः अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए)

प्रधानमंत्री ने 15 अक्तूबर को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ब्राजील के राष्ट्रपति तथा दक्षिण अफ्रीका के नवनियुक्त राष्ट्रपति ने सम्मेलन में भाग लिया।

आईबीएसए के तीसरे शिखर सम्मेलन में प्रिटोरिया (अक्तूबर, 2007) में आयोजित दूसरे आईबीएसए शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित तथा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्वीकृत सहयोग कार्यक्रम तथा संपर्क समस्याओं को दूर करने एवं सभ्य समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने से संबंधित करारों के क्रियान्वयन से आगे के कार्यों पर बल दिया गया। तीसरे शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के उन महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया, जिनका तीनों देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, अर्थात् वित्तीय संकट, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा मुद्दे, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद। 25 बिलियन अमरीकी डालर के त्रिपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसे वर्ष 2015 तक प्राप्त किया जाना है। इस बात पर सहमति हुई कि प्रस्तावित भारत-मरकोसर-एसएसीयू व्यापार व्यवस्थाओं पर वार्ता को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

निम्नलिखित 7 क्षेत्रों में शिखर बैठक में समझौता ज्ञापन/कार्य योजनाएं/करार संपन्न किए गएः पर्यटन मानक, तकनीकी विनियम एवं समरूपता आकलन के लिए व्यापार सुविधा, पर्यावरण, मानव अधिवास विकास, समुद्री परिवहन के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना, नागर विमानन के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तथा महिला विकास एवं लैंगिक समानता कार्यक्रम।

शिखर सम्मेलन से पूर्व सितंबर-अक्तूबर, 2008 के दौरान भारत में 14 कार्यकारी दलों की बैठकें तथा शिक्षाविदों, व्यावसायिक, शिखर बैठक, संपादकों एवं महिला मंचों की बैठकों का आयोजन किया गया, जो आईबीएसए प्रक्रिया के विकास के महत्वपूर्ण घटक है और जो सभ्य समाज के साथ संपर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यकारी दलों की बैठकों के दौरान कार्योन्मुख कार्यकारी योजनाएं तैयार की गयीं। आईबीएसए के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र विविधतापूर्ण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रासंगिक हैं। भारत ने शिखर सम्मेलन के दौरान आईबीएसए सांस्कृतिक महोत्सव तथा पहले खाद्य महोत्सव का आयोजन किया तथा आईबीएसए फिल्म महोत्सव शीघ्र ही आयोजित किया जाने वाला है।

हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर-एआरसी)

मार्च, 2007 में तेहरान में आयोजित आईओआर-एआरसी मंत्रियों की परिषद की सातवीं बैठक के दौरान घोषित भारतीय पहल के भाग के रूप में फरवरी-मार्च, 2008 में नई दिल्ली में प्रथम आईओआर-एआरसी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, ईरान, कीनिया, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया और थाइलैंड ने भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने 4 मई को तेहरान में आयोजित हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर-एआरसी) के मंत्रियों की परिषद की 8वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रियों की परिषद में कार्ययोजना को क्रियान्वित किए जाने तथा इस संघ की भावी दिशा हेतु 10वर्षीय योजना तैयार करने की आवश्यकता, व्यवसाय, व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में संघ की गतिविधियों में शामिल निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु ट्रेक-II तंत्र के कार्यों में तेजी लाने और साथ ही सचिवालय की वित्तीय क्षमता इसके कार्मिकों के वेतन और भत्तों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने एवं

सचिवालय को और भी प्रभावी एवं गतिशील बनाए जाने का आह्वान किया।

मंत्रियों की परिषद की 8वीं बैठक इस संघ और विशेष रूप से भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 3-4 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसमें प्राथमिकता वाले निम्नलिखित 6 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया हैः (1) व्यापार और निवेश, वित्त एवं उर्जा; (2) शिक्षा, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी; (3) मात्स्यिकी; (4) पर्यटन; (5) आपदा प्रबंधन तथा जोखिम प्रशमन; तथा (6) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। भारत ने प्रस्ताव किया कि 6 निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे नए क्षेत्रों को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है, जिनका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता हो और जिससे इस संघ में क्षेत्रीय सहयोग की भावना का संवर्धन हो। हिंद महासागर अध्ययन पीठ के अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है। ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के भारतीय उम्मीदवार प्रो. राव का चयन इस पद पर किया गया है।

भारत ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम के अंतर्गत सदस्य देशों की आवश्यकताओं के अनुसार क्षमतानिर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया। यूएमआईओआर तथा शैक्षिक समूह द्वारा सहमत सामान्य करार के तहत अलग-अलग देशों द्वारा प्रतिसदस्य राज्य दो छात्रों के वित्तपोषण का प्रस्ताव किया गया है, इसके अंतर्गत भारत ने क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में भारत में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत कुल 36 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया। भारत ने आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत आईओआर-एआरसी सचिवालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ फिक्की की सहायता से आईओआरएनईटी पर प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया है। भारत ने आईओआर-एआरसी सदस्य देशों के विदेशी राजनयिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है, जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा किया जाएगा। भारत में फरवरी, 2008 में यहां आयोजित प्रथम आईओआर-एआरसी फिल्म महोत्सव की सफलता को देखते हुए प्रत्येक दो वर्षों में फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को दोहराया है।

एशिया सहयोग वार्ता

एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) की 7वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन 16 अक्तूबर को अस्ताना में किया गया था। मंत्रियों द्वारा चर्चा की कार्यसूची मदों में शामिल थीं- एशिया सहयोग वार्ता में हुई प्रगति, इसकी भावी दिशा, एशिया सहयोग वार्ता की सदस्यता पर लगाए गए अस्थायी स्थगन को उठाने से संबंधित मुद्दे, आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। बैठक में किर्गीजस्तान गणराज्य को 31वें सदस्य देश के रूप में शामिल करने पर सहमति हुई और साथ ही मोरक्को को विकास के लिए एशिया सहयोग वार्ता भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। बैठक के अंत में एशिया सहयोग वार्ता की समीक्षा करते हुए और खाद्य, ऊर्जा तथा वित्तीय संकट जैसी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रियों ने एक घोषणा पारित की। मंत्रियों ने सांस्कृतिक सहयोग को एशिया सहयोग वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत 20वें क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। इसका प्रस्ताव ईरान ने किया, जबकि भारत सह-प्रस्तावक था। सभी प्रतिनिधिमंडलों ने एशिया सहयोग वार्ता प्रक्रिया में भारत की सक्रिय भूमिका तथा वर्ष 2009 में ट्रेक-II सेमिनार, चौथे एसीडी पर्यटन व्यवसाय मंच के आयोजन से संबंधित इसकी पहल तथा सांस्कृतिक सहयोग परियोजना के लिए सह-प्रस्तावक बनने की पहल का स्वागत किया।

■■

11 तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास में भागीदारी

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम और अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्केप), जिनमें अनुभवों के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, विकासशील विश्व के साथ भारत की विकास भागीदारी और सहयोग के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। विभिन्न देशों में इन सहकारी क्रियाकलापों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता की झलक अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया, लैटिन अमरीका और केरीबिया के विकासशील देशों से प्राप्त उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व और विभिन्न द्विपक्षीय एंव बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय समकक्षों के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकों में मिलती है।

आईटेक और स्केप कार्यक्रमों ने असैनिक तथा रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारी संख्या में भागीदारों का ध्यान आकर्षित किया है। 158 विकासशील देशों (सर्बिया और मोंटिनेगरो, 2008 में भागीदार राष्ट्र बने) के सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के 5000 व्यावसायिकों ने अपनी-अपनी रुचि और लाभ के पाठ्यक्रमों मे भाग लिया। आईटेक और स्केप आवेदकों के लिए पिछले वर्ष आरंभ की गयी वेबसाइट प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है और इसके कारण आईटेक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में काफी सुधार आया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विवरणिका अंग्रेजी सहित 5 अन्य भाषाओं- अरबी, फ्रैंच, पुर्तगाली, स्पैनिश और रूसी भाषाओं में निकाली गयी (158 आईटेक भागीदार देशों की सूची अनुबंध-XIII पर है)।

असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसके पैनल में 43 संस्थाएं हैं और इसके तहत कार्यरत व्यावसायिकों के लिए व्यापक आधार वाले एवं विभिन्न प्रकार कौशलों एवं विषयों पर मुख्य रूप से 200 अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए। सबसे अधिक लोकप्रिय सूचना प्रोद्योगकी एवं भाषा विज्ञान (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम रहे। सरकारी अधिकारियों को वित्त एवं लेखा, लेखा परीक्षा, बैंकिंग, शिक्षा, आयोजना एवं प्रशासन, संसदीय अध्ययन, अपराध रिकार्ड इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए गए। अन्य ने वस्त्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, उपकरण डिजाइन तथा नेत्र विज्ञान उपकरण जैसे तकनीकी/विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सेवाओं का सदुपयोग किया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, एसएमई और उद्यम विकास से जुड़े सामान्य पाठ्यक्रमों ने भी सहभागियों का ध्यान आकर्षित किया। (विदेश मंत्रालय के आईटेक एवं स्केप कार्यक्रमों के अंतर्गत असैनिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं की सूची अनुबंध-II पर है।)

आईटेक कार्यक्रम अनिवार्यतः द्विपक्षीय है। तथापि, हाल के वर्षों में आईटेक गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और इसे क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संगठनों के साथ संयोजित किया गया है। इन संगठनों एवं समूहों में शामिल हैंः दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ (आसियान), जी-15, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), मैकांग गंगा सहयोग (एमजीसी), अफ्रीकी संघ (एयू), अफ्रीका- एशिया ग्रामीण विकास संगठन (आरडो), पैन अफ्रीकी-संसद, केरीबियन समुदाय (केरीकोम), राष्ट्रमंडल तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)।

नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी सहयोग (टीसी) प्रभाग ने विशेष पाठ्यक्रमों और अध्ययन दौरों का भी आयोजन किया। अप्रैल, 2008 में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के आलोक में 70 अफ्रीकी महिलाओं और युवाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 28 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व वाले महिलाओं के समूह ने ग्रामीण और आधुनिक भारत की झलक पाने के उद्देश्य से भुज, अहमदाबाद, हैदराबाद, आगरा, जयपुर और दिल्ली का दौरा किया। भुज, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर में स्व-सहायता महिला समूहों के साथ वार्ता सत्रों का आयोजन किया गया। उत्तर-पूर्व के गुवाहाटी और शिलाँग जाने से पूर्व युवकों के समूह ने भारत में दुग्ध क्रांति का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के नजदीक आनंद तथा इंफोसिस, बायोकोन, भारतीय विज्ञान संस्थान को देखने के लिए बंगलौर का दौरा किया। उत्तर-पूर्व में स्थानीय विश्वविद्यालय के छात्रों और अफ्रीकी युवक समूह के सदस्यों के बीच एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच भी खेला गया।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के अनुसरण में इस वर्ष अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखा परीक्षा केंद्र, नोएडा के जरिए अफ्रीका, आईओआर-एआरसी देशों तथा अफगानिस्तान के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में लेखा परीक्षा" विषय पर एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2009-10 के लिए पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया और इसकी सूचना आईटेक भागीदार मिशनों के साथ-साथ आईटेक के अंतर्गत पैनलबद्ध संस्थानों को दी गयी। देश-वार स्थानों को अंतिम रूप दिया गया और इसकी सूचना सभी आईटेक भागीदार मिशनों को संप्रेषित की गयी।

रक्षा प्रशिक्षण

रक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ती रुचि का पता इस बात से चला कि रक्षा सेवा के तीनों विंगों, अर्थात् सेना, नोसेना और वायुसेना ने विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में 757 अधिकारियों/प्रशिक्षुओं को स्वीकार किया, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 572 थी। इन पाठ्यक्रमों का स्वरूप सामान्य और विशेष था और इनमें सुरक्षा तथा सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, आर्टिलरी, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जल विज्ञान, उग्रवाद का मुकाबला तथा जंगल युद्ध कला शामिल थे। साथ ही इसमें तीनों सेनाओं के युवा अधिकारियों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम शामिल थे। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज तथा रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन के लिए निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और विकसित देशों के अधिकारियों ने भी स्व-वित्तपोषण आधार पर उनमें भाग लिया। उत्तरोत्तर बढ़ते इस क्रियाकलाप से भारत में रक्षा प्रशिक्षण को विकासशील एवं विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले महत्व का पता चलता है। रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज के लिए स्थानों के वितरण को अंतिम रूप दिया गया और इसकी सूचना संबंधित मिशनों को संप्रेषित की गयी।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर असैनिक एवं रक्षा क्षेत्र में 45 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए गए जो सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा, विधिक सुविज्ञता, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों, फार्माकालोजी, सांख्यिकी एवं जनसंख्या विज्ञान एवं लोक प्रशासन तथा वस्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सलाह देने और सुविज्ञता प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त हैं। लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, सेशल्स और जांबिया जैसे देशों द्वारा प्रशिक्षण तथा सलाहकारी क्षमता में रक्षादलों की सेवाएं प्राप्त की गयीं।

अन्य सहायता

इस वर्ष के दौरान मंगोलिया को गेहूं के बीज उपहार स्वरूप दिए गए।

अध्ययन दौरे

(i) मंगोलिया के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र, कोलकाता के दो विशेषज्ञों को मंगोलियाई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए लघु आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु एक सप्ताह के लिए मंगोलिया में प्रतिनियुक्त किया गया।

(ii) नाईजीरिया के अनुरोध पर भारत के योजना आयोग के 4 विशेषज्ञों की एक टीम को "संघीय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ आयोजना अधिकारियों के लिए नाईजीरिया में विकास योजना के प्रभावी निर्माण" पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए नाईजीरिया में प्रतिनियुक्त किया गया।

परियोजना भागीदारी तथा परियोजना सहयोग

वर्ष 2008-09 में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और लघु एवं मझौले उपक्रमों, सिविल विनिर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक द्विपक्षीय परियोजनाएं चलाई गयीं। द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं में मुख्यतः आवश्यक भौतिक अवसंरचना की स्थापना तथा क्षमता निर्माण पर बल दिया गया, जिससे कि इन परियोजनाओं की दीर्घावधिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

क्रियान्वयनाधीन मुख्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य (लाओ पीडीआर): लाओ पीडीआर के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमता संवर्धन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात एनआईसी द्वारा दूसरे वर्ष भी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना का संचालन किया गया।

इंडोनेशिया: ऐसेह में प्रशासनिक स्टाफ कालेज की स्थापना हेतु ऐसेह, इंडोनेशिया में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया।

लैटिन और मध्य अमरीकी देश: सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल सल्वाडोर, होंडुरास तथा निकरागुआ जैसे लैटिन और मध्य अमरीकी देशों में 3 आईटी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गयी है, जिनमें प्रशिक्षण भी आरंभ हो चुका है। एनआईआईटी लिमिटेड द्वारा जैमेका में एक आईटी केंद्र की स्थापना किए जाने पर करार संपन्न किया गया है। इन केंद्रों का उद्देश्य इन देशों में क्षमता निर्माण करना तथा आईटी अवसंरचना का संवर्धन करना है।

मालदीव: भारत-मालदीव मैत्री आतिथ्य सत्कार एवं पर्यटन अध्ययन संकाय में सिविल निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है और इसके वर्ष 2009 में पूरा हो जाने की आशा है।

जिम्बाब्वे: वर्ष 2006 में जिम्बाब्वे के साथ संपन्न द्विपक्षीय करार के फलस्वरूप लघु एवं मझौले उपक्रमों से संबद्ध परियोजना क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है। उपकरण और मशीनें भेजी जा चुकी हैं। जिम्बाब्वे के 19 कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया है।

अन्य विकासशील देशों को सहायता

अल सल्वाडोर, निकरागुआ तथा होंडुरास में आईटी केंद्रों की स्थापना की गयी और प्रशिक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया। जैमेका में आईटी केंद्र की स्थापना की गयी और प्रशिक्षण कार्य आरंभ हुआ। लाओ पीडीआर में वाट फोऊ मंदिर परिसर परियोजना के संरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य आरंभ किया गया। पहले चरण के कार्यों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निधियां जारी की गयीं।

व्यवहार्यता अध्ययन

अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं, विशेष रूप से एंटीगा और बरबुडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। सी-डेक के विशेषज्ञों द्वारा रियाद, सऊदी अरब में आईटी केंद्र की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। सीरिया में भी आईटी केंद्र की स्थापना

के लिए ऐसे ही व्यवहार्यता अध्ययन का क्रियान्वयन किया जा रहा था। सीरिया में आईटी केंद्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जा चुका है। एंटिगा और बरबुडा में मल व्यवस्था संयंत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है। एसेह (इंडोनेशिया) में प्रशासनिक स्टाफ कालेज की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन मार्च, 2009 में आरंभ किया गया।

आपदा राहत के लिए सहायता

भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विभिन्न देशों के लिए तत्काल राहत सहायता प्रदान की। मंगोलिया को 5000 मीट्रिक टन चीनी और 5000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गयी। बेलिज, हैती और डोमेनिकन गणराज्य में चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए चिकित्सा राहत उपलब्ध करायी गयी। किर्गीस्तान, मलावी, जांबिया और मोजांबिक को बाढ़ राहत सहायता उपलब्ध करायी गयी। भूकंप, चक्रवातों और बाढ़ इत्यादि से प्रभावित चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यूबा, लाओ पीडीआर तथा हैती को मानवीय सहायता प्रदान की गयी। ताजिकिस्तान को जेनरेटर सेट और अन्य उपकरणों के आपूर्ति की गयी। चीन को भूकंप राहत सहायता दी गयी।

■■

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन

12

ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) हमारी विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। आईटीपी प्रभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के साथ विचार-विमर्श करके विभिन्न मैत्रीपूर्ण विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण श्रृंखलाओं के अनुरोध पर कार्रवाई की गई। एलओसी से हमारी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं तथा प्राप्तकर्ता देशों में अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में योगदान करने की हमारी इच्छा का प्रदर्शन हुआ। अप्रैल 2008 - दिसंबर 2008 की अवधि के दौरान 672.68 मिलियन अमरीकी डालर के 15 एलओसी का अनुमोदन किया गया। प्रभावी क्रियान्वयन एवं एलओसी वित्तपोषित परियोजनाओं में ऋण लेने वाली सरकारों द्वारा कार्रवाई करने एवं संविदा दिए जाने की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एलओसी को शासित करने वाली नीति की भी समीक्षा की गई।

आईटीपी प्रभाग ने जनवरी 2009 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका व्यावसायिक भागीदारी शिखर सम्मेलन के आयोजन में फिक्की को सहायता प्रदान की। रवांडा के राष्ट्रपति श्री पाउल कगामे इस शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। इसमें 32 अफ्रीकी देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें से आधे से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों ने किया। शिखर सम्मेलन में रेलवे, सड़क एवं विनिर्माण, स्वास्थ्य एवं भेषज, आईसीटी, विद्युत, खनन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। इससे पूर्व भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सहयोग से सितंबर 2008 में हैदराबाद में ''भारत लैटिन अमरीका एवं कैरीबिया - व्यापार एवं निवेश के अवसर'' विषय पर अनेक सेमिनारों का आयोजन किया गया। सेमिनारों को राजधानी से बाहर इसलिए आयोजित किया गया कि इससे जनसंपर्क गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और हमारे राज्यों में अवस्थित भारतीय व्यावसायिक घरानों को विश्व के विभिन्न भागो में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों से अवगत कराया जा सके।

आईटीपी प्रभाग ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वैपकोस, एक्जिम बैंक, अन्य व्यापारिक निकायों की बैठकों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रभाग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरो पर व्यापार संवर्धन निकायों तथा प्रतिनिधि मंडलों को विदेश से जुड़े उनके कार्यों में सहायता प्रदान की। इस अवधि के दौरान उर्वरक एवं आयुर्वेदिक उत्पादों से जुड़े व्यापार एवं निवेश मुद्दों को भी उठाया गया।

अक्तूबर 2008 में भारत-गतिशील व्यावसायिक भागीदारीः निवेशक हितैषी गंतव्य के अद्यतन संस्करण का प्रकाशन किया गया और इसे विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों में परिचालित किया गया। इस प्रकाशन में भारत के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई थी और यह व्यावसायिक एवं निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के लिहाज से अत्यंत उपयोगी था।

हमारे मिशनों/केंद्रों ने देश की आर्थिक ताकत, वित्तीय व्यवहार्यता तथा व्यावसायिक संभावनाओं एवं निवेश लाभ का प्रचार-प्रसार करने के लिए इस प्रकाशन का उपयोग किया।

आईटीपी प्रभाग की वेबसाइटः www.indiabusiness.nic.in पर भारत में उपलब्ध वाणिज्यिक एवं निवेश अवसरों के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध है। संभावित विदेशी निवेशकों और व्यापार भागीदारों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिहाज से यह वेबसाइट अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

ऊर्जा सुरक्षा एकक

जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। ऊर्जा से जुड़े मुद्दे हमारी कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। विदेश मंत्री के अनुमोदन से सितंबर 2007 में एक ऊर्जा सुरक्षा एकक (ईएसयू) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में अपने हितों का संरक्षण करने में बहुफलकीय वैश्विक क्रियाकलाप को सुविधाजनक बनाना था। ईएसयू ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों पर विदेश मंत्रालय में नोडल केंद्र का कार्य करता है और उपयुक्त राजनयिक हस्तक्षेपों तथा हमारे मिशनों के साथ सक्रिय क्रियाकलाप के जरिए उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों में संबंधित ऊर्जा मंत्रालयों की सहायता करता है।

यह इकाई सर्वोच्च वाणिज्यिक संघों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। अनेक अवसरों पर इस इकाई ने अतिरिक्त ऊर्जा वाले देशों के साथ भारतीय कंपनियों के क्रियाकलापों में आ रही कठिनाई का समाधान करने के लिए भारतीय कंपनियों की ओर से सक्रिय बातचीत की।

ईएसयू ने नवंबर 2008 में हाइड्रोकार्बन पर भारत-सीआईएस गोलमेज सम्मेलन और 2009 में पेट्रोटेक के आयोजन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। इस एकक ने भारत के ऊर्जा विकल्पों पर सेमिनारों की मेजबानी/सह-मेजबानी की, अतिरिक्त ऊर्जा वाले देशों और क्षेत्रों में अध्ययनों का संचालन किया तथा विदेशों में ऊर्जा सहयोग एवं अवसरों के संबंध में कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों को सहायता प्रदान की। इस एकक ने तेल एवं अवसंरचना क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा पर एक कार्यकारी दल की स्थापना करने की पहल की।

13 नीति आयोजना और अनुसंधान

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और इससे जुड़े कार्यालयों तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित एरिया अनुसंधान केंद्रों के साथ क्रियाकलाप के एक नोडल बिन्दु के रूप में कार्य किया।

इस प्रभाग ने भारत के विदेश संबंध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सम्मेलनों, सेमिनारों के आयोजन, अनुसंधान दस्तावेजों की तैयारी, विद्वानों का आदान-प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अवस्थित विविध शैक्षिक संस्थाओं/विचार मंचों को वित्तीय सहायता प्रदान की। नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित सेमिनारों/सम्मेलनों/बैठकों/गैर सरकारी संगठनों की सूची परिशिट के रूप में दी गई है। इस प्रभाग द्वारा नीति अनुसंधान एवं विश्लेषण के विशेषज्ञों और संस्थाओं का एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस बनाया गया है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन बनाया जाता है।

नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट का वित्तपोषण विदेश मंत्रालय द्वारा नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग के जरिए किया जाता है। यह बीस ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययनों का संचालन कर रहा है जिनका प्रभाव भारत के राष्ट्रीय हितों और इसकी विदेश नीति पर पड़ सकता है। कुछ अध्ययन पूरे भी कर लिए गए हैं।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश जारी करने का कार्य करता रहा। इसमें एक माह के दौरान विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों के व्यापक परिदृश्य को शामिल किया जाता है।

यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सरकार के विचारों सहित राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शेष विश्व के साथ भारत के क्रियाकलापों के एक संकलन के रूप में कार्य करता है।

इस प्रभाग ने विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशनों और केंद्रों में स्थापित वाणिज्य केंद्रों के कार्यकरण तथा मिशनों की रिपोर्टिंग की विषय-वस्तु, क्षेत्र एवं बारंबारता की समीक्षा की।

स्थिति कक्ष

स्थिति कक्ष मंत्रालय का एक बहु-फलकीय, बहु-सुविधा संपन्न अत्याधुनिक कक्ष है। वर्ष 2000 में स्थापित इस कक्ष में आवश्यक संचार संपर्क सुविधा एवं डिस्प्ले पैनल्स हैं जिनकी आवश्यकता किसी संकटपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के दौरान पड़ता है। मंत्रालय के संकट प्रबंधन सेल के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका के अतिरिक्त इस कक्ष का उपयोग मंत्रालय के सभी प्रभागों द्वारा प्रस्तुतियों तथा टेलीफोन/वीडियो सम्मेलनों इत्यादि सहित अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। स्थिति कक्ष की भूमिका निम्नलिखित हैः

(क) एक बहु-सुविधा संपन्न कक्ष के रूप में सम्मेलनों, प्रस्तुतियों, आवधिक चर्चाओं, मिशन प्रमुखों के साथ वीडियो/टेलीफोन सम्मेलनों का आयोजन तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा अपेक्षित मानचित्रों और चित्रों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना।

(ख) संकट की स्थिति में संकट प्रबंधन सेल (नियंत्रण कक्ष) के रूप में कार्य करना।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान क्रियाकलाप

संकट प्रबंधन सेल के रूप में स्थिति कक्ष - मुम्बई में हाल में उत्पन्न संकट के दौरान 27 नवंबर - 1 दिसंबर 2008 तक स्थिति कक्ष में 24 घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी। यह नियंत्रण कक्ष मुम्बई में स्थापित एक अन्य नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय करते हुए कार्य करता था। इस नियंत्रण कक्ष ने घटना से प्रभावित विदेशी रािट्रकों के हित कल्याण के संबंध में संपूर्ण विश्व के सभी देशों से प्राप्त और उन्हें दी जाने वाली सूचनाओं को सुविधाजनक बनाया और इनका समन्वयन किया। इसी कक्ष में हेल्प लाइनों की स्थापना की गई थी, जहां भारतीयों एवं विदेशी राष्ट्रिकों के प्रश्न लिए गए और तत्काल उनका जवाब दिया गया।

मिशनों में वीडियो सम्मेलन सुविधा की स्थापना - मंत्रालय में संचार सुविधा को नया आयाम प्रदान करने के विदेश सचिव के ''वीडियो सम्मेलन'' के विजन के अनुसरण में चुनिंदा मिशनों में चरणबद्ध तरीके से वीडियो सम्मेलन सुविधा की स्थापना की जा रही है। चरण-1 के भाग के रूप में जून 2008 में पेरिस बेसेल्स और लंदन स्थित मिशनों में, नवंबर 2008 में ढाका और कोलम्बो में तथा दिसंबर 2008 में बीजिंग में इस सुविधा की स्थापना की गई। मार्च 2009 में न्यूयार्क, वाशिंगटन, मास्को, जिनेवा स्थित मिशनों में इस सुविधा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त निकट भविय में अन्य सार्क देशों के मिशनों में इस सुविधा की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इन मिशनों में वीडियो

सम्मेलन सुविधा के लिए अपेक्षित संचार सम्पर्क की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने के बाद इन मिशनों में भी यह सुविधा स्थापित कर दी जाएगी।

चुनिंदा मिशनों के लिए संचार के वैकल्पिक साधन - मई 2008 में स्थिति कक्ष परिसर में इनमारसैट के एक टर्मिनल की स्थापना की गई। इस टर्मिनल का उपयोग कुछ ऐसे भारतीय मिशनों (10) के साथ संचार के वैकल्पिक साधन के रूप में किया जा रहा है जहां सामान्य लैंडलाइन संचार विश्वसनीय नहीं है।

सीमा सेल

1. नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग के भाग के रूप में स्थापित सीमा सेल के निम्नलिखित कार्य हैं -

   (क) भारत की विदेशी सीमाओं के सभी पहलुओं की जांच, प्रकाशन हेतु भारतीय सर्वेक्षण के समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा भारत के साथ लगने वाली सीमाओं के मानचित्र पत्रकों की जांच।

   (ख) क्षेत्रीय प्रभागों को सीमा से जुड़े मामलों पर मानचित्र से संबंधित सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

   (ग) उपलब्ध मानचित्र पट्टियों, बुनियादी नक्शों के संग्रहण, मिलान तथा अंकीयकरण में सहायता।

   (घ) भारतीय क्षेत्र में सीमा खंभों के अनुरक्षण/मरम्मत सहित संयुक्त सीमा सर्वेक्षण और भारतीय भू-क्षेत्र में अतिक्रमण की रिपोर्ट पर भारतीय सर्वेक्षण/राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करना (डाटा बेस इत्यादि का अनुरक्षण)।

   (ङ) समुद्रीय सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, मिलान और अंकीयकरण तथा महाद्वीपीय जल-सीमा का चित्रण।

   (च) विकास कार्यों के प्रयोजनार्थ विभिन्न सरकारों और अर्धसरकारी संगठनों के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय के समन्वय से प्रतिबंधित मानचित्र पत्रकों की जांच करना।

   (छ) नौसेना जल विज्ञान कार्यालय तथा महासागर विकास विभाग के साथ संपर्क स्थापत करना।

   (ज) भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित सभी मानचित्रों/दस्तावेजों/सूचनाओं के न्यास के रूप में कार्य करना।

   (झ) विदेशी पत्रिकाओं, जर्नलों और एटलसों में प्रकाशित गलत मानचित्रों की जांच करना और इन मानचित्रों को सही करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

2. सीमा सेल ने भारत की अंतर्राट्रीय भूमि एवं समुद्री सीमा पर आयोजित निम्नलिखित आंतरिक/अंतरर्सरकारी बैठकों में भाग लियाः

   (क) 22 मई 2008 को आयोजित चीन अध्ययन दल की बैठकों में भाग लिया और सीएसजी के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपेक्षित जानकारियां दीं।

   (ख) गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई संयुक्त कार्यकारी दल की अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (ग) संयुक्त सचिव (बीएसएम) द्वारा जुलाई 2008 में बंगलादेश पर बुलाई गई अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (घ) 18 जुलाई 2008 को रक्षा मंत्रालय के जेएसजी द्वारा बंगलादेश पर बुलाई गई अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (ङ) भू-विज्ञान मंत्रालय के साथ महाद्वीपीय जल-सीमा पर अंतर्मत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (च) 21 जुलाई 2008 को भारत में आधार रेखा प्रणाली पर रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नौसेना) द्वारा बुलाई गई अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (छ) 12 सितंबर 2008 को विशेष सचिव (पीपी) द्वारा भारत की भूमि और समुद्री सीमाओं की स्थिति पर आयोजित अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (ज) 13 अक्तूबर 2008 को भारत-पाकिस्तान राट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ताओं में भाग लिया।

   (झ) भारत-म्यामां और भारत-बंगलादेश सीमा प्रश्न पर 22 अक्तूबर 2008 को संयुक्त सचिव (बीएसएम) द्वारा बुलाई गई अंतर्मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

   (ञ) अंतर्राट्रीय सीमा (पश्चिम बंगाल सेक्टर) से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि रिकार्ड विभाग का दौरा किया।

   (ट) वर्तमान फील्ड मौसम 2008-09 के दौरान कार्य किए जाने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर अंतर्राट्रीय सीमा खंभों का पता लगाने तथा गुमशुदा खंभों के पुनर्निर्माण और अनुरक्षण पर अंतर्मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के साथ इसका समन्वय किया।

   (ठ) भारत में बेस लाइन प्रणाली पर सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति की टिप्पणी तैयार की।

   (ड) भारत के विस्तारित महाद्वीपीय जल-सीमा दावे पर

सीसीएस नोट के लिए सूचना सामग्री (नक्शे) उपलब्ध कराया।

(ढ) निम्नलिखित देशों के महाद्वीपीय जल सीमा दावे पर अंतर्मंत्रालयी बैठक में सूचना सामग्री उपलब्ध कराईः (I) म्यामां (II) श्रीलंका

(ण) महाद्वीपीय जल सीमा और आधार लाइन प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अवगत कराया।

(त) भारत-चीन सीमा (सिक्किम सेक्टर) पर डेस्कटॉप अभ्यास।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त इस वर्ष निम्नलिखित कार्य भी किए गएः

(क) भारत की बाह्य सीमा को शामिल करने वाले सीमा पत्रक मानचित्रों के लिए डेटाबेस का निर्माण (भूटान, पाकिस्तान का कार्य पूरा)।

(ख) सीमा-पत्रक मानचित्रों के अभिलेख एवं अंकीयकरण।

(ग) भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शामिल करते हुए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित अंकीय एवं लिखित रूप में स्थलाकृतिक मानचित्रों के अभिलेख।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को मानचित्र संबंधी सहायता प्रदान की गई।

(ङ) भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किए जा रहे स्थलाकृतिक मानचित्रों और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे अंतर-सीमान्त मानचित्रों में आसूचना ब्यूरो का प्रमाणीकरण।

(च) भारतीय सीमा मुद्दों पर प्रस्तुतिः (क) सरक्रीक पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को। (ख) भूटान में भारत के मनोनीत राजदूत को।

(छ) असम - नागालैंड सीमा पर पुरातत्वीय मानचित्रों का अनुमोदन

(ज) भारतीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला अफगानिस्तान का मानचित्र।

(झ) सर्वेक्षण एवं मानचित्रण तकनीकों पर भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुति।

प्रोतोकोल

14

इस वर्ष के दौरान राज्याध्यक्ष/उपराष्ट्रपति/शासनाध्यक्ष/विदेश मंत्री के स्तर की भारत की 62 यात्राएं तथा भारत से इन्हीं स्तरों की 27 विदेश यात्राएं हुईं, जो विश्व के साथ भारत के सक्रिय क्रियाकलाप को परिलक्षित करती हैं। दिल्ली में 3 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया- अप्रैल, 2008 में भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन; अक्तूबर, 2008 में तीसरा भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) वार्ता मंच शिखर सम्मेलन; तथा नवंबर, 2008 में बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन। अप्रैल-दिसंबर, 2008 के दौरान पांच देशों ने भारत में अपना आवासीय मिशन खोला जिनमें शामिल हैं: लिथुवानिया, मैसेडोनिया, मेडागास्कर, गेबोन तथा अल सल्वाडोर। वर्ष 2008 में पांच देशों के लिए नए प्रधान कोंसलावासों का अनुमोदन प्रदान किया गयाः तुर्की का कोलकाता, चेन्नै, मुंबई और हैदराबाद में; फ्रांस का कोलकाता और बंगलौर में; इराक का मुंबई में; अर्जेंटिना का मुंबई में; तथा जापान का बंगलौर में। वर्ष 2008 में बारह देशः वोत्सवाना, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, फिनलैंड, घाना, आइबरी कोस्ट, लिथवानिया, मालदीव, पोलैंड, रूसी परिसंघ, स्विटजरलैंड तथा जांबिया को मानद कोंसलावास खोलने की अनुमति दी गयी। वर्ष 2008 में स्वीडन और न्यूजीलैंड ने मुंबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले। व्यापार प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने के नए दिशा-निर्देशों का निर्माण किया गया और चार नए मामलों पर कार्य किया जा रहा है। विदेश स्थित मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 143 नए पदों का सृजन किया गया। इस प्रभाग के सम्मेलन कक्ष में तीन शिखर सम्मेलनों में सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त नई दिल्ली में सिस्टेमा इंटेग्रेशन डी सेंट्रो अमेरिका (एसआईसीए) विदेश मंत्रियों के सम्मेलन (जून, 2008); बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक (अगस्त, 2008); आईबीएसए केंद्र बिंदु तथा विदेश मंत्री बैठक (अक्तूबर, 2008); और 14वें आसियान कार्यकारी दल की बैठक (अक्तूबर, 2008) के आयोजन को सहायता प्रदान की। राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उप राष्ट्रपति और समान स्तर के राजकीय दौरे

राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उप राष्ट्रपति और समान स्तर के राजकीय दौरे

क्र.सं.	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
1	महामहिम श्री कोस्तास करामानलिस, यूनान के प्रधान मंत्री	10-13 जनवरी
2	महामहिम श्री फ्रेंक ग्युरसानी, हंगरी के प्रधान मंत्री	16-19 जनवरी
3	परम माननीय गोर्डन ब्राउन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री	20-21 जनवरी
4	महामहिम श्री निकोलस सरकोजी, फ्रांस के राष्ट्रपति	25-26 जनवरी
5	महामहिम श्री एन्ड्रे फोघ रासमुसेन, डेनमार्क के प्रधान मंत्री	4-8 फरवरी
6	महामहिम श्री मोमून अब्दुल कयूम	6-12 फरवरी
7	महामहिम श्री योवेरी कागूता मुसेविनी, उगांडा के राष्ट्रपति	7-11 अप्रैल
8	ब्रुनेई दारुसलाम के महामहिम सुल्तान हाजी हस्सनल बोल्किया	20-23 मई
9	महामहिम श्री बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति	17-21 जून
10	महामहिम ल्योंचेन जिग्में वाय थिनले, भूटान के प्रधान मंत्री	14-17 जुलाई
11	महामहिम श्री हामिद करजई, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	3-5 अगस्त
12	महामहिम श्री आनंद सत्यानंद, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल	8-14 सितंबर
13	महमहिम महमूद अब्बास, फिलीस्तीन के राष्ट्रपति	6-9 अक्तूबर
14	बेल्जियम के सम्राट महामहिम अल्बर्ट II तथा महारानी महामान्या पाओलो	3-12 नवंबर

15	महामहिम श्री मोहम्मद होस्नी मुबारक, मिस्र के राष्ट्रपति	17-19 नवंबर
16	महमहिम श्री रेसेप तय्यिप इरदोगान, तुर्की के प्रधान मंत्रा	20-24 नवंबर
17	महमहिम श्री दिमित्री ए मेदवेदेव, रूस के राष्ट्रपति	4-6 दिसंबर

शिखर सम्मेलन

1	बुरकिना फासो के प्रधान मंत्री (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
2	कांगो के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
3	इथोपिया के प्रधान मंत्री (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
4	घाना के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
5	नाइजीरिया के उप राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
6	सेनेगल के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
7	दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
8	तंजानिया के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
9	उगांडा के राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
10	जांबिया के उप राष्ट्रपति (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	8-9 अप्रैल
11	ब्राजील के राष्ट्रपति (आईबीएसए शिखर सम्मेलन)	14-16 अक्तूबर
12	दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति (आईबीएसए शिखर सम्मेलन)	14-16 अक्तूबर
13	महामहिम लायोन्चेन जिगेमी वाय. थिन्ले, भूटान के प्रधान मंत्री (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर
14	महामहिम डॉ. फकरुद्दीन अहमद, मुख्य सलाहकार, बांग्लादेश (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर
15	महामहिम जनरल थीन सेन, म्यांमा के प्रधान मंत्री (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर
16	महामहिम श्री पुष्प कमल दहाल "प्रचंड", नेपाल के प्रधान मंत्री (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर
17	महामहिम श्री महिन्दा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर
18	महामहिम श्री सोमचई वोंगसावत, थाईलैंड के प्रधान मंत्री (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन)	12-13 नवंबर

राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उप राष्ट्रपति तथा समान स्तर के सरकारी/कार्यकारी दौरे

1	महामहिम श्री नवीनचंद्र रामगुलाम, मॉरीशस के प्रधान मंत्री	6-10 जनवरी
2	महामहिम श्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नार्वे के प्रधान मंत्री (दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन)	5-7 फरवरी
3	महामहिम श्री मैती विनहेनन, फिनलैंड के प्रधान मंत्री (दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन)	6-8 फरवरी
4	महामहिम डॉ. ओलफुर आर. ग्रिमसन, आइसलैंड के राष्ट्रपति (दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन)	6-10 फरवरी
5	महामहिम श्री विक्टर ए. जुबकोव, रूसी परिसंघ की सरकार के अध्यक्ष	12-13 फरवरी
6	थाइलैंड की महामहिम राजकुमारी महा चकरी सिरिन्धोर्न	17-22 मार्च
7	महामहिम डॉ. अली मोहम्मद शीन, तंजानिया के उपराष्ट्रपति	18-25 मार्च
8	महामहिम आगा खान	12-19 मई
9	महामहिम श्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड, नेपाल की प्रधान मंत्री	14-18 सितंबर

विदेश मंत्री तथा समान स्तर के सरकारी दौरे

1	महामहिम श्री यू न्यान विन, म्यांमा के विदेश मंत्री	01-04 जनवरी
2	माननीय मैक्सिम बर्निया, कनाडा के विदेश मंत्री	10-12 जनवरी
3	महामहिम राशिद मेरेदोव, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री	20-22 जनवरी
4	महामहिम श्री अदनान करावएव, किर्गीज गणराज्य के विदेश मंत्री	04-06 फरवरी
5	महामहिम श्री अली बबाकन, तुर्की के विदेश मंत्री	05-10 फरवरी
6	महामहिम राजकुमार सऊद अल-फैजल, सऊदी अरब के विदेश मंत्री	28-29 फरवरी
7	कांगो के विदेश मंत्री, महामहिम श्री एंटिपस म्बुसा न्यामविसा	12-14 मार्च
	केन्या के विदेश मंत्री (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	08-09 अप्रैल
8	लीबिया के अफ्रीकी मामले मंत्री (भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन)	08-09 अप्रैल
9	महामहिम श्री जार्ज येओ, सिंगापुर के विदेश मंत्री	21-25 अप्रैल
10	महमहिम श्री जान कुबिस, स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री	29 अप्रैल-1 मई
11	महामहिम डॉ. दिमित्रिज रूपेल, स्लोवेनिया गणराज्य के विदेश मंत्री (यूरोपीय संघ त्रोयका बैठक)	30-31 मई
12	महामहिम सुश्री रमा, फ्रांस की विदेश राज्य मंत्री (यूरोपीय संघ त्रोयका बैठक)	30-31 मई

एसआईसीए मंत्रालयीय बैठक (9-11 जून, 2008)

1 कोस्टारिका
महामहिम श्री ब्रूनो स्टेगनो इगारते, विदेश मंत्री

2 अल सल्वाडोर
महामहिम श्रीमती मारिसोल आरग्वेटा डी बरिल्लास, विदेश संबंध मंत्री

3 ग्वाटेमाला
महामहिम श्री रोडास हारोल्डो

4 निकारागुआ
महामहिम श्री सैमुअल सान्तोस लोपेज, विदेश संबंध मंत्री

5	पनामा महामहिम श्री सैमुअल लेविस नवारो, प्रथम उप राष्ट्रपति और विदेश संबंध मंत्री	
6	डोमिनिकन गणराज्य महामहिम सुश्री क्लारा क्विनोन्स डी लोंगो, विदेश उप मंत्री	
7	होंडुरास महामहिम श्री एडुआर्डो एनरिक रेना गार्सिया, विदेश उप मंत्री	9-11 जून
8	महामहिम श्री रोहित बोगोल्लागामा, श्रीलंका के विदेश मंत्री	15-16 जून
9	महामहिम श्री मखदूम शाह महमूद कुरेशी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री	27 जून
10	महामहिम डॉ. लुई अमादो, पुर्तगाल के विदेश मंत्री	7-10 जुलाई
11	महामहिम श्री मासाहिको कुमुरा, जापान के विदेश मंत्री	3-5 अगस्त
12	महामहिम श्री यांग जियेची, चीन के विदेश मंत्री	7-9 सितंबर
13	महामहिम श्री स्टीफन स्मिथ, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री	8-12 सितंबर
14	महामहिम श्री वुक जेरेमिक, सर्बिया के विदेश मंत्री	18-20 सितंबर
15	महामहिम श्री अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री	19-20 सितंबर
16	महामहिम डॉ. कोंडोलिजा राइस, विदेश मंत्री, अमरीका	04-05 अक्तूबर
17	महामहिम श्रीमती जैनब हवा बंगुरा, सियेरा लियोन के विदेश मंत्री	07-11 अक्तूबर
18	महामहिम श्री महमूद अली दुर्रानी, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार	11-15 अक्तूबर
19	महामहिम श्री कमलेश शर्मा, राष्ट्रमंडल, महासचिव	19-22 अक्तूबर
20	महामहिम श्री सर्गई लावरोव, रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री	19-20 अक्तूबर
21	संयुक्त राष्ट्र महासचिव	30-31 अक्तूबर
22	अरब लीग महासचिव	29 नवं.-2 दिसं.
23	इक्वाडोर के विदेश मंत्री	14-17 नवंबर
24	महामहिम डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, जर्मनी के विदेश मंत्री और वॉयस चांसलर	19-21 नवंबर
25	इस्टोनिया के विदेश मंत्री	24 नवंबर
26	महामहिम सुश्री कोंडोलिजा राइस, विदेश मंत्री, अमरीका	03-04 दिसंबर

राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों/उप-राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला और समान स्तर के निजी/पारगमन दौरे

1	महामहिम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम, मॉरीशस के प्रधान मंत्री (बिहार सरकार के अतिथि) पटना, जयपुर, आगरा	17-24 फरवरी
2	महामहिम अलहाजी अली महामा, घाना के उपराष्ट्रपति (सीआईआई कंक्लेव)	18-22 मार्च
3	श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति	27-30 मई

भारत के राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री के विदेश दौरे

1	प्रधान मंत्री का चीन दौरा	12-15 जनवरी
2	उप राष्ट्रपति का तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान दौरा	4-10 अप्रैल
3	राष्ट्रपति का ब्राजील, मैक्सिको और चिली दौरा	12-25 अप्रैल
4	प्रधान मंत्री का भूटान दौरा	16-17 मई
5	प्रधान मंत्री का जापान दौरा	7-10 जुलाई
6	प्रधान मंत्री का श्रीलंका दौरा	1-3 अगस्त
7	प्रधान मंत्री का अमरीका और फ्रांस दौरा	22 सितंबर- 1 अक्तूबर
8	प्रधान मंत्री का जापान और चीन दौरा	21-25 अक्तूबर

9	राष्ट्रपति का भूटान दौरा	5-8 नवंबर
10	प्रधान मंत्री का ओमान और कतर दौरा	8-11 नवंबर
11	उप राष्ट्रपति का मालदीव दौरा	10-12 नवंबर
12	प्रधान मंत्री का अमरीका दौरा	13-17 नवंबर
13	राष्ट्रपति का वियतनाम और इंडोनेशिया दौरा	24 नवंबर- 1 दिसंबर

विदेश मंत्री के विदेश दौरे

1	ओमान	13-14 जनवरी
2	ब्रासीलिया और दक्षिण अफ्रीका	16-19 फरवरी व 20-23 फरवरी
3	वाशिंगटन और लंदन	23-27 मार्च
4	सऊदी अरब	19-20 अप्रैल
5	दक्षिण अफ्रीका	9-16 मई
6	पाकिस्तान	20-21 मई
7	चीन	4-7 जून
8	आस्ट्रेलिया	21-24 जून
9	कोलंबो	30 जुलाई- 3 अगस्त
10	न्यूयार्क	28 सितंबर- 2 अक्तूबर
11	वाशिंगटन	10-11 अक्तूबर
12	ईरान	31 अक्तूबर- 2 नवंबर
13	भूटान	5-7 नवंबर
14	काठमांडू	24-25 नवंबर

सम्मेलन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित/सहायता प्रदत्त सम्मेलनों की सूची (1 अप्रैल- 31 जनवरी, 2009)

1	मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली विदेश मंत्री बैठक	10 जून, 2008
2	बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक	29 अगस्त, 2008
3	आईबीएसए वार्ता मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन	13-15 अक्तूबर, 2008
4	आसियान-भारत कार्यकारी दल की चौदहवीं बैठक	30-31 अक्तूबर, 2008
5	तीसरा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन	11-13 नवंबर, 2008
6	भारतीय मिशन प्रमुखों का सम्मेलन	22-24 दिसंबर, 2008

सम्मेलन/बैठक का कार्यक्रम

7	मैकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) के मंत्रियों की बैठक	जनवरी, 2009
8	तालमेल एवं विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)	फरवरी, 2009

1.4.2008 से 30.11.2008 की अवधि के दौरान प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने वाले विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

1	महामहिम श्री मार्को एंटोनियो डी. ब्रंडाओ, ब्राजील के राजदूत	4 अप्रैल, 2008
2	महामहिम श्री दुर्गेश मान सिंह, नेपाल के राजदूत	4 अप्रैल, 2008

3	महामहिम श्री डिजायर कोंबा, गेबरोन के राजदूत	4 अप्रैल, 2008
4	महामहिम श्री एस.जे. क्लाउड अपीथी, बेनिन के राजदूत (अनिवासी)	4 अप्रैल, 2008
5	महामहिम श्रीमती एंजेल पेट्रिकिया फिगोरोआ रोड्रिग्ज, अल सल्वाडोर के राजदूत	16 मई, 2008
6	महामहिम श्री हाजी सादिक अली, ब्रूनेई के उच्चायुक्त	16 मई, 2008
7	महामहिम श्री लेवेंट बिलमेन, तुर्की के राजदूत	16 मई, 2008
8	महामहिम श्री राइनेर इम्पेर्टी, मोरक्को के राजदूत (अनिवासी)	16 मई, 2008
9	महामहिम श्री खालिद सलमान, लेबनान के राजदूत	10 जुलाई, 2008
10	महामहिम श्री अंदी मुहम्मद घालिब, इंडोनेशिया के राजदूत	10 जुलाई, 2008
11	महामहिम श्री वोरोशिलोव इंखवोल्ड, मंगोलिया के राजदूत	10 जुलाई, 2008
12	महामहिम श्री मैनुअल पिकासो, पेरु के राजदूत	10 जुलाई, 2008
13	महामहिम श्री हुमैद बिन अली अल-मानी, ओमान के राजदूत	3 नवंबर, 2008
14	महामहिम श्री जैदी गबाका रिचर्ड, कोर्ट डी आईबर के राजदूत	10 नवंबर, 2008
15	महामहिम श्री जोसेफ केरोन, कनाडा के उच्चायुक्त	10 नवंबर, 2008
16	महामहिम श्री रोबर्टो तोसकानो, इटली के राजदूत	10 नवंबर, 2008
17	महामहिम श्री फ्रांसिको एल. बेनेडिक्टो, फिलीपींस के राजदूत	10 नवंबर, 2008
18	महामहिम श्री केन्नाथ थॉम्पसन, आइरलैंड के राजदूत	10 नवंबर, 2008

1/04/2008 से 30/11/2008 की अवधि के दौरान नई दिल्ली में निम्नलिखित देशों ने अपने आवासी मिशन खोले

1. लिथ्युनिया
2. मैसेडोनिया
3. मेडागास्कर
4. गेबोन
5. अल-सल्वाडोर

■■

कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं **15**

पासपोर्ट कार्यालय

भारत में इस समय 37 पासपोर्ट कार्यालय और 15 पासपोर्ट संग्रहण केंद्र हैं। वर्ष 2008 के दौरान अमृतसर, देहरादून और कोयम्बटूर में तीन नए पासपोर्ट कार्यालय खाले गये। सभी पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार मशीन मुद्रित और मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्ट जारी करते हैं। पासपोर्ट आवेदनों को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैन करके रखा जा रहा है।

पासपोर्ट सेवाएं

पिछले वर्षों के दौरान जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 में कुल 53.10 लाख पासपोर्ट जारी हुए जो 2007 के इसी प्रकार के आंकड़ों की तुलना में लगभग 7.45% अधिक है। 2008 में कुल 54.11 लाख आवेदन प्राप्त हुए जो 2007 के इसी प्रकार के आंकड़ों की तुलना में 10.52% अधिक है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों से प्राप्त हुए कुल राजस्व भी बढ़कर लगभग 617 करोड़ हो गया जिसमें 2007 के कुल राजस्व की तुलना में 8.81% की वृद्धि हुई। मंत्रालय आम जनता के आराम एवं सुविधा के लिए पासपोर्ट जारी करने की पद्धति को और सरल एवं तेज करने के कई उपाय करता रहा है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उपायों का नीचे उल्लेख किया गया हैः-

जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ और स्पीड पोस्ट केंद्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण

पासपोर्ट जारी करने और इससे संबंधित सेवाओं को आवेदकों के द्वार के निकट ले जाने के लिए जिला स्तर पर जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ खोले गए हैं जहां जिलाधीश/पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करता है और संवीक्षा तथा पुलिस सत्यापन के उपरांत उन्हें पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित पासपोर्ट कार्यालय में भेज देता है। इस समय 463 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ हैं। पासपोर्ट आवेदन 1095 स्पीड पोस्ट केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से भी प्राप्त किए जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उपर्युक्त जिला पासपोर्ट केंद्रों और स्पीड पोस्ट केंद्रों को भी ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने तथा तत्संबंधी आंकड़े पासपोर्ट कार्यालयों को अंतरित करने की अनुमति दी गई है जहां से शीघ्रतापूर्वक पासपोर्ट जारी करने में काफी सुविधा होती है।

अवसंरचना

वर्ष 2008 के दौरान लखनऊ, जयपुर, बरेली और सूरत स्थित पासपोर्ट कार्यालय अपने नवनिर्मित सरकारी भवन में स्थानांतरित हुए। भुवनेश्वर स्थित पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न होने वाला है और यह कार्यालय जून 2009 में यहां स्थानांतरित हो जाने की आशा है। विशाखापट्टनम स्थित नए कार्यालय का निर्माण 2009 के मध्य तक शुरू हो जाने की आशा है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय किए गए हैं। आवेदकों की सहायता के लिए और शिकायतों की शीघ्र सुनवाई हेतु सुविधापटल और सहायक डेस्क भी स्थापित किया गया है। संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की कड़ी निगरानी में सी.पी.वी. प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र भी गठित किया गया है।

पासपोर्ट अदालतें

पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों के निवारण हेतु पासपोर्ट कार्यालय आवधिक रूप से पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करते रहे हैं। ये अदालतें पुराने मामलों के निपटान में काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.)

आर.टी.आई.के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

वेबसाइट

1999 में स्थापित सी.पी.वी. प्रभाग की वेबसाइट www.passport.nic.in को और अधिक प्रयोक्ता हितैषी बनाने के लिए इसे समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है। इसमें पासपोर्ट, वीजा, कोंसली मामलों और पी.आई.ओ.पत्रकों के संबंध में विस्तृत सूचना निहित है। इसमें डाउनलोड किए जा सकने वाले फार्म भी हैं। 2008 में सी.पी.वी.प्रभाग की वेबसाइट

हिन्दी में शुरू की गई है। मुख्य वेबसाइट में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में जमा किए गए पासपोर्ट आवेदनों की स्थति की पूछताछ संबंधी जांच का प्रावधान भी है।

कोंसली साक्ष्यांकन

इस साल (अप्रैल, 2008-मार्च 2009) के दौरान मंत्रालय द्वारा 2,50,958 वैयक्तिक एवं शैक्षिक दस्तावेज तथा 2,23,017 वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्यांकित किए गए।

वीजा जारी करना

पिछले वर्षों में हमारे मिशनों और केंद्रों द्वारा वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है जिसमें निर्गम प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है। अधिकांश मिशन और केंद्र या तो वीजा काउन्टर पर उसी दिन अथवा अधिकतम 48 घंटे के भीतर वीजा प्रदान करते हैं।

वीजा से छूट संबंधी करार

2008 के दौरान मिस्र, अल साल्वाडोर, हाण्डूरास, निकारागुआ, दक्षिण अफ्रीका और टर्की के साथ वीजा से छूट संबंधी करारों पर हस्ताक्षर हुए।

राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट जारी करना

सी.पी.वी.प्रभाग ने 2007 में जारी 1950 राजनयिक और 24,867 सरकारी पासपोर्टों की तुलना में 2008 में 2,775 राजनयिक और 22,948 सरकारी पासपोर्ट जारी किए। सी.पी.वी. प्रभाग ने वर्ष 2008 में विदेशी राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को 8,754 वीजा जारी किए।

नई परियोजनाएं

मंत्रालय ने पासपोर्ट/वीजा जारी करने की प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन की दृष्टि से अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। ये निम्नानुसार हैं:

(i) पासपोर्टों का केंद्रीकृत मुद्रण
मंत्रालय ने विदेश स्थित 140 भारतीय मिशनों/केंद्रों के संबंध में सी.पी.वी. प्रभाग, नई दिल्ली में मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों (एमआरपी) के केंद्रीकृत मुद्रण हेतु परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।

(ii) ई-पासपोर्ट जारी करना
राष्ट्रपति ने 25 जून, 2008 को ई-पासपोर्ट जारी करने का शुभारंभ किया जिसे बायो-मेट्रिक पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पायलट परियोजना के तौर पर अब सभी राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किए जा रहे हैं। इस पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर 2009 के अंत तक सामान्य वर्ग में ई-पासपोर्ट जारी करने की शुरुआत करने का प्रस्ताव है।

(iii) पासपोर्ट सेवा परियोजना
सरकार ने नागरिकों को समय पर, पारदर्शी, अधिक आसानी से उपलब्ध होने वाले और भरोसेमंद तरीके से पासपोर्ट संबंधी सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से इसके सूचना प्रौद्योगिकी पहलुओं सहित पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली पर समयबद्ध अध्ययन करने का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एन.आई.एस.जी.) हैदराबाद को सौंपा था। सरकार द्वारा एन.आई.एस.जी. की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है जिसके फलस्वरूप "पासपोर्ट सेवा परियोजना" शुरू की गई है।

इस प्रस्ताव में देश भर में 77 पासपोर्ट सेवाकेंद्र होंगे जिनमें पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया से संबद्ध गैर सरकारी कार्य जैसे आवेदन पत्रों की आरंभिक संवीक्षा, शुल्क प्राप्त करना, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो लेना इत्यादि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेवा प्रदाता द्वारा किए जाएंगे। संवेदनशील कार्य जैसे सुविधा प्रदान करना सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जाएंगे। इस परियोजना के परिणामस्वरूप पासपोर्ट तीन दिनों के भीतर जारी होंगे और जहां पुलिस सत्यापन की जरूरत है, वहां सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिनों के भीतर जारी होंगे। यह पायलट परियोजना जून, 2009 तक चंडीगढ़ और बंगलौर में शुरू हो जाने की आशा है और यह परियोजना 2010 के प्रारंभ तक समूचे देश में पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाने की आशा है।

(iv) वीजा कार्य की आउटसोर्सिंग
विदेश स्थित इक्यावन भारतीय मिशनों/केंद्रों को वीजा आवेदन संग्रहण कार्य आउटसोर्स करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिनमें से 30 भारतीय मिशनों/केंद्रों सियोल, तोक्यो, क्वालालम्पुर, वाशिंगटन, न्यूयार्क, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को, तेल अवीव, बैंकाक, पेरिस, कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, कोलंबो, सिंगापुर में स्थित है। दि हेग, बीजिंग, शंघाई, गुवांगझाऊ, लंदन, बर्मिघम, एडिनबर्ग, इस्लामाबाद, ढाका, चिटगांव, मिलान और काबुल ने पहले से ही इस कार्य को आउटसोर्स कर दिया है।

(v) एपोस्टिल अभिसमय और विधिक सहायता
साक्ष्यांकन के लिए समूचे भारत से दिल्ली आने वाले हजारों लोगों की सुविधा की दृष्टि से चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद तथा कोलकाता स्थित मंत्रालय के शाखा सचिवालय कार्यालयों में 15 जून, 2008 से दस्तावेजों के साक्ष्यांकन एवं एपोस्टिल कार्य भी शुरू हुए। विदेशों में इस्तेमाल के लिए सदस्य देशों के 1,11,331 दस्तावेजों का एपोस्टिल एवं साक्ष्यांकन किया गया

25 जून, 2008 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील केंद्रीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से "इ-पासपोर्ट " प्राप्त करते हुए।

25 जून, 2008 को नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को ई-पासपोर्ट प्रस्तुत करते हुए।

प्रत्यर्पण मामले और विधिक सहायता

वित्तीय धोखा-धड़ी सहित संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का सामना करने के लिए मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय करार संपन्न करने हेतु सक्रियता से बातचीत करता रहा है ताकि इसे एक विधिक और संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जा सके। इन कोंसुली करारों में प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता, सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता और सजायाफ्ता कैदियों का स्थानांतरण शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 16 अप्रैल, 2008 को एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान 23 जून, 2008 को आस्ट्रिया के साथ और 2 नवंबर, 2008 को ईरान के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 18 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में भारत और मिस्र के बीच एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न हुई। पोर्ट लुई में 23 जून, 2008 को मॉरीशस, मैक्सिको में 18 दिसंबर, 2008 को मैक्सिको और दुशांबे में 18 फरवरी, 2009 को ताजिकिस्तान और भारत के बीच अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया और सभी प्रत्यर्पण संधियां अनुसमर्थन दस्तावेज के आदान-प्रदान की तारीख से लागू हो गईं। भारत गणराज्य और पुर्तगाल गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संबंधी करार 13 नवंबर, 2008 से प्रभावी हुआ है। वर्ष के दौरान प्रत्यर्पण एवं पारस्परिक विधिक सहायता संबधी संधियों पर बातचीत करने के लिए एक भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने ईरान की और एक इजराइल प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की।

इस वर्ष के दौरान भारत से विभिन्न देशों को छः व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया गया और विदेशों से चार व्यक्ति भारत में प्रत्यर्पित किए गए। भारत में विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों/राज्य सरकारों/जांच एजेंसियों से प्राप्त बहुत से वारंट/सम्मन/नोटिस और याचना-पत्र (एनआर)कार्यान्वयन हेतु विदेश स्थित संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए।

■■

प्रशासन और स्थापना 16

विदेशों में 171 आवासीय भारतीय मिशन तथा केंद्र हैं। समीक्षाधीन वर्ष में भारत का राजदूतावास रिकजाविक, आइसलैंड के नाम से एक भारतीय मिशन खोला गया। नियामे, बमाको और ग्वाटेमाला शहर में तीन नए मिशन शीघ्र ही खोले जाएंगे। दस वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से मंत्रालय में 514 नये पदों को शामिल किये जाने की मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय के प्रशासनिक तंत्र को कारगर बनाने की दृष्टि से निर्णयन की प्रक्रियाओं को और अधिक विकेन्द्रित करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। अफगानिस्तान और ईराक में रहन-सहन की कठिन स्थितियों को देखते हुए गृह छुट्टी किराया नियमावली का एक पृथक सेट जारी किया गया है तथा इन दोनों देशों में तैनात प्रत्येक भारत आस्थानी कार्मिकों को 30 लाख रु.का बीमा कवर प्रदान किया गया है। "चयनात्मक प्रशासनिक/स्थापना नियमावली एवं क्रियाविधि के दिशा-निर्देश" का संकलन किया जा रहा है और यह अंतिम प्रुफ-शोधन की अवस्था में है। छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन के पश्चात मंत्रालय में मुख्यालय के सभी संवर्गों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और देय बकाया राशि का संवितरण किया जा चुका है। छठे वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए भा.वि.से. (पीएलसीए)नियमावली में संगत संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बदले हुए परिदृश्य के अनुरूप नियमों के निर्वचन एवं अद्यतन करने में होने वाली अस्पष्टता को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहां नियमों में छूट देना आवश्यक है, ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई है और सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके पात्र अधिकारियों को उनकी समस्याओं के प्रति मानवीय एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण रखते हुए राहत प्रदान की गई है।

नई भर्तियों के लिए मांग समय से प्रस्तुत की गयी और सभी स्तरों पर मानव-शक्ति की तैनाती की आवधिक समीक्षा की गई। सभी मिशनों और केंद्रों में मानव-शक्ति की तैनाती की समीक्षा का व्यापक कार्य शुरू किया गया है।

विभागीय प्रोन्नति समिति की नियमित बैठकों और सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन के जरिए मंत्रालय में कार्यरत विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया गया। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों और उनके संभावित समाधान के तौर-तरीकों पर कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त परामर्शी तंत्र की नियमित बैठकें भी हुईं।

मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 3551 है। ब्यौरे परिशिष्ट- । पर दिए गए हैं। ये कार्मिक भारत तथा विदेश स्थित 171 मिशनों/केंद्रों में तैनात हैं। इसमें भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) और भारतीय विदेश सेवा,शाखा "ख" दुभाषिया संवर्ग, विधि एवं संधि संवर्ग तथा पुस्तकालय संवर्ग शामिल हैं परन्तु इसमें समूह "घ" और संवर्ग-बाह्य पद शामिल नहीं हैं।

1 अप्रैल-30 नवंबर 2007 तक सीधी भर्ती, विभागीय प्रोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षाओं, के जरिए विभिन्न समूहों में मंत्रालय में की गई भर्ती, जिसमें आरक्षित रिक्तियों की भर्ती भी शामिल है, का ब्यौरा परिशिष्ट-॥ पर है। परिशिष्ट-III में मंत्रालय के अधिकारियों की भाषा प्रवीणता संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं।

महिला/पुरुष संबंधी मुद्दे

महिला/पुरुष समानता मंत्रालय की समग्र नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसके अनुसरण में महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देकर समान अवसर प्रदान किया जाता है। मंत्रालय में निदेशक तथा इसके ऊपर रैंक के 53 अधिकारी हैं (8 मुख्यालय में तथा 38 विदेश स्थित मिशनों में हैं)। विदेश में तैनात 38 महिला अधिकारियों में से 25 मिशन प्रमुख/केंद्र प्रमुख हैं।

विकलांग व्यक्ति

विकलांग कार्मिकों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करना और अपने कार्मिकों में उन्हें यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने विकलांगों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की है जिनमें भारतीय विदेश सेवा के पद भी शामिल हैं।

अभिलेख एवं रिकार्ड प्रबंधन (ए एंड आर एम)प्रभाग

2008 की प्रथम तिमाही में रिकार्ड प्रबंधन अनुभाग में रखे हुए सभी अभिलेखों को डिजिटल बना दिए जाने के पश्चात यह परियोजना अगले चरण अर्थात् चरण-III में प्रवेश कर गई है जिसके द्वारा मुख्यालय और मिशनों/केंद्रों से प्राप्त हो रहे नए अभिलेखों को डिजटल बनाया जा रहा है।

अभिलेख एवं रिकार्ड प्रबंधन प्रभाग ने 1983 से पूर्व के रिकार्डों का मूल्यांकन करने के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार

(एनएआई) से एक अधिकारी की सेवाएं भी ली हैं जिससे कि मूल्यांकन किए गए रिकार्डों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किया जा सके और जो रिकार्ड कालातीत हो चुके हों उन्हें नष्ट किया जा सके। अब तक 1727 रिकार्ड एनएआई को स्थानांतरित किए जा चुके हैं तथा 1820 रिकार्डों को नष्ट किया जा चुका है। रिकार्डों के अवर्गीकरण, समीक्षा तथा नष्ट किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

9 जनवरी, 2009 को विदेश सचिव द्वारा चुनिंदा लोगों के इस्तेमाल के लिए मंत्रालय के दस्तावेजों की स्कैनिंग हेतु ब्राउजिंग कक्ष का उद्घाटन किया गया।

राजभाषा नीति का अनुपालन एवं विदेशों में हिन्दी का प्रचार प्रसार

10 जनवरी, 2008 को विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया। केंद्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया।

स्थापना प्रभाग

स्थापना प्रभाग के प्रभार में मुख्यतः परिसम्पत्तियों को किराए पर लने एवं उसके अनुरक्षण, विदेश भत्ते तथा प्रतिनिधिक भत्ते के निर्धारण, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर एवं सरकारी वाहनों की खरीद, आपूर्ति और अनुरक्षण, कलात्मक वस्तुओं की आपूर्ति, विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसरों एवं हॉस्टलों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण, तोशाखाना के अनुरक्षण तथा लेखन-सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति शामिल हैं।

वर्ष के दौरान इन मुद्दों को प्रशासित करने वाले नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के प्रयास जारी रहें ताकि उन्हें सरल एवं पारदर्शी बनाया जा सके। इस कार्य के भाग के रूप में विदेश भत्ते, विशेष अनुदान, आवास आवंटन, मुख्यालय में उपकरणों के रखरखाव तथा कार कोड को प्रशासित करने वाले नियमों की समीक्षा की गई और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाया गया।

सूचीकरण योजना के अंतर्गत विदेश भत्ते की वार्षिक समीक्षा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई। 1954 से पहली बार विदेश भत्ते का निर्धारण करने वाले सामानों एवं सेवाओं के समूह में संशोधन करके उसे आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप अधिक यथार्थ बनाया गया।

वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से विदेशों में तैनात अधिकारियों के लिए स्लैब कटौती संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चूंकि विदेशों में तैनात अधिकारियों के मूल वेतन का अधिकांश भाग स्लैब कटौती के रूप में चला जाता था, इसलिए इस पर उनकी ओर से काफी आक्रोश होता था। 1 सितंबर, 2008 से स्लैब कटौती की यह पद्धति समाप्त कर दी गई है जिससे विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों की काफी समय से लंबित शिकायत दूर हो गई है।

इस प्रभाग ने आइसलैंड, माली, नाइजर तथा ग्वाटेमाला में चार नए मिशन खोलने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया। इस प्रयोजन हेतु संपदा दल की यात्रा के उपरांत भारतीय राजदूतावासों के लिए स्थान हेतु उपयुक्त परिसरों की पहचान करने, अस्पतालों, होटलों और विद्यालयों को पैनल में रखने तथा भत्तों के निर्धारण के उपाय किए गए।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के निरीक्षण के तौर पर सैन्टियागो, साओपोलो, ब्यूनस आयर्स, सूवा, ब्रुनेई, पोर्ट मोर्सबी, ताशकंद, दुशांबे, विषकेक, कुवैत, आबूधाबी, दार-एस-सलाम, जोहांसबर्ग, कम्पाला, कैनबरा, सिंगापुर और बैंकाक स्थित हमारे मिशनों का निरीक्षण निरीक्षकों के एक उच्चस्तरीय दल द्वारा किया गया। उनकी रिपोर्टों से इन मिशनों में प्रकार्यात्मक एवं प्रशासनिक मसलों को सुलझाने में काफी सहायता मिली।

पिछले वर्ष शुरू किए गए के.जी.मार्ग और गोल मार्किट स्थित विदेश मंत्रालय के हॉस्टल का नवीकरण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रहा। इसके फलस्वरूप, इन हॉस्टलों में रहन-सहन की स्थितियों में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसी प्रकार द्वारका स्थित विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसर में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए और भी उपाय किए गए। फलस्वरूप अब इस परिसर के अधिभोग में 90% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुम्बई स्थित जिन्ना हाउस के नवीकरण के लिए भी उपाय किए गए जोकि इस सम्पत्ति से संबंधित चल रहे मुकदमे के कारण रूक गया था। कानूनी राय लेने के बाद नवीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू की गई है।

प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के चाणक्यपुरी आवासीय परिसर को अधिग्रहित करने का कार्य शुरू किया। इस प्रयोजन हेतु एकीकृत भवन प्रबंधन वाली एक कंपनी को परिसर का अधिग्रहण करने तथा निर्माण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया ताकि उनकी त्रुटि को देयता अवधि के भीतर ठीक किया जा सके। भवन के निर्माण संबंधी समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह आवासीय परिसर मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रकार्यात्मक हो गया। इससे मंत्रालय की आवासीय समस्या का समाधान करने में काफी सहायता मिलेगी।

मंत्रालय में सभी ओडीए मदों को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया कार्य अब समाप्त होने वाला है। पहली बार मंत्रालय में प्रायः सभी ओडीए मदों का डिजिटज रिकार्ड साफ्टवेयर एवं आंतरिक वेबसाइट के रूप में तैयार किया गया है। मंत्रालय इन खरीदी गई ओडीए मदों के अभिलेखन की प्रणाली तथा स्टाक रजिस्टरों को पहले से ही काफी आधुनिक एवं सुस्पष्ट बनाया जा चुका है। लोगों की आवाजाही एवं वस्तुओं को मानीटर करने के लिए ओडीए प्रकोष्ठ में एक वीडियों कैमरा पहले से ही लगा दिया गया है।

मोबाइल फोन तथा आवासीय फोन सुविधाओं को शासित करने वाली नई नीति का क्रियान्वयन कि गया जिससे विदेश स्थित हमारे मिशनों को सुचारू रूप से कार्य करने की सुविधा प्राप्त हुई। इसी प्रकार प्रतिनिधिक उपयोग के लिए मिशन प्रमुखों को दी जाने वाली क्राकरी, छुरी-कांटा एवं रसोई के वर्तनों की व्यवस्था को अद्यतन करने के उपाय किए गए। इन सुधारों को शुरू करने से पहले विदेशों मे प्रतिनिधिक दायित्वों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को देखते हुए इन मदों में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

व्यापक अभ्यास के उपरांत विदेशों में सरकारी वाहनों को बदलने और उनके रखरखाव संबंध में अपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया। तत्पश्चात् आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कार कोड लाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करके कार कोड का अब संशोधन कर दिया गया है जिससे विदेशों में हमारे मिशनों के कार्यकरण में सुविधा होगी।

प्रभाग ने अनावश्यक मुकदमेबाजी तथा सरकार को हाने वाली वित्तीय हानि से बचने के लिए विदेश स्थित सरकारी एवं किराए की सम्पत्तियों के बेहतर रखरखाव के लिए एक नई प्रणाली भी शुरू की है। इन मुद्दों पर नए नीतिगत दिशानिर्देश सभी मिशनों एवं केंद्रों को जारी किए गए।

सरकारी कार्यालयों विशेषकर साउथ ब्लाक, अकबर भवन तथा पटियाला हाउस की साफ-सफाई एवं रखरखाव में सुधार लाने के लिए मुख्यालय में और भी उपाय किए गये। विदेश मंत्रालय के सभी कार्यालयों के लिए कार्यालय उपकरणों की खरीद एवं रखरखाव को और भी सुव्यवस्थित करने के उपाय भी किए गए।

सतर्कता

- 1 अप्रैल 2008 की स्थिति के अनुसार मामलों का विवरण।
- 31.03. 2008 तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 162
- 1.4.2008 से 31.3. 2009 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए मामलों की संख्या 50
- 31.3.2009 तक मामलों की कुल संख्या उ (162+50)ः 212
- 31.3.2009 तक औपचारिक जुर्माना लगाकर बंद किए गए मामलों की संख्या 28
- 31.3.2009 तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मृत्यु आदि के कारण औपचारिक जुर्माना लगाए बिना बंद किए गए मामलों की संख्याः 50
- 31.3.2009 तक बंद किए गए कुल मामलों की संख्याः (28+50) 78
- 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार लंबित कुल मामलों की संख्याः (212-78) 134

3.11.2008 से 7.11.2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों तथा विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने केन्दीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित शपथ ली।

वर्ष के दौरान प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर खर्च करने, पदवियां स्वीकार करने संबधी संवैधानिक प्रावधानों, निविदा प्रक्रिया आदि संबंधी सीवीसी के दिशानिर्देशों पर विभिन्न परिपत्र जारी किए गए

ई-शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान मास्को, दोहा, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और ह्यूस्टन स्थित पासपोर्ट और वीजा सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हुआ। जेद्दा स्थित पासपोर्ट सेवाओं की आउटसोर्सिंग का कार्य पूरा हुआ। दुबई, आबूधाबी, कुवैत, रियाद, कुआलालंपुर स्थित पासपोर्ट एवं वीजा सेवाओं आउटसोर्सिंग का कार्य चल रहा है।

मंत्रालय ने कार्मिक बजट, विदेश यात्राओं तथा संसद प्रश्नों से संबंधित जानकारी एकत्र करने एवं इन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की है। इसके लिए साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है जोकि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। जनवरी 2009 में सिंगापुर स्थित हमारे मिशन के वीजा एवं पासपोर्ट सेवाओं की आउटसोर्सिंग का कार्य पूरा हुआ।

परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग विदेश मंत्रालय के उपयोग के लिए, इसके कार्यालयों एवं कर्मचारियों के आवासों हेतु भारत तथा विदेशों में भवनों के पुनर्निर्माण एवं भूमि एवं भवनों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। विदेशी स्टेशनों में सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य भी परियोजना प्रभाग द्वारा देखा जाता है। अब तक विदेश में 77 स्टेशनों पर 80 चांसरी भवन, विदेश में 91 स्टेशनों पर मिशन/केंद्र प्रमुखों के आवास तथा विदेश पर 47 स्टेशनों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 634 आवास विदेश मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसके अतिरिक्त 2 स्टेशनों पर सांस्कृतिक केंद्र तथा एक स्टेशन पर 1 संपर्क कार्यालय की परिसम्पत्तियां भी सरकार के स्वामित्व में हैं। इस समय निर्माण/पुनर्विकास/नवीनीकरण की 40 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

इस समय विदेश स्थित परियोजनाओं में बीजिंग, टोक्यो और काठमांडू में चांसरी तथा आवास एवं सिंगापुर में आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। करांची में तीन परिसम्पत्तियों के नवीनीकरण, बोगोटा कोलम्बो, प्राग में चांसरियों के नवीनीकरण

का कार्य भी चल रहा है। बूडापेस्ट, ब्रासिलिया, ढाका इस्लामाबाद, काबुल, लंदन, ताशकंद तथा वार्सा में निर्माण परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया की अवस्था में है।

बोगोटा में चांसरी, सोफिया और त्रिपोली में राजदूतों के लिए आवास, हैम्बर्ग में प्रधान कोंसुल के लिए आवास तथा मिलान में 5 कर्मचारियों के आवास के लिए 2008-09 में निर्मित परिसम्पत्तियां अधिग्रहित की गई हो। गैबरोन में चांसरी और आवासों के निर्माण के लिए खाली पड़े भूखंड अधिग्रहित किए गए हैं। जहां तक संभव हो अधिक से अधिक स्टेशनों पर निर्मित परिसम्पत्तियां अधिग्रहित करने के लिए मंत्रालय सतत एवं जोरदार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में उन स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है जहां किराए के भुगतान संबंधी व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। निर्मिम परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए प्रक्रियाधीन प्रस्तावों में शामिल हैं-कोलंबो, डबलिन, हनोई,प्रीटोरिया, रोम ओर सैन्टियागो। ब्रुनेई और वेलिंगटन में चांसरियों एवं आवासों के लिए तथा नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए भूमि की खरीद हेतु प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अदन (जोशी भवन), दार-एस-सलाम (खाली पड़ा फ्लैट)और ब्युनस आयर्स (पुरानी चांसरी)में तीन अधिशेष परिसम्पत्तियों का विक्रय कर दिया गया है।

भारत की परियोजनाओं में विदेश मंत्रालय के भावी मुख्यालय अर्थात् जवाहर लाल नेहरू भवन तथा कैनिंग लेन, नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास का निर्माण कार्य जोरों पर है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आवासी परिसर और एफ्रो एशियाई विधिक परामर्शदात्री समिति के मुख्यालय हेतु भवन तथा इसके महासचिव के लिए चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आवास एवं कोलकाता में आईसीसीआर के क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

2008-09 के अनुमोदित बजट आबंटन में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है ओर परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए 2009-10 के लिए पूंजीगत परिव्यय बजट के अंतर्गत 612 करोड़ रुपए के प्रावधान की मांग की गई है।

■■

समन्वय

17

समन्वय प्रभाग की तीन शाखाएं हैं अर्थात् संसद अनुभाग, समन्वय अनुभाग और शिक्षा अनुभाग।

संसद अनुभाग

समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय का संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु है; इन कार्यों में प्रश्न-उत्तर आश्वासन, विदेश संबंधों पर बहस और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। यह प्रभाग विदेश मामलों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है और विदेश मामलों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति तथा अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग राज्यपालों, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, यात्रा की राजनैतिक एवं प्रकार्यात्मक औचित्य, की गई बैठकों और संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र की सिफारिश को ध्यान में रखने के बाद ही विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक अनापत्ति प्रदान की जाती है। अप्रैल से नवंबर, 2008 के दौरान समन्वय प्रभाग ने इन दौरों के लिए वर्ष 2007 की तुलना में लगभग 21% वृद्धि दर्ज करते हुए, 2539 राजनीतिक अनापत्ति जारी की थी। इस अनुभाग ने विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों तथा नौसैनिक जहाजों से यात्राओं के लिए राजनयिक अनापत्तियां प्रदान करने से संबंधित कार्यों को भी निपटाया। अप्रैल-नवंबर 2008 के दौरान समन्वय प्रभाग द्वारा विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए वर्ष 2007 की इसी अवधि की तुलना में 859 के विरुद्ध 13 की वृद्धि दर्ज करते हुए 971 अनापत्तियां जारी की गईं।

इस प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके एक ओर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों और दूसरी ओर विदेशी सरकारों या भारत में उनके मिशनों, विदेश स्थित राजनयिक मिशनों/केंद्रों के प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार माध्यम सबंधी दिशानिर्देशों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है।

समन्वय अनुभाग ने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भारतीय खिलाड़ियों और खेल-कूद टीमों की भागीदारी के लिए और विदेशी खिलाड़ियों/टीमों की भारत यात्रा के लिए बड़ी संख्या में अनुमोदन प्रदान करने की भी कार्रवाई की थी।

यह अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मैत्री और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के वास्ते अनापत्ति देने के अनुरोधों की भी जांच करता है।समन्वय अनुभाग विदेशी राष्ट्रिकों को पद्म अवार्ड प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है।

समन्वय अनुभाग विदेश स्थित भारतीय मिशनों/कंद्रों से नामांकन प्राप्त करता है और मंत्रालय की सिफारिशों से गृह मंत्रालय को सूचित करता है। समन्वय प्रभाग द्वारा मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में कौमी एकता सप्ताह/दिवस (19-25 नवंबर) भी मनाया गया;

समन्वयन अनुभाग ने फरवरी, 2008 में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित डिफेक्सपो भारत- 2008 के दौरान मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ तालमेल बैठाने में रक्षा मंत्रालय की सहायता की। यह प्रभाग बंगलोर में फरवरी, 2009 में आयोजित होने वाले आगामी एयरो इंडिया-2009 के लिए विदेश मंत्रालय/विदेश स्थित मिशनों एवं केंद्रों के साथ तालमेल बैठाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय की मदद कर रहा है।

समन्वय अनुभाग ने विभिन्न मुद्दों पर विविध अंतरमंत्रालयी बैठकों में प्रतिनिधित्व किया तथा मंत्रालय की जानकारी दी; इसी प्रकार समन्वय अनुभाग ने महत्वपूर्ण विषयों पर दस्तावेज, टिप्पणियां और सार-संक्षेप तैयार करने में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से जानकारी हासिल की। पदेन निदेशक के रूप में संयुक्त सचिव (समन्वय)ने सार्वजनिक क्षेत्र के एक संगठन एजुकेशन कंसलटैंट्स इंडिया लि. की बोर्ड बैठकों में भाग लिया और उनके मौजूदा कार्यकलापों तथा भावी कार्यक्रमों पर सलाह दी।

शिक्षा अनुभाग

शिक्षा अनुभाग इस मंत्रालय को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों पर स्ववित्त पोषित विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत

एमबीबीएस/बीडीएस/बीई/बी.फार्मेसी ओर भारत के विभिन्न संस्थाओं से डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 63 मित्र, पड़ोसी एवं विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है। इस अनुभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं और शोध पाठ्यक्रमों में चयनात्मक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप सहित इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परा-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान करने की भी कार्रवाई की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए शिक्षा अनुभाग ने एमबीबीएस/बीडीएस और बीई/बी फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्रमशः 52 और 93 आवेदन प्रज्ञपत किए और उन पर कार्रवाई की। इसके अलावा अप्रैल से नवंबर, 2008 की अवधि के दौरान भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 433 आवेदकों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान की गई।

■■

विदेश प्रचार

18

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दृष्टिकोण/पक्ष को रखने के साथ तालमेल के माध्यम से विभिन्न राट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के कार्य जारी रखा। यह नियमित एवं विशेष प्रेस ब्रीफिंग, वक्तव्यों, पृष्ठभूमि और विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर पोस्टिंग के माध्यम से किया गया।

प्रभाग का मुख्य कार्यकलाप अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत का संबंधों पर सूचना के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित रहा। अमरीका के साथ नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने पर सहयोग करार, जिसे कि 123 करार के रूप में भी जाना जाता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठकों एवं संगोष्ठियों की मेजबानी करना कुछ ऐसे कार्य थे जिनपर प्रभाग द्वारा यथोचित बल दिया गया।

प्रभाग ने मुख्यालय में सभी प्रयोक्ताओं के लिए मीडिया अनुवीक्षण परियोजना के प्रथम चरण की शुरूआत की। इसका उद्देश्य मंत्रालय के लिए मीडिया संसाधनों की मॉनीटरिंग को सुव्यवस्थित करना है। यह परियोजना प्रिंट, वेब और इंटरनेट आधारित मीडिया को सुव्यवस्थित ढंग से मानीटर करती है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक काल के आधार पर 5 दैनिक उत्पाद उपलब्ध कराता है।

भारत आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का प्रेस कवरेज

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के ठोस क्रिया-कलाप का प्रमाण विदेशों से गणमान्य व्यक्तियों के भारत दौरों की संख्या से मिला। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए दौरों में उल्लेखनीय थेः ईरान के राष्ट्रपति, श्री अहमदनेजाद, सीरिया के राष्ट्रपति डा. बशर अल-असाद, मिस्र के राष्ट्रपति श्री होस्नी मुबारक, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहाल "प्रचंड" भूटान के प्रधानमंत्री श्री लयोनचेन जिग्मी वाई. थिन्ले और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री अनातोली मेदवेदेव। प्रभाग ने इन यात्राओं से मिले अवसरों का उपयोग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोणों का प्रचार-प्रसार करने में किया। प्रभाग ने आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त प्रैस बातचीत का आयोजन भी किया। भारत की चिंता के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया को अद्यतन रखने के लिए मंत्रालय के प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष ब्रीफिंग का भी नियमित रूप से आयोजन किया गया।

भारत के गणमान्य लोगों के विदेश दौरों का प्रेस कवरेज

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के विदेश दौरे के साथ जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सभी संभारतंत्रीय व्यवस्था जिसमें कि पत्रकारों द्वारा कवरेज को फाइल करने की सुविधा से पूर्ण सुसज्जित मीडिया केंद्र स्थापित कर उसे प्रकार्यात्मक बनाना शामिल है, मीडिया ब्रीफिंग और अन्य व्यवस्था करना ताकि कार्यक्रम का समय पर मीडिया का कवरेज सुनिश्चित हो सके - प्रभाग के कार्य का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। वर्ष के दौरान राष्ट्रपति की ब्राजील, मैक्सिको, चिली, वियतनाम और इंडोनेशिया की यात्रा; प्रधानमंत्री की भूटान, जापान (जी-8 शिखर बैठक) श्रीलंका (15वें सार्क शिखर बैठक) अमरीका और फ्रांस (यूएनजीए और असैनिक नाभिकीय सहयोग करार), चीन, ओमान और कतर (द्विपक्षीय) की यात्रा; उपराष्ट्रपति की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा और विदेश मंत्री की सउदी अरब, पाकिस्तान, रूस, आस्ट्रेलिया, मिस्र और अमरीका की यात्रा के साथ जाने वाले मीडिया प्रतिनिधिमंडल को सुविधाएं प्रदान की गई।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ संपर्क

सरकारी प्रवक्ता के कार्यलय ने भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख घटनाक्रमों, आने और जाने वाली उच्च स्तरीय यात्राएं और दिन-प्रतिदिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नियमित ब्रीफिंग आयोजित कर पूरे वर्ष के दौरान भारतीय और विदेशी मीडिया के साथ संपर्क बनाए रखा। वर्ष के दौरान (नवबंर, 2008 तक) 177 प्रैस विज्ञप्तियां, 91 प्रैस ब्रीफिंग और 25 संयुक्त प्रैस वक्तव्य और 66 मीडिया सलाह चिंता के विभिन्न मुद्दों पर प्रभाग द्वारा जारी किया गया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टी.वी. संगठनों के साथ प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसे साथ-साथ मंत्रालय के वेबसाइट पर लोड किया गया।

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय भारतीय विदेश नीति के संचालन से संबंधित दिन-प्रतिदिन के घटनाक्रमों पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने के केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। कार्यालय ने प्रवक्ता द्वारा नियमित मीडिया ब्रीफिंग आयोजित किया जिसे

प्रैस विज्ञप्तियों, ब्रीफिंग मुद्दे एवं वक्तव्यों द्वारा संपूरित किया गया। अप्रैल-नवंबर, 2008 के दौरान सरकारी प्रवक्ता के कार्यलय द्वारा लगभग 91 प्रैस ब्रीफिंग आयोजित किए गए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान 200 से अधिक प्रैस विज्ञप्तियां और वक्तव्य जारी किए गए। इन्हें ई-मेल के माध्यम से मीडिया में परिचालित किया गया और साथ-साथ मंत्रालय के वेबसाइड पर भी डाला गया। मीडिया को ब्रीफिंग के बारे में और वेबसाइठ के अद्यतन किए जाने के बारे में मीडिया को एसएमएस द्वारा अलर्ट करना प्रभाग ने जारी रखा। वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधकारियों द्वारा हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष मीडिया समूह को संबोधित किया गया। इसके साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया से जुड़े लोगों को पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान कर सरकार की स्थिति और महत्व पर सूचना देने के लिए नियमित प्रयास किए गए। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और टीवी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री; विदेश राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए।

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का अनुरक्षण एवं उसे नियमित रूप से अद्यतन करना

प्रभाग के प्रचार-प्रसार के प्रयासों में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने उपयोगी साधन के रूप में कार्य करना जारी रखा। वेबसाइट के प्रैस खंड को प्रधानमंत्री, मंत्रियों द्वारा विदेश नीति पर दिए गए व्याख्यानों/साक्षात्कारों/वक्तव्यों तथा प्रैस विज्ञप्तियों, सरकारी प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ब्रीफिंग के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया गया। इस वेबसाइट का व्यापक रूप से भारत के अंदर और बाहर लोगों द्वारा उपयोग किया गया और विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र और विभिन्न मंत्रालयों के वेबसाइट से हाइपरलिंक किया गया।

प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के सूचना पट्ट का प्रयोग करना जारी रखा ताकि विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को भारत के विभिन्न पहलुओं पर स्थानीय मीडिया में प्रचार के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से लिखी सामग्री मिल सके। हमारे मिशनों/ केन्द्रों के उपयोग के लिए समाचार पत्रों से रूचि के समाचार कतरनों को दैनिक आधार पर बोर्ड पर भी अपलोड किया गया।

वर्ष 2006 में शुरू की गई वेबसाइट के हिंदी रूपांतर की विशेष रूप से हिंदी भाषा के मीडिया से जुड़े लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई। प्रभाग वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाना जारी रखा।

भारत आस्थानी विदेशी मीडिया को संभारतंत्रीय सहायता

भारत में आस्थानी लगभग 300 से अधिक सशक्त विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे रूचि के विभिन्न विषयों पर संगत सूचना प्राप्त करने तथा प्रत्यय दस्तावेज, वीजा और आवासीय परमिट के मामलों में सहायता प्रदान करने के माध्यम से आसानी से अपना कार्य निष्पादन कर सकें। विदेशी पत्रकारों को वीजा विस्तार और/ अथवा प्रत्यापन सुविधा प्रदान की गई।

विदेशी पत्रकारों द्वारा परिचय यात्रा

भारत में विदेशी पत्रकारों द्वारा की जाने वाली परिचय यात्राएं विदेशी मीडिया के समक्ष भारत की और वास्तविक और समकालीन छवि दर्शाने के लिए प्रभाग द्वारा किया जा रहा एक महत्वपूर्ण प्रयास है क्योंकि इससे पत्रकार भारत की राजनीति, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति की अद्वितीय और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों की सिफारिश पर प्रभाग ने अप्रैल-नवंबर, 2008 की अवधि के दौरान भारत में 72 विदेशी पत्रकारों की परिचय यात्राएं आयोजित की। इन यात्राओं के दौरान प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों और भारत के उत्कृष्टता प्राप्त केंद्रों का दौरा कर सकने के लिए पत्रकारों को सभी संभारतंत्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराए गए। प्रभाग ने दौरे पर आने वाले विदेशी पत्रकारों के लिए मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और व्यवसाय के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें भी आयोजित की।

वृत्त-चित्र एवं फिल्म

प्रभाग के मुख्य कार्यों में विदेशी दृश्य-श्रृव्य एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए वृत्त-चित्रों को मंजूरी प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा विदेशी निर्माताओं द्वारा भारत में वृत्त चित्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु कार्रवाई की गई। अंतर-मंत्रालयी परामर्शो के परिणामस्वरूप प्रक्रियाएं काफी सरल हो गई हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा अमरीका, यूके, जापान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्वीडेन, इटली, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और चीन से विदेशी निर्माताओं द्वारा वृत्त चित्र निर्माण करने के 370 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन एवं विशेष कार्यक्रम

संबंधित क्षेत्रीय प्रभाग की सिफारिशों पर प्रभाग ने भूटान और मालदीव जैसे देशों में विशेषज्ञ कार्यक्रम और मीडिया सहायता उपाय शुरू किया। प्रभाग ने इब्सा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) संपादक सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शीर्षस्थ मीडिया घरानों के संपादकों ने भाग लिया। प्रभाग ने बिमस्टेक शिखर बैठक के लिए मीडिया सुविधा स्थापित करने में भी सहायता की। मुम्बई पर कायरतापूर्ण आंतकी हमले के पश्चात प्रभाग ने हमले के बाद के प्रथम सप्ताह में 272 तक विशेष वीजा जारी करने और इस दुखद घटना को कवर करने के लिए विदेशी मीडिया को सुविधा प्रदान की।

■■

लोक राजनय प्रभाग **19**

अप्रैल 2006 में अपने सृजन के बाद से ही विदेश मंत्रालय का लोक राजनय प्रभाग दोनों ही भारत के भीतर और विदेशों में शोधकर्ताओं, विचारकों, विद्वानों, सिविल समाज और उद्योग के सम्पर्क में रहा है। और भारतीय विदेश नीति के मूलतत्वों को प्रकाश में लाने के साथ-साथ भारत के सामने पेश आए विदेश नीति संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनसमुदाय विमर्श के लिए पहल करता रहा है। प्रभाग के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत के भीतर और दुनिया भर में पहुँच बनाने वाले कार्यकलाप और श्रव्य-दृश्य और प्रकाशन शामिल है। इसका उद्देश्य भारत की विदेश नीति को जन साधारण में प्रभावकारी ढंग से प्रक्षेपित करना है ताकि लोग स्वंय भारत के बारे में और इसके विदेश संबंधों के बारे में अधिक से अधिक समझ और जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसी समझ उत्पन्न करने के लिए यह वांछनीय है कि अंतरराष्ट्रीय नीतियों के मुद्दों में सिविल समाज और जनसामान्य की भावनाओं और प्रतिभाओं को शामिल किया जाए। अतएव यह प्रभाग भारतीय विदेश नीति के निमाण में सार्वजनिक भागीदारी/लोकहित से जुड़े मामलों की निगरानी करता है।

प्रभाग विदेश मंत्रालय के साथ-साथ विदेश नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और परस्पर मेलजोल के कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र विशेषज्ञों और शोधकताओं के स्रोतों का उपयोग करता रहा है। नीति निमाण में जनसामान्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली से बाहर विदेश नीति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा।

व्यापक पहुँच कार्यकलाप

प्रभाग ने व्यापक पहुँच के अनेक कार्यकलापों का आयोजन किया जिनमें विदेश नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलनों और संगोष्ठियों के साथ-साथ दूसरे देशों से आए सांसदों के लिए भारत पर पूर्वाभिमुखी कार्यक्रम भी शामिल है।

प्रभाग ने लेबर फ्रेण्ड्स ऑफ इण्डिया(एल एफ आई एन), यूके से आए 7 सदस्यों वाले सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल के लिए चेन्नै, हैदराबाद और नई दिल्ली में 11 से 16 फरवरी तक आंतरिक और विदेश नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रभाग ने बिहार सरकार के सहयोग से 26-27 अप्रैल, 2008 को पटना में "भारत-नेपाल संबंधों में उभरते रूझान" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। बिहार के मुख्य मंत्री और नेपाल के प्रत्यक्ष योजना और निमार्ण कार्य मंत्री ने इस सांगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने समापन भाषण दिया। एक 45 सदस्यों वाले नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ने संगोष्ठी में हिस्सा लिया जिसमें भारत से कई विद्वानों, विचारकों, उद्योग के प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और सिविल समाज के प्रबुद्धजनों ने भी हिस्सा लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य हमारे द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना था और संगोष्ठियों में हमारे राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों, व्यापार और आर्थिक सहयोग, सीमा सुरक्षा और उसका प्रबंधना,पन-विद्युत क्षेत्र में सहयोग, साझा नदी जल का बंटवारा और बाढ़ की समस्याओं जैसे मुद्दों को शामिल किया गया।

पटना संगोष्ठी के बाद 26-27 सितम्बर, 2008 को वाराणसी में "भारत और नेपालः लोकतंत्र और विकास के भागीदार" विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने इस विचार-गोष्ठी का उद्घाटन किया। नेपाल के विधि, न्याय और निर्वाचन सभा के मंत्री महामहिम श्री देव गुरूंग ने एक 30 सदस्यों वाले नेपाली प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की थी। नेपाल में शांति प्रक्रिया का समेकन, संघर्ष के बाद की स्थितियों में पुर्नवास की प्रक्रिया, संघीय ढाँचा और सर्वग्राहयता, नए संविधान का निर्माण, खुली सीमा इस विचार गोष्ठी में बात-चीत के कुछ खास मुद्दे रहे।

प्रभाग ने पुस्तक समीक्षा लिटरेरी ट्रस्ट के सहयोग से नई दिल्ली में "21वीं सदी में महाशक्तियों की प्रतिद्वन्दिताः 21वीं सदी के लिए सीख" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। भारत और चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मिश्र, आस्ट्रेलिया से कई विदेशी विद्वानों और विचारकों ने इस विचार-गोष्ठी में हिस्सा लिया जिसमें शीत युद्ध के क्षत्रीय परिणामों, 21वीं सदी में बहु-ध्रुवीकरण की संभावनाओं और उभरती वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की गई।

प्रभाग ने ग्रामीण और औद्योगिक विकास केन्द्र, चंडीगढ़ के सहयोग से वर्ष के आरंभ में "कुल कृषि-कार्यशाला और स्थल दौरे-कृषि संबंधी ज्ञान की साझीदारी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को जोड़ना" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। पाकिस्तान से आए एक 16 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ उत्पादन, विपणन और शोध संबंधी

अनुभवों का आदान-प्रदान किया। विचार गोष्ठी का उद्देश्य दोनों ओर के पंजाब प्रान्तों के लोगों के बीच सीधा सामाजिक-आर्थिक उपयोग के क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करना और भरोसा बढ़ाना था।

प्रभाग ने भारत और इथोपिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदिस अबाबा में 29 अप्रैल, 2009 को आयोजित एक दिवसीय की संगोष्ठी को अपना सहयोग प्रदान किया। इस संगोष्ठी में भारत-इथोपिया संबंधों की मौजूदा स्थिति और कैसे दोनों देश अपने आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं इस विषय पर चर्चा हुई।

लोक राजनय प्रभाग ने दिव्य जीवन प्रतिष्ठान सोसाइटी द्वारा 15-17 मई, 2008 को शिलांग में "उत्तर पूर्व के साठ वर्षः अनुभवों का स्मरण" विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसका आंशिक वित्तपोषण किया। इस सम्मेलन में पूरे उत्तर-पूर्व के कुल लगभग 200 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय ने कई वरिष्ठ भारत-सरकार के अधिकारियों और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर व्यवसाय और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, डी आई पी पी, डी ओ एन ई आर और सी आई आई से प्रतिभागियों ने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के साथ-साथ प्रतिभागियों ने कहा कि इन उद्देश्यों को प्राथमिकता और समय-बद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाना बेहद जरूरी है।

दस सदस्यों वाले ताइवानी एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें संसद सदस्यों और सामरिक एवं राजनैतिक मुद्दों से जुड़े विज्ञान, विचारक और व्यापारी वर्ग के लोग शामिल थे ने 27 जुलाई से 3 अगस्त, 2008 तक नई दिल्ली, चेन्नै और कोचिन की यात्रा की। इस दौरे का उद्देश्य प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष आधुनिक भारत की छवि दर्शाना और सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की विभिन्न चिंताओं तथा हितों और साथ ही भारत में विद्यमान निवेश के अवसरों से रू-ब-रू करना था।

लोक राजनय प्रभाग के आमंत्रण पर मारिशस के 25 संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई में मारिशस संसद के उपाध्यक्ष ने 12-16 अक्तूबर, 2008 को भारत की यात्रा की। दिल्ली के अतिरिक्त प्रतिनिधिमण्डल ने मुम्बई का भी दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य आगन्तुक प्रतिनिधियों को भारत की व्यापक छवि से परिचित कराना और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चाएं कराना एवं स्थल दौरें कराना और हमारी चिंता से जुड़े मुद्दों पर उद्योग, विद्वानों, विचारकों, अधिकारियों और राजनैतिक नेताओं के साथ बैठकें करवाना था। प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल से भेंट की और विदेश मामले संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल को पर्यावरण में परिवर्तन पर भारत की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ता में चल रही रूकावटों पर भी चर्चा की गई। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी विस्तृत जानकारी दी गई और सी आई आई के सदस्यों से भी भेंटवार्ता कराई गई और पश्चिमी नौसेना कमान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा कराई गई।

यू.के. संसद से दो प्रतिनिधिमंडल "लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेन्डस ऑफ इण्डिया" और "कंजरवेटिव फ्रेन्डस ऑफ इण्डिया" ने क्रमशः सितम्बर और नवम्बर, 2008 अभिमुखी कार्यक्रम के लिए भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमण्डल ने राजनैतिक नेताओं से भेट की और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय आर्थिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा, भारतीय शांतिरक्षक बल पर जानकारी ली और साथ ही कुछ व्यापारिक उद्यमों और सामाजिक संस्थाओं कर भी दौरा किया।

सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी संसद सदस्यों के 10 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमण्डल ने 7-12 दिसम्बर, 2008 को एक अभिमुखी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। दिल्ली के अतिरिक्त इस प्रतिनिधिमण्डल ने आगरा और कोलकाता की भी यात्रा की। प्रतिनिधिमण्डल ने विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री (ए एस), प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्य मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमडल को केन्द्र-राज्य संबंधों, स्थानीय स्वशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी योजनाओं, भारतीय रक्षा बल, एड्स का सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही व्यापारियों और जादवपुर विश्विवद्यालय के फैकल्टी और छात्र-छात्राओं से वार्ता कराई गई ताकि प्रतिनिधिमण्डल को आधुनिक भारत की सही तस्वीर की जानकारी मिल सके।

जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए प्रभाग ने इन मुद्दों पर कई व्यापक पहुँच वाले कार्यकलाप आयोजित किये। सी आई आई के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन 21 अप्रैल, 2008 को मुम्बई में आयोजित किया गया जिसमें प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम शरण ने स्थिति पर पर्यावरण पर भारत की परिक्रम्य मूल सिद्धांत भाषण दिया ताकि कारपोरेट सैक्टर के बीच इस संबंध में जागरूपता बढ़े। इसके बाद 30 मई, 2008 को इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आई एस बी) में जलवायु परिवर्तन पर श्री श्याम शरण द्वारा एक और वार्ता की गई जिसमें श्री शरण ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के संबंध में चल रही मौजूदा बहस पर चर्चा की और जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना के मूल तत्वों के बारे में भी जानकारी दी। इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस की इस वार्ता में लगभग 150 छात्र-छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों और साथ ही प्रेस और कारपोरेट कार्यकारियों ने हिस्सा लिया।

विदेश नीति और राजनयिक विषयों पर छात्रवृति और लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभाग ने "दि अल्टीमेट प्राइजः ऑयल एण्ड सद्दाम्स इराक" नामक पुस्तक के विमोचन का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्रियों, विदेशी राजदूतों, राजनयिको, विचारकों और पत्रकारों सहित बड़ी संख्या में विद्वज्जनों की उपस्थिति में विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने पुस्तक का विमोचन किया। एक अन्य पुस्तक "ए लाइफ एक्रास थ्री कंटीनेण्टस्: रिकलेक्सन्स ऑफ ए डिप्लोमैट्स वाइफ" का विमोचन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरूशरण कौर द्वारा कई गण्यमान्य जनों की उपस्थिति में गया।

श्रव्य-दृश्य प्रचार

प्रभाग भारत की छवि को सकारात्मक ढंग से विदेशों में दर्शाने के उद्देश्य से बने वृत्तचित्रों को अधिकृत / क्रय करता है और उन्हें स्क्रीनिंग और विदेशी टीवी चैनेलों पर प्रसारण के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजता है। विदेशों में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सवों और भारतीय फिल्म सप्ताहों के लिए फीचर फिल्मों को खरीदना और उन्हें भेजना, सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार और प्रदर्शनियों का आयोजन इस प्रभाग द्वारा चलाए जाने वाले अन्य श्रव्य-दृश्य प्रचार-प्रसार कार्यकलाप हैं।

वर्ष के दौरान कई वृत्तचित्र पूरे किए गए। इनके नाम इस प्रकार हैः "सांग ऑफ सैंक्वुअरी; "कास्मोपोलिटन कल्वर ऑफ इण्डिया"; "इण्डिया इन्नोवेट्स"; "पाथेर पंचाली"; "ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ इण्डियन स्पाइसेस", "दि स्काई इज नाट दि लिमिट", "आन दि लाइफ ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान; "बैक टू गोण्डवाना लैण्ड", "बीटिंग रिट्रीट", "शिलांग चैम्बर कोइर", "काजी नजरूल इस्लाम", "क्रैडल बाइ दि स्ट्रीम", "पाथ ब्रेकर", "पाथ ब्रेकर-II", "डिस्मैण्टलिंग दि डिजिटल डिवाइड", "डज गाँधी मैटर", "इण्डिया एण्ड दि यू एन", "कॉमनवेलथ गेम्स- 2010- न्यू दिल्ली वेल्कम्स", "जम्मू एण्ड कश्मीर- क्वेस्टर फॉर लास्टिंग पीस", "रॉकिंग दि हिल्स", "स्टोरी ऑफ टैगोर्स गीतांजलि" और तीन भागों की वृत्तचित्र श्रृंखला" जम्मू एण्ड कश्मीर-फ्रॉम पीस टू प्रास्परिटी (क) वुमेन्स एम्पॉवरमेण्ट (ख) कश्मीरियत एण्ड स्राइन्स और (ग) यूथ एण्ड डेवलपमेंट।

मिशनों/केन्द्रों को पुस्तकालय और प्रस्तुतीकरण के प्रयोजनों के लिए बेटाकैम कैसेट, सीडी रोम, आडियो एवं वीडियो सीडी, डीवीडी और कैसेट के रूप में श्रव्य-दृश्य सामग्रियाँ भेजी जाती हैं। निम्नलिखित सीडी बालीवुडः 60 इयर्स ऑफ रोमाश, म्यूजिक एज थेरेपी और दि डि-स्ट्रेस श्रृंखालाएं खरीद कर मिशनों को भेजी गईं।

वर्ष के दौरान 18 वृत्तचित्रों अर्थात् कैन यू हियर मी, कॉमनवेल्थ गेम्स-2010 न्यू दिल्ली वेलकम्स, हीलिंग दि वर्ल्ड, माध्यम, इण्डिया एण्ड दि यू एन, उर्दू एण्ड मार्डन इण्डिया, थ्रू ए लेन्स क्लीयरिटी; रघु राय इण्डिया, दि सिटी ऑफ म्यूजिक, बियाण्ड ट्रेडिसन्स, मस्त कलंदर, इण्डियन इलैक्शन्स-ए मम्मथ डिमोक्रेटिक इक्सरसाइज, वाटरिंग दि ग्रास रूट्स, रिलीजियस लिंकेजेज बिटवीन भूटान एण्ड लद्दाख, को अधिकृत किए जाने की मंजूरी दी गई।

निम्नलिखित वृत्तचित्रों को भी विदेशी टीवी चैनलों और फिल्म महोत्सवों पर प्रसारित/स्क्रीन किया गयाः

- ब्रीटिंग रिट्रीट को 15 अगस्त, 2008 को न्यूयार्क के एक स्थानीय चैनल टीवी एशिया द्वारा प्रसारित किया गया।
- बोत्स्वाना दूरदर्शन द्वारा 17 अगस्त, 2008 को पाँच वृत्तचित्रों का प्रसारण किया गया जिनके नाम हैः बिस्मिल्लाह और बनारस, फूटस्टेप्स ऑफ निकिटिन, दि वननेस ऑफ क्रियेशन, रिविविंग इण्डिया एण्ड इण्डिया इन्फ्रास्ट्राक्चर-एन अपार्टुनिटी
- पाथेर पांचाली और फूटप्रिण्ट्रस ऑफ निकिटिन को अशगाबात में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में वृत्तचित्र और लघु फीचर फिल्म के लिए नामित/स्क्रीन किया गया। पाथेर पांचाली को इस समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।
- शिलांग चैम्बर कोइर को लिस्बन फिल्म महोत्सव में विशेष सराहना मिली।
- पाथेर पांचाली को नवम्बर, 2008 में लघु फिल्म केन्द्र गोवा द्वारा ऊपरी सूची में रखा गया।

मुद्रण प्रचार

इण्डिया परस्पेक्टिव मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण विभागीय पत्रिका है। इस पत्रिका में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों, कला, साहित्य, वन्य प्राणी, फिल्म/पुस्तक उद्योग, सचूना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा, स्वास्थ्य-चिकित्सा, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों जैसे अनेक विषयों को शामिल किया गया है। यह पत्रिका पूरे विश्व में भारत की प्रगति और विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक जानकारी का प्रचार-प्रसार करने का जरिया है। इसमें एक गूढ़-सांकेतिक तरीके से भारत की चिंताओं को भी जाहिर करने की इच्छा शामिल है। इस के साथ इटालियाई सम्पादन को इस वर्ष से जोड़े जाने के परिणाम स्वरूप यह पत्रिका अब 16 भाषाओं में प्रकाशित की जाने लगी है और भारत के भीतर और पूरे विश्व में वितरित की जा रही है। इण्डिया परस्पेक्टिव्स के अंकों को मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रजी में इलैक्ट्रिनिक फारमेट में भी देखा जा सकता है। अपने नए फारमेट और विषय सूची की दृष्टि से यह पत्रिका अपने जनवरी-मार्च 2008 के अंको से काफी ख्याति अर्जित कर चुकी है। सितम्बर-अक्तूबर 2008 का विशेष अंक भारत में पुस्तकों के प्रकाशन पर है जिसका विमोचन इसी वर्ष फ्रैंकफोर्ट पुस्तक मेले में किया

जाएगा। इस पत्रिका को विषय सूची के लिए 29 अक्तूबर, 2008 की फ्रैंकफोर्ट एलेजीमीन जीतंग में सराहा गया है। पत्रिका की 20वीं वर्षगांठ का अंक का विमोचन विदेश सचिव द्वारा 7 जनवरी, 2008 को किया जाएगा।

पुस्तकों और प्रकाशन के माध्यम से भारत को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना इस प्रभाग की विदेशों में प्रचार-प्रसार की रणनीति का अहम अंग है। 2008 में आयोजित दो पुस्तक विक्रय समितियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, कला और संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों की पुस्तकों का चयन किया गया जिन्हें विदेश स्थित मिशनों को प्रस्तुतिकरण एवं पुस्तकालयों में रखे जाने के लिए भेजा गया है। विदेश मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठयों/सम्मेलनों के लिए विदेश जाने वाले स्वदेश पधारे विद्वज्जनो/प्रतिनिधियों द्वारा/ को प्रस्तुतिकरण हेतु भी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी।

प्राइमरी स्तर की पाठ्य पुस्तकों के 100 सेट(प्रत्येक सेट में 25 पुस्तकें) ग्रीस में भारतीय संघों को प्रस्तुतिकरण हेतु भेजी गई थी। भारत-विद्या पर 90 पुस्तकें लाझू विश्वविद्यालय, गान्सू, चीन प्रस्तुतिकरण हेतु भेजी गई थी। इसी तरह भारत विद्या पर 36 पुस्तकें पुला विश्वविद्यालय, जागरे को प्रस्तुतिकरण हेतु भेजी गई थी और भारत विद्या पर 27 पुस्तकें मैड्रिड स्थित हमारे राजदूतावास को भेजी गई थी जिनका प्रस्तुतिकरण कासा डे ला इण्डिया कल्वर सेण्टर में किया जाना था। भारत- विद्या पर पुस्तकें सेण्टर फॉर ओरिएण्टल स्टडीज, विल्नियस विश्वविद्यालय, लिथुआनिया को भी प्रस्तुतिकरण हेतु भेजी गई थी।

भारतीय साहित्य और संस्कृति पर लगभग 300 पुस्तकें जिनमें तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तकें भी थी कोलम्बों स्थित भारतीय राजदूतावास भेजी गई थी जिन्हें सार्क देशों की ओर से आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में रखा जाना था। लोक राजनय प्रभाग ने हमारे ओमान स्थित राजदूतावास को लगभग 2000 पुस्तकें कालेजों, विश्वविद्यालयों और ओमान स्थित भारतीय स्कूलों के लिए जहां दो ओमानी विश्वविद्यालयों के पुस्ताकालयों में "भारतीय पुस्तकें" की खिड़की लगाई गई थी भी भेजी थी ।

लोक राजनय प्रभाग ने महात्मा गाँधी की आत्मकथा "सत्य के साथ मेरा प्रयोग" की 1000 प्रतियाँ स्पैनिश भाषा में 5100 अमरीकी डालर की लागत से एक स्थानीय प्रकाशक द्वारा मुद्रण हेतु बोगोटा स्थित भारतीय राजदूतावास के एक प्रस्ताव को वित्तपोषित किया। लोक राजनय प्रभाग ने बुल्गारियाई भाषा में "बाइबिल ऑफ ह्यूमनिज्म" शीर्षक से महात्मा गॉधी पर लिखी गई एक पुस्तक की 1000 प्रतियाँ प्रकाशित किए जाने हेतु इण्टरनेशनल अकादमी ऑफ बुल्गारियन स्टडीज, इन्नोवेसन एण्ड कल्वर और वर्न के यूनेस्को क्लब को वित्तीय सहयोग प्रदान किया। बुल्गारियाई भाषा में टैगोर की कविताओं का एक विशेष खण्ड प्रकाशित किये जाने हेतु भारतीय राजदूतावास, सोफिया के एक अन्य प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है।

भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोक राजनय प्रभाग ने विख्यात इजराइली लेखकद्वय प्रोफेसर डेविड सुलेमान और शेल्वा वील द्वारा रचित "कार्मिक पैसेजेजः इजराइली स्कॉलरशिप ऑफ इण्डिया" पुस्तक की 750 प्रतियाँ खरीदने के लिए तेल एविव स्थित भारतीय मिशन के एक प्रस्ताव को वित्तपोषित किया। एमेस्टरडेम-भारत महोत्सव के लिए भारत-डच संबंध पर एक विशेष खण्ड के प्रकाशन के लिए भारतीय राजदूतावास, दि हेग के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

लोक राजनय प्रभाग ने भारत के प्रधान कोंसलावास, डरबन के स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रयोगार्थ तेलगू भाषा में "शिक्षकों की नियमपुस्तक" तैयार किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव को वित्तपोषित किया। विभिन्न प्रकाशनों में, प्रभाग ने "विश्व का सामरिक स्वरूप" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित किया जो दिसम्बर, 2007 में नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्रालय आई आई एस एस विदेश नीति वार्ता की कार्यवाही का रिकार्ड है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें "मिलेनियम डेवलपमेण्ट गोल्सः इण्डिया कण्ट्री 2007" और "सार्क शिखर सम्मेलन 2008 में प्रधानमंत्री का भाषण" थीं।

■■

विदेश सेवा संस्थान 20

भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण

संस्थान एक मुख्य कार्यकलाप भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को दोनों विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों के साथ-साथ भारत में उनके पेशेवर कैरियर के दौरान अपेक्षित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए तैयार करना है।

विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम 15 जनवरी, 2008 को शुरू हुआ। इस पाठ्यक्रम में 21 देशों के 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

"आईएमएफ और विश्व बैंक का भविष्य" विषय पर शिकागो विश्व विद्यालय के प्रोफेसर व आईएमएफ के भूतपूर्व अर्थशास्त्री डा. रघुराम राजन ने 16 जनवरी को एफएसआई में भाषण दिया और "भारत व चीन की मृदु शक्ति" विषय पर एशिया सोसाइटी, न्यूयॉर्क के अध्यक्ष डा. विषाक देसाई ने 28 जनवरी को भाषण दिया।

2007 बैच के भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों को 2008 के पूरे वर्ष भर गहन एवं व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों के मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रक्षा तथा सुरक्षा, सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, सूचना का अधिकार और राजभाषा नीति इत्यादि। इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्थापना, लेखा, प्रोतोकॉल, संप्रेषण कौशल, प्रतिनिधित्व कौशल और मीडिया के साथ संबंध जैसे व्यवहारिक कौशल संबंधी मॉड्यूल भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम व्याख्यानों, वार्ता सत्रों के साथ-साथ विभिन्न प्रमुख संस्थानों के साथ संबद्ध करके कार्यान्विति किया गया। तदनुसार, भारत अफ्रीका भागीदारी मंच शिखर सम्मेलन, वायुसेना व थलसेना, मंत्रालय का सीमा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और वाणिज्य मंत्रालय इत्यादि से संबद्धता भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग थे। आईआईएम बैंगलूर में आर्थिक कूटनीति, प्रबंधन और नेतृत्व विषयों पर परिवीक्षार्थियों ने विशेषतौर पर उनके लिए संचालित तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी भाग लिया।

परिवीक्षार्थियों को भारत के भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक विविधता से सुपिरिचित कराने के लिए परिवीक्षार्थियों ने अपने भारत दर्शन यात्रा के एक भाग के रूप में नौ राज्यों का दौरा किया। भारत के निकटतम पड़ौसी के बारे में परिवीक्षार्थियों की जानकारी को संवर्धित करने और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यों से उन्हें परिचित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक सप्ताह के लिए अप्रैल, 2008 के महीने में ढाका, बंगलादेश के लिए मिशन अभिविन्यास दौरा भी शामिल था।

पुस्तकालय के सूची पत्र का कम्प्यूटरीकरण कर तथा अपेक्षित पुस्कालय सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाकर परिवीक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय सुविधाओं को उन्नत बनाया गया।

2008 बैच के भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों ने दिसम्बर, 2008 में संस्थान में प्रवेश लिया।

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों के प्रशिक्षण के अलावा विदेश सेवा संस्थान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित करता रहा है। इनमें सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक के लिए पांच आधारभूत पेशेवर पाठ्यक्रम (बीपीसी) और अनुभाग अधिकारियों के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शामिल थे। 2008 में एफएसआई ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय की सहायता से स्थानांतरण पर विदेश जाने वाले कर्मचारियों और अनुभाग अधिकारियों के लाभ के लिए एकीकृत मिशन लेखाकरण सॉफ्टवेयर (आईएमएएस) पर एक विस्तृत प्रशिक्षण माड्यूल शुरू किया। मंत्रालय के लगभग दो सौ कार्मिकों ने इन प्रशिक्षण मॉड्यूलों में भाग लिया।

अन्य मंत्रालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संबंधों का संवर्धन

भारतीय विदेश सेवा व अन्य सेवाओं के बीच संबंधों को और विकसित करने की दृष्टि से संस्थान ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विदेश सेवा संस्थान में मंत्रीमंडल सचिवालय के 32 वरिष्ठ तथा 12 कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल संचालित किए। फरवरी 2008 में विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय पुलिस सेवा और

भारतीय विदेश व्यापार सेवा के लिए तृतीय उर्धवाधर वार्ता पाठ्यक्रम भी आयोजिक की। इस पाठ्यक्रम में कौंसुली कार्य, विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, द्विपक्षीय संबंधों इत्यादि सहित अनेकों विषयों को शामिल किया गया।

राजनयिक संवाददाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग के सहयोग से अप्रैल/मई 2008 में राजनयिक संवाददाताओं के लिए छठा कार्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में भारत से आठ और विदेशों से नौ संवाददाताओं सहित कुल सत्रह राजनयिक संवाददाताओं ने भाग लिया।

विदेशी राजनयिकों के लिए कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान विश्वभर के देशों के साथ मैत्री के सेतु का निर्माण करने के अपने प्रयासों में विदेशी राजनयिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता रहा। विदेश सेवा संस्थान द्वारा 45वां और 46वां विदेशी राजनयिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) का क्रमशः 15 जनवरी-20 फरवरी और 5 नवंबर-15 दिसंबर 2008 तक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन दो पाठ्यक्रमों में से हर एक में विभिन्न देशों के 24 राजनयिकों ने भाग लिया।

संस्थान ने दो विशेष पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया, एक दक्षिणी सूडान के 15 राजनयिकों के लिए और दूसरा 24 आशियान राजनयिकों के लिए। विशेष पाठ्यक्रम और पीसीएफडी के दौरान विदेशी राजनयिकों को दिल्ली के आसपास के एतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक महत्व वाले विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने कोलकाता, गोवा, मुम्बई, हैदराबाद, केरल तथा बैंगलूर इत्यादि का भी दौरा किया।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 48वें पाठ्यक्रम में भाग ले रहे विदेशी रक्षा अधिकारियों ने 31 जुलाई, 2008 को विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया, और उनके लिए एक विशेष व्याख्यान का प्रबंध भी किया गया।

विदेश स्थित समकक्ष संस्थानों के साथ संपर्क

मार्च, 2008 में विदेश सेवा संस्थान तथा यूक्रेन के समकक्ष संस्थान के बीच सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मार्च, 2008 में बांग्लादेश विदेश सेवा अकादमी के उप-प्रधानाचार्य के नेतृत्व में बांग्लादेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल डीन (भा.वि.से.) से मिला।

अप्रैल, 2008 में रोमानियाई राजनयिक संस्थान, के महानिदेशक ने अक्तूबर 2006 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की परिधि के तहत दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को और गहराई और मजबूती प्रदान करने के लिए भा.वि.से. संस्थान का दौरा किया और डीन (भा.वि.से.) के साथ एक बैठक की।

इब्सा (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) देशों के राजनयिक संस्थानों के डीन की द्वितीय बैठक 15 सितंबर से 16 सितंबर, 2008 को भा.वि.से. संस्थान में हुइ। इस अवसर पर "भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका सहयोगः चुनौतियां और अवसर" विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

नवंबर, 2008 में चीन के विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल डीन (भा.वि.से.) से मिला।

10 जनवरी, 2009 को विदेश मंत्रालय द्वारा भा.वि.से. संस्थान में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) मुख्य अतिथि थे।

भा.वि.से. संस्थान ने नॉर्वे से आए राजनयिकों के लिए 19-21 जनवरी, 2009 तक एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

भा.वि.से. संस्थान द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए 47वें पेशेवर पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) का आयोजन 11 फरवरी से 23 मार्च, 2009 तक किया जाएगा।

जनवरी 2009 में भा.वि.से. संस्थान ने सहायकों/लिपिकों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (बीपीसी) का संचालन किया। अनुभाग अधिकारियों के लिए एक अन्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम फरवरी, 2009 में आयोजित किया गया है।

■■

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

21

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ स्थापित और सुदृढ करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 1950 में भारतीय सांस्कृतिक परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। जैसा कि संलग्न ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, इसके निम्न लिखित लक्ष्य हैं:

- भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में भागीदारी करना।
- दूसरे देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- अन्य देशों और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना।
- संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित और विकसित करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद ने निरंतर कार्य किया है।

परिषद के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

भारत सरकार और अन्य अभिकरणों की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कल्याण, भारतीय नृत्य एवं संगीत सीखने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं परिसंवादों का आयोजन एवं उनमें भाग लेना, विदेशों में मुख्य सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना, विदेशों में "भारत महोत्सव" का आयोजन करना, मंचीय कलाकारों के मंडलीयों का आदान-प्रदान, विदेशों में मंचीय कलाकारों द्वारा व्याख्यान-प्रदर्शन का आयोजन; विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विदेशों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और आगंतुकों का विदेश कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विदेशों में व्याख्यान देना, पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण करने, श्रव्य-दृश्य सामग्री, कला-वस्तुएं तथा संगीत यंत्र मुहैया कराने के लिए विशेषज्ञ भेजे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार हेतु सचिवालय उपलब्ध कराना, वार्षिक मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन करना, मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, भारत तथा विदेशों में वितरण के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को बनाए रखना, एक समृद्ध पुस्तकालय और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पांडुलिपियों का रख-रखाव, दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल बनाना।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 11 क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, पुणे और वाराणसी में कार्य कर रहे हैं। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शिलांग, कटक और गुवाहटी में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों में स्थानीय निकायों/संगठनों के साथ समन्वय और परिषद की छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों को सहायता प्रदान करना शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय आने और जाने सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों और परिषद के विशिष्ट आगुतंकों को संभारिकी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

परिषद की प्रमुख परियोजना, रविन्द्रनाथ टैगोर केन्द्र (आरटीसी) का उद्घाटन पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और भा.सा.स.प. के अध्यक्ष डा. करणसिंह की मौजूदगी में विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 1 जून, 2008 को किया गया। भवन में आधुनिकतम सुविधाएं हैं जैसे- बहुलकला दीर्घा, ऑडिटोरियम, सम्मेलन हॉल, पुस्तकालय, अतिथिकक्ष, कैफे, स्मारिका, दुकान इत्यादि। यह केन्द्र पूर्वी क्षेत्र में भा.सा.स. प. का आउटरिच ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में पड़ौसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, म्यानमां, और भूटान के साथ एक सेतु भी होगा।

परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ-बूझ को स्थापित, पुनर्जीवित तथा सुदृढ़ करना है। विदेशों में भारत की सामरिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद बीस सांस्कृतिक केन्द्रों का संचालन कर रहा है। ये काहिरा (मिस्र), बर्लिन (जर्मनी), पोर्टलुई (मॉरीशस), पारामारिबो (सूरीनाम), जॉर्जटाउन (गुयाना), जकार्ता (इंडोनेशिया), मॉस्को (रूसी संघ), लंदन (यूके) अलमाती (कजाखिस्तान), ताशकंद (उजवेकिस्तान), डरबन और जॉहंसवर्ग (दक्षिणी अफ्रीका), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबैगो), कोलंबो (श्रीलंका), दुशान्दे (ताजकिस्तान), क्वालालंपुर (मलेशिया), सुवा (फिजी), टोकियो (जापान), काठमांडु (नेपाल), काबुल (अफगानिस्तान) में स्थित हैं। बाली (इंडोनेशिया) और लोटोका (फिजी) में दो उप केन्द्र भी हैं। परिषद ढाका (बांग्लादेश) में संगीत एवं नृत्य अकादमी का वित्त पोषण भी कर रहा है और एक नया केंद्र खोलने के प्रस्ताव

पर विचार कर रहा है। परिषद विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में भारतीय अध्ययन पीठों का अनुरक्षण करता है। भारतीय प्रोफेसरों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर इन पीठों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। वर्तमान में परिषद द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजना और परिषद के अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत भारतीय भाषाओं एवं अन्य संबंधित विषयों के शिक्षण के लिए, विदेशों में बीस भारतीय अध्ययन पीठों का संचालन कर रहा है। ये पीठ पारामारिबो (सूरीनाम), बुडापेस्ट (हंगरी), मॉस्को (रूस), सियोल (दक्षिण कोरिया), वारसा (पोलैंड), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद एवं टोबैगो), सोफिया (बुल्गारिया), बुखारेस्ट (रोमानिया), बीजिंग (चीन), मैड्रिड (स्पेन), अंकारा (टर्की), बैंकाक (थाईलैंड), पेरिस (फ्रांस), ओस (क्रिगिस्तान), ताशकंद (उजबेकिस्तान), ब्रूसेल्स (बेल्जियम), डरबन (दक्षिण अफ्रीका) तथा जलालाबाद (अफगानिस्तान) में हिंदी, संस्कृत, तमिल, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता के क्षेत्र में है।

परिषद आठ आवर्ती अल्पकालिक पीठ भी चला रहा है, जो उलानबटा (मंगोलिया) में संस्कृत एवं बौद्ध अध्ययन, पेन्सिलवेनिया (यूएसए) में भारतीय साहित्य, जर्मनी के तीन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन, साइंसेस पो-पेरिस (फ्रांस) में भारतीय अर्थव्यवस्था, जोहांर्सवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) के विट्सवाटरसंड विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन तथा गुआंमहु (चीन) के सेनझेन विश्वविद्यालय में मानविकी के क्षेत्र में हैं।

विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं कल्याण

भा.सां.स.प. की महत्वूपर्ण गतिविधियों में से एक है विदेशी छात्रों को डॉक्टोरल, स्नातकोत्तर, अधोस्नातक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ इंजीनियरिंग, फार्मेशी, व्यवसाय प्रशासन और लेखा-शास्त्र जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र-वृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन। भा.सां.स.प.द्वारा प्रशासित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में इस समय लगभग 2200 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अप्रैल-नवंबर, 2008 के दौरान परिषद ने अफगानी छात्रों के लिए 500 छात्र वृत्तियों सहित 1868 नई छात्रवृत्तियां दी हैं ।

परिषद विदेशी छात्रों के लिए नियमित रूप से शिविर व अध्ययन दौरे आयोजित करता है।

अफगानिस्तान छात्रवृत्ति योजना से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनुभाग ने तीस अप्रैल 2008 को भा.सां.स.प., आजाद भवन में एक एक दिवसीय सम्मेलन का भी आयोजन किया। उच्चतर शिक्षा के अफगान मंत्री ने अपने मंत्रालय के तीन अधिकारियों के साथ सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने बैंगलूर और पुणे विश्वविद्यालयों का भी दौरा किया और वहां पढ़ रहे अफगान छात्रों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बात-चीत की।

क्षेत्रीय निदेशकों/अधिकारियों की बैठक

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विदेशी छात्रों के लिए किए जा रहे क्रियाकलापों की समीक्षा करने और विदेशी छात्रों के कल्याण से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उप-महानिदेशक ने 10 अप्रैल, 2008 को आजाद भवन, आईपी स्टेट, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की। मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुखों ने भी बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकारों की बैठक

भा.सां.स.प. द्वारा प्रायोजित विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, 11 अप्रैल, 2008 को आजाद भवन, आईपी स्टेट, नई दिल्ली में भा.सां.स.प. के अध्यक्ष डॉ. करणसिंह की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकारों की एक बैठक आयोजित की गई। 15 विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रतिनिधियों और भा.सां.स.प.के सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

अभिविन्यास कार्यक्रम

परिषद द्वारा भा.वि.से. के 2007 बैच के परिवीक्षार्थियों के लिए 28 अप्रैल से 2 मई 2008 तक एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके लिए व्याख्यानों/व्याख्यान सह प्रदर्शनों/संग्रहालयों दीर्घाओं और एतिहासिक स्थलों को देखना का भी प्रबंध किया गया है। विख्यात व्यक्तियों द्वारा भारतीय पारंपरिक एवं आधुनिक कला, संस्कृति तथा समकालीन भारतीय कला जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए गए।

अफ्रीकी मिशन प्रमुखों के साथ बैठक

भारत अफ्रीका का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों के राष्ट्रिकों के लिए मौजूद छात्रवृत्तियों को दुगना करने की घोषणा की थी, की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 21 अगस्त 2008 को आजाद भवन, आईपी स्टेट, नई दिल्ली में भा.सां.स.प. के महानिदेशक श्री पवन कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अफ्रीकी मिशन प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई।

अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन

भारत में विदेशी छात्रों के कल्याण से संबद्ध मुद्दों पर, 15 अप्रैल, 2008 को भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा बैठक बुलाए जाने के पश्चात भा.सां.स.प. के महानिदेशक अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालय समिति का गठन किया गया। समिति ने दिल्ली में चार बैठकें आयोजित की हैं। इस समिति ने विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं, एफआरओ/एफआरआरओ के प्रतिनिधियों, संबंधित राज्य सरकार के विभागों और विदेशी छात्रों से बातचीत करने के लिए पुणे, बैंगलूर, चेन्नै और हैदराबाद का क्षेत्रीय दौरा भी किया। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और उपर्युक्त पांच

शहरों में स्थित मुख्य विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं से भी फीडबैक मांगा गया। समिति ने 13 अक्तूबर 2008 को भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

परिषद, 18 दिसंबर, 2008 को सीरीफोर्ट सभागार, नई दिल्ली में XVI अंतर्राष्ट्रीय छात्र सांस्कृतिक महोत्सव भी आयोजित कर रहा है।

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

भा.सां.स.प. भारत वर्ष के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विदेशी मंचीय कलाकारों के भारत दौरे का आयोजन करता है। इन मंडलीयों की मेजबानी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत और साथ ही विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सिफारिशों और भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केंद्रों के अनुरोधों पर की जाती है। अप्रैल-नवंबर, 2008 की अवधि के दौरान परिषद ने पाकिस्तान, अल्जीरिया, मिस्र, इथोपिया, घाना, केन्या, लीबिया, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिणी अफ्रीका, तंजानिया, उगांडा, जांबिया, स्पेन, रूस, इरान, इजरायल, बांग्लादेश, उजबेकिस्तान, सीरिया, बोत्सवाना, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील, तजाकिस्तान, हंगरी, कोलंबिया, इटली, चीन, जापान, मोरक्को, फिलीस्तीन, कतर और यमन से 39 विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों के दौरों की मेजबानी की। परिषद ने 25 विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए, जैसे भारत में रह रहे विदेशी कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य, मल्हार उत्सव और श्रीनगर में सूफी संगीत उत्सव।

प्रकाशन

परिषद का अपनी एक उच्चाकांक्षी प्रकाशन कार्यक्रम है जिसमें वर्षों से वृद्धि हुई है। परिषद ने पांच अलग-अलग भाषाओं में छः पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं अर्थात "भारतीय क्षितिज" और "अफ्रीका त्रैमासिक" (दोनों अंग्रेजी त्रैमासिक), "गगनांचल" (हिंदी त्रैमासिक), "पेपेल्स-डी-ला-इंडिया" (स्पेनिश अर्द्धवार्षिक), रेनकांटरे अवेक ले इंडे (फ्रेंच अर्द्धवार्षिक) और "थकाफत-उल-हिंद" (अरबी त्रैमासिक)।

सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद ने विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों, मत निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सम्मेलन एवं संगोष्ठियों के आयोजन में सहयोग किया। इनमें निम्नलिखित शामिल थेः (क) 7-9 जुलाई, 2008 तक थामसट विश्वविद्यालय, बैंकॉक में "भारत थाई एतिहासिक व समकालीन सांस्कृतिक संबद्ध" विषय नाम से "भारत थाई एतिहासिक व समकालीन सांस्कृतिक संबद्ध" पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत और थाईलैंड से 18 छात्रों ने भाग लिया। (ख) 8-15 सितंबर 2008 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली और कोलकाता में भारत-इजराइल विद्वत संगोष्ठी इसमें भारत और इजराइल के प्रख्यात विद्वानों, फिल्मनिर्माताओं, पत्रकारों एवं लेखकों ने भाग लिया। परिषद ने कोलंबिया राजदूतावास के सहयोग से नई दिल्ली में इक्कीस से छब्बीस अक्तूबर 2008 तक एक कोलंबियाई सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया। परिषद ने भारत में चौदह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने में विभिन्न संगठनों/संस्थानों को भी सहयोग दिया।

अर्ध प्रतिमाएं एवं प्रदर्शनियां

भा.सां.स.प. ने केपटाउन (द.अफ्रीका) में लगाए जाने के लिए महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा भेजी। पांच बड़ी प्रदर्शनियां विदेशों में लगाई गईं जिनमें प्राग, अस्थाना, इडिनबरा और लंदन में "सेलेब्रेटिंग वीमैन-अमृता शेरगिल रिविजिटेड" नामक प्रदर्शनी, अल्जीरिया में "महिलाओं द्वारा महिलाएं" की प्रदर्शनी, नेपाल में "सार्कचित्र प्रदर्शनी", मिस्र में "भारत के भित्तिचित्र" प्राग में "गुड़िया और परिधान" पर प्रदर्शनियां शामिल थी।

परिषद ने विदेशों में अन्य विभिन्न प्रदर्शनियों को प्रायोजित किया, जैसे टैगोर केंद्र, बर्लिन, जर्मनी में सुश्री बेलासारथी द्वारा संयोजित स्व. श्री एस.एल. पराशर का एकल प्रदर्शन, सात भारतीय बंगाली कलाकारों द्वारा ढाका, बांग्ला देश में "रिटर्न टू रूट्स" प्रदर्शनी, विएना, आस्ट्रिया में सुश्री भारती कपाड़िया द्वारा एकल प्रदर्शनी, नेहरू केंद्र, लंदन में सुश्री रंजिता कांत द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी, हनोई, वियतनाम में सुश्री जी.एस. भवानी द्वारा चित्रकला व छाया चित्र प्रदर्शनी, लंदन में श्रीमती शोभा दीपक सिंह द्वारा फोटो प्रदर्शनी, श्रीमती गीता भट्ट, सुश्री मौसमी व श्रीमती गोवरी चंद्र शेखर द्वारा "चित्रकला" पर प्रदर्शनी व्याख्यान-प्रदर्शन सत्र, संयुक्त राज्य में सुश्री गौरी गिल द्वारा "दी अमेरिकन्स" पर छाया चित्र प्रदर्शनी, मस्कट में सुश्री नीलम धर द्वारा "एबस्ट्रेक्ट पेंटिंग्स" पर प्रदर्शनी, दक्षिण अफ्रीका में साझे इतिहास के साहित्य उत्सव हेतु "सत्याग्रह" प्रदर्शनी और मस्कट में सुश्री प्रभा शाह और सुश्री वंदना शौरी द्वारा "एबस्ट्रेक्ट पेंटिंग्स" पर प्रदर्शनी।

भा.सां.स.प. ने भारत में ईरानी संस्कृति दिवस मनाने के लिए छाया चित्र, लोक पहनावा, हस्तशिल्प और पुस्तकों की आने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन किया। परिषद और इरान इस्लामिक गणराज्य का राजदूतावास, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली और मुम्बई के सहयोग से आयोजित, अफगानिस्तान के साहित्य कलाकारों द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी, नई दिल्ली में सुश्री अंजोली इला मेनन द्वारा तैयार "कल्पना-प्रतिकात्मक भारतीय समकालीन चित्रकला की उत्कृष्ट कलाकृतियां" पर प्रदर्शनी, नई दिल्ली में आदित्य आर्य व सवीना द्वारा संयोजित कुलवंत राय की "दृश्य अभिलेख का निर्माणाधीन इतिहास" पर प्रदर्शनी, गैबरियल गैरसिया मारक्यूज पर चित्र प्रदर्शनी, "गैबो द राईटर" नई दिल्ली में

कोलंबिया का सांस्कृतिक सप्ताह आयोजित करने के लिए कोलंबिया के नोबल पुरस्कार विजेता चित्र प्रदर्शनी "डेज ऑफ ताजिक कल्चर इन न्यू दिल्ली"; तथा नई दिल्ली में दृश्य कलाकार सुश्री सादिया सईद की अध्यक्षता में प्रदर्शनी "लोस्ट सिटी"।

विदेश जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

इस अवधि के दौरान परिषद ने 3 नवंबर, 2008 तक 70 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित किया था तथा नवंबर, 2008 में विश्व के सभी महाद्वीपों में स्थित 72 देशों में प्रायोजित किए जाने के लिए 7 समूहों पर विचार किया जा रहा है।

परिषद ने सुश्री प्रेरणा शिमाली (कत्थक), सुश्री पदमिनी राय (लोकप्रिय संगीत), सुश्री प्रतिभा प्रहलाद (भरतनाट्यम), श्री प्रतीक चौधरी (सितार), सुश्री उमा शर्मा (कत्थक), सुश्री सरोज वैद्यनाथ (भरतनाट्यम), सुश्री रंजना गोहार (ओडिसी) तथा सुश्री अनिता सिंघवी (गजल) सहित अन्य कई स्थापित कलाकारों को प्रायोजित किया था।

परिषद ने बैंकाक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य तथा संगीत समारोह में भारत के शास्त्रीय नृत्यों की झलकियां प्रस्तुत करने के लिए उत्कृष्ट कलाकारों के संयुक्त नृत्य दल (सुश्री माधवी मुदगल का ओडिसी नृत्य दल, सुश्री चारु माथुर का मणिपुरी नृत्य दल, सुश्री गीता चंद्रन का भरतनाट्यम नृत्य दल, कत्थकली व कत्थक नृत्य दल के कत्थक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कत्थकली केंद्र के कत्थकली नृत्य दल) को 34 यात्रा अनुदान प्रदान किए थे। इसके अलावा परिषद ने डॉ. शानो खुराना (गायन), श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता (थियेटर), प्रो.सी.वी. चंद्रशेखर, गुरु वामपति चिन्ना सत्यम (कुचीपुड़ी), सुश्री रमा वैद्यनाथन जैसे कई उत्कृष्ट कलाकारों को भी यात्रा अनुदान प्रदान किया। परिषद ने पाकिस्तान के लिए एक थियेटर ग्रुप को 38 यात्रा अनुदान भी प्रदान किए।

परिषद ने जिन मुख्य समारोहों को समान समर्थन दिया है, उनमें तुर्की में इजमिर समारोह, सीरिया में अरब सांस्कृतिक समारोह, बोसनिया व हर्जेगोबिना में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव "डुकत", दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय कला उत्सव, ग्राहमस्टोन, इंडोनेशिया में बाली कला उत्सव, जर्मन में 7वीं गायन प्रतिस्पर्द्धा, यूनाइटेड किंगडम में थियेटर उत्सव (विश्व से संपर्क), इजराइल में कार्मिल उत्सव, श्री लंका में सार्क सांस्कृतिक उत्सव, यूएसए में फोकाना का 25 वर्षीय जयंती समारोह, हंगरी में गियोंगियस उत्सव, स्वीटजरलैंड में भारतीय ग्रीष्मकालीन उत्सव, यूएसए में 5वीं अक्का विश्व कन्नड़ सम्मेलन, बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, स्पेन में बार्सिलोना उत्सव, मैक्सिको में करवेनिटो उत्सव, हांगकांग में सीमांतर संगीत, जर्मन में डीआईजी श्रृंखलाबद्ध दौरा, जापान में नमस्ते भारत उत्सव, फ्रांस में त्यागराज उत्सव, कनाडा में वार्षिक संगीत उत्सव, म्यांमा में फिक्की महोत्सव, नाइजीरिया अबुजा महोत्सव, ग्याना, जमाइका, त्रिनिडाड व तोबेगो तथा सूरीनाम में भारतीय आगमन दिवस, पाकिस्तान में विश्व प्रस्तुतिकरण कला उत्सव तथा कनाडा में अपान उत्सव समारोह हैं। परिषद ने श्री लंका में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह, जन्माष्टमी समारोह व नवरात्रि समारोह, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व जिम्बाब्वे में दिवाली समारोह तथा गुरु ग्रंथ साहब का 300 वर्षीय आयोजन के लिए दलों को प्रायोजित किया।

भारत के उत्सव

भारत तथा अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों व आपसी सूझबूझ को सशक्त बनाने व उसका प्रचार करने के लिए अपने प्रयास के एक भाग के रूप में परिषद ने निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए थे।

सीरिया में भारतीय उत्सव

निम्नलिखित समूहों को उत्सव में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया था।

1) 10-18 अक्तूबर, 2008 को समांदर खान लांगा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय राजस्थानी दल। इस दल ने श्रृंखलाबद्ध दौरे के भाग के रूप में बेरुत की यात्रा भी की।

2) 10-17 अक्तूबर, 2008 को श्री दयाशंकर का 5 सदस्यीय शहनाई दल। इस दल ने प्रस्तुतिकरण के लिए बेरुत की यात्रा भी की।

3) 7 अक्तूबर, 2008 को श्री मेजर सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भागड़ा दल।

मिस्र में भारतीय संस्कृति के दिवस

निम्नलिखित दलों को उत्सव में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया था।

1) 27 अक्तूबर- 13 नवंबर, 2008 को गोवानी नृत्य का 12 सदस्यीय दल। दल ने प्रस्तुति कार्यक्रम के लिए इथोपिया व सूडान की यात्रा भी की, जिसका आयोजन भारत के संबंधित दूतावासों ने किया था।

2) 8-13 नवंबर, 2008 को डॉ. अनिल चौधरी का 6 सदस्यीय ताल वाद्य काचेरी दल।

3) 12 नवंबर, 2008 - 8 दिसंबर, 2008 को सुश्री राखी पूनम सपरा के नेतृत्व में 11 सदस्यीय राजस्थानी दल। दल ने भारत के संबंधित दूतावासों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में अर्जेंटिना व चिली की यात्रा भी की।

4) 10 नवंबर- 8 दिसंबर, 2008 को सुश्री मधुमिता राव व श्री शोविक चक्रवर्ती के नेतृत्व में 6सदस्यीय कत्थक नृत्य दल। इस दल ने हमारे संबंधित मिशनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण के लिए इटली, अर्जेंटीना व चिली की यात्रा भी की।

नीदरलैंड में एमस्टर्डम- भारत उत्सव

परिषद ने कंसर्टजीवाओ के समन्वय से नीदरलैंड में सबसे बड़ा भारतीय उत्सव आयोजित किया। आईसीसीआर के माननीय अध्यक्ष डॉ. करन सिंह ने उद्घाटन समारोह के लिए नीदरलैंड की यात्रा की। नीचे लिखे मंचीय कला दलों ने इस उत्सव में भाग लिया।

1) 19-24 नवंबर, 2008 को श्री अनूप जलोटा का 7 सदस्यीय भजन दल।

2) 7-25 नवंबर, 2008 को पं. बिरजू महाराज का 14 सदस्यीय कत्थक दल। इस दल ने संबंधित भारतीय दूतावासों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए जर्मन, हंगरी व पोलैंड की यात्रा भी की।

3) 18-24 नवंबर, 2008 को श्री संजय सुब्रामण्यम का 5 सदस्यीय कर्नाटक गायन दल। इस दल ने भारत के संबंधित मिशनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए इटली व स्पेन की यात्रा भी की।

4) 10-15 नवंबर, 2008 को श्री अश्विनी भिड़े का 4 सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन दल। इस दल ने इटली की यात्रा भी की। रोम में भारतीय दूतावास द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5) 16-28 नवंबर, 2008 को नृत्यगान का 10 सदस्यीय ओडिसी दल। इस दल ने रोम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए इटली की यात्रा भी की।

6) 11-18 नवंबर, 2008 को 14 सदस्यीय कत्थकली दल। इस दल ने मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित प्रस्तुतिकरण में भाग लेने के लिए स्पेन की यात्रा की।

हंगरी में भारतीय उत्सव

परिषद ने 28 नवंबर, 2008 से 6 दिसंबर, 2008 को आयोजित उत्सव में भाग लेने के लिए हंगरी में श्री आला भैय्या के 10 सदस्यीय राजस्थानी दल को प्रायोजित किया।

भूटान में राज्याभिषेक समारोह, 3-9 नवंबर, 2008 को अस्ताद देवू के नेतृत्व में 38 सदस्यीय समकालीन नृत्य दल को राजा के राज्याभिषेक समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए भूटान भेजा गया था।

विदेश जाने वाले यात्रियों के कार्यक्रम

परिषद ने भारतीय बुद्धिजीवियों, विद्वानों, शिक्षाविदों व कलाकारों की विदेशों में आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों, अध्ययन दौरों, संगोष्ठियों में सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी यात्राओं को प्रायोजित किया।

अप्रैल, 2008 से नवंबर, 2008 की अवधि के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में 82 प्रतिष्ठित विद्वानों की यात्राओं को प्रायोजित किया।

प्रतिष्ठित यात्री कार्यक्रम

भारत तथा अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंध व आपसी सूझबूझ बढ़ाने के प्रयासों के रूप में परिषद ने अपने प्रतिष्ठित यात्रा कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य देशों से सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों तथा कलाकारों की भारत यात्रा को प्रायोजित किया। इस अवधि के दौरान परिषद ने चीन, जर्मन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, बहरीन, तजाकिस्तान, रूस व 9 यूरोपीय देशों से 10 प्रतिष्ठित यात्रियों की मेजबानी की।

पुरस्कार

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति हुसने मुबारक को वर्ष 1995 के दौरान 18 नवंबर, 2008 को आयोजित विशेष समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया।

■■

22 भारतीय विश्व कार्य परिषद

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया:-

i)	व्याख्यान	07
ii)	संगोष्ठियां/सम्मेलन	09
iii)	द्विपक्षीय वार्ताएं	06
iv)	पृष्ठभूमि टिप्पणी, पुस्तक विमोचन/ पैनल विचार-विमर्श तथा अन्य कार्यक्रम	14
	कुल योग	36

इन कार्यक्रमों में बहुत अच्छी उपस्थिति रही। उपरोक्त कार्यक्रमों की एक सूची संलग्न है।

इस अवधि के दौरान आईसीडब्ल्यूए ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय सहयोग के छः समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:-

1. अफगानिस्तान के विदेश कार्य मंत्रालय का सामरिक अध्ययन केंद्र (सीएसएस)।
2. न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान (एनआईआईए), वेलिंगटन।
3. आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान (एआईआईए), मेलबोर्न।

परिषद ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विदेशी अतिथियों की मेजबानी की।

(1) स्विस संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष महामहिम श्री क्रिस्टोफेल ब्रेंडली- 13 अगस्त, 2008

(2) जनवादी गणराज्य चीन के विदेश कार्य मंत्री श्री यांग जिची- 9 सितंबर, 2008

(3) आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य मंत्री श्री स्टीफन स्मिथ- 11 सितंबर, 2008

(4) कोलोन के लॉर्ड मेयर श्री फ्रिट्ज सक्रमा- 17 नवंबर, 2008

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने भारत-मध्य एशिया फाउंडेशन (आईसीएएफ), आईसीडब्ल्यूए तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग, अलफराबी कजाख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अल्माटी, कजाखस्तान के बीच "राजनीतिक आधिनुकीकरण की समकालीन प्रक्रिया: मध्य एशियाई राज्यों व भारत के अनुभव" के संबंध में एक संयुक्त अध्ययन प्रायोजित किया।

आईसीडब्ल्यूए के अनुसंधान अध्येताओं ने संगोष्ठियों में नियमित रूप से भाग लिया तथा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में व्याख्यान/शोधपत्र का योगदान दिया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईसीडब्ल्यूए की पत्रिका "इंडिया क्वार्टरली" का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया। इस अवधि के दौरान "इंडिया क्वार्टरली" के चार संस्करण अर्थात् जनवरी-मार्च 2008, अप्रैल-जून 2008, जुलाई- सितंबर 2008, अक्तूबर-दिसंबर, 2008 का प्रकाशन किया गया।

अप्रैल 2008 से नवंबर, 2008 तक सीएससीएपी से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. 2-3 अप्रैल, 2008 को सियोल में "एशिया प्रशांत में समुद्री सुरक्षा सहयोग की सुविधा" के संबंध में सीएससीएपी एसजीएम का आयोजन।
2. 26-27 मई, 2008 के दौरान वियतनाम के हो-चि-मिन शहर में आयोजित एशिया प्रशांत में जनसंहार व शस्त्र प्रसार के विरोध के संबंध में सीएससीएपी एसजीएम।
3. 2 जून, 2008 को कुआलालम्पुर में आयोजित 29वां एससीएम।
4. 2-5 मई, 2008 को कुआलालम्पुर में आयोजित 22वीं एशिया प्रशांत गोलमेज बैठक।
5. 8-9 जुलाई, 2008 को ब्रूनेई में आयोजित ऊर्जा सुरक्षा की चौथी बैठक।
6. 24-26 अगस्त, 2008 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित निर्यात नियंत्रण विशेषज्ञ समूह सीएससीएपी एसजीएम।
7. 13-15 नवंबर, 2008 को बीजिंग, चीन में आयोजित एआरएफ विशेषज्ञों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों (ईईपीएस)की तीसरी बैठक।

पुस्तकालय के परिवेश में सुधार हुआ है तथा इसकी सदस्यता में वृद्धि हो रही है। विगत वर्ष सदस्यों की संख्या 289 थी, जो कि इस वर्ष बढ़कर 602 हो गयी है। पुस्तकालय के माहौल व

उसकी बनावट में काफी सुधार हुआ है, जिससे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तीन मूर्ति सचिवालय तथा अन्य प्रतिष्ठित पुस्तकालयों से दैनिक आधार पर संदर्भगत पूछताछ की जा रही है। प्रतिष्ठित समाचारपत्रों के मुख्य संवाददाता जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्कालय के दौरे करते रहे हैं। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य, पूर्व व पश्चिम एशिया से संबंधित विदेशी नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर 600 पुस्तकें पुस्तकालय में शामिल की गयी हैं। भारत के प्रतिष्ठित संस्थाओं व विश्वविद्यालयों से लगभग 250 शोध छात्रों ने इस पुस्तकालय की सदस्यता ली तथा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं व समाचार पत्रों की कतरनों का उपयोग किया। प्रमुख सरकारी अधिकारियों ने पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग किया तथा उसकी सराहना की है। विभिन्न प्रणालियों को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं।

आईसीडब्ल्यूए उपरोक्त अवधि में भारत में विदेशी मामलों के विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच तथा एक विचार केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

■■

23 विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

पर्यावलोकन

आरआईएस ने एक स्वायत्त नीति विचार केंद्र के रूप में अन्य कार्यों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों से संबंधित नीतिगत अनुसंधान तथा विभिन्न देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहभागिता के लिए संयुक्त अध्ययन समूह सीईपीईए के ट्रेक-II अध्ययन समूह, विश्व व्यापार वार्ता, सार्क व बिम्सटैक सम्मेलन, आईबीएसए सम्मेलन व पूर्व एशिया सम्मेलन जैसी कई महत्वपूर्ण वार्ताओं के लिए व मुख्य सम्मेलन बैठकों की तैयारी के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की है। इसने एशिया में अग्रणी नीतिगत विचार-केंद्रों के सहयोग से एशियाई आर्थिक समुदाय के लिए प्रासंगिक तथा प्रगतिशील नीतिगत वार्ता आयोजित करना जारी रखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों व विकासात्मक सहयोग के संबंध में नीतिगत समरूपता लाने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों के नीति विचारक केंद्रों के साथ अपना नेटवर्क जोड़ा है।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान व सूचना प्रणाली (आरआईएस)

आईआईएस नई दिल्ली में स्थापित एक विचार केंद्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विकासात्मक सहयोग में विशेषज्ञता प्राप्त है। आरआईएस विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसे समय-समय पर सौंपे जाने वाली क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय सहयोग व्यवस्था सहित बहुपक्षीय आर्थिक व सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर भारत सरकार के एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। आरआईएस को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के विचार केंद्रों में प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान आरआईएस के कार्यों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:

सरकार को अनुसंधान व नीतिगत निविष्टियां प्रदान करना

आरआईएस ने वर्ष के दौरान आयोजित ट्रेक-II पहल के अलावा मुख्य सम्मेलन बैठकों व अन्य वार्ताओं की तैयारी व नीति निर्माण में सहायता के लिए अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए हैं। इन निविष्टियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सार्क सम्मेलनः आरआईएस ने दक्षिण एशिया विकास व सहयोग रिपोर्ट 2008 प्रकाशित की, जो कि विदेश मंत्री ने कोलंबो सार्क सम्मेलन के अवसर पर जारी की तथा सभी सार्क देशों के प्रतिनिधिमंडलों को प्रदान की।
- बिम्सटेक सम्मेलनः आरआईएस ने बिम्सटेक सम्मेलन की कार्यसूची; पश्चिम बंगाल में घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर एक नीतिगत विवरण तैयार किया, जो कि नवंबर, 2008 में दूसरे बिम्सटेक सम्मेलन के सहयोग से शीर्ष चैंबर द्वारा आयोजित बिम्सटेक व्यापार सम्मेलन 2008 में जारी किया गया व प्रस्तुत किया गया। आरआईएस ने बिम्सटेक आर्थिक सहयोग के संबंध में विदेश मंत्रालय को निविष्टियां भी प्रदान कीं।
- पूर्व एशियाई सम्मेलन व भारत-आसियान सम्मेलनः आरआईएस आसियान व पूर्व एशिया (ईआरआईए) के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान तथा पूर्व एशिया की व्यापक आर्थिक सहभागिता से संबंधित ट्रेक-II अध्ययन समूह नामक पूर्व एशिया सम्मेलन से उत्पन्न दो ट्रेक-II प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। आरआईएस, ईआरआईईए विशेषज्ञ समूह तथा क्षेत्रीय अनुसंधान नेटवर्क में देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसने विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों में योगदान दिया है तथा पूर्व एशिया में ढांचागत विकास के संबंध में क्षेत्रीय अध्ययन को समन्वित किया है। इसने रिपोर्ट के प्रारूप में योगदान देने के अलावा फरवरी, 2008 में नई दिल्ली में सीईपीईए अध्ययन समूह की एक बैठक की मेजबानी की। प्रथम चरण की रिपोर्ट पूरी कर ली गयी थी तथा सिंगापुर में अगस्त, 2008 में ईएएस के आर्थिक मंत्रियों को प्रस्तुत कर दी गयी थी, जिसमें समूह को अपना कार्य जारी रखने तथा और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने 2009 के प्रारंभ में थाईलैंड में आयोजित किए जाने वाले ईएएस के चौथे सत्र की तैयारी में एशिया में चैंग माई पहल व वित्तीय सहयोग जैसी कई निविष्टियां प्रदान की थीं। 13वें आसियान-भारत कार्य समूह, 10वें आसियान-भारत जेसीसी तथा 10वें आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के लिए भी निविष्टियां प्रदान की गयी थी। वाणिज्य विभाग तथा प्रधान मंत्री के विदेश दूत को भी एशिया में उभरती क्षेत्रीय संरचना से संबंधित कुछ निविष्टयां प्रदान की गयी थीं।
- मैकांग-गंगा सहयोगः मैकांग उपक्षेत्र के साथ भारत के

हवाई संपर्क पर एक मूल्यांकन टिप्पणी विदेश मंत्रालय को उपलब्ध कारवाई की गयी थी। आरआईएस ने विदेश मंत्रालय को भारत-एमजीसी सहभागिता के संबंध में एक और विस्तृत टिप्पणी भी प्रदान की थी।

- तीसरा आईबीएसए सम्मेलनः आरआईएस ने तीसरे आईबीएसए सम्मेलन में आईबीएसए शैक्षणिक मंच को समन्वित किया था, जिसमें तीन आईबीएसए देशों से वरिष्ठ शिक्षाविदों ने भाग लिया था। शैक्षणिक मंच ने आईबीएसए शैक्षणिक मंच के भावी कार्यकलापों पर विचार-विमर्श करने के अलावा आईबीएसए की संभावित सहभागिता तथा वित्तीय संकट, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। डीजी-आरआईएस ने आईबीएसए के नेताओं को सम्मेलन में मंच की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आरआईएस ने मंच की रिपोर्ट प्रकाशित की है। आरआईएस ने आईबीएसए सम्मेलन की तैयारी के लिए सरकार को ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा से संबंधित निविष्टियां भी प्रदान की हैं।

- भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलनः आरआईएस ने आईसीडब्ल्यूए के सहयोग से भारत सरकार की मेजबानी में भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन की तैयारी की प्रक्रिया के अवसर पर भारत-अफ्रीका आर्थिक सहभागिता से संबंधित सम्मेलन आयोजित किया। इन विषयों पर अफ्रीकी विशेषज्ञों व अन्य भारतीय विशेषज्ञों के अलावा आरआईएस द्वारा तैयार कई अध्ययन रिपोर्टें सम्मेलन में प्रस्तुत की गयी।

- विश्व व्यापार संगठन दोहा दौरः आरआईएस ने व्यापार वार्ता के चालू दोहा दौर के संबंध में एक वार्ता दस्तावेज व नीतिगत टिप्पणी प्रकाशित की है। आरआईएस ने जुलाई, 2008 में मंत्रालयीय सम्मेलन के परिणामों पर एक वार्ता बैठक की मेजबानी भी की है।

- एशियाई सहयोग वार्ताः आरआईएस ने एसीडी के भावी निर्देशों पर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का प्रतिनिधित्व किया है। इसने ट्रेक-II सहभागिता के तौर-तरीकों व इसके भविष्य पर एक अवधारणा दस्तावेज तैयार किया है तथा इसकी बैठकों में भाग लिया है।

- आईओआर-एआरसी शैक्षणिक समूह (आईओआर-एजी)ः आरआईएस ने आईओआर-एजी के कार्यकलापों को समन्वित किया है तथा 2008 को तेहरान में मंत्रालयीय बैठक में आयोजित समूह की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

- इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड व आस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करारों के लिए संयुक्त अध्ययन समूहः आरआईएस ने संबंधित देशों के समकक्षों सहित सरकार द्वारा स्थापित 3 संयुक्त अध्ययन समूहों में प्रतिनिधित्व किया है। आरआईएस ने उनकी बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया तथा दोनों देशों के मध्य निर्धारित कार्य वितरण के अनुसार रिपोर्टों के प्रारूप तैयार करने में योगदान दिया।

- अन्य नीतिगत कागजात व निविष्टियांः आरआईएस ने वर्ष के दौरान भारत सरकार को कई नीतिगत निविष्टियां व टिप्पणियां प्रदान कीं, जिनमें यूरोप के आर्थिक एकीकरण से सीखे गए सबक तथा इसके परिणामस्वरूप एशिया पर प्रभाव से संबंधित टिप्पणी, ब्रेटन बुड्स संस्थानों में यूएन-ईसीओएसओसी की उच्चस्तरीय बैठकों के लिए निविष्टियां तथा आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) के लिए विश्व व्यापार संगठन व यूएनसीटीएडी; उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए एफडीआई नीति से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों पर टिप्पणी, मंत्रिमंडल सचिव के लिए ढांचागत निवेश से संबंधित क्षेत्रीय संरचना पर निविष्टियां शामिल हैं।

नीतिगत वार्ता, सम्मेलन व संगोष्ठियां

2008/09 के दौरान आरआईएस ने विकासशील देशों के मध्य बुद्धिजीवी वार्ता का प्रसार करने के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कई नीतिगत वार्ताएं सम्मेलन व संगोष्ठियां आयोजित की हैं। इस अवधि के दौरान आयोजित कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

वित्तीय संकट, विश्वव्यापी आर्थिक प्रशासन व विकास से संबंधित उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एशिया व दक्षिण विश्व की प्रतिक्रिया, 6-7 फरवरी, 2009ः आरआईएस के रजत जंयती समारोह शुरू करने के लिए 6-7 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में वित्तीय संकट, विश्वव्यापी आर्थिक प्रशासन व विकास से संबंधित उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एशिया व दक्षिण विश्व की प्रतिक्रिया के संबंध में एक उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आरआईएस के कार्यों की मुख्य विषयवस्तुओं को सम्मिलित किया गया। यह सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसईएएस), सिंगापुर; आसियान व पूर्व एशिया (ईआरआईए), इंडोनेशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान; टफ्स विश्वविद्यालय, मैडफोर्ड, यूएसए में विश्वस्तरीय विकास व पर्यावरण संस्थान, सेंट्रो डी इंवेटीगेशियंस पैरा ला ट्रांसफोरमेशियंस, (सीईएनआईटी), ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना, राष्ट्रीय मंडल सचिवालय, यूके, एशियाई विकास बैंक, मनीला; सासाकावा पीस फाउंडेशन तथा फोर्ड फाउंडेशन, यूएसए के सहयोग से आयोजित किया गया था। उच्चस्तरीय सम्मेलन में पूरे विश्व के नीति विचार केंद्रों से वरिष्ठ विशेषज्ञों अथवा अध्यक्षों तथा उन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों को एक साथ लाया गया, जिनमें आरआईएस ने संस्थागत नेटवर्क संपर्क स्थापित किए हैं। इसमें भारत के बाहरी देशों से 35 संस्थानों तथा देश के भीतर अनेक संस्थानों ने प्रतिनिधित्व किया।

माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी तथा वित्त मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष महामहिम श्री हुरुहिको कुरुदा ने उद्घाटन सत्र में मूल व्याख्यान दिया, जिसकी अध्यक्षता आरआईएस के अध्यक्ष व संसद सदस्य डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता ने की थी। राष्ट्रमंडल के महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने 6 फरवरी को रात्रि भोज संबोधन किया। सार्क महासचिव डॉ. शीलकांत शर्मा ने 7 फरवरी को एक मूल व्याख्यान दिया तथा विदेश मंत्रालय के सचिव, राजदूत एच.एस. पुरी ने सत्र का विदाई भाषण दिया, जिसकी अध्यक्षता आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत लीला पोनाप्पा ने की।

सम्मेलन की रिपोर्ट आरआईएस के पोलिसी ब्रीफ41 के रूप में जारी की गयी। सम्मेलन के दस्तावेज www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

तीसरा आईबीएसए सम्मेलन शैक्षिक मंच- साझा समृद्धि तथा व्यापक वैश्वीकरण के लिए आईबीएसए सहभागिताः आईबीएसए सम्मेलन के भाग के रूप में आरआईएस ने विकासशील देशों के सामने आने वाली नीतिगत चुनौतियों तथा विकास के समकालिक मुद्दे उठाने तथा उन पर विचार करने के लिए 13-14 अक्तूबर, 2008 को उच्चस्तरीय शैक्षिक मंच समन्वित किया। शैक्षिक मंच में विकास की साझा चिंताओं व पारस्परिक हितों की विषयवस्तुओं पर विचार-विमर्श के लिए 3 देशों के वरिष्ठ शिक्षाविदों व अग्रणी विचार केंद्रों के विशेषज्ञों तथा सभ्य समाज के अन्य सदस्यों इकट्ठा किया गया। माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन भाषण दिया। मंच की रिपोर्ट तीसरे आईबीएसए सम्मेलन में प्रस्तुत की गयी।

दक्षिण एशिया के बढ़ते आर्थिक एकीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलनः आरआईएस ने भारतीय वाणिज्य व उद्योग चैंबर (फिक्की) तथा सार्क चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एससीसीआई) के सहयोग से दक्षिण एशिया में बढ़ते आर्थिक एकीकरण पर 24 जुलाई, 2008 एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, ताकि कोलंबो सम्मेलन के लिए एक मंच स्थापित किया जा सके। माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा आरआईएस का प्रकाशन, दक्षिण एशिया विकास व सहयोग रिपोर्ट 2008 जारी किया। माननीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने विदाई भाषण दिया। सार्क के अन्य देशों के कुछ मुख्य सहभागियों में सार्क महासचिव डॉ. शीलकांत शर्मा, बांग्लादेश के भूतपूर्व विदेश कार्य मंत्री डॉ. कमल हुसैन, श्री लंका के राष्ट्रपति के सलाहकार श्री निहाल रोड्रिगो, नीतिगत अध्ययन संस्थान श्रीलंका के कार्यपालन निदेशक डॉ. सामन केलिगमा, नेपाल के भूतपूर्व विदेश कार्य मंत्री डॉ. वेग बहादुर थापा, एससीसीआई के अध्यक्ष श्री तारिख सईद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आरएनडी समिति) के अध्यक्ष श्री सुल्तान चावला शामिल हैं।

21वीं शताब्दी में अफ्रीका-भारत सहभागिता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः आरआईएस ने भारतीय विश्व कार्य परिषद के साथ संयुक्त रूप से तथा भारत की अफ्रीकी अध्ययन संस्था के सहयोग से भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के पूर्व आयोजन के रूप में 2-3 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में 21वीं शताब्दी में अफ्रीका-भारत सहभागिता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। भारत व अफ्रीकी शिक्षाविदों तथा विचार केंद्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री नलिन सूरी ने उद्घाटन भाषण दिया। माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने विदाई भाषण दिया। नई दिल्ली में मोजांबिक के राजदूत महामहिम श्री कारलोस अगस्तिनो डू रोजाइरो तथा अफ्रीकी डिप्लोमेटिक कोर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

दक्षिणी आम सहमति के लिए- 21वीं शताब्दी में व्यापार व विकास नीति से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के लोकमंच का सत्रः आरआईएस ने टफ्स विश्वविद्यालय, मैडफोर्ड, यूएसए में विश्वव्यापी विकास व पर्यावरण संस्थान तथा आर्थिक परिवर्तन के लिए अनुसंधान केंद्र, अर्जेंटिना के साथ संयुक्त रूप से 25 सितंबर, 2008 को जिनेवा में दक्षिणी आम सहमति के लिए- 21वीं शताब्दी में व्यापार व विकास नीति से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के लोकमंच का सत्र आयोजित किया। पैनल के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष श्री फैजल इस्माइल तथा जीडीएई के डॉ. केविन गालागर; आईआरईएनई के डॉ. सिफाइदीन, यूनिवर्साइट डी न्यू चेटल स्वीटजरलैंड तथा डीजीआरआईए, डॉ. नागेश कुमार शामिल हैं।

उभरते एशियाई क्षेत्रवाद पर सम्मेलनः आसियान-इंडिया एफटीए तथा आगेः आरआईएस ने एशियाई विकास बैंक, मनीला के साथ संयुक्त रूप से 19 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में उभरते एशियाई क्षेत्रवाद पर सम्मेलनः आसियान-इंडिया एफटीए तथा उसके आगे विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया। राज्य मंत्री डॉ.जयराम रमेश ने उद्घाटन भाषण दिया था। मुख्य वक्ताओं में एडीबी संस्थान, टोक्यो के डीन शामिल थे।

भारत-आसियान आर्थिक सहयोगः व्यापार व निवेश के अवसर विषय पर सम्मेलन, 24 नवंबर, 2008ः आईआरएस ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 24 नवंबर, 2008, सोमवार को नई दिल्ली में भारत-आसियान आर्थिक सहयोगः व्यापार व निवेश के अवसर विषय पर सम्मेलन आयोजित किया था। भारत तथा आसियान पक्ष की ओर से विभिन्न विशेषज्ञों ने हाल ही में संपन्न भारतीय-आसियान एफटीए के विभिन्न पहलुओं पर कई प्रस्तुतियां दीं।

रजत जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यान- 24 मार्च, 2009ः आरआईएस की स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आरआईएस ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। नीदरलैंड के भूतपूर्व खनिज विकास मंत्री तथा वैश्वीकरण, सतत् विकास व संघर्ष पर अग्रणी

विकास विचारक प्रो. जैन प्रोंक ने 24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में प्रथम रजत जयंती प्रतिष्ठित व्यक्ति भाषण दिया। आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तथा सीएसडी के अध्यक्ष प्रो. मुचकुंद दुबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। आरआईएस के अध्यक्ष डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता ने उद्घाटन टिप्पणी की थी। आरआईएस के महानिदेशक डॉ. नागेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आरआईएस/एनएआरसी/यूनेस्कोः प्रौद्योगिकी एवं विकास पर चौथा एशियाई सम्मेलन, 12-13 फरवरी, 2009ः आरआईएस ने नेपाल की कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से 12-13 फरवरी, 2009 को आरआईएस/एनएआरसी/यूनेस्कोः प्रौद्योगिकी एवं विकास पर चौथा एशियाई सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का समर्थन यूनेस्को ने किया था।

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में सचिव श्री टेक बहादुर थापा ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। आईआईएस के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया था। नेपाल सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जयप्रकाश पी. गुप्ता ने उद्घाटन भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष प्रो. गोबिन्दन प्रायल तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जापान के निदेशक ने मूल भाषण दिया। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, काठमांडू के कार्यपालक निदेशक ने धन्यवाद मद प्रस्तुत किया था। 19 देशों से 90 सहभागियों तथा 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारत की ओर से जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में सलाहकार डॉ. एस. आर. राव तथा आरआईएस के एसोशिएट फेलो डॉ. के. रवि श्रीनिवास ने हिस्सा लिया।

यह सम्मेलन संयुक्त रूप से यह पता लगाने का एक प्रयास है कि एशिया व अन्य विकासशील देश अपने प्रौद्योगिकीय तथा अनुसंधान व विकास निवेशों से किस प्रकार इष्टतम प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यह यूनेस्को के सहयोग से तथा कई अन्य राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता से शुरू आरआईएस पहल का एक हिस्सा है। इस सम्मेलन की रिपोर्ट आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण पर प्रथम दक्षिण-एशियाई आर्थिक सम्मेलनः दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण पर प्रथम दक्षिण-एशियाई आर्थिक सम्मेलनः साफ्टा व उसके आगे का आयोजन 28-30 अगस्त, 2008 को कोलंबो में किया गया। अन्य संगठनों के साथ आरआईएस भारत के सहयोग से श्री लंका के फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा श्री लंका के नीतिगत अध्ययन संस्थान ने इस सम्मेलन को आयोजित किया। श्री लंका में भारत के उच्चायुक्त श्री आलोक प्रसाद ने इस सम्मेलन में आरआईएस की दक्षिण एशिया विकास व सहयोग रिपोर्ट 2008 जारी की थी।

राष्ट्रीय जैव सुरक्षा नियम तथा कार्ट जेना जैव सुरक्षा प्रोतोकोल से संबंधित कार्यशालाः आरआईएस तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सतत् विकास केंद्र ने राष्ट्रीय जैव सुरक्षा नियम तथा कार्ट जेना जैव सुरक्षा प्रोतोकोल पर 14 मई, 2008 को बोन, जर्मन में एक कार्यशाला आयोजित की थी कि हम किस प्रकार समरूप क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। वक्ताओं में पीबीएस नीदरलैंड से जोन कोमेन सुसैक्स विश्वविद्यालय, यूके से अनुसंधान फेलो डॉ. एड्रियन ऐली, आरआईएस के फेलो डा. सचिन चतुर्वेदी तथा आईसीटीएसडी, जिनेवा के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मारिया जुलिया ऑलिवा शामिल थे।

व्यापार वार्ता पर दोहा दौर पर संगोष्ठीः चुनौतियां एवं संभावनाएंः आरआईएस ने विकसित एवं विकासशील देशों में वार्ता की मुख्य स्थिति, समानता के उभरते क्षेत्र तथा इस दौर में शामिल की जाने वाली विशेष चुनौतियां तथा भावी संभावनओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 13 अगस्त, 2008 को एक संगोष्ठी आयोजित की। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव श्री गोपाल के. पिल्लेई तथा योजना आयोग के सदस्य डा. अनवारुल होडा ने सहभागियों को संबोधित किया।

आउटरीच, सार्वभौमिक उपस्थिति और नेटवर्किंग

आरआईएस ने वैश्विक घटनाओं पर संगोष्ठियां आयोजित करके अपने कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा संस्थागत नेटवर्किंग को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए हैं। विगत वर्ष में सहभागी संस्थानों अर्थात् आईसीटीएसडी, जिनेवा, एडीबी मनीला, नीतिगत अध्ययन संस्थान श्रीलंका, आईडीई/जेट्रो व ईआरआईए जापान, टफ्स विश्वविद्यालय यूएसए में जीडीएई, सेनिट, अर्जेंटिना, एडीबी संस्थान टोक्यो, फिक्की, सीआईआई, आईटीपीओ, चीनी अध्ययन संस्थान, भारतीय विश्व कार्य परिषद के साथ संयुक्त रूप से कई नीतिगत वार्ताएं आयोजित कीं। आरआईएस ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यह विभिन्न देशों के कई समतुल्य संस्थानों जैसे कि चीन की राज्य विकास अनुसंधान परिषद, कोरिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान, श्री लंका का नीतिगत अध्ययन संस्थान, सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, टोक्यो में विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान, बैंकाक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व विकास संस्थान, जकार्ता में दक्षिण-दक्षिण तकनीकी सहयोग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन केंद्र तथा जकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (सीएसआईएस) को संयुक्त कार्यकलापों की रूपरेखा प्रदान करेगा।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमः विदेश मंत्रालय के इटेक/स्केप कार्यक्रम के तत्वावधान में प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों तथा विकास नीति पर एक चार सप्ताहिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2008 में विभिन्न देशों से 10 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। फरवरी-मार्च, 2009 में 14 देशों से 16 प्रतिभागियों के एक अन्य समूह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

ईआरआईए के सहयोग से ईएएस देशों के प्रतिभागियों के लिए फरवरी, 2008 को विश्वस्तरीय व क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर एक अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूर्व एशियाई देशों से 8 सहभागियों ने इसमें भाग लिया था। फरवरी-मार्च, 2009 में 11 पूर्व एशियाई देशों से 12 सहभागियों के एक अन्य बैच ने इसमें भाग लिया।

वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था तथा भारत के क्षेत्रीय आर्थिक कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमः आरआईएस ने विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 3-4 जून, 2008 को नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

वैश्वीकृत विश्व में भारत की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमः आरआईएस ने 24-25 जून, 2008 को मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया था।

विश्वस्तरीय आर्थिक मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षण मॉड्यूलः विकासशील देशों पर प्रभावः आरआईएस ने 10 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए आयोजित 46वें व्यावसायिक कार्यक्रम के उपलक्ष में एक प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया था।

एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को समझने संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल, 5 नवंबर, 2008ः आरआईएस ने शैक्षिक कर्मचारी महाविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए, एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को समझने के लिए, प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया।

आरआईएस प्रकाशन

वर्ष 2008-09 के दौरान आरआईएस ने 5 पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित कीं, 5 पॉलिसी ब्रीफ जारी किए और 15 विचार-विमर्श पत्र जारी किए। साउथ एशिया इकोनामिक जनरल के दो अंक बायोटेक्नोलाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू के तीन अंक तथा न्यू एशिया मानीटर के 3 अंक निकाले गए तथा आरआईएस मेंकांग-गंगा पालिसी ब्रीफ नाम का एक अंक प्रकाशित किया गया । इसके अलावा, आरआईएस डायरी के चार अंक भी प्रकाशित किए गए थे (परिशिष्ट XVII देखें) । आरआईएस प्रकाशनों को इसकी वेबसाइट- http:// www.ris.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

बजट

आरआईएस को विदेश मंत्रालय से वर्ष 2008-09 के दौरान 260 लाख रुपए की बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

■■

पुस्तकालय

24

मंत्रालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, समृद्ध स्रोत सामग्री और मानचित्रों का विशाल संग्रहण, माइक्रोफिल्में एवं सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह नीति नियोजन और शोध की सहायता के लिए आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय लगभग 480 पत्रिकाओं, जर्नलों (ऑनलाइन जर्नलों एवं डेटाबेस सहित) और अखबारों की खरीददारी प्राप्ति और रखरखाव करता है।

पुस्तकालय के पास एक आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली है, जिसमें एक सर्वर और 12 पीसी टर्मिनल हैं। इस प्रणाली में हिन्दी में भी डाटा की एंट्री और पुनः प्राप्त कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में विदेशी मामलों एवं वर्तमान मामलों पर सीडी-रोम डाटाबेस है। पुस्तकालय के पीसी में सीडी-राइटर और लेजर प्रिंटर भी लगे हैं। यहां एक रंगीन स्कैनर (ओसी आर क्षमता के साथ-साथ प्रतिबिंबों के संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति की सुविधा सहित), एक माइक्राफिल्म/फिशे रीडर प्रिंटर, प्लेन पेपर फोटोकॉपियर और डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डी.पी.टी.)साफ्टवेयर के साथ-साथ एक एच पी आफिस-जेट प्रो लेजर प्रिंटर भी है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकों के क्रय और जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं को मंगवाने के साथ-साथ पुस्तकालयों के क्रिया-कलापों का प्रबंधन करती है। अप्रैल, 2008 में विदेश सचिव ने पुस्तकालय समिति का पुनर्गठन किया। वर्तमान पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (पीपी एंड आर) हैं, प्रादेशिक प्रभागों के तीन निदेशक सदस्य हैं और निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना)इसके सदस्य सचिव हैं। पुस्तकालय के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत पुस्तकालय साफ्टवेयर पैकेज लिबसीस का कर समस्त प्रलेखन ग्रंथ सूची संबंधी सेवाओं एवं पुस्तकालय के अन्य कार्यों एवं सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। लिबसीस में मार्क के साथ-साथ नॉन-मार्क फार्मेट का प्रयोग किया जाता है और यह बूलीयन आपरेटरों के प्रयोग से शब्द-आधारित फ्री टैक्स्ट सर्चिंग की सहायता करता है। यह डाटाबेस को अद्यतन करने से पहले इनपुट डाटा का ऑनलाइन सत्यापन भी करता है। पटियाला हाउस स्थित विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के समस्त पीसी में इंटरनेट के माध्यम से समस्त पुस्तकों मानचित्रों, दस्तावेजों एवं 1986 से पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली पत्रिकाओं से चुने गए लेखों (और 1986 से पहले के अधिक उपयोग में आने वाले प्रकाशनों) की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। पुस्तकालय की जानकारी www.mealib.nic.in नामक विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

पुस्तकालय में प्राप्त समस्त नए दस्तावेजों अर्थात् पुस्तकों, मानचित्रों, मानक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं से चुने गए लेखों- को विदेशी मामले संबंधी डाटाबेस में नियमित रूप से संग्रहित किया जाता है। इस डाटाबेस और सीडी-रोम डाटाबेसों का प्रयोग करके पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता सेवा और ग्रथ सूची एवं निर्देशिका सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय नियमित तौर पर जारी करता है। विदेशी मामलों से संबंधित प्रलेखन बुलेटिन (एफएडीबी) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर चुनिंदा लेखों की एक सूची हाल ही में हुए परिवर्धन पुस्तकालय में पुस्तकों/प्रकाशनों की विस्तृत सूची शामिल की गई।

पुस्तकालय नियमित रूप से लेख सतर्कता सेवा प्रदान करता है जिसमें विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण लेखों के उद्धरण निहित होते हैं जो मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में सभी विदेश सेवा अधिकारियों को ग्रुप ई-मेल आईडी के जरिए उपलबध होते हैं।

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय असल में एक वास्तविक पुस्तकालय बन गया है, क्योंकि इसने नई दिल्ली में मुख्यालय तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के प्रयोक्ताओं के लिए "ईआईयू ऑनलाइन डेटाबेस/सेवा" ई-गेटः सामाजिक विज्ञान और प्रबंध विज्ञानः बहुप्रयोक्ता डेटाबेस का पूर्ण पाक और जस्टर डेटाबेस मंगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुस्तकालय 91 ऑनलाइन पत्र-पत्रिकाएं भी उनकी मुद्रित प्रतियों के साथ मंगा रहा है। ये ऑनलाइन डेटाबेस और पत्र-पत्रिकाएं प्रयोक्ता नाम तथा पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर सुलभ हो सकती है। ऐसे नामों की एक सूची मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों में भी परिचालित की गई है तथा यह विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइटः www.mealib.nic.in पर भी उपलब्ध है।

एनआईसी के सहयोग से पुस्तकालय ने विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998-99 तक) तथा विदेश मंत्रालय के अभिलेख (1955 से 199 (अगस्त)) के सी डी रोम रूपांतर का एक पूरा पाठ निकाला है। सीडी संबंधी सूचना किसी भी दिए हुए शब्द या शब्द युग्म पर खोज सहित संयुक्त खोज के जरिए पुनः प्राप्त की जा सकती है। यह सीडी रोम रूपांतर 1 जनवरी,

2000 को उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया गया। पटियाला हाउस, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में संदर्भ हेतु इस सीडी का उपयोग किया जा सकता है। पुरानी और अप्रयुक्त पुस्तकों और जर्नलों को हटाने का कार्य जो कुछ वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था, अभी भी जारी है और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय संबंधी अभिलेखों के पश्च-रूपांतरण एवं बार-कोडिंग की परियोजना को अनुमोदन मिल गया है। यह कार्य चल रहा है जोकि इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

यह पुस्तकालय समय-समय पर दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं में पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद पुस्तकालय के नवीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। यह कार्य के.लो.नि.वि. को सुपुर्द किया गया है और यह इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) तथा अन्य व्यावसायिक लोगों ने समय-समय पर विभिन्न पुस्तकालय संघों/ आईएमएलए के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लिया।

पुस्तकालय ने 17 वर्षों के अंतराल के पश्चात् वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार श्रेणी V पुस्तकालय के मामले पर भी कार्रवाई की है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट www.mealib.nic.in को पुनः निर्मित एवं अद्यतन किया गया है। विदेश सचिव के अनुदेशों के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशनों सहित मंत्रालय के सभी अधिकारियों को इस संबंध में एक परिपत्र भेजा गया है।

शोधकर्ताओं सहित पुस्तकालय प्रयोक्ताओं का सीडी-रोम डेटाबेस तथा विदेश मामलों संबंधी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली (एमएआईआरएस)सहित पुस्तकालय तथा इसके डेटाबेस का लाभ उठाने के लिए स्वागत है।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय बजट से प्रदान किए गए पद और बाह्य-संवर्ग पद इत्यादि शामिल हैं)।

क्रम सं.	काडर/पद		मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रुप I		5	26	31
2	ग्रुप II		9	34	43
3	ग्रुप III		38	140	178
4	ग्रुप IV		36	110	146
5	कनिष्ठ प्रशा. संवर्ग/वरिष्ठ वेतनमान		44	147	191
6	(i)	कनिष्ठ वेतनमान	10	39	49
	(ii)	परिवीक्षार्थी आरक्षित	62	-	62
	(iii)	छुट्टी आरक्षित	15	-	15
	(iv)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	19	-	19
	(v)	प्रशिक्षण आरक्षित	7	-	7
		कुल जोड़	**245**	**496**	**741**
भा.वि.से.(ख)					
7	(i)	ग्रेड I	84	212	296
	(ii)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	6	-	6
8	(i)	एकीकृत ग्रेड II & III	147	236	383
	(ii)	अवकाश आरक्षित	30	-	30
	(iii)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	16	-	16
	(iv)	प्रशिक्षण आरक्षित	25	-	25
9	(i)	ग्रेड IV	189	416	605
	(ii)	अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	55	-	55
10	(i)	ग्रेड V/VI	168	101	269
	(ii)	अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	14	-	14
11	(i)	साइफर संवर्ग के ग्रेड II	41	147	188
	(ii)	अवकाश आरक्षित	24	-	24
12	(i)	आशुलिपिक संवर्ग	174	488	662
	(ii)	अवकाश आरक्षित	47	-	47
	(iii)	प्राशिक्षण आरक्षित (हिन्दी)	10	-	10
	(iv)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	12	-	12
13	दुभाषिया संवर्ग		7	26	33
14	एल एंड टी संवर्ग		14	1	15
	योग		**1183**	**1627**	**2810**
	कुल योग		**1427**	**2123**	**3551**

परिशिष्ट II

विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2008 से नवम्बर 2008 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े ।

ग्रुप	**पदों की कुल संख्या**	**पदों की संख्या**			
		आरक्षित			अनारक्षित
		अ जा	अ ज जा	ओबीसी	
ग्रुप ए	19	4	1	4	10
ग्रुप ए (भाह्य संवर्ग)	–	–	–	–	–
ग्रुप बी	34	6	2	6	20
ग्रुप सी	8	–	–	2	6
ग्रुप डी	–	–	–	–	–
कुल	**61**	**10**	**3**	**12**	**36**

परिशिष्ट III

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भा.वि.से. के अधिकारियों की संख्या

भाषा	अधिकारियों की संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
अरबी	91	कोरियाई	3
बहासा मलेसिया	2	नेपाली	3
बहासा इंडोनेसिया	12	फारसी	20
बर्मी	2	पुर्तगाली	21
चीनी	60	रसियन	77
डच	1	सर्बो-क्रोशियन	3
फ्रेंच	68	सिंहली	1
जर्मन	31	स्पेनिस	58
हिब्रू	4	थाई	2
इटालियन	3	तुर्किस	7
जापानी	24	यूक्रेनियन	1
कज़ाक	1	वियतनामी	2
किसवाहिली	5		

परिशिष्ट **IV**

1 जनवरी से 31 दिसंबर 2008 तक प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों और तत्काल योजना सहित जारी किए गए पासपोर्टों, विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाएं एवं राजस्व (तत्काल योजना के तहत राजस्व सहित) और पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय संबंधी आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त हुए विविध आवेदनों पत्रों की संख्या	दी गई विविध सेवाएं	तत्काल सेवा के तहत जारी पासपोर्टों की संख्या	तत्काल सेवा के तहत प्राप्त राजस्व	कुल राजस्व	कुल व्यय
अहमदाबाद	**272609**	**280415**	**12626**	**12286**	**20203**	**27542450**	**303428770**	**47001756**
अमृतसर #	53306	34190	7439	6868	3559	7194400	62590600	*
भंगलौर	321287	310436	28664	27976	36527	64993400	342337850	34177234
भरेली	70852	65950	3556	3551	3309	536250	78505430	15780475
भोपाल	69394	70187	2761	2750	8302	12373000	81537072	11169915
भुवनेश्वर	46620	49938	2934	2565	17262	19330600	67363240	5333674
चंडीगढ़	295120	307760	36517	34895	22066	49553422	337646760	35104863
चेन्नई	292756	307433	24377	23689	85414	131617500	446284553	41226878
कोचीन	249626	249513	52937	52360	47778	72509000	340196000	39582000
कोएम्भटूर ##	20926	11409	1757	1514	5139	13955700	28107900	2992559
देहरादून ###	20668	14314	1238	1127	928	3594700	23500700	**
दिल्ली	272075	280168	25649	24481	58338	13560000	35840000	5370000
गाजियाभाद	93610	92645	7238	7046	7146	14858300	80555965	11730373
गुवाहाटी	35036	31872	4029	3842	8643	20988100	44978500	6431960
हैदराभाद	373172	372001	18209	13556	44440	101139980	480497925	46163557
जयपुर	195568	174081	11767	8828	20087	39335300	221283240	26054479
जालंधर	198787	191409	34806	33369	3916	6259600	228692862	40407428
जम्मू	15937	16938	1099	995	111	166500	17534010	3690765
कोलकाता	232897	200007	17521	17248	14204	34178000	243976200	24468070
कोझीकोड	193747	195112	31318	30642	34514	55600000	259700000	27900000
लखनऊ	332521	334233	19667	18204	12827	34000000	364800000	39300000
मदुरई ####	149670	131602	9286	8564	28993	75579500	203241683	17943800
मालापुरम	155941	152176	23372	23358	19903	30400000	207800000	20800000
मुम्भई	298569	293427	20707	20289	22361	30226000	333569177	88261531
नागपुर	56768	59701	1834	1771	5568	7040200	63768414	6093239
पणजी	30381	30755	4553	4445	1602	2532000	35227143	5595033
पटना	206974	164020	7403	7872	2869	4532000	209222121	16365075
पुणे	119895	120786	7913	7888	14589	19345500	141775510	11271480
रायपुर #####	22101	16115	975	966	2857	7142500	25853800	***
रांची	42286	38409	4083	3760	6218	9421000	42636000	5475609
शिमला	27292	26257	1481	1450	1611	4505600	29337828	****
श्रीनगर	15247	14812	1197	1167	260	386000	16388230	7819874
सूरत	87901	89479	7737	7644	1946	2745600	91465100	*****
थाने	149925	151497	5842	5752	8731	15441500	166470450	******
त्रिची	143907	177306	8998	8983	16575	26139000	190112030	26689783
त्रिवेन्द्रम	164699	163077	35231	34148	28795	44056000	226450679	20660807
विशाखापट्टनम	83234	90737	12453	11777	9700	14901500	99629759	9636910
	5411304	5310167	499174	477626	627291	1017620102	6172305501	700499127

* क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जालंधर द्वारा किया गया व्यय

** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली द्वारा किया गया व्यय

*** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल द्वारा किया गया व्यय

**** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा किया गया व्यय

***** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद द्वारा किया गया व्यय

****** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई द्वारा किया गया व्यय

28 जून 2008 को अमृतसर खुला

13 सितम्बर 2008 को कोएम्बटूर खुला

17 जून 2008 को देहरादून खुला

17 दिसम्बर, 2007 को मदुरै खुला

17 दिसम्बर, 2007 को रायपुर खुला

वर्ष 2008-2009 में विदेश मंत्रालय का वित्त

बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.) 2008-2009 में विदेश मंत्रालय का बजट आबंटन 5062.00 करोड़ रुपये है जो 2007-08 के बजट प्राक्कलन 4433.60 करोड़ रुपये की अपेक्षा 628.40 करोड़ रुपये अर्थात 14.17% अधिक है। वर्ष 2008-09 के संशोधित प्राक्कलन में वर्ष 2008-09 के बजट प्राक्कलन की तुलना में 1806.42 करोड़ रुपये अर्थात् 35.68% तक की वृद्धि हुई है।

विदेश मंत्रालय का व्यय और बजट (2002-2003 से 2008-2009)

वर्ष	वास्तविक (करोड़ रुपये में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर
2002-2003	3253.79	23.98
2003-2004	3344.53	2.79
2004-2005	3756.15	12.31
2005-2006	4089.67	8.88
2006-2007	3695.05	-3.43
2007-2008	4572.39	15.77
2008-2009 (ब.प्रा.)	5062.00	14.17
2008-2009(सं.प्रा.)	6868.42	54.92

परिशिष्ट **VI**

वर्ष 2008-09 बजट (संशोधित प्राक्कलन) में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (राजस्व और पूंजी)

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपये में)
विदेश मंत्रालय सचिवालय	186.21
राजदूतावास और मिशन	1230.96
पासपोर्ट और उत्प्रवासन	247.76
विशेष राजनयिक खर्च	1041.39
तकनीकी और आर्थिक सहयोग	1730.09
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	1015.56
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	86.75
विदेशी सरकारों को ऋण और अग्रिम	914.60
अन्य	415.10
कुल	6868.42

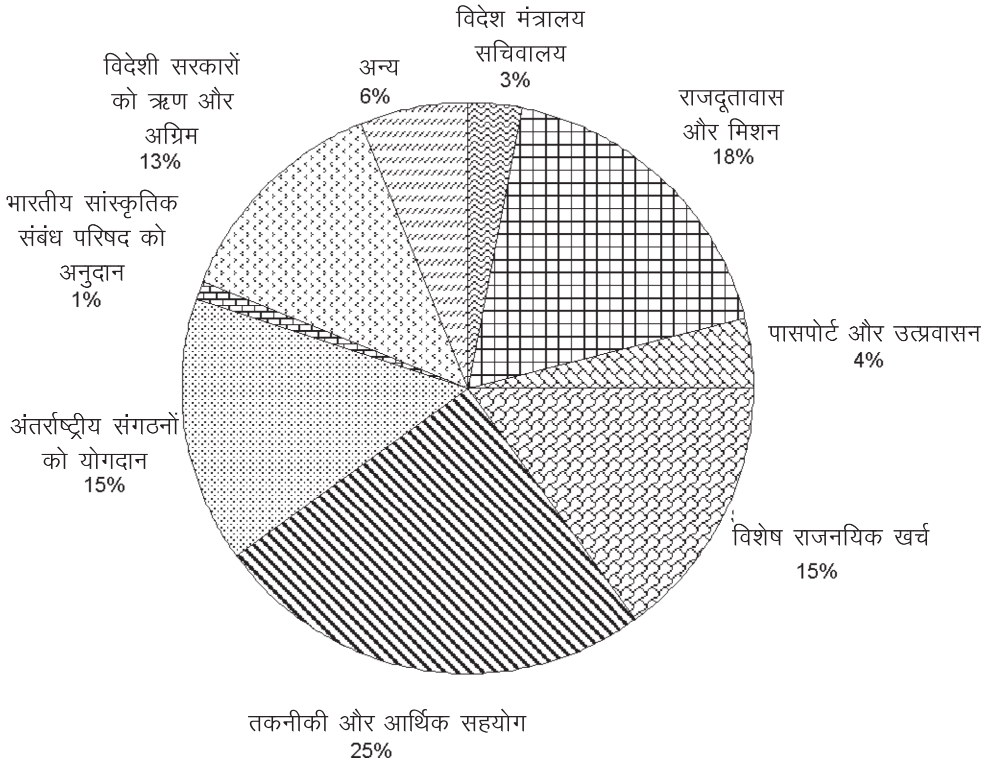

परिशिष्ट VII

भारत के सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2008-09) में हमारे सहायता और ऋण कार्यक्रमों के प्रधान लाभार्थी निम्नलिखित हैं (संशोधित प्राक्कलन)

देशों को सहायता और ऋण	(करोड़ रुपये में)	भारत के कुल सहायता और ऋण बजट का %
भूटान	1205.92	45.60
मालदीव	504.70	19.08
अफगानिस्तान	418.50	15.82
अन्य विकासशील देश	215.75	8.16
नेपाल	113.00	4.27
अफ्रीकी देश	95.00	3.59
म्यामां	35.00	1.32
श्रीलंका	30.00	1.13
मध्य एशिया	18.82	0.71
बंगलादेश	6.00	0.23
लैटिन अमरीकी देश	2.00	0.08
कुल	2644.69	100.00

1. भारत सरकार ने उसकी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए भूटान सरकार को ऋण दियाहै। वर्ष 2008-2009 के दौरान भूटान सरकार को दिया गया ऋण 114.60 करोड़ रुपये रहा है। इस वर्ष भूटान को 300 करोड़ रू. की सहयोगीऋण सुविधा भी दी गई है ।

2. विदेश मंत्रालय का बजट अनिवार्यतः गैर-योजनागत बजट है। तथापि 1996-97 से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक योजनागत शीर्ष स्थापित किया गया है। यह मुख्य रूप से भूटान की कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए है जो भारत सरकार द्वारा 'भूटान को सहायता' कार्यक्रम के रूप में भूटान सरकार के अनुरोध पर परियोजना की सहायता के भाग के तौर पर चलाई जा रही हैं। ताला जल विद्युत परियोजना शुरू हो चुकी है। भूटान की कुछ अन्य परियोजनाएं जो योजनागत शीर्ष से वित्तपोषित की जा रही हैं :- पुनात्सांगछू जल विद्युत परियोजना, और डुंगसुंग सीमेंट संयंत्र परियोजना हैं। योजनागत आबंटन से अफगानिस्तान की काबुल-पुल-ए-खुमरी में दोहरी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और म्यामां में कलादान बहुविध परिवहन परियोजना भी वित्तपोषित की जा रही हैं। इस योजनागत खण्ड के तहत् भूटान सरकार को दिए गए ऋण भी आते हैं जो कि चालू वित्तीय वर्ष (2008-2009) के लिए 114.60 करोड़ रुपये है।

3. विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय 186.21 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के कुल अनुमानित 5227.57 करोड़ रुपये राजस्व बजट का लगभग 3.56% है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय 1230.96 करोड़ रुपये होने की आशा है, जो कि मंत्रालय के कुल राजस्व व्यय का लगभग 23.55% है।

4. पासपोर्ट तथा वीजा शुल्क और अन्य प्राप्तियों के रूप में विदेश मंत्रालय का राजस्व 2008-09 के लिए 2000.36 करोड़ रुपये के लगभग हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि पासपोर्ट शुल्क 950 करोड़ रुपये और वीजा शुल्क 1000 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राप्तियां 50.36 करोड़ रुपये होंगी।

परिशिष्ट **VIII**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विदेश मंत्रालय संबंधी रिपोर्ट से उद्घृत अंश

मंत्रालय का सऊदी अरब अधिराज्य के लिए 18-20 दिनों की लंबी समयावधि हेतु भारी भरकम हज सदभावना शिष्ट मंडल का अनुमोदन, जो कि शिष्टमंडल की भूमिका के अनुरूप नहीं है, इसे अपव्ययी बना देता है । शिष्ट मंडल के लिए सदस्यों के नामांकन से संबंधित कोई मानदंड सुनिश्चित नहीं किया गया है । मंत्रालय प्रतिनिधियों के साथ जाने वाले उनके पति/पत्नी परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी खर्च पर होटल की सुविधा मुहैया कराता है जो कि अनियमित है । *(2008 के रिपोर्ट संख्या सीए।)*

परिशिष्ट **IX**

वर्ष 2008 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
क.	**बहुपक्षीय**			
1	सार्वभौमिक डाक संघ के संविधान का सातवां अतिरिक्त प्रोतोकॉल	5.10.2004	07.03.2008	
2	अंतर्राष्ट्रीय कॉफी करार, 2007	28.08.2008	18.09.2008	22.09.2008
3	क्यूतो प्रोतोकॉल के पक्षकार सम्मेलन द्वारा अपनाए गए क्यूतो प्रोतोकॉल के अनुभंध ख में संशोधन	17.11.2006	30.09.2008	18.11.2008
4	अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिभंधीय काष्ठ करार, 2006	23.04.2008	19.06.2008	25.7.2008
5	सार्क विकास निधि (एसडीएफ) का चार्टर	03.8.2008	27.10.2008	
6	अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य का दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) से संभंधित करार के अधिमिलन का प्रोतोकॉल	03.08.2008	27.10.2008	
7	अपराधिक मामलों से संभंधित पारस्परिक सहयता पर सार्क अभिसमय	03.08.2008	29.08.2008	
8	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (सारसो) को स्थापित संबंधी करार	03.08.2008	27.10.2008	
9	अभिसमय 174, बड़े औद्योगिक दुघटनाओं की रोकथाम से संबंधित अभिसमय 1993	03.04.2008	06.06.2008	06.06.2009
10	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) और भारत गणराज्य की सरकार के बीच मुख्यालय करार	30.11.2008	30.11.2008	
ख.	**त्रिपक्षीय**			
	इब्सा (आईबीएसए)			
1	भारत गणराज्य की सरकार, संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच मानव आवास विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15.10.08		15.10.08
2	भारत गणराज्य की सरकार संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच इब्सा मंच के तहत पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	15.10.08		15.10.08
3	भारत गणराज्य की सरकार संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच इब्सा के तहत पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध त्रिपक्षीय करार।	15.10.08		

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
4	भारत गणराज्य की सरकार संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच मानक, तकनीकी विनियमन और अनुरुपता के अनुसार मूल्यांकन के लिए व्यपार सुविधा से संबंधित समझौता ज्ञापन।	15.10.08		
5	भारत गणराज्य की सरकार, संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच महिला विकास और लैंगिक समानता कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	15.10.08		
6	भारत गणराज्य की सरकार, संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच पवन संसाधनों से संबद्ध करार।	17.10.07		
7	भारत गणराज्य की सरकार, संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच लोक प्रशासन और शासन से संबद्ध करार।	17.10.07		
ग.	**द्विपक्षीय**			
1	आस्ट्रेलिया भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के मध्य प्रत्यर्पण करार।	23.06.2008	11.08.2008	
2	आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबंधित भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के बीच संधि।	23.6.2008	14.8.2008	
3	बेल्जियम भारत गणराज्य और बेल्जियम अधिराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा से संबंद्ध करार।	03.11.2006	03.06.2008	
4	भूटान भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच भूटान में दूरचिकित्सा परियोजना से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	28.03.2008		
5	बाजील भारत गणराज्य और संघीय गणराज्य ब्राजील के बीच प्रत्यर्पण संबंधी संधि।	16.04.2008	14.08.2008	
6	भारत गणराज्य की सरकार और संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार के बीच दृश्य-श्रव्य यह उत्पादन से संबद्ध करार।	04.06.2007	22.08.2008	
7	बोसनिया व हर्जेगोविना भारत और बोसनिया व हर्जेगोविना के बीच निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध द्विपक्षीय करार।	12.09.2006	27.11.2007	14.02.2008
8	ब्रिटिश उच्चायोग भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय और ब्रिटिश उच्चायोग के बीच महामान्या की सरकार से संबद्ध समझौता ज्ञापन	21.01.2008		
9	बेलारूस भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।	16.04.2007	17.04.2008	

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
10	बुल्गारिया 26 अक्तूबर, 1998 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य की सरकार और बुल्गारिया गणराज्य की सरकार के बीच संपन्न हुए निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबंधित करार को संशोधित करते हुए भारत गणराज्य की सरकार और बुल्गारिया गणराज्य की सरकार के बीच प्रोतोकॉल।	12.09.2007	08.11.2007	12.5.2008
11	भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के मध्य आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि।	12.9.2007	24.9.2008	9.10.2008
12	भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानातंरण से संबद्ध संधि।	12.9.2007	28.2.2008	9.10.2008
13	भारत गणराज्य की सरकार और बुल्गारिया गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार।	12.9.2007	20.3.2008	
14	ब्रूनई दारुस्लाम द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बीपा)।	22.5.2008	14.7.2008	
15	भारत गणराज्य सरकार और कंबोडिया की शाही सरकार के मध्य सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	8.12.2007	5.6.2008	
16	चीन राष्ट्रीय कृषि बैंक और चीन के ग्रामीण विकास और कृषि विकास बैंक के बीच पारस्परिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	14.1.2008	14.1.2008	
17	भारत गणराज्य के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के निर्माण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
18	भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य की 21वीं शताब्दी के लिए साझी दृष्टि।	14.1.2008		
19	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के रेल मंत्रालय बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
20	भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और चीन के लोक गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध सामान्य प्रशासन के बीच भारत से चीन के तम्बाकू के पत्तों के निर्यात के लिए पादप स्वास्थ्य की जरूरतों से संबद्ध प्रोतोकॉल।	14.1.2008		14.1.2008
21	भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और चीन के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच भूविज्ञान में वैज्ञानिक सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
22	भारत गणराज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के भूमि और संसाधन मंत्रालय के मध्य भूमि संसाधन प्रबंधन, भूमि प्रशासन और पुनर्वास व पुनर्स्थापना में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
23	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग तथा चीन गणराज्य के पारंपरिक चीनी औषधि (एसएटीसीएम) के राज्य प्रशासन के बीच पारंपरिक औषधि से संबद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
24	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों से मित्रता के लिए चीनी लोक संघ के बीच संस्कृति में सहयोग से संबंध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
25	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशी देशों से मित्रता के लिए चीनी लोक संघ के बीच भारत चीन संयुक्त चिकित्सा मिशन से संबंध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
26	भारत गणराज्य के योजना आयोग और चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग के बीच सहयोग से संबंध समझौता ज्ञापन।	14.1.2008		14.1.2008
27	भारत गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय के बीच बाढ़ के मौसम में चीन द्वारा भारत के यालुजांबु/ब्रह्मपुत्र नदी के जल वैज्ञानिक सूचना देने संबंधी व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन।	5.6.2008		5.6.2008
28	साइप्रस भारत गणराज्य की सरकार और साइप्रस गणराज्य की सरकार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से निपटने से संबद्ध करार।	25.05.07	25.01.2008	
29	कनाडा भारत सरकार के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कनाडा के सस्काचवान विश्वविद्यालय के बीच भारत-कनाडा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	28.3.2008		28.3.2008
30	भारत गणराज्य की सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	17.11.2008	10.9.2008	
31	डेनमार्क भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क अधिराज्य की सरकार के बीच राजनयिक मिशन या कोंसली केन्द्र में रह रहे परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी रोजगार से संबद्ध व्यवस्था।	6.2.2008		6.2.2008
32	जीबोती भारत गणराज्य की सरकार और जीबोती गणराज्य की सरकार के बीच निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	19.5.2003	16.10.2008	
33	इथोपिया भारत गणराज्य की सरकार और संघीय लोकतांत्रिक गणराज इथोपिया की सरकार के मध्य निवेश के पारस्परिक संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	5.06.07	3.09.07	13.8.2008

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
34	मिस्र भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र के अरब गणराज्य की सरकार के मध्य सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	8.1.2008	5.6.2008	
35	भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र के अरब गणराज्य की सरकार के मध्य आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार।	8.1.2008	24.1.2008	
36	भारत सरकार और मिस्र की अरब गणराज्य की सरकार के मध्य प्रत्यर्पण संधि।	18.11.2008	8.12.2008	
37	भारत गणराज्य की सरकार तथा मिस्र गणराज्य की सरकार के बीच स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।	18.11.2008	18.11.2008	
38	फ्रांस भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा क्षेत्र में वर्गीकृत सूचनाओं और सामग्री के संरक्षण से संबद्ध करार।	25.1.2008		19.12.2008
39	भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	25.1.2008	16.7.2008	
40	भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा फ्रांस राज्य के कमीसारियट एलिनेरगी एटोमिक के मध्य जूल्स होरोबीच रियक्टर के निर्माण तथा संचालन से संबद्ध द्विपक्षीय करार।	25.1.2008		
41	भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के मध्य एएफडी के माध्यम से भारत-फ्रांस विकास सहयोग से संबद्ध करार।	25.1.2008		
42	भारत सरकार के राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केन्द्र (एनबीआरसी) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संसहबद्ध प्रयोगशाला “परियोजना” स्थापित करने के लिए सहयोग से संबद्ध करार।	25.1.2008		
43	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फ्रेंच रेल (एसएनसीएफ) के बीच समझौता ज्ञापन	14.5.2008		14.5.2008
44	भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हेतु निकासि से संबद्ध करार।	30.9.2008		
45	जर्मनी संघीय गणराज्य जर्मनी के संघीय रक्षा मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण से संबद्ध करार।	30.10.2007	30.10.2008	

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
46	हैलेनिक गणराज्य भारत और हैलेनिक गणराज्य की सरकार के मध्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध करार।	26.04.07	18.07.07	29.2.2008
47	भारत और हैलेनिक गणराज्य सरकार (ग्रीक) के मध्य द्विपक्षीय निवेश के संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	26.04.07	21.8.2007	12.4.2008
48	हंगरी भारत गणराज्य के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और हंगरी गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के मध्य स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग की योजना।	18.1.2008		18.1.2008
49	भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और हंगरी गणराज्य के कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच कृषि तथा संबद्ध सेक्टरों के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	18.1.2008		18.1.2008
50	ईरान भारत गणराज्य की सरकार और ईरान की इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार।	2.11.2008	18.11.2008	
51	इटली इटली गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध करार।	12.7.2004		6.10.2008
52	भारत गणराज्य की सरकार तथा इटली के कृषि, खाद्य व वानिकी नीति मंत्रालय के बीच कृषि और पादपस्वास्थ्य मसलों पर सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	16.1.2008		16.1.2008
53	आइसलैंड भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड गणराज्य की सरकार के मध्य निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	29.6.2007	19.10.2007	16.12.2008
54	आयरलैंड भारत गणराज्य की सरकार और आयरलैंड की सरकार के मध्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पर सहयोग से संबद्ध करार।	19.1.2006	19.2.2008	
55	जापान जापान-भारत ऊर्जा संवाद की तीसरी बैठक के अवसर पर भारत के योजना आयोग और जापान के आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय के मध्य संयुक्त वक्तव्य।	17.9.2008		
56	भारत और जापान के मध्य सामरिक और वैश्विक भागीदारी की प्रगति पर संयुक्त वक्तव्य	22.10.2008		
57	भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग से संबद्ध संयुक्त घोषणा।	22.10.2008		
58	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा जापान के आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्री के बीच संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुआ।	21.10.2008		

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
59	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक और इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड तथा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।	21.10.2008		
60	भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जापान के उच्च ऊर्जा त्वरक अनुसंधान संगठन (केईजेड) के मध्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	22.10.2008		
61	किरगिज गणराज्य भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और किरगिज गणराज्य के विदेश मंत्रालय के मध्य सहयोग से संबद्ध कार्यक्रम।	4.2.2008		4.2.2008
62	मेसिडोनिया भारत सरकार और मेसिडोनिया गणराज्य की सरकार के बीच पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	17.3.2008	30.4.2008	17.10.2008
63	मेडागास्कर भारत गणराज्य की सरकार तथा मेडागास्कर गणराज्य की सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन।	18.9.2008		
64	मॉरीशस भारत और मॉरीशस के बीच प्रत्यर्पण संधि।	21.11.2003	21.8.2007	23.6.2008
65	म्यामां भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच आसूचना आदान प्रदान से संबद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	2.4.2008		
66	भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यामां में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कलादान नदी की बहुविध पारगमन परिवहन सुविधा के निर्माण और संचालन से संबद्ध ढांचागत करार।	2.4.2008		
67	भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच कलादान बहुविध पारगमन परिवहन की सुविधा से संबद्ध प्रोतोकॉल।	2.4.2008		
68	भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच कलादान बहुविध पारगमन परिवहन सुविधा के रखरखाव और प्रशासन से संबद्ध प्रोतोकॉल।	2.4.2008		
69	भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	24.6.2008	1.10.2008	
70	भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच आय से संबंधित करों के दुगने कराधन के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से संबद्ध करार।	2.4.2008		

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
71	मोन्टीनेग्रो भारत गणराज्य की सरकार और मोन्टीनेग्रो की बीच दुगने कराधन के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से संबद्ध अभिसमय।	8.2.2006	12.9.2008	23.9.2008
72	मालदीव भारत सरकार और मालदीव के बीच माले में स्थित इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल (आईजीएमएच) के लिए मानव शक्ति की जरूरतों से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	19.9.2008		19.9.2008
73	भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच भारत-मालदीव प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन।	19.9.2008		19.9.2008
74	भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	11.2.2008		11.2.2008
75	मैक्सिको भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	21.5.2007	2.7.2007	23.2.2008
76	नीदरलैंड भारत गणराज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीदरलैंड की आर्थिक मामलों के मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	28.3.2008		
77	नार्वे भारत गणराज्य की मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नॉर्वे अधिराज्य के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	18.6.2008		
78	पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के मध्य कोंसुली सुविधा पर करार	21.5.2008		21.5.2008
79	भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और पाकिस्तान के प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग के मध्य समझौता ज्ञापन।	28.1.2008		28.1.2008
80	रक्षा अध्ययन संस्थान और विश्लेषण (नई दिल्ली, भारत) और सामरिक अध्ययन संस्थान (इस्लामाबाद, पाकिस्तान) के मध्य समझौता ज्ञापन।	4.2.2008		
81	भारत और पाकिस्तान के मध्य हवाई सेवाओं से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	15.2.2008		15.2.2008
82	फिलस्तीन भारत गणराज्य की सरकार और फिलस्तीन मुक्ति संगठन के मध्य फिलस्तीन प्राधिकरण के लाभ से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	7.10.2008		

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
83	कतर भारत गणराज्य सरकार और कतर राज्य की सरकार के मध्य रक्षा सहयोग से संबद्ध करार।	9.11.2008		9.11.2008
84	भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार के बीच सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन मामलों से संबद्ध करार।	9.11.2008	19.12.2008	
85	रोमानिया भारत गणराज्य की सरकार और रोमानिया गणराज्य की सरकार के मध्य आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार।	23.10.2006	20.3.2008	
86	रूसी परिसंघ भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के मध्य अवैध स्वापक मनःप्रभावी वस्तुओं और उनके पूर्वगामी प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग से संबद्ध करार।	12.11.2007	1.10.2008	
87	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और संघीय अभिलेखागार एजेंसी (रूसी परिसंघ) के मध्य अभिलेखों के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध ज्ञापन।	12.2.2008		
88	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और रूसी परिसंघ के विदेश मंत्रालय के मध्य परामर्श से संबद्ध 2009-10 के लिए प्रोटोकॉल।	20.10.2008		
89	भारत गणराज्य के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और संघीय सीमा शुल्क सेवा (रूसी परिसंघ) के मध्य कानून प्रवर्तन मामलों से संबद्ध सहयोग में वृद्धि पर ज्ञापन।	12.2008		
90	भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के मध्य संयुक्त घोषणा।	5.12.2008		
91	व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर-सरकारी आयोग के चौदहवें सत्र पर प्रोटोकॉल।	5.12.2008		
92	भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के मध्य कुदनकुलम में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई के निर्माण के साथ-साथ भारत गणराज्य में नए स्थलों पर रूस द्वारा अभिकल्पित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग से संबद्ध करार।	5.12.2008		
93	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रूसी परिसंघ अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त क्रियाकलाप के संबद्ध समझौता ज्ञापन।	5.12.2008		
94	2009-10 की अवधि के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम।	5.12.2008		

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
95	भारत के राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी तथा रूसी सीमा शुल्क अकादमी के मध्य सहयोग से संबद्ध ज्ञापन।	5.12.2008		
96	भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रूसी परिसंघ के संघीय वित्तीय बाजार सेवा के बीच पारस्परिक सहयोग और सूचना सहभाजन से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	5.12.2008		
97	80 एम आई- 175 वी-5 हेलिकॉप्टर्स की आपूर्ति के लिए ठेका।	5.12.2008		
98	भारत की वित्तीय आसूचना इकाई और रूसी परिसंघ की संघीय वित्तीय मानिटिरिंग सेवा के बीच अपराध पर मुकदमा चलाने के वेधीकरण के विरोध के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	5.12.2008		
99	भारत रूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद के सहअध्यक्षों के बीच समझौता ज्ञापन।	5.12.2008		
100	2009-10 से भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और रूसी परिसंघ के विदेश मंत्रालय के मध्य परामर्श से संबद्ध के लिए प्रोतोकॉल।	20.10.2008		20.10.2008
101	सेनेगल भारत गणराज्य की सरकार और सेनेगल गणराज्य की सरकार के मध्य निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	3.7.2008	25.8.2008	
102	सर्बिया आय और पूंजी से संबद्ध करों के दुगने कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया गणराज्य की सरकार के बीच संधि।	8.2.2006	10.1.2008	
103	सीरियाई अरब गणराज्य भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच 2008-09 के लिए कृषि और संबद्ध सेक्टरों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन के तहत कार्य योजना।	18.6.2008		18.6.2008
104	भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के मध्य पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	18.6.2008	12.9.2008	
105	सऊदी अरब भारत और सऊदी अरब अधिराज्य के मध्य अपराध से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन।	25.1.2006	22.2.2006	14.8.2008
106	भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	25.1.2006		20.6.2008

परिशिष्ट **IX**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
107	श्रीलंका भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के मध्य श्रीलंका में दूर चिकित्सा परियोजना से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	12.6.2008	21.11.2007	
108	भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के मध्य श्रीलंका में दूर-शिक्षा परियोजना से संबद्ध समझौता ज्ञापन।	28.6.2008		
109	श्रीलंका के कतूनायके में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में भूमिगत जल को कृत्रिम तरीके से पुनःचार्ज करने के लिए भारत सरकार से अनुदान सहायता के बारे में श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	4.9.2008		
110	श्रीलंका में स्थित सार्क आतंकवादी अपराध मॉनिटरिंग डेस्क (एसटीओएमडी) और सार्क ड्रग ऑफेन्सेस मॉनिटरिंग डेस्क (एसडीओएमडी) को मजबूत बनाने से संबद्ध भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन।	4.10.2008		
111	श्रीलंका में ग्रामीण सौर ऊर्जा विद्युतिकरण परियोजना से संबद्ध भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन।	रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।		

परिशिष्ट X

1 जनवरी 2008 से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
1	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मेसिडोनिया गणराज्य की सरकार के मध्य करार पर हस्ताक्षर करने के लिए मेसिडोनिया में भारत के राजदूत श्री एम.लाल डिगंरलियाना के पक्ष में।	18.01.2008
2	17 नवम्भर, 1997 को नई दिल्ली में हस्तारित भारत गणराज्य की सरकार और रोमानिया सरकार के मध्य पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संभद्ध करार को संशोधित करते हुए भारत गणराज्य सरकार और रूमानिया सरकार के मध्य प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए रूमानिया में भारत के राजदूत श्री देवाशीष चक्रवर्ती के पक्ष में।	31.01.2008
3	निवेश संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और उरूग्वे गणराज्य की सरकार के मध्य करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा के पक्ष में।	06.02.2008
4	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संभद्ध भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के भीच करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्भल के पक्ष में।	24.03.2008
5	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और फ्रेंच राष्ट्रीय रेल (एस.एन.सीएफ) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अतिरिक्त सदस्य योजना, रेलवे बोर्ड के श्री आर.के. गोयल के पक्ष में।	03.04.2008
6	श्रमिकों के रोजगार से संबद्ध भारत सरकार और मलेशिया सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य के मंत्री श्री वयालर रवि के पक्ष में।	04.04.2008
7	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और महामहिम सुल्तान की सरकार तथा ब्रूनई दारूस्लाम के यंग डी-परटूयन के मध्य करार पर हस्ताक्षर करने के लिए वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के पक्ष में।	19.05.2008
8	सूचना की सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फिनलैंड की परिवहन व संचार मंत्रालय के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव श्री एम.माधवन नाम्बियार के पक्ष में।	22.05.2008
9	आय और पूंजी से संबंधित करों के दुगने कराधन के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लक्समवर्ग के ग्रांड डची के बीच करार और प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर.एस. मथोड़ा के पक्ष में।	22.05.2008
10	आबू डीस में स्थित जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल के निर्माण और साजोसमान से संबद्ध फिलस्तीनी प्राधिकरण के लाभ के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिलीस्तीन मुक्ति संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद के पक्ष में।	04.06.2008
11	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और म्यामां संघ की सरकार के मध्य करार पर हस्ताक्षर करने के लिए वाणिज्य व विद्युत राज्यमंत्री श्री जयराम रमेश के पक्ष में।	23.06.2008
12	अंतर्राष्ट्रीय कॉफी करार, 2007 पर हस्ताक्षर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त श्री रविशंकर मुखर्जी के पक्ष में।	07.08.2008

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
13	सामाजिक बीमा से संबद्ध भारत गणराज्य और संघीय जर्मन गणराज्य के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अप्रवासी भारतीय कार्य के मंत्रालय के सचिव श्री के. मोहनदास के पक्ष में।	07.10.2008
14	कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत गणराज्य की सरकार और इक्वेडर गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा (डेयर) विभाग के अपर सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सचिव श्री अनिल कुमार उपाध्याय के पक्ष में।	14.11.2008
15	भारत गणराज्य की सरकार और तजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच आय से संबंधित करों के दुगने कराधन के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से संबद्ध करार पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, श्री एन.बी. सिंह के पक्ष में।	17.11.2008
16	भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी-विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल के पक्ष में।	17.11.2008
17	भारत सरकार और बहरीन अधिराज्य के बीच श्रम और मानव शक्ति विकास से संबद्ध समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य के मंत्री श्री वयालर रवि, के पक्ष में।	21.11.2008

परिशिष्ट **XI**

1 जनवरी 2008 से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज

क्र.सं.	अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	अनुसमर्थन जारी करने की तारीख
1	आय और पूंजी से संबंधित करों के दुगने कराधन के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सर्बिया गणराज्य की सरकार के मध्य अभिसमय।	10.01.2008
2	भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के मध्य आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार।	24.01.2008
3	भारत गणराज्य की सरकार और साइप्रस गणराज्य की सरकार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से निपटने से संबद्ध करार।	25.01.2008
4	भारत गणराज्य की सरकार और आयरलैंड सरकार के मध्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध करार।	19.02.2008
5	भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच सजाप्राप्त व्यक्तियों के स्थानातंरण से संबद्ध संधि।	28.02.2008
6	5 अक्तूबर 2004 को बूचारेस्ट में हुई XXIII काँग्रेस संघ द्वारा अपनाई गई सार्वभौमिक डाक संघ के संविधान का सातवां अतिरिक्त प्रोतोकॉल।	7.3.2008
7	भारत गणराज्य सरकार और रूमानिया सरकार के मध्य आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार।	20.03.2008
8	भारत गणराज्य की सरकार और बुल्गारिया गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार।	20.03.2008
9	अभिसमय 174, बड़े औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अभिसमय 1993,	03.04.2008
10	भारत गणराज्य की सरकार और मेसीडोनिया गणराज्य की सरकार के बीच पारस्परिक निवेश संवर्धन एवं संरक्षण के लिए।	30.04.2008
11	भारत गणराज्य की सरकार तथा उरूग्वे गणराज्य की सरकार के मध्य निवेश संवर्धन तथा संरक्षण से संबद्ध करार।	30.04.2008
12	भारत गणराज्य और बेल्जियम अधिराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा से संबंद्ध करार।	03.06.2008
13	भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र के अरब गणराज्य की सरकार के मध्य सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	05.06.2008
14	भारत गणराज्य की सरकार और कंबोडिया की शाही सरकार के मध्य सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	05.06.2008
15	अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ करार, 2006	09.06.2008
16	भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच सजा-प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबद्ध करार।	16.07.2008
17	भारत गणराज्य की सरकार और महामहिम सुल्तान की सरकार और ब्रुनेई-दारूस्लाम के यंग-डी-प्रेटूअन के बीच पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	14.07.2008
18	भारत गणराज्य और आस्ट्रलिया की बीच प्रत्यर्पण संधि	11.08.2008
19	भारत गणराज्य की सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त अधिराज्य की सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच चलचित्र निर्माण संबंधी करार।	11.8.2008

परिशिष्ट **XI**

क्र.सं.	अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	अनुसमर्थन जारी करने की तारीख
20	भारत गणराज्य और ब्राजील के संघीय गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।	14.8.2008
21	आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबंधित भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के बीच संधि।	14.8.2008
22	भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील की संघीय गणराज्य सरकार के बीच दृश्य-श्रव्य सह उत्पादन से संबद्ध करार।	22.8.2008
23	भारत गणराज्य की सरकार और सेनेगल की सरकार के मध्य निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	25.8.2008
24	भारत गणराज्य की सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।	10.09.2008
25	भारत गणराज्य की सरकार और मोन्टीनेग्रो गणराज्य की सरकार के बीच आय और पूंजी से संबंधित करों पर दुगने कराधन के परिहार से संबद्ध अभिसमय।	12.09.2008
26	भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य के मध्य पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबद्ध करार।	12.09.2008
27	अंतर्राष्ट्रीय कॉफी करार।	18.09.2008
28	भारत सरकार और मिस्र की अरब गणराज्य की सरकार के मध्य प्रत्यर्पण संधि।	08.12.2008
29	भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार के बीच सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन मामलों से संबद्ध करार।	19.12.2008
30	भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा क्षेत्र में वर्गीकृत सूचनाओं और सामग्री के संरक्षण से संबद्ध करार।	19.12.2008

परिशिष्ट XII

जनवरी, 2008 तक नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रु प से वित्त पोषित की गई संस्थाओं/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
1	05-06 मार्च 2007 को गंगटोक में "भारत-चीन सीमा व्यापार -सीमांत विकास के लिए कार्यनीति" पर संगोष्ठी	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एस एस आर) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग (मेघालय)
2	29 -31 मार्च 2007 तक विशाखापटनम में "एक नए दक्षिण एशिया की कल्पना" पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी	सार्क अध्ययन केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश)
3	प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा द्वारा "भारत की नेपाल नीति के नए आयाम : चुनौतियां, विकल्प एवं आगामी मार्ग" पर अध्ययन	लोक कार्य केन्द्र (सी पी ए) , नोयडा (उ.प्र.)
4	निम्नलिखित पर अनुसंधान परियोजनाएं : i. भारत-म्यांमार भू-राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंध : व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को सुधारने के उपाय। ii. भारतवर्ष की "पूर्व की तरफ देखो" की नीति में अड़चनें : सुझाए गए उपाय। iii. नई विश्व व्यवस्था में भारत-रूस सामरिक संबंधः अवसर/चुनौतियाँ। iv. भारतीय महासागर क्षेत्र में नई वास्तविकताएं : भारतवर्ष उनसे कैसे लाभांवित हो सकता है ?	एशिया केन्द्र, बंगलौर
5	""राष्ट्रीय हित परियोजना" पर अध्ययन।	अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधो पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई सी आर आई ई आर), नई दिल्ली।
6	विदेश मंत्रालय द्वारा गठित निःशस्त्रीकरण व परमाणु अप्रसार संबंधी कार्यबल, जिसमें डा. के. सुब्रमनियम, अरूधंति घोष, श्याम शरण और अन्य शामिल हैं, द्वारा अध्ययन।	विदेश मंत्रालय
7	भारत का उन्नत अध्ययन के लिए केन्द्र (सी ए एस आई) को वित्तीय सहायता।	पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय (यू.एस. ए)
8	अक्तूबर 2007 में सिओल (कोरिया) में 7 वीं भारत-कोरिया वार्ता।	अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधो पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई सी आर आई ई आर), नई दिल्ली।
9	23-25 नवंबर, 2007 तक नई दिल्ली में "एशियाई राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संघ की तृतीय अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस"।	विकासशील देश अनुसंधान केन्द्र (डी सी आर सी), दिल्ली विश्वविद्यालय।
10	"भारत एवं खाड़ी" पर संगोष्ठी।	भारतीय राजनयिक संघ (ए आई डी), नई दिल्ली।
11	"विदेशी मामलों की पत्रिका प्रेक्षक" का प्रकाशन।	भारतीय राजनयिक संघ (ए आई डी), नई दिल्ली।
12	"समकालीन म्यांमार : अलगाव से सक्रिय संलग्नता" संबंधी डॉ के. यौमे की अनुसंधान परियोजना।	प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान (ओ आर एफ), नई दिल्ली।
13	ढाका में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग - बांग्लादेश, चीन, भारतवर्ष तथा म्यांमार (बी सी आई एम) पर सातवाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।	चीनी अध्ययन संस्थान (आई सी एस), नई दिल्ली।

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
14	08-09 दिसंबर, 2007 को "पर्यावरणीय कानून के अंतरराष्ट्रीय आयाम" पर 5 वाँ सम्मेलन।	भारतीय अंतरराष्ट्रीय कानून सोसाइटी (आई सी आई एल)
15	10-12 दिसंबर, 2007 को "प्रजातंत्र, राष्ट्रीय निर्माण एवं दक्षिण एशिया में शांति : चुनौतियां एवं संभावनाएं" विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी।	समकालीन अध्ययन संबंधी राजीव गाँधी पीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
16	11-12 दिसंबर, 2007 को आयोजित द्वितीय सततता शिखर सम्मेलन : एशिया।	भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई एल), नई दिल्ली
17	"दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी संकट-बांग्लादेश, इंडोनेशिया, एवं मलेशिया का एक अध्ययन" -पर डॉ अबू नसर सईद अहमद द्वारा अनुसंधान अध्ययन।	ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन एवं विकास संस्थान (ओ के डी आई एस सी डी) , गुवाहाटी
18	प्रोफेसर के वारिको, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की "केन्द्रीय एशिया -चीन संबंध, 1991-2006" पर अनुसंधान परियोजना।	दक्षिण, मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिययाई अध्ययन केन्द्र (सी एस सी एस ई ए एस) , जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
19	03-05 जनवरी, 2008 को "भारत एवं दक्षिण-एशिया : 21 वीं शताब्दी में सामरिक समरूपण" पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी।	सार्क अध्ययन केन्द्र (सी एस एस) आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
20	11-12 जनवरी, 2008 को "क्षेत्रीय एकीकरण की रूपरेखा" पर सम्मलेन।	एसोसिएशन ऑफ एशिया स्कालर्स (ए ए एस), नई दिल्ली।
21	"अफगानिस्तान" पर अंतरर्राष्ट्रीय सम्मलेन -फरवरी 2008।	सेन्टर फॉर साऊथ , सेन्ट्रल साऊथ ईस्ट एशिया एन्ड साउथवेस्ट पैसिफिक स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जे.एन.यू., नई दिल्ली।
22	"पाकिस्तान में राज्य एवं समाज" तथा भारत-पाकिस्तान संबंधों पर संगोष्ठी।	भारत-पाकिस्तान मैत्री सोसाइटी (आई पी एफ एस), नई दिल्ली।
23	इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ ट्रैक-II वार्ता के 28 वें दौर की बातचीत।	भारत-पाकिस्तान नीमराना पहल (आई पी एन आई), नई दिल्ली।
24	"मध्य एशिया में सहयोग विकास एवं शांति : एक भारतीय दृष्टिकोण" पर संगोष्ठी।	ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र (सी आर आर आई डी) , चंडीगढ़
25	"भारत के लिए वैकल्पिक पाठयक्रम का विश्लेषण : क्योतो समझौते के बाद" पर अध्ययन परियोजना।	विकास के लिए एकीकृत अनुसंधान एवं कार्रवाई (आई आर ए डी), नई दिल्ली।

परिशिष्ट **XIII**

आई टी ई सी/एस सी ए ए पी भागीदार देशों की सूची

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1	अफगानिस्तान	43	डोमिनिकन गणराज्य
2	अलबानिया	44	पूर्व तिमोर
3	अलजीरिया	45	इक्वाडोर
4	अंगोला	46	मिश्र
5	अंग्यूला	47	एल-सल्वाडोर
6	एंटिगुआ और बारबुडा	48	भूमध्यवर्ती गिनी
7	अर्जेंटीना	49	इरिट्रिया
8	आर्मेनिया	50	इस्टोनिया
9	अजरबैजान	51	इथिओपिया
10	बहामास	52	फिजी
11	बहरीन	53	गैबोन
12	बांग्लादेश	54	गाम्बिया
13	बारबाडोस	55	जॉर्जिया
14	बेलारुस	56	घाना
15	बेलीज	57	ग्रेनेडा
16	बेनिन	58	ग्वाटेमाला
17	भूटान	59	गिनी
18	बोलिविया	60	गिनी बिस्साउ
19	बोस्निया-हर्जेगोविना	61	गुयाना
20	बोत्सवाना	62	हैती
21	ब्राजील	63	होंडुरास
22	ब्रुनई दारूसलम	64	हंगरी
23	बुलगारिया	65	इंडोनेशिया
24	बुरकिना फासो	66	ईरान
25	बुरुंडी	67	ईराक
26	कम्बोडिया	68	आइवरी कोस्ट
27	कैमेरुन	69	जमैका
28	केप वरडे द्वीप	70	जॉर्डन
29	कैमेन द्वीप	71	कजाखस्तान
30	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	72	केन्या
31	चाड	73	किरीबाती
32	चिली	74	कोरिया (डी पी आर के)
33	कोलम्बिया	75	किर्गिस्तान
34	डोमिनिका राष्ट्रमण्डल	76	लॉओस
35	कॉमोरोस	77	लातविया
36	कांगो	78	लेबनान
37	कोस्टा रिका	79	लेसेथो
38	क्रोसिया	80	लाईबेरिया
39	क्यूबा	81	लिबिया
40	चेक गणराज्य	82	लिथुआनिया
41	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	83	मैसिडोनिया
42	जीबोती	84	मैडागास्कर

परिशिष्ट **XIII**

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
85	मलेशिया	122	सेशल्स
86	मलावी	123	सिगापुर
87	मालदीव	124	सियरा लियोन
88	माली	125	स्लोवाक गणराज्य
89	मार्शल द्वीप	126	सोलोमान द्वीप
90	मॉरीशस	127	दक्षिण अफ्रीका
91	मॉरीतानिया	128	श्रीलंका
92	मैक्सिको	129	सेंट किटस तथा नेविस
93	माइक्रोनेशिया	130	सेंट लुसिया
94	मोलडोवा	131	सेंट विंसेंट तथा ग्रेनाडाइन्स
95	मंगोलिया	132	सूडान
96	मांटसेराट	133	सूरीनाम
97	मोरक्को	134	सिरिया
98	मोजाम्बिक	135	स्वाजीलैंड
99	म्यामां	136	तंजानिया
100	नामीबिया	137	ताजिकिस्तान
101	नारु	138	थाइलैंड
102	नेपाल	139	टोगो
103	निकारागुआ	140	टोंगा
104	नाइजर	141	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो
105	नाइजेरिया	142	टयूनीसिया
106	ओमान	143	तुर्की
107	पलावु	144	तुर्कमेनिस्तान
108	फिलीस्तीन	145	तुर्क एवं कैकोस द्वीप
109	पनामा	146	तुवालु
110	पापुआ न्यू गिनी	147	यूगांडा
111	परागुवे	148	यूक्रेन
112	पेरु	149	उरुग्वे
113	फिलीपीन्स	150	उज्बेकिस्तान
114	पोलैंड	151	वानुआतू
115	कतर	152	वेनेजुएला
116	साओ तोमे गणराज्य	153	वियतनाम
117	रोमानिया	154	यमन
118	रुस	155	जाम्बिया
119	रवान्डा	156	जिम्बाब्वे
120	समोआ	157	सर्बिया
121	सेनेगल	158	मानटिनिग्रो

परिशिष्ट **XIV**

भारत में आई.टी.ई.सी. प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	शहर
1	भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	हैदराभाद
2	अपटेक लिमिटेड	नई दिल्ली
3	भारतीय मानक भ्यूरो	नई दिल्ली
4	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण भ्यूरो	नई दिल्ली
5	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाभाद, हरियाण
6	अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराभाद
7	केन्द्रीय औजार अभिकल्प संस्थान	हैदराभाद
8	केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतिकरण संस्थान	हैदराबाद
9	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन	नई दिल्ली
10	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	मोहाली (चंडीगढ़)
11	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	नॉएडा (उ.प्र.)
12	सी.एम.सी. लिमिटेड	नई दिल्ली
13	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान	भाट, गुजरात
14	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	केरल
15	मानव पुनर्वास प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
16	भारतीय जनसंचार संस्थान	नई दिल्ली
17	अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा परीक्षा केन्द्र (सीएजी)	नॉएडा (उ.प्र.)
18	भारतीय उत्पाद प्रबंधन संस्थान	उड़ीसा
19	भारतीय सूदुर संवेदन संस्थान	देहरादून
20	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की
21	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
22	सरकारी लेखा वित्त संस्थान	नई दिल्ली
23	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
24	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र	कोलकाता
25.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	पुणे
27.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासनिक विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नॉएडा, उ.प्र.
29.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	पंजाब
30.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
31.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संस्थान (पूर्ववर्ती एन.आई.एस.आई.ई.टी.)	हैदराबाद
32.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
33.	एन.आई.आई.टी. लिमिटेड	नई दिल्ली
34.	गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
35.	श्रीराम व्यापार व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	नई दिल्ली
36.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ	कोयम्बटूर
37.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी व प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र	मुम्बई
38.	ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी)	नई दिल्ली
39.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	नॉएडा, उ.प्र.
40.	यू.टी.एल. प्रौद्योगिकी लिमिटेड	बैंगलूर
41.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	अहमदाबाद

परिशिष्ट **XV**

आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित व्याख्यान/संगोष्ठियां/सम्मेलन/बैठकें/द्विपक्षीय वार्ताएं/पुस्तक विमोचन समारोह

क्रम सं	दिनांक	कार्यक्रम
1	9 सितम्बर	"चीन-भारत सामरिक भागीदारी" पर चीन लोक गणराज्य के विदेश मंत्री, महामहिम श्री यांग जिची द्वारा व्याख्यान (चीनी अध्ययन संस्थान और चीन लोक गणराज्य के राजदूतावास के सहयोग से)।
2	11 सितम्बर	आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री माननीय स्टिफेन स्मिथ, द्वारा "एशिया प्रशांत शताब्दी में आस्ट्रेलिया व भारत" पर व्याख्यान।
3	17 नवम्बर	कोलोन के लॉर्ड मेयर श्री फ्रीज सरामा द्वारा कोलोन क्षेत्र और भारत : नई भागीदारी और अवसर पर प्रस्तुति।
4.	19 फरवरी, 2009	रवाण्डा गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री पॉल कागामे द्वारा "अफ्रीका में राष्ट्र निर्माण की अनिवार्यताएंः सुरक्षा, शांति और सुलह" पर व्याख्यान
5.	5 फरवरी, 2009 (आईसीडब्ल्यूए सभागर)	राष्ट्रमंडल के महासचिव महामहिम श्री कमलेश शर्मा द्वारा "सिमटती दुनिया में परिवर्तन एवं विविधता का प्रबंधन" पर भारतीय राजनयिक संघ का "वार्षिक व्याख्यान 2009" (भारतीय राजनयिक संघ के सहयोग से)
6.	26 फरवरी, 2009	शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव श्री बोलट नुरगालिव द्वारा व्याख्यान (आईसीएएफ के सहयोग से)
7.	27 मार्च, 2009	भारत में क्यूबा के राजदूत महामहिम मिगेल एंजेल रामीरेज रामोस द्वारा "हवाना की दृष्टि से कैरेबियाई क्षेत्र" पर व्याख्यान
संगोष्ठी/सम्मेलन		
8.	2 से 3 अप्रैल	"21वीं सदी में भारत-अफ्रीका भागीदारी पर" अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
9.	9 से 10 जून,	"नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व की ओर" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से)।
10.	13 अगस्त	भारत स्विस मैत्री संधि, 1948 की 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर "भारत-स्विस संबंधः प्रवर्धित सहयोग" पर संगोष्ठी और स्विजरलैंड राजदूतावास के सहयोग से बरर्नाड इम्हसली द्वारा संपादित "विविधता में मैत्री; भारत-स्विस संबंध के साठ वर्ष" पुस्तक का विमोचन।
11.	27-28 नवम्बर	"भारत-रूस सामरिक भागीदारीः चुनौतियाँ एवं संभावनाएं" पर संगोष्ठी (मास्को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान, मास्को के सहयोग से)।
12.	2-3 दिसंबर, 2008	भारत-अरब ऐतिहासिक संपर्क एवं सम्यतामूलक वार्ता पर गोलमेज बैठक, उद्घाटन भाषणः विदेश राज्य मंत्री माननीय ई.अहमद मूल सिद्धांत भाषणः अरब लीग राज्य के महासचिव डा.आमरे मुसा द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के सहयोग से (फिक्की) विदेश मंत्रालय, आईसी डब्ल्यू ए और अरब लीग राज्य द्वारा 2-7 दिसंबर, 2008 तक संयुक्त रूप से आयोजित भारत अरब मंचः संस्कृति के माध्यम से भागीदारी के अवसर पर
13.	12-14 जनवरी, 2009	"मानव एकजुटताः दृष्टि एवं परियोजनाएं" पर क्रास-कल्वर कंवर्सेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।
14.	24-26 मार्च, 2009	खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम, जेएनयू के सहयोग से "खाड़ी एवं उभरता एशियाः क्षेत्रीय ढांचे का निरूपण " पर संगोष्ठी।
15.	30 मार्च, 2009	"भारत-कज़ाखस्तान संबंधः नए क्षितिजं" पर संगोष्ठी
16.	31 मार्च, 2009	"भारत-कज़ाखस्तान सामरिक भागीदारीं" पर संगोष्ठी
द्विपक्षीय वार्ताएं		
17.	8-11 अगस्त	आई.सी.डब्लू.ए. और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामरिक अध्ययन केन्द्र (सीएसएस) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का काबुल, अफगानिस्तान का दौरा।
18.	18 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भारत-नाइजीरिया ट्रैक-II संवाद और नाइजीरियाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान के महानिदेशक प्रो. ओसीता सी. इजे, द्वारा "वैश्वीकरण के युग में गतिशील भारत-नाइजीरियन संबंध" पर व्याख्यान (नाइजीरियाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के यात्रा के अवसर पर)

परिशिष्ट **XV**

क्रम सं	दिनांक	कार्यक्रम
19.	16-17 अक्तूबर	चौथा भारत-स्पेन संवाद मंच
20.	6-8 नवम्बर	न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान (एनआईआईए) वेलिंगटन (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी) का आई.सी.डब्ल्यू.ए. के प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा दौरा।
21.	9-11 नवम्बर	ऑस्ट्रलियाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान, (ए.आई.आई.ए.) मेलबॉर्न (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी) का आई.सी.डब्ल्यू.ए. के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दौरा।
22.	12-13 नवम्बर	लॉवी संस्थान सिडनी का आई.सी.डब्ल्यू.ए. के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दौरा, प्रथम आस्ट्रेलिया भारत गोलमेज।
पुस्तक विमोचन/पैनल चर्चा/पृष्ठभूमि विवरण तथा अन्य कार्यक्रम		
23.	5 जून	9-10 जून, 2008 को "परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की ओर" विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रेस सम्मेलन (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन व सामरिक के (सीएसआईएस) के सहयोग से)।
24.	6 जून	"परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की ओर" विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर 9-10 जून, 2008 को प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन, द्वारा सामरिक व अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र के निदेशक, एयर कोमोडोर जसजीत सिंह और आई.सी.डब्ल्यू.ए. के कार्यवाहक महानिदेशक श्री अशोक कुमार द्वारा पृष्ठभूमि विवरण (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन व सामरिक केन्द्र (सी.एस.आई.एस.) के सहयोग से)।
25.	29 अगस्त	"एक नवीन एशियाई ढांचे की ओर-एक भारतीय दृष्टि" पर परियोजना के संबंध में पहली बैठक (शांति एवं संघर्ष अध्ययन संस्थान के सहयोग से)।
26.	12 सितंबर	"एक नवीन एशियाई ढांचे की ओर-एक भारतीय दृष्टि" पर परियोजना के संबंध में दूसरी बैठक (शांति एवं संघर्ष अध्ययन संस्थान के सहयोग से)।
27.	15 सितंबर	"काकेशस में हाल के घटनाक्रमों" पर गोलमेज चर्चा।
28.	18 सितम्बर	"नया नेपाल- इसकी आकांक्षाएं एवं स्वप्न" पर चर्चा
29.	26 सितम्बर	"एक नवीन एशियाई सुरक्षा ढांचे की ओर-एक भारतीय दृष्टि'' पर परियोजना के संबंध में तीसरी बैठक (शांति एवं संघर्ष अध्ययन संस्थान के सहयोग से)।
30.	25 नवंबर	"फिलीस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस" मनाने के लिए समारोह
31.	26 नवंबर	"न्यूक्लियर सिनर्जीः भारत-अमरीका सामरिक सहयोग एवं उसके आग" नामक पुस्तक (इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजीव गांधी समकालीन अध्ययन पीठ के प्रो.एन.के.झा द्वारा संपादित) का भारत के पूर्व विदेश सचिव राजदूत ललित मानसिंह द्वारा लोकार्पण और उस पर सामूहिक परिचर्चा।
पुस्तकों का प्रचार		
32.	1 मई, 2008	सप्रु हाउस के उद्घाटन की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर आईसीडब्ल्यू ए और आईसीएएफ की संयुक्त परियोजना "भारत-किर्गिज संबंधः संदर्श एवं संभावनाएं" लोकार्पण
33.	16 जून, 2008	विशेष कार्याधिकारी एवं विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एफएसआई)श्री प्रदीप कुमार कपूर और प्रो. सच्चिदानंद सहाय द्वारा लिखित "ता प्रोह्मः अंगकोर सभ्यता का एक वैभवशाली युग" नामक पुस्तक का माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोकार्पण
34.	26 नवंबर, 2008	इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजीव गांधी समकालीन अध्ययन पीठ के प्रो.एन.के.झा द्वारा संपादित "न्यूक्लियर सिनर्जीः भारत-अमरीका सामरिक सहयोग एवं उसके आगे" नामक पुस्तक का भारत के पूर्व विदेश सचिव राजदूत ललित मानसिंह द्वारा लोकार्पण और उस पर सामूहिक चर्चा
35.	13 जनवरी, 2009	सिक्किम के राज्यपाल श्री बी.पी.सिंह द्वारा लिखित पुस्तक "बहुधा और 9/11 के बाद की दुनिया" पर सामूहिक चर्चा मुख्य अतिथिः डा.कर्ण सिंह, संसद सदस्य
36.	29 जनवरी, 2009	डा. सुधीर कुमार सिंह द्वारा संपादित पुस्तकः 9/11 के बाद भारतीय विदेश नीतिः चुनौती एवं अवसर का लोकार्पण और उस पर पैनल चर्चा मुख्य अतिथिः राजदूत ए.एन.राम

परिशिष्ट **XVI**

आरआईएस द्वारा आयोजित संगोष्ठिया

- 20 नवम्बर, 2008 को नई दिल्ली में विकास सहयोगः उभरती हुई प्रवृत्तियों, प्रतिमान और नीतियों पर संगोष्ठी।
- 24 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में वैश्विक वित्तीय संकट और भारत पर संगोष्ठी।
- 22 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में एशिया के आर्थिक एकीकरण के लिए क्षत्रीय आधारभूत संरचना पर संगोष्ठी।
- 16 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में वैस्वीकरण, उत्पादकता और रोजगार पर संगोष्ठी।
- नई दिल्ली में संयुक्त रूप से चीनी अध्ययन संस्थान (आई सी एस) के साथ मिलकर भारत-पूर्व एशिया आर्थिक सहयोगः संभारिकी तंत्र का मामला पर संगोष्ठी।
- 17 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में भारतीय निर्यात में बाजार मूल्य निर्धारणः विषमता और उत्पाद विभिन्नता की भूमिका पर संगोष्ठी।
- 20 मई, 2008 को बॉन में एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा (एबीडीआर) के विशेष अंक का शुभारंभ
- 5 मई 2008 को नई दिल्ली में संप्रभु धन कोषः भारत के मुद्दे व चुनौतियों पर संगोष्ठी।
- 12 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में, वैश्विक आर्थिक संकटः दक्षिण से प्रतिक्रिया पर संगोष्ठी (चीनी अध्ययन संस्थान और सामाजिक विकास परिषद के साथ संयुक्त रूप से)

आरआईएस प्रकाशन

पुस्तकें एवं रिपोर्ट

- दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2008, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रैस द्वारा 2008 में प्रकाशित।
- औद्योगिक समूह, उत्पादन तंत्र और एफ.डी.आई. संवर्धन दो समूह में भारत में ऑटो घटक उद्योग के अनुभव। आर.आई.एस. 2008. आशियान व पूर्व एशिया (ईरया) के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान, टोकियोः आई.डी.ई-जैट्रो।
- भारत में आधारभूत संरचना विकास पर अध्ययन और आरआईएस आधारभूत संरचना सूची 2008, आशियान व पूर्व एशिया (ईरिया) के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान, टोकियोः आई डी ई.जैट्रो ।
- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी, नवाचार और विकासः मापन और साख्यिकी संग्रहण से संबद्ध अंक।
- सेवा में सार्क व्यापार पर क्षेत्रीय अध्ययन, आरआईएस और सार्क सचिवालय, 2008।
- पुनरूत्थानशील चीनः भारत के लिए उलझन, आरआईएस, 2009।

नीति पक्षसार

#34 जलवायु परिवर्तन के प्रबंध के लिए वैश्विक समझौते की ओर, नवम्बर 2007

#35 विकास निर्माण- मैत्रीपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, मार्च, 2008

#36 वापस आरेख पट परः दोहा दौर की वार्ता को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है, अप्रैल 2008

#37 उभरती हुई सहायता संरचना शर्तों को सख्त बनाना? जुलाई, 2008

#38 बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग को गहन करनाः विम स्टिक शिखर सम्मेलन की कार्यसूची, नवंबर, 2008

#39 साझी समृद्धि और सम्मिलित वैश्वीकरण के लिए इब्सा भागीदारी- तीसरी इब्सा अकादमिक शिखर सम्मेलन मंच की रिपोर्ट, दिसंबर, 2008

#40 वैश्विक लोकतांत्रिक शासन और विकास के लिए ब्रिटेन-बुड प्रणाली में सुधार करना।

विचार-विमर्श संबंधी कागजात

#132 विश्व व्यापार संगठन का दोहा वार्ताः भागीरथ लालदास द्वारा मूल्यांकन।

#133 क्षेत्रीय वित्तीय संरचना के पुनर्निर्माण के लिए एक एशियाई "ब्रिटेन-बुडस" की ओर, रामगोपाल अग्रवाल द्वारा

#134 भारत अफ्रीका आर्थिक भागीदारीः प्रवृत्तियां और संभावनाएं, एस.के. मोहंती और सचिन चतुर्वेदी द्वारा।

#135 पूर्व एशियाई आधारभूत संरचना विकास, वैश्विक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में : आरआईएस आधारभूत संरचना सूची का विश्लेषण, नागेश कुमार व परावीर डे द्वारा

#136 एशियाई आर्थिक एकीकरण की क्षमताः जापानी उद्यमों की कार्यनीति संबंधी एक परिप्रेक्ष्य, तेतसूजी कवामोरा द्वारा।

#137 उचित प्रौद्योगिकी और निवेश के स्रोतों के तौर पर उभरते देशः भारत के मामले का अध्ययन, सचिन चतुर्वेदी द्वारा

#138 उभरते देश और विश्व अर्थव्यवस्थाः विकासशील देशों

पर भारत के नवीनतम विस्तार के निहितार्थ, एस.के. मोहंती द्वारा

#139 विकास सहयोग और आर्थिक सहायता प्रबंधन के लिए संरचना के उभरते प्रतिमान भारत के लिए चुनौतियां व निहितार्थ, सचिन चतुर्वेदी द्वारा

#140 भारतीय उद्यमों का अंतर्राष्ट्रीयकरणः प्रतिमान, कार्यनीतियां, स्वामित्व लाभ व निहितार्थ, नागेश कुमार द्वारा

#141 दोहा वार्ता दौरे से पहले गैट में विकासशील देशों की भूमिका की पुनः खोज, फैजल स्माइल द्वारा

#142 ढुलाई लागत और व्यापार प्रतिस्पर्धा भारत से अनुभवसिद्ध प्रमाण, प्रवीर डे और भीष्म राउत द्वारा

#143 बदलती आर्थिक शक्ति, मनमोहन अग्रवाल द्वारा

#144 विकसित और उभरते हुए बाजारों में भारतीय निर्यात की विनिमय दर सुशांत मलिक और हेलेना मार्क्स द्वारा

#145 एशिया प्रशांत में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहायताः विकास सहयोग में एक नए प्रतिमान की ओर, नागेश कुमार द्वारा

पत्रिकाएं

1. साउथ एशिया इकानोमिक जरनल (खंड 9 सं. 1) जनवरी-जून, 2008

   साउथ एशिया इकानोमिक जरनल (खंड 9 सं. 2) जुलाई-दिसंबर, 2008

2. एशियन बायोटेकनोलाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 10(1 और 2) नवंबर, 2007 से फरवरी, 2008

   एशियन बायोटेकनोलाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 10(3) जुलाई, 2008

   एशियन बायोटेकनोलाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 11(1) नवंबर, 2008

3. न्यू एशिया मानीटर, खंड 5 सं. 1, जनवरी 2008

   न्यू एशिया मानीटर, खंड 5 सं. 2 और 3, अप्रैल-जुलाई, 2008

   न्यू एशिया मानीटर, खंड 5 सं. 4, अक्तूबर, 2008

   मेकांग-गंगा पॉलिसी ब्रीफ, सं. 3, मई 2008

न्यूजलेटर

आर आई एस डायरी, खंड 6 सं. 1, जनवरी 2008

आर आई एस डायरी, खंड 6 सं. 2, अप्रैल, 2008

आर आई एस डायरी, खंड 6 सं. 3, जुलाई, 2008

आर आई एस डायरी, खंड 6 सं. 4, अक्तूबर,, 2008

संक्षिप्तियाँ

आल्को	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन	डीटीएसी	दोहरा कराधान परिहार अभिसमय
एएमएम	आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक	ईएसी	पूर्व अफ्रीकी समुदाय
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच	ईएएस	पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन	इकोवास	पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक	ईआईएल	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
एसोचैम	एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री	ईएमएम	पूर्व एशिया मंत्री बैठक
एयू	अफ्रीकी संघ	ईयू	यूरोपीय संघ
आयुष	आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक	एक्जिम	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
		फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
बिमस्टेक	बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल	एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
		एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार	एफटीए	मुक्त व्यापार करार
सीईपी	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	गेल	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
		जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक	जीएसटी	सामान एवं सेवा कर
सीआईसी	केन्द्रीय सूचना आयोग	एचएएल	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ	एचआईवी/एड्स	ह्यूमन ईम्यूनो वायरस/एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिसिएंसी सिण्ड्रोम
सीआईएस	स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल		
कोमेसा	पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार	आईएईए	अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
कॉरपट	समन्वित गश्ती	आईबीएफ	भारतीय व्यवसाय मंच
सीओएससी	चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी	आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार	आईसीआरआईईआर	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा		
सीएससीएपी	एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद	आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
		आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
सीएसडी	व्यापक सुरक्षा वार्ता		
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
डीएसएससी	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज	आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा

संक्षिप्तियाँ

आईआईबीएफ	भारतीय बैंकिंग एवं विश्व संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलओ	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएनएस	भारतीय नौसैनिक पोत
आईएनएसटीसी	अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा
आईओआर-एआरसी	हिन्द महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ
आईएससीएस	अन्तरराज्य परिषद सचिवालय
आईटेक	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलएनजी	तरल प्राकृतिक गैस
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमएफएन	अत्यंत अनुकूल राष्ट्र
एमओयू	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन परिसंघ लिमिटेड
नैम	गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
नास्कोम	राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ
नाटो	उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
एनईएलपी	नई दोहन लाइसेंसिंग नीति
नेपाड	अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनपीटी	नाभिकीय अप्रसार संधि
एनएससी	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
एनएसजी	नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह
ओसीआई	भारतीय समुद्रपारीय नागरिकता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
राइट्स	रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएडीसी	दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय
साफ्टा	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एस्कैप	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेवा	स्व-नियोजित महिला संघ
एसईजेड	विशेष आर्थिक सत्र
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसटीपीआई	भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीम-9	टेक्नो-इकोनॉमिक अप्रोच फार अफ्रीका इण्डिया मेवमेंट
अंकटाड	व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
वीएसएनएल	विदेश संचार निगम लिमिटेड
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन